

# रूस का आर्थिक विकास

[ Economic Development of Russia ]

डा० राजकुमार अग्रवाल,

डी० फिल० [इलाहाबाद], •

कामर्स विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।

कि ता ब म ह ल, इ ला हा वा द

बम्बई : दिल्ली • कलकत्ता • भोपाल हैदराबाद : जयपुर

१९६०

प्रथम संस्करण, १९६०

प्रकाशक—किताब महल, ५६ ए, जीरो रोड, इलाहाबाद ।

मुद्रक—अनुपम प्रेस, १७ जीरो रोड, इलाहाबाद ।

श्रद्धेय माता-पिता  
को  
सादर समर्पित

## भूमिका

रूस का इतिहास, संसार के अन्य देशों की तरह जनता, परम्परा, प्रथा तथा संस्था का इतिहास नहीं है। इसकी उत्पत्ति और विकास के केवल दो श्रोत थे— राजा और पादरी। शक्ति का प्रतीक राजा था, आस्था का केन्द्र पादरी। समाजवाद आने के बाद इनका स्थान शासक और कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रहण कर लिया। आर्थिक विकास को समझने के लिये इनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। यह वस्तुतः सत्य है कि रूसी आर्थिक कार्य प्रणाली और विचारधारा की जड़ें युद्ध और दास प्रथा में दिखलाई पड़ती हैं। आदिकाल से ही युद्ध के केन्द्र-बिन्दु पर रूस के आर्थिक तथा राज-नैतिक ढाँचे की रचना हुई। एशिया और योरोप के बीच पहाड़-सा अटल खंड रह कर इस देश ने विभिन्न एशियाई जातियों के हमले सहन किये। विन्वसकारी वर्ग शक्तियाँ अधिकतर रूस में ही विलीन हो जाती अथवा अत्यन्त क्षीण होकर आगे बढ़ती। पश्चिमी योरोप के शान्तिपूर्ण विकास का यह भी एक कारण था। युद्ध का रूसी विचार-धारा पर सदा से ही अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता आया है। देश का सामाजिक पुनर्संज्ठन या तो पराजय से दुबारा उठने का प्रयत्न था, या अधिक शक्तिशाली बन कर दूसरों को जय करने की इच्छा। जब महान् पीटर नर्वा के युद्ध में स्वीडन से हारा तब सेना और समाज की नई नींव पड़ी। नैपोलियन के आक्रमण ने रूस को योरोपीय राज-नीति का खिलाडी बना दिया। क्रीमिया में इंग्लैंड और फ्रांस से पराजित होने पर दास मुक्ति व शासन सुधार का जन्म हुआ। 1905 की रूसी क्रान्ति का प्रमुख कारण था जापान के हाथों देश की करारी हार। प्रथम विश्व युद्ध और इन सब बातों ने मिल कर 1917 के राज्यक्रान्ति की भूमिका तैयार की जिसके विस्तार से आधुनिक रूस का निर्माण हुआ।

अनेकों जातियों का मिश्रण होने से रूसी रक्त में कुछ विलक्षण गुण उत्पन्न हुए। धर्म पर आस्था और अपने सम्राट पर अटूट श्रद्धा इनके शक्ति का रहस्य था। अपूर्व त्याग, आश्चर्यजनक सहनशक्ति, शारीरिक बल और चमत्कारी साहित्यकारों की प्रेरणा की सहायता से देश ने हर कठिनाई पर विजय पाई तथा हर पराजय के बाद दुगुने जोश से पुनर्निर्माण किया।

एकतन्त्रात्मक जारशाही के अत्याचार और दास प्रथा के भयंकर त्रास ने रूसी जनता के लिए राजकीय दमन तथा सामाजिक शोषण स्वाभाविक-सा बना दिया। प्रत्येक देश के इतिहास ने कभी न कभी अपने मार्ग को बदला। किन्तु रूसी इतिहास राजकीय



दमन, कठोर अनुशासन एवं जनता के मौन त्याग के मार्ग पर नियत गति से चलता आ रहा है । रूपान्तर हुए, परिवर्तन नहीं । चित्र का रङ्ग बदला, पृष्ठ-भूमि वही बनी रही ।

रूस का आर्थिक इतिहास एक रोचक एवं शिक्षाप्रद अध्ययन है । हर अविकसित अथवा कम विकसित देश के लिए इसमें अनेकों लाभपूर्ण संकेत तथा सदेश मिलते हैं । राजनैतिक मतभेद चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, प्रगति के क्षेत्र में रूसी अनुभव व प्रदर्शनों के महत्व में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

जहाँ तक सम्भव हो सका वर्तमान अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़ों को रूस के सरकारी सूत्रों से ही लिया गया है । अनेकों स्थान पर प्रोफेसर क्लुशेवस्की, लाइशेन्को, मेवर, वेन, हूवर, श्वाट्ज तथा डौव की छाया मिलने पर कोई आश्चर्य न होना चाहिये । इन उद्भट विद्वानों के प्रयास से ही रूस का आर्थिक इतिहास ससार के सामने सविस्तार आया ।

यह अध्ययन रूसी इतिहास को हिन्दी में प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न है । इसकी प्रेरणा डा० एम० एम० नेहता, डाइरेक्टर आफ स्टैटिस्टिक्स, मध्य प्रदेश सरकार, से मिली, जिनसे इस विषय को पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था । मेरे विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर, डा० अमर नारायण अग्रवाल, की कृपा और प्रोत्साहन से यह कार्य सम्भव हो सका । मेरे गुरु एवं सुहृद् सहयोगी वाणिज्य विभाग के श्री डी० एन० एलहंस, तथा अर्थशास्त्र विभाग के श्री महेश चन्द के सक्रिय योगदान का यह प्रभाव है । मैं इनका आभारी हूँ । उन सभी व्यक्तियों का मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने प्रारूप की तैयारी तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों में सहायता किया ।

कामर्स विभाग,  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,  
नव वर्ष, 1960,

}

राजकुमार अग्रवाल

## अनुक्रमणिका

अध्याय 1	आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि	I
अध्याय 2	कृषि का विकास [1861 तक]	10
अध्याय 3	वस्तु निर्माण तथा उद्योग [1861 तक]	33
अध्याय 4	कृषि-दासता तथा दास-मुक्ति	45
अध्याय 5	आर्थिक सङ्गठन [1861-1917]	59
अध्याय 6	राज्य-क्रान्ति	73
अध्याय 7	विदेशी हस्तक्षेप तथा युद्धकालीन साम्यवाद	86
अध्याय 8	नवीन आर्थिक नीति	103
अध्याय 9	सोवियत राज्य की सैद्धान्तिक रूपरेखा	127
अध्याय 10	अर्थ-व्यवस्था व आयोजन प्रणाली का सङ्गठन	143
अध्याय 11	रूसी योजनाएँ	188
अध्याय 12	अर्द्ध-विकसित देशों के लिए रूसी आर्थिक विकास का सदेश	233
परिशिष्ट 1	सोवियत रूस का यातायात सङ्गठन	238
परिशिष्ट 2	रूस में सामाजिक सुरक्षा	245

# विषय—विस्तार

## प्रथम भाग

### अध्याय 1. आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि

[1] प्राकृतिक साधन : भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक साधन—शक्ति—  
खनिज पदार्थ; कृषि साधन—उपज—विस्तार—पशु-पालन ।

[2] राजनैतिक विकास : इस्काइथियन जाति—स्लाव जाति—वाइ-  
जेन्टाइन सभ्यता—मंगोल प्रभाव—आइवन चतुर्थ [1533-1584]—  
माइकेल रोमानोव [1613]—महान् पीटर प्रथम [1689-1725]—  
कैथरीन द्वितीय [1762-1796] अलेक्जान्डर द्वितीय [1855-  
1881]—निकोलस द्वितीय [1894-1917]—लेनिन [1917-1924]—  
न्नालिन [1927-1952]—निकिता ख्रुश्चेव ।

[3] सामाजिक विकास : विशिष्ट रूसी सामाजिक सगठन—शोषण—  
सेनाधिकारी—धर्माधिकारी—राज्याधिकारी शिक्षित बुद्धिवादी वर्ग—राज्य  
और जनता—रूसी चरित्र ।

### अध्याय 2. कृषि का विकास [1861 तक]

[1] भूमि-स्वामित्व का उदय तथा विस्तार : आरम्भिक अर्थ-व्यव-  
स्था—पारिवारिक अथवा जाति जन-समूह—क्षेत्रीय समुदाय—सामुदायिक  
भूमि स्वामित्व—भूमि एवं दास स्वामी वर्ग—सामन्तवाद—वशानुगत भू-  
सम्पत्ति या बोशीना—पोमेस्ती भू-स्वामी ।

[2] भूमि-स्वामित्व के प्रधान वर्ग : बोशीना तथा पोमेस्ती का पतन—  
सामन्त बैङ्क [Nobles Bank]—चर्च स्वामित्व—दरबार भूमि-स्वा-  
मित्व—जार स्वामित्व—राज्य स्वामित्व—अन्य स्वामित्व—पोलोव्नीकी—  
पुराने मैनिन ।

[3] किसान की स्वतन्त्रता कृषि सगठन का विकास—ऋणी  
किसान—प्रवास पर प्रतिबन्ध—सोवर नियम—भूमि व किसान का गठ-  
बन्धन—वस्तु तथा मुद्रा भुगतान प्रथा [obrok]—श्रम-भुगतान [bart-  
shina]—गृह-दास [dvorovic lyude] सह-कृषि [share-crop-  
ping]—राज्य और कृषि—उदासीनता—कर प्राप्ति का साधन—आपसी  
आश्वासन या सामुदायिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त—कर-व्यवस्था ।

[4] उत्पादन संगठन तथा प्रणाली : मीर अथवा ओवशीना—स्लाव-भक्त [slavophiles]—अर्थ-विकास—विशेषताएँ—कमजोरियाँ ।

अध्याय 3 वस्तु निर्माण तथा उद्योग [1861 तक]

33

[1] वस्तु निर्माण और कारखाना उत्पादन में अन्तर—वस्तु निर्माण का क्रमिक विकास : राजनैतिक स्थिति—सैनिक दृष्टिकोण—आत्म-निर्भर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था—बलात् कारखाना श्रम—पीटर प्रथम का प्रभाव—व्यापारवाद द्वारा पुनर्संगठन - आधुनिक उद्योग का जन्म—दास प्रथा का अवरोध ।

[2] उत्पादन संगठन : राजकीय उत्पादन प्रणाली—महान् पीटर द्वारा श्रमिक वेतन निर्धारण—हस्तान्तरित उद्योग—भू-स्वामी उत्पादन प्रणाली—रूसी कुटीर उद्योग—विकास—कुटीर उद्योग का स्वर्ण-युग—पतन ।

[3] राज्य तथा औद्योगिक विकास : विशेषताएँ—पीटर प्रथम—कैथरीन द्वितीय—निकोलस प्रथम ।

अध्याय 4. कृषि दासता तथा दास मुक्ति

45

[1] दास प्रथा का विकास : केलाद—युद्ध-दास - कृषि-दास आर्थिक कारण—वैधानिक प्रोत्साहन ।

[2] कृषक आन्दोलन एवं दास मुक्ति : विभिन्न विद्रोह—शोषण में वृद्धि—नैपोलियन का आक्रमण—शाही अध्ययन समितियाँ—एलेक्जान्डर द्वितीय के प्रयत्न ।

[3] दास प्रथा टूटने के कारण : आर्थिक कारण—प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था का भंग होना—उद्योग का विकास—श्रम-स्थानान्तर करने की आवश्यकता—1820-25 की कृषि मन्दी—पूँजीवादी मूल्य-व्यवस्था की स्थापना, राजनैतिक कारण - क्रीमिया के युद्ध की पराजय [1854-56]—औद्योगीकरण की सैनिक आवश्यकता; सामाजिक कारण—जागृति—समझ—संगठन—नेतृत्व ।

[4] दास-मुक्ति अधिनियम : मुख्य नियम—स्वामित्व हस्तान्तरण—भुगतान प्रणाली—मीर के अधिकार ।

[5] दास मुक्ति के परिणाम : नया युग—असन्तोष में वृद्धि—कमजोर शासन—अधिनियम की त्रुटियाँ—रूढ़िवादिता पर असर—अव्यवहारिक ।

अध्याय 5. आर्थिक संगठन [1861-1917]

59

[1] रूसी कृषि [1861-1917] : पूँजीवाद का उदय—व्यापारिक

कृषि—व्यक्तिवाद का प्रसार—आवादी का भार—पुनर्वैटवारा—मीर का दूटना—किसानों के खेत—वैल्यूयेव कमीशन—बकाया कर में अपार वृद्धि, कृषि उत्पादन—उत्पादन का विकास—कुलक वर्ग का उदय—कृषक भूमि वैङ्क—भू-स्वामियों के खेत—भूमि-स्वामित्व में परिवर्तन—अन्तर्राष्ट्रीय मन्दी—व्यापारिक कृषक—विस्तृत असन्तोष—व्यापारिक-पूँजीवादी कृषि में प्रसार, पीटर स्तोलाइपिन के कृषि सुधार—जमीन की भूख—व्यक्तिगत स्वामित्व—मीर के अधिकारों में कमी—जारशाही को सहारा—असफल प्रयोग—शोषण बढ़ा—मजदूर वर्ग का निर्माण—1914 में सुधार स्थगित; प्रथम महायुद्ध का प्रभाव—श्रम, उत्पादन, मशीन की कमी—अन्न-संकट—मुद्रा-स्फीति ।

[2] रूसी उद्योग [1861-1917] : सामन्त उत्पादन का पतन—व्यापारिक पूँजीपति—पूँजी-प्रधान कारखानों का उदय—भूमि से स्वतन्त्र मजदूर वर्ग—कुटीर उद्योग का पतन—सन्तोषजनक उत्पादन कृषि—मजदूरों की शोचनीय दशा—संयुक्त पूँजी कम्पनी—उत्पादन संस्था के आकार की वृद्धि—एकाधिकार तथा संयुक्तिकरण—1910-1913 की तीव्र प्रगति ।

## द्वितीय भाग

### ध्याय 6. राज्य क्रांति

73

[1] क्रांति के समय आर्थिक स्थिति . प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, वित्त-व्यवस्था—मद-निषेध—अप्रत्यक्ष कर—मुद्रा-स्फीति का सहारा—विदेशी ऋण, उद्योग—विदेशों पर निर्भरता—राज्य की अयोग्यता—कोयले की कमी—1916 के बाद व्यापक विनाश; कृषि—राजकीय उदासीनता—अनिश्चित नीति—किसानों की सेवा में भर्ती—पशुओं की कमी—अन्न की कमी—अकाल की स्थिति—केन्द्रीय निर्देशन का अभाव—किसानों की दयनीय दशा; श्रमिक—बेकारी—मूल्य-वृद्धि—राजनैतिक प्रचार ।

[2] राज्य क्रांति : कारण—1861 के सुधार—प्रथम ड्यूमा—निकोलस द्वितीय की दुर्बलता—प्रतिनिधि शासन—प्रथम विश्व युद्ध—जार द्वारा सिंहासन त्याग—लेनिन—केरेन्स्की सरकार का पतन—बोल्शेविक पार्टी की जिम्मेदारी—‘शान्ति तथा सोवियत’—भूमि का बँटवारा—राष्ट्रीयकरण—मजदूरों द्वारा औद्योगिक प्रवन्ध—वैतनिक श्रम वर्जित ।

[3] राज्य क्रांति का प्रभाव : अनुशासनहीनता निरर्थक विध्वंस—आर्थिक अधोगति—मुद्रा-स्फीति—व्यापारिक वैङ्कों तथा पूँजी का राष्ट्रीय-

करण—विदेशी ऋण का खडन—उद्योग में अवनति—छिन्न-भिन्न याता-यात—किसानों से लेनिन की निराशा, क्रांति सबसे पहले रूस में क्यों हुई ?

### अध्याय 7. विदेशी हस्तक्षेप तथा युद्धकालीन साम्यवाद

86

[1] विदेशी हस्तक्षेप : इंग्लैंड—फ्रांस—जापान—संयुक्त राज्य अमेरिका—2/3 क्षेत्रफल—1921 में रीगा की सन्धि—लेनिन का त्रिसूत्री युद्ध ।

[2] युद्ध-कालीन साम्यवाद—घोर सकटकाल—आत्मरक्षा का उद्देश्य—व्यवहारिकता का आधार, कृषि—“शान्ति और जमीन” का नारा—किसानों का सहयोग आवश्यक—तुच्छ स्वार्थ से उत्पन्न असंतोष—सोवियत फार्म—किसानों पर प्रतिबन्ध—अनाज की अनिवार्य सरकारी खरीद तथा मूल्य निर्धारण—असाधारण आयोग, 1919,—वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन—कुलक—केन्द्रीयक—बेदव्याक—कृषि क्षेत्रफल में संकुचन—उत्पादन में कमी—पशुधन की हानि—सुधार के उपाय—शहरों से आबादी का प्रवास—आपसी बल-परीक्षा, उद्योग—हस्तक्षेप न करने की नीति—सम्पर्क के लिए अर्थ-व्यवस्था की उच्चतम समिति वर सोवनार-खोज—असहयोग—स्थानीय अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीयकरण—दिसम्बर 1918 में पूर्ण राष्ट्रीयकरण—उद्योगों में तीव्र अवनति; वित्त-संगठन—अनिश्चित नीति—कारण—मुद्रा को बन्द करने के प्रयत्न—आर्थिक सकट, व्यापार—परिस्थिति के साथ नियन्त्रण बढ़ा—व्यापार या वितरण—व्यापार तथा वर्ग संघर्ष—नारकमप्रोद्—आर्थिक बेरावन्दी—नाममात्र का विदेशी व्यापार—1920 के बाद पुनः आरम्भ

[3] युद्धकालीन साम्यवाद का प्रभाव—कोरे सिद्धान्त से वास्तविकता की ओर—पुराने सामाजिक ढाँचे का उन्मूलन—साम्यवाद का प्रयोगात्मक काल—मनोवैज्ञानिक विचार-परिवर्तन—उत्कृष्ट नेतृत्व—विस्तृत विनाश—आत्म-आलोचना की प्रवृत्ति—उत्पादन प्रेरक की आवश्यकता—1921 का क्रान्ताद विप्लव—1921 की शुद्धि [purge]—नीति परिवर्तन की लाचारी ।

### अध्याय 8—नवीन आर्थिक नीति

103

[1] जटिल समस्याओं के समाधान का प्रयत्न—नई नीति की आवश्यकता—किसान-मजदूर सम्बन्ध [Smytchka]—किसी भी मूल्य पर उत्पादन वृद्धि—स्नायु-केन्द्र पर नियन्त्रण—पूँजीवाद का निर्धनित

आह्वान—“पूर्व निश्चित नीति”—“सैद्धान्तिक हार”—“दूसरा क्षणिक विश्राम काल”—अस्थायी प्रकृति—स्तालिन का उदय—नवीन आर्थिक नीति का अन्त ।

[2] विशेषताएँ : देशी व्यापार—व्याक्तगत व्यापारी, पूँजी तथा लाभ को छूट—राजकीय व्यापार संगठन—तोर्गो, ट्रस्ट, सिण्डीकेट—केवल थोक व्यापार—फुटकर व्यापार निजी क्षेत्र में—“कैची-सकट”—1924 से स्वतन्त्रताओं का अन्त, विदेशी व्यापार—राज्य का एकाधिकार—मुख्य उद्देश्य—राष्ट्रीय उन्नति तथा राजनैतिक दबाव—संगठन—विदेशी व्यापार-मंत्रालय—सेन्कोस्यूज—सेल्कोस्यूज—विदेशों में स्क्व प्रणाली कम्पनी—1929 में नारकमतोर्ग, मुद्रा वैकिंग और वजट—पूर्ण राजकीय संचालन—मुद्रा का महत्व घटा—लेखा की इकाई व मूल्य मापन का साधन—गोस वैङ्क—कार्य-विधि—सर्वव्यापी वजट—घाटा—नई कर नीति—वस्तु ऋण तथा मुद्रा ऋण—नोट छापना; कृषि—समस्याएँ—अस्थायी उदारता—बलपूर्वक अन्न वसूली बन्द—मुद्रा में लगान—व्यक्तिगत सम्पत्ति—उत्पादन में तेज प्रसार—1925 के बाद से उदारता का प्रतिपाद, उद्योग—नीति के मुख्य सिद्धान्त—अराष्ट्रीयकरण—औद्योगिक शासन का विकेन्द्रिकरण अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप में कमी—व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तथा प्रयत्न को प्रोत्साहन—मिश्रित उत्पादन व्यवस्था औद्योगिक शासन का पुनर्संगठन—वेस्त्रा—यात्रिक संगठन—एक-व्यक्ति-प्रवध—उत्पादन में वृद्धि—व्यक्तिगत उत्पादक—विदेशियों को विशेषाधिकार—नवीन आर्थिक नीति का सैद्धान्तिक वर्गीकरण ।

अध्याय 9 सोवियत राज्य की सैद्धान्तिक रूप-रेखा

127

[1] यूरोप के विचारों का प्रभाव . साम्यवादो घोषणापत्र—कार्ल मार्क्स—मार्क्सवाद—अंग्रेज और फ्रान्सीसी विचारक—आदर्शवादी साम्यवाद—वैज्ञानिक साम्यवाद—इतिहासकार और अर्थशास्त्री मार्क्स—इतिहास की पुनर्विवेचना—आर्थिक संगठन का नया सिद्धान्त—अतिरिक्त-श्रम-मूल्य—हिंसात्मक क्रान्ति—वर्ग संघर्ष तथा वर्ग विभाजन—मार्क्सवाद तथा समाजवादी संगठन की रूपरेखा—शोपकों का शोषण—सामाजिक स्वामित्व—संयोजित उत्पादन तथा वितरण—मार्क्सवाद का विश्वव्यापी आकर्षण मार्क्स के विचारों के आधुनिक अपवाद ।

[2] रूस में मार्क्सवाद का आगमन : शून्यवादी [Nihilist] धाराएँ—नेपोलियन का आक्रमण—क्रान्तिकारी आन्दोलन का सामाजिक

रूप—मार्क्सवाद का उदय—बी० जी० प्लेखानोव—रूसी समाजवादी प्रजातंत्रात्मक मजदूरदल [ Russian Soviet Democratic Labour Party ]—बोलशेविक तथा मेनशेविक—सामाजिक क्रान्तिकारी दल—1905 की क्रान्ति—रविवार का रक्तपात—वैधानिक सुविधा और ब्यमा ।

[3] लेनिनवाद अथवा बोलशेविकवाद : मार्क्स के सिद्धान्तों का व्यवहारिक रूप—क्रियात्मक दृष्टिकोण—उत्कृष्ट अवसरवादिता—औद्योगीकरण और समुदायिक खेती, स्तालिनवाद—अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष का परित्याग—प्रबल राष्ट्रीयता—औद्योगीकरण तथा अस्त्रीकरण—कठोरता की नीति—एक वर्ग का समाज ।

[4] पूंजीवाद तथा समाजवाद : समाजवाद की श्रेष्ठता—पूर्ण आर्थिक साधन और श्रम का प्रयोग—सामाजिक आवश्यकता पूर्ति—उत्पादन की अव्यवस्था का अन्त—सामयिक संकट का नाश—श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि—निरर्थक प्रतिस्पर्धा का परित्याग—उत्पादन के साधनों का उत्पादन—समय की वचत—“जो काम नहीं करेगा वह खाना नहीं खायेगा”—मौग और पूर्ति की जगह सामाजिक आवश्यकता का सिद्धान्त—व्यक्तिगत प्रेरक—प्रतिस्पर्धा ।

[5] समाजवाद और साम्यवाद : सोवियत रूस का इस सम्बन्ध में नया प्रयत्न—राज्य सम्पत्ति और सामुदायिक फार्म की सम्पत्ति का विलयन—अविभाजनीय कोष तथा निजी जमीन का त्याग—मजदूर और किसान का एक वर्ग—पूर्ण यंत्रीकरण—बुद्धिजीवी और श्रमजीवी का भेद मिटाना—न्यूनतम और अधिकतम वेतन में समानता का प्रयत्न—वस्तु तथा मुद्रा सम्बन्ध—वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा दृष्टिकोण—सर्वव्यापी राज्य स्वामित्व—समाजवादी प्रजातंत्र का आदर्श—अस्पष्ट तथा अपूर्ण ।

अध्याय 10 अर्थव्यवस्था व आयोजन प्रणाली का संगठन

143

[1] आयोजन प्रणाली : पूंजीवादी व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न—आयोजन की परिभाषा—व्यापक रातुलन—उत्पादन के साधनों का सामुदायिक स्वामित्व—निजी सम्पत्ति का उन्मूलन—व्यक्तिगत सम्पत्ति का स्थान—सामुदायिक निर्णय तथा संचालन—राजकीय योजना आयोग—योजना समाज का पवित्र कर्तव्य—उपभोक्ताओं की रुचि, स्वार्थ संघर्ष का परित्याग—प्रमापीकरण—निर्धारित प्राथमिकताएँ—उपभोग तथा उत्पादन उद्योग—कृषि तथा उद्योग—शक्ति संचय, औद्योगीकरण, समाजवादी



संगठन का उद्देश्य: समाजवादी उत्पादन प्रणाली—प्रतिस्पर्धा—समाजवादी प्रतिस्पर्धा—प्रेरणा—आर्थिक, व्यक्तिगत प्रभाव, सामाजिक सम्मान—लाभ—बाजार की प्रणाली—लाभ का नया अर्थ [ Use value ]—पूँजी—महत्व में कमी—यत्र कौशल और प्रबन्ध का उत्कर्ष—अनुदान—बेकार करना तथा हास—मूल्य निर्धारण—समाजवादी अर्थ के नियम—व्यापार—केवल वितरण का साधन; सोवियत योजना प्रणाली में नई धाराएँ—केन्द्रीकरण—आर्थिक समितियाँ—दीर्घकालीन आयोजन—योजना का नया संगठन—क्षेत्रीय विशिष्टीकरण तथा प्रमापीकरण ।

[2] संगठन तथा प्रबन्ध [I] योजना संगठन : उच्चतम आर्थिक समिति—राज्यकीय योजना आयोग अथवा गौस प्लान—इसका कार्य क्षेत्र—राज्य तथा क्षेत्रीय योजना समितियाँ—संघीय, प्रजातंत्र राज्य और स्थानीय महत्व के उद्योग—जनवरी 1948 का पुनर्संगठन—1951 का परिवर्तन—योजनाओं का परिवर्तनशील स्वभाव,

[II] औद्योगिक उत्पादन संगठन तथा प्रबन्ध : औद्योगिक व्यवस्था की विशेषताएँ—अनुशासन शक्ति—राज्य शक्ति का पूर्ण केन्द्रीकरण—कठोर आधिपत्य—अधिकार प्राप्त छोटा-सा समूह—कार्य क्षेत्र जीवन है, जीवकोपार्जन का साधन नहीं—सद्धान्तीकरण—व्यक्तिवादी विचारों का समूल विनाश—बहुसूत्रीय प्रबन्ध व्यवस्था—अन्यन्त जटिल संचालन संगठन—1934 का प्रबन्ध सुधार—एक व्यक्ति प्रबन्ध, निर्णय की स्वतंत्रता, बाहरी हस्तक्षेप में कमी, उत्पादन का क्षेत्रीय संचालन अर्थात् केन्द्रीय औद्योगिक प्रबन्ध समिति, प्रत्येक कारखाना एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई; सोवियत कारखाना संगठन—त्रिसूत्रीय प्रबन्ध व्यवस्था—कारखाना प्रबन्धक—कारखाना साम्यवादी दल संगठन—कारखाना श्रमिक संघ समिति, अपूर्ण निर्माण कार्य—उत्पादन संगठन का गभीर असंतुलन—विशाल अपव्यय—अनावश्यक देरी—इसके कारण,

[III] कृषि उत्पादन संगठन तथा प्रबंध : कृषक और राजनीति के आधार—सामुदायिक संगठन—किसानों के त्याग से औद्योगीकरण, कृषि संगठन—तोड़—आरटेल—कम्यून—सामुदायिक फार्म या कोलखोज—राजकीय फार्म या सोवखोज—मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन, कोलखोज—विशेषताएँ—उद्देश्य—भूमि—उत्पादन के साधन—सदस्यता—भूमि तथा पशु के उत्पादन का प्रयोग—वार्षिक आय का बँटवारा—संगठन—ब्रिगेड तथा ज्विनो—1950 की नीति—भुगतान—कार्य-दिवस का काल्पनिक

माप—1933 तथा 1948 का वर्गीकरण—आन्तरिक प्रबन्ध—अकेक्षस समिति—प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्त तथा स्वशासन—राज्य का प्रभाव—संचालन स्थापना—कम्युनिष्ट पार्टी का प्रभाव—1950 की नीति—विशाल कृषि नगर, सोवखोज—विकास—सैद्धान्तिक जोश—पुराने सामंतों के खेत—नई भूमि पर कृषि—वर्गीकरण—महत्व—सोवखोज और कोलखोज में अंतर, संगठन तथा प्रबंध—सोवखोज मंत्रालय—एक-व्यक्ति-प्रबन्ध—लागत लेख प्रणाली—1954 के परिवर्तन—राजकीय अनुदान वृद्धि—आत्मनिर्भरता—नई मूल्यनिर्धारण पद्धति मशीन-ट्रेक्टर स्टेशन [मट्रस]—याचिक सहायता—अन्य सभी सहायताएँ—राजकीय निर्देशन का साधन—1947 मट्रस केन्द्रीय बोर्ड; कृषि आयोजन में नई धाराएँ—स्तालिन की मृत्यु के बाद—कोलखोज की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध—राजकीय संचालन में वृद्धि—कृषि में उद्योग के सिद्धान्त—कोलखोज और मट्रस का विलयन—सामुदायिक तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति का एकीकरण—अन्य कोलखोज विनियोग—व्यक्तिगत भूमि तथा पशु का अंतर—आर्थिक साधन तथा वेतन प्रणाली में 1953 तथा 1956 के परिवर्तन ।

[IV] श्रमिक संघ संगठन तथा प्रबंध—श्रमिक संघ का नवीन अर्थ—राज्य तथा श्रमिक संघ—श्रमिक नियम—अनुशासन तथा सामाजिक सुरक्षा प्रबन्ध, श्रमिक संघ का विकास—1905 का विद्रोह—घटना महत्व तथा संख्या—ऐच्छिक सदस्यता—प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीयकरण [Democratic Centralism] द्वारा संचालन—सामुदायिक समझौता—अखिल सोवियत श्रमिक संघ की केन्द्रीय समिति [A. U. C. C. T.-U.]—श्रमिक संघ के कार्य—1957 में वैधानिक कार्य निर्धारण—समाजवादी प्रतिस्पर्धा—श्रमिक उत्पादकता—योजना पूर्ति—लागत में कमी—सामुदायिक समझौता—सामाजिक बीमा—मजदूरों का प्रतिनिधित्व ।

## अध्याय 11 : रूसी योजनाएँ

183

[1] गोयलरो योजना : संसार की प्रथम देशव्यापी योजना—विद्युतकरण—राजकीय विद्युतकरण आयोग अथवा गोयलरो—विजली उत्पादन वृद्धि ।

[2] प्रथम पंचवर्षीय योजना [1928-1932] : छः वर्ग का परिश्रम—ग्राम उद्देश्य—समाजवाद की स्थापना—उत्पादन वृद्धि—मजदूरों

की दशा सुधार—नवीन आर्थिक नीति का पुनर्संगठन—विकास का औद्योगिक ढाँचा—कृषि का समूल परिवर्तन—विकास का किसानों पर बोझ—किसान-मजदूर सहयोग का अन्त—संचालित एवं असंचालित लक्ष्य पूर्ति; कृषि—पूँजीवादी प्रवृत्ति का उन्मूलन—व्यक्तिगत स्वामित्व—प्रथा—अन्य स्वतन्त्रताएँ—बड़ी कृषि इकाइयाँ—सामुदायिक खेती—कुलक वर्ग का विनाश—कृषि का यंत्रीकरण—किसानों द्वारा विरोध—“सफलता का उन्माद” [Dizzy with Success]—नवीनतम आर्थिक नीति (Newest Economic Policy)—प्रभाव—व्यापक पशु-वध—1931-32 का अकाल—स्तालिन क्रान्ति; पूँजीनिर्माण—पूँजी विनियोग की मात्रा—30.1% वृद्धि—विनियोग का अर्थव्यवस्था में वितरण—उद्योग—शक्ति—यातायात—कृषि—राजकीय क्षेत्र—सामुदायिक क्षेत्र—व्यक्तिगत क्षेत्र—उद्योग—आर्थिक आत्म-निर्भरता—मैनिक शक्ति—उत्पादन वृद्धि—इसके कारण—लागत घटी—किस्म खराब—विद्युतकरण पर जोर—गतिशील योजना लक्ष्य, श्रम—वेकारी का उन्मूलन—मजदूरों की कमी—प्रवास की प्रवृत्ति—कुशलता तथा अनुभव—प्रशिक्षण—समाजवादी प्रतिस्पर्धा—कठोर अनुशासन—वैज्ञानिक प्रचार, व्यापार—उपभोग पर नियंत्रण—राजकीय षट्कारा—काम का महत्व व मात्रा के अनुसार वितरण, संचिप्त समीक्षा—सन्तुलन को कमी—प्रतिष्ठा वृद्धि—अधूरे काम—हास—आकार—प्रियता—मूल्य-वृद्धि—यातायात अविकसित—आंशिक सफलता।

[3] द्वितीय पंचवर्षीय योजना [1933-1937]: राष्ट्रीय शुद्धि [National purge]—जर्मनी का पुनः जागरण—युद्ध का भय, उद्योग—पैनिश शक्ति के लिए औद्योगीकरण—अधूरे निर्माण की पूर्ति—पूँजी का महत्व घटा—प्रमापीकरण—यांत्रिक कुशलता तथा प्रशिक्षण—श्रमिक कुशलता तथा प्रवृत्ति में सुधार—“सब निर्णय कर्मचारी करें”—स्तालिनोव आन्दोलन—आर्थिक लाभ की आवश्यकता—व्यक्तिगत प्रयत्न—समान वेतन के सिद्धान्त का परित्याग—उपभोग का उत्पादन बढ़ा—निम्न कोटि का उत्पादन—सुधार के प्रयत्न, कृषि—समाजवादी संगठन की पुष्टि—राशनिंग समाप्त—कृषि आरटेल के आदर्श नियम—अनाज वस्ती में सुधार—कुलक वर्ग उन्मूलन—व्यक्तिगत सम्पत्ति की आशा—“समस्त सामुदायिक किसानों को समृद्धिशाली बनाओ”—सैद्धान्तिक प्रचार का विस्तार।

[4] तृतीय पंचवर्षीय योजना [1938-1942] : साहसपूर्ण तथा व्यापक दृष्टिकोण—यातायात की उन्नति—वैज्ञानिक स्थानीयकरण नीति—सुरक्षा तथा शस्त्र उद्योग पर ध्यान—इनमें गुण का सुधार—पूँजी विनियोग—उत्पादन वृद्धि—समाजवादी प्रतिस्पर्धा में विस्तार—आर्थिक पारितोषिक—श्रम-उत्पादकता में सुधार—औद्योगिक प्रबन्ध में सुधार—कारखाने की आत्म-निर्मरता—मौद्रिक मूल्यांकन—व्यवस्थित लेखा-प्रणाली—लाभपूर्ण उत्पादन—अंतर-कारखाना विनियोग को प्रोत्साहन—कुछ कमजोरियों—अफसरशाही—तत्कालीन निर्णय व उत्तरदायित्व—संतुलन तथा सम्पर्क—1940 में योजना स्थगित—प्रगति का अनुमान

[5] चतुर्थ पंचवर्षीय योजना [1946-1950] : उद्देश्य—पुनर्निर्माण—1939-40 का उत्पादन स्तर प्राप्त करना—इससे अधिक प्रगति—यातायात—उद्योग—रगत तथा लोहा पर जोर—विद्युत—कृषि में युद्ध से हानि—लक्ष्य तथा पूर्ति ।

[6] पंचम पंचवर्षीय योजना [1950-1956] : विश्व युद्ध के प्रभाव को मिटाने का प्रयत्न—पुरानी परिपाटी—सुरक्षा—भारी उद्योग—यांत्रिक प्रगति—उत्पादन वृद्धि—पूँजी विनियोग—योजना पद्धति में उन्नति—आर्थिक निर्णय का विकेन्द्रीकरण

[7] छठवीं पंचवर्षीय योजना [1956-1960] : स्तालिन पद्धति की अंतिम योजना—1957 में संशोधित—1958 में स्थगित—स्वयंचालित यंत्रों [automation] का प्रयोग—उपभोग की वस्तुओं पर जोर—अव्यवहारिक लक्ष्य ।

[8] सप्तवर्षीय सातवीं योजना [1959-1965] : अवधि बढ़ी—आधारभूत परिवर्तन—उद्देश्य—भारी उद्योग—शान्तिपूर्ण आर्थिक प्रतिस्पर्धा—प्राकृतिक साधनों की खोज तथा विकास—यांत्रिक कुशलता पर जोर—श्रमिक-उत्पादकता—रहन-सहन के स्तर में विकास—साम्यवाद की स्थापना, पूँजी निर्माण तथा विनियोग—विलक्षण पूँजी विनियोग का आकार—वर्तमान कारखानों का आधुनिकरण—सराहनीय यथार्थवादिता—प्राथमिकताएँ—विकास में सामंजस्य—उत्पादन में विशिष्टीकरण—लागत लेखा आधार, कृषि—उत्पादन वृद्धि से समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति—भोजन—कच्चा माल—कोलखोज व राजकीय खेत का विलयन—राजकीय फार्म के उत्पादन का विशिष्टीकरण—लागत में कमी—पूर्वी प्रदेश की नई भूमि का विकास—पशु पालन—यत्र एवं बिजली का प्रयोग—कृषक

श्रम-उत्पादकता की वृद्धि—किसान-मजदूर का विलयन—कृषि में समाजवादी प्रतिस्पर्धा; उद्योग—पूर्ववत आधार— भारी उद्योग—रसायनिक उद्योग—विजली—उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन—उत्पादन प्रणाली में सुधार; यातायात—रेल तथा वायु यातायात—पूर्वी प्रदेशों में विस्तार—तेल-वाहन में सुधार; जन-कल्याण—आर्थिक प्रेरणा—उपभोग-क्षमता—वास्तविक आय में वृद्धि—वेतन प्रणाली में सुधार—सामाजिक सुरक्षा—समाजवादी उत्पादन क्षेत्र ।

अध्याय 12. अर्द्ध-विकसित देशों के लिए रूसी आर्थिक विकास का संदेश :

233

रूस की महत्ता—राजनैतिक पृष्ठभूमि की कालिमा—रूसी विकास का परिणाम—सफलता का कारण—स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी अधिकतर अच्छे शान्तिकालीन राज्य-कर्मचारी तथा अनुशासनपूर्ण नागरिक नहीं होते—कम समय में प्रगति का साधन राजकीय पूँजीवाद—मिश्रित अर्थ-व्यवस्था—अल्पकालीन तरीका—व्यक्तिगत प्रयत्न की जगह केन्द्रीय संचालन, स्वामित्व तथा निर्देशन—योजना का सामाजिक आधार—सफलतापूर्वक योजना को लागू करना सबसे आवश्यक—वित्तीय योजना तथा उत्पादन योजना का सन्ध—विशालता अथवा आकार-प्रियता का डर—प्रतिष्ठा आयोजन—श्रम सम्बन्धी संदेश ।

परिशिष्ट 1. सोवियत रूस का यातायात संगठन :

238

रेल-यातायात—नदी यातायात—समुद्र यातायात—वायु यातायात—मोटर तथा सड़के ।

परिशिष्ट 2 रूस में सामाजिक सुरक्षा :

245

स्वास्थ्य सेवाएँ—सामाजिक पोषण [Social maintenance] सामाजिक बीमा—अनिवार्य सामाजिक बीमा—ऐच्छिक सामाजिक बीमा—अन्य सामाजिक बीमा—सोवियत सामाजिक सुरक्षा की विवेचना—आलोचनाएँ—विशेषताएँ—आँकड़े ।

## अध्याय १

# आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि

### सोवियत रूस के प्राकृतिक साधन

भौगोलिक परिस्थितियों को राष्ट्रीय विकास का मुख्य अथवा निर्णायक कारण तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह निर्विवाद रूप से प्रगति की स्थायी आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमरीका के बाद सोवियत रूस के अतिरिक्त कोई ऐसा देश नहीं है जिसे प्रकृति ने मुक्तहस्त दान दिया हो। प्रचुर प्राकृतिक साधन, विस्तृत उपजाऊ प्रदेश तथा हर प्रकार की जलवायु रूस की विशेषता है। विशाल नदियाँ और प्रशस्त समतल भूमि के क्षेत्र यातायात के लिये आदर्श है। बहुत पुष्ट शरीर के अत्यन्त मेहनती लोग यहाँ बसते हैं। 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 20 करोड़ से कुछ अधिक आबादी है जिसका 43% तो शहरों में रहता है और 57% ग्रामीण जनता है। 15 प्रजातंत्र राज्यों के सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ [The Union of Soviet Socialist Republics : U. S. S. R.] की जनता को तीन सामाजिक वर्गों में विभाजित किया जाता है : कारखाना, आफिस तथा अन्य कर्मचारी 58.3%; सामुदायिक तथा सहकारी किसान व कारीगर 41.2%, और व्यक्तिगत किसान तथा कारीगर जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं 0.5%। तीसरे वर्ग में लगभग 10 लाख व्यक्ति रखे जाते हैं।

योरप और एशिया में फैले हुए इस देश का उत्तरी भौग शीत-कटिबंध में पड़ता है। योरप में स्वीडन से लेकर एशिया में बेरिंग समुद्र तक का भाग अधिकतर बर्फ का रेगिस्तान है। अगर यह छोटा-सा समुद्र बीच में जमीन काट न देता तो संयुक्त राज्य अमरीका का अलास्का राज्य रूस को छूता होता। उत्तर से दक्षिण तक 2700 मील और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 7000 मील तक फैले इस देश का आकार संयुक्त राज्य अमरीका का तीन गुना अथवा सप्ताह की भूमि का  $\frac{1}{7}$  भाग है। इतने बड़े क्षेत्रफल का  $\frac{1}{6}$  हिस्सा सदा बर्फ से ढका रहता है। यूराल, काकेशस, मध्य-साइबेरिया के पठार मुख्य पहाड़ी क्षेत्र हैं। इनसे निकली नदियाँ यातायात और सिंचाई के लिये प्रसिद्ध हैं। खास नदियों में कामा, दिना, नीपर, नेस्तर, डान, वोल्गा, ओबी, यनीसी तथा लीना आती हैं।

### औद्योगिक साधन

औद्योगिक शक्ति [industrial power] के क्षेत्र में आधुनिक उन्नति करने के लिये रूस के पास पर्याप्त कोयला, तेल, जल-विद्युत [Hydro-electricity] लकड़ी का कोयला और गैस पाई जाती है। इनमें से कोयले का महत्व अभी भी काफी है। पश्चिमी-दक्षिणी प्रदेश अथवा दोनेत्स् घाटी, पूर्वी दक्षिणी साइबेरिया में कज़नेत्स्क घाटी और करागान्दा घाटी प्रमुख कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं। इसके बाद जल-विद्युत का स्थान आता है। पथरीले प्रदेशों पर साल भर बहने वाली तेज नदियों के भरने इतने काफी हैं कि जलविद्युत की उत्पादन क्षमता में रूस को सबसे ऊँचा स्थान दिया जाता है। 280 मिलियन किलोवाट जलविद्युत शक्ति होने पर भी इसका बहुत कम अंश प्रयोग में लाया गया है। पेट्रोल का कोष भी रूस में सब से ज्यादा है। काकेशस प्रदेश में बाकु, ग्राजनी, और क्यूबन के अतिरिक्त यूराल और वोल्गा नदी के बीच विशाल तेल-भंडार का पता चला है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से तेल के उत्पादन में 60% से अधिक उन्नति की गई है। गैस के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयत्न हाल में शुरू हुआ है। इसमें भी देश के पास काफी बड़ा भंडार है। सब से सस्ती शक्ति का साधन होने के कारण इसका प्रयोग बढ़ता ही जायगा।

खनिज पदार्थों में रूस के पास अपार भंडार की आशा की जाती है। कुछ विश्वस्त अनुमानों द्वारा संसार का 64% पोटैशियम, मैंगनीज, और फास्फेट के साथ 35% पेट्रोल और 53% लोहा है। धातु उत्पादन में सब से अधिक महत्व लोहे को दिया जायेगा। काकेशस पहाड़ के आस-पास क्रीमिया और युक्रेन प्रदेश में 60% तथा यूराल प्रदेश में 30% रूस का कोयला-भंडार मिलता है। जिंक, सीसा, अल्म्युनियम, ताँबा और पीतल भी वर्तमान आवश्यकता से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनके अतिरिक्त अत्यन्त मूल्यवान धातुएँ जैसे, पारा, ऐन्टीमनी और यूरेनियम इत्यादि की कोई खास कमी होने का अनुमान नहीं मिलता। सोने के बारे में आँकड़े तो प्रकाशित नहीं होते किन्तु यह आशा की जाती है कि रूस की गिनती सफ़र के सबसे बड़े सोना उत्पादक देशों में होनी चाहिये।

### कृषि-साधन

कृषि के उत्पादन के लिये तापक्रम, वर्षा और मिट्टी आवश्यक बातें हैं। अधिकतर रूस, कनाडा और संयुक्तराज्य अमरीका के समानान्तर पड़ता है। इसलिये कृषि के उपयोगी जलवायु व विस्तृत समतल भूमि के कारण कृषि की प्रायः सभी मुख्य वस्तुएँ यहाँ पैदा की जाती हैं, जैसे, गेहूँ, जौ, ओट्स [Oats], फ्लेक्स, चुकन्दर, कपास और तेलयुक्त बीज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। विषुवत् रेखीय जलवायु के गर्म और नम प्रदेशों में होने वाली उपज जैसे, खर और मसाले, यहाँ नहीं होती।

1955 में 286 मिलियन हेक्टर भूमि पर खेती की जाती थी। यह करीब-करीब रूसी क्षेत्रफल का एक तिहाई हिस्सा हुआ। बचे हुए दो-तिहाई भाग खेती के लिये अनुपयुक्त है क्योंकि यह अधिकतर जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ या दल-दल है। वैज्ञानिक साधनों से इसके बहुत बड़े अंश को पॉन्चवीं और छठवीं योजना में खेती योग्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। देश के योरोपीय भाग में दूर तक फैले हुए काली मिट्टी के प्रदेश सबसे उपजाऊ हैं। औद्योगीकरण के साथ-साथ औद्योगिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न लगातार किया जा रहा है।

पश्चिमी साइबेरिया, कजाखस्तान और यूक्रेन प्रदेश में पशु-पालन के केन्द्र हैं। रूसी कृषि में पशुपालन का महत्व बहुत अधिक है। जंगलो से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में रोयेदार खाल सब से महत्वपूर्ण है। पूर्वी साइबेरिया और उत्तर का भाग रोयेदार खाल के लिये संसार के बाजार में प्रसिद्ध है। सबसे आसानी से प्राप्त और सस्ता भोजन का साधन मछलियाँ होती हैं। कैस्पियन सागर में मछलियाँ इतनी अधिक मिलती हैं कि उसे 'मछली का तालाब' [fish pond] के नाम से पुकारा जाता है। घनी आबादी के निकट होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया। सुदूर पूर्व में कमचत्का का किनारा, आमूर का डेल्टा और दक्षिणी शाखालीन में विख्यात हेरिंग और सेमन मछलियाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिलती हैं। आर्कटिक महासागर पर मरमन्स्क के 'अलावा काला सागर और अजोव सागर भी मछलियों का अच्छा भंडार है।]

अन्त में यह कहा जा सकता है कि रूस के विकास में प्रकृति का इतना सहयोग होने पर, वहाँ के मजबूत और परिश्रमी जनता ने इसका पूरा लाभ समाजवादी सरकार के अन्तर्गत उठाया। इसी कारण पिछले तीस वर्षों में सोवियत रूस संसार में सब से ऊपर पहुँचने के इतने नजदीक आ गया है।

## राजनैतिक विकास

इतिहास को क्रमबद्ध परिवर्तनों का एक लेखा कहा जा सकता है। यह आवश्यक है कि किसी भी देश के वर्तमान का अध्ययन करने के लिए प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिहास को भी देखा-जाय। एशिया और योरप के बीच बसा यह देश, इन दोनों महाद्वीपों की अच्छाईयों तथा बुराईयों का अजीब मिश्रण है। इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाते कि रूस सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से एशिया के अधिक निकट है या योरप के।

आरम्भ में यह बराबर बदलती हुई जातियों का देश था। यह जातियाँ अधिकतर एशिया से आईं। ऐतिहासिक प्राथमिकता के साथ विशेष उल्लेखनीय इस्काइथियन [Scythian] जाति है। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में



इनका अधिपत्य जम चुका था। कृषि तथा पशुपालन मुख्य धंधा था। कई प्रकार के गुलाम रखने की प्रथा भी पाई जाती थी। इनके बाद कई जातियों का उदय हुआ किन्तु उनका कोई स्थायी प्रभाव न पड़ा। लगभग पाँचवीं शताब्दी के निकट स्लाव [ Slav ] जाति का बढ़ता हुआ अस्तित्व दिखलाई पड़ता है। इनकी उत्पत्ति के बारे में काफी मत-भेद है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि यह जाति एशिया से आई और डेन्यूब नदी के किनारे-किनारे दूर तक फैल गई। दूसरे विचारक इनको रूस के दक्षिणी-पूर्वी भाग का आदिम निवासी मानते हैं। सामाजिक संगठन छोटे-छोटे समूह [ Clans ] से शीघ्र ही, सैनिक जत्थों में बदल गया। खेती, पशुपालन और युद्ध इनका काम था।

सातवीं शताब्दी में स्लाव लोग तीन शाखाओं में विभक्त होकर बिखर गये। इनके प्रवास की दिशा थी—पश्चिम में वर्तमान जर्मनी-पोलैण्ड क्षेत्र; पूर्व में नीपर और वाल्गा नदी के किनारे-किनारे; दक्षिण में कारपेथियन पर्वत और उसके पार बाल्कन प्रदेश। इनमें से पूर्वी शाखा सबसे अधिक संगठित और क्रियाशील थी। इसी का नाम “रूस” [ Russ ] या रूसी स्लाव पड़ा। 1000 ईस्वी के निकट यह जाति बाई-जेन्टाइन [ Byzantine ] साम्राज्य के सम्पर्क में आई। ईसाई धर्म के साथ-साथ बाइजेन्टाइन भाषा, लिपि और सभ्यता स्लाव लोगों ने स्वीकार किया। स्लाव जाति का शारीरिक बल और परिश्रम, बाइजेन्टाइन कूरता, तानाशाही और विकसित मानसिक शक्ति के साथ मिलकर, आने वाली रूसी जाति के गुणों का निर्माण होने लगा।

1236 से 1480 तक रूस मंगोल जाति के प्रभुता में रहा। चंगेज खाँ के एक निकट सम्बन्धी ने बवडर की तरह रूस पर हमला किया और देखते-देखते सारे योरोप पर छा गया। इन मंगोल आक्रमणकारियों को रूसी “टारटार” कहते थे। लगभग ढाई सौ साल का मंगोल राज्य रूसी समाज, विचारधारा, कार्य-प्रणाली, राजनीति तथा सभ्यता पर अमिट छाप छोड़ गया।

भिन्न-भिन्न जातियों से भरा हुआ यह विशाल प्रदेश धीरे-धीरे संगठन, शक्ति और स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर हुआ। मास्को का छोटा-सा राज्य कई सदियों से सामन्त-वादी राज्य के रूप में चला आ रहा था। व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने से मास्को नगर का विकास बराबर होता रहा। आगे चलकर रूस के राष्ट्र-निर्माण का यह केन्द्र-बिन्दु सिद्ध हुआ। अनेक उपायों द्वारा मास्को के शासकों ने मंगोल खानों [ Khans ] से विशेष सुविधाएँ प्राप्त कर रखी थी। मास्को के प्रतापी शासक आइवन तृतीय [1462-1505] ने 1480 में मंगोल साम्राज्य की रही-सही शक्ति को नष्ट कर दिया। इस प्रकार प्रथम स्वतन्त्र रूसी राज्य की स्थापना हुई। आइवन चतुर्थ [1533-1584] ने “जार” की पदवी ग्रहण किया और छोटे-छोटे राज्यों को मास्को के केन्द्रीय शासन में मिलाना आरम्भ किया। विजय और विलियन का यह क्रम आइवन चतुर्थ की ही देन

थी। इसकी दृष्टि एशिया की ओर भी गई। कजान [1552] और अस्त्राखॉ [1556] के समृद्धिशाली शहरों को जीतकर, इस विलक्षण जार ने प्रशान्त महासागर तक एशिया के विजय का रास्ता साफ कर दिया।

1613 में माइकेल रोमानोव ने मास्को में रोमानोव वंश की स्थापना किया। इनके तीन सौ सालों के राज्य काल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि राजा और प्रजा के बीच का अन्तर बराबर बढ़ता गया। समाज दो स्पष्ट वर्गों में बंट गया—आश्चर्य-जनक धनी और विलासी उच्चवर्ग तथा अवर्णनीय दरिद्रता से घिरा हुआ कृषि-दास वर्ग। रूसी इतिहास का युगप्रवर्तक इस वंश के महान् सम्राट् पीटर प्रथम [1689-1725] को माना जाता है। इस छः फुट नौ इंच लम्बे, अद्भुत शारीरिक शक्ति वाले शासक में पाशविकता, दूरदर्शिता, कूटनीतिज्ञता, कार्य-कुशलता और संगठन की विलक्षण क्षमता थी। देश को रूढ़िवादिता से निकाल कर आधुनिकता की ओर बढ़ाने का सारा श्रेय महान् पीटर को ही है। यह प्रथम रूसी सम्राट था जो योरोप के देशों में गया और उनकी उन्नति के नमूने और तरीके को देखा। पीटर के शासनकाल में रूस की सभी दिशाओं में उन्नति हुई। यूरोपवाद की एक ऐसी लहर देश में आई, कि पहली बार जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैण्ड की विचारधाराओं, सामाजिक संगठन और औद्योगिक विकास के ढाँचे में रूस अपने आपको बदलने की कोशिश करने लगा। विदेशों से राज-नैतिक और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, साम्राज्य की सीमा को समुद्र तट तक बढ़ाने के लिए पीटर जीवन भर युद्ध में लगा रहा। उत्तर के श्वेत सागर एवं बाल्टिक सागर और दक्षिण में काला सागर, कैस्पियन सागर और अजोव सागर इनके लक्ष्य थे।

पूँजीवादी औद्योगीकरण पीटर की सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। योरप में उस समय प्रचलित वाणिज्यवाद के सिद्धान्तों ने सम्राट को बहुत ही प्रभावित किया था। यह कहना तो उचित नहीं होगा कि रूसी औद्योगीकरण का सूत्रपात्र ही पीटर ने किया। किन्तु पीटर के ही कारण राजकीय संरक्षता और प्रेरणा से उद्योगों की उन्नति में नया जोश, नया चिन्तार, नया तरीका, नया संगठन, विदेशी कारीगर और पूँजी आई। व्यक्तिगत पूँजीवाद की मदद से उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक पूँजी, विशेष सुविधाएँ और टैरिफ सरक्षण राज्य ने पूरी तरह किया। राज्य को इस दिशा में इस सीमा तक अग्रसर करने के मूलतः दो कारण थे—पीटर ने स्पष्ट रूप से यह देखा कि उसकी सैनिक विजय देश में सैनिक सामान के प्रचुर उत्पादन पर ही निर्भर करती है; इसके अतिरिक्त यूरोप भ्रमण ने पीटर को विश्वास दिला दिया कि देश की संवृद्धि खेती से नहीं, उद्योगों से होगी।

पीटर की मृत्यु के बाद कई सम्राज्ञियों ने राज्य किया—कैथरीन प्रथम [1725-27], अन्ना [1730-40], एलिजाबेथ [1741-62] और कैथरीन द्वितीय [1762-1796] जिसको महान् कैथरीन भी कहा जाता है। इनके राज्यकाल के करीब-करीब हर क्षेत्र में पीटर की नीति को ही आगे बढ़ाया गया। एलिजाबेथ ने प्रथम रूसी विश्व-विद्यालय स्थापित किया [मास्को विश्वविद्यालय-1755]। कैथरीन द्वितीय इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली शासक थी। अपने 34 साल के राज्यकाल में उसने पीटर प्रथम के करीब-करीब सभी अधूरे कामों को समाप्त किया। पृथक्वाद की सकीर्णता को दूर करने के लिए कैथरीन ने यूरोप के प्रमुख दार्शनिक, कलाकार, कुशल कारीगर, वैज्ञानिकों और राजनीतिज्ञों को अपने दरबार में आकर्षित किया। संभव था कि रूस कैथरीन के निर्देशन में सचमुच योरोप से मिल जाता किन्तु फ्रान्स की राज्य क्रान्ति ने इस दिशा की प्रगति को एकदम रोक दिया। रूस के शासक वर्ग को विश्वास हो गया कि उदार विचारधाराये ही क्रान्ति को जन्म देती हैं।

कैथरीन द्वितीय के बाद पूरी 19 वीं शताब्दी में कोई भी उसके कोटि का शासक न हुआ। देश में अमीर और गरीब, वंशपरम्परानुगत सामंत तथा किसान के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। शासन भी एक चुने हुए कृपापात्र वर्ग के हाथ में था। भूमि के साथ बंधा हुआ किसान अब स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगा। पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के प्रथम विकास की अत्याचारपूर्ण कमजोरियों ने मजदूरी करने वाले किसानों में भी घोर असंतोष पैदा किया। निकोलस प्रथम [1825-55] के राज्यकाल में करीब 600 स्थानीय विद्रोह हुए जिनको अत्यंत क्रूरता से दबा दिया गया। यह दशा इतनी गिरावटी कि अलेक्जेंडर द्वितीय [1855-81] ने बड़े पैमाने पर सुधार करने की कोशिश की। 1861 में रूसी किसान अपने बहुत से बन्धनों से मुक्त कर दिये गये। यह सुधार पूरी तरह लाभदायक न हो सके; क्योंकि स्वार्थी एवं प्रभावशाली सामंतों ने ज़ार को इनमें कई बड़ी कमजोरियाँ छोब देने को बाध्य किया। अतएव यह हुआ कि इस उमड़ते हुये असंतोष का निशाना ज़ार स्वयं बना। 1881 में उसकी हत्या कर दी गई। अंतिम ज़ार निकोलस द्वितीय [1894-1917] रोमानोव वंश के शताब्दियों के अत्याचार और जनता के क्रोध का बोझ अपने कमजोर कंधों पर उठाने के लिए सर्वथा अयोग्य था। 16 जुलाई 1918 में इस वंश का प्रकाशहीन अंतिम दीपक साम्यवादियों द्वारा सदा के लिए बुझा दिया गया।

1917 की राज्य क्रान्ति के बाद शासन की बागडोर लेनिन [V. I. Lenin] के हाथों में आई। इस चमत्कारी विचारक तथा राजनीतिज्ञ ने रूस में एक नये सामाजिक संगठन की नींव डाली जो अपने तरीके का पहला प्रयोग था। लेनिन को वास्त-

विक रूप में तानाशाह नहीं कहा जा सकता। इस पर लोगों की अपार आस्था थी लेकिन शासन में यह अकेला न था। तानाशाही की नींव इसके उत्तराधिकारी जोसेफ स्तालिन ने डाली। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद धीरे-धीरे शक्ति संग्रह करने के प्रयत्न में, स्तालिन ने अपने सब प्रतिद्वन्द्वियों को मार्ग से हटा दिया। 1929 तक वह एकछत्र तानाशाह बन बैठा। अपनी योग्यता और लगन से 1952 तक के शासन काल में इसने रूस को अत्यन्त शक्तिशाली एवं आधुनिक देश में बदल दिया। स्तालिन की मृत्यु के बाद एक साथ कई व्यक्ति राज्यशक्ति पाने के लिये प्रयत्न करने लगे। लेकिन अंत में निकिता ख्रुश्चेव की विजय हुई। ख्रुश्चेव का जन्म 1894 में कर्स्क के पास के एक गाँव में हुआ था। खान में काम करते वाले एक मजदूर का पुत्र होने से विशेष शिक्षा बिना इसने भी कोयले की खान में कम उम्र से मजदूरी शुरू किया। अत्यन्त चपल और चालाक होने के कारण मजदूरों के स्कूल में पढ़ने के लिये चुना गया। 35 वर्ष की आयु में मास्को औद्योगिक विद्यालय में भर्ती होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उसे अवसर मिला। तेज बुद्धि और कुशल राजनैतिक दावपेच से 1930 तक ख्रुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टी में अत्यन्त महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका था। शक्ति प्राप्त करते ही स्तालिन के प्रभाव को बटाकर ख्रुश्चेव ने राष्ट्र की दकती हुई प्रगति को नया जीवन दिया।

### सामाजिक विकास

सामाजिक दृष्टि से रूसी जनता को दो वर्गों में रखा जा सकता है : शासकवर्ग तथा शासितवर्ग। यह वर्गीकरण इसलिये आवश्यक है कि रूसी इतिहास रूसी सरकार का इतिहास है जिसमें आम जनता के जीवन, विचार और अभिलाषाओं की कोई छाप नहीं मिलती। संसार में शायद और कहीं भी राजा और प्रजा के बीच इतनी अधिक दूरी नहीं पाई जाती। इसका कारण यह है कि इस देश में शासक जनता पर राज्य जरूर करते हैं किन्तु वे कभी भी उनका एक अंग नहीं बन सके। रूसी इतिहास के अध्ययन से उच्चतम वर्ग के छोटे से समूह के अतिरिक्त जनता की इच्छाओं की कोई अनुभूति नहीं होती। इस सामाजिक संगठन से परिचित न होने पर आर्थिक इतिहास की बहुत-सी बातें साफ समझ में नहीं आती।

रूसी समाज आदिकाल से ही शोषण के वातावरण में रहता आया है। सेनाधिकारी, धर्माधिकारी और राज्याधिकारी सभी शोषण के कार्य में सहयोग देते रहे। इस बात ने रूसियों के चरित्र पर गहरा प्रभाव डाला। सदियों से चले आते हुए धार्मिक और राजनैतिक शोषण ने आम जनता को वेबसी और गरीबी से इतना तोड़ दिया कि वे भाग्यवादी बन गये। परिवर्तन की आशा और प्रयत्न दोनों ही उन्हें बेकार दिखने लगा। पादरी तथा जार का षड्यन्त्र इतना सफल रहा कि—[1] जनता के मन में

अटल विश्वास पैदा हो गया कि शासक और उसके कर्मचारियों को राज्य करने का दैवी अधिकार प्राप्त है। उसे बदलने की कोशिश ईश्वर के प्रति घोर पाप होगा। [२] पादरी उनके आत्मा का स्वामी और स्वर्ग का द्वारपाल होता है। उसकी कृपा किसी भी मूल्य पर पाना आवश्यक है। (बन देकर स्वर्ग में स्थान सुरक्षित कराने की प्रथा बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक पाई जाती थी)। इस प्रकार जनता की धर्म-भीरु, भाग्यवादी प्रकृति में साम्यवादी नेताओं के सफलता का एक खास कारण छिपा है।

शिक्षित बुद्धिवादी वर्ग [The Intelligentia] का शासन से निकट सम्बन्ध जरूर था किन्तु उन्हें अपने प्रगतिशील विचारों को व्यवहारिक रूप में लाने का अवसर कभी नहीं मिला। इसका प्रभाव यह पड़ा कि साहित्य और वाद-विवाद में विचारों का जो ऊँचा स्तर पाया जाता था, वह केवल कोरा सिद्धान्त बनकर पड़ा रहा। पिछड़ी हुई जनता को इसका कोई लाभ न हो सका।

राज्य और जनता : विचार और व्यवहार में आपसी सम्पर्क न होने से आम जनता का व्यवहार और दृष्टिकोण संयत, स्पष्ट और सन्तुलित न हो पाया। ज़ार-काल में धर्म, और आजकल प्रचार [Propaganda], को स्वतन्त्र तथा विवेचनात्मक रूप से न समझ सकने के कारण, रूसी जनता इतनी आसानी से क्रूर जारों और तानाशाह नेताओं के हाथों में अपने को छोड़ देती है।

रूस की जनता के चरित्र-निर्माण पर दीर्घकालीन सामन्तवादी अत्याचार का ही प्रभाव नहीं पड़ा वरन् भौगोलिक<sup>३</sup> परिस्थितियों तथा धार्मिक विचारों ने भी काफी असर डाला। रूसी चरित्र की विशेषतायें समाज के शासकवर्ग अथवा बुद्धिवादियों में न पैदा हुईं और न उनके बीच पनप सकीं। रूसियों के सम्पर्क में आने वाले पुराने-से-पुराने पश्चिमी यात्रियों को उनमें अपार क्षमता और उन्नति की सम्भावनाओं का जो आभास मिलता था, उसका प्रादुर्भाव सदा से पददलित निम्नवर्ग में हुआ। धैर्यपूर्ण परिश्रम, बिना शिकायत के कष्ट और दुःख सहने की आदत, एकदम अपरिष्कृत रूप में मानवता का गहरा समावेश, भावुकता तथा भाववेश [sentimentalism and emotionalism] की प्रत्यक्ष कमी, पेचीदी चालाकी और लक्ष्य प्राप्ति के लिये नैतिक-अनैतिक विचारों का पूर्ण अभाव, उनके चरित्र की विशेषताओं में मुख्य है। अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक नींव होने से उनमें स्वाभाविक गम्भीरता पाई जाती है। संसार के सम्पर्क से यहाँ की जनता इतनी दूर रहती आई है कि यूरोपीय आधुनिक सभ्यता के विपरीत इनकी अपनी संस्कृति बिना विशेष परिवर्तन के पूर्ववत् बनी है। रूस के बाहर पाये जाने वाले विचारों और तरीकों के साथ इनमें सहानुभूति, उदारता और समझ प्रायः कम होती है। शायद यही कारण है कि रूस की सरकार और जनता हर एक विदेशी

बातों और चीजों के प्रति सन्देह तथा अमैत्री दिखलाती थी। अपनी सफलताओं को तुलनात्मक दृष्टि से न देखने के कारण गौरव के स्थान पर गर्व के उत्पन्न होने का भय है।

आधुनिक रूस के सामाजिक चित्र में आशापूर्ण और प्रभावशाली बातें मिलती हैं। विचारों में अन्तर होने पर भी रूसियों के सम्पर्क में आने वाला कोई व्यक्ति उनके अटल आत्मविश्वास, दूरदर्शी विचारधारा और स्पष्ट उद्देश्यों की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। अन्त में यह कहना होगा कि यह देश अपनी तमाम कमजोरियों के साथ-साथ इतना सुसंगठित और कर्मठ है कि संसार के भविष्य-निर्माण में इसका बहुत बड़ा हाथ होना निश्चित मालूम पड़ता है।

## अध्याय २

### कृषि का विकास [१८६१ तक]

[Agricultural Development upto 1861]

प्राचीन रूस की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। यहाँ की जनता गेहूँ, जौ, राई [Rye] और ओट्स [Oats] की कृषि सदियों से करती आयी है। विशाल भूखण्ड पर कम आबादी होने के कारण बड़े पैमाने पर विस्तृत खेती [extensive cultivation] प्रचलित थी। कृषि-विकास और संगठन समय-समय पर अपना रूप बदलता रहा। इसी कारण कृषि केवल आर्थिक महत्व न रखकर युद्ध संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गयी। किसान और कृषि अनेक बातों से प्रभावित हुए। उनमें सबसे पहला स्थान निरन्तर होने वाले विदेशी हमले और सैकड़ों सालों की परतंत्रता को दिया जाना चाहिये। विदेशी आक्रमणकारी शासकों ने अपनी सेना के लिए भोजन प्राप्त करने के अतिरिक्त और किसी प्रकार का ध्यान कृषि की ओर न दिया। विजेता होने के नाते अधिक से अधिक कर प्राप्त करना इनका ध्येय रहा। इसकी अमित छाप रूसी खेती पर सदा के लिए पड़ी है। चूँकि स्थायी सेना रखने की प्रथा बहुत बाद में शुरू हुई इसलिये खेती संगठन को सैनिकों को अपने यहाँ रखने और उनको खिलाने की क्षमता उत्पन्न करनी पड़ी। युद्धकाल में आसानी के साथ देश के बिल्वे हुये गाँवों से सैनिकों की भरती की जा सके इसकी भी जिम्मेदारी गाँवों पर ही थी।

#### भूमि स्वामित्व का उदय तथा विस्तार

मनुष्य जाति के वचन की अवस्था वर्धमान थी। व्यक्तिगत अस्तित्व, खाना-बदोशी [nomadic] और शिकार इसके लक्षण थे। इस स्थिति का मध्य और अंतिम चरण या पाषाण तथा धातु-युग। धातु का प्रयोग जानने के बाद ही जंगली मनुष्य घरेलू [domestic] बना। जानवर को पालतू बनाना, शान्त स्थिर जीवन, गाँव और जाति गुट [clans] तथा खेती सभ्यता के विकास की शृङ्खला की पहली कड़ी थी। इस प्रकार आरम्भिक अर्थ-व्यवस्था [primitive economy] का जन्म हुआ। इस उत्पादन संगठन की विशेषता थी—उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक श्रम तथा संयुक्त उत्पादन। इस समय तक सामाजिक वर्ग, शोषण एवं व्यक्तिगत संपत्ति का उदय नहीं हुआ था।

प्राचीन रूस के आर्थिक इतिहास में दो मुख्य बातें लगभग आठवीं शताब्दी तक दिखाई पड़ती हैं—प्रथम—लोगों की पारिवारिक अथवा जाति-गुट [जन समूह या clan] में विभक्ति। स्लाव जाति में बहुत लम्बे अर्से से जाति गुट के आधार पर ही छोटे-छोटे जन-समूह बने थे। इनका शासन जन-समूह के वयोवृद्ध करते थे जिनका सदैव यही प्रयत्न रहता था कि उनका समूह स्वयं शासित हो एवं निकटतम आपसी सम्बन्ध से बँधा रहे। दूसरी विशेषता थी भूमि का सामुदायिक स्वामित्व। अपार भूमि निःशुल्क अवस्था में पड़ी थी। हर जन-समूह अपनी इच्छा एवं सुविधा के अनुसार जितनी जमीन चाहता था उस पर खेती आरम्भ कर देता था। इसलिये भूमि स्वामित्व की कोई समस्या ही न थी। नवीं शताब्दी तक यह व्यवस्था टूटने लगी। खेतीयोग्य भूमि की कमी अनुभव हुई। आर्थिक लाभ के लिये पारिवारिक तथा जाति-गुट के जगह पर क्षेत्रिक रूप से लोग संगठित हुये। यही गाँव का आरम्भ था। एक ही बड़ा परिवार या एक ही जाति के अतिरिक्त गाँव में उन सभी लोगों को जगह मिली जो किसी न किसी प्रकार से एक-दूसरे के आर्थिक कार्य-शीलता में सहयोग दे सकते थे। इस समय तक व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व [private land ownership] का जन्म नहीं हुआ था। क्षेत्रिक समुदाय [territorial commune] बना अवश्य था पर इसका कार्य केवल शासन से ही सम्बन्धित माना जाता है। रूसी कृषि की सबसे बड़ी विशेषता सामुदायिक भूमि स्वामित्व [land communes] का निश्चित लक्षण १५ वीं शताब्दी से उपलब्ध होता है। दास प्रथा का आरम्भ इस प्रारम्भिक वर्ग-हीन समाज के नष्ट होने में बहुत सहायक हुआ। इस समय की दासता उत्पादन के लिये न होकर घरेलू [domestic] कामों के लिये ही थी।<sup>१</sup> आगे चलकर इनका उत्पादन कार्य में भी प्रयोग हुआ क्योंकि प्राचीन स्लाव समाज का एक मुख्य अंग ओग्नोशान [ognitschane] अर्थात् भूमि एवं दास-स्वामी वर्ग था।

नवीं शताब्दी की प्रारम्भिक अर्थ-व्यवस्था [primitive economy] के पतन से सामंतवाद [Feudalism] का उदय हुआ जो कि लगभग दो शताब्दी के भीतर ही रूस का सामाजिक आर्थिक संगठन बन गया। इसके अन्तर्गत कृषि मुख्य धंधा थी। औद्योगिक वस्तु निर्माण [manufacturing] तथा कृषि का कार्य एक वर्ग ही करता था। निःशुल्क पड़ी हुई भूमि बहुत बड़े पैमाने में भूस्वामियों के हाथ में चली गयी। व्यक्तिगत किसान और कारीगर अपने औजार की मदद से इन भूस्वामियों से जमीन लेकर काम करते थे। इस सुविधा के बदले में अपने उत्पादन का एक अंश [obrok] तथा अपने श्रम का निश्चित समय [bartschina] भूस्वामियों को देना पड़ता था। अपने श्रम और साधन के लाभपूर्ण प्रयोग के लिये दूसरे पर निर्भर रहने का यह बीज

<sup>१</sup> Engels Origin of Family, Private Property and State,



सदियों तक अपना विपाक प्रस्फुटन एवं प्रसार करता रहा। शोषण से किसान की बराबर विगडती हुयी हालत का पूरा लाभ भूस्वामियों ने उठाया। उस पर तरह-तरह का आर्थिक व अनार्थिक बोझ बढ़ता गया। अन्त में दायित्व के अपार भार से बोझिल किसान को आसानी से भूमि के साथ बाँधने में भूस्वामी सफल हुये और स्वतंत्र किसान कृषि-दास में परिवर्तित हो गया।

प्राचीन रूसी इतिहासकार यह नहीं मानते थे कि रूस में कभी सामतवाद रहा हो। समकालीन यूरप के विकसित सामतवाद की कुछ छाया ही उनको रूस में दिखाई पड़ती थी।<sup>1</sup> किन्तु लेनिन मेवर, लाइशेन्को, आदि विद्वानों ने इस विचारधारा को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। सामतवाद के अन्तर्गत भूमि-व्यवस्था काफी सरल थी। देश के शक्तिशाली महासामंतों ने भूमि पर अपना स्वामित्व घोषित कर रखा था। इस प्रकार के स्वामित्व को वोशीना [Votchina] अथवा वशानुगत भूसम्पत्ति कहते हैं। वोशीना भूस्वामियों को बोयर [Boyer] अथवा विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति पुराता जाता था। 18 वीं शताब्दी तक इस श्रेष्ठ सामाजिक वर्ग का प्रभाव रूसी शासकों पर अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। वैसे तो सर्वदा ही किसी न किसी प्रभावशाली भूस्वामीवर्ग के हाथ में रूस का शासन खिलौना बना रहा। 16 वीं शताब्दी में कृषि की एक विशेषता यह थी कि आइवन तृतीय के नेतृत्व में एक नये प्रकार के भूस्वामियों को प्रोत्साहन दिया गया। सामत भूस्वामियों के विपरीत छोटे और मध्यम किसान वर्ग का प्रभुत्व अर्थ-व्यवस्था में बढ़ा। इन्हें पोमेस्ती भूस्वामी कहा जाता था। इनका काम सीपा-प्रदेश की रक्षा और राज्य की सैनिक सेवा था। इसके बदले में इनको जमीन दी जाती थी। लेकिन यह भूमि स्वामित्व स्थायी न था। इसका सीधा सम्बन्ध सैनिक सेवा से था। इसकी इतनी तीव्र प्रगति हुयी कि 16 वीं शताब्दी के मध्य तक 95% खेती योग्य भूमि इनके अधिकार में चली गयी। इस भूमि-व्यवस्था को प्रोत्साहन देने से कृषि उन्नति में सहायता हो सकती थी। ऐसा न होने का मुख्य कारण था कि पोमेस्ती वर्ग का भूमि-अधिकार स्थायी न था। अस्थायी भूमि स्वामित्व के साथ-साथ इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति उचित श्रम इकट्ठा करके लाभपूर्ण खेती करने में बाधक सिद्ध हुयी।

इस शताब्दी में मुद्रा के प्रयोग और व्यापारिक विनिमय के आर्थिक व्यवस्था में आ जाने से श्रम अधिक लाभपूर्ण धन्यों में जाने की कोशिश करने लगा। श्रमिकों का खेत छोड़कर भाग जाना एक सार्वजनिक समस्या बन गया था। चूँकि सामंतों [Feudal Lords] का प्रभाव श्रमिकों को रोक रखने में सफल न हो सका, इनलिये पोमेस्ती भूस्वामियों

<sup>1</sup> See notes no. 10 in Lyashehenko History of the National Economy of Russia. pp. 93—94

ने किसान को भूमि से बाँध देने की व्यवस्था करनी आरम्भ की। आगे चलकर किसानों को दिये गये कर्ज की वसूली का बहाना लेकर इस वर्ग के आन्दोलन तथा प्रभाव के कारण किसानों के भूमि छोड़ने पर प्रतिबंध लगा और उनकी दासता में नया युग आरम्भ हुआ।

17 वीं शताब्दी में देश में ऐसी उथल-पुथल रही कि कृषि की दशा और विगड़ती गयी। 1601-3 के महाकाल में पोमेस्टी वर्ग की शक्ति इतनी कम हो गयी कि इन्होंने अपने यहाँ रहने वाले श्रमिकों को भोजन देने से भी इन्कार कर दिया। इस कुदरती कहत [Natural Calamity] के साथ-साथ आइवन चतुर्थ की लिवोनियन युद्ध [1858 से 1883] में अफलता से देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी। दासता किसान को अपने दान में बाँधती जा रही थी। विगड़ी हुई आर्थिक स्थिति से आक्रुत होकर किसानों में विद्रोह पैदा हुआ। विद्रोह तथा अनुशासनहीनता की भावना को पोलैंड द्वारा चढाई व मास्को पर कब्जा [1607-1612] से और भी प्रोत्साहन मिला। 1605, 1608, 1672 में कुछ प्रसिद्ध विद्रोह हुये। उचित नेतृत्व एवं संगठन होने से इनको कठोरता से दबा दिया गया। किसान विद्रोहों के अतिरिक्त शताब्दी के आरम्भ में ही पोमेस्ती वर्ग ने किसानों की श्रम-शक्ति तथा शरीर पर कानूनी अधिकार अपने आप ग्रहण कर लिया। इनका प्रभाव और शक्ति इस बात से ही प्रकट होती है कि रोमानोव वंश को जार चुना गया। यह स्वयं बहुत बड़े पोमेस्ती भूस्वामी थे। अब किसानों की स्वतन्त्रता का प्रायः पूर्ण विनाश हो चुका था। बारशीना पद्धति, कृषि दासता के यन्त्र के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगी।

18 वीं शताब्दी देश में आनेवाले युगपरिवर्तन की अग्रिम सूचना थी। इस समय में नया भविष्य तथा नये दिशा में प्रगति के लिए कदम उठाया गया। इतना सब होने पर भी कृषि में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। महान पीटर की हिम्मत शक्तिशाली भूस्वामियों से टक्कर लेने की न पड़ी। एक ही बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है; सुद्रा तथा व्यापार में उन्नति के कारण एक नये तरह का किसान वर्ग सामने आया जिनको व्यापारी किसान [Trading Peasant] कहा जाता था। कुछ समृद्धशाली किसानों ने लाभ की दृष्टि से गाँवों से अनाज खरीदकर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में बड़े व्यापारियों के हाथ बेचना शुरू किया। इस अनाज का निर्यात होता था। यूरोप का प्रभाव तेजी के साथ बढ़ रहा था। इससे प्रेरित होकर यूरोपीय सस्कृति, कला और विलासिता ने रूसी भूस्वामियों में धन की आवश्यकता को बहुत बढ़ा दिया। इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ा। बारशीना और अग्रौक का कठोर भार बढ़ने लगा। इसके विरुद्ध कई किसान-विद्रोह हुए जिनमें से मुख्य अस्त्राखॉ [1705] और डॉन [1707] का किसान विद्रोह था। 18वीं शताब्दी के औद्योगिक विकास ने भी कृषि को प्रभावित किया।

किसान कारखानों में मिलनेवाली अच्छी मजदूरी से शहरों की ओर आकर्षित हुए। कृषि की तरफ से ध्यान हटाकर उन्होंने अधिक से अधिक समय कारखानों में बिताना आरम्भ किया। खेती में केवल उतना ही समय देते थे जितने से उनके स्वयं उपभोग का अनाज मिलता रहे। इतने अधिक किसान शहरों में चले गये कि अत्यन्त उपजाऊ प्रदेशों में भी उपज घटी और अनाज का दाम दूना हो गया।

19वीं शताब्दी के मध्य तक कृषि समस्याये प्रायः उसी प्रकार की रही जैसी कि पिछले 200 सालों से थी। अनुस्थित भूस्वामी शहर के सुखों का आकर्षण, सैनिक सेवाएँ और दरबार की राजनीति को छोड़कर दुबारा कृषि की ओर आने के लिए बाध्य हुए। सालों तक स्वामी के स्वयं गावों में न रहने से भयकर कुप्रबन्ध और अत्याचार चल निकला था। गिरना हुआ उत्पादन एक समस्या बन गया क्योंकि परिस्थितियों से लाचार होकर किसान ने केवल अपनी जीविका के लिए खेती करना शुरू कर दिया। अनाज का दाम बढ़ता गया। इससे लाभ उठाने के लिए भूस्वामियों ने अपने निरीक्षण से उत्पादन कराने का सोचा। इसके अतिरिक्त नव-विकसित उद्योगों के अत्यन्त लाभपूर्ण आकर्षण ने पूँजी का महत्व और आवश्यकता बढ़ा दिया। उस समय की आर्थिक व्यवस्था में पूँजी प्राप्त करने का एकमात्र साधन कृषि-उत्पादन में वृद्धि था। इंग्लैण्ड और फ्रांस में नये-नये कृषि-यन्त्र और वैज्ञानिक तरीके निकाले जा चुके थे जिससे कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक प्रगति करना संभव मालूम पड़ने लगा। कृषि-दासता बहुत बड़े रूप में रुकावट बनकर खड़ी हुई। फिर भी नयी विचारधारा ने ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवर्तन जरूर किये। दक्षिणी हिस्सों में मेड पालने और चुकन्दर [Sugar Beet] की खेती में काफी पूँजी लगायी गयी। लेकिन 1825-1850 के बीच किसान और भूस्वामी दोनों की दशा बिगड़ती ही गयी। परिस्थिति को और गम्भीर बनाने में, फसल न का होना बहुत बड़ा कारण था। भीषण अन्न-भाव और अकाल इस समय में नियमित मेहमान बन गये। इनमें से मुख्य 1820-21, 1832-34, 1839, 1843-47 और 1850-51 के दुर्भिक्ष थे। कृषि की यह दुर्दशा पुराने ढंग की खेती, तीन खेतों की पद्धति पर अनावश्यक जोर, केवल खाद्यान्न की उपज पर ध्यान, पशुपालन की ओर लापरवाही और खाद का अभाव था, और यह सब मूलतः दास प्रथा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम थे।

### भूमि-स्वामित्व के प्रधान वग

बौयर वर्ग का प्रभुत्व राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र से घटता गया। यह वंश-परम्परागत भूस्वामी अब अपने विशेष अधिकार खोकर पोमेस्ती वर्ग के चढ़ते सितारों के आगे प्रायः मिट गये। स्वामी वर्ग के इस परिवर्तन के साथ-साथ ही किसान भी

अपनी स्वतन्त्रता से हाथ धो चुका था और दासता के बन्धनों में अब केवल श्रम ही उसका एकमात्र सामाजिक काम रह गया। खेती देश का मुख्य धन्धा थी किन्तु दासों द्वारा वस्तु उत्पादन कार्य की भी वृद्धि हो रही थी। लगातार युद्ध में लगा हुआ देश किसानों के अधिकारों के लिए श्राप बन गया। युद्ध में भूस्वामी वर्ग की मदद आवश्यक थी। अतः उनके अधिकार बढ़ते ही गये और दायित्व कम होता गया किन्तु किसानों पर बोझ का दबाव असह्य होने लगा।

इस समय के भूमि स्वामित्व के विचारधारा की बुनियाद यह थी कि मास्को राज्य जार की बोशीना सम्पत्ति है। किसानों के प्रवासी स्वभाव पर पूरी तरह कानून और प्रथा का कठोर अवरोध लग चुका था। बोशीना पर रहने वाले लोगों का स्वतन्त्र अस्तित्व, इस प्रकार, बोशीना में ही विलय हो गया। भूमि के साथ उसपर रहने वाले किसान भी भूस्वामी की सम्पत्ति बन गये।

महान् पीटर ने बौयर वर्ग को नष्ट कर दिया। दूसरा प्रभावशाली परिवर्तन एक स्थायी सेना का निर्माण था। इसका सीधा प्रभाव भूमि-स्वामी [पोमेस्ती] की आवश्यकता ही समाप्त हो गयी। सीमा प्रदेश की देख रेख अब सेना का उत्तरदायित्व था। १८वीं शताब्दी के आरम्भ तक इस नई प्रगति ने इस भूस्वामी वर्ग का अस्तित्व प्रायः समाप्त कर दिया। १६८४ तक बोशीना वंशानुगत सम्पत्ति थी और इसका विभाजन नहीं हो सकता था; पोमेस्ती भूमि-अधिकार जो कि केवल सेवाओं के बदले में ही रखा जा सकता था, वंशानुगत नहीं था। १६८४ और १७१४ के आज्ञा द्वारा इन दोनों को मिला दिया गया। सभी भूसम्पत्ति वंशानुगत, अविभाजनीय व पारिवारिक बनी, तथा इन सबको राज-सेवा करना अनिवार्य हो गया।

१७८२ तक सामन्तों ने निम्नलिखित अधिकारों द्वारा अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया था। [१] बोशीना या वंशानुगत सम्पत्ति को बेचना। [२] दास रखने का एकाधिकार। [३] कानूनी और पुलिस अधिकार में वृद्धि। [४] किसानों को भूमि से पृथक् बेचने का अधिकार। [५] अचल सम्पत्ति को सरकार के पास गिरवी रखकर सस्ता उधार प्राप्त करना। इसके लिए सामन्त बैंक [Nobles Bank] १७५३ में स्थापित किये गये। इनकी पूँजी ७,५०,००० रुबल थी। जिस समय बाजार में गिरवी रखने का व्याज २०%, था यह बैंक केवल ६% पर सामन्तों को उधार देते थे।

१८वीं शताब्दी के अन्त में भूमि स्वामित्व इस प्रकार था।

[१] चर्च स्वामित्व [Church Ownership]

[२] दरबार भूमि-स्वामित्व [Court Ownership]

[३] जार स्वामित्व [Tzar Ownership]

[4] राज्य स्वामित्व [State Ownership]

[5] अन्य स्वामित्व [Other Ownership]

### चर्च स्वामित्व

कैथरीन द्वितीय—[1760] के समय में करीब १० लाख व्यक्ति अर्थात् रूस और साइबेरिया की ग्रामीण आबादी का करीब 14% इस श्रेणी में था। बड़े धर्माधिकारी और गिरजे भी दास रखते थे। मठों की भूमि कई बार राज्य ने ले लिया पर बार-बार यह उसे प्राप्त कर लेने में सफल हुये। 1649 में जार एलेक्जेंडी, 1701 में महान् पीटर, [1762] में पीटर तृतीय तथा [1864] में कैथरीन II ने इनको राज्य के अधिकार में ले लिया। कैथरीन ने इस भूमि और दासों के प्रबन्ध के लिये एक अर्थ-विभाग [Economic Collegium] बनाया। इसके नाम के कारण इसके आधीन रहने वाले किसानों को आर्थिक किसान [Economic Peasants] कहा जाता है। इनका संगठन प्रायः उसी प्रकार था जिस तरह वोशीना संपत्ति का होता था। इस संगठन में भी किसानों की दशा बहुत अच्छी न थी। पहले इनको साल में काफी कठोर वारशीना करना पड़ता था। कुछ जगहों पर 163 दिन प्रति वर्ष किसानों को मठ की भूमि पर काम करना होता और साथ ही साथ ओब्रोक भी मुद्रा में चुकाना पड़ता था। कैथरीन ने 1764 में वारशीना उठा दिया। राज्य कर [Poll tax] के साथ अब हर किसान को 1½ रूबल प्रति व्यक्ति ओब्राक देना निश्चित हुआ। इसका प्रभाव करीब २० लाख किसान परिवारों पर पड़ा। यह नयी व्यवस्था किसानों की दशा सुधारने में विशेष मददगार न हो सकी। 1783 तक ओब्रोक बढ़कर करीब 3½ रूबल हो गया। मठों की भूमि लेने का काम कठिन और पेचीदा था। ईसानदार शासन के न होने से 1764 की राजाज्ञा के बाद करीब २२ साल इस काम को पूरा होने में लगा। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इन आर्थिक किसानों [Economic peasants] की दशा व्यक्तिगत भूस्वामियों के किसानों से अच्छी थी।

### दरबार भूमि स्वामित्व

दरबार भूमि स्वामित्व काफी प्राचीन समय से प्रचलित था। 14-15 शताब्दी में मध्य रूस के काफी विस्तृत प्रदेश उनमें सम्मिलित किये गये। इनमें विशेष कर वह भूमि थी [Black Lands] जो कि उस समय तक व्यक्तिगत तथा दरबार स्वामित्व में नहीं थी। दरबार भूस्वामित्व 18वीं शताब्दी के अंत तक बढ़ता गया। 1772 में दरबार के अंतर्गत 3,57,328 और 1782 में 5,97,238 पुरुष [Souls of male sex] थे। इस भूमि का मुख्य कार्य दरबार के प्रमुख राजकुमारों [princes] तथा कर्मचारियों को दी जाने वाली राजकीय अर्थ सहायता इकट्ठा करना था। इस

भूमि पर वारशीना और ओब्राक दोनों ही लिया जाता था। मुद्रा के प्रचलन के बाद इनको अधिकतर धन में ही वसूल किया गया। किसानों की स्थिति पोमेस्ती किसानों से अच्छी थी। इनको कम ओब्राक और श्रम देना पड़ता था। दरबार इन किसानों को आवश्यकतानुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेज दिया करता था जिससे बहुत असुविधा थी। इनका शासन दरबार के एक विभाग द्वारा होता था, जिसके प्रतिनिधि गाँव का प्रबंध करते थे। धीरे-धीरे कैथरीन द्वितीय के समय से दरबार की भूमि राज्य स्वामित्व में बदल गयी।

### राज्य स्वामित्व

राज्य के प्रशस्त भूमि पर जो किसान बसे थे वे राज्य की सम्पत्ति थे। इन किसानों की मदद से महान पीटर ने अपनी औद्योगिक संस्थाओं के लिये श्रम शक्ति प्राप्त की। यह लोग राज्य की सम्पत्ति थे इसलिये राजाशा के अनुसार इनको किसी भी काम पर भेजा जा सकता था। प्रोफेसर मेयर के अनुसार अगर इन कृषकों का उचित प्रबंध किया जाता तो रूसी भूमि स्वामित्व पद्धति का यह उत्कृष्ट एवं उच्चतम आदर्श रूप बन सकता था।<sup>1</sup> कैथरीन द्वितीय ने इनकी दशा सुधारने का काफी प्रयत्न किया। इस समय के किसान आन्दोलन से डर कर, इन सुधारों को स्थायी रूप देने की जगह जारिना [Tzarina] ने इनको दासता में और अच्छी तरह जकड़ना ही उचित समझा। 1742 तथा 1762 के जनगणना के बीच राज्यस्वामित्व में 5,54,425 से बढ़कर 6,27,027 पुरुष हो गये।

### जार स्वामित्व

महान पीटर के समय में कुछ भूमि जार ने अपने परिवार वालों को वंशानुगत स्वामित्व में दे दी थी। इनको जार की व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाता था। इसका प्रबंध एक अलग विभाग बनाकर या व्यक्तिगत रूप से किया जाता था। दरबार के किसानों के तरह जार के भूमि और किसानों पर एक-सा केन्द्रीय नियंत्रण नहीं था। अलग-अलग सदस्य अपनी भूमि को अपने विचार और तरीके से चलाते थे। यहाँ पर कर की इकाई मिल थी। अर्थात् प्रति पुरुष व्यक्ति के स्थान पर चार दम्पति [four couples] पर एक साथ कर लगता था। अपने स्वामी के धन की आवश्यकताओं के अनुसार इनका ओब्राक घटता और बढ़ता रहता। कहीं-कहीं पर इस प्रकार की भूमि पश्चिमी योरोप की कृषि प्रणाली का प्रयोग केन्द्र बनी। कुछ दशाओं में इससे लाभ हुआ किन्तु अधिकतर प्रयोग आरंभ होने के कुछ दिन बाद बंद कर दिये जाते थे।

<sup>1</sup> James Meyer : An Economic History of Russia, Vol. I, p. 267.

इसका कारण था कि कुछ दिनों बाद या तो स्वामी का शौक समाप्त हो जाता था, या उसे कोई नई चीज आकर्षित कर लेती थी। किसानों की मुसीबत का अन्दाज लगाया जा सकता है।

### अन्य भूमि स्वामित्व

रूस और साइबेरिया के कुछ भागों में किसानों का नया वर्ग 18वीं शताब्दी में सामने आया जिसको पोलोव्नीकी [Polovneke] कहते हैं। यह किसान खेती करते थे, और उत्पादन को भूमि स्वामी के हाथ बाँट लेते थे। इस वर्ग की वृद्धि 18वीं शताब्दी से आरम्भ हुई जब कि बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान इस वर्ग में शामिल हुये। इनको बिना आशा के भूमि छोड़ कर चले जाने का अधिकार था। इस तरह रूस में एक अजीब-सी परिस्थिति पैदा हो गयी। ऐसे देश में जहाँ कि भूमि छोड़ कर जाने पर कितने ही प्रकार का प्रतिबन्ध था, पोलोव्नेकी की स्वतंत्रता पर एकदम रुकावट न थी। यह किसान अधिकतर स्वतंत्र थे। शीघ्र ही इनके उधार लेने की प्रवृत्ति ने स्वतंत्रता नष्ट कर दी। 18वीं शताब्दी के मध्य से इनकी संख्या घटने लगी। इनको अपने उत्पादन का आधा भाग भूस्वामी को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त फसल काटना, भूसा निकालना, जंगल साफ करना, कपड़ा बुनना इत्यादि यह भूस्वामी के लिये करते थे। स्त्रियाँ और बच्चे उनके घरों पर काम करने के लिये बाध्य थे।

स्वतंत्र किसान उन किसानों को कहते हैं जिनको कि देश की सीमा की रक्षा के लिये सैनिकों के रूप में रखा गया था। इस सेवा के लिये इनको भूमि दी जाती थी। इनका दायित्व दूररे किसानों के समान था। एक विशेषता यह थी कि इनको अपने परिवार से कपड़े, हथियार और घोड़े से सुसज्जित, 15 वर्ष से अधिक के पुरुषों को फौज में भेजना पड़ता था। इनके अतिरिक्त एक और प्रकार का भूमि स्वामित्व था। 'पुराने सैनिक' ऐसे व्यक्ति थे जिनका काम केवल सैनिक श्रम था। हर दूसरे साल इनको सेना में जाना होता था। जो लोग घर पर रह कर खेती करते थे उनको एक खास टैक्स देना होता था। इनका दायित्व स्वतंत्र किसानों से इतना मिलता-जुलता है फिर भी 1762 की जनगणना में इनको अलग स्थान दिया गया।

### किसान की स्वतंत्रता

रूसी कृषि का संगठन आरम्भ में किस प्रकार का था और इसका क्रमिक विकास लगभग 14 वीं शताब्दी तक किस प्रकार हुआ इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। 14-15 वीं शताब्दी के बाद से यह कहा जा सकता है कि अग्नेयी ढाँचे से मिलती-जुलती तीन खेतों की पद्धति तक कृषि की प्रगति हो चुकी थी, लेकिन न तो इनमें एक-

रूपता थी और न व्यापकता। मास्को के आस-पास के क्षेत्रों में तो यह तरीका स्थापित हो चुका था लेकिन देश के दूसरे फैले हुए हिस्सों में इसके पूर्ण विकास की ओर अलग-अलग स्तर की प्रगति ही दिखलाई पड़ती थी।

इस समय तक किसान धरती के स्वतंत्र पुत्र थे। अपनी इच्छा व सुविधा के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भूमि पर जाकर काम कर सकते थे। अधिकतर कृषियोग्य भूमि राजा की व्यक्तिगत संपत्ति थी या बड़े-बड़े सामंतों और सेनापतियों के हाथ बँटी हुई थी। प्रसिद्ध रूसी इतिहासकार लाइशेको के अनुसार कहीं-कहीं पर कुछ किसान परिवार एक ही भूमि पर बहुत दिन तक बसे रह गये इसका कारण वृद्धावस्था, बड़ा परिवार या सुविधाजनक वातावरण हो सकता है। धीरे-धीरे प्रवास-प्रिय स्वतंत्र किसान जगह-जगह पर अपनी जड़े जमाने लगे। किसानों के एक जगह पर बस जाने की प्रवृत्ति का एक कारण यह भी हो सकता है कि बढ़ती हुई आबादी से बिगड़ी आर्थिक दशा ने उनको ऋणी बना दिया। किसान अपनी एकमात्र संपत्ति—श्रम शक्ति के द्वारा एक जगह रहकर इन ऋणों को चुकाने के लिए बाध्य हुए। जिन ऋणों के भुगतान के लिए किसान जगह-जगह पर बसने लगे थे अनेकों कारण से वे ऋणमुक्त न हो सके। ऋणों की बलात् वसूली से बचने के लिये यही किसान खेतों को छोड़कर भागने लगे। उत्पादन और धन की हानि ने शक्तिशाली भूस्वामियों को इस दिशा में कठोर कदम उठाने के लिए उत्साहित किया। सोलहवीं शताब्दी में भागे हुये किसानों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगे। अब इस कानून के पाँच बरस पहले तक के भागे हुये किसानों को पकड़ मँगवाने का अधिकार भूस्वामियों को प्राप्त हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय के शासन संगठन में यह आसान काम नहीं था। इसी से कुछ विद्वानों का मत है कि किसानों को जमीन से सदा के लिए बाँध देने का कानूनी प्रयत्न एक खोखली-सी चीज थी।

स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबन्ध बढ़ता गया और 17 वीं शताब्दी के आरम्भ में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से जनता पर पड़ने लगा। भूस्वामियों ने किसानों के इस तरह बंध जाने का लाभ समझा और अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए लालायित हो उठे। सरकार में उनका प्रभाव बहुत गहरा था। कानूनी प्रतिबन्ध को वे अपने इच्छानुसार बढ़ाते गये। इसकी प्रतिक्रिया किसानों पर भी हुई और 17 वीं तथा 18 वीं शताब्दी में इसके विरुद्ध जगह-जगह लगातार कृषक विद्रोह होने लगे। उस समय तक मजदूरों और किसानों का कोई राजनैतिक और आर्थिक संगठन न होने से ओजस्वी नेताओं ने जिस उत्साह के साथ विद्रोह कराया, उससे कहीं भीषण कठोरता के साथ राज्य ने उन्हें दबा दिया। 1649 में “सोवर नियम” बना जिसके अंतर्गत जमीन छोड़कर भागे हुये किसानों को [चाहे वे जब कभी भी भागे हों] फिर से वापस बुला लेने का अधिकार मिला



ही गया। स्वतन्त्र किसानों के भूमि का अधिकार बराबर कम होता गया और वह करीब करीब एक विशेष प्रकार के गुलाम बन गये जिनको “सर्फ “या” कृषी-दास” कहते हैं। एक विचित्र संयोग है कि रोमानोव वंश ने ही किसानों को दासता की वेडियाँ स्थायी रूप से पहनाई जिसको तोड़ फेंकने में इन्हीं मजदूर किसानों ने इस वंश का नाश कर दिया। दो महान् शासकों ने (पीटर प्रथम तथा कैथरीन द्वितीय) जो अमर प्रयत्न देश की उन्नति के लिए किया उस पर सबसे बड़ा कलुष कृषिदासता को रूसी अर्थ-व्यवस्था का एक अंग बनाना है। जार सम्राटों के शासन में खेती योग्य भूमि सामंतों के हाथ में इकट्ठा होती गई। इस भूमि पर लाभपूर्व खेती करने के लिए श्रमशक्ति प्राप्त करना आवश्यक हो गया। इस कारण कृषी दासों की संख्या बराबर बढ़ती रही। यहाँ तक कि रूसी कृषी का यह एक विशिष्ट अंग बनी।

17 वीं शताब्दी के आरम्भ तक राज्य की भूमि [ State domain ] पर के किसानों को पूरी तरह जमीन के साथ बाँधा जा चुका था। बोशरीना और पोमेस्ती भूस्वामियों द्वारा भी वह बन्धन लागू किया गया किन्तु इसे अभी तक कानूनी अनुमति नहीं मिल पाई थी। किसानों की गरीबी के कारण उनके कर्ज का भार बहुत बढ़ा। इससे मुक्त होने के लिए उन्होंने भूमि छोड़कर जाने का अधिकार बेच दिया और स्वामी के यहाँ काम करने का वादा किया। इसके बदले में स्वामी ने उनको ऋणमुक्त कर दिया। जो किसान इस प्रकार अपने को बेच देते थे वे किसान वर्ग से गिर कर गृह-दास के स्तर पर आ जाते थे। धीरे-धीरे किसान और गृह-दास का कार्य क्षेत्र और अधिकार आपस में मिलता गया। 17 वीं शताब्दी के आरम्भ में इनमें अन्तर बताना कठिन हो गया। भूस्वामियों की शक्ति बराबर बढ़ती रही। यहाँ तक कि 1765 तक किसानों के आचरण की जिम्मेदारी, साइबेरिया में निष्कासन तथा अपराधियों को कठोर कारावास [Hard Labour] देने का अधिकार प्राप्त हो गया। किसानों और भूस्वामियों का पारस्परिक सम्बन्ध एक विशेष व्यक्तिगत समझौता द्वारा निश्चित होता था। इसकी अवधि अधिकतर उसे 5 वर्ष और कभी-कभी 10 से 12 वर्ष होती थी। इसी माध्यम द्वारा वैधानिक रूप में भी किसानों को अपने मनचाहे तरीके से भूस्वामी बाँध लेता था। इस समझौते के अंतर्गत भूमि के साथ साथ किसान को आवश्यक बीज, खाद और दूसरी वस्तुएँ मिलती थी। इन सुविधाओं के भुगतान में कई प्रथाएँ थी जैसे वस्तु, श्रम, अथवा धन भुगतान।

**वस्तु तथा मुद्रा भुगतान [Obrok]**

भूस्वामी और किसान के आपसी सम्बन्ध के अनुसार सम्पूर्ण किसान वर्ग को बाँटा जा सकता है। इसका मापदण्ड होगा कि किस प्रकार किसान भूस्वामी के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करता था। इसमें मुख्य थे ओब्राक, बारशीना तथा द्वोरोबी

ल्यूद [obrok, bartshina and dvorovie lyude]। आदि काल से संसार में प्रायः सर्वत्र कृषि अधिकारों के भुगतान का साधन खेत में उत्पन्न वस्तु थी। जब प्रसंविदा [Contrac] बनता था तो उसी में इसका अंश निश्चित कर दिया जाता था। मध्यकालीन यूरोप में [14वीं शताब्दी] प्रथा के अनुसार मजदूरी करने के दायित्व से किसान कुछ वस्तु देकर छुटकारा पा जाता था।<sup>1</sup> इस वस्तु भुगतान को ओब्राक कहते हैं। एक किसान परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या [number of souls of male sex] पर निर्धारित यह एक निश्चित भुगतान था जोकि एक गाँव या गाँवों के समूह के लिए अलग-अलग लगाया जाता था। इसको पूर्ण तरह किसान और भू-स्वामी के सम्भौते पर छोड़ दिया गया था। यह किसी भी प्रकार कृषि आय से सम्बन्धित न था। अधिकतर इसकी मात्रा इतनी अधिक होती थी कि किसान अपनी कृषि-आय से उसका पूर्ण भुगतान न कर पाता या भुगतान के बाद उसके पास अपने लिये कुछ भी न बचता। दोनों हालत में उसे दूसरे कामों का सहारा लेकर धनोपार्जन करना आवश्यक था। यह प्रथा अधिकतर कम उराऊ जमीन पर प्रचलित थी जहाँ भू-स्वामी स्वयं खेती करके अधिक नहीं कमा सकता था। इस प्रथा में किसानों को काफी आर्थिक स्वतन्त्रता थी और साथ ही साथ अधिक से अधिक मेहनत और सफल उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन मिलता था। इसके अतिरिक्त स्वामी के आवश्यकता की सभी वस्तुएँ चूँकि ओब्राक से ही प्राप्त होती थी इसलिये भूमि-स्वामी का स्वार्थ और रूचि दोनों ही खेती और किसानों में बनी रहती थी। इस प्रथा के इतने बड़े पैमाने पर लागू होने का एक और कारण था। देश की अव्यवस्थित राजनैतिक स्थिति, और सदा होने वाले युद्धों से बाध्य होकर भूस्वामियों को अधिकतर राजधानी में या युद्धस्थलों में ही रहना पड़ता था। भूमि की देख-रेख और प्रबन्ध की भूमंड से बचने के लिये ओब्राक भुगतान प्राप्त करना सबसे सुविधाजनक सिद्ध हुआ। लगभग 16वीं शताब्दी तक देश में मुद्रा का प्रयोग राजधानियों और शहरों को छोड़कर गाँवों तक बहुत कम पहुँचा था। इसलिये सभी ओब्राक भुगतान वस्तु या उपज में होते थे। सोलहवीं सदी से मुद्रा का प्रचलन बढ़ता गया। उसी अनुशात में यह भुगतान भी वस्तु और उपज की जगह मुद्रा में लिया जाने लगा।

### श्रम-भुगतान [Bartshina]

दूसरे तरह के भुगतान को वारशीना कहते हैं। इसके अन्तर्गत हर एक किसान को हफ्ते में निश्चित दिन अपने खेतों के अनाया स्वामी के खेतों पर काम करना पड़ता था। भारत में प्रचलित बेगार प्रथा से यह काफी मिलता-जुलता है। अन्तर केवल इतना

<sup>1</sup> Clive Day : Economic Development in Europe, p. 538.

है कि बेगार की अवधि किसान और भूस्वामी के प्रसविदे में नहीं लिखी होती। इसका निश्चय प्रथा के अनुसार होता है। बारशीना भूस्वामी का एक कानूनी अधिकार था जोकि एक प्रकार से किसानों को दिये गये अधिकारों का शुल्क था। इसमें भी कोई नियम या सामान्य प्रथा नहीं पाई जाती। अलग-अलग क्षेत्र में काफी अन्तर था। फिर भी 1780-1790 तक तीन दिन का बारशीना औसत माना जा सकता है। किन्तु कहीं-कहीं 5 या 6 दिन तक किसान को भूस्वामी के खेत पर काम करना पड़ता था।

स्वामी के खेतों में काम करने का अर्थ बराबर व्यापक होता गया और 17वीं शताब्दी में बारशीना में मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, बगीचों की देखरेख, घर का काम, यातायात और दूसरी सभी सेवाएँ सम्मिलित हो गयी। आरम्भ में ओब्राक के समान यह प्रथा प्रचलित न हो सकी क्योंकि इसमें स्थायी संगठन और निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती थी। थोड़े से बड़े-बड़े खेत ही इसका प्रयोग करते थे। ज्यों-ज्यों सामंतों और मठों के स्वामित्व में भूमि बढ़ती गयी, इस भूमि पर काम करने के लिये श्रम की आवश्यकता बढ़ी। किसानों की सदा बढ़ती हुयी गरीबी ने उनका अधिकतम शोषण सम्भव बनाया। यह देखा गया कि ओब्राक के साथ-साथ बारशीना के मिला देने से किसानों का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रथा ने कृषि दास पद्धति के निर्माण और प्रचलन में बहुत मदद किया।

आवश्यक श्रम को स्थायी रूप में अपने भूमि से बाँध लेने का सबसे सुगम साधन बारशीना सिद्ध हुआ। स्वामी के खेतों पर और दूसरे कामों में किसान का इतना समय लगने लगा कि अपने खेत की देखभाल करने की शक्ति और सुविधा दोनों ही घटती गयीं। किसानों की गरीबी ने अपने शिकजे कसने शुरू किये। लाचारी का स्वार्थपूर्ण लाभ उठाकर स्वामियों ने किसान को बीज और औजार उधार दिया जिसका भुगतान उसे धन, उज्र या मेहनत से करना था। छोटे-छोटे विखरे खेत इतना बोझ न उठा सके। किसान को अपने खेत से भी हाथ धोना पड़ा। अब स्वामी उनको खेत भी किराये पर देता था। किराये की वगूली मालिक के खेतों पर काम करने के रूप में होती थी। इस तरह आर्थिक रूप से स्वतंत्र किसान सदा के लिये दासता में चला गया।

### गृह-दास [Dvorovie lyude]

18 वीं शताब्दी में रूस के अलावा यूरोप में कहीं भी आजीवन गृह-दास नहीं पाये जाते थे। यह दास और दासियाँ स्वामी के घर पर रह कर उनके सभी काम करते थे। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व अथवा अधिकार एकदम शून्य था। स्वामी के क्रोध, और क्रूरता का पूरा बोझ यही दास और दासियाँ उठाते थे।<sup>1</sup> बर्दई, लुहार, जुलाहा,

गायक, राजगीर इत्यादि सभी आवश्यक कार्यों के लिये इनमें से ही व्यक्ति चुने जाते थे। कैथरीन द्वितीय के राज्यकाल में [१८६२-१८९८] इनको अकेले या परिवारों में जानवरों के हाट पर ले जाकर बेचा जाता था। वास्तव में यह भी भूतपूर्व किसान थे। आर्थिक पतन के कारण हार कर अपनी स्वतंत्रता का इन्हें पूर्ण परित्याग करना पड़ा। धीरे-धीरे यह स्वामी की सम्पत्ति बन कर रह गये।

### सह-कृषि [Share-cropping]

एक अन्य प्रकार का भी किसान स्वामी सम्बन्ध था जिसको सह-कृषि कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत किसान स्वामी के साथ एक सहयोगी के रूप में खेती करता था और सुविधाओं के लिये उपज का एक निश्चित अंश स्वामी को देता था। यह प्रथा बड़े पैमाने पर लागू न हो सकी क्योंकि भूस्वामियों ने उपज का इतना बड़ा भाग लेना शुरू कर दिया कि खेती करना असम्भव हो गया। १८वीं शताब्दी तक यह प्रथा देश में यदाकदा ही पाई जाती थी।

### राज्य और कृषि

विश्व सम्पर्क से दूर रहने वाला जारो का देश, रूस, कृषि के बारे में एक स्वतंत्र विचारधारा एवं स्पष्ट नीति निर्धारण कभी न कर सका। देश का राजनैतिक सगठन बहुत देर में शुरू हुआ। छोटे-छोटे राज्यों और सरदारों में विभक्त होने के कारण आपसी लड़ाई ही शासक वर्ग का सारा समय ले लेती थी। आरम्भ से ही कृषक और किसान के प्रति उच्च वर्ग के व्यक्ति उदासीन थे। उनके विचार से कृषि ऐसा धंधा था जिसको निम्न कोटि के व्यक्ति स्वभावतः ही करते हैं। इसमें खोज, विज्ञान, समझ या सुधार की कोई सम्भावना नहीं हो सकती। पृथक्वाद का प्रभाव रूसी शासकों पर इतना अधिक था कि यूरोप के कृषि पद्धति के विकास से रूसी भूस्वामी और किसान दोनों ही १९वीं शताब्दी तक अनभिज्ञ रहे। सत्रहवीं शताब्दी में रूस एक राष्ट्र का स्तर प्राप्त कर सका। केन्द्रीय शासन-व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न आरम्भ हुआ। राजधानी में बैठा सम्राट दरबार के प्रड्युत्त और राज्य-विस्तार में व्यस्त था। कृषि सम्बन्धी किसी 'नीति' की आवश्यकता होती है इसका अनुभव ही न हुआ।

सामंतशाही पर आधारित शासन इस परिस्थिति का मूल कारण था। जार को संपर्क केवल सामंतों तक सीमित था। उसके कार्य की परिधि भी यही सामंत निश्चित करते थे। प्रचलित विचारधारा भी इन प्रभावों से विकृत हो चुकी थी। लोगों को विश्वास था कि किसान कम समझ, आलसी तथा दरिद्र व्यक्ति हैं जोकि मूलतः काम नहीं करना चाहता। चूँकि अनाज का उत्पादन देश के लिये आवश्यक है इसलिये इनसे काम लेना ही होगा। किसान से काम करा लेने का अनुभव और प्रणाली केवल भूस्वामियों के पास

है। इसलिये सम्राट को इस दिशा में उन्नति करने के लिये इतना ही करना होगा कि भूस्वामियों को किसान और खेती का पूरा प्रबन्ध देना भी श्रेयस्कर है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध या हस्तक्षेप आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होगा।

इसके अतिरिक्त जार तथा सामंत भूस्वामियों को अकाव्य रूप से विश्वास था कि किसान को सही मार्ग पर चलाने के लिये कठोर अनुशासन अनिवार्य है। इसका सबसे आसान और सुरक्षित उपाय है उनको दासता से जकड़े रहना। किसानों के स्वतन्त्रता का विचारमात्र अराजकता तथा अनुशासनहीनता को आह्वान देना है। राजनैतिक ढाँचे को बनाये रखना किसान की दासता से ही सम्भव है। असंतुष्ट एवं शोषित किसान द्वारा समय-समय पर होने वाले विरोध तथा विद्रोह इन विचारों का प्रमाण माने जाते थे। इस पृष्ठभूमि में कृषि सम्बन्धी नीति और इनकी विफलता को समझ सकना आसान हो जाता है। महान पीटर, कैथरीन द्वितीय तथा निकोलस प्रथम के सद्भावनाओं को निरर्थक सिद्ध होने का मुख्य कारण था कि वे दो परस्परविरोधी धाराओं को एक साथ चलाना चाहते थे। दासता और भूस्वामी के विस्तृत अधिकारों को बनाये रखने के साथ उन्होंने किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया। वे यह न समझ न सके कि किसानों की दासता ही उनकी प्रगति में इतना बड़ा अवरोध है कि बिना उसे दूर किये उन्नति असम्भव होगी। एलेक्जेंडर द्वितीय ने जब यह समझा और दासों की मुक्ति के लिये उद्यत हुआ, उस समय तक दशा इतनी बिगड़ चुकी थी कि बिना समूल परिवर्तन किये किसानों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। सम्राट को घेरे हुए स्थायी सलाहकारों ने मुक्ति अधिनियम [Emancipation act 1861] को इस तरह विकृत कर दिया कि सारा प्रयत्न ही विध्वंस हो गया और असीमित सद्भावना तथा सद्बुद्धयता लिये हुये उस नेक सम्राट को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी।

यह कहना अनुचित न होगा कि आदि काल से ही सभी शासक और जारों की कृषि नीति का मूलाधार था—अधिकतम कर व उसकी वसूली में सुविधा जिससे उनकी विलासिता और सैनिक कार्यवाही का खर्च निकल सके।

पहला काम जो रोमनोव वंश ने शासन भार संभालते ही किया वह था मीर का पुनर्संगठन और कर वसूली के लिये आपसी आश्वासन [Mutual guarantee] को फिर से संगठित रूप से प्रयोग में लाना। सुविधा का ध्यान रख कर हर करदाता को रजिस्टर करने का प्रयत्न किया गया जिससे कि वह एक क्षेत्र से ही सदा टैक्स दिया करे। पीटर महान् ने अपने समय में कर की वसूली के लिये अपनी सेना का प्रयोग किया। इनके अत्याचार के कारण बहुत से किसान अपनी जमीन छोड़-छोड़ कर भाग गये। इससे खेती में अव्यवस्था पैदा हुई। किसान की गरीबी और असन्तोष की वृद्धि में सहायता मिली। पीटर के कुर-व्यवस्था के अनुसार स्वतन्त्र किसान, कृषि दास, गृह दास इत्यादि

में कोई अन्तर न रह गया। ग़हदास [khorop] अभी तक कर नहीं देते थे। अब उन पर भी कर लगाया गया।

पीटर ने एक और बहुत बड़ा परिवर्तन कर-व्यवस्था में किया। उस समय तक कर उस भूमि पर लगता था जिस पर खेती की गयी हो। परिणामस्वरूप विस्तृत पैमाने पर भूमि खेती के बाहर चली गयी। इस कमी को दूर करने के लिये पीटर ने भूमि के जगह परिवार [Household] पर कर लगाया। यह भी सफल न हुआ क्योंकि लोगों ने बचने के लिये एक ही परिवार में बहुत से व्यक्ति शामिल कर लिया। कर-वृद्धि तो कम हुई पर गाँव की व्यवस्था बिगड़ने लगी। दुबारा फिर पीटर ने नई पद्धति चलाई। परिवार [Household] के स्थान पर प्रति व्यक्ति [per soul] पर कर लगाया। कर की मात्रा आबादी के साथ सम्बन्धित हो गयी और कम भूमि पर खेती करने की प्रवृत्ति भी न रही। 18 वीं शताब्दी में खेती के क्षेत्रफल और किसानों तथा भूस्वामियों की सम्बद्धि में काफी प्रगति हुई जिसका मुख्य कारण पीटर की कर-व्यवस्था ही मानी जाती है। इन परिवर्तनों के साथ-साथ करवसूली का तरीका भी बदला। दो व्यक्तियों की जिम्मेदारी प्राप्त करने के लिये, सीधे किसान के बजाय, भूस्वामियों से कर लिया जाने लगा। भूस्वामी इसे अपने क्षेत्रों के किसानों से इकट्ठा करते थे। इस प्रकार भूस्वामी केवल भूमि और दासों के मालिक होने के साथ-साथ ज़ार के प्रतिनिधि के रूप में टैक्स-वसूली भी करने लगे।

### उत्पादन संगठन तथा प्रणाली

रूसी कृषि के उत्पादन संगठन की अभी तक एक निराली पद्धति थी जिसे मीर अथवा ओबशीना [mir or obtschina] कहते हैं। यह ग्रामीण संगठन कितना पुराना है अथवा रूस में इसकी उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ इसमें बहुत मत-भेद है। लगभग 1550 के पहले के कृषि संगठन से 18 वीं शताब्दी के कृषि संगठन में कुछ सादृश्य अवश्य पाया जाता है किन्तु यह अत्यन्त अस्पष्ट ही रहा। बाद में भी इसका रूप और कार्य-प्रणाली समय-समय पर और भिन्न-भिन्न स्थानों में अलग-अलग रही। यह भिन्नता इतनी प्रबल है कि किस समय या स्थान पर पाया जाने वाला कौन-सा ग्रामीण संगठन मीर का सच्चा प्रतिनिधि रूप माना जाय, यह कहना प्रायः असम्भव है। 1861 तक के मीर संगठन में मोटे तौर पर यह विशेषताएँ थीं—

1. इसकी सदस्यता वंशानुगत थी लेकिन नये सदस्य भी बनाये जाते थे।
2. सदस्य खेतों पर परिवार सहित काम करते थे और पद्धतियों का सामयिक बँटवारा [periodic distribution] किया जाता था। यह बँटवारा श्रमशक्ति अर्थात् वयस्क काम करने वाले पुरुष, या परिवार में रहने-खाने वालों की संख्या के अनुसार होता था।

३. ग्रामीण सङ्गठन के सदस्य सार्वजनिक चरागाह, मछली के तालाब, जंगल इत्यादि का प्रबन्ध करते थे। इसके साथ अनावश्यक सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल, नई जमीन खरीदना अथवा विशेष अधिकार प्राप्त करना सामूहिक रूप से मीर के द्वारा होता था।

गाँव के इस सार्वजनिक भूमि स्वामित्व और उत्पादन पर मीर सङ्गठन की नींव थी। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई; उतना ही अस्पष्ट है जितना कि उसकी उत्पत्ति का कारण। प्राचीन रूसी परम्परा और प्रथाओं को आदर्श मानने वाले स्लाव भक्तों [Slavophiles] के विचार से कृषि के क्रमिक विकास के साथ स्मृतिलिखित रूप से मीर का भी जन्म और विकास हुआ। किसान की सहकारी प्रवृत्तियों का यह ग्रामीण सङ्गठन स्वाभाविक परिणाम था। इस प्रकार इस वर्ग के लोग यह नहीं मानते कि राज्य अथवा शासन की सुविधा से मीर का कोई भी सम्बन्ध रहा हो। दूसरे वर्ग के विचारक 16 वीं शताब्दी से लगातार बढ़ते हुए राज्य के वित्त और शासन प्रबन्ध के कार्यक्रम का सीधा प्रभाव मीर सङ्गठन को मानते हैं। उनके अनुसार दास प्रथा पर आधारित भूस्वामित्व के कारण यह प्रथा विस्तृत रूप से प्रचलित हो गयी। स्मृतिलिखित दृष्टि से दोनों विचार-धाराओं का अध्ययन करने पर मालूम पड़ता है कि मीर रूसी कृषि की अत्यन्त प्राचीन सङ्गठन प्रणाली थी जिसका विकास राज्य और दास स्वामित्व द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित होकर 16 वीं शताब्दी के बाद हुआ। कीव रूस [Kiev Russia] तथा मंगोल काल में कृषि की यह विशेषता थी कि खास-खास कामों को सामूहिक रूप से किया जाता था जैसे भूमि का हस्तांतरण; नये निवासियों को लेना, बेकार भूमि का प्रयोग इत्यादि। इस सङ्गठन का जो रूप 19 वीं शताब्दी के प्रथम भाग में पाया जाता था उसकी रूपरेखा 15 वीं शताब्दी के अन्त तथा 16 वीं शताब्दी के आरम्भ में बनना शुरू हुई। भूमि का पुनर्वितरण, सामुदायिक भूमि स्वामित्व तथा श्रम, और भी बाद में इसका अंग बने। किन्तु सदा से प्रथा पर अवलम्बित विधान, सिद्धान्त और अधिकार इसका मूलधार थे। समय एवं बाहरी रूप परिवर्तन इसमें कोई बुनियादी अन्तर न ला सके। दुर्गल राज्य सङ्गठन तथा सैनिक आवश्यकताओं के दबाव के कारण 17 वीं और 18 वीं शताब्दी में मीर पर ही राजकीय करों की वसूली का कार्य सौंप दिया गया। यद्यपि 19 वीं शताब्दी के मध्य तक सामान्य रूप से बकाया कर की वसूली का उत्तरदायित्व मीर पर नहीं आया था, शासन की सुविधा ने शीघ्र ही यह काम भी मीर के ऊपर लाद दिया। इस प्रकार यह कृषि-सङ्गठन राजकीय वित्त शासन प्रबन्ध का एक हिस्सा बन गया।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> John Mavnard Russian Peasant and Other Studies. p. 30.

रूसी भाषा में गाँवों को 'मीर' कहा जाता है जिसका कि दूसरा अर्थ 'ससार' भी होता है। यह गाँव आत्म-निर्भर, बाहर की दुनिया से एकदम पृथक् एवं स्वशासित सङ्गठन था। इस सङ्गठन की प्रमुख विशेषता, सामुदायिक उत्तरदायित्व [mutual guarantee system], लगभग 16 वीं शताब्दी से सामने आने लगा। इसके अंतर्गत उत्पादन, भूमि स्वामित्व, श्रम और आय का बँटवारा और विशेषकर कर का बँटवारा व भुगतान की जिम्मेदारी अलग-अलग व्यक्तियों पर न होकर सामूहिक रूप से सारे गाँव अथवा मीर पर होती थी। कर के भुगतान के साथ दाखों का भी दायित्व मीर सम्मिलित रूप से उठाता था। गाँव समुदाय या मीर अपने ऊपर लगे कर को उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर बँट देते थे। सामुदायिक उत्तरदायित्व होने से अगर कोई सदस्य निजी कर-भाग न दे सके तो मीर को मिल कर उस कमी को पूरा करना पड़ता था। यह इतना बड़ा दबाव था कि किसान द्वारा कर न देना, सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करना था। साथ-साथ यह भी था कि अगर मीर का किसान गाँव छोड़कर शहर में नौकरी करना चाहे तो भी उसे अपने हिस्से का कर अदा करना ही होता था। इस बात की छूट थी कि सदस्य किसान अपने खेत पर काम करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति से तय कर ले और स्वतः बाहर जाकर नौकरी करे। किन्तु यह प्रबन्ध उसका व्यक्तिगत प्रबन्ध होगा। मीर अथवा राज्य अपना सम्पर्क उस किसान से ही रखेगा। इस तरह रूसी किसान जमीन के साथ ऐसा बँध गया कि उसका छूट निकलना किसी भी प्रकार सम्भव न था।

प्रसिद्ध यात्री मिर्कैज़ी वेल्लेस ने लिखा है कि मीर सङ्गठन [जिसमें देश की 5/6 जनता बसती थी] वैधानिक प्रजातन्त्र शासन का उत्कृष्ट एवं अचूक नमूना था। न केवल टैक्सों का विभाजन और भूमि का बँटवारा इनका उत्तरदायित्व था वरन् सदस्यों द्वारा सामाजिक कर्तव्यों का पालन कराना भी इनका अधिकार था। न्याय का कार्य इनकी अधिकार-सीमा के बाहर था। पर छोटे दोषों और दुष्कर्मों का दंड निर्धारण मीर करते थे जैसे जुर्माना, जेल और कोड़े लगाना। गाँव का 2/3 मत प्राप्त करने पर किसी दुश्चरित्र अथवा समाजद्रोही को निष्कासन भी दे सकता था। इसके अतिरिक्त मीर के प्रतिनिधि को शासन में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह अपने क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अफसरों का सहायक माना जाता था। जिले का टैक्स निर्धारण, नये बसने वालों में बेकार भूमि का वितरण इत्यादि कार्यों में वह मदद करता था। अपने क्षेत्र की ओर से वह स्थानीय अदालत का सदस्य था और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय समस्याओं को केन्द्रीय सरकार तक ले जाता था।

मीर के आंतरिक शासन का कोई एक निश्चित रूप सभी जगह नहीं पाया जाता। प्रत्येक वयस्क पुरुष को भूमि के बँटवारे के लिये एक इकाई माना जाता था।



1906 तक हर एक परिवार एक इकाई होता था न कि उस परिवार का कर्त्ता। 1906 के बाद परिवार के कर्त्ता को ही भूमि के बँटवारे और कर के हिस्से के लिये इकाई माना गया। इस दिशा में यह भी ध्यान रखा जाता था कि परिवार कितना बड़ा है और उसके पास कितने पशु हैं। भूमि बँटवारे का अर्थ यह नहीं हुआ कि गाँवों की भूमि ही किसानों को मिल जाती थी। किसान को केवल गाँव के भूमि का एक हिस्सा दिया जाता था जिस पर कि वह काम कर सके। उसका स्वामित्व मीर के पास ही रहता था। भूमि का विभाजन अनेक प्रकार से होता था। सबसे प्रचलित रूप यह था : गाँव के सभी परिवारों को उनमें वयस्क काम करने वालों की संख्या के अनुसार भूमि दी जाती थी। गाँव की जमीन को पट्टियों में विभाजित करके, श्रम शक्ति के अनुसार परिवारों में बाँट दी जाती थी। मकान, फ्लैक्स, तरकारी और दूधरी ऐसी आवश्यकताओं के लिये एक छोटा-सा बगीचा प्रत्येक परिवार की पैतृक सम्पत्ति होती थी। इस पर मीर समुदाय का अधिकार न था। घास के मैदान और जंगल या तो आवश्यकतानुसार बाँटे जाते थे या फिर सारा गाँव मिलकर उनका प्रयोग करते थे। खेतों का सङ्गठन प्राचीन तीन-खेत पद्धति पर था। यूरोप के दूसरे देशों के विपरीत रूसी तीन-खेत पद्धति में पट्टियों का बँटवारा आवादी में परिवर्तन के साथ-साथ बार-बार होता रहता था।

सामुदायिक कृषि पद्धति की एक विशेषता है जिसको आर्टेल [artel] कहते हैं। शताब्दियों से आक्रांत और शोषित किसान संरक्षण और आत्मविश्वास की खोज में धीरे-धीरे इतना आपस में बँध गया कि रूसी कृषि की एक निराली कार्य प्रणाली का जन्म हुआ। सुख और दुख, काम और आराम सभी में उन्होंने साथी और साथ का सिद्धान्त अपनाया। इस प्रकार जीवन के विविध क्षेत्रों में सहकारिता का सहारा लेना काफी प्राचीन रूसी परंपरा है। किसी भी काम करने के लिये किसान सहकारी समिति अथवा आर्टेल बनाता था। इनकी रूढ़ि-रेखा और काम का ढंग समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहा है। कृषि में इनका सबसे विस्तृत प्रयोग मीर के सामुदायिक कृषि के तरह होता था। 1917 के क्रान्ति के बाद साम्यवादी सिद्धान्तों से प्रेरित होकर उसकी श्रेष्ठता एवं व्यापकता दोनों ही निखर उठीं। आर्टेल कार्य प्रणाली में उत्पादन सामूहिक रूप से होता था और अधिकतर उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व बना रहता था। मिलकर खेती करने से होने वाली उपज को आपस में बाँट लिया जाता था। व्यक्तिगत स्वामित्व का इसमें काफी स्थान था। निवास स्थान, निजी बगीचे के लिये जमीन, पशु इत्यादि किसान का अपना होता था। इनसे होने वाली आय उसकी निजी सम्पत्ति थी।<sup>1</sup>

1. For details about Artel see Maurice Dobb. Economic Deve-

अब रूसी ग्रामीण संगठन अथवा मीर पर एक विवेचनात्मक दृष्टि डाली जा सकती है। रूसी कृषि को इस समय में कई त्रुटियाँ दिखलाई पड़ती हैं। इनका आधार मीर और आरटेल ही कहा जायेगा। खुले खेतों की पद्धति यूरोपीय कृषि की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। खुले खेतों के साथ-साथ जमीन का तीन हिस्सों में बँटवारा करके अज्ञानतावश किसान खुद अपनी आय कम कर लेता था। जमीन के एक-तिहाई हिस्से पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता। फसल की उचित अदला-बदली न होने से उत्पादन और कृषि का लाभपूर्ण होना दोनों ही घट जाता। मीर की बढ़ती हुई आबादी के कारण भूमि का पुनर्वँटवारा बराबर होता रहा। इससे सभी सदस्यों को भूमि तो जरूर मिली लेकिन भूमि का परिमाण कम होता गया। पुराने क्रिम की खेती का तरीका और अवैज्ञानिक खाद के साथ जब यह कमजोरी भी मिल गयी, तो किसानों की दशा पर बहुत बुरा असर पड़ा। यह जोत की कमी कितने बड़े पैमाने पर हुई, इन आँकड़ों से विदित होता है।<sup>1</sup>

	1860	1880	1890
केन्द्रीय क्षेत्र	4	3.3	2.6
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	8.4	5.3	3.2

इसके अलावा किसी भी किसान को निश्चित रूप से भूमि के प्रति अपना-पन अनुभव न होता था। वह नहीं जानता था कि चन्द वर्षों में उसकी जमीन किसके पास होगी। हो सकता है कि अगर उसने जमीन की बहुत अच्छी देख-रेख की तो अगले बँटवारे में किसी अन्य अधिक प्रभावशाली व्यक्ति को वह दे दी जाय। इसलिये जोतो के छोटे होने के साथ-साथ पुनर्वँटवारे के डर ने उस छोटे से खेत को भी पूर्ण उपजाऊ अवस्था में बनाये रखने का प्रोत्साहन किसानों से छीन लिया। इससे भूमि की उत्पादकता पर गहरा असर पड़ा। वंशपरंपरानुसार संयुक्त परिवार के एक कार्यकर्ता के पूर्ण अनुशासन में रहने की पद्धति ने रूसी कृषि में रूढ़िवाद और पुराने विचारों को बड़े व्यापकता के साथ भर दिया। यह कर्त्ता परिवार पर पूर्ण अधिकार रखता था और अधिकतर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता था। सामूहिक कृषि प्रथा के कारण सभी को अपनी फसल एक ही समय पर एक-ही विधि द्वारा बोना और काटना पड़ता था। इससे व्यक्तिगत उत्साह और प्रगति-प्रेम प्रायः नष्ट-सा हो जाता था।

lopment of Russia Since 1917 pp. 223-224; L. C. A. Knowles, *Economic Development in the 19th century*, p. 78, H. Schwartz *Russia's Soviet Economy* pp. 258-260.

1. Figures are in Desyantine. One desyantine=2.7 acres—Knowles, op. cit, p. 79.

मीर के द्वारा प्राप्त सुरक्षा और संरक्षण इतना विस्तृत और पूर्ण था कि किसानों को अपनी पूर्ण बुद्धि और कार्य शक्ति के साथ काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी। संयुक्त दायित्व ने किसान को लापरवाह और आलसी बना दिया। वह कम से कम उतना ही कार्य करता था जितने में दूसरे सदस्य उस पर उँगली न उठा सके। खेत छोटे होने के साथ-साथ इतने बिखरे हुए थे कि उनका लाभपूर्ण प्रयोग होना बहुत कठिन हो जाता। एक व्यक्ति के पास बहुत-सी पट्टियाँ भी होती थी। 20 या 30 से लेकर कभी-कभी 100 तक एक व्यक्ति या परिवार के पास पट्टियाँ होती थी। केवल इतना ही नहीं, इनकी आपसी दूरी 51-20 किलोमीटर तक होती थी। ये दूरियाँ इतनी काफी थीं कि एक पट्टी से दूसरी पट्टी तक जाने में अक्सर किसानों को सारे दिन की यात्रा करनी पड़ती थी। इससे होने वाली श्रम-हानि किसान के लिये असहनीय भार था।

आवादी के बढ़ जाने पर मीर पास की भूमि खरीद कर अपनी सीमा-विस्तार करते थे। नयी भूमियों के बँटवारे में पुनर्वटवारे के ही तरह बड़े पैमाने पर पक्षपात होता। प्रभावशाली व्यक्तियों को अच्छी जमीन पास की पट्टियों में मिल जाती थी। एक तरह से देखा जाय तो मीर में दिये गये शक्तिशाली सामूहिक अधिकारों का ग्रामीणों द्वारा स्वयं न्यायपूर्ण प्रयोग करना प्रायः असंभव-सा था। संसार के आधुनिक स्वायत्त शासन और ग्रामीण संगठनों में इसका पर्याप्त उदाहरण मिलता है। इस पक्षपात ने मीर की जनता को दो वर्गों में तोड़ना शुरू किया। धनवान और सफल किसान तरक्की करने लगे लेकिन उनसे कम भाग्यशाली साथी आगे न बढ़ सके। इस परिवर्तन ने मीर की आंतरिक संगठन शक्ति को बहुत कम कर दिया।

सामुदायिक ग्राम संगठन में कुछ बुराईयाँ भी थी। कृषक की कुशलता तथा अधिकतम मेहनत करने का उत्साह कभी बढ़ नहीं पाया था। वह केवल इतना ही काम करना पसन्द करता था कि मीर के दूसरे सदस्य आपत्ति न कर सकें। कृषि के ढंग में भी रूढ़िवादिता आ गयी और नये तरीके का अपनाना प्रायः असंभव बन गया। भूमि के समबंटवारे से किसान सदा के लिये बँध गया। खेती को छोड़ कर या खेती के साथ और किसी काम को करने की बात वह नहीं सोचता था। इससे उद्योग तथा शहरों की उन्नति में अवरोध पैदा हुआ। भूस्वामी तथा किसान संसार से दूर अपने गाँवों की सीमा को ही अपनी सीमा मान बैठे। इनका देश तथा विश्व से सम्पर्क न रहा। सामाजिक प्रगति तथा विचारों का उत्कर्ष ऐसी परिस्थिति में कदापि सम्भव न था। मीर संगठन के ऊपर बताये गये लाभ भी स्वार्थपूर्ण, अकुशल प्रबन्ध के कारण पूरे न मिल पाते थे। बाहर रहने वाले भूस्वामी अपने रिश्तेदार अथवा कर्मचारी पर ही सम्पत्ति का प्रबन्ध छोड़ देते थे। अगर उनको आवश्यकतानुसार धन मिलता रहा

तो सब कुछ ठीक समझ कर संतुष्ट रहते थे। अस्सर यह हुआ कि कर्मचारी निरंकुश होकर मनमानी करने लगे। किसान को राज्य-कर तथा भूस्वामी के शोषण के साथ-साथ इन कर्मचारियों के लालच का भी बौझ टोना पड़ता था।

इन सब बुराइयों के साथ-साथ मीर संसार की प्राचीनतम सामाजिक सुरक्षा पद्धति कहा जा सकता है। हर एक व्यक्ति को उसके आवश्यकतानुसार सुविधाये देने का प्रयत्न, विपद में सहायता और कार्य में सहयोग, मीर को सबसे बड़ी देन थी। कोई भी यह नहीं अनुभव कर पाता था कि वह अनाथ, निराश्रित या बेकार है। जन्म-सिद्ध अधिकार के रूप में भूमि के पुनर्बँटवारे का नियम किसी भी सदस्य को बिना जीविका के साधन के न रहने देता। आत्मनिर्भरता [Self Sufficiency] और प्रजातन्त्रात्मक ढाँचा लोगों में शान्ति और सतोष उत्पन्न करने के लिये आदर्श कहा जा सकता है। सामुदायिक श्रम काल के बाद, व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त परिश्रम द्वारा आयवृद्धि की छूट किसानों को सर्वदा अधिकतम प्रयत्न के लिये उत्साहित करती थी। यह प्रयास विशेषकर कुटीर उद्योग की उन्नति में दृष्टिगोचर होता है। मीर संगठन से किसानों को बहुत लाभ तथा सुविधाये मिलती थी। सदस्यों के बीच भूमि के बराबर बँटवारे से सभी को लाभ था। भूस्वामी को कर मिलने में सुविधा होती थी आलसी अशक्त व्यक्तियों का आर्थिक भार समुदाय पर पड़ता था। किसानों को इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि समाज में कोई भी भूमिहीन नहीं हो सकता था। सभी को जीविकोपार्जन का साधन - भूमि—मिलती थी। कोई किसान दूसरे से अत्यधिक अमीर नहीं हो सकता था। आपस में इतने निकटता से बँधे होने के कारण, किसानों में अत्याचार का विरोध करने की शक्ति भी मिलती थी। अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेको लाभ थे। सामान्य श्रम, गरीब और वृद्ध की मदद तथा आपसी उदारता उनको सुन्दर सामाजिक सुरक्षा बीमा प्रदान करती थी। एक सामाजिक अन्न कोष का निर्माण किया जाता था जिससे निराश्रित का पालन होता था। मीर सामुदायिक साख पर राज्य या भूस्वामी से जमीन पट्टे [lease] पर लेता था। इससे सदस्यों को अधिक भूमि मिलना सम्भव हो जाता था।

मीर संगठन का महत्व तथा प्रभाव उन सम्पत्तियों पर अधिक था जहाँ बारशीना न होकर ओब्राक पद्धति थी। इनकी शक्ति उन स्थानों पर बहुत विकसित थी जहाँ पर भूस्वामी अधिकतर राज्य सेवा में बाहर रहता था। ऐसी दशा में मीर के आंतरिक प्रबन्ध में किसानों को अच्छे पैमाने पर स्वायत्त शासन [Self Government] प्राप्त था। १८वीं शताब्दी के आरम्भ में बहुत विस्तृत रूप में यही दशा पाई जाती थी।

एलेक्जान्डर द्वितीय के दास-प्रथा सम्बन्धित सुधार के प्रयत्नों ने मीर को रूसी कृषक का एकमात्र संगठन बना दिया। इनको भूमि का पूर्ण प्रबन्ध सौंप दिया गया। एक

वैधानिक शक्ति प्राप्त सस्था की तरह मीर किसान और भूस्वामी के बीच मध्यस्थ बना। 1861 के दास-मुक्ति तक तो इस समुदायिक ग्राम संगठन को मीर कहा जाता था, पर उसके बाद इसे ओबश्चीना [obtschina] की संज्ञा दी गयी। इसकी चार मुख्य विशेषताएँ थी।

1. भूमि का सामान्य अधिकार [common possession]
2. खेत की अनिवार्य समानता
3. समाज का कठोर वर्ग विभाजन
4. कर भुगतान का आपसी आश्वासन अथवा उत्तरदायित्व [mutual guarantee]

अतः यह कहना अनुचित न होगा कि मीर संगठन रूसी कृषि और कृषकों की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। लेकिन आधुनिक मुद्रा विनिमय युग में मीर उपयुक्त न सिद्ध हो सका और 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान शताब्दी के प्रथम चन्द वर्षों में यह प्रभावहीन होकर नष्टप्राय हो गया।

## अध्याय ३

# वस्तु निर्माण तथा उद्योग [१८६१ तक]

[Manufacturing and Industry] [upto 1861]

रूसी औद्योगीकरण की पूर्व कथा का लगभग वही क्रम रहा है जो कि संसार के दूसरे देशों में पाया जाता है। अर्थ-व्यवस्थाओं की शृङ्खला के अनुसार [प्रारम्भिक, सामंतवादी, पूँजीवादी, तथा समाजवादी] इसका भी रूप और क्षेत्र बदलता रहा। वस्तु उत्पादन [Manufacturing] तो मनुष्य की आवश्यकताओं से जुड़ा एक ऐसा कार्य है जो कि रूसी जनता सदा से करती आई है। इसके अंतर्गत अपने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए अथवा पास-पड़ोस वालों के लिए छोटी-छोटी चीजों का निर्माण करना आता है जैसे कपड़ा, चमड़ा और छोटे औजार। किन्तु उद्योग के अंतर्गत कारखाना उत्पादन पद्धति को रखना होगा जिसकी व्यापकता [उत्पादन तथा बाजार] बहुत अधिक थी और इनके काम का ढङ्ग भिन्न था। औद्योगिक पूँजीवाद के विकास तक इस क्षेत्र में [आर्थिक क्षेत्र के एक विशिष्ट अंग की तरह] कारखाने नहीं बन सके थे। उलभन को हटाने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु-उत्पादन [Manufacturing] तथा कारखाना उत्पादन [Factory] में अंतर किया जाय।

## वस्तु-निर्माण का क्रमिक विकास

नवी, दसवीं शताब्दी तक छोटे पैमाने पर स्वयं के प्रयोग के लिए कुछ उद्योग पाये जाते थे जिनमें से मुख्य बड़ईगरी, कनवास बनाना, चमड़ा, कच्चा लोहा और औजार निर्माण था। इसकी प्रगति इतनी धीमी थी कि लगभग 17 वीं शताब्दी तक शहरों में वस्तु उत्पादन छोटे पैमाने पर केवल समाज के निम्न वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता था। इस उत्पादन में मुख्य प्रोत्साहन, संगठन एवं आर्थिक सहारा व्यापारियों द्वारा प्राप्त था। व्यापार को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इन्होंने अपने बाजार की आवश्यकता की चीजों का निर्माण कराना आरम्भ किया। इस तरह व्यापारिक-पूँजी पूँजी के ऐतिहासिक रूप में प्रयोग होने लगी। इसमें विशेषता यह थी कि उत्पादन में पूँजी का पूर्ण प्रभुत्व आने में कई सौ वर्ष की देरी थी।

कारखानों की स्थापना तथा वस्तु-उत्पादन की वृद्धि दोनों पर समकालीन राज-नैतिक स्थिति तथा सैनिक दृष्टिकोण का बहुत गहरा प्रभाव था। 17वीं शताब्दी तक देश

राजनैतिक रूप से अत्यन्त अस्थिर तथा असंगठित था। परिणामस्वरूप सभी शहरों का निर्माण योरोप से एकदम पृथक् तरीके से हुआ। योरोप के शहर व्यापारिक मार्गों पर स्थापित हुये और धीरे-धीरे औद्योगिक रूप से भी विकसित हुये। इसके विपरीत, रूस के शहर केवल शासन नियंत्रण केन्द्र तथा सेना का गढ़ मात्र बने। शहरों का विकास केवल देर में ही नहीं हुआ, इसका उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं था। अतः वस्तु-निर्माण के लिए स्थायी केन्द्र न होने से इस दिशा में प्रगति बहुत कम हो गई। जिस समय योरोप में कारीगर सघ [Craft guilds] का निर्माण हो चुका था; रूस के शहरों में औद्योगिक वर्ग का जन्म भी नहीं हुआ था।

निर्मित वस्तुओं की माँग अत्यन्त कम थी। गरीब ग्रामीण जनता अपनी चन्द माँगों की पूर्ति आत्मनिर्भर ग्राम सगठन [Self-sufficient Village economy] में कर लेती थी। शहरों में वैसे लोग अधिकतर सरकारी या फौजी अफसर थे। धनवान लोग विलासिता की विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते थे और अन्य व्यक्ति अपनी आवश्यकता स्थानीय कारीगर द्वारा पूरी कर लेते थे। इस परिस्थिति में वस्तु-निर्माण का पिछड़ा जाना स्वाभाविक था। इस समय तक अधिकतर उत्पादन कार्य समाज के कुछ वर्ग ही करते थे। प्रथम तो गाँव की प्राचीन वस्तु-निर्माण व्यवस्था थी। इसमें अपनी या पड़ोसियों की आवश्यकता के लिए धातु, प्लैक्स, सिल्क तथा ऊन का सामान तैयार होता था। इसकी स्थानीय बाजार थी। 15 वीं और 17 वीं शताब्दी के बीच अधिकतर उत्पादन कृषक द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए होता था। किसान इस उत्पादन को खेती से बचे समय में करता। 16 वीं शताब्दी के अन्त तथा 17 वीं के आरम्भ में एक दूसरे प्रकार का बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ हुआ। इसे भूस्वामी वर्ग अपने-अपने क्षेत्र में अपने ही किसानों द्वारा चलाता था। किसानों से श्रम भुगतान [Bartschina] कारखाने में काम के रूप में वसूल करके, इन कारखानों का श्रम प्राप्त किया गया। बाद में वस्तु या धन भुगतान [Obrok] करने वाले किसानों से भी इन पर काम कराया जाने लगा। इनके अतिरिक्त समृद्धिशाली किसानों में एक नया वर्ग सामने आया जिसने उन उद्योगों को चलाना आरम्भ किया जिनमें साल भर उत्पादन होता था और बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। इस क्षेत्र में सबसे पहले लोहा और नमक उद्योग किया गया। बाद में खान, पोटास और धातु निर्माण [Metallurgy] भी सम्मिलित हो गया। कुछ सामत भी इस ओर आकर्षित हुये। इस समय की एक विशेष उन्नति उल्लेखनीय है। खानों और फौजी उत्पादन के क्षेत्र में राजकीय कारखाने बने। कुशल विदेशी कारीगरों को निमन्त्रित करके पश्चिमी यूरोप की प्रगति का लाभ उठाने का श्रेय इन राजकीय कारखानों को ही प्राप्त है।

भूस्वामी, व्यक्तिगत तथा राजकीय कारखानों में कृषक-दास [Serf] द्वारा ही

श्रम प्राप्त होता था। जार, भूस्वामी और गिरजाघरो के भूमि से बँधे कृषि-दासों को खेती से हटाकर कारखानों में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार रूस के प्रायः सभी महान् उद्योगों की नींव दास श्रमिकों के द्वारा पड़ी। इसका मुख्य कारण था कि उस समय स्वतन्त्र श्रमिक वर्ग का निर्माण नहीं हुआ था। किसान जमीन और खेती छोड़कर कारखाने में काम करने को तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, भूस्वामी भी उनको छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी खेती के काम के लिए भी भारी आवश्यकता थी। यह स्पष्ट है कि आरम्भ से ही किसान कारखाने के बन्धन का विरोध करता था। यह विरोध दास-मुक्ति [Emancipation 1861] तक लगातार चलता रहा। कृषि से किसानों को बलात् हटा लेने से कमजोर आर्थिक कृषि एकदम अव्यवस्थित हो गई। किसानों के इस असंतोष को दास-मुक्ति का मुख्य कारण कहा जा सकता है। बलात् कारखाना श्रम [Forced factory labour] की प्रथा लगभग 200 सालों तक चली। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति सदा अस्पष्ट रही। श्रमिकों की दशा सुधारने के सभी प्रयत्न असफल हुए क्योंकि यह प्रथा अभिन्न रूप से दास-प्रथा से जुड़ी थी। राजकीय सरक्षण तथा प्रोत्साहन प्राप्त होने पर भी इसी प्रथा के कारण रूस का औद्योगिक विकास आशातीत रूप से न हो सका।

वस्तु निर्माण के क्रमिक विकास में 15 से 17 वीं शताब्दी के बीच कुछ विशेष परिवर्तन पाये जाते हैं : श्रम का सामाजिक विभाजन, मुद्रा अर्थ-व्यवस्था का विकास तथा वस्तु विनिमय बाजार का निर्माण। इन परिवर्तनों ने देश के औद्योगिक प्रगति में प्रोत्साहन दिया।

पीटर प्रथम अथवा महान् पीटर के आने से इस दिशा में मौलिक परिवर्तन हुआ। इस समय उपभोग के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में वस्तु-निर्माण आरम्भ हुआ। विकास की यह दशा 19 वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही जबकि पूँजीवादी कारखाना पद्धति का उदय हुआ। यह कहना तो उचित न होगा कि रूसी उद्योग की नींव केवल महान् पीटर द्वारा डाली गई किन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि वस्तु-निर्माण की आवश्यकता को अत्यन्त प्रभावशाली रूप में पीटर ने सामने रक्खा। आरम्भ से ही सम्राट पीटर और उसके सहयोगी योरप के व्यापारवाद के सिद्धान्त से प्रभावित थे। एक विलक्षण कुशल कारीगर होने के साथ साथ योरप भ्रमण से महान् पीटर में रूस के प्रगति की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट हुई। योरप के उन्नतिशील देशों को देखकर रूस के इस लौह पुरुष ने तेजी के साथ देश की फौज तथा सुरक्षा को सुधारने के लिए मिल और कारखाने बनाने शुरू किये। इस समय उत्पादन कार्य करीब-करीब पूरी तरह राज्य के द्वारा ही किया जाता था। इसलिए इस क्षेत्र की उन्नति राज्य के अतिरिक्त साधनों पर निर्भर थी। किसान के शोषण द्वारा भूस्वामियों ने विशाल धन-राशि एकत्र की, लेकिन औद्योगिक



विकास को उसका सहारा आगे चलकर ही मिल सका। कृषि-दासता के ढाँचे में बँधी हुई रूस की अर्थ-व्यवस्था में उपभोग के लिए उत्पादन होता था। साथ-साथ श्रम का सामाजिक वर्गीकरण न होने से उपभोग की वस्तुओं की माँग भी बहुत कम थी। पश्चिमी योरोप तथा रूस के औद्योगिक विकास में एक विशेष अन्तर था। पश्चिमी योरोप की तरह, बढ़ते हुये उद्योगों को स्वतन्त्र औद्योगिक श्रमिक कृषि दासता के कारण प्राप्त न हो सके।

१८ वीं शताब्दी में दास-श्रमिक [Serf labour] उत्पादन की उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट थी। श्रम प्राप्त करने की समस्या सम्राट पीटर ने दास-प्रथा के रूपांतर से हल करना चाहा। १७२१ में एक राजाज्ञ द्वारा व्यापारियों को यह अधिकार मिला कि वे फैक्टरी में काम कराने के लिए निवासियोंसहित पूरे गाँव को खरीद सकते हैं। ये गाँव सदा के लिए कारखाने के एक अङ्ग माने जायेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों को कारखाने में काम करने के लिए आज्ञा दी जाती थी। इस तरह के श्रम को नियत अथवा नियुक्त श्रम [Assigned or ascribed labour] पुकारा जाता था। इससे यह विदित होता है कि उद्योग की प्रगति हो तो रही थी पर धीमी थी। पीटर प्रथम के समय से पहले भी कुछ उद्योग थे किन्तु उनको वास्तविक प्रोत्साहन पीटर के राज्यकाल में मिला। इनमें-से लोहा, हथियार, जहाज-निर्माण, ऊनी व सूती कपड़ा, सीसा, चमड़ा तथा रेशम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी संख्या के बारे में कोई भी विश्वस्त आँकड़े नहीं मिलते। फिर भी इतना माना जा सकता है कि पीटर प्रथम के राज्यकाल के अंत तक रूस में करीब २०० बड़े कारखाने थे। इनमें से अधिकतर राजकीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही बनाये गये थे। अर्थ और प्रगति की दृष्टि से यह काफी कमजोर थे।

कैथरीन द्वितीय के राज्यकाल में [१७६२-१७९६] उन्नति का क्रम बराबर चलता रहा किन्तु इसके पक्के आँकड़ों में भारी मतभेद है। इतना निर्विवाद है कि खनिज उद्योग [लोहा-कोयला] में उत्पादन बहुत बढ़ा। यूराल पर्वत की विशाल खानों पर काम आरम्भ हुआ। इस क्षेत्र से रूसी उत्पादन का ९०% ताँबा और करीब ९५% लोहा प्राप्त होता था।

आधुनिक उद्योग की नींव तो १९ वीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्षों के बाद पड़ी। सम्राट नेपोलियन के वापस जाने पर [१८१२] जब देश स्थिर हुआ, तभी योरोप से नयी औद्योगिक प्रणाली का रूस में प्रवेश हुआ, इसके आगमन से ही औद्योगिक विकास ने नई करवट ली। १८०५ में प्रथम वाष्प इंजन [Steam Engine] सूती कपड़ा उद्योग में लगा। १८१७ में प्रथम वाष्प-नौका [Steam boat] बनी। १८३६

में रेल तथा तार [Telegraph] का आरम्भ हुआ। 1857 में स्पात बनाने का बेस्मर प्रणाली पर परीक्षण आरम्भ हुआ। इस प्रकार कृषि-दासता के अवरोध के होने पर भी काफी बड़े पैमाने पर उद्योगों ने पुराना संगठन छोड़कर पूँजीवादी उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया।

दास-मुक्ति अर्थात् मध्य 19वीं शताब्दी तक आते-आते सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति की आपसी तनातनी व विरोध सामने आ चुका था। उसमें किसी को सदेह नहीं रह गया था कि औद्योगिक अकुशलता, खराब उत्पादन और पिछड़ेपन का अकेला दोषी दासता है\*। यह प्रभाव इतना अधिक था कि ऊँचे टैरिफ से सुरक्षित होने पर पश्चिमी योरोप के माल से घरेलू बाजार में भी सफल प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती थी। यह-उत्पादन की प्रथा, पिछड़े हुये समाज का अल्प उपभोग, और गरीबी के कारण\* निर्मित वस्तुओं की माँग अत्यन्त कम थी। कुछ उद्योग तो इन कठिनाइयों के बावजूद भी विकास कर गये किन्तु इनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। इतना विकास होने पर भी पश्चिमी यूरोप की तुलना में देश बराबर पिछड़ा जा रहा था। सूती कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त (जिसमें 1866 में 42 आधुनिक मिलें और 94600 मजदूर थे) लोहा निर्माण उद्योग का विकास बंद था। 1840 में शुरू होने पर भी रेल यातायात ने नाममात्र की उन्नति किया। आधुनिक साख संस्थाएँ लगभग नहीं के बराबर थी और प्रथम स्कंध प्रणाली व्यापारिक बैंक [Joint stock commercial bank] 1844 में स्थापित हो सका। चलन मुद्रा [currency] अस्थिर होने के साथ-साथ विघटित पत्र-मुद्रा [Depreciated paper currency] होने से उद्योग और व्यापार पर बहुत धक्का पहुँचा।

### उत्पादन संगठन

रूस के औद्योगिक विकास का संगठन किसी एक निर्दिष्ट पथ पर नहीं चला। कई दिशाओं से इसका सूत्रपात व विकास आरम्भ होकर 1861 तक इन मुख्य विभागों में परिणित हो गया।

#### १. राजकीय उत्पादन प्रणाली [State manufacture]

महान् पीटर की सैनिक, नौ-सेना तथा संरक्षण की आवश्यकताओं ने राज्य को वस्तु-निर्माण करने को उद्यत किया। देश के कुछ बहुत बड़े-बड़े कारखाने इस प्रकार बने। राजकीय उत्पादन को तीन मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है : पहाड़ी प्रदेश में लोहे के कारखाने, जहाज निर्माण की लकड़ी प्राप्त करने के लिये जंगल तथा अस्त्राखॉ [Astrakhan] का रेशम उद्योग।

राजकीय उत्पादन क्षेत्र में काम करने वाले किसान-राजकीय कृषक [State

peasants ] से भिन्न थे। राजकीय कृषकों को पोल टैक्स [ Poll tax ] तथा मुद्रा में ओग्राक देना पड़ता था किन्तु जो राजकीय किसान उत्पादन-क्षेत्र में काम करने के लिये नियुक्त किये जाते थे उनको केवल श्रम में भुगतान करना होता। 1769 के बाद उन्हें इतनी सुविधा और मिली कि श्रम-भुगतान का एक अंश धन से भी चुका सकते थे। अधिकतर राजकीय गाँवों के आधे व्यक्ति कारखानों में कार्य करने के लिए बाध्य थे। बहुत अधिक विरोध होने पर राज्य की ओर से इसे घटाकर एक-तिहाई कर दिया गया। किसानों को केवल राजकीय कारखानों के अलावा उन व्यक्तिगत उद्योगों में भी नियुक्त किया जाता था जिनको कि राज्य प्रोत्साहन देना चाहता हो। इस प्रकार के श्रम [Ascribed labour] की दशा [1741-1761] के बीच अत्यन्त शोचनीय हो गयी क्योंकि साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र के राजकीय उद्योगों को व्यक्ति प्रबन्ध में देने की नीति अपनाई। कैथरीन द्वितीय ने इन उद्योगों को द्विजारा राज्य के संरक्षण में लेकर विगडी दसवीं दशा को कुछ समझाया।

1724 में पीटर प्रथम ने एक राजाज्ञा द्वारा देश भर के औद्योगिक श्रमिकों का वेतन निश्चित कर दिया। राज्य द्वारा श्रमिकों की मजदूरी निश्चित करने का संसार में यह पहला उदाहरण है। राज्य यह प्रयत्न करता था कि इन सभी श्रमिकों पर एक-सा कर-भार पड़े। वास्तविकता में यह सफल न हो सका। फिर भी श्रमिकों पर कर का बँटवारा उन्हीं के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि-मण्डल करता था। अधिकतर राजकीय उद्योगों का प्रबन्ध तथा संचालन एक केन्द्रीय संस्था द्वारा होता था।

## (2) हस्तान्तरित उद्योग [Possessional Manufacture]

इस वर्ग के कारखानों का जन्म 1721 की राजाज्ञा द्वारा कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों अथवा व्यापारियों के कारखाने तथा वह उद्योग आते हैं जिन्हें राज्य ने इनको हस्तान्तरित किया। इस वर्ग के उद्योगपतियों को राज्य-सेवा और कर से मुक्ति तथा अन्य सुविधाएँ भी दी गयी थी। इस प्रकार के उत्पादन-संगठन की विशेषता यह थी कि गाँवों [और उसमें रहने वाले किसान] कारखाना मालिक से बँधे न होकर उद्योग अथवा कारखाने की सम्पत्ति थे। उनका अस्तित्व कारखाने से पृथक् नहीं किया जा सकता था। कारखाने के साथ ही साथ उन्हें भी खरीदा और बेचा जाता था। दूसरी विशेषता यह थी कि इन कारखानों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता था। उत्पादन, मूल्य, वेतन और काम का तरीका राज्य नियंत्रित एवं संचालित करता था। इस प्रकार यह विचारधारा सही नहीं मालूम पड़ती कि यह कारखाने पूँजीवादी उत्पादन के अग्रदूत थे। दासता के अन्त [1861] तक यह उत्पादन सङ्गठन पाया जाता था। दास-मुक्ति के साथ-साथ इस तरह के कारखाने भी विलीन होने लगे।

इस वर्ग के कारखाने की नींव उनके प्रशस्त अधिकारों में थी जिसे महान् पीटर ने प्रदान किया था। इनमें से सबसे बड़ा अधिकार भूमि के साथ उन पर बसे हुये किसानों को भी खरीद सकने का था। इसका विरोध होना स्वाभाविक था। साम्राज्ञी अन्ना ने १७४० में इन पर प्रतिबन्ध लगाया। कारखाना मालिक भूमि के साथ किसानों को नहीं खरीद सकता; किन्तु किसान भूमि के बिना खरीदे जा सकते थे। इस प्रतिबन्ध के विरुद्ध स्वामियों ने ऐसा आन्दोलन किया कि १७४४ में उनको यह अधिकार दुबारा मिल गया। लगभग पूरे १८ वीं शताब्दी में कारखाना स्वामी और भूस्वामियों के बीच इस विषय में अपने-अपने अधिकारों के लिये झगडा चलता रहा। १७६२ में पीटर तृतीय ने कारखाने के लिये पूरा गाँव खरीदने पर रोक लगाई। कैथरीन द्वितीय ने गद्दी पर आने के बाद इस प्रतिबन्ध को बनाये रखा। १८०२ तथा १८०८ में कारखानों द्वारा किसानों के खरीदे जाने के अधिकार पर और अधिक रूकावटें लगीं। इस समय के विचारधारा के प्रभाव से १७९६ में कारखानों द्वारा किसानों को खरीदना वर्जित कर दिया गया। इन सब प्रतिबंधों का असर यह हुआ कि कारखानों के लिये श्रम प्राप्त करना एक समस्या बन गई। १८ वीं शताब्दी के अन्त तक अधिकतर कारखाने ऐसे व्यक्तियों के हाथ में चले गये जिनको दास रखने का वशानुगत अधिकार था अर्थात् सामंत वर्ग [Boyer]।

### (३) भूमि स्वामी उत्पादन प्रणाली [Votchinal manufacture]

इस प्रकार के उत्पादन व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि पर छोटे तथा मध्यम कोटि के कारखाने स्थापित होते थे जिनमें बोशीना के कृषि-दास काम करते थे। इनको कारखाना मजदूर का स्तर नहीं मिला था। परिवर्तन केवल इतना ही था कि अपना निश्चित श्रम-भुगतान [Bartschina], मालिक के खेत पर काम न करके, मालिक के कारखाने में काम द्वारा चुकाना पड़ता था। अधिकतर किसी प्रकार का वेतन न दिया जाता। इस प्रकार के अवैतनिक श्रम के अलावा, इन कारखानों को और भी कई लाभ थे जिसके कारण इनकी इतनी उन्नति हुई। भूस्वामी के पास प्रचुर मात्रा में श्रम था जिसको वह मनमाने तरीके से प्रयोग कर सकता था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह श्रम अकुशल, आलसी और लापरवाह था। किन्तु इसमें विशेष रूकावट न होती। उस समय के उत्पादन-कला में कुशलता अपना बहुत अधिक महत्व नहीं रखती थी। इनके अतिरिक्त भूस्वामियों को अपना कच्चा माल निर्मित वस्तु के रूप में बेचना अधिक लाभप्रद था। बोशीना में अथवा उसके आस-पास के क्षेत्रों में बाजार आसानी से मिल जाते थे। माल के मुफ्त यातायात का भार कृषिदासों पर था। १८ वीं शताब्दी के अन्त एवं १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में प्रायः सभी वशानुगत भूस्वामी [Boyers] इस प्रकार के उत्पादन की ओर आकर्षित हुये। इसके प्रचलन का अन्दाजा प्रोफेसर क्लाइव के द्वारा सकलित इन आँकड़ों से लग सकता है। १८२६

में कुल 2,10,568 श्रमिकों में से स्वतन्त्र श्रमिक 1,14,515, हस्तान्तरित श्रमिक 29,328 तथा बोशीना श्रमिक 66,725 थे।<sup>1</sup>

इन श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब थी। इन पर भूस्वामी का पूर्ण निरंकुश अधिकार था। स्वार्थपरायण लोगों ने सरकार को यह विश्वास दिला रखा था कि सङ्गठन तथा अनुशासन के हिन में सरकार के लिये किसी भी प्रकार उचित नहीं है कि वह भूस्वामी और कृषक के व्यक्तिगत सम्बन्ध में हस्तक्षेप करे। बोशीना सम्पत्ति—कृषि और उद्योग—उसके विशेषाधिकार प्राप्त स्वामी की निजी सम्पत्ति मानी जाती थी इसलिये सरकारी नियम से इनको मुक्त रखा गया। रूसी सरकार के संरक्षण का लाभ उठाने के लिये अठारहवीं शताब्दी में इनका प्रचलन खूब बढ़ा। लगभग 1840-50 तक नये बनते हुये औद्योगिक श्रमिक वर्ग में अशान्ति, असंतोष एवं कारखाने के प्रति घृणा के बीज बोकर इस प्रकार की उत्पादन पद्धति का लोप होने लगा।

#### (4) रूसी कुटीर उद्योग [Russian kustar industry]

रूस के औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योग का बहुत महत्व है। इसके विकास में रूस तथा अन्य पश्चिमी योरोप के राष्ट्रों में मौलिक भिन्नता मिलती है। प्रायः सभी स्थानों पर कारखाना उत्पादन शहरों में केन्द्रित कुशल कारीगर [Master Craftsman] तथा उत्पादकों के संघ [Craft-guilds] से हुआ। किन्तु रूस में एक स्थान पर केन्द्रित उत्पादक संघों की जगह दूर दूर तक फैले हुये घरेलू उद्योग [Household kustar Industry] ही उत्पादन व्यवस्था के सङ्गठन की नींव थे। कुस्तार उद्योग कृषि के साथ-साथ किये जाने वाले उस उत्पादन को कहते हैं जिसे किसान अपने घर पर ही चलाता था। उसमें और अंग्रेजी घरेलू उत्पादन प्रथा [Domestic System] में विशेष अन्तर यह है कि कुस्तार उत्पादन में एक कारीगर वर्ग नहीं होता जो कि केवल वस्तु उत्पादन का ही काम करता हो। यहाँ पर उत्पादन ऐसे किसानों द्वारा होता था जिनको किसी प्रकार के उत्पादन में दक्षता प्राप्त हो किन्तु उनका मुख्य धन्धा खेती ही रहती थी। दूसरी विशेषता यह थी कि उत्पादन का ध्येय प्राचीन कृषक उत्पादन की तरह उपभोग न होकर विक्रय तथा लाभ था।

सदा से ही किसान अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को तैयार करता रहा है। किन्तु यह कहना उचित न होगा कि इसी से आगे चलकर कुस्तार उद्योग का जन्म हुआ। कुस्तार उद्योग का व्यापक प्रचलन 18 वीं और 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में पाया जाता है। प्रोफेसर जेम्स मेयर तथा प्रोफेसर दूगान-बरानोवस्की जैसे विद्वानों के अनुसार इस संबंध में रूस में अजीब प्रगति पाई जाती है। स्वयं उपभोग के लिये

<sup>1</sup> Clive Day, Op. Cit., p. 536.

प्राचीन तरह की उत्पादन-व्यवस्था पर, पीटर महान् ने आधुनिक उत्पादन कारखाना लाद दिया। स्वाभाविक था कि विकास के क्रम को तोड़ने का यह प्रयत्न पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सका। असफल कारखाना उत्पादन प्रयोग के अवशेषों में कुस्तार उद्योग ने अपने प्रसार की शक्ति पाई। बहुत नीचे तरह की यांत्रिक कुशलता और उत्पादन स्तर होने के कारण रूसी फैक्टरी एक प्रकार का विशाल गृह उद्योग था, जहाँ पर किसानों को कारीगर के रूप में इकट्ठा करके, अधिकतर बिना मशीन तथा वैज्ञानिक कुशलता के, उत्पादन कराया जाता था। इसलिये यह स्वाभाविक था कि अपना घर, जमीन और परिचित वातावरण छोड़कर दूर शहरों में जाने के बजाय किसान आसानी से कारखाने के तरह का उत्पादन अपने घर पर ही कर सकता था। 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में [1812] सम्राट नेपोलियन की चढ़ाई से बहुत बड़े पैमाने पर कारखाने विध्वंस हो गये। उनमें काम करने वाले कारीगरों ने अपने-अपने घर जाकर बाजार के लिये उत्पादन शुरू कर दिया। आर्थिक कमजोरी तथा कुप्रबन्ध के कारण भी काफी कारखाने बंद होते रहते थे। इन सबसे काम करने वाले व्यक्तियों को अपनी कुशलता को प्रयोग करने का एकमात्र अवसर कुस्तार उद्योग में मिलता था। किसानों की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी कुशलता थी। कारखानों में काम करके विदेशी विशेषज्ञों से शिक्षा पाकर यह उच्चतम कोटि के कारीगर बन गये। कुस्तार उद्योग में इन्होंने अपने उत्पादन के उच्च स्तर से कारखानों के लिये मुकाबला करना अत्यंत कठिन बना दिया। पोमेस्ती भूस्वामी भी अपने-अपने किसानों को उस दिशा में अग्रसित होने के लिये उत्साहित करते थे। इन सब बातों ने मिल-जुलकर कुस्तार उत्पादन पद्धति को बहुत आगे बढ़ाया। इनकी प्रतिस्पर्धा इतनी विकट हो गयी कि 19 वीं शताब्दी के प्रथम 20 वर्षों में इनका सामना न कर सकने से अधिकतर कारखाने व्यक्तिगत कुस्तार उत्पादन केन्द्रों में परिणित हो गये।

19 वीं शताब्दी के आरम्भ से ही कुस्तार उद्योग का स्वर्ण युग चालू हुआ और निकोलस प्रथम के राज्यकाल में अपने शिखर पर पहुँच गया। इसके साथ-साथ ही बड़े पैमाने के कारखाना-उत्पादकों द्वारा इसका विरोध आरम्भ हुआ। कई बार सरकार पर दबाव डाला गया कि इसे पर रोक लगा दी जाय लेकिन कोई विशेष सफलता न मिली। लगभग 19 वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव रूस तक पहुँचा। मशीन, भाप का इंजन और पेचीदे वैज्ञानिक तरीकों के आगे कुस्तार उद्योग को झुकना पड़ा। इन नवीन परिवर्तनों का लाभ उठाना बड़ी पूँजी पर आधारित, एक केन्द्रीय स्थान पर स्थापित कारखानों की ही सामर्थ्य थी। 1835-1855 के बीच मशीनों का प्रयोग इतने विस्तृत रूप से प्रचलित हो चुका था कि हाथ से काम करने वाले कारीगरों का महत्व तेजी से घटने लगा। महत्व घटने के साथ-साथ कुस्तार कारीगर अपनी बिगड़ी हुई दशा के कारण कबीर-कबीर पुरी तरह व्यापारियों के आर्थिक सहायता

पर आश्रित हो गये। कितने तेजी के साथ यह रूस के आर्थिक चित्र से उठे हैं, यह इस बात से पता चलता है कि 1866 में अनुसूचित कारखाना तथा घर पर काम करने वाले कारीगरों में कुस्तार कारीगरों की संख्या प्रायः 70% थी। 1894 में यह घट कर केवल 8% रह गयी। आगे चल कर उनको फिर से पनपाने की कोशिश हुई किन्तु इनका क्षेत्र केवल कलात्मक वस्तुओं के निर्माण तक ही सीमित रहा।

### राज्य तथा औद्योगिक विकास

पूरे 18 वीं शताब्दी में अधिकतर सभी उत्पादन राज्य की आवश्यकता पूर्ति के लिये तथा केवल कुछ अंशों में उच्चवर्ग के लिये किया जाता था। इससे समाज के सबसे बड़े अंश ग्रामीण क्षेत्र के अपने घरेलू उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस समय में वस्तु-विनिमय बाजार भी विकसित न हो पाये थे। लेकिन 19 वीं शताब्दी में इन कारखानों का उत्पादन इतना काफी बढ़ गया कि जनता की छोटी-सी माँग को पूरा करने के बाद भी अतिरिक्त उत्पादन हुआ। पश्चिमी योरप से रूस यात्रिक कुशलता तथा उत्पादन व्यवस्था में इतना पिछड़ा था कि माल का निर्यात संभव न हो सका। वह एक विशेष कारण बन गया जिससे सरकार तथा उत्पादक वर्ग यह अनुभव करने को बाध्य हुये कि उत्पादन पद्धति में समूल परिवर्तन किये बिना उद्योग उन्नति नहीं कर सकता।

रूस में राज्य एवं उद्योगों का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के विपरीत रूसी उद्योग व्यक्तिगत लाभ के लिये आरम्भ नहीं हुये वरन् राज्य द्वारा निर्मित होने से इनका मुख्य ध्येय राजकीय आवश्यकताओं का पूरा करना था। पीटर प्रथम के समय निर्धारित औद्योगिक नीति अपने मूलरूप में, छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ, 19 वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। राजकीय प्रोत्साहन तथा संचालन की मदद से, व्यापारवादी सिद्धान्त पर, औद्योगिक उन्नति करना इस समय की मुख्य नीति रही। साथ-ही-साथ हर प्रकार से व्यक्तिगत पूँजीपतियों की मदद भी राज्य करता था। बड़े उद्योगों के निर्माण में राजकीय खजाना पूरी सहायता देता था। इतना ही नहीं, बहुत बड़े तथा अत्यंत महँगे उद्योगों को राज्य ने पूर्ण रूप से चलाया। देशी उद्योगों को सहारा देने के लिये ऊँची टैरिफ नीति तथा बहुत से वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा। श्रमिक प्राप्त करने की समस्या बलात् श्रम [Forced labour] तथा कृषि दासों का कारखानों में हस्तांतरण के द्वारा हल की गयी। जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है कि वैतनिक श्रमिक पद्धति [paid labour system] की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो चुका था। पीटर प्रथम ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के जोश में ऋण तथा एकाधिकार [loans and monopoly] देने की भी नीति अपनाई

जिसके द्वारा केवल सामंत लोग ही लाभ उठा सके। एलिजाबेथ और अन्ना के समय में पक्षपात का बाजार गरम था, परिणामस्वरूप विस्तृत औद्योगीकरण की नींव न पड़कर समस्त अधिकार कुछ कुपापन्न व्यक्तियों के हाथ में इकट्ठा हो गये।

कैथरीन द्वितीय के राज्यकाल में [१७६० से] भूस्वामी सामन्तों की शक्ति को फिर से बढ़ाया गया। महान् कैथरीन ने व्यापारिक तथा औद्योगिक स्वतन्त्रता को अपने औद्योगिक नीति का सिद्धान्त बनाया। अनेकों एकाधिकार छीन लिए गये। अतर्देशीय संरक्षण में औद्योगिक विकास होने के कारण उद्योगों पर इतने नियम लादे गये कि उत्पादन-व्यवस्था के उन्मुक्त विकास में रुकावट पैदा होने लगी। कैथरीन द्वितीय द्वारा आवश्यकता से अधिक नियमों को जब कम कर दिया गया तो बड़े पैमाने पर औद्योगिक निर्माण आरम्भ हुआ। ये प्रतिबन्ध इतने अधिक थे कि किसी भी फैक्टरी स्वामी को कारखाने का आन्तरिक प्रबन्ध तथा उत्पादन नीति स्थिर करना प्रायः असम्भव हो जाता करता था। राजकीय नियन्त्रण के कम होने के अतिरिक्त कुछ और भी कारण थे जिनके द्वारा १८ वीं शताब्दी के अन्त तथा १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में औद्योगिक उत्पादन को बहुत सहारा मिला। एकाधिकार में पड़े हुए उद्योगों के अंतर्गत एक कुशल कारीगर का वर्ग उत्पन्न हुआ जिनका महत्व बड़े कारखाने के लिए इतना अधिक था कि उन पर विशेष दवाब न डाला जा सकता था। एक स्वतन्त्र वैतनिक श्रमिक वर्ग बनना आरम्भ हुआ। खेतों पर काम करने के बदले में धन-भुगतान [Obrok] देने की प्रथा ने जोर पकड़ा। बड़े पैमाने पर किसान गाँवों को छोड़कर शहरों के तरफ रवाना हुये। १७९६ की जनगणना के अनुसार २० प्रतिशत ग्रामीण व्यक्ति १८ वीं शताब्दी के अन्त तक खेती छोड़कर वस्तु उत्पादन में लग चुके थे। इस समय [१८३०-१८४०] उद्योगों की विशेष उन्नति में कृषि उत्पादन का मूल्य घट जाना भी काफी सहायक हुआ। १८३० तक भयंकर मंदी आई जिससे बहुत बड़ी संख्या में अनार्थिक [Uneconomic] भूमि छोड़कर किसान वैतनिक श्रमिक की तरह कारखाने में काम करने लग गये। नेपोलियन की चढ़ाई [१८१२] ने औद्योगिक उन्नति में विशेष मदद किया।

१८ वीं शताब्दी में दास-श्रमिकों की गिरी हुई दशा के कारण बराबर श्रमिक-अशान्ति बनी रही। जब तक कि उत्पादन का मुख्य साधन श्रम था, और वस्तु उत्पादन में विशेष कुशलता की आवश्यकता न थी, बलात् श्रम [Forced labour] सुस्त होने पर भी लाभपूर्ण था। किन्तु जब से यंत्रों का प्रयोग बढ़ा, कुशल तथा अनुभवी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ने लगी। बलात् श्रम की दशा में इस प्रकार के मजदूर मिलना प्रायः असम्भव था। २० वीं शताब्दी के आरम्भ तक यूरोप औद्योगिक क्रान्ति से गुजर रहा था। रूस के उद्योग के मार्ग में दासता उसी प्रकार रुकावट बनी जिस प्रकार यह कृषि उन्नति में थी। १८२४ में एक कानून द्वारा कृषकों का अस्तित्व कारखाने से पृथक् कर



दिया गया। 1835 से इनको फैक्टरी छोड़ने की भी आज्ञा मिली। इससे यह स्पष्ट है कि कारखाना मालिक दास-श्रमिकों को लाभपूर्ण न पाकर उनको हटा रहे थे; क्योंकि उनके सहमति बिना इस तरह के कानून तथा 1840 की राजाज्ञा कभी पास न होती। 1840 में सम्राट निकोलस प्रथम ने राजकीय किसानों को कारखाने से मुक्ति दिलाने के लिए आर्थिक मुआवजे का प्रयत्न किया। इसका लाभ उठाकर करीब 15 हजार व्यक्तियों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। अनिवार्य से एच्छिक श्रम का यह परिवर्तन काफी विरोध के साथ हुआ। इस दिशा में प्रगति प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट हो जाती है।<sup>1</sup>

1	2	3	4
वर्ष	कारखाना सख्या	मजदूर-सख्या (हजार में)	वैतनिक मजदूर सख्या 3 का प्रतिशत
1770	260	55.3	32.
1804	2,402	95.2	47
1812	2,322	119.0	50
1820	4,578	179.6	58
1825	5,261	210.6	54
1860	14,388	565.1	88

18 वीं शताब्दी के अन्त तक उद्योग के विकास में अनेकों दिशाओं से मदद मिली। हालाँकि औत्राक प्रथा ने किसानों को कुछ स्वतन्त्रता प्रदान की किन्तु दासता-प्रथा, संयुक्त परिवार, आपसी आश्वासन [Mutual guarantee] तथा अन्य बाधाओं ने किसानों को पूर्ण रूप से औद्योगिक श्रम में न बदलने दिया।

19 वीं शताब्दी में अधिकतर वह सभी कारण पाये जाते थे जिन्होंने उस समय तक के औद्योगिक विकास को सहारा दिया था। इनके साथ-साथ कुछ विशेष घटनाओं ने इस प्रगति को और तीव्र बना दिया। सम्राट नेपोलियन की योरप विजय ने सभी देशों के औद्योगिक विकास में युद्धकालीन तीव्र उन्नति किया। अंग्रेजी और फ्रांसीसी माल का देश में आना एकदम बंद हो गया। इसके अलावा सम्राट पॉल प्रथम, एलेक्जेंडर प्रथम तथा निकोलस प्रथम ने रूस की सीमाओं को काफी बढ़ाया। युद्ध और सीमा विस्तार ने अंतर्देशीय बाजार के विकास एवं संगठन पर बहुत प्रभाव डाला। 18 वीं शताब्दी की अंग्रेजी औद्योगिक क्रान्ति रूसी उद्योग में संगठन एवं संचालन के नये विचार और नई पद्धतियाँ ले आई। उस समय का सबसे विकसित औद्योगिक देश इंग्लैंड पुराने व्यापारवाद को छोड़कर स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाने लगा। इससे इंग्लैंड ने मशीनों का निर्यात फिर से आरम्भ किया [1842] रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर मशीनें मंगा कर अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाया।

<sup>1</sup> Lyashchenko Op Cit. p 337

## कृषि-दासता तथा दास-मुक्ति

[ Serfdom and Emancipation ]

### दास-प्रथा का विकास

रूस में अत्यन्त प्राचीन काल से ही दास-प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन रूसी कानून में विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक वर्ग को 'ओग्नीशान' [Ognitschan] अर्थात् दास-स्वामी कहा गया था। इस प्रथा का प्रादुर्भाव युद्ध के कारण माना जाता है। छोटे-छोटे सरदारों तथा राजाओं में विभक्त यह देश सदा ही आपसी लड़ाई से ग्रस्त था। युद्ध-बन्दी को दास बनाना सर्वमान्य परम्परा थी। इस प्रकार के युद्ध-दास तथा उनके वंशज 'केलाद' [Chelad] कहलाते थे। यही समाज की नींव थी। 12वीं शताब्दी में इन दासों की सहायता से कृषि आरम्भ हुई। इससे पूर्व 11वीं शताब्दी तक इनका निर्यात आया का मुख्य साधन था। बिना दासों के भूमि बेकार थी। अतः भूमि-स्वामित्व का उदय ही दासता को लेकर हुआ। समकालीन सामाजिक नियम था : 'यह भूमि मेरी है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पर खेती करते हैं वे मेरे हैं।' दासों का खेती के लिये प्रयोग होने के कारण इनका नाम भी बदल गया। केलाद (युद्ध-दास) खोलौप (दास-कृषक) बन गये। इनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। हर प्रकार से स्वतंत्र व्यक्तियों को दास बनाने की एक प्रचंड लहर आई, जोकि उस समय के अव्यवस्थित राजनैतिक संगठन में बिना अवरोध बढ़ती ही गई।

यह खोलौप इतने लाभप्रद सिद्ध हुए कि भूमिधरों की लालच और भी बढ़ी। स्वतंत्र कृषकों को भी किसी प्रकार भूमि से बाँधने का प्रयत्न होने लगा। 16वीं शताब्दी में वोशीनी व पोमेस्ती भू-स्वामियों की विशेष वृद्धि हुई। इनमें से जो अधिक अमीर थे वे कम अमीर भू-स्वामियों के किसानों को लोभ देकर अपने यहाँ बुला लेते थे। किसानों के इस प्रकार स्थान बदलने से राज्य को उचित सेवा प्राप्त करने में और कर-वसूली में असुविधा होती थी। इसलिये स्वतंत्र किसान के प्रवास पर अवरोध लगाया गया। प्रवास की स्वतंत्रता से विहीन किसानों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के छिन जाने में भी अधिक देर न हुई। इस प्रकार देश के एकमात्र आर्थिक कार्य—कृषि—में लगी हुई जनता दो वर्गों में विभक्त हो गई—[१] भू-स्वामी वर्ग तथा [२] दास [खोलौप] एवं कृषि-दास [सर्फ] वर्ग। किन्तु प्रोफेसर मेयर, क्लूशेवस्की के विचार से सहमत है,

कि 'कृषि-दासता [Serfdom] का आरम्भ किसी भी कानून के द्वारा न होकर आर्थिक कारणों से हुआ।' किसान अधिकतर बहुत गरीब था। जब कभी वह किसी भू-स्वामी के यहाँ काम करने जाता तो उसके पास औजार, घोड़े तथा आवश्यक पूँजी न होती। वह सब उसे भू-स्वामी उधार देता था। इस प्रकार हर किसान को राज्य-कर, भू-स्वामी की भूमि का लगान तथा उससे प्राप्त ऋण का व्याज चुकाना पड़ता था। सब मिल-जुल कर वह इतनी बड़ी रकम हो जाती थी जिससे उन्मृण होना प्रायः असम्भव था। जब तक वह इसे चुका न दे, किसान स्वयं ही भूमि से बँध गया। इसके अतिरिक्त, कुछ किसान [old-livers] एक ही भूमि-स्वामी के यहाँ इतने अधिक समय कार्य कर चुके थे कि उन्होंने स्वयं ही कभी अपने प्रवास का अधिकार प्रयोग नहीं किया, जिससे वह धीरे-धीरे नष्ट हो गया।

फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि इन मौलिक आर्थिक कारणों को वैधानिक सहमति प्राप्त होने से कृषि-दासता के तीव्र विस्तार में बहुत सहायता मिली। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में अनेको राजाशाहें जारी हुईं जिन सब का केवल एक उद्देश्य था कि बिना अपना ऋण चुकाये किसानों द्वारा भूमि छोड़ कर जाने के अधिकार पर रूकावट लगाई जाय। जार फ्योडोर की प्रसिद्ध 1597 की राजाशाह से 5 वर्ष पूर्व तक के भूमि छोड़ कर भागे हुए किसानों को वापस बुलाया जा सकता था। 1607 में यह अवधि बढ़ा कर 15 वर्ष कर दी गई। लेकिन उनका प्रवास का अधिकार बना रहा। उनके ऊपर दो प्रकार की रूकावट लगी। प्रथम, भू-स्वामी के साथ अपना समस्त दायित्व चुकाये बिना किसान भूमि छोड़ कर नहीं जा सकता था। द्वितीय, कोई किसान अपने ऋण-भार से मुक्त होने के लिये अपने को भू-स्वामी के हाथ खोलौप [दास] की भाँति नहीं बेच सकता था। इस रूकावट का कारण यह था कि खोलौप पर राज्य-कर नहीं लगता था।

इस समय में ही दासता प्रथा के कुछ अन्य रूप सामने आये जिनमें से विशेष उल्लेखनीय है बंधक-दास [Kabala Kholop], यह अस्थायी दास वर्ग था। किसान भू-स्वामी से लिये हुए ऋण का भुगतान हो जाने तक अपने आपको उसके यहाँ बंधक [Mortgage] रख देता था अर्थात् खोलौप की भाँति कार्य करना = स्वीकार करता था। ऋण के भुगतान हो जाने के पश्चात् वह स्वतंत्र हो जाता था। कहीं-कहीं पर समझौते के अन्तर्गत बंधक-दास स्वामी के जीवन-काल तक ही दासता में रहता था। यदि कुछ परिस्थितियों में वे अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते तो आपसी समझौते द्वारा पूर्ण दास [Full Kholop] की अवस्था स्वीकार कर लेते थे।

17वीं शताब्दी में रोमानोव वंश [1613-1916] के आरम्भ से ही दासता की रूपरेखा और विस्तार का प्रसार हुआ। राज्य-कर की वसूली के हेतु जनगणना की गई जिसमें किसानों को भूमि-दास के साथ-साथ व्यक्तिगत-दास के वर्ग में रखा गया। राज्य की ओर से कर-वसूली की सुविधा के लिये यह प्रयत्न किया गया कि किसान एक निश्चित भूमि पर स्थायी रूप से बना रहे। इसके अतिरिक्त राज्य ने किसी भी प्रकार से वैधानिक दबाव के द्वारा दासता को बढ़ाने में प्रत्यक्ष सहायता न दी। अप्रत्यक्ष रूप से यह अवश्य कहा जायगा कि राज्य ने दासता की वृद्धि को एकदम भूस्वामियों तथा किसानों का व्यक्तिगत समझौता मान कर अनियंत्रित छोड़ दिया। किसानों की दीर्घ दशा से नाजायज लाभ उठा कर बंधक-दासों [Krbala Kholop] की संख्या तेजी से बढ़ी। सम्राट एलेक्जेंडर ने 1649 ई० में कुछ नियम बनाये जिनका गहरा प्रभाव पड़ा। अब भागे हुए किसानों को पकड़ कर वापस बुलाया जा सकता था चाहे वे कभी भी भागे हों। किसानों को दास-कृषक [Kholop] में बदलने की गति और तीव्र हो गई। इतना ही नहीं, किसान के दायित्व का भार उसका वंशानुगत [Hereditary] भार बन गया जिसे उसके बच्चे भी ढोते रहेंगे। 1649 ई० के नियम कृषि-दासता से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग कहे जा सकते हैं। इन्होंने एक पेचीदी एवं विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी। किसान के वैधानिक स्तर को निश्चित रूप से स्थिर न करके भू-स्वामी के ऊपर ही छोड़ दिया गया। किसान की स्थिति एकदम अस्थिर बनी रही। इसके पास संपत्ति [Possessor] थी किन्तु इसका स्वामित्व भू-स्वामी को प्राप्त था। इस प्रकार किसान अपने अधिकारों के लिये पूर्ण रूप से भू-स्वामियों पर आश्रित हो गया। किसान पर लगे राजकीय कर को भी, भू-स्वामी को मिलने वाले भुगतान का एक भाग बना दिया गया। इससे राज्य को कर-वसूली में बहुत सुविधा हो गई। प्रो० क्यूशेवस्की के अनुसार इन्हीं गाँवों से मिल कर वह भयंकर फदा बना जिसने किसानों को दासता में जकड़ दिया।<sup>1</sup>

महान् पीटर ने अपनी सेना के लिये सैनिक प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषक दासों में से भर्ती शुरू किया। धन की आवश्यकता ने कृषक दासों पर भी कर लगाने के लिये पीटर को बाध्य किया। स्वतंत्र किसान भूमि-दास [Serf] तथा कृषक-दास [Kholop] इन सब को एक वर्ग में बाँध कर सम्राट पीटर ने अनजाने में ही दासता का क्षेत्र अधिक विस्तृत किया। देश को नवीन दिशा में ले जाने का श्रेय उसी सम्राट को प्राप्त है; किन्तु साथ ही दासता की व्यापकता तथा कठोरता प्रदान करने का दायित्व भी इन्हीं पर है।

1 Meyer, Op Cit., p. 91.

साम्रज्ञी कैथरीन द्वितीय ने दासता को देश की आर्थिक व्यवस्था की नींव माना और इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने से सदा बचती रही। 1825-1861 के बीच निकोलस प्रथम एवं एलेक्जेंडर द्वितीय दोनों ने अपने राज्य-काल में इस ओर ध्यान दिया। नैपोलियन के युद्ध के साथ प्रचुर मात्रा में फ्रान्स के प्रगतिवादी विचार रूस को प्रभावित कर चुके थे। जार दास-प्रथा में सुधार करना चाहते थे किन्तु वे यह न निर्धारित कर पा रहे थे कि न्यूनतम अवरोध का मार्ग क्या होगा। अतः परिस्थितियों ने स्वयं इसका निर्णय कर दिया। 1861 में सरकारी तौर पर दास-प्रथा का उन्मूलन हुआ।

### कृषक आन्दोलन एवं दास-मुक्ति

1762 ई० में पीटर तृतीय ने एक राजाज्ञा द्वारा पोमेस्ती और बोशीनी भूस्वामियों को अनिवार्य राज्य सेवा से मुक्त कर दिया। इस सुधार से किसानों में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि अब शीघ्र ही उनके भी बन्धन ढीले कर दिये जायेंगे। नये युग की आशा ने उनको स्वतन्त्रता के लिये अधीर कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 18 वीं एवं 19वीं शताब्दी में बराबर कृषक आन्दोलन चलता ही रहा। रह-रहकर यह आन्दोलन विद्रोह का रूप धारण कर लेता था। जार और भूस्वामी इस स्वतन्त्रता की माँग में अपने शक्ति की अवहेलना, अपने प्रभुत्व का पतन तथा किसानों की अनुशासनहीनता की गन्ध पाकर घबड़ा गये। सुधार एवं पश्चिमी योरप की स्वतन्त्र विचारधारा को ही इसका जिम्मेदार समझा गया। बदलती हुई हवा के रुख को उनका रुढ़िवादी मस्तिष्क न समझ सका। बलप्रयोग से किसानों की इन समाजविरोधी प्रवृत्तियों को कुचल देने की कोशिश होने लगी। 1762 से 1769 तक विद्रोह जगह-जगह पर भड़कता रहा जिसे सेना ने कठोरता से दबा दिया। शोषित किसान 1775 में पूगाचेव के विद्रोह में खुले आम प्रथम बार सामने आये।

प्रो० मेवर<sup>1</sup> ने दासों के जीवन का जो वर्णन किया है उससे पता चलता है कि इतना सब होने पर भी कैथरीन द्वितीय के समय में कृषि-दासों का क्रय-विक्रय, भूस्वामियों का ओग्राक एवं वारसीना वसूली बढ़ती ही गई। परन्तु इन्हीं के राज्य-काल में [1762-1796] किसानों की दशा सुधारने के लिये उच्चतम स्तर पर विद्वानों एवं विचारकों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1765 में राजकीय स्वतन्त्र आर्थिक समिति [The Imperial Free Economical Society] बनाई गयी जिसने इस विषय पर विरोधी विचार-धाराओं का अच्छा अध्ययन किया। इस दिशा में अगला कदम 1768 में उठाया गया जबकि एक उच्चायोग की स्थापना हुयी जिसमें कि किसान और भूस्वामी दोनों ही

<sup>1</sup> Mevor, Op. Cit., Chapter 5.

सदस्य थे। दुर्भाग्यवश, यह सभी प्रयत्न कोरे सिद्धान्त तक ही सीमित रहे। किसानों की दशा बिगड़ती गयी। कैथरीन के चारो ओर प्रभावशाली भूस्वामियों का ऐसा जाल था कि वास्तविकता में कुछ न हो सका। 1775 ई० में कृपक-विद्रोह ने किसान-सुधार के विषय पर खुले हुये विचार-विनिमय समाप्त कर दिये। कैथरीन और उनके आने वाले ज़ारो में यह विश्वास बैठ गया कि किसानों के मन में किसी भी प्रकार से सुधार की भावना देश की अर्थ-व्यवस्था को तोड़ने का कारण होगा।

1796 ई० में पॉल प्रथम और उसके बाद एलेक्जेंडर प्रथम के समय में यही दशा बनी रही। 1803 ई० में कृपको की बर्शा सुधारने के लिये एक नया कानून बना जिसके द्वारा किसान व्यक्तिगत रूप से अथवा सम्पूर्ण ग्राम मिलकर, अपने तथा भूस्वामियों के बीच एक आपसी समझौता करके स्वतन्त्र हो सकते थे। इस समझौते का जार स्वयं निरीक्षण करता था। इसका उद्देश्य यह था कि भूस्वामियों को अपने दासों को स्वतन्त्र करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। स्वाभाविक है इसकी प्रगति बहुत न होनी थी। 1804-1825 के बीच कुल 47,153 व्यक्ति स्वतन्त्र किये गये। स्वतन्त्रता के समझौते एकरूप न थे। कुछ लोग दासों से एक निश्चित रकम लेकर उन्हें मुक्त करते थे। यह धन राज्य की ओर से किसानों को उधार दिया जाता था, जिसको वे किस्त में चुका देते थे। कुछ समझौतों में बासीना और औब्रौक की शर्तें लगी हुई थीं। 1825 तक इस क्षेत्र में कई सुधार किये गये। भूस्वामियों पर बहुत से छोटे-छोटे प्रतिबन्ध लगे जिनसे किसानों की दशा सुधरने की आशा थी। एलेक्जेंडर प्रथम के राज्य काल के अन्त तक [1825] इतने वाद-विवाद और अनेकों राजाशाहों ने किसानों की दशा में थोड़ा ही परिवर्तन किया। जो आशाएँ अधिक प्रगतिशील थीं, वे लागू न की जा सकीं। सबसे बड़ा अन्तर यह पड़ा कि भूस्वामी अब पहले इतने बड़े पैमाने पर कृपि-दासों को दण्ड नहीं दे पाते थे।

इसके पश्चात् 1842 तक कई समितियाँ इस विषय पर बनाई गईं। सम्राट निकोलस प्रथम ने इसमें विशेष दिलचस्पी ली, जिसके फलस्वरूप 1842 में एक राजाशाह निकाली गई। इतने दिनों के कठिन तथा विद्वतापूर्ण मेहनत को कानून का रूप मिला। इसमें दो विशेष बातें थीं। किसान और भूस्वामी के आपसी समझौतों का ऐच्छिक रूप [Voluntary nature] न बदला जाय तथा भूस्वामियों का वंशानुगत अधिकार कम न हो। आपसी समझौते द्वारा किसान को कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, इस पर यह कानून चुप रहा। एक बार समझौता हो जाने पर इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। इस कानून ने भूमि स्वामित्व पूरी तरह से पोमैस्ती वर्ग के हाथ में रखा। निःसन्देह इससे किसानों की दशा सुधारने की इच्छा प्रकट होती है। लेकिन यह सुधार

कितना और किस रूप में होगा, यह एकदम भूस्वामियों के हाथ में छोड़ दिया गया। अतः इन सुधारों का निष्क्रिय होकर प्रभावहीन हो जाना स्वाभाविक था।

1840-1844 में एक ऐसी समिति बनाई गई जिसने कि ड्वोरोवी ल्यूद [Dvorovie lyude] अर्थात् गृह-दासों की समस्या पर विचार किया। समिति ने सलाह दी कि यह वर्ग राजा के लिए हिनकर नहीं है तथा किसानों को इस वर्ग में सम्मिलित करने पर रुकावट लगानी चाहिये। इसलिए दो राजाशाह 1844 ई० में निकाली गईं जिनके अन्तर्गत गृहदास स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे परन्तु उनको बसाने के लिए भूमि नहीं दी जायगी। साथ ही साथ, यह स्वतन्त्रता स्वामियों द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही प्राप्त होगी। इन कानूनों की कर्मजोरियों ने स्वयं इन्हें महत्वहीन बना दिया।

1844-1847 के बीच बराबर सम्राट निकोलस अलग-अलग व्यक्तियों को इस विषय पर अध्ययन करने को कहते रहे। कई समितियाँ भी बनीं। परन्तु सदैव ही इस बात का प्रयत्न किया गया कि किसानों की दशा इतने क्रमिक रूप में सुधारी जाय कि उनको आने वाली स्वतन्त्रता का पूर्व-आभास न हो। लोगों का विश्वास था कि ऐसा होते ही किसान अपने कर्तव्य भूल जायेंगे और आर्थिक-व्यवस्था में विषमवादिता [Anarchy] फैलना निश्चित है।

1848 में पश्चिमी यूरोप में राज्य-क्रांतियों की जो आग भड़की उससे रूसी प्रगतिवादी विचारक सहम गये। क्रिमिया के युद्ध ने उनको इस ओर ध्यान देने के लिए दुबारा बाध्य किया। सम्राट एलेक्जेंडर द्वितीय के समय तक हर विचारशील व्यक्ति को स्पष्ट हो चुका था कि दासता को हटाने के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। अपने पिता निकोलस की भाँति एलेक्जेंडर द्वितीय भी सद्भावनाओं से प्रेरित होकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अधीर था, 1856 में सम्राट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने ऐतिहासिक कार्य किया। 1857 में इसके सुझावों को आने वाले प्रसिद्ध दास-मुक्ति के कानून [Act of Emancipation] की नींव मानी जाती है, भूस्वामियों को यह अनुभव होने लगा था कि बहुत बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं तथा उसके विरुद्ध समस्त शक्ति से जार तथा सरकार पर प्रभाव डालना अति आवश्यक है। समस्त देश में सुधार तथा दासों की स्वतन्त्रता पर उत्तेजनापूर्वक बहस हो रही थी। जार एवं उसके सलाहकार दृढ़ता के साथ नया मार्ग प्रशस्त करने में संलग्न थे जिसमें भू-स्वामी वर्ग ने खुला असहयोग दिखलाया। 1856 की समिति कार्य-शील थी और देश एक तूफान की भाँति आने वाले परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा था।

विरोधी विचारधाराओं के बीच जार की सुधार के लिए अधीरता और 1856 में मुख्य समिति के अध्यक्ष प्रयत्नों द्वारा फरवरी 1861 में मुक्ति कानून [Emancipation

Act] बना। शताब्दियों से चली आई हुई दासता कम से कम वैधानिक रूप से समाप्त हो गई। यह कहा जा सकता है कि वास्तविकता में मुक्ति-कानून भूस्वामियों ने ही बनाया और इसीलिए वह इतना असंतोषजनक रहा। मुख्य समिति के अधिकांश सदस्य भू-स्वामी ही थे, इनके सम्मुख एक आदर्श प्राप्ति का लक्ष्य था। उसके स्थान पर भू-स्वामियों के आर्थिक हितों की रक्षा तथा राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मुक्ति कानून के नियम बनाये गये। जो कुछ भी सुधार हुआ, उसका श्रेय जार परिवार में दो सदस्यों को दिया जा सकता है। प्रथम, ग्रैण्ड डचेज एलीना पावलोवना। द्वितीय, ग्रैण्ड-ड्यूक कैन्सटेन्टाइन।

## दास-प्रथा टूटने के कारण

### आर्थिक कारण

रूसी कृषि दासता के टूटने के कारणों की जड़े इस प्रथा के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्तरों तक फैली हैं। देश के क्रमिक विकास में 1840-1850 तक वह स्थिति आ चुकी थी कि नयी व्यवस्था की आवश्यकता सभी को अनुभव होना आरम्भ हो गया था। उच्च वर्ग के व्यक्तियों एवं विद्वानों में इस प्रथा को लेकर गहन विवाद चल रहा था। इसमें सदेह नहीं कि यह विवाद आम जनता से बहुत दूर रहा परन्तु शासक वर्ग एवं जार पर इसका प्रभाव पड़ा। कार्यसिद्धि के लिए इन्हीं को प्रभावित करना आवश्यक था।

यदि देखा जाय तो कृषि-दासता [Serfdom] प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था [Natural economy] पर निर्भर रहती है। बाहरी सम्पर्क से दूर आत्मनिर्भर समूह में बँटा समाज ही इस प्रथा का लाभ उठा सकता है। ज्यों-ज्यों बाहरी प्रभाव, विचारधारा तथा सम्बन्ध विकसित होंगे, दासता की पकड़ अपने आप ही ढीली होती जायगी। 18 वीं शताब्दी में ही भूस्वामी अपने निजी भूमि की उपज बाजार में बेचने लगे थे। इसमें फ्लैक्स, ऊन, कपड़ा इत्यादि मुख्य था। 19 वीं शताब्दी तक तो यह भू-स्वामी काफी अच्छे पैमाने पर उद्योग भी चला रहे थे, किसानों द्वारा श्रम-सुगतान [Bartschina] से निर्मित यह वस्तुएँ अधिकतर दक्षिणी तथा मध्य रूस के उपजाऊ प्रदेशों से ही आन्ती थी। उत्तरी पथरीले प्रदेश के भू-स्वामी मुद्रा [Obrok] लेकर अपने किसानों को उद्योगों में काम करने की अनुमति देते थे। इस रूप में वे घर बैठे धन कमा रहे थे। दक्षिण-मध्य रूस के अनाज और कच्चे माल का आदान-प्रदान, उत्तर के औद्योगिक उत्पादन के साथ होना अधिक दिनों तक रुक न सका। इस प्रकार एक विस्तृत बाजार तथा वस्तु-विनिमय प्रथा के स्थापित होते ही व्यापारिक दृष्टि से बाजार के लिए उत्पादन



करने की ओर लोग आकर्षित हुये। दास प्रथा एव प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था के लिए यह मृत्यु का आह्वान था।

1820-25 की अनाज की भयंकर मन्दी ने इस दिशा में लोगों का ध्यान खींच लिया। यह विश्वास उनके मन में घर करने लगा कि श्रम के सामाजिक विभाजन द्वारा ही [Social division of labour] इस मन्दी को दूर किया जा सकता है। आवादी को व्यापक रूप में खेती से उद्योग की ओर जाना चाहिये और इसके लिए स्वतन्त्र श्रम होना आवश्यक है। कृषि-दासता में किसान भूमि से बँधा था। अतः कृषि-दासता को दूर करना देश के लिए परमहितकर नीति होगी।

वाजार के लिए सफल कृषि उत्पादन करने में यह आवश्यक था कि भू-स्वामी उपज की लागत [Cost of Production] का पक्का पता लगा सके। मूल्य-व्यवस्था [Price System] में व्यापारिक-वस्तु-विनिमय इसके बिना कभी सफल नहीं हो सकता। कृषि-दासता में लागत का माप या अनुमान दोनों ही असम्भव था। भू-स्वामी को कृषि-दासों से कुछ सुविधाये [Obrok and bartschina] मिलती थी। इनके द्वारा वह खेती करता था। उपज की लागत तथा मूल्य में इनका अंश निर्धारित नहीं किया जा सकता था। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से लाभपूर्ण खेती नहीं हो पाती। यह स्पष्ट है कि जत्र पूँजीवादी वाजार-मूल्य निर्धारण [Capitalist market price determination] की परिस्थिति पैदा हो चुकी थी तो देश की अर्थव्यवस्था में सामंतवादी कृषि-दासता [Feudal serfdom] का कोई स्थान न रहा।

### राजनैतिक कारण

रूसी इतिहास युद्ध-सेना-सेनापति की चिन्मूर्ति के चारों तरफ ही बुना गया है। आइवन तृतीय, पीटर प्रथम, कैथरिन द्वितीय तथा एलैक्जेंडर प्रथम जब तक विजय और विस्तार में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे, आर्थिक तथा सामाजिक रूढ़िवादी दासता का संगठन किसी प्रकार चलता रहा; किन्तु जत्र निकोलस प्रथम के समय में देश ने टर्की, इंग्लैण्ड, फ्रान्स तथा सारडीनिया द्वारा क्रीमिया के युद्ध [1854-56] में पराजय एव अपमान की विभीषिका देखी, तो निर्विवाद रूप से अटल विश्वास उत्पन्न हुआ कि स्वतंत्र श्रम पर आधारित औद्योगिक पश्चिमी राष्ट्रों से किसी प्रकार भी रूस सामना नहीं कर सकता। इसलिए औद्योगीकरण के मार्ग को प्रशस्त करना होगा और उसकी सबसे बड़ी रुकावट, सामंतवादी दास प्रथा, को तोड़ना ही होगा।

### सामाजिक कारण

यह देखा जा चुका है कि किसान विद्रोह समय-समय पर बराबर होते रहे किन्तु इनको दृढ़ संगठन तथा विवेकपूर्ण संचालन की कमी ने प्रभावहीन बना दिया। 1775

का पूराशेव विद्रोह पहला पूर्ण विद्रोह था जिसमें जनता ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके बाद से देश में असतोष, विद्रोह और दमन का कठोर चक्र चलने लगा।

18 वीं शताब्दी में इन विद्रोहों की तीव्रता एवं व्यापकता दोनों में काफी वृद्धि हुई। सरकारी रूप से घोषित इनकी संख्या इस प्रकार रही है<sup>1</sup>—

1826-1834	148	विद्रोह
1835-1844	216	”
1845-1854	348	”
1855-1861	474	”
समस्त	<u>1,186</u>	”

सामाजिक दशा तेजी के साथ विगड़ रही थी। किसान सामंतों के विरुद्ध किसी भी मूल्य पर आवाज उठाने को तैयार हो चुका था। इन उपद्रवों में सामंतों ने अपना शत्रु तो पहचान लिया किन्तु उस शत्रु का शक्ति-सूत्र न जान सके। अपने प्रभुत्व को दी गई चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। जार तथा राज्य की सैनिक शक्ति का सहारा लेकर किसानों में बढ़ती अराजकता को दबाना आरम्भ हुआ। इस समय तक उच्च शासक तथा भू-स्वामी वर्ग को यह विश्वास था कि स्वतंत्रता के नाम से ही किसानों में खुली क्रान्ति पैदा हो जायगी। समझ तथा सहानुभूति के स्थान पर बल प्रयोग से असंतोष तथा विरोध शान्त न होकर अंदर-अंदर सुलगते रहे।

इन सब कारणों से अवस्था इतनी खराब बन गई कि दास-मुक्ति का नाटक सुधार करने में सर्वथा असफल रहा। सम्राट एलेक्जेंडर द्वितीय की प्रेरणा तथा उपरोक्त आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दबाव ने दास-मुक्ति का कानून 1861 में पास करा दिया। किन्तु स्वार्थी और अदूरदर्शी सामंतों ने इस योजना को ऐसा विध्वंस किया कि दास-मुक्ति का अच्छा प्रभाव प्रायः पूर्णरूपेण नष्ट हो गया। इतना ही नहीं यह स्वयं एक असंतोष का कारण बन गया।

यह नहीं था कि 1861 तक कृषि-दासों की स्वतंत्रता की ओर कोई प्रगति नहीं हुई। अनार्थिक [uneconomic] दास-श्रम से होने वाली हानि को भू-स्वामी तथा औद्योगिक उत्पादक समझ चुके थे। उत्तर के कम उपजाऊ एवं औद्योगिक क्षेत्र में वर्षाणा के जगह पर ओब्रोक का प्रचलन बढ़ रहा था। 19 वीं शताब्दी के आरम्भ से ही भू-स्वामी अधिकतर भूमि किसानों को ओब्रोक पर दे चुके थे। इससे उनको बँधी हुई आय निश्चित हो जाती थी। उनको खेती से मुक्त होकर उद्योग द्वारा लाभ उठाने

<sup>1</sup> Lyashchenko, op. cit., P. 370

का समय मिलता था। दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी कृषि-प्रदेशों में आरम्भ से ही दास-प्रथा नाम-मात्रा को ही थी। इन भागों में सबसे प्रगतिशील कृषि होती थी। और रूसी गेहूँ का १०% निर्यात इसी क्षेत्र से होता था। कृषि-दासता का केन्द्र—मध्य रूस की अत्यन्त उपजाऊ काली मिट्टी का विशाल प्रदेश था। यहाँ पर १०% से अधिक उत्पादन श्रम-भुगतान [Bartschina] द्वारा होता था। खेती के अलावा भू-स्वामियों तथा किसानों का कोई भी दूसरा आय का साधन नहीं था। ससार से पृथक् इस पिछड़े हुए रूढ़िवादी, विस्तृत क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का आधार दासता से प्राप्त श्रम था। इसी कारण अत तक यह क्षेत्र दास-मुक्ति के मार्ग में रुकावटें डालता रहा तथा २० वीं शताब्दी तक राजनैतिक उथल-पुथल का केन्द्र बना रहा।

### दास-मुक्ति अधिनियम [Emancipation Act]

सर्वप्रथम यह मान लिया गया कि समस्त भूमि चाहे उसको भू-स्वामी प्रयोग में लाता हो या किसान भू-स्वामी की निजी संपत्ति है। पश्चिमी योरप के देशों में समकालीन कृषि-सुधारों से बहुत बड़े भूमिहीन किसान वर्ग का निर्माण हुआ जिसकी जीविका का कोई स्पष्ट साधन सम्मुख न था। मुख्यतः इसी वर्ग के असंतोष के कारण विद्रोह तथा क्रान्तियाँ हुईं, इसलिये सिद्धान्त रूप से यह प्रयत्न किया गया कि मुक्ति के बाद प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी भूमि होनी चाहिये। अधिक मात्रा में भूमि छोड़कर शहरों की तरफ जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये भू-स्वामियों को सबसे उत्तम तरीका यही मालूम हुआ कि किसानों के पास अपनी भूमि होनी चाहिये। वे स्वतंत्र रहेगें तो कृषि छोड़कर उद्योग की तरफ जाने की उनकी इच्छा न होगी। भूमि मिल जाने का यह अर्थ नहीं हुआ कि वह अपनी भूमि बेचने अथवा गिरवी रखने का अधिकार भी पा गया। प्रत्येक किसान के पास कितनी भूमि होगी इसके सम्बन्ध में बहुत मतभेद था। भू-स्वामियों को डर था कि यदि जीविकोपार्जन के लिये पर्याप्त भूमि किसानों को मिल गई तो वे सामंत भूमि पर कार्य न करेंगे। यह निश्चित हुआ कि हर किसान को इतनी भूमि दी जाय जिससे उसकी जीविका चल सके और राज्य तथा भू-स्वामी के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करने को वह बाध्य रहे। इसमें मदद करने के लिये कानून में यह निर्देशन भी रखा गया कि जहाँ तक हो सके व्यक्तिगत बोशीली तथा पोमेस्ती सम्पत्तियों पर किसानों के पास लगभग उतनी ही भूमि छोड़ दी जाय जितनी कि दासता उन्मूलन के समय उनके पास थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असमानता, असंतोष तथा अन्याय को दूर किये बिना ही दास-प्रथा की हालतों को मुक्ति के बाद के लिये भी आदर्श मान लिया गया। सुधार की भावनाओं से यह खिलवाड़ देखकर सरकार पर से किसानों की आस्था उठ जाना अवश्यम्भावी था। भूमि का वँटवारा और उसकी मात्रा-निर्धारण के नियम कुछ ऐसे विचित्र थे कि उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय भू-स्वामियों के ही हाथ में

रहा। प्रो० लाइशेको के अनुसार दास-मुक्ति के बाद प्रति-व्यक्ति भूमि की मात्रा में काफी कमी हुई। किसान को भूमि का स्वामित्व प्राप्त न होता था वरन् उसे भूमि एक अनिश्चित काल के लिये दी जाती थी। इस अधिकार के बदले में किसान को श्रम अथवा धन देने का व्यक्तिगत समझौता भू-स्वामी से करना पड़ता था। इस प्रकार किसानों के दायित्व का निर्धारण पुराने तरीकों से ही होता रहा।

कुछ समय बाद किसानों को भू-स्वामित्व भी दिलाया गया। दासों से मिलने वाले श्रम तथा मुद्रा-भुगतान के बदले में सरकार ने भू-स्वामियों को मुद्रावज्रा देने की योजना बनाई। किसान को भूमि मुक्त ही नहीं मिली। भू-स्वामियों ने अपने प्रभाव के कारण जमीन की बहुत ऊँची कीमत प्राप्त की। किसान को स्वामित्व पाने के लिये एक निश्चित धन-राशि मुद्रावजे के रूप में देनी पड़ती थी। इस भुगतान का 4/5 भाग किसान को सरकार की ओर से उधार मिलता था। इस उधार को किसान 49 बराबर किस्तों में अपने टैक्स के साथ राज्य को अदा करता था। इस प्रकार राज्य ने ही एक अंश में उस धन को प्रदान किया जिससे किसानों की मुक्ति हो सके। इस वार्षिक भुगतान का पूरा लाभ गरीब किसान न उठा सका। मूल भुगतान तथा व्याज के बोझ ने किसानों की दशा सुधारने के बजाय और खराब बना दी। 1904-1906 के बीच पिछले और भविष्य में बचे हुए भुगतानों को सरकार ने रद्द करके किसानों को स्वतंत्रता की तरफ ठोस कदम उठाया। भू-स्वामी के स्थान पर ग्राम समुदाय अथवा मीर को भू-स्वामित्व के अधिकार मिले। श्री के० ऐ० वीश्च-नूडसे के अनुसार 81.4% भूमि मीर के स्वामित्व को मिली तथा 18.6% व्यक्तिगत कृषक को।<sup>1</sup> दूसरी स्थिति में भी कर के लिये मीर ही जिम्मेदार था। मीर संगठन को पुनः जायत किया गया। किसान तथा भू-स्वामी के बीच का यह एकमात्र संवध बना। यहाँ तक कि मुद्रावजे के भुगतान के लिये व्यक्तिगत किसान के स्थान पर सामुदायिक रूप से मीर ही उत्तरदायी था। इस भुगतान ने किसानों को मीर छोड़ने की स्वतंत्रता न मिलने दिया। नये कानूनों द्वारा मीर एक 'सहकारी संगठन' न होकर 'सरकारी संगठन' बन गया। पुलिस के अधिकार, टैक्स लगाना, भूमि का सामयिक बँटवारा इत्यादि इतने अधिकार मीर को मिले कि ग्राम समुदाय की लुप्त कुशता [petty despotism] भू-स्वामी के कठोरता से भी अधिक असह्य हो गयी। जैसे प्रो० मेयर ने कहा है कि दास-मुक्ति से न तो किसानों को राजनैतिक स्वतंत्रता मिली, न भू-स्वामी को, परिवर्तन केवल इतना हुआ कि किसी को भी राजनैतिक स्वतंत्रता से स्थायी रूप से वंचित नहीं किया जा सकता था।<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Knowles, op. cit. 77.

<sup>2</sup> Mevor, op. cit., vol. I., p. 416.

### दास-मुक्ति के परिणाम [Effects of Emancipation]

दास मुक्ति से रूसी अर्थ-व्यवस्था में एक नये युग का आरम्भ हुआ। इसमें असतोप, विद्रोह तथा दमन-चक्र निरन्तर चलता ही रहा। वे सभी कारण किसानों पर ही केन्द्रित थे जो कि अन्त में चलकर 1917 की राज्यक्रान्ति के रूप में परिणित हो गये। किसानों की दशा तथा असतोप की जड़े दास-मुक्ति कानून में ही पाई जाती हैं। जिन उच्चादशों को सम्मुख रख कर इस ओर देश अग्रसर हुआ, उनकी प्राप्ति दुर्लभ बनी रही, जिस दासता से मुक्त करने के लिये सदियों से चली आई हुई आर्थिक तथा सामाजिक पद्धति के बदलने का प्रयत्न किया गया, वही दासता अपना रूप बदल कर एक व्यवहारिक प्रथा होने के स्थान पर वैधानिक मान्यताप्राप्त प्रथा बन गई। प्रसिद्ध रूसी सुधारक, हारजेन, मुक्ति अधिनियम को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्राचीन दासता एक नये रूप में बदल गयी। दासता का उन्मूलन न हुआ और देश को धोखा दिया गया।<sup>1</sup>

इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि 4 करोड़ उद्धारित व्यक्तियों को सम्पूर्ण योरोप के 2/3 क्षेत्रफल के बराबर देश में बसाना कोई हँसी नहीं थी।<sup>2</sup> उस समय की शासन-व्यवस्था की दशा बहुत खराब थी। घूसखोरी, पक्षपात, बेइमानी आदि से अत तक फैली हुई थी। साथ ही साथ स्वार्थी सामंतों तथा भू-स्वामियों द्वारा निर्मित यह कानून यदि किसानों के आशानुसार उदार सिद्ध न हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं। वास्तव में, इससे कोई भी संतुष्ट न था। क्योंकि किसान एवं भूमिधरों की आशाएँ परस्पर विरोधी थीं। किसान अधिक से अधिक भूमि चाहता था किन्तु भू-स्वामी किसान से प्राप्त श्रम एवं भुगतान को त्यागना नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, स्वयं भूमि-स्वामियों में अलग-अलग क्षेत्र में पृथक् इच्छाएँ थी। उत्तर के औद्योगिक प्रदेश अपनी अनुपजाऊ भूमि किसानों को देकर उनसे कारखाने का श्रम प्राप्त करना चाहते थे, मध्य रूस में काली मिट्टी वाले उपजाऊ प्रदेश कृषि से कम भूमि देकर बाशाना पद्धति में किसानों के श्रम को पाना चाहते थे। इन सबके बीच का रास्ता खोज निकालना, जिससे सभी संतुष्ट हो जायें, लगभग असंभव था। इन दोनों वर्गों को संतुष्ट करने के असफल प्रयत्न से राज्य ने उनका विश्वास एक साथ खो दिया। थोड़ी-सी स्वतंत्रता पाकर कृषक और अधिक के लिए व्यग्र हो उठे : अपने अधिकारों में कमी देखकर भू-स्वामी विरोधी बन गये : सम्राट एलेक्जेंडर द्वितीय ने सुधारों को जन्म देकर अपनी हत्या ही नहीं वरन् जारशाही के अंत को घोषणा कर दी : यही उसके सद्विचारों का पारितोषिक था।

<sup>1</sup>Lyashchenko op. cit., p. 378.

<sup>2</sup>Excellent discussion in D. M. Wallace, Russia, pp 496-510

कानून में चन्द ऐसी कमजोरियाँ छूट गयीं जिसको अदूरदर्शिता तथा स्वार्थ दोनो का प्रभाव माना जा सकता है। दास-मुक्ति के पश्चात् किसान ने अपने को पूँजीवादी संगठन की ओर बढ़ती हुयी व्यापारिक अर्थ-व्यवस्था [Commercial Economy] में पाया। परन्तु खुली हुई प्रतिस्पर्धा का आधार, पूँजी पर अविलंबित, बड़े पैमाने का उत्पादन था। उनके छोटे-छोटे खेत एवं प्राचीन खेती का ढङ्ग उसके योग्य न था। नवीन वातावरण में उनकी भूमि पाने की इच्छा एक आर्थिक आवश्यकता बन गई। दूसरी ओर भू-स्वामियों ने अपनी संपत्ति का वही हिस्सा किसानों को बेचा था जो सबसे कम उपजाऊ था। इसके साथ अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने के उत्साह में किसानों ने खेती योग्य भूमि ही खरीदने पर जोर दिया। चरागाह, तालाब तथा जंगल बिना, उनके छोटे पैमाने की खेती और भी अनाधिक बन गई। खराब जमीन एवं ऐसी विकट परिस्थिति के दुष्परिणामों से बचने के लिये मुआवजे तथा राज्य-कर के दायित्व का भुगतान [बिना अधिक भूमि प्राप्त किये] कर पाना असंभव था। इस अधिनियम के फल-स्वरूप सदियों से निरन्तर चली आई भूमि की भूख ऐसी प्रचंड ज्वाला बनी, जिसमें कि समस्त देश लगभग अगले 60 वर्षों तक जलता रहा, और अन्त में सन् 1917 में जार एवं प्राचीन शासन पद्धति की आहुति लेकर ही यह शान्त हुई।

शीघ्र ही स्वतंत्र कृषक पुनः उसी पतन की ओर चलने को बाध्य हुआ जहाँ से उसे उठाने के लिये इतना सारा प्रयत्न हुआ था। दायित्व को पूर्ण करने का साधन जब अपने खेतों से प्राप्त न हुआ तब किसान भू-स्वामियों के यहाँ उनके खेतों पर काम करने के लिये जाने लगा। इस कार्य एवं इससे प्राप्त वेतन ने कृषक को ऐसा जकड़ा कि पुनः पुराने मालिकों के पंजों में वह फँसने लगा। दास पद्धति के एक नवीन रूप का प्रादुर्भाव हुआ।

दास-मुक्ति अधिनियम से टूटती हुई सामतवादी अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। केवल दासों को ही इससे मुक्ति न मिली वरन् देश की शासन-व्यवस्था के अन्य अंशों को भी नवीन ढाँचे में ढालने के लिए सुधार किये गये। इनमें से मुख्य सुधार थे—1864 में ग्रामीण संगठन तथा न्यायालय, 1870 में नगरों का स्वायत्त शासन एवं 1874 में सैनिक संगठन।

सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों ने देश में प्रथम बार जनता की इच्छा को राजनैतिक रूप से संगठित होने के लिये उत्साहित किया। अभी तक जनता की माँग केवल सामाजिक सुधार की थी। जार एवं बुद्धिवादी वर्ग भी राजनैतिक सुधार का नाम लेते घबड़ाते थे। सुधार की सम्भावना देखकर, इस समय से जनता के माँग का आकार बढ़ने लगा। इससे उत्पन्न विचारधाराएँ एवं दल आने वाले राजनैतिक संघर्ष की तैयारी में प्रथम चरण सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त नई पीढ़ी के नवयुवकों ने इन सुधारों को

एकदम पृथक दृष्टि से देखा। इनमें न तो प्राचीन पद्धति और प्रथाओं की भक्ति थी और न अनुभव की गम्भीरता। दास-मुक्ति से असंतुष्ट होकर इनका विचार व्यापक एवं समूल परिवर्तन पर केन्द्रित हो गया। अब सुधारों की माँग की जगह, देश का ढाँचा ही बदलने पर लोगों की आस्था स्थिर हो गई। अपनी आशावादिता तथा जोश से इन्होंने समस्या का रूप बदल कर अत्यन्त सरल कर दिया। परिवर्तन क्रमिक हो अथवा अचानक : नेतृत्व उदार विचारधारा का होगा या क्रान्तिकारियों का—केवल यही तय करना बाकी रहा।

इतना अवश्य है कि दास-मुक्ति ने रूढ़िवादिता को समूल हिला दिया और देश के संगठन में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा आधुनिकता का आगमन संभव बनाया। किन्तु यह प्रभाव दीर्घकालीन था। औद्योगिक आधुनिकता में इसकी सबसे बड़ी देन औद्योगिक श्रम का निर्माण था। यह दासों [Dvorovie lyud'e] को स्वतंत्रता के साथ भूमि नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त वोशीना के दास व राजकीय तथा व्यक्तिगत कारखाने के दासों को भी भूमि नहीं दी गई। इनकी संख्या लगभग 40,00,000 के अनुमान की गई है। इनको लाचार होकर नगरों में नौकरी करने आना पड़ा। औद्योगिकीकरण के पुकार पर बने नये श्रमिक वर्ग ने इन्हे सहर्ष स्वीकार किया।

1861 से आरंभ होने वाले सुधार वैधानिक ही थे। उनको व्यवहार रूप में आने में काफी समय लगा। फिर भी हम इन सुधारों को नवीन प्रगति का युग-प्रवर्तक मान सकते हैं। यदि तत्काल इनका लाभ न दिखाई दिया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुराने विचार, आदतें तथा रीति-रिवाज न तो एकदम से बनते हैं, न उनका उन्मूलन ही अचानक सम्भव है। इनका महत्व इस बात में है कि, आधुनिकता तक पहुँच कर, योरोप के दूसरे देशों के साथ खड़े होने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट गई। आने वाले औद्योगिक पूँजीवाद के लिये वातावरण बनाने में इन सुधारों का बड़ा भारी हाथ था।

इतना सब होने पर भी, ये सुधार 19 वीं शताब्दी के अंत तक आर्थिक व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन न कर सके। सामंतवादी-दासता की अर्थव्यवस्था [Feudal-serf economy] कुछ रूपान्तर के साथ पूर्ववत् बनी रही। जार पूर्ण निरंकुश था और भू-स्वामियों का प्रभाव शासन में कम न हुआ। प्राचीन बुनियादी ढाँचे पर नया संगठन लादने के प्रयत्न में जो गुत्थियाँ पड़ी, उनको सुलझाने का असफल प्रयास ही रूस का 1917 तक का इतिहास है।

## अध्याय ५

### आर्थिक संगठन [१८६१-१९१७]

[Economic Organisation 1861-1917]

रूसी कृषि [1861-1917]

[Russian Agriculture 1861-1917]<sup>\*</sup>

दास-मुक्ति अधिनियम और उसके लागू करने का तरीका किसानों के लिये अत्यन्त निराशाजनक सिद्ध हुआ। मुआवजे [redemption payment] की ऊँची दर और सीमित भूमिस्वामित्व के कारण दास-मुक्ति से किसानों को थोड़े-से अधिकार, कुछ भूमि, किन्तु प्रचुर उत्तरदायित्व मिला<sup>1</sup>। 1861 के बाद किसानों की दशा बराबर बिगड़ती गई। 1877 और 1905 के बीच गाँवों को आबादी में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई जिससे उल्लब्ध भूमि और भी कम पड़ने लगी। प्रति-परिवार भूमि इस समय में 13.2 देस्यातिन<sup>2</sup> से घटकर 10.4 हो गई।

1861 के सुधारों ने रूसी कृषि के बुनियादी संगठन को समूल परिवर्तित नहीं किया। भू-स्वामी के असीमित अधिकारों में किसान, ससार से पृथक्, आत्म-निर्भर रूप से उत्पादन और जीवनयापन करता रहा। व्यापारिक तथा पूँजीवादी कृषि की आवश्यकताएँ उत्पन्न नहीं हुई थीं। दूषित वारशीना श्रम पद्धति भी कुछ परिवर्तित रूप में बनी रही। धनी किसान तथा भूस्वामी ने कृषि-क्षेत्र का नेतृत्व सामन्तों से अपने हाथ में ले लिया। किन्तु इससे किसान की आश्रित स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। देश की कृषि के दो मुख्य क्षेत्र बन गये। भूस्वामियों ने अपनी भूमि के कुछ भाग पर तो पूँजीवादी खेती करना आरम्भ किया जिसमें मशीन तथा वैतनिक श्रम का प्रयोग हुआ। बाकी हिस्से में पुराने ढंग पर खेती चलती रही। इस प्रकार किसानों का शोषण बना रहा और शोषण से मुक्ति पाने का प्रयत्न भी उपद्रव तथा क्रान्तिकारी कार्यवाही के रूप में अपने शिखर की ओर अग्रसर हुआ।

#### पूँजीवाद का उदय

इस समय में व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती आरम्भ हुई। बाजार की माँग को

<sup>1</sup>G. T. Robinson Rural Russia Under Old Regime, p. 88.

<sup>2</sup>One desyatina = 2 7 acres.



ध्यान में रखकर किसी एक वस्तु के उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा। वैतनिक श्रम और मशीनों से बड़े पैमाने पर काम करना ही लाभप्रद था। इस प्रकार की कृषि के लिए धन की आवश्यकता थी, जो किसान तथा पुराने सामन्त भूस्वामियों के पास प्रायः नहीं थी। पूँजी प्राप्त करने के लिये कृषि, समृद्धिशाली किसान, व्यापारी एवं अन्य धनवान व्यक्तियों के हाथों में जाने लगी। श्रम का महत्व पूँजी ने ले लिया और कृषि क्षेत्र से वशानुगत सामन्त तथा उच्च वर्ग के व्यक्तियों का स्वामित्व व प्रभुत्व दोनों ही घटने लगा। इसको बनाये रखने के लिये इस वर्ग ने प्राण-प्रण प्रयत्न किया जिसमें उचित-अनुचित का विचार निजी स्वार्थ के आगे न टिक सका। पूँजीवादी प्रभाव के कारण व्यक्तिगत खेती की ओर समाज झुक रहा था। इस प्रवृत्ति में सामन्तों को अपना निश्चित विनाश दिखाई दिया। वे इस व्यक्तिवाद को रोके रखना चाहते थे और किसान इसे प्राप्त करने पर तुले थे। मीर का अनुशासन अब मजूर न था। सामाजिक संघर्ष और गहन हुआ। आने वाले विस्फोट की तैयारी पूरी तीव्रता से अनायास ही हो गई।

### मीर

ग्राम समुदाय [ Village Commune ] अथवा मीर 1861 के बाद बहुत ही शक्तिशाली बन गये थे। 1880-1890 के बीच भूमि पर आबादी का भार इतनी जोरो से बढ़ा कि मीर ने भूमि का पुनर्वितरण बहुत जल्दी-जल्दी करना आरम्भ किया। भूमि-स्वामित्व किसानों को न मिलकर मीर में निहित था। जब तक किसान मुआवजे की पूरी रकम चुका न दे, उसे स्वतन्त्र स्वामित्व प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिये इन पुनर्वितरणों ने किसानों की दशा को बहुत ही खराब कर दिया। उनके खेत छोटे होते गये और कृषि-उत्पत्ति की सभी आवश्यकताओं को तिलाजलि दे दिया गया। अमीर किसानों का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि मीर का स्वतन्त्र रूप से कार्य करना असम्भव था। 1890 तक इसका पतन आरम्भ हो गया।

### किसानों के खेत [ Peasant Farm ]

दास-मुक्ति अधिनियम के बाद किसानों को अपने खेत प्राप्त करने की स्वतन्त्रता अवश्य मिली किन्तु उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई। भूमि की कमी तथा मुआवजे के भुगतान के बोझ ने उनको वस्तुतः तोड़ दिया। जगह-जगह पर तो स्थायी अकाल की परिस्थिति में किसान रह रहे थे। 1872-78 में सरकार ने इनकी अवस्था में जाँच करने को स्थानीय आयोग [ Local Commissions ] बनवाये किन्तु उनके सदस्य सरकारी कर्मचारी तथा सामन्तों के होने से यह केवल जाँच आयोग ही रह गया। राजकीय वैल्यूयेव कमीशन [ Valueyev Commission ] 1872 में बैठा। इसने कृषि की दयनीय स्थिति का जो चित्र खींचा उससे शासन सहम उठा। मदिरा तथा

आलस के अतिरिक्त कमीशन ने इस दुर्दशा का मुख्य कारण राज्य-कर की असमानता तथा पक्षपात पाया। सामन्त-भूमि की तुलना में किसानों के भूमि पर १०, २० तथा कहीं-कहीं ४० गुना कर-भार अधिक था। सामन्तों के खेतों पर जब आय का २ से १०% तक टैक्स देना पड़ता था, किसानों के खेतों पर इसकी मात्रा सभी जगह ५०% से अधिक थी। सम्पूर्ण कृषि-क्षेत्र से प्राप्त २०८ मिलियन रूबल कर में से १९५ मिलियन किसान देते थे तथा कुल १३ मिलियन भूस्वामी। किसी-किसी प्रान्त में खेत की आय-शक्ति से २ या ३ गुना अधिक कर लगा था। इसका प्रभाव यह पड़ा कि वार्षिक भुगतान में किसान पिछड़ने लगा। वकाया [ arrear ] कर-भार की मात्रा तेजी से ऊपर उठी :

किसानों के वकाया कर की प्रतिशत वृद्धि<sup>१</sup>

प्रान्त	1871-1875	1876-1880	1881-1885	1886-1890	1891-1895	1896	1898
सिम्बर्स्क	५%	६%	३४%	४२%	२०४%	२२३%	२७७%
तूला	३	५	१६	३५	१३४	१५१	२४४
क्रजान	४	३१	१०१	१७०	७३०	३३४	४१८
ऊफा	२५	४०	७७	२०८	३३६	३६०	३९७

इस हालत का बुनियादी प्रभाव यह पड़ा कि किसानों की खेती घटने लगी। बड़े पैमाने पर, बाजार के लिए पूँजीवादी खेती आरम्भ हुई।

### कृषि उत्पादन

सुधार के बाद लगभग ३० सालों में अन्न के उत्पादन तथा क्षेत्रफल दोनों में अच्छी वृद्धि मिलती है। अनाज की पैदावार करीब दूनी हो गई। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह विस्तार किसानों की दशा में सुधार का परिचायक है। यह विस्तार लाचारी-वश किया गया था। उत्पादन जरूर बढ़ा परन्तु इसका उद्देश्य लाभ कमाना न था। अत्यधिक बढ़े हुये कर-दायित्व को पूरा करने का यह केवल एक असफल प्रयत्न था। एक विशेष हानि यह हुई कि चरागाह, जंगल और दूसरी जितनी भी भूमि मिल सकी, उन सब पर खेती होने लगी। स्वभावतः कृषि-उत्पादन का संतुलन नष्ट हो गया।

<sup>१</sup>Lyashchenko, op. cit., p. 447.

[Rise of Kulak or rich peasant] कुलक अथवा समृद्धिशाली किसान वर्ग का उदय

1880-90 के कृषि-मन्दी से ग्रामीण आवादी के नये वर्गीकरण को बहुत प्रोत्साहन मिला। 1900 तक यह वर्गीकरण स्पष्ट रूप से पूँजीवादी खेती का रूप ग्रहण कर चुका था। रूसी किसान तथा भू-स्वामी प्राकृतिक अर्थव्यवस्था [natural economy] में उत्पादन करने के अभ्यस्त थे। तेजी के साथ देश में बनते हुए पूँजीवादी बाजार के नियम व तरीकों से वे पूर्ण अनिभिन्न थे। प्रतिस्पर्धा [Competition] की अवस्था में, लाभ कमाने के लिए, बाजार मूल्य तथा लागत के सन्तुलन की दृष्टि से उत्पादन सगठित करना इनको नहीं आता था। अनार्थिक खेती तथा मन्दी से आक्रान्त, नये परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त कृषि-उत्पादकों की विवशता का अनुचित लाभ उठाया जाना स्वाभाविक था। इन्हीं के बीच से ऐसे व्यक्तियों का छोटा-सा वर्ग सामने आया जिसके पास आवश्यक चतुरता, तेजी तथा धन था। इनको ग्रामीण पूँजी-पति, धनी किसान अथवा अनादरसूचक रूप में, कुलक [Kulak] या कृषण [first] कहते हैं। इन्होंने अपने धन से बड़े पैमाने पर गरीब किसानों की भूमि खरीद कर उनसे वेतन पर काम कराया। इस तरह लेनिन के अनुसार दो धारायें प्रगट हुई। एक तरफ तो गरीब किसान अपनी जमीन तथा मवेशी खो कर मामूली मजदूर बन गया। दूसरी ओर समृद्धिशाली किसानों को अमीर बनने के कई साधन मिले जैसे, बड़े पैमाने पर मशीनों से वैज्ञानिक ढंग की खेती, छोटे उद्योग और उधार देने का धन्धा। यह सब काम बीसवी सदी में भी चलता रहा। इस धनी किसान वर्ग का प्रभाव बढ़ता गया। 1883 में कृषक भूमि बैंक [Peasant Land Banks] की स्थापना हुई।<sup>1</sup> इनका उद्देश्य किसानों को भूमि खरीदने में आर्थिक सहायता करना था। 1887 और 1903 के बीच बैंक की सहायता से किसानों ने 55 लाख देस्यातिन भूमि खरीदी। इसके भुगतान में किसानों द्वारा दिये गये धन से जो अमीर किसान वर्ग बना वही आगे चल कर कुलक वर्ग में बदल गया।<sup>2</sup>

**भू-स्वामियों के खेत [Landowner's Farms]**

कृषि-क्षेत्र का दूसरा विशिष्ट अङ्ग, सामन्त-कृषि [nobility farming] भी सुधारों के बाद नई दिशा में अग्रसर हुई। इस वर्ग के पास भूमि लगातार घटती ही गई।

<sup>1</sup>For details, Maurice Dobb, op. cit., p. 53 and Lyashchenko, op. cit., pp. 467 and 749

<sup>2</sup>G. T. Robinson, op. cit., p. 101

भूमि स्वामित्व ( प्रतिशत में )<sup>1</sup>

सामाजिक वर्ग	1877	1877	1905
सामंत	77.8%	68.3%	52.5%
किसान	7.0	13.1	23.9
व्यापारी इत्यादि	14.2	16.3	20.2

इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भूमि सामंतों के हाथ से निकल कर नये वर्गों के पास जा रही थी। इसके अलावा भूमि के वशानुगत अधिकारी वर्ग का जन्म-सिद्ध एकाधिकार खंडित हो चुका था। सामाजिक श्रेष्ठता जन्म की जगह अब पूँजीपति को मिलने लगी। प्रोफेसर लाईशेन्को द्वारा दिये गये आँकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में भी कृषि के स्वामित्व का केन्द्रीयकरण कितना विकट था। 80% से अधिक आबादी के पास केवल 5% भूमि थी; 20% आबादी 95% भूमि की मालिक थी।<sup>2</sup> इस छोटे से वर्ग ने बड़े-बड़े खेत प्राप्त करके उन पर अधिक लाभदायक उपज जैसे चुकन्दर [Sugar-beet] और आलू की खेती, पूँजी लगा कर, व्यापार के लिये किया। प्रायः सभी जगह इनसे सम्बन्धित उद्योग भी स्थापित किये गये जैसे चीनी मिल, और आलू की शराब।

व्यापारिक कृषि एवं उद्योगों के लिए और भी पूँजी की आवश्यकता हुई। 1880-90 की मन्दी के समय बहुत ही बड़ी मात्रा में सामन्तवर्ग ने अपनी जमीन किराये पर देना शुरू किया। इसका भुगतान या तो वे सुद्रा में या कटाई के अंश [Share Cropping] में लेते थे। इस धन का प्रयोग कुछ चुने हुए खेतों के पूर्णतम उपयोग तथा उद्योग में होता था। इतना होने पर भी सामन्त भू-स्वामियों का ऋण-भार बढ़ता ही गया। 1885 में सामंत भूमि बैंक [Noblemen's Land Bank] स्थापित किये गये जिनका उद्देश्य सामंतों को इस स्थिति में मदद करना था। भूमि को बंधक रखकर यह बैंक उधार देते थे। 1886-1912 के बीच 1,146 मिलियन रूबल उधार दिया गया।

1875-1885 की अंतर्राष्ट्रीय कृषि-मंदी का प्रभाव

1880 तक यह मंदी बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। रूस की खेती अपना सबसे बड़ा सहारा निर्यात द्वारा [‘योरप में अन्न भंडार’ के रूप में] प्राप्त करती थी। इस मंदी ने अनाज का दाम इतना गिरा दिया कि उत्पादन का खर्च भी निकलना

<sup>1</sup> Lyashchenko, op. cit, p. 462

<sup>2</sup> Ibid.

असम्भव हो गया। क्रयशक्ति कम हो जाने से लोगों की माँग घटी और उद्योग पर भी उसका बुरा असर पड़ा। कृषि उत्पादन का दाम 1880-90 के बीच 1870 का कुल 1/5 रह गया। मंदी के फलस्वरूप औसत किसानों की गरीबी, चन्द समृद्धशाली किसानों तथा व्यापारियों की शक्ति में अपार वृद्धि, मशीनों के प्रयोग में कमी, और पूँजीवाद की ओर बहुत प्रगति हुई। यह कहा जा सकता है कि गरीबी, समृद्धशाली किसानों का शोषण तथा राज्य की अनिश्चित नीति ने आने वाले विद्रोह की नीवि डाली।

दास-मुक्ति के लगभग 40 वर्ष बाद तक देश की अवस्था बराबर बिगड़ती गई। इसके पहले कि नयी शताब्दी का इतिहास देखा जाय, इन 40 वर्षों पर संक्षेप में दृष्टिपात करना उचित होगा। इस समय में होने वाले सभी परिवर्तनों को देखकर यह विदित होता है कि दासता उन्मूलन से किसानों की दशा बहुत शोचनीय हो गई। भू-स्वामी तथा व्यापारी वर्ग अपने प्रभुत्व में बराबर वृद्धि करता रहा। किसान ने जिस स्वतंत्रता के सुस्वप्न देखे थे, उनको साकार बनाने के लिए उन्हें नये जोश और उत्साह के साथ अन्याय के विरुद्ध संग्राम चालू करना पड़ा। पूँजीवादी सामाजिक विभाजन तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से सगठित बड़े ग्वेतों की प्रगति तेजी के साथ हुई। समृद्धशाली किसान तथा व्यापारिक कृषक [Merchant Landowner] के प्रादुर्भाव ने देश में वर्ग संघर्ष [Class Struggle] को और उत्साहित किया। दबे हुए किसान में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ प्रकट हुईं। इनको बहाना बना कर सामंतों ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए सामाजिक और राजनैतिक दबाव को बढ़ाया। किसानों को आर्थिक परतंत्रता [Financial Enslavement] में जकड़ने का उपाय किया गया। अनेक कानूनों द्वारा 1881-1893 के बीच सामंतों ने किसानों को पुनः अपने संरक्षण में ले लिया। कहने के लिये इसका कारण उनकी अनुशासनहीनता को बश में रखना था। किसान की दशा तथा उनसे सम्बन्धित अधिनियमों का पुनः सिंहावलोकन करने को सामंतों के दबाव से जार ने 1893 में नये आयोग की स्थापना की। इसके सुभाव 1903 में सामने आये। उस समय तक मजदूरों की बढ़ती हुई संख्या और संगठन; स्थान-स्थान पर किसान-विद्रोह; मजदूर हड़ताल; विद्यार्थियों तथा बुद्धिवादी वर्ग में राज्यक्रान्ति की भावना का समावेश व प्रसार; और इस परिस्थिति को बुद्धिमानी तथा तत्परता से सम्हालने में सरकार की पूर्ण अयोग्यता; वे मुख्य कारण थे जिनसे 1917 की साम्यवादी राज्यक्रान्ति की पृष्ठ भूमि तैयार हुई।

मन्दी के बाद 1909-1913 में आश्चर्यजनक कृषि-संवृद्धि आई। हर एक क्षेत्र में खेती की उन्नति हुई। इस समय अन्न तथा व्यापारिक उत्पादन बढ़े। पूँजी के उपयोग से नये वस्तुओं का कृषि-उत्पादन आरम्भ किया गया। अभी तक व्यापारिक

उत्पादन की मात्रा आशातीत रूप से न बढ़ी थी। इतना ही नहीं, प्रति एकड़ उत्पादन में कोई परिवर्तन न हुआ। संसार के दूसरे देशों में रूस का स्थान सबसे नीचा था।

२०वीं शताब्दी में व्यापारिक-पूँजीवादी कृषि-क्षेत्र में और भी वृद्धि हुई। औद्योगिक कच्चा माल पैदा करने में विशेष कुशलता प्राप्त की गई। कपास, चीनी, तम्बाकू तथा आलू इनका मुख्य उत्पादन था। बढ़ते हुए उद्योगीकरण से इस क्षेत्र में बड़े उत्पादनकर्त्ताओं को विदेशी बाजार के अतिरिक्त देशी बाजार भी मिला। इसका विस्तार लगातार हो रहा था।

रूसी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी के लाभदायक प्रयोग के लिए इतना बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत था कि देशी पूँजी पर्याप्त न हुई। विदेशियों ने इसका बड़ी मात्रा में लाभ उठाया। उद्योगों को छोड़कर कृषि में भी इनका प्रभुत्व २०वीं शताब्दी के आरम्भ तक जम चुका था। अनाज की बड़ी आहूतें तथा निर्यात-व्यापार विदेशी पूँजी के हाथ में चला गया। देशी बैंकों ने भी खेती में रुचि लिया किन्तु इनका प्रभाव, कम से कम विदेशी व्यापार में, अधिक नहीं था।

### पीटर स्तोलाइपिन के कृषि-सुधार

१९०३ में सुआवजे के सुगतान की सामूहिक जिम्मेदारी मीर से ले ली गई और १९०५ में सुआवजे की वसूली बन्द कर दी गई। इन परिवर्तनों ने मीर की शक्ति को छीन लिया। जनता की क्रान्तिकारी मानसिक स्थिति का प्रमुख कारण उनकी 'जमीन की भूख' [Land-hunger] थी। इसे शान्त करने के लिये निश्चय किया गया कि भूमि किसानों के पूरे व्यक्तिगत अधिकार में दे दी जाय। रूस के प्रभावशाली प्रधान मंत्री पीटर स्तोलाइपिन ने कृषि-सुधार करने की योजना बनाई। १९०५ की क्रान्ति में यह देखा गया था कि अगर किसानों को अपने खेतों का पूर्ण स्वामित्व मिल जाय तो वे शान्त हो जायेंगे। इसलिये स्तोलाइपिन ने यह प्रयत्न किया कि सामुदायिक भूमि-स्वामित्व तथा किसानों का भूमि पर पारिवारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाय। उसकी जगह पर एक व्यक्तिगत स्वामित्व वाला [Individual ownership] भूमि संगठन किया जाय जिससे आधुनिक वैज्ञानिक खेती के लिए अवसर मिल सके। दूरदर्शी, मेहनती एवं कुशल व्यक्ति बिना मीर के दबाव के आगे बढ़ने में समर्थ हो। १९०६ में एक कानून द्वारा इन सुधारों को लागू किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण समाज को दो भागों में बाँटा गया :—

(१) वह समुदाय जहाँ दास-उन्मूलन के बाद किसानों के बीच पुनर्बँटवारा हो चुका था। इन जगहों में अगर कोई किसान मीर से अलग होना चाहे तो उस पर

कोई रुकावट न होगी। जहाँ तक सम्भव हो, ग्राम समुदाय बिखरी हुई पट्टियों के स्थान पर एक बँधा हुआ खेत किसान को देने का प्रयत्न करे।

(2) वह समुदाय जहाँ पुर्नबँटवारा नहीं हुआ था। ऐसे मीर में जितनी भूमि उस समय एक परिवार के पास थी, उसे उस परिवार की सम्पत्ति मान लिया गया। व्यक्तिगत किसानों की भूमि उनके स्वामित्व में दे दी गई।

इसके अतिरिक्त स्वेच्छा से किसी भी मीर के सदस्य केवल बहुमत [majority] प्राप्त करके पूरे मीर का भूस्वामित्व व्यक्तिगत स्वामित्व में बदल सकते थे। इसके नियम इतने आसान बना दिये गये कि ग्राम समुदाय [mir] को तोड़ने में कोई कानूनी बाधा न रही। मीर के टूटने से जो व्यक्तिगत खेत बने, उनको वेचने व उत्तराधिकारियों को देने का पूर्ण अधिकार दिया गया।

इस समय के परिवर्तनों का ध्येय यह था कि किसानों में बढ़ती हुई क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों को रोक जाय। पीटर स्तोलाइपिन कृषि-सुधार के आड में स्वतंत्र, व्यक्तिगत किसानों का एक शक्तिशाली वर्ग तैयार करना चाहता था जिस पर जारशाही का आधार स्थिर किया जाय। शोषित किसान ही क्रान्तिकारियों की ताकत थे। स्तोलाइपिन के विचार से यह वर्ग क्रान्तिकारियों के विरुद्ध विश्वस्त मोर्चा ले सकेगा। इस दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के अनुसार राज्य को दुर्बल, निर्धन किसानों पर नहीं, बल्कि बलवान, सवृद्ध, व्यक्तिगत कृषक वर्ग पर राजतंत्र और जारशाही की नींव स्थापित करनी चाहिये। इन सुधारों की यह राजनैतिक गृष्ठभूमि थी। इसलिये मीर को क्रान्तिकारियों का अड़्डा घोषित किया गया। व्यक्तिगत खेती में सगाठित होने के लिये किसानों ने पूर्ण सहयोग पाया। 1914 तक लगभग 24% किसान व्यक्तिगत खेती अपना चुके थे। मीर-सङ्गठन को छोड़ने वाला की संख्या लगभग 20 लाख थी। इसमें या तो धनवान किसान थे या अत्यन्त गरीब किसान जो अपनी भूमि वेचकर शहरों में मजदूरी करना चाहते थे।<sup>1</sup>

प्रधान मंत्री पीटर स्तोलाइपिन [1906-1911] ने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचे पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। यह प्रभाव आशातीत दिशा में न हुए। सुधारकों की यह आशा साकार न हुई कि इन सुधारों से किसान की भूमि की माँग सन्तुष्ट हो जायगी, तथा देश में बढ़ते हुए क्रान्तिकारी विचार थम जायेंगे। भूस्वामियों द्वारा अपने हित में किसानों की दशा सुधारने का यह दूसरा प्रयत्न था, और करीब-करीब उन्हीं

<sup>1</sup> For details, G. T. Robinson, Op. Cit, p. 231. and Lyashchenko. op. cit, p. 747.

सब कारणां से यह विफल हुआ जिससे 1861 के सुधार खराब हुए थे। इसके द्वारा 1861-1866 के सुधारों को विध्वंस कर दिया गया। किसान यह कमी नहीं भूल सके कि सुधारों के पाखंड ने सामंत तथा धनी व्यापारियों की शक्ति को और प्रबल बना दिया। इनकी भूमि की माँग पूरा करने का यह सच्चा प्रयत्न नहीं था। प्रोफेसर नाइट के अनुसार मीर का विघटन तथा व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रसार उच्च ग्रामीण वर्ग के लिए ही किया गया।<sup>1</sup> मीर को छोड़ने के अधिकार का अधिकतर लाभ धनी किसानों ने उठाया जो बहुत अधिक भूमि प्राप्त कर चुके थे। इस स्वतंत्रता ने छोटे और गरीब किसानों को आसानी से अपनी भूमि अमीर किसानों के हाथ बेचने का मौका दिया जिससे कि वे भूमि से अपना सम्बन्ध तोड़कर मजदूर बन सके। कृषक बैंक [Peasant-Bank] भूमि को बेचने का प्रमुख साधन बने। राज्य इन बैंकों के द्वारा स्वतंत्र भूस्वामियों से भूमि खरीदता था। इसके लिए बहुत ऊँचा दाम इन बैंकों ने दिया और इस प्रकार प्राप्त भूमि का जो भाग बैंकों ने अपने भूमि-कोष में रोक लिया उससे भूमि की कमी, किसानों की माँग, और जमीन का दाम सभी कुछ बहुत बढ़ गया। यह विश्वास किया जाता है कि अनुचित संचालन के कारण इस भूमि-कोष के बेचने से भूमिहीन तथा छोटे किसानों को लाभ नहीं हुआ। अधिकतर यह भूमि समृद्धशाली किसानों के पास केन्द्रित हो गई। किसानों के असंतोष को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था।

कम से कम दो मुख्य प्रभाव इन सुधारों से प्रकट हुए। देश में भूमि से पृथक् मजदूर वर्ग का निर्माण तीव्रता से होने लगा। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में व्यापारी-पूँजीवाद के शक्तिशाली पोषकों का एक प्रबल वर्ग बना। दास अर्थ-व्यवस्था के सामंतों का स्थान नये पूँजीवादी संगठन में इस वर्ग ने ले लिया। किसान की दशा में विशेष परिवर्तन का अवसर न मिला : न उनका ऋण कम हुआ, न भूमि मिली, और न तो उनको आर्थिक सन्तुलन एवं स्थिरता का अनुभव हुआ। स्तोलाइपिन सुधारों ने क्रान्ति की लहर रोकने की जगह यह सिद्ध कर दिया कि समकालीन संगठन का समूल उन्मूलन किये बिना किसी भी प्रकार की आशा करना निरर्थक होगा। 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने से सुधारों की स्थगित कर दिया गया। जारों द्वारा कृषि-सुधार के प्रयत्न विलम्ब से अवर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रभावहीन रहे। आगे आने वाली घटनाओं ने ऐतिहासिक रूप से इस विचार की पुष्टि किया है।

1914-17 के विश्वयुद्ध में रूसी कृषि पर सहनशक्ति से अधिक भार पड़ा। सबसे बड़ा असर श्रम की कमी थी। श्रमिक वर्ग से [जिसमें अधिकतर ग्रामीण मजदूर

<sup>1</sup>Knight, Barnes & Flugel Economic History of Europe, p. 755



किसान थे] लगभग 75 लाख व्यक्ति सेना में भरती किये गये। इसके अतिरिक्त ग्रामीण मशीनों तथा खाद व बीज की कमी ने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया। बहुत बड़े पैमाने पर रूसी किसान का मुख्य मवेशी, घोड़ा, सरकारी फौजों द्वारा ले लिया गया। इन सब का असर यह हुआ कि अनाज के उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई।

1916 तक इसका प्रभाव सामने आया। अन्न संकट एक राष्ट्रीय समस्या बन गया। सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से कृषि उत्पादन को निश्चित दर पर खरीद लेना, अन्याय व असंतोष का कारण बना। उस क्षेत्र के खुले बाजार प्रायः नष्ट हो गये। मुद्रा-स्फीति के कारण रूबल का दाम इतनी तेजी से गिर रहा था कि निश्चित सरकारी मूल्य तथा बाजार-भाव में अन्तर सदा बढ़ता ही गया। सरकारी अत्याचार का यह नया तरीका सभी को बहुत अप्रिय था। सरकार की अदूरदर्शिता से उत्पन्न कटुता को परिस्थितियों ने पूरा बढ़ावा दिया और देश अपने भाग्य से मिलने तेजी के साथ क्रान्ति के मार्ग पर बढ़ चला।

### रूसी उद्योग—[ 1861-1917 ] [Russian Industry 1861-1917]

दास-प्रथा के अन्त ने रूस की अर्थव्यवस्था को एक भयंकर उथल-पुथल में डाल दिया था। उद्योगों की इन परिस्थितियों से स्थिरता प्राप्त करने में लगभग तीस वर्ष लग गये। इस परिवर्तन के काल में [ Transition Period ] इनको अपना रूप एकदम बदल देना पड़ा। 1860-70 में रूसी उत्पादन छोटे पैमाने पर विकेंद्रित पूँजीवादी ढाँचे का उत्पादन था जिसका आर्थिक संचालन किसी केन्द्रीय स्थान पर बसे हुए व्यापारिक पूँजीपति करते थे। इस समय बोशीना कारखानों का तेजी से पतन होकर, मशीनों तथा पूँजी से फैक्टरी उत्पादन आरम्भ हुआ। दास श्रमिकों के जाने से सामंत कारखाने एवं हस्तान्तरित उत्पादन पद्धति दोनों का उन्मूलन पूँजीप्रधान कारखानों ने कर दिया। लेनिन के अनुसार 1861 के सुधार भूमि को पूँजीवादी खेती के लिए तैयार कर चुके थे, अर्थात् बहुत बड़ी मात्रा में किसान भूमि को छोड़कर उद्योग की ओर आकर्षित हुए। श्रम की कमी को पूरा करने के लिए पूँजी और मशीन खेती में आई। 1865-1890 के बीच बड़े कारखाने, मिल तथा रेलों में काम करने वालों की संख्या 7,06,000 से बढ़कर 14,35,000 हो गई।

1890 तक पूँजीवादी उत्पादन रूस में पूरी धाक जमा चुका था। ज्यों-ज्यों पूँजी और मशीन का प्रयोग फैलता गया, विस्तृत कुस्तार-उत्पादन का क्षेत्र सिकुड़ता गया। कुछ कुस्तार उद्योगों ने इस विनाश से बचने के लिए पूँजीवादी उत्पादन के तरीकों को अपना लिया। उत्पादन की मात्रा सभी उद्योगों में बढ़ रही थी।

	1860	1876
मिलियन रुबल मे :		
सूत कटाई	28.7	44.2
सूती कपड़ा	42.9	96.3
ऊनी सूत	0.45	2.5
ऊनी कपड़ा	34.9	52.7
मशीने	14.0	43.4
मिलियन पूड में :		
पेट्रोल	0.6	10.9
कोयला	7.3	111.3
कच्चा लोहा	18.2	25.5
लोहा	11.7	17.1
रसात	0.1	1.1

इतना ही नहीं उत्पादन की पूँजीवादी प्रवृत्ति के अनुसार छोटे उद्योग या तो बड़े उद्योगों में मिलने लगे या प्रतिस्पर्धा में न खड़े हो सकने के कारण क्षेत्र छोड़कर हट गये।

इस समय में कारखाना मजदूरों की दशा बहुत ही खराब थी। 16-18 घंटे तक काम करना औसत समझा जाता था। पुरुष, किशोर, स्त्रियाँ तथा बच्चों के कार्य-काल में कोई अन्तर न था। बच्चों और अवयस्क [Adolescents] से ही सस्ते दामों पर अधिक से अधिक काम लेने की कोशिश होती थी। 1882 में पहला कारखाना अधिनियम [Factory Act] बना जिसमें असफल रूप से इन हालातों को सुधारने की कोशिश की गई। इस समय से ही अपनी दशा सुधारने के लिए मजदूरों द्वारा हड़ताल तथा प्रदर्शन शुरू हुआ।

संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी [Joint Stock Company] की संख्या और पूँजी दोनों बढ़ी। पूँजी की कमी के कारण विदेशी पूँजी भी अच्छी मात्रा में आई। इसका मुख्य आकर्षण रेलवे कम्पनी की स्थापना थी। उद्योगइतने लाभदायक थे कि मुआवजे का धन [Redemption Payment] और भूमि बेचने से प्राप्त पूँजी सामंतों ने अधिकतर उद्योगों में लगाया। बैंक प्रणाली का विकास आश्चर्यजनक पैमाने पर हुआ। 1860 में State Bank की स्थापना हुई और 1870 तक उसकी 41 शाखाओं के अतिरिक्त 29 संयुक्त पूँजीवाले बैंक [Joint Stock Banks], 15 आपसी ऋण कम्पनियाँ [Mutual Credit Companies], 163 नगर-पालिका बैंक [Municipal

Banks] तथा 16 बचत एवं उधार सघ [ Savings and loan societies ] बने ।

पूँजीवाद के आगमन के साथ ही साथ औद्योगिक मन्दी भी रूसी अर्थव्यवस्था में आई । 1873-1875 तथा 1881-82 में आनेवाली मन्दी ने औद्योगिक उत्पादन में काफी बड़ी रूकावट पैदा की । इस रोग के दूसरे साथी, माँग की कमी, कारखानों की बन्दी, बेरोजगारी, तथा अतः में श्रमिक आन्दोलन व हड़ताल भी नकशों में आये । किसानों के बढ़ते हुए असतोष में महाबलशाली औद्योगिक मजदूर वर्ग के सम्मिलित हो जाने से, बिगड़ती हुई राजनैतिक स्थिति और भी अस्थिर हो गई । इस मन्दी की अस्थिरता काफी समय तक चली । अन्त में 1891 का भयंकर अकाल आया ।

1890 से ही पूँजीवादी औद्योगीकरण ने अपने पूरे जोर से प्रगति आरम्भ किया । इसका क्रम इतना तेज था कि औद्योगिक पूँजी तथा बड़े कारखानों की दृष्टि से रूस जर्मनी के भी आगे निकल गया ।

उद्योगों में प्रतिशत वृद्धि—1887 से 1897<sup>1</sup>

	कम्पानिया की संख्या	उत्पादन का मूल्य	मजदूर संख्या
बुनाई उद्योग	56.3%	104.4%	60.9%
खनिज उत्पादन	28.5	152.4	39.2
धातु निर्माण	75.2	175.8	107.8
रसायन उद्योग	30.8	177.2	67.3
समी वर्ग के उद्योग	26.0	113.0	59.0

इस प्रभावशाली उन्नति की दिशा वास्तव में पूँजीवादी ढाँचे को अपना चुकी थी । तेजी से बढ़ते हुए उत्पादन के साथ, उत्पादन की इकाई भी बढ़ने लगी । छोटे उत्पादन केन्द्र प्रतिस्पर्धा में गिरते गये । प्रोफेसर लाइशेन्को के अनुसार 1879-1902 के बीच 1000 से अधिक मजदूर रखने वाले कारखानों की संख्या में 123% तथा मजदूरों की संख्या में 141.4% वृद्धि हुई ।<sup>2</sup>

पूँजी के क्षेत्र में भी उन्नति हुई । 1889 में 504 संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी थी जिसमें 911.8 मिलियन रूबल की पूँजी लगी थी । 1899 में कम्पनियों की संख्या 1181 तथा पूँजी 1,736.8 मिलियन हो गई । इस समय के बीच विदेशी पूँजी का

<sup>1</sup> Adapted from Lyashchenko. Op. Cit., p. 527

<sup>2</sup> Ibid., p. 531

प्रभुत्व अर्थ-व्यवस्था के प्रायः सभी क्षेत्रों में पहुँच चुका था क्योंकि इन दस वर्षों में विदेशी पूँजी औद्योगिक पूँजी के  $\frac{1}{3}$  से बढ़कर  $\frac{1}{2}$  हो गई थी।

1900 तक रूसी उद्योग अत्यन्त तीव्र गति से उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था। पश्चिम यूरोप के औद्योगिक देशों के साथ पूँजीवादी उत्पादन के पूर्ण विकसित न होने पर भी औद्योगिक मन्दी का असर देश को उठाना पड़ा। 1900-1903 के बीच सारे यूरोप में भयंकर संकट [Crisis] आया जिसने रूसी सगठन से पुरानी अर्थ-व्यवस्था के अवशेषों को उखाड़ फेंका। इस संकट के उथल-पुथल में पूँजीवाद का दूसरा चरण आरम्भ हुआ। जिसमें एकाधिकार की शक्ति ने उद्योगों को अपने पजों में ले लिया। संकट की अवस्था में आर्थिक दृष्टि से कमजोर, यंत्रकुशलता में पिछड़ी हुई एवं कुप्रबन्ध से पीड़ित, उत्पादन इकाइयों नष्ट हो गई अथवा इतनी कमजोर हो गई कि उन्हें बड़ी इकाइयों ने अपने प्रभुत्व में कर लिया। इस समय के बाद से औद्योगिक रूस का इतिहास एक तरह से एकाधिकार तथा पूँजी के विस्तार का इतिहास है। प्रायः हर एक उद्योग में सिडिकेट के रूप में संयुक्तिकरण [Combination] शुरू हुआ। यहाँ तक कि प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक लोहा और स्पात, कोयला, पेट्रोल, हलके उद्योग, यातायात तथा बैंकों में आपसी समझौते और सिडिकेट द्वारा शक्तिशाली एकाधिकारों की स्थापना हो चुकी थी। अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप की तरह रूस में एकाधिकार का उच्चतम रूप, अर्थात् ट्रस्ट, सामने नहीं आया था। सिडिकेट केवल बाजार, मूल्य, माँग तथा यातायात को ही प्रभावित करते थे, जबकि ट्रस्ट उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र को भी अपने कठोर अनुशासन तथा संचालन में रखते थे।

1900-1903 का संकट, 1905 का विप्लव, जापान से युद्ध तथा इन कारणों से 1908 तक की मन्दी ने कम्पनी निर्माण तथा औद्योगिक पूँजी पर बहुत बुरा असर डाला। किन्तु 1910 से 1913 तक की प्रगति बहुत तेज थी।

#### औद्योगिक कम्पनियाँ<sup>1</sup>

वर्ष	संख्या	पूँजी—मिलियन रबल
1899	325	363.7
1909	131	108.8
1910	198	224.3
1913	372	545.2

<sup>1</sup> Lyashchenko, Op. Cit., p. 713

इन आकड़ों में विदेशी पूँजी का हाथ काफी था। 1916-17 तक निम्नलिखित स्थिति पाई जाती थी।

कुल औद्योगिक पूँजी में विदेशी पूँजी का प्रतिशत भाग<sup>1</sup>

उद्योग	विदेशी पूँजी
खान	90%
धातु निर्माण	42
कपड़ा	28
रसायन	50

इस प्रकार फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी तथा बेल्जियम ने आपस में मिलकर विदेशी पूँजी का लगभग 90% रूसी उद्योग में लगाया। इस विषय में प्रो० लाइशेको द्वारा निकाले हुये निष्कर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।<sup>2</sup>

[1] विदेशी पूँजी विनियोग (Investment) की वृद्धि देशी विनियोग से अधिक थी।

[2] केवल मात्रा में रूसी पूँजी विदेशी पूँजी से अधिक थी। अगर यह प्रवृत्ति चलती रहती तो शायद 10 वर्ष के अन्दर रूस भी शक्तिशाली पूँजीवादी देशों द्वारा एक उपनिवेश में परिणित कर दिया जाता।

रूसी उद्योग का उत्पादन बराबर प्रगति की ओर बढ़ता गया। उत्पादन तथा मजदूरों की संख्या ने विशेष उन्नति की। 1887-1908 के बीच उत्पादन 1,334.5 से बढ़कर 4,908.7 मिलियन रूबल हो गया। इसी प्रकार मजदूरों की संख्या भी 13,18,000 से बढ़कर 26,79,700 हो गई। 1913-14 तक प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्पादन लगभग दूना हो गया। इस समय प्रगति की गति अत्यधिक तीव्र थी। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि देश को समृद्धिशाली बनाने में बिना साम्यवाद के भी काफी जल्दी सफलता मिल जाती।

<sup>1</sup> Ibid. p. 716

<sup>2</sup> Ibid p. 717

## अध्याय ६

### राज्य क्रान्ति

[The Revolution]

#### क्रान्ति के समय आर्थिक स्थिति

बोलशेविक शासन की समुचित विवेचना के लिये क्रान्ति के समय देश की आर्थिक अवस्था का विशेष अध्ययन आवश्यक है। इस समय तक अर्थशास्त्र ने राजनीति पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि 1917 में क्रान्ति का मुख्य कारण आर्थिक ही कहा जा सकता है। 1917 तक के उद्योग, कृषि तथा राजनीति का क्रमिक विकास हम देख चुके हैं। इस स्थान पर आर्थिक स्थिति की उन विशेष धाराओं पर दृष्टिपात करना होगा जिन्होंने मुख्य रूप से क्रान्ति के सफल संपादन के लिये वातावरण तैयार किया।

#### प्रथम विश्व युद्ध

1914 के युद्ध ने बिगड़ी हुई आर्थिक दशा को और भी बिगाड़ने में मदद किया। रूस के हाथों से औद्योगिक पोलैंड, बाल्टिक प्रान्त, कृषि प्रधान यूक्रेन प्रदेश, बाल्टिक सागर तथा काला सागर के बंदरगाह भी चले गये। विदेशों से संपर्क रखने के लिये या तो हजारों मील लम्बी सुस्त साइबेरियन रेलवे थी, अथवा उससे भी कम लाभदायक आर्कटिक सागर के बंदरगाह थे जिनका प्रयोग साल के चढ़ महीनों तक ही हो सकता था। विदेशी व्यापार, मशीन, पूँजी तथा कारीगरों के ऊपर निर्भर रूस इस युद्ध में अपनी अर्थ-व्यवस्था का पंगु बना बैठा। युद्ध का भार उठाने के लिये उस समय देश एकदम तैयार न था। राजनैतिक अराजकता तथा आर्थिक दुर्बलता के समक्ष युद्ध एक भयंकर भूल थी। लगभग 140 लाख व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया गया जिनपर प्रायः 240 लाख खुरल रोजाना खर्च होता था। इसके साथ काफी पिछड़ी हुई उत्पादन व्यवस्था को शान्ति से युद्धकालीन उत्पादन संगठन में परिवर्तित करना अपार बुद्धि, अदम्य उत्साह एवं असाधारण प्रबंध कौशल का काम था। यह काम व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त, देश की उच्चतम शासन सस्था, जार की शाही-समिति [Imperial Council] के योग्यता के बाहर था। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि 1917 में जब आर्थिक हड़तालों ने विद्रोह का रूप धारण करना आरम्भ किया तो उनके नेताओं

को आर्थिक संगठन के हर एक हिस्से में जनता के असतोष को बढ़ाने के लिये यथेष्ट साधन मिला।

### वित्त-व्यवस्था

क्रान्ति के आरम्भ में देश की वित्तीय व्यवस्था [Financial System] काफी ढाँवाडोल हो चुकी थी। युद्ध के व्यय ने पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को प्रायः खोखला बना दिया था। 1905 की क्रान्ति के बाद शराब बनाने तथा प्रयोग करने पर पूर्ण निषेध लगा। 1915 में इस सुधार से सरकार को 7918 मिलियन रूबल की हानि हुई। आय का यह साधन राज्य की कुल आय का लगभग 20% होता था। अधिक आय की खोज में प्रगतिशील आयकर लगाने के बजाय अप्रत्यक्ष करों का सहारा लिया गया। इसकी असाधारण वृद्धि ने जनता को और विपत्तिग्रस्त कर दिया। अस्थायी सरकार की कुछ वास्तविक वित्तसुधार योजनाओं को 1916 की अस्थिर परिस्थितियों ने कार्यान्वित न होने दिया। 1917 तक क्रान्तिकारी प्रचारों के कारण जनता ने करीब-करीब सभी सरकारी कर देना बंद कर दिया।

युद्ध के लिये धन की आवश्यकता ने राज्य को नोट छापने के लिये बाध्य किया। जिससे रूबल का मूल्य 1915 के बाद तेजी से गिरने लगा। फरवरी 1917 के बाद तो यह दृष्टा हो गयी कि प्रतिदिन 750 लाख रूबल नये नोटों की आवश्यकता थी और सरकार का छपाखाना कुल 300 लाख रूबल के नोट प्रतिदिन छाप सकता था। क्रान्ति के चन्द महीनों बाद मुद्रा-मूल्य का विघटन 25% से अधिक हो गया। मुद्रास्फीति के साथ अनाज की कमी और नागरिक उपभोग के औद्योगिक सामान को सेना की तरफ खिंच जाने से चीजों का दाम ऊपर उठने लगा।

	चलन में नोट [करोड़ रूबल]		मूल्यांक
जुलाई 1, 1914 ..	163.0	...	100
जनवरी 1, 1915 ..	294.6	...	115
जनवरी 1, 1916 ..	561.7	...	238
जनवरी 1, 1917 ..	910.3	...	702
अक्टूबर 1, 1917 ...	1717.5	...	1,171

मुद्रास्फीति के तरह ही 1914-1915 के बीच देशी तथा विदेशी साधनों से 550 लाख रूबल उधार लिया गया। जुलाई 1917 तक देश पर 4391 लाख रूबल का कर्ज लद चुका था। व्यापारिक बैंक इस दिशा में गतिशील हुए। जनवरी 1915-

1917 के बीच इनकी जमा पूँजी 277 लाख से बढ़कर 674 लाख रुबल हो गयी। हर प्रकार के उधार में करीब 100% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का बहुत बड़ा भाग सरकार की मदद में लगा। 1914-17 के युद्ध काल में पश्चिमी यूरोप के देशों से रूस ने करीब 850 करोड़ रुबल उधार लिया। युद्ध के पहले दो सालों में विदेशी पूँजी में कुछ कमी हुई जबकि इनका भाग कुल पूँजी का 40.5% [1913] से घटकर 35.9% [1916] हो गया था। इन विदेशी ऋणों का प्रभाव यह पड़ा कि क्रान्ति के समय तक वित्त-व्यवस्था विदेशों पर आश्रित हो गई।

### उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र में भी 1914 के युद्ध के कारण भयंकर गिरावट हुई। विदेशी सम्पर्क टूट जाने से मुख्यतः निर्यात के लिये निर्मित रूसी उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। विदेशी बाजार की जगह देशी बाजार पर निर्भर रहना पड़ा जिसकी मुख्य माँग युद्ध के सामानों की सरकारी आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति उद्योगों को पुनर्व्यवस्थित करने पर निर्भर थी। कुप्रबन्ध, अदूरदर्शिता एवं कोयले की कमी ने यह परिवर्तन संभव नहीं होने दिया। देश के कमजोर उद्योग नई परिस्थितियों में एकदम बिलख न जाँय, इसलिये उद्योगपतियों ने इनके युद्धकालीन सङ्गठन के प्रश्न को राष्ट्रियता की भावना से जोड़ने की कोशिश की। किन्तु राज्य की ओर से उन्हीं उद्योगपतियों को सहायता न मिली जिनके सहारे पर जारशाही खड़ी थी। फिर भी यह प्रयास विफल न रहा। प्रत्येक उद्योगों में उत्पादन समितियों का निर्माण हुआ और घरेलू उद्योगों को भी इस कार्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस दिशा में स्थिति इस प्रकार थी<sup>1</sup>—

वर्ष	कारखानों की संख्या	कुल उत्पादन [मिलियन रुबल]	मजदूरों की संख्या
1913	13,485	5,621	1,927
1914	13,858	5,690	1,926
1915	12,649	6,390	1,899
1916	12,492	6,831	2,094

उत्पादन की 21% वृद्धि अवश्य हुई लेकिन युद्ध के विशाल सङ्गठन के लिये

<sup>1</sup> Lyashchenko, Op Cit, p. 761



यह एकदम अपर्याप्त थी। मुद्रा में नापे गये इस उत्पादन का महत्व प्रायः कुछ भी नहीं रहता जब यह देखा जाय कि रूबल का मूल्य 1916 तक 25% से अधिक घट चुका था। लोहा, कोयला, लोहे के सामान तथा पेट्रोल उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरा उल्लेखनीय क्रम कारखानों की संख्या में था। गिरती हुई कारखाना संख्या के साथ बढ़ता उत्पादन, मजदूरों की संख्या तथा पूँजी का स्पष्ट इशारा बड़े उद्योगों के आकार में वृद्धि तथा एकाधिकारी उत्पादन [ monopoly ] की ओर है। बिना किसी योजना के बहुत बड़ी मात्रा में कुशल कारीगरों, प्रबन्धकों, और दूसरे अनुभवी व्यक्तियों को सेना में भर्ती होने के लिये बाध्य किया गया। इस नीति ने युद्ध उत्पादन पर जो कुठाराघात किया, उसका प्रभाव दूर न किया जा सका। मजदूरों में असन्तोष फैला और देश की सहायता भी न हो सकी। उद्योगपतियों के उत्साह और परिश्रम के कारण 1916 के मध्य से 1917 के आरम्भ तक उत्पादन में वृद्धि दिखलाई पड़ी। उद्योग के हर एक अङ्ग में उन्नति आरम्भ हुई। नई कम्पनियाँ तेजी के साथ खुलीं। अधिकतर इनको किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिये राजकीय आर्थिक सहायक अथवा एकाधिकार प्राप्त था। 1913-16 के बीच उद्योग में लगी पूँजी 52.6 करोड़ से बढ़कर 92.35 करोड़ रूबल हो गयी। बैंकों ने अपना प्रभुत्व उद्योग-धन्यों पर बढ़ाया। औद्योगिक लाभ में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। 791 कम्पनियाँ [ कुल कम्पनियों का दो-तिहाई ] के आँकड़ों के अनुसार 1913-15 के बीच इनका लाभ [ Gross profit ] 35.17 करोड़ से 69.2 करोड़ रूबल हो गया। बँटे हुये लाभांश [ dividends ] की मात्रा 15.53 करोड़ रूबल से बढ़कर 21.63 करोड़ रूबल हो गयी। कुछ उद्योगों ने तो अपनी पूँजी का 150 से 250% तक लाभांश बाँटा। 1916 में निकोलस द्वितीय के सिंहासन छोड़ने के बाद हालांते एकदम बदल गई। अस्थायी सरकार के राज्यकाल से क्रान्ति तक कोयले की भयङ्कर कमी, कच्चा माल न मिलना, व्यापक हड़ताले तथा अराजकता ने विश्वास और उन्नति को नष्ट कर दिया। पुराने ढाँचे पर सङ्गठित यह उद्योग पूँजीवाद के नष्ट होते ही अपनी प्रगति खो बैठे। 1917 में बोल्शेविक सरकार को विरासत में पुराने वैभव तथा उन्नति का केवल खंडहर मिला।

### कृषि

रूस के अर्थव्यवस्था में, तमाम औद्योगिक विकास होने पर भी, कृषि का प्रमुख स्थान क्रान्ति के समय और उसके बाद भी कुछ दिन तक पूर्ववत् बना रहा। सबसे अधिक जनता इस क्षेत्र में व्यस्त होने के साथ-साथ रूसी कृषि को कमी भी यथोचित ध्यान नहीं मिला। राजतन्त्र के समय में कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता न समझी गई। अस्थायी सरकार ने प्रो० मिल्यूकोव के निर्देशन में प्रथम प्रयास किया। इसके द्वारा राजकीय भूमि उस पर काम करनेवाले किसानों में बाँटने का विचार था।

सरकार ने यह तो मान लिया कि व्यक्तिगत किसानों को भूस्वामित्व मिलना चाहिये किन्तु मुआवजे के बारे में कुछ निश्चय न कर सकी। क्रान्तिकारी केरेन्सकी ने बिना मुआवजे के सारी भूमि किसानों में बाँटने का निश्चय किया। बुनियादी तौर पर इसमें, और आगे आने वाली लेनिन की कृषि-योजना में कोई अन्तर न था। इसके असफल होने का कारण इन योजनाओं में न होकर परिस्थितियों में मिलता है। जार के गद्दी छोड़ने ही आक्रान्त किसानों ने अपने को स्वतन्त्र समझना शुरू कर दिया। भूमि प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वैधानिक रीति से स्वामित्व प्राप्त करने की प्रतीक्षा वे न कर सके। लेनिन के आने के पहले तक बलप्रयोग द्वारा अधिकतर भूमि किसानों ने छीन ली थी। “सारी जमीन किसानों को” [All land to the peasants] का बोल्शेविक नारा यथार्थ को वैधानिक बनाने का अकेला तरीका था।

प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ होने के बाद से ही रूसी कृषि का पतन होने लगा। 1917 तक कृषि-क्षेत्र से एक-तिहाई से आधे तक श्रमिक सेना में भर्ती किये जा चुके थे। इसका सबसे बड़ा प्रभाव कृषि उत्पादन में अवन्नति थी। उत्पादन के गिरने का उत्तरदायित्व और भी कई बातों पर था। अर्थव्यवस्था में विदेशियों का प्रभाव होने से उद्योग एवं कृषि का सतुलित विकास न हुआ। बड़े खेतों पर मशीनों का प्रयोग इतना कार्फा बढ़ चुका था, फिर भी इन मशीनों के बनाने की देश में कोई व्यवस्था न की गई। युद्ध में उनका आयात रुक जाने से उत्पादन का गिरना स्वाभाविक था। यही दशा रसायनिक खाद तथा उच्च कोटि के बीजों की भी हुई। सेना ने किसान का मुख्य पशु [घोड़ा] विशाल संख्या में जब्त कर लिया। जर्मन सेना के साथ रूसी सेना को भी जब भोजन की कमी अनुभव हो तो आसपास के गाँवों के पशु प्रयोग में लाये जाते थे। 1917 तक मुख्य अन्न का क्षेत्रफल 780 लाख हेक्तायर हो गया जबकि 1914 में यह क्षेत्रफल 886 लाख था। अनाज तथा आलू की उपज 690 करोड़ पौंड [1914] से घटकर 500 करोड़ पौंड हो गई।

युद्ध, अराजकता तथा शासन प्रबन्ध की खराबी से भोजन की कमी धीरे-धीरे बढ़कर 1917 तक अकाल का रूप धारण कर चुकी थी। रूस को यूरोप का अन्न भंडार कहा जाता था। 1913 में रूस ने 64.8 करोड़ पौंड अन्न यूरोप को बेचा। युद्ध के कारण अन्न का निर्यात 1916 में कुल 27 लाख पौंड हुआ। इतने अन्न के बच जाने से अभाव का अनुभव नहीं होना चाहिये था। सेना की माँग तथा यातायात की कमजोरी से वितरण की दिशा और मात्रा दोनों एकदम बदल गये। अच्छा यह था कि कटाई के बाद ही युद्ध छिड़ गया। इससे 1914 की पूरी फसल निर्यात होने से बच गई। 1915 से मुद्रास्फीति तथा उत्पादन में कमी ने अनाज का अभाव पैदा कर दिया। अभाव को संकट में बदलने का शासन-प्रबन्ध ही जिम्मेदार था। पश्चिमी रूस के युद्ध स्थलों

से भागे हुए लाखों शरणार्थियों के पुनर्निर्वास का कोई केन्द्रीय संचालन न था। इससे अन्न की उपलब्धि देखते हुए उनको अलग-अलग क्षेत्रों में नहीं भेजा गया। किसानों से अनाज खरीदने और इस खरीद का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार अलग-अलग जिलों के अधिकारियों को दिया गया था। केन्द्रीय निर्देशन न होने से पड़ोसी जिलों में एक ही वस्तु का अलग दाम निश्चित हुआ। किसान अपनी उपज अपने जिले में ही न बेचकर आस-पास के क्षेत्रों में बेचते थे जहाँ पर मूल्य अधिक निर्धारित किया गया हो। सेना अपनी आवश्यकता का अनाज खुले बाजार से भी खरीदती थी। उपज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये नागरिक अधिकारियों द्वारा निश्चित मूल्य से अधिक सेना के अधिकारी देते थे। अनुशासनहीनता को यह खुला निमंत्रण था। इन सबके परिणामस्वरूप 1917 के आरम्भ में बाजार से अनाज, मांस, चीनी, मक्खन आड़े प्रायः गायब हो चुके थे। चोरबाजार और सट्टेबाजों ने अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। ऐसे समय में सरकार ने बड़े शहरों में राशनिक शुरू किया। अव्यवस्थित एवं अस्थिर परिस्थितियों में इस भूल ने विपम उलझने पैदा की। यह कहा जाता है कि राजतन्त्र के उन्मूलन का एक मात्र तात्कालिक कारण अन्नसंकट था।

### श्रमिक :

आर्थिक सङ्गठन के उपरोक्त पृष्ठभूमि से सरलता के साथ यह विदित होता है कि किसानों के साथ-साथ श्रमिकों की दशा भी अत्यन्त शोचनीय थी। उद्योगों में होने वाली प्रगति तथा लाभ के साक्षीदार यह श्रमिक न बने। जो कुछ उनके वेतन में वृद्धि हुई थी, वह चीजों के बढ़े हुए मूल्य ने खा डाला। युद्धकालीन असाधारण माँग और औद्योगिक प्रगति के बीच देश की अविकसित अर्थ-व्यवस्था दीवार बन कर खड़ी हो गई। अत्यन्त लाभदायक अधिक उत्पादन की आवश्यकता के साथ-साथ देश के मजदूरों में विलुप्त रूप में बेकारी फैली। इसकी वजह मशीनों तथा कुशल कारीगरों के विदेशों से आने में कठिनाई थी। नागरिक उपभोग के उद्योग बड़ी मात्रा में बन्द हुए, जिससे बेकारी को और सहारा मिला। अन्न की भयंकर कमी ने इन बेरोजगार मजदूरों को क्रान्ति के लिये लाचार किया। कारखाना मजदूर आरम्भ से ही क्रान्तिकारी दलों के प्रचार का केन्द्र रहा है। इनमें से जब मजदूरों को 'मेना' में भेजा गया तो वहाँ पर सैनिकों में क्रान्ति की भावना जागृत करने का काम इन्होंने बड़ी सफलता से किया। राजनैतिक दलों ने मजदूरों को समझाया कि भोजन और काम उनको माँगने से नहीं मिल सकता। इसे लड़कर प्राप्त करना होगा। 1915 से ही पैट्रोग्राड में अन्न के लिये दंगा होना शुरू हो गया था। अपने असंतोष को प्रभावशाली बनाने के लिये बड़ी-बड़ी हड़ताले हुईं, जो किसी भी प्रकार से शान्तिपूर्ण नहीं कही जा सकती। जब इन हड़तालियों को दबाने के

लिये भेजी गयी सेनाओं ने उनका साथ देना शुरू किया तब से आर्थिक हड़तालें राज्य-क्रान्ति में बदल गयीं ।

### राज्य-क्रान्ति :

रूस की यह विशेषता रही है कि देश ने प्रत्येक युद्ध के बाद अपना कलेवर बदला अथवा बदलने का प्रयत्न किया था । क्रीमिया में युद्ध का प्रभाव दास मुक्ति; रूसी-जापानी युद्ध का प्रभाव 1905 की क्रान्ति एवं प्रजातन्त्र शासन में प्रयोग, तथा 1914 के युद्ध के परिणामस्वरूप 1917 की राज्य-क्रान्ति हुई । प्रत्येक युद्ध अथवा अराजकता के बाद जनता यह आशा करती है कि जो नई सरकार या व्यवस्था बनी, इसके द्वारा सभी काट दूर हो जायेंगे । इसी आस्था का सहारा लेकर देश की प्रगति नवीन दिशा में होती रही है । लेनिन के अनुसार किसी भी देश में क्रान्ति के लिये चार बातें जरूरी हैं—प्रथम, अधिकांश जनता अत्यन्त असंतुष्ट हो, और जीवन असहनीय हो चुका हो । द्वितीय, जनता शासकों में श्रद्धा एवं विश्वास खो चुकी हो । तृतीय, शासक में आत्म-विश्वास न हो । चतुर्थ, शासक का सब से शक्तिशाली अस्त्र, सेना तथा पुलिस, प्रभावहीन हो जाय । 1917 में यह सभी हालते उत्पन्न हो चुकी थी ।

इस क्रान्ति के बीज 1861 में बोये गये जब कि दास-मुक्ति का नाटक रचकर जार ने असंतुष्ट किसानों को धोखे से भूस्वामियों तथा पूँजीपतियों के हाथ में ही बने रहने दिया । जिस व्यापक तथा गंभीर शोषण को इन सुधारों ने सम्भव बनाया, उसका प्रभाव अत्यन्त विपत्ति पड़ा । 1905 की क्रान्ति इस असंतोष का प्रथम विस्फोट थी । इससे बाध्य होकर 1906 में पहली प्रतिनिधि सभा [ड्यूमा] बनी । यह अन्तिम अवसर था जब कि जार बदले हुये जमाने के साथ अपना सन्तुलन स्थापित कर सकता था । दुर्भाग्यवश, आइवन, पीटर तथा कैथरीन का वंशज निकोलस द्वितीय अत्यन्त कमजोर इच्छा-शक्ति वाला व्यक्ति था जिसमें चालाकी, दूरदर्शिता, साहस तथा कूटनीति का लेशमात्र भी न था । सद्भावना का अपार भंडार लिये हुए यह दुर्बल शासक, रोमानोव वंश के तमाम भूलों तथा अत्याचारों का भार ढोने में असमर्थ सिद्ध हुआ । अपनी महत्वाकांक्षिणी पत्नी सम्राज्ञी एलेक्जान्द्रा के पूर्ण प्रभाव ने जार को केवल नाम मात्र का शासक बना रखा था ।

1905 से 1917 तक के शासन में जनता के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को आंशिक रूप में पूरा किया गया । देश के कुछ बहुत योग्य व्यक्ति इस उदार शासन के प्रयोग में सम्बन्धित थे जैसे प्रिंस लवोव, प्रोफेसर मिल्यूकोव तथा केरेन्सकी । इनके सफल न होने का मुख्य कारण था कि वे परिस्थिति का उचित विश्लेषण न कर सके । इनका प्रयास जार की शक्ति को बनाये रखना था । भूस्वामियों तथा पूँजीपतियों के प्रभाव इन

पर स्पष्ट थे। जनता के असंतोष को दूर करने का, उनके विचार से, राजनैतिक सुधार ही एक मात्र उपाय था। किन्तु एक पिछड़े हुए गरीब देश की अशिक्षित जनता शासन-पद्धति तथा राजनैतिक स्वतंत्रता की तरफ विशेष रुचि नहीं रखती। सचमुच देखा जाय तो जनता शान्ति, भूमि एवं रोटी चाहती थी। रूस-जापान के युद्ध का प्रभाव अभी दूर न हो पाया था कि 1914 की लड़ाई छिड़ गई। पोलैंड, यूक्रेन तथा बालकन प्रदेश के निकल जाने से देश की आर्थिक व्यवस्था और भी बिगड़ी। युद्ध का खर्चा तथा रूसी सैनिकों की मृत्यु ने जनता को किसी भी मूल्य पर शान्ति प्राप्त करने का इच्छुक बना दिया। हथियारों की कमी, उद्योग तथा कृषि में लगे एक-तिहाई पुरुषों का युद्ध पर जाना, मुद्रा-स्थिति तथा गिरे हुए उत्पादन के कारण महँगाई, मजदूरों की कमी, सेना की खपत के कारण अप्राप्य अनाज, कोयले की कमी, हडताल तथा यातायात के टूटने से कारखानों की बन्दी और अन्त में बेरोजगारी ने विप्लव की सभी अवस्थाओं को उत्पन्न कर दिया। 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी और उनके भाई ने परिस्थिति देखते हुए जार बनना अस्वीकार कर दिया। एक अस्थायी सरकार बनाई गई परन्तु उस समय तक हालते इतनी बिगड़ चुकी थी कि क्रान्तिकारी केरेन्सकी की सरकार भी स्थिति को सम्भाल न सकी।

१

अप्रैल 1917 में लेनिन अपने मुख्य सहयोगियों के साथ 11 वर्ष पश्चात् रूस वापस आया। उसने आते ही अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, असाधारण प्रतिभा, विस्तृत ज्ञान एवं अनुभव से सेन्टपीटर्सबर्ग [पिट्रोग्राड] में अस्थायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का भंडा गाड़ा। यह कहा जा सकता है कि लेनिन ने क्रान्ति करायी नहीं, केवल एक सफल क्रान्ति का निर्देशन अपने हाथों में ले लिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि मार्च 1917 में आरम्भ हुई क्रान्ति के पैदा करने में तथा सफल बनाने में बोलशेविक पार्टी का मुश्किल से ही हाथ रहा होगा। इस दल में कुछ हजार व्यक्ति थे और इसके बारे में जनता बहुत कम जानती थी, किन्तु जब जार के हटने के बाद जनता में विश्वास-पात्र नेता न होने से क्रान्ति के अपने आप असफल होने का अन्देश था; लेनिन ने आकर “रोटी-शान्ति-भूमि” तथा “सोवियत सर्व-शक्तिमान है” का नारा लगाया। अक्टूबर 1917 [नये कलेंडर के अनुसार नवम्बर 1917] में लेनिन और उसके साथियों ने केरेन्सकी को हटाकर देश का शासन बोलशेविक पार्टी के हाथ में ला दिया।

इस प्रकार निकोलस के सर से गिरे हुए रूसी ताज को जब कोई भी संभालने को सामने न आया तो लौह-पुरुष लेनिन ने आगे बढ़ कर उसे उठा लिया। सारांश में, रोमानोव वंश का अन्त किसी के द्वारा नहीं हुआ; ड्यूमा ने इसके अधिकार नहीं छीने; लेनिन उस समय स्विट्जरलैण्ड में था; ट्रास्की न्यूयार्क में; तथा बोलशेविक पार्टी के दूसरे सदस्य सोवियत में प्रभावहीन अल्पसंख्यक [Minority] थे। जब यह लोग नकशे में

आये उस समय अनुशासनहीन पागल भीड़, भागे हुए सैनिकों के साथ मिलकर, क्रान्ति का प्रथम चरण पूरा कर चुकी थी। जारशाही का अन्त अपनी ही अयोग्यता से हुआ और तात्कालिक कारण सम्राज्ञी अलेक्जेंड्रोवा तथा धूर्त रासपुतीन का अविवेकपूर्ण पक्षपात एवं अप्रिय हस्तक्षेप था।

क्रान्ति हुई और संसार में नये सिद्धान्तों पर आधारित समाज का निर्माण हुआ। कितना महान् आश्चर्य है कि इतना बड़ा परिवर्तन होने पर भी देश के सगठन की मौलिक रूप-रेखा न बदली; शक्ति का अधिकतम केन्द्रीयकरण, अत्यन्त विस्तृत राजकीय अफसरवाद [Massive bureaucracy], सेना पर अत्यधिक निर्भरता, कठोरतम बल प्रयोग, गुप्तचरों का जाल तथा नेताओं की देवता के समान पूजा-पूर्ववत् बनी रही।

राजनैतिक दृष्टि से इस क्रान्ति द्वारा राज्य-शक्ति कट्टरपथियों के हाथ से निकल कर क्रान्तिकारियों के हाथ में चली गई। इस क्षेत्र में लेनिन की नीति के दोनों अंग जनता को अत्यन्त आकर्षक मालूम पड़े। प्रथम थी शान्ति—जिसको पाने के लिये लेनिन ने यूक्रेन तथा पोलैण्ड के रूप में बड़ी ऊँची कीमत चुका कर ब्रेस्त लीतोवस्क की सन्धि दिसम्बर 1917 में कर ली। द्वितीय थी—सोवियत सगठन की स्थापना। सोवियत अर्थात् श्रमिकों के प्रतिनिधियों की समिति का निर्माण 1905 के क्रान्ति में हुआ था। 1917 के क्रान्ति के आरम्भ में पेट्रोग्राड में इन सोवियतों ने मिलकर रूसी सरकार के समानान्तर एक दूसरी सरकार स्थापित कर ली। मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित यह सरकार शासन-शक्ति से वंचित जनता को वरदान-सा लगा। जून 1917 में अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन बुलाया गया जिसको बोल्शेविक नेताओं ने अपने योग्य हाथों में एक प्रभावशाली शक्ति बना लिया। प्रजातन्त्रात्मक बुनियाद पर निर्मित यह सोवियत सस्था का विकास केवल क्षणिक था। लक्ष्यप्राप्ति के बाद वास्तविक राज्य-सत्ता चुने हुए बोल्शेविक नेताओं में केन्द्रित हुई। आज भी इन सोवियत का अर्थहीन तथा खोखला ढाँचा खड़ा है। देश का सरकारी नाम भी समाजवादी गणतन्त्र सोवियत संघ [Union of Soviet Socialist Republics—U. S. S. R.] है।

आर्थिक क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी मॉँग, भूमि, को भी लेनिन ने बिना समय नष्ट किये पूरा कर दिया। फरवरी 1918 की राजाज्ञा द्वारा भू-स्वामियों की सारी भूमि बिना किसी मुआवजे के किसानों में बाँट दी गई। हर किसान को इतनी भूमि प्राप्त करने का अधिकार मिला जिस पर वह सफलता से खेती कर सकता हो। शताब्दियों से चला आ रहा अभिशाप [भू-स्वामी] नष्ट हो गया। वैतनिक श्रम वर्जित कर दिया गया क्योंकि दूसरों की मेहनत से लाभ उठाना शोषण माना जाता था। कारखाना मजदूरों का सहयोग लेनिन के दो नारों ने प्राप्त कर लिया—रोटी और मजदूरों द्वारा उद्योग संचालन। उत्पादन के सभी साधन राष्ट्रीय संपत्ति बन गये। जून 1918 में

राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ हर कारखाने का प्रबंध मजदूरों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया जो कि मजदूर संघ समिति [Trade Union Committee] के रूप में काम करते थे। इन्होंने पुराने प्रबंधकों को या तो एक दम हटा दिया, या उनसे केवल नाममात्र को सहायता लिया। पूँजीवादी 'लाम' का सिद्धान्त बिल्कुल उड़ा दिया गया।

### राज्य क्रान्ति का प्रभाव

रूसी क्रान्ति के तरह व्यापक विप्लव आर्थिक दृष्टि से कभी भी अच्छा नहीं होता। विनाश पर आधारित इसका कार्यक्रम निर्माण की सम्भावना ही समाप्त कर देता है। प्रथम चरण में जनता की अनुशासनहीनता तथा पशुता की प्रवृत्तियों को पूरी छूट मिलती है, जिससे उद्देश्यविहीन, निरर्थक विध्वंस आरंभ होता है। इसके बाद इन प्रवृत्तियों पर फिर से काबू पाने के लिये इनको संतुष्ट करने या दबाने का समय आता है। क्रान्ति के नेताओं का प्रभाव इसी समय सामने आता है। यदि यह सफल हुआ तब निर्माण का कार्य ध्यान आकर्षित करेगा। अन्यथा क्रान्ति में जागी हुई जनता विनाश को पहलू में लिये फिर सो जायगी।

रूसी क्रान्ति में भी यही क्रम विद्यमान था। 1917 में हुई क्रान्ति लगभग मार्च 1918 में पूरी हुई। इसका द्वितीय चरण इस समय से लेकर 1921 के आरम्भ तक चलता रहा। क्रान्ति के बाद जब देश की बागडोर बोल्शेविक सरकार ने सम्भाला तो देशी तथा विदेशी परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए लेनिन ने आश्चर्यजनक क्षमता का परिचय दिया। आर्थिक अधोगति क्रान्ति के कुछ पहले से आरम्भ हो चुकी थी और क्रान्ति के बाद भी काफी देर तक चलती रही। मुद्रा-स्फीति को रोकने का कोई उपाय बोल्शेविक सरकार सामने न ला सकी और यह बढ़ती ही गयी। अक्टूबर 1917 के बाद देश की वित्त-व्यवस्था बराबर गिरती रही। आरम्भ में तो उद्योगपति तथा विदेशी पूँजीपति इसी विचार में थे कि ऐसे देश में जहाँ कि राजनैतिक स्थिति तेजी से बदलती हो, बोल्शेविक सरकार एक अस्थायी व्यवस्था ही रहेगी। लेकिन जर्मनी से सन्धि करने के बाद जब व्यापारिक वैकों का [ग्राहकों की पूँजी तथा संपत्ति के साथ] राष्ट्रीयकरण कर लिया गया [Dec 14, 1917] तब से पुराने अर्थशास्त्रियों एवं उद्योगपतियों का विश्वास नयी सरकार से उठने लगा। लगभग इसी समय तमाम प्राचीन सिद्धान्त एवं प्रथा की अवहेलना करके नयी सरकार ने अपनी निरंकुशता का परिचय दिया। अक्सो रुबल के देशी तथा विदेशी ऋण को रद्द कर दिया गया। इसने व्यापारिक तथा आर्थिक दृष्टि से रूस को एक अछूत बना दिया। एकदम पृथक्वाद में देश को खींचकर सारे ससार के विरुद्ध कुख्यात लौह-द्वार [Iron-curtain] बंद हो गया।

उद्योग में भी क्रान्ति के बाद अवनति होती गई। मजदूरों में अनुशासन की समाप्ति के साथ अनुभवी प्रबंधकों के हट जाने से, या प्रभावहीन हो जाने से, कारखानों की व्यवस्था अपना क्रम खो बैठी। अशिक्षित मजदूरों को क्रान्ति एवं स्वतंत्रता का अर्थ यह समझ में आया कि आगे से बिना काम किये सरकार उनकी सब जरूरतों को पूरा करेगी। यातायात एकदम छिन्न-भिन्न हो गया था। कोयला और पेट्रोल का उत्पादन, लोहा और ताँवे के साथ, इतना गिरा कि पूरे उत्पादन-क्षेत्र में भीषण कमी दिखलाई दी और कच्चा माल न मिलने के कारण कपड़ा तथा चीनी उद्योग उत्पादन बन्द करने पर बाध्य हुए।

लेनिन को सबसे बड़ी निराशा किसानों से मिली। समृद्धशाली किसानों के विरुद्ध गरीब किसानों ने उस तरह का विद्रोह नहीं किया जैसी कि लेनिन को आशा थी। क्रान्ति के उच्चादशों को किसान समझने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुआ। कठोरता एवं बल प्रयोग के अतिरिक्त, सेना तथा शहरों के लिये अनाज प्राप्त करने का दूसरा उपाय लेनिन के सामने नहीं था। इससे किसानों में और असंतोष फैला। उत्पादन कम होता गया, और रूस तेजी से 1920-21 के भीषण अकाल की ओर बढ़ा।

अतः यह तथ्य निकाला जा सकता है कि क्रान्ति की अव्यवस्थाएँ एवं अस्थिरता आर्थिक क्षेत्र में इतनी विस्तृत रही कि क्रान्ति के बाद कई साल तक गिरता हुआ उत्पादन, बेरोजगारी एवं मूल्य की वृद्धि के रूप में जनता को क्रान्ति का मूल्य चुकाना पड़ा।

### साम्यवादी क्रान्ति और रूस

इसमें कोई सन्देह नहीं कि क्रान्ति के प्रमुख कारण समकालीन आर्थिक स्थिति में मिलते हैं। किन्तु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्रान्ति सबसे पहले रूस में ही क्यों हुई? कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवादी क्रान्ति 'उस देश में सबसे पहले होनी चाहिये थी जहाँ औद्योगीकरण बहुत हो चुका हो; जहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक हो और जहाँ विकसित प्रजातंत्र पाया जाता हो। सौ वर्ष से भी अधिक पुराना यह कथन आज भी कुछ संशोधनों के साथ सत्य है। साम्यवाद, पूँजीवाद के विकसित रूप, साम्राज्यवाद [imperialism] की सबसे कमजोर कड़ी को तोड़कर अपना स्थान बनाता है। यह जरूरी नहीं है कि जिस देश में सबसे कमजोर कड़ी पाई जाय, वह उद्योग-प्रधान हो।<sup>1</sup> पिछड़े हुए खेतिहर देश में क्रान्ति हो सकती है। इस तरह भारत, चीन, मिश्र, टर्की, या रूस कहीं भी साम्यवाद का प्रवेश सम्भव था। रूस की साम्राज्यवादी सरकार

<sup>1</sup>J. Stalin Problems of Leninism, p 20



सबसे कमजोर सिद्ध हुई। इसके कई कारण थे: लगातार युद्ध से जान और धन की हानि, अफसरवाद और बेइमानी का असाध्य रोग, राजा-प्रजा के बीच आपसी सम्पर्क का एकदम अभाव तथा अविवेकपूर्ण, शक्तिहीन सम्राट। इनसे उत्पन्न शासन की दुर्बलता ने साम्यवाद का मार्ग निष्कटक बना दिया। अन्य देशों में यह दुर्बलता न होने से, प्रथम तो, क्रान्ति की स्थिति आ न सकी; और यदि आ भी जाती, तो उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता था।

रूस में मार्क्सवाद का आगमन साम्यवादी क्रान्ति से नहीं सामाजिक क्रान्ति के कारण हो सका। सामाजिक व्यवस्था के प्रति असन्तोष हर तरफ था। राज्यकर्मचारी, सेना और जनता सभी इससे व्याप्त थे। यह बात विशेषकर याद रखनी चाहिये कि जिन परिस्थितियों का साम्यवादी नेताओं ने लाभ उठाया, वह महँगी रोटी और घूसखोरी के विरुद्ध सामाजिक असंतोष की अभिव्यक्ति थी। क्रान्ति के आरम्भ और विकास के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि 1917 की क्रान्ति न तो जार के विरुद्ध थी, न शासन में प्रतिनिधित्व पाने के लिए थी। अगर शहरों में अनाज और गाँवों में उपभोग की वस्तुएँ उचित दाम में पहुँचाई जा सकती, तो विप्लवी प्रवृत्तियाँ अपने आप शान्त हो जाती। कम से कम राज्य क्रान्ति न होती। अन्य सरकारों ने सामाजिक असंतोष इतना बढ़ने ही नहीं दिया कि विस्फोट का डर पैदा हो।

मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार साम्यवादी क्रान्ति उसी समय होगी जब पूँजीवादी शोषण असह्य हो जायगा। यहाँ तक माना जाता है कि समाजवाद की स्थापना के लिए असह्य शोषण पैदा करने में पूँजीवाद को सहयोग देना चाहिये। रूस में पूँजीवादी शोषण तो असह्य नहीं था किन्तु जनता के दमन का विस्तार असीमित था। फिर इससे क्या अन्तर पड़ता है कि यह दमन पूँजीवाद की जगह जारशाही से पैदा हुआ हो? मार्क्स की बुनियादी आवश्यकता तो पूरी हो गई केवल उसके उद्गम में भिन्नता थी।

मार्क्स के अनुसार पूर्ण विकसित पूँजीवादी औद्योगिक देश में मजदूरों का शोषण सबसे अधिक होता है। इसी शोषण के कारण क्रान्ति का सहारा लेकर मजदूर समाजवादी समाज की रचना करता है। किन्तु समय के साथ मजदूरों के असंतोष की सीमा में बाँधे रहने के लिए पूँजीवाद में बहुत तरकीबें निकल आयीं [राजकीय नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि]। पूर्ण विकसित औद्योगिक देश में उद्योगपतियों के पास इतना धन संचय हो चुका रहता है कि वे बहुत त्याग के बिना अपने शोषण में कमी कर सकते हैं और मजदूरों को संतुष्ट रखने के उपाय अपना सकते हैं; लेकिन ऐसे देशों में जोकि पूँजीवाद में कुछ ही दूर गये हों, शोषण अपने सबसे विकराल रूप में होता है। नये उद्योगपति पूँजी संचय [Capital accumulation] में इतने लिप्त रहते हैं कि दूसरी और सभी

बाते अर्थहीन मालूम पड़ती है। इस प्रकार मार्क्सवाद के आगमन के लिए जिस शोषण की आवश्यकता होती है वह उस समय के रूस के अर्ध विकसित पूँजीवादी उद्योग में पूर्णतया वर्तमान थी।

अन्त में देश के सौभाग्य से उस समय अपूर्व साहस, बुद्धि तथा अवसरवादिता से परिपूर्ण नेता सामने आये। अपनी नीति तथा रूसी परम्परा में पूर्ण तारतम्य स्थापित करके इन्होंने जनता का सहयोग प्राप्त कर लिया। जनता ने साम्यवादी कार्यक्रम में करीब-करीब उतनी ही कठोरता, व्यक्तित्व का दमन, रक्त, स्वेद और अश्रु पाया जिससे सदियों की जारशाही में वे पूर्ण अभ्यस्त हो चुके थे। फिर भी वे इस ओर आकर्षित हुए क्योंकि पहली बार साम्यवादियों ने जनता को त्याग के बदले कुछ देने का वादा किया—जब इस वादे में जनता ने 'शान्ति, भूमि और रोटी' की प्राप्ति देखी, तो वे कुछ भी करने को तैयार हो गये।

## विदेशी हस्तक्षेप तथा युद्धकालीन साम्यवाद

[ Foreign Intervention and War Communism ]

### विदेशी-हस्तक्षेप

क्रान्ति के बाद साम्यवादियों को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा। इसके पहले कि इस टूटे हुए शासन-व्यवस्था की शृङ्खला फिर से जोड़ी जा सके, देश और विदेश में एक साथ नई सरकार को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र चालू हुआ। पराजित राज-नैतिक दलों ने पश्चिमी राष्ट्रों के साथ गठबंधन रचा। युद्ध अभी चल ही रहा था। जर्मनी के विरुद्ध पूर्वी मोर्चा बनाने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों ने असंतुष्ट रूसी दलों तथा व्यक्तियों को पूर्ण सहयोग दिया। इनकी मदद से प्रभावशाली व्यक्तियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लिया। दक्षिण में अग्रेजों ने कर्नीलोव [General Kornilov] को विद्रोह के लिए उसकाया। फ्रांस की निगाह क्रीमिया पर थी। शर्नोव [Chernov] ने वोल्गा नदी के नीचे की ओर दूसरी सरकार बनाई। अग्रेजों की मदद से साइबेरिया में एडमिरल कोलचक [Admiral Kolchak] ने विशाल प्रदेश दबा लिया और अपने को रूस का शासक घोषित किया। बैकाल झील के आस-पास कर्नल सेमिनोव [Colonel Semenov] और मंचूरिया में जनरल हारवट [General Horvat] ने जापानी सहायता से व्लाडीवोस्टोक को अपना केन्द्र बनाया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी कई हजार सैनिक षड्यंत्रकारियों की मदद के लिए साइबेरिया भेजा था। चेक [Czech] सैनिकों ने उस क्षेत्र में फैलकर बड़ी हानि पहुँचाई। इस तरह बोल्शेविक सरकार ने आरम्भ में देश के क्षेत्रफल का दो-तिहाई भाग खो दिया।

नवम्बर 1918 में जर्मनी ने हार मान ली। बोल्शेविक सरकार की आश्चर्यजनक लगन तथा बोरता देखकर तथा रूस के गृह-युद्ध में पश्चिमी राष्ट्रों की रुचि घटने लगी। एक-एक करके विद्रोही गिरने लगे। अग्रेजी फौजे अत तक डटी रही। गृह-युद्ध तथा विदेशी हस्तक्षेप का अंतिम चरण पोलैंड का युद्ध था। वहाँ पर काफी हानि उठाकर मार्च 1921 में लेनिन को रीगा की सन्धि करनी पड़ी। इस प्रकार महान् पीटर द्वारा विजित बाल्टिक सागर का मार्ग तथा यूक्रेन व साइबेरिया का बड़ा भाग खोकर बोल्शेविक सरकार ने अपने अस्तित्व की रक्षा की। यह कहा जा सकता है कि गृह-युद्ध के काल में

लेनिन एक साथ तीन विभिन्न युद्ध में लगा हुआ था—श्वेत रूसी नेता कोलचक के साथ पुराने शासन की पुनः स्थापना रोकने के लिए; पश्चिमी राष्ट्रों तथा जापान के साथ देश की स्वतन्त्रता व सीमाओं की रक्षा के लिए; एवं अन्य राजनैतिक दलों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की निर्विवाद एकलुत्र प्रभुता जमाने के लिए।

### युद्ध-कालीन साम्यवाद

1918-1921 के बीच का यह समय युद्ध कालीन साम्यवाद [War Communism or Period of Militant Communism] का युग कहलाता है। इस समय का आर्थिक इतिहास युद्ध की आवश्यकताओं से संचालित हुआ। रूसी अर्थ-व्यवस्था एक धिरे हुए किले की व्यवस्था के समान थी जहाँ पर उन्मूलन एवं विनाश का भय ही एकमात्र प्रेरक था। इस घोर संकटकालीन अवस्था में आत्मसंरक्षण की भावना ने, सिद्धान्तों को हटाकर, केवल व्यवहारिकता को देखते हुए नीति निर्धारण के लिए राज्य को बाध्य किया।

जिस किसी देश को इतने बड़े पैमाने पर चारों ओर से शत्रुओं का सामना करना हो, उनके आर्थिक संगठन में बड़ी स्पष्ट समरूपता दिखलाई पड़ेगी। हर क्षेत्र में बढ़ता हुआ राजकीय हस्तक्षेप, साधारण निर्देशन से लेकर उत्पादन तथा वितरण का पूर्ण स्वामित्व तक हो सकता है। सैनिक आवश्यकताओं की प्राथमिकता नागरिक उपभोग को कम कर देती है। विशाल सैनिक संगठन जनसंख्या का सबसे अच्छा भाग उत्पादन क्षेत्र से हटाकर कृषि तथा उद्योग में उत्पादन कम कर देता है। यातायात की समस्या सैनिकों तथा युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे अधिक रुकावट उपस्थित करती है। मुद्रास्फीति एवं बढ़े हुए मूल्य जनता के हर वर्ग में असंतोष [और अंगर प्रकृति ने साथ न दिया तो अकाल] की स्थिति व्यापक रूप से उत्पन्न करते हैं। ऐसे समय में किसी भी मूल्य पर जनता से अधिकतम काम लेना होगा। चाहे तो यह धन देकर किया जाय अथवा जनता की माँगों को पूरा करके किया जाय। रूस में लेनिन ने करीब-करीब इन सभी परिस्थितियों का सामना किया।

यह कहना उचित न होगा कि युद्धकालीन साम्यवाद का जन्म सिद्धान्तों को लेकर हुआ। मार्क्स के आदर्श साम्यवाद के अनेकों गुणों को व्यवहार रूप में लागू करने का यह प्रयत्न न था। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1917-1920 के बीच इस तरह की अनेकों बातें पाई जाती हैं, जैसे, अर्थ व्यवस्था में से मुद्रा का प्रयोग हटाना, व्यापार में राजकीय एकाधिकार, केन्द्रीय वितरण संस्था [Narcomprod] के द्वारा गाँवों और शहरों के बीच अनाज तथा वस्तु का वेंचवारा। इन्हीं कुछ बातों को देखकर अनेकों पश्चात्य विद्वानों का विचार है कि युद्धकालीन साम्यवाद सिद्धांत को यथार्थ बनाने का एक

असफल प्रयत्न था। जरा गहराई से देखने पर विदित होगा कि यह सभी कदम युद्ध से उत्पन्न संकटकालीन अवस्था को दूर करने के अकेले उपाय थे। मुद्रास्फीति तथा अन्य कारणों से मुद्रा की क्रय-शक्ति प्रायः नष्ट हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में वस्तु-विनिमय [barter] द्वारा मुद्रा प्रयोग का हट जाना बहुत बड़ी बात नहीं थी। 1921 में तो सरकार यह सोच रही थी कि राज्य-कर उठा दिया जाय क्योंकि राज्य की सभी आवश्यकताएँ वस्तु के रूप में ही प्राप्त होती थी। एक अविकसित देश होने के कारण युद्धकाल में देश के अल्प साधन सैनिक क्षेत्र में लग गये। नागरिक उपभोग की वस्तुओं की भीषण कमी को कम करने का एकमात्र तत्कालिक उपाय वितरण के तरीकों में सुधार करना था। निश्चित प्राथमिकता के अनुसार कम साधनों को अधिक से अधिक सामाजिक लाभ के लिये वितरित करने का काम नारकमप्राद नामक संस्था को सौंपा गया। व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध इसी उद्देश्य से लगा। अतः युद्धकालीन साम्यवाद एक निश्चित आर्थिक नीति के स्थान पर अस्थायी व्यवस्था मात्र था। लेनिन और दूसरे समकालीन विचारक इस समय में उठाये गये कदम को युद्ध तथा विनाश की उत्तेजना में की गई भूल मानते हैं। संकटकाल में तो इनको उचित कहा जा सकता है किन्तु शान्तिकालीन नीति का आधार यह कभी नहीं बन सकते थे।<sup>1</sup>

### कृषि

रूस में शक्ति का एकमात्र अवलम्ब आरम्भ में केवल किसान ही हो सकते हैं, यह बोलशेविक पार्टी अच्छी तरह जानती थी। किसानों का सहयोग पाने का सबसे अच्छा उपाय 'शान्ति और जमीन' का नारा था। जार एवं अस्थायी सरकार [provisional government] के नेता प्रिंस लवोव, प्रोफेसर मिल्यूकोव तथा केरेस्की कोई भी मित्र-राष्ट्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। केवल लेनिन ही किसी भी मूल्य पर शान्ति स्थापित करने को तैयार था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अस्थायी सरकार की कृषि-सुधार योजनाएँ लेनिन के प्रस्तावों से बहुत मिलती थी। अंतर केवल इतना था : जब दूसरे दलों ने सुव्यवस्थित रूप से वैधानिक मार्ग द्वारा किसानों को भूमि दिलाना चाहा था, लेनिन ने वैधानिकता पर समय खोये बिना एकदम से किसानों को भू-स्वामित्व हस्तांतरित करने का वादा किया। 'शान्ति और जमीन' का नारा इतना प्रभावशाली था कि किसान धोखे में आ गये। वे यह न सोच सके कि मजदूर किसानों की सरकार अगर भूमि का राष्ट्रीकरण कर ले, तो भी एक प्रकार से भू-स्वामित्व किसानों का ही हुआ। लेनिन की तीव्र बुद्धि ने यह देख लिया कि जब तक युद्ध के बादल साफ नहीं हो जाते, किसानों को शान्त रखने के लिये आवश्यक है कि राष्ट्रीयकरण व कृषि पुनर्संगठन पर

<sup>1</sup>Maurice Dobb, op cit, p 123

अधिक जोर न दिया जाय। इसलिये युद्धकालीन साम्यवाद का केन्द्र-विन्दु व्यक्तिगत खेती बनी रही। बिना सरकारी मदद के, भू-स्वामियों को हटाकर किसानों ने लेनिन की एक बड़ी मुसीबत समाप्त कर दी। उनका दिन भी आ गया है इसका आभास किसानों को बाद में हुआ। फिर भी किसान देश का साथ ऐसी संकटापन्न अवस्था में इतने जल्दी छोड़ देगा [अन्न उत्पादन घटाना, उपज बेचने से इन्कार, खुला असहयोग आदि], इसकी आशा लेनिन को भी न थी। देश ने किसानों को इसलिये कभी क्षमा न किया।

क्रान्ति के समय में किसानों द्वारा बलपूर्वक प्राप्त की हुई भूमि, पशु एवं अन्य संपत्ति का कोई न कोई हल निकालना अति आवश्यक था। भूमि सङ्गठन में किसानों का कम से कम विरोध लेते हुए कुछ व्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयत्न हुआ। आमतौर पर आवश्यकता के अनुसार भूमि वितरण का सिद्धांत लागू किया गया। गाँवों की भूमि हर एक परिवार में, खेती पर आश्रित सदस्यों की संख्या के अनुसार, बाँटी गई। जिनके पास अधिक कृषि थी या जिन समृद्धशाली किसानों के पास अधिक औजार व पशु थे, उनको भी इसी सिद्धांत के अनुसार बाँट दिया गया। एक समृद्धशाली किसान तथा पुराने भू-स्वामी के बीच यह अंतर था कि प्रथम को समान अनुपात में भूमि रखने का अधिकार मिला जब कि दूसरे से सारी भूमि छीन ली गई। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार तो वैधानिक बन गया किन्तु भूमि राज्य की ही संपत्ति रही, जिसको बेचने का अधिकार किसान को न था।

शीघ्र ही किसानों ने देखा कि क्रान्ति के समय में की गई मनमानी उनका भविष्य नहीं बन पायेगी। 18 नवम्बर 1917 में बिना किसी मुआवजे के भू-स्वामियों की संपत्ति तथा भूमि छीन लेने का जो अधिकार मिला था उसमें व्यवस्था उत्पन्न करने के प्रयत्न किसानों को अच्छे न लगे। क्षणिक संतुष्टि के बाद उनमें अनेकों असंतोष पैदा हुए। इस कानून के अंतर्गत भूमि-स्वामित्व व्यक्तिगत किसानों को नहीं मिला। अस्थायी तौर पर इसे ग्राम समुदाय को दिया गया। भूमि का समान बाँटवारा हो जाने पर भी प्रत्येक किसान को आवश्यकतानुसार पर्याप्त भूमि उपलब्ध न हुई। एक तो खेती योग्य भूमि इतनी नहीं थी कि हर किसान मामूली तौर पर अच्छा रहन-सहन पा सके। अनेकों बड़े-बड़े जमींदारों के विकसित फार्म किसानों में न बाँट कर राज्य ने अपने अधिकार में ले लिया। 1919 से इनको सोवियत फार्मों में संगठित किया गया। इसका उद्देश्य प्रदर्शन द्वारा आधुनिक ढङ्ग की खेती का प्रचार करना था। किन्तु यह प्रयोग उस समय सफल न हुआ क्योंकि अधिकतर बड़े फार्मों के पशु और औजार आसपास के किसानों ने आपस में बाँट लिये थे। इन पर काम करने वाले व्यक्तियों में से लगभग 55% निजी भूमि पाकर स्वतंत्र कृषक बन चुके थे। ऐसी दशा में इनको चलाने के लिये कुछ आसाधारण

नियम बनाये गये जैसे जिला-सल्लाई-समिति के द्वारा मशीन, औजार, पशु और बीज सबसे पहिले सोवियत फार्म को मिलता था; पडोस के गाँवों को अनिवार्य रूप से मजदूर व घोड़े देने पड़ते थे; तथा गाँवों में प्रति-दिवस कार्यकाल बढ़ाकर दस घण्टे कर दिया गया। किसानों ने सोवियत फार्म का घोर विरोध किया क्योंकि वे इतनी बड़ी भूमि से वंचित हो गये। 1920 तक यह प्रयोग सिवा असतोष उत्पन्न करने के किसी प्रकार भी सफल न हो सका।

कृषक समुदाय को बहुत-आशा थी कि जार शासन के अंत होने से उन पर लगे कर भी हट जायेंगे। जब उन्होंने देखा कि उनकी अपनी सरकार भी कर माँगती है तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। मध्यम तथा उच्चवर्ग के किसानों को और भी बोझ उठाना पड़ा क्योंकि कृषक जनसंख्या के 35% गरीब किसान [बेदनीकी] कर-गुक्त थे। युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राज्य ने किसानों द्वारा खुले बाज़ार में अन्न बेचना बंद कर दिया। अनाज का सरकारी मूल्य निर्धारण किसानों को बहुत अखरता था। सच भी है, गिरते हुए रूबल के दाम के कारण, कोई भी निर्धारित मूल्य बाज़ार भाव से सदा कम रहता था। किसानों ने यह माँग की कि मुद्रा की जगह वस्तु-विनिमय द्वारा व्यापार हो। उसमें कई कठिनाइयाँ थी। सीमित औद्योगिक उत्पादन-शक्ति युद्ध की आवश्यकताओं के बाद बहुत कम उपयोग की वस्तु बनाती थी। जो कुछ बनती भी थी वे सेना तथा शहरों में ही समाप्त हो जाती। नारकमप्रोद के अथक प्रयत्नों से भी यह समस्या नहीं सुलझी। यातायात की कमी व अराजकता के कारण मार्ग में लुट जाने की घटनाएँ इस केन्द्रीय सल्लाई संस्था के काम में मुख्य रुकावटें थी। किसानों ने अपनी उपज बेचना बंद कर दिया। लाचार होकर सैनिक सहायता से बलपूर्वक अनाज प्राप्त किया गया। अनाज वगूली के नाम से गाँव के बदमाश तथा आवारों ने घोर अत्याचार किया। बाद में लेनिन ने स्वयं स्वीकार किया कि मजदूरों तथा सैनिकों को खिलाने के लिये किसान का लगभग सारा उत्पादन सरकार ले लेती थी। कभी-कभी तो उनके पास बोनो के लिये भी अनाज नहीं बचता था।

आर्थिक क्षेत्र में जुलाई 1919 तक आते-आते बोलशविकों को अपने विरुद्ध क्रांति का भय इतना बढ़ गया कि सारे देश में असाधारण आयोग [Extraordinary Commission] के द्वारा पूँजीवादी तथा कथित पूँजीवादी व्यक्तियों को खोज-खोज कर नष्ट करने अथवा प्रभावहीन बनाने का भयंकर दमन-चक्र चला। सारे देश में इस आयोग का जाल-सा बिछ गया। कृषि में दरिद्रों की समिति [Committee of the Poor] ने सभी उन्नतिशील व्यक्तियों में संभावित शत्रु की छाया पाई, आयोग की दृष्टि में प्रत्येक शिक्षित, समझदार, कुशल तथा अनुभवी सफेदपोश कर्मचारी देशद्रोही व पूँजीवादी बन गया। उत्पादन की अवनति में नया युग आरम्भ हुआ। अपनी आंतरिक

कमजोरी से उत्पन्न यह सशक्ति मनोवैज्ञानिक स्थिति छोटे-से-छोटे रूप में कितनी हानि कर सकती है, इसका सबसे हाल का उदाहरण संयुक्त राज्य अमरीका में सेनेटर मैकार्थी द्वारा संचालित साम्यवादियों की खोज थी। इस प्रकार उद्योगिक जीवन को तोड़ने में बोल्शेविक सरकार उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि साम्यवाद के शत्रु।

समृद्धिशाली किसानों के दमन के लिये वर्ग-संग्राम [Class struggle] आरम्भ करने की नीति बोल्शेविक पार्टी ने अपनाई। नई सरकार को इस वर्ग के किसानों से ही खतरा उत्पन्न होने का डर था। किसानों को तीन वर्गों में बाँटा गया—कुलक [Kulak], केरेदन्याक [Ceredniak] व बेदन्याक [Bedniak]। कुलक सिद्धान्त में एक समृद्धिशाली किसान था जिसको सामाजिक शोषक माना गया क्योंकि वह अपना काम दूसरों से वैतनिक श्रम द्वारा कराता था। केरेदन्याक मध्यम वर्ग तथा बेदन्याक गरीब वर्ग के किसान थे। इस वर्गीकरण का निश्चित नियम न होने के कारण पक्षपात, विद्वेष, मतभेद एवं राजनैतिक प्रतिहिंसा को पूर्ण छूट मिली। अधिकतर वर्गीकरण का काम स्थानीय गरीबों की समिति [Local Committee of the Poor] करती जिसकी सदस्यता गाँव के निम्नतम कोटि के व्यक्ति [आलसी, बेकार, लुच्चे तथा बद-माश] व्यक्ति करते थे। जो कोई परिवार कुलक घोषित किया जाय उसका नागरिक अधिकार [बच्चों को स्कूल भेजने का अधिकार तक] छिन जाता था। अपनी अल्प आय का 40% कर देने के साथ-साथ वे सामाजिक अछूत बन जाते थे।

इन सब कारणों से सारे कृषि-क्षेत्र पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। फिर भी बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना उनको हितकर न लगा। यह विश्वास पूरी तरह धर जमा चुका था कि दूसरी कोई भी सरकार उनके पास भूमि न रहने देगी। प्रभावशाली रूप से अपना असंतोष और विरोध प्रकट करने का केवल एक ही उपाय उनके पास था—उत्पादन कम करना। इसकी प्रथम अभिव्यक्ति पैदावार को छिपाने तथा चोरी से बेचने में हुई। जिन वस्तुओं की राज्य को आवश्यकता थी उनकी जगह दूसरी चीजों को बोना शुरू किया गया। अंत में कृषि का क्षेत्रफल ही कम करना आरम्भ हुआ। किसान उतनी भूमि पर ही अनाज बोता था जोकि उसको कम-से-कम उपभोग के लिये पर्याप्त हो। इसका प्रभाव था कि 1917-1920 में खेती का क्षेत्रफल गिरकर कुल 1/6 रह गया।

इस समय में उत्पादन गिरने का एक और कारण था। 1914 तक बड़े किसान अपने आधुनिक खेतों पर वैज्ञानिक कृषि करके दूसरे किसानों से 50% अधिक अनाज उत्पन्न करते थे।<sup>1</sup> क्रान्ति तक इनकी सारी संपत्ति किसानों ने आपस में बाँट ली। इससे उत्पादन कम होना स्वाभाविक था। ऐसा मालूम पड़ा कि बोल्शेविक नेता नये समाज की स्थापना, अनुभवी तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों की सहायता एवं सहयोग के बिना,

<sup>1</sup> Leites, K., Recent Economic Developments in Russia, p. 119.



केवल सिद्धान्त की मदद से करना चाहते थे। बहुत बड़ी सख्या में किसानों को सेना में भर्ती होने से उनके खेतों की पैदावार नाममात्र की रह गयी थी। परिणाम-स्वरूप, सम्पूर्ण कृषि उत्पादन में भयंकर अवनति हुई। 1919-20 में फसल न होने के कारण देश में प्रायः अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी। 1920-21 के अकाल में सबसे ज्यादा हानि देश के पशुधन की हुई। चारे की कमी ने घोड़ों तथा भेड़ों की सख्या में भारी कमी किया। इसकी सख्या 1921 तक लगभग 1917 की आधी रह गयी। विश्व-विख्यात मेरीनो भेड़ की सख्या में 94% कमी हुई। चारा इतना महंगा हो गया था कि एक मेरीनो भेड़ को खिलाने में प्रतिवर्ष 1680 रूबल का खर्चा था। उनका ऊन 500 रूबल से ज्यादा का न बिकता था।

इस परिस्थिति से निकलने का सबसे पहला उपाय खेती का क्षेत्रफल बढ़ाना और किसानों को पूरे मेहनत से काम करने के लिये उत्साहित करना था। उसके तीन तरीके सरकार ने सामने रखे : (1) खेती योग्य भूमि की पूर्णरूप से जोताई राज्य की प्रथम आज्ञा घोषित की गई। (2) कोई भी व्यक्ति, किसी भी वहाने, यदि अपने पूरे खेत को नहीं जोतेगा तो उसकी भूमि सरकार जब्त कर लेगी। (3) लाल सेना के सैनिकों की भूमि समाज की ओर से जोती बोई जायगी, अगर उसके परिवार में दूसरा कोई नहीं है। इन नियमों के लागू होने के बाद किसानों ने पूरा खेत तो बोया किन्तु उसमें इतना कम बीज डाला कि उपज में विशेष अंतर न पड़ा। शहरों में भोजन की कमी के कारण आबादी का प्रवास गाँवों की ओर हुआ। पेत्रोग्राड की जनसंख्या 1916 में 24 लाख से घटकर 1920 में 6 लाख तथा मास्को की आबादी 22 लाख से घटकर 10 लाख हो गयी।<sup>1</sup> औद्योगिक उत्पादन तथा शासन दोनों में इस प्रवास ने जटिल समस्याएँ उत्पन्न कीं।

युद्ध कालीन साम्यवाद कृषि-क्षेत्र में किसानों तथा बोलशेविक सरकार के बीच अम्यसी बल-परीक्षा का समय था। सरकार जानती थी कि एक कृषि-प्रधान देश में किसानों का पक्ष प्राप्त किये बिना कोई सरकार सफल नहीं हो सकती। फिर भी केन्द्रीय अनुशासन तथा संचालन में किसान को बिना बाँधे साम्यवाद की स्थापना असंभव थी। किसान सरकार के लिये अपनी संख्या तथा अमूल्य उत्पादन के सहयोग का महत्व समझता था। इस तनातनी में किसानों को काफी छूट दी गयी। 1920 में जबकि श्वेत रूसी सेनाएँ पूरी तरह हार गयी और गृहयुद्ध तथा विदेशी हस्तक्षेप का अन्त हो गया तब बोलशेविक पार्टी व किसान बराबरी से एक दूसरे के सामने आये। निरंतर बढ़ते हुए किसानों के दंगे-फसाद और लगातार गिरता हुआ उत्पादन इस बात का निर्देशक था कि किसानों की तृप्ति में देर करना अत्यन्त अनिष्टकर सिद्ध होगा। इस अनुभूति ने युद्ध-कालीन साम्यवाद का अन्त घोषित किया।

<sup>1</sup> Alpert, P. *Twentieth Century Economic History of Europe*, p. 101.

## उद्योग

आधुनिक युद्ध औद्योगिक उत्पादन शक्ति से लड़ा जाता है। लोहा, कोयला, पेट्रोल तथा स्वर का जो देश सबसे अधिक उत्पादन कर सकेगा, सिद्धान्त तथा न्याय के विपरीत, उसकी विजय निश्चित है। क्रान्ति के बाद अपने अस्तित्व के रक्षार्थ 1918-1920 के युद्ध का आधार भी उत्पादन शक्ति ही थी। विदेशियों की स्वार्थलोलुपता को सन्तुष्ट करने के लिये स्थापित रूसी औद्योगिक ढाँचा, युद्धकाल में अवलंबनीय होकर, अपने आप ही निष्प्राण हो गया। क्रान्ति के बाद औद्योगिक उत्पादन का आरम्भ हुआ। पूरे युद्धकाल में सरकार के सभी प्रयत्न इस दिशा में प्रगति लाने की ओर केन्द्रित थे। उद्योगों में उत्पादन गिरने का उत्तरदायित्व बोल्शविक सरकार के ही कंधों पर रखा जाता है। ऐसा विचार सन्तुलित नहीं प्रतीत होता। शासन-भार संभालने के बाद लेनिन ने अनुभव किया कि युद्ध की स्थिति में समकालीन उत्पादन सङ्गठन को छेड़ना कदापि श्रेयस्कर न होगा। उसी विचार से क्रान्ति के बाद तुरन्त ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि क्रान्ति के समय और उसके बाद कारखाना प्रबन्ध के लिये बनाई गईं मजदूर समितियों को एक मात्र प्रबन्धक होने की मान्यता प्राप्त हुई [Nov. 14 1917]। इन बिखरी हुई समितियों में संपर्क [Coordination] स्थापित करने के लिये अर्थव्यवस्था की उच्चतम समिति [Supreme Council of National Economy] या सोबनारखोज 5 दिसम्बर 1917 में स्थापित की गई। यदि पुराने प्रबन्धक, इंजीनियर तथा अन्य विशेषज्ञों को विश्वास दिलाया जा सकता कि बदले हुए जमाने के साथ उन्हें भी बदलना होगा तो चालू उत्पादन व्यवस्था में इतनी हानि न होती जितनी कि सामने आयी। व्यक्तिवादी ढाँचे के अभ्यस्त वह कुशल तथा अनुभवी व्यक्ति हड़ताल और असहयोग के द्वारा अपना विरोध प्रकट करने लगे। बाध्य होकर कम्युनिस्ट सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ना पड़ा। यह सभी मानते थे कि राष्ट्रीयकरण का समय नहीं आया है। बिना केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के 1918 जून के आरम्भ तक 486 सबसे बड़े कारखानों को अलग-अलग स्थानीय अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद परिस्थित को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने 28 जून 1918 में सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके स्थानीय अधिकारियों के कार्य को वैधानिक बनाया। अखिल रूसी निर्माता सङ्घ के अनुसार इस कानून का प्रभाव 1100 कारखानों [पूँजी 300 करोड़ रूबल] पर पड़ा।<sup>1</sup> चूँकि बड़े उद्योग विस्तृत रूप से लघु उद्योगों पर निर्भर थे और उनका असहयोग रूकावट करने लगा, तब 29 दिसम्बर 1918 में इनको भी सरकार ने ले लिया। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की उच्चतम समिति

<sup>1</sup> Leites, op. cit., p 94.

[ Supreme Council of National Economy ] सन्तुलन, सम्पर्क, तथा संचालन का केन्द्रीय सङ्गठन बन गयी। उत्पादन की अवनति के मुख्य कारखानों में औद्योगिक प्रजातन्त्र [ Industrial Democracy ] का हाथ कई प्रकार से था। चुनाव द्वारा स्थापित मजदूर समितियों के संचालन में काम करना पुराने सङ्गठन के अन्यस्त प्रबंधकों को अपमानजनक लगता था। नया संचालन स्वयं अत्यन्त अपूर्ण, अनुभवहीन तथा विद्वेष की भावना से परिपूरित था। इस प्रबन्ध में उत्पादन शक्ति तथा लागत का कोई स्थान न था। गृह युद्ध में उत्तरी तथा केन्द्रीय रूस के बड़े उद्योगों को ईंधन व कच्चे माल से पृथक कर दिया गया। दोनेत्ज घाटी का कोयला, वाकू का पेट्रोल और तुर्किस्तान क्षेत्र की कपास मिलों तक न पहुँचती थी। लाल सेना ने बड़ी संख्या में मजदूरों को खींच लिया था। केन्द्रीय संचालन सुव्यवस्थित न होने के कारण परम आवश्यक कुशल कारीगर सेना में भर्ती होने को लाचार किये गये। विद्रोही नेता एडमिरल कोलचक व जनरल डेनिकिन की सेनाओं ने भी मजदूर तथा किसानों को उत्पादन क्षेत्र से हटाया। श्रम की स्थिति को और पेचीदा बनाने में भोजन की कमी के कारण मजदूरों का शहरों से प्रवास व क्रान्ति के समय से उनमें जाग्रत अनुशासनहीनता और उल्लुङ्खलता की भावना ने काफी सहयोग दिया। विदेशी मशीन, रसायन तथा विशेषज्ञ का सहारा न मिलने से उद्योगों के उत्कर्ष की शक्ति क्षीण हो गयी। रूसी राज्य योजना आयोग के अनुसार उत्पादन के निर्देशांक इस प्रकार थे।<sup>1</sup>

वर्ष	बड़े उद्योग	छोटे उद्योग	कुल उद्योग
1913	100°0	100°0	100°0
1916	116°1	88°2	109°4
1917	74°8	78°4	75°7
1918	33°8	73°5	43°4
1919	14°9	49°0	23°1
1920	12°8	44°1	20°4

<sup>1</sup> Baykov, A. Soviet Economic System, p. 8.

इन आँकड़ों से कई क्रम स्पष्ट होते हैं। बड़े उद्योग में अवनति की गति छोटे उद्योगों से अधिक तेज थी। अत्यधिक केन्द्रित स्थानीयकरण होने के कारण यह उद्योग राजनैतिक तनातनी का शिकार बने। युद्धकालीन साम्यवाद ने केवल उत्पादन में ही कमी नहीं किया, पूरे औद्योगिक संगठन में ऐसे विकार उत्पन्न कर दिये जिनको दूर करने में कठिन परिश्रम और कीमती समय व्यय करना पड़ा। बिना पूरी मरम्मत और देख-रेख के मशीनों से इतना काम लिया गया कि उनके जीवनकाल के साथ उत्पादन की श्रेष्ठता बुनियादी रूप से कम हो गयी। अनुभवी प्रबन्धकों एवं विशेषज्ञों के हट जाने से उनके रिक्त स्थान की पूर्ति में लम्बी अवधि तक उत्पादन की हानि और धन का अपव्यय होता रहा। उखड़े हुए मजदूरों को शान्तिपूर्ण ढङ्ग में नियम के अनुसार काम पर पुनः लगाना सालों तक एक समस्या बना था।

### वित्त संगठन [Finance]

क्रान्ति की उथल-पुथल के साथ यह युद्ध की अव्यवस्था ने मिलकर अपना कुप्रभाव रूस की वित्त-व्यवस्था पर डाला। इस क्षेत्र के प्रायः सभी विभागों में हिच-किचाहट व उलझनों से भरी हुई अनिश्चित नीति दिखलाई पड़ती है। नई सरकार की साख और आर्थिक स्थिरता पर जनता का विश्वास एकदम नहीं जम सका। आज जारी की हुई आज्ञा का खंडन दूसरे ही दिन प्रकाशित होता; राजाज्ञा, उसका खंडन और दूसरी आज्ञा राजधानी से दूर क्षेत्रों में लगभग एक साथ पहुँचती थी; नये नियुक्त किये हुए सरकारी कर्मचारियों की अपने पद के लिए उपयुक्तता का मापदण्ड उनकी क्रान्तिकारी सेवाएँ थीं, न कि योग्यता, अधिकतर प्रांतीय व स्थानीय राज्य कर्मचारी क्रान्तिकारी जोश को ही निर्णय का आधार बनाते थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का अर्थ अपने इच्छानुसार निकालकर भिन्न-भिन्न स्थानों पर पृथक् रूप में लागू किया जाता था। आर्थिक संगठन के प्रत्येक अंग को दोहरी आज्ञाओं में चुनाव करना पड़ता। दूरस्थ केन्द्रीय सरकार की जगह स्थानीय अधिकारी का दबाव इनसे अपनी बात मनवा लेता था। यह दोहरा शासन और परस्पर विरोधी आज्ञाएँ वित्तव्यवस्था में अकथनीय उलझन पैदा करते थे।

इस क्षेत्र की नीति में एकरूपता का अभाव अनेकों कारणों का असर था। बोलशेविक सरकार एकदम नवीन आर्थिक और राजनैतिक संगठन में लगी थी जिसमें हर एक पग पर प्रयोगात्मक दृष्टिकोण बनाये रखने के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन न था। यह कहा जा सकता है कि तानाशाही की पोषक बोलशेविक सरकार के नीति निर्धारण में दुविधा का क्या काम था? यह कहना अनुचित है। लेनिन सर्वमान्य नेता अवश्य था किन्तु यह-युद्ध के बाद तक वह एकछत्र निरंकुश तानाशाह नहीं बन सका था। अपने

विचारों को प्रभावशाली सोवियत सभा से स्वीकृत कराने के लिए उसे अपने बुद्धिबल, वाक्शक्ति तथा तेजवान व्यक्तित्व का सहारा लेना पड़ता था। इसलिए नीति में विरोधाभास का सारा दोष लेनिन की योग्यता पर नहीं किया जाना चाहिये। बोलशविक पार्टी के अधिकतर क्रान्तिकारी नेताओं ने क्रान्ति के राजनैतिक पहलू पर तो अच्छा अध्ययन कर लिया था किन्तु क्लिष्ट आर्थिक ज्ञान, और इससे भी कठिन अनुभव द्वारा विचारों का विकास करने का न तो उनको अवसर मिला और न उन्होंने क्रान्ति के पहले इसे आवश्यक समझा होगा। इसलिए जितनी दृढ़ता राजनैतिक क्षेत्र में दिखलाई पड़ी, उतना ही अपवादपूर्ण परीक्षण आर्थिक मामलों में सालों तक चलता रहा।

इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बुनियादी समस्या मुद्रा के प्रचलन का उन्मूलन था। साम्यवादी सिद्धान्त दृढ़ रूप से स्थिर कर चुका था कि मुद्रा का प्रयोग ही शोषण का एकमात्र माध्यम है, इसलिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं। अब प्रश्न यह था कि मुद्रा के प्रयोग और प्रचलन को किस प्रकार हटाया जाय। विशेषकर पत्र मुद्रा के विरुद्ध काफी दवाव था। सोवियत सरकार के प्रायः सभी प्रारम्भिक योजनाओं में मुद्रा के उन्मूलन को स्थान मिला। इनके विचार से शीघ्र ही मुद्रा का स्थान उपभोग की वस्तुओं को ले लेना चाहिये जिससे सेवाओं एवं वस्तुओं का विनिमय सीधे रूप से हो सके। वास्तविकता में यह केवल बड़े शहरों के सगठित श्रमिकों के साथ ही सम्भव था। यातायात की कमजोरी और वेईमान कर्मचारियों के कारण रूस की तरह विशाल एवं विस्तृत ग्रामीण जनता में इसे प्रचलित करना अत्यन्त कठिन सिद्ध हुआ। फिर भी समय-समय पर बोलशविक सरकार इस ओर अग्रसर होती थी। सोवनारखोज [Supreme Council of National Economy] ने मजदूरों के लिए मुद्रा का प्रयोग बन्द कर दिया। भिन्न-भिन्न औद्योगिक इकाइयों के बीच के हिसाब-किताब में भी मुद्रा को हटा दिया गया। इसका यह अर्थ समझना भूल प्रतीत होता है कि मुद्रा के उन्मूलन की आंशिक सफलता साम्यवादी सिद्धान्त की सफलता है। इस सफलता का मुख्य कारण मुद्रा स्फीति और रूबल का गिरता हथ्था मूल्य था। किसान अपनी उपज मुद्रा में बेचकर नाममात्र की ही क्रयशक्ति प्राप्त करता था। सरकार से पहले, किसानों ने स्वयं अपने उत्पादन के बदले में उपभोग की निर्मित-वस्तुओं की माँग की। शहरों में अब की भीषण कमी ने मजदूरों को अपने श्रम का भुगतान अनाज में प्राप्त करना ही हितकर बना दिया। इस प्रकार मुद्रा का प्रयोग न होना, रूबल के विघटन, शहर और गाँव में दूटा आपसी सम्बन्ध और बढ़ते हुए मूल्य से जनता को बचाने का एक साधन था।

यह युद्ध, विदेशी हस्तक्षेप और शासन-प्रबन्ध का खर्च इतनी तेजी से बढ़ा कि सरकार के सामने घोर आर्थिक संकट प्रकट हुआ। द्वितीय महायुद्ध, ज़ार का निष्काशन एवं अस्थायी सरकार के प्रयत्नों ने वित्त-संगठन को जर्जर बना दिया था। ऐसे समय में

जबकि धन का अभाव नये शासन को पशु बनाने पर तुला था, बोल्शेविक नेता साम्यवाद की स्थापना का कार्य इस क्षेत्र में लागू करने में न हिचके। दुर्भाग्यवश सरकार के कार्य और प्रभाव से क्रिया-प्रतिक्रिया का ऐसा चक्र उत्पन्न हुआ कि यह कहना कठिन है कि दशा को विगाड़ने का दोष बोल्शेविक सरकार को दिया जाय या परिस्थितियों को। क्रांति के बाद कुछ समय तक तो सरकार ने अर्थ-व्यवस्था को अकेला छोड़ दिया। जैसे-जैसे धनाभाव बढ़ता गया और युद्ध की विपरीत गति बनी रही, साधनों को उपलब्ध करने के नये मार्ग खोजना आवश्यक हो गया। धनी व्यक्तियों तथा पूँजी-पतियों को यह आभास मिला कि नई सरकार स्थायी जड़े पकड़ रही है और उनके प्रति विरोधी भावनाओं में कमी होने की संभावना दूर होती जा रही है तो उनका पहला काम बैंको से अपनी पूँजी निकालना था। उपरोक्त हालत में इस प्रवृत्ति पर रूकावट लगाना जरूरी हो गया। 17 मार्च 1918 में अस्थायी रूप से बैंको से जमा-पूँजी निकालने पर प्रतिबन्ध लगा।

## व्यापार

उत्पादन पर राजकीय निर्देशन होने के कारण अस्थिर सामाजिक व आर्थिक स्थिति ने यह आवश्यक बना दिया कि देशी और विदेशी व्यापार पर राजकीय प्रभुत्व स्थापित हो। इस समय की रूसी व्यापारिक नीति अपनी समस्त रूपरेखा में एक संकट-कालीन नीति थी। इसमें कोई सदेह नहीं कि सिद्धान्तवाद का कुछ पुट इसमें था। युद्धकालीन साम्यवाद के दूसरे विभागों के समान इस क्षेत्र में भी राजकीय एकाधिकार उत्पन्न करने में परिस्थितियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। युद्ध का विनाश, उत्पादन में कमी के साथ माँग में वृद्धि, आयात पर निर्धारित अर्थ-व्यवस्था तथा भयंकर मुद्रास्फीति से बाध्य होकर, व्यक्तिगत व्यापारियों से व्यापार अपने हाथ में लेने के सिवाय कोई दूसरा चारा न था। 14 नवम्बर 1917 में मजदूर निर्देशन [workers-control] का अधिनियम बना जिसमें उद्योग के साथ साथ व्यापार पर भी रूकावटें लगाई गयीं। इन रूकावटों में व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए काम करने का काफ़ी स्थान था। परिस्थिति विगाड़ने के साथ-साथ राज्य और भी अधिक क्रियाशील बना। 21 नवम्बर 1918 को उपभोग की सभी वस्तुओं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो गया तथा जनवरी 1919 को अनाज के व्यापार का एकाधिकार राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। समय बीतने के साथ-साथ व्यापार के राष्ट्रीयकरण का क्रम तेज हुआ क्योंकि हालांते बराबर खेराब होती रही। इसके अतिरिक्त शासन में स्थिरता आ रही थी। इससे सरकार में आत्म-विश्वास भी बढ़ने लगा।

आमतौर पर कहा जा सकता है कि सोवियत रूस में पूँजीवादी व्यापार का कोई

स्थान नहीं था। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कुल एक ही मध्यस्थ संभव था—राज्य। यह मध्यस्थता सोवियत राज्य के हाथ में एक विशाल शक्ति थी। क्रान्ति की गहराई [Deepening of revolution] बढ़ाने के लिए उपभोग की वस्तुओं के वितरण से समाज में वर्ग-संघर्ष [class struggle] सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता था। पूँजी का अपने लाभ के लिए प्रयोग करना राज्य की दृष्टि में शोषण बन गया था। साख और मुद्रा दोनों प्राप्त करना जितना कठिन था उतना ही बेकार था क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण और मुद्रा के मूल्य में भयंकर कमी से इनका कोई लाभपूर्ण प्रयोग नहीं हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्पादन वृद्धि में प्रत्यक्ष प्रेरक [Direct Stimulant] के रूप में व्यापार का कोई महत्व न रहा। 21 नवम्बर 1918 में एक विशेष संस्था, नारक्रमप्राद, स्थापित हुई जिसको उपभोग की सभी वस्तुओं को उत्पादकों से प्राप्त करके उपभोक्ताओं तक वितरित करने का एकाधिकार था। उस वितरण का मुख्य माध्यम या तो पुरानी सहकारी समितियाँ थी या राजकीय वितरण केन्द्र। मुद्रा का प्रयोग कम हो जाने से व्यापार का प्रमुख रूप वस्तुतः वस्तु-विनिमय हो था। वर्ग-संघर्ष को बढ़ाने के लिये विस्तृत राशनिंग व्यवस्था में विभिन्न वर्गों को अलग-अलग मात्रा में भोजन प्राप्त होता था। धीरे धीरे 1920 तक 30 वर्गों में उपभोक्ता बॉट दिये गये और इन सबको अपने-अपने राष्ट्रीय महत्व के हिसाब से राशन मिलता था। इस समय करीब 350 लाख व्यक्ति केन्द्रीय वितरण व्यवस्था के अंतर्गत थे। प्रथम वर्ग और चतुर्थ वर्ग के बीच भेदभाव उत्पन्न करने के प्रयत्न में पहले को 35 पौंड रोटी और दूसरे को 12 पौंड रोटी प्रति मास मिलती थी।<sup>1</sup>

अपने प्रचलित अर्थ में देशी व्यापार तो सोवियत सरकार ने उठा ही दिया था किन्तु उसी सफलता से विदेशी व्यापार को सरकार अपने अधिकार में न ले पाई। आरम्भ में तो इस क्षेत्र में सम्मेलन-सम्मेलन कर कदम उठाया गया। दिसम्बर 1917 को विदेशी व्यापार के लिए राजकीय अनुमति [लाइसेंस] की प्रथा चलाई गयी। शीघ्र ही, उस समय की परिस्थितियों ने अधूरा नियंत्रण चल सकना असम्भव बना दिया। 22 अप्रैल 1918 को विदेशी व्यापार भी राजकीय एकाधिकार में चला गया। विदेशी बैंकों ने किसी भी रूप में रूसी मुद्रा एवं साख को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। इतना ही नहीं, धन की कमी से नई सरकार को पंगु बनाने के लिए इंग्लैण्ड और फ्रांस के नेतृत्व में 1918 से आर्थिक घेराबन्दी चल रही थी। ऐसी हालत में नाममात्र का ही विदेशी व्यापार हुआ।

<sup>1</sup> Baykov op. cit., p. 26

विदेशी व्यापार<sup>1</sup>

	मिलियन रूबल : 1913 मुद्रा मूल्य में		
	निर्यात	आयात	शेष
1913	1520.1	1374.0	+ 146.1
1914	137.0	802.0	— 665.0
1918	7.5	61.1	— 53.6
1919	0.1	3.0	— 2.9
1920	1.4	28.7	— 27.3

1920 तक कुछ माल यूरप के छोटे-छोटे देशों से असंगठित रूप से आ जाता था। इन देशों में स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैण्ड मुख्य थे। वास्तविकता पर बने अवसरवादी जर्मनी ने रूस की विशाल बाजार और नगद भुगतान का लाभ उठाना तुरन्त आरम्भ कर दिया। चूँकि रूस अपने आयात का भुगतान सोना या हीरे-जवाहिरात में करता था, इसका आकर्षण बहुत था। जर्मनी का इस प्रकार बढ़ता हुआ प्रभाव देख कर मित्र-राष्ट्रों को लालच हुई। इङ्गलैण्ड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका के विचारों में परिवर्तन होना अनिवार्य था। जनवरी 1920 से आरम्भ होकर 1921 के मध्य तक आर्थिक घेराबन्दी टूट गयी। अविकसित देश ने अपनी उन्नति में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यापारिक और औद्योगिक सुविधाओं से विदेशी धन तथा अनुभव को आकर्षित करना आरम्भ किया। व्यापार में दी गयी यह छूट 1920-21 के राजनैतिक विवाद का केन्द्र-बिन्दु बना।<sup>2</sup>

## युद्धकालीन साम्यवाद का प्रभाव

युद्धकालीन साम्यवाद ने सोवियत सरकार के सिद्धान्त, विचार एवं कार्यप्रणाली

<sup>1</sup> Ibid p. 29.

<sup>2</sup> See the famous speech of Lenin at the Tenth Congress of the Communist Party, March 1921.



को पुष्ट और परिष्कृत करने में बहुत सहायता की। कोरे सिद्धान्त एवं निरर्थक भावावेश को छोड़कर वास्तविकता को और अग्रसर करने का लगभग पूरा श्रेय इस समय की घटनाओं को है। विश्वयुद्ध तथा गृहयुद्ध के विनाश में एक विशेष अच्छाई छिपी थी। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक ढाँचे का जो विध्वस्त खंडहर सोवियत सरकार को विरासत में मिला, उसके पुनर्निर्माण की आशा करना भी बेकार था। इसलिए पुराने ढाँचे को पूरी तरह उखाड़ कर फिर से नई नींव पर निर्माण करना पड़ा। इससे पिछड़े विचार, रूढ़िवादिता और संकीर्णता से बोझिल हुए बिना, नवीन उन्नति की ओर गतिशील हुआ जा सका।

साम्यवाद का यह प्रयोगात्मक काल भूल और सुधार की शृङ्खला थी। बिना किसी दृढ़ सिद्धांतिक आधार के, अस्पष्ट विचारों और अनजाने तरीकों के धुंधलेपन में आगे बढ़ने का प्रयत्न हो रहा था। इस मार्ग में और भी इतनी रुकावटें थी जिन्होंने परिस्थिति को अत्यन्त जटिल कर दिया। अशिक्षित जनता उच्च साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार अपना मार्ग निर्धारित करने में असमर्थ थी। छोटा-सा किन्तु प्रभावशाली शिक्षित एवं बौद्धिक वर्ग स्वार्थ लोलुपता में डूबा था। निकम्मे कर्मचारियों से बनी शासन प्रणाली प्रभावहीन थी। इन सबके ऊपर पूँजीवादी विदेशी सरकारें मिलकर आर्थिक और राजनैतिक हस्तक्षेप से नई सरकार को मिटा देने में प्राणपण लगी थी। गृह-युद्ध और संकटकालीन स्थिति ने रूस के राजनैतिक ढाँचे का निर्माण निम्न - प्रगतिवादी ताना-शाही और समस्त शासन शक्ति का प्रवल केन्द्रीयकरण। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पिछड़ी हुई जनता चोटी के चन्द नेताओं पर अपार श्रद्धा और देवतुल्य भरोसा करने लगी। पुराने ईश्वर में विश्वास न करने वाले साम्यवादियों ने अपने नये ईश्वर का निर्माण प्रमुख नेता व राज्य के अधिष्ठाता लेनिन के रूप में किया। विदेशी आक्रमण तथा बेराबन्दी से त्रस्त देश, जब हर तरफ से निराश हो गया, तब असाधारण एकता और आत्मनिर्भरता उत्पन्न हुई। संसार में पहली बार शासन में बल प्रयोग के साथ “मनोवैज्ञानिक विचार परिवर्तन” [psychological indoctrination] का सहारा लिया गया। अपार प्रभावशाली वैज्ञानिक प्रचार इतना बढ़ा कि रूस में बहुत दिनों तक के लिए प्रचार ही शिक्षा बन गया। विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक बेराबन्दी ने नई सरकार के सदस्यों को अटल विश्वास दिला दिया कि रूस के बाहर के सभी देश सोवियत शासन के शत्रु हैं : उनसे रक्षा करने के लिए एक लौह-आवरण की आवश्यकता होगी। विदेशियों के प्रति स्टालिन की कटुता और पृथक्वाद उस समय के अनुभवों की युक्तिसंगत प्रतिक्रिया थी। फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति की तरह, रूसी क्रान्ति के बाद युद्धकालीन साम्यवाद-काल में सुदृढ़-भर चोटी के बौद्धिक ठेकेदारों के स्थान पर निम्नतर सामाजिक स्तर की विराट इच्छाशक्ति तथा प्रगति-प्रेरणा [Initiative] बन्धन से छूट गई। सेना

और शासन में निडर, साहसी, विचारपूर्ण व्यक्ति ऊपर उठे। रूस की उन्नति इनकी क्रियाशीलता और लगन का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

रूसी इतिहास में पहली बार [और शायद अंतिम बार भी] किसानों ने प्राथमिकता प्राप्त की। उनको अधिकार तथा विशेष छूट मिली किन्तु यह अधिक दिन न चली। जल्दी ही शहरों के मजदूरों ने किसानों का महत्व फिर से घटा दिया। सिद्धान्त के क्षेत्र में, यह मान लिया गया कि मिछेड़े हुए छोटे पैमाने के कृषिप्रधान देश में केन्द्रीय मजदूर सरकार की आज्ञा द्वारा साम्यवाद का स्थापना नहीं हो सकती। लेनिन ने स्वयं स्वीकार किया कि साम्यवाद के लिये देश को तैयार करना होगा, जिसका मार्ग राजकीय पूँजीवाद [State Capitalism] तथा समाजवाद [Socialism] है।

कुछ भी हो ब्रान्ति तथा गृहयुद्ध ने मिल कर देश को बर्बाद कर दिया। निकोलस द्वितीय की पत्नी सम्राज्ञी एलेक्जेंड्रोवना तथा धूर्त रासपुटिन से आरम्भ होकर यह विनाश अस्थायी सरकार के समय में बढ़ा और बोल्शेविक सरकार ने अपने प्रयोगों द्वारा इसे चरम सीमा पर पहुँचा दिया। भयंकर सुधारक्रांति से विनिमय का कार्य असम्भव हो गया। लगभग 5-6 उद्योग नष्ट हो चुके थे : यातायात नाम मात्र का बचा था : देशी व्यापार आरंभ से ही बन्द था। गृह-युद्ध, आर्थिक विरागन्दी, समस्त व्यक्तिगत संपत्ति का बलात् हस्तांतरण व विदेशी ऋण का खडन, व्यापार का गला घोट चुका था। चन्द शब्दों में देश की उत्पादन शक्ति दूट गई और समाज अपनी पूर्व-संचित पूँजी पर निर्वाह करने को लाचार हुआ।

एक बहुत बड़ा प्रभाव इस काल के प्रयोगों का यह हुआ कि हर एक क्षेत्र में आत्म-आलोचना [Self-criticism] और पुनर्विवेचना [re-assessment] की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। औद्योगिक प्रवन्ध एवं संगठन में मजदूर समिति के जगह पर एक व्यक्ति प्रवन्ध [one man management] की जरूरत सामने आई। कुशलता, अनुभव तथा प्रशिक्षित [trained] व्यक्तियों के महत्व को समझा गया। उत्पादन शक्ति की वृद्धि के लिए उत्पादन प्रेरकों [Production incentives] की अनिवार्यता दिखलाई दी। सुसंयत आर्थिक-व्यवस्था के लिये कठोर मजदूर अनुशासन की आवश्यकता का फिर से अनुभव हुआ। मजदूरों को भी अपना उचित स्थान मालूम पड़ा। विस्तृत दुर्मिन्न, उपयोग की सामग्री की कमी, खड़े हुए वेकर कारखाने और बिना जोती-बोई जमीन ने युद्ध-कालीन साम्यवाद-काल के अंत तक, इन सब बातों की आवश्यकता पूरी तरह सामने रखा। परिवर्तन का तत्कालिक कारण बढ़ते हुए किसान असहयोग, मजदूरों की हड़तालें और मार्च 1921 का क्रौन्स्टाद [Kronstadt] विद्रोह था। सफलतापूर्वक इनका दमन तो कर दिया गया किन्तु लेनिन की तेज आँखों

ने इनके कारणों को तुरन्त देख लिया। एकदम ठीक समय पर मिला यह इशारा भविष्य की नीति का आधार बना। कुख्यात रूसी शुद्धी-प्रणाली [Purge] का जन्म उसी समय में हुआ जिसका सहारा रूस के नेता बराबर लेते रहे। एक ओर तो जनता के असंतोष का कारण दूर करने की कोशिश की गई और दूसरी ओर देश के अन्दर उन तत्वों [elements] को भी नष्ट कर दिया गया जो जनता के असंतोष का नेतृत्व करके उनको अभिव्यक्ति प्रदान करते। 1921 में नीचे से ऊपर तक ऐसे व्यक्तियों को, स्थायी अथवा अस्थायी रूप में, हटाकर लेनिन ने शासन प्रणाली को शुद्ध किया। इस परिष्कृत वातावरण के कारण ही आने वाली नई आर्थिक नीति स्वीकृत हो सकी।

## अध्याय ८

# नवीन आर्थिक नीति

[New Economic Policy]

## नवीन आर्थिक नीति [New Economic Policy]

यह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप के समाप्त होते ही सोवियत सरकार ने देश की जटिल आन्तरिक समस्याओं की ओर ध्यान दिया। साम्यवादी दल की विरोधी आवाजों ने काफी प्रबल रूप धारण कर लिया था। यह समस्त देश में असंतोष की अभिव्यक्ति थी। तत्कालीन एव समुचित उपकरण का अभाव शिशु सोवियत राज्य का अस्तित्व संकट में डाल सकता था। क्रान्ति के बाद उत्साह और आदर्श का रङ्गीन पर्दा अपना बहुत कुछ आकर्षण खो चुका था और वास्तविकता इस पर्दे को फाड़कर नागरिकों और राजनीतिज्ञों तक पहुँच रही थी। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन ने भावना सिद्धान्त और सुख-स्वन्न के स्थान पर कठिन परिश्रम की ओर देश को मोड़ा। आर्थिक आवश्यकताओं ने अपने महत्व को प्रभावशाली तरीके से सामने रखकर प्राथमिकता प्राप्त किया। उच्च शासक वर्ग में प्रथम बार यह अनुभूति हुई कि शब्दों का इन्द्रजाल रचनेवाले क्रान्तिकारियों से आर्थिक एवं औद्योगिक विशेषज्ञ अधिक आवश्यक हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रूस के साम्यवादी क्रान्तिकारी नेता औद्योगिक लाभ और धर्म का प्रभाव मिटाने में कट्टर आदर्शवादी थे। साथ-ही-साथ उनमें पक्की यथार्थवादिता का इतना गहरा पुट था कि सिद्धान्तों में कितनी सफलता प्राप्त करना सम्भव है, यह वे अच्छी तरह समझते थे। इसी कारण आशाओं के विपरीत सकल क्रान्ति को स्थायी रूप दिया जा सका। हर नई गम्भीर परिस्थिति के अनुसार तुरन्त अपने को बदल लेने से परिस्थिति और नीति का आपसी तारतम्य व सामंजस्य कभी बिगड़ने नहीं पाया। मध्य 1921 में उत्पन्न दूसरी संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिये जो कार्यक्रम निश्चित किया गया उसे नवीन आर्थिक नीति अथवा नये [N. E. P. or New Economic Policy] कहते हैं।

मार्च 1921 में साम्यवादी दल के दसवें अधिवेशन के सामने इस नीति की आवश्यकता बतलाते हुए लेनिन ने तीन मुख्य बातों पर जोर दिया। प्रथम, किसी भी मूल्य पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना। क्रान्ति के बाद कृषि और उद्योग के उत्पादन में जो भीषण अवनति हुई थी उससे समस्त आर्थिक और राजनैतिक ढाँचे के टूट जाने

का डर पैदा हो गया था। बिना उपभोग की सामग्री मिले अन्न का उत्पादन करना किसानों को अर्थहीन लगता था। दूसरी ओर अनाज और कच्चे माल की कमी ने औद्योगिक उत्पादन की दशा को शोचनीय बना रखा था। सेना, कारखाना और खेत में लगे हुए व्यक्ति राज्य का आधार थे और यह आधार उत्पादन पर बना था। देश की उन्नति के लिये आवश्यक विदेशी मशीन और कारीगर उसी समय मिल सकते थे जबकि व्यापार द्वारा उनके भुगतान का साधन इकट्ठा किया जाय। द्वितीय, राजनैतिक संकट से बचाव—आरम्भ से ही सोवियत सरकार कारखाना मजदूरों को जागृत नागरिक [enlightened citizens] और किसानों को सुसुत नागरिक समझती थी। युद्धकाल में जब अत्यन्त कठोरता से मजदूर और सैनिकों को खिलाने के लिये किसानों की फसल जब्त करना पड़ा तो यह भावना और भी बढ़ी। 1921 तक मजदूर और किसानों, गांवों और शहरों के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि बिना कुछ उपाय किये हँसिया और हथौड़ा का आपसी सम्बन्ध पूर्ण रूप से विच्छेद होने के लक्षण दिखाई देने लगे। किसान और मजदूर का आपसी अटल सम्बन्ध [Smytchka] लेनिन साम्यवादी रूस की नींव मानता था। सच भी है, अगर यह न होता और सोवियत सरकार श्रमिक राज्य न स्थापित करके मजदूर अथवा किसान राज्य का आदर्श सामने रखती तो आज-दिन इस इतिहास के लिखने की आवश्यकता न होती। तृतीय, राष्ट्रीय स्नायु मंडल के प्रमुख केन्द्रों को अपने हाथ में रखकर, उनके द्वारा नई पैदा हुई पूँजीवादी शक्तियों का राज्य के अधिकतम कल्याण के लिये प्रयोग करना यह स्नायु-केन्द्र [commanding heights] थे—मुख्य बड़े उद्योग, साख, नुद्रा, यातायात और कर-प्रणाली। पूँजीवाद के घृणित दानव की पुनरावृत्ति करने का कारण समझने के लिये एक तर्कात्मक विवाद उत्पन्न हुआ। किसान और मजदूरों का आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ बनाने के लिये व्यापार की आवश्यकता थी जिससे उनका उत्पादन एक-दूसरे के उपभोग में काम आ सके। व्यापार की वृद्धि निर्भर करती थी अधिक उत्पादन पर। कृषि और उद्योग-में पूरी तरह अधिक उत्पादन के लिये कुशलता और मशीनों का अभाव दूर करना पहला कदम था। धन, श्रम, कच्चा माल और माँग सब कुछ होते हुए भी कुशलता न होने से इनका उचित प्रयोग असम्भव था। यह कुशलता देशी, किन्तु अधिकतर विदेशी, साधनों से ही मिल सकती थी। इनको पुनः जागृत करने का एकमात्र उपाय काम का आकर्षक वातावरण उपस्थित करना था। वह वातावरण बिना पूँजीवाद के आह्वान के दुर्लभ था। पुनः निमंत्रित पूँजीवादी शक्तियाँ निरंकुश न हो जायें इसलिये स्थान-स्थान पर उनको संयोजित करने का प्रबन्ध किया गया।

नवीन आर्थिक नीति के बारे में एक उल्लेखनीय बात है कि यह एक पूर्वनिश्चित, विधिपूर्वक निर्मित, आर्थिक नीति नहीं थी। देश के बदलते हुए चित्र के साथ इसका

रूप और गुण बराबर बदलता रहा। इतना ही नहीं किसी समय भी यह नीति तथा इसके सिद्धान्त न तो स्थिर रहे और न उनको स्थायी जड़े पकड़ने का अवसर दिया गया।

1921 में राज्य-शक्ति पर अच्छी तरह अधिपत्य स्थापित करने के बाद नये राज्य की नीति में परिवर्तन आवश्यक हो गया। जैसे ही विदेशी हस्तक्षेप का दबाव, देश की अराजकता व असंगठन, बोल्शेविक विरोधियों का दमन तथा विदेशी आक्रमण से छुटकारा हुआ, लेनिन ने साम्यवाद का भी परित्याग कर दिया। यही कारण है कि इस काल को आर्थिक पराजय कहते हैं क्योंकि इस समय शासन के सिद्धान्त रूप में तो साम्यवाद बना रहा लेकिन व्यावहारिकता में उससे बचने का उपाय किया गया। 1921 मार्च के बाद से लगभग 1924 के अंत तक रूस में साम्यवादी पाये जाते थे, साम्यवाद नहीं। सच पूछा जाय तो विशुद्ध साम्यवाद का इसी समय से जो अंत हुआ वह फिर कभी पुनर्जायित न हो सका। राजनैतिक शक्ति, ब्रह्मकार, विदेशी व्यापार, बैंक तथा यातायात राजकीय एकाधिकार में बने रहे। लेकिन और सभी क्षेत्रों में काफी गम्भीर परिवर्तन हुए जिसको 'साम्यवाद की पराजय' के नाम से अनेकों विद्वानों ने पुकारा है। राष्ट्रीयकरण के बाद जनता द्वारा औद्योगिक प्रबन्ध का स्थान राजकीय ट्रस्टों ने ले लिया। भारी टैक्स देने के बाद अनाज बाजार में बेचने की स्वतंत्रता किसानों को मिली, ट्रस्ट एवं व्यक्तियों को कारखाने वापस कर दिये गये, व्यक्तिगत व्यापार को छूट मिली किन्तु इसका रूप अस्थायी बना रहा; सरकार उत्सुकता से पूँजीवादी देशों की ओर बढ़ी कि उनसे स्थायी राज्य-शक्ति की स्थापना में सहायता ली जाय। विरोधाभास [Paradox] के इस युग में पूँजीवादी संसार से मित्रता का प्रयत्न और युद्ध की धमकियाँ, विश्व-साम्यवाद की नीति और देश में पूँजीवादियों को छूट एक साथ मिलती थी। इस नीतिपरिवर्तन ने अनेकों पुराने साम्यवादियों में भार असंतोष पैदा किया। किन्तु पूँजीवादी देशों में लाभ की लालच से प्रेरित होकर इसका स्वागत हुआ। लोग जानते थे कि यह छूट स्थायी नहीं थी फिर भी 1921 में इंग्लैंड, 1922 में जर्मनी व नार्वे तथा 1924 में अधिकतर योरोपीय राष्ट्रों ने रूस से व्यापारिक संधियाँ की। प्रथम साम्यवादी राष्ट्र की स्थापना के तीन वर्षों बाद ही मूल-विरोधियों से इस प्रकार सहयोग पाना, रूस की विजय नहीं, हार मानी जाती है। कारण यह है कि इस सहयोग का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा अर्थात् साम्यवाद के सिद्धान्तों में परिवर्तन किया गया। अनेक विचारक इसको 'सैद्धान्तिक हार' [Ideological failure] का नाम देते हैं।

लेनिन के विचार से सिद्धान्त व्यवहारिक लक्ष्य प्राप्ति के निर्देशक होते हैं। वे कभी भी निर्णायक नहीं हो सकते। अगर परिस्थितियाँ विपरीत थीं और उनसे निकलने का एक मात्र उपाय सिद्धान्तों में अस्थायी संशोधन था, तो इसे स्वीकार करना न तो साम्यवादी दल का पतन था और न साम्यवाद की हार। यह केवल देश की विध्वस्त

अर्थ-व्यवस्था के पुनरुद्धार का तत्कालिक निदान था । इस नीति ने सिद्धान्तों के मूल-धार में परिवर्तन नहीं किया । केवल उसका विस्तार [detail] बदल दिया । राज्य की श्रेष्ठता, प्राथमिकता और अधिकार में बिना परिवर्तन किये, अपनी विवशता से हारकर, पूँजीवादियों से सुलह कर लेना उनके बुद्धि का संकेत था । इस सुलह को आर्थिक परा-जय या सैद्धान्तिक हार न कह कर 'दूसरा क्षणिक विश्रामकाल' [second breathing space] कहना अधिक उचित होगा क्योंकि इस समय अपकर्ष का क्रम [trend of degeneration] रोक कर इस नीति ने सरकार को सम्हलने का अवसर दिया । एक बार पैर जम जाने पर इस सहारे की कोई आवश्यकता न रही । ठीक इसी तरह मार्च 1918 में लेनिन ने ब्रेस्ट-लीटोवस्क की संधि से शान्ति खरीद कर साम्यवाद की जड़ें जमाने का अवकाश पाया था । नीति की सफलता तथा भविष्य में समाजवादी सिद्धान्तों की स्थापना की प्रगति यह सिद्ध करती है कि नवीन आर्थिक नीति जटिल समस्याओं से परिपूर्ण, विनाशकारी गम्भीर परिस्थितियों से निकलने का केवल एक साधन था जिसमें स्थायित्व [permanence] लाने का आरम्भ से ही कोई प्रयास नहीं किया गया । सकटकालीन स्थिति से बचने का यह उपाय पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों ने साम्यवाद के नाश का आरम्भ समझा जो शीघ्र ही उनकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई ।

नवीन आर्थिक नीति के अध्ययन के पहले समकालीन राजनैतिक रंग-मंच पर दृष्टिपात कर लेना असंगत न होगा । लेनिन के जीवन काल में उसके नेतृत्व और विचारों को सार्वमान्यता ही नहीं सर्वभौमिकता प्राप्त थी । उसके प्रमुख साथियों में ट्राट्स्की, बुखारिन, केमेनीव, जिनोवीव और स्टालिन थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग के अनूठे, साम्यवाद के सिद्ध योद्धा थे । इनमें से स्टालिन सबसे कम उम्र का कार्यकर्ता था । आरम्भ में इसका मुख्य कार्य पार्टी के लिये सरकारी खजानों पर छाप मार कर धन प्राप्त करना था । इस कार्य में अद्भुत साहस और विलक्षण सगठन शक्ति का परिचय मिला । यह जर्मनिया-वासी नवयुवक शान्त, तीव्र बुद्धि, कोरे सिद्धान्तों से दूर रहने वाला, देश निर्माण का कर्मठ सेनानी और राजनैतिक दावपेच का अद्वितीय ज्ञाता था । 1922 में यह साम्यवादी दल का सचिव [Secretary] चुना गया । लेनिन की मृत्यु के समय [1924] केन्द्रीय महासमिति अथवा पोलित-ब्यूरो में सात सदस्य थे जिनमें से केवल स्टालिन ही पक्का रूसी था अर्थात् इसके खून और शिश्ना में विदेशी मिश्रण का सम्पर्क बिल्कुल नहीं था । लेनिन के मरने पर रेकोव प्रधानमंत्री बना लेकिन शासन की बागडोर स्टालिन केमेनीव और जिनोवीव के हाथ रही । अपने पुराने साथी ट्राट्स्की से लेनिन का मतभेद उस समय तक काफी बड़ा रूप ले चुका था । लेनिन के जाने ही शक्ति प्राप्त करने की अपनी योजना को स्टालिन ने कार्यान्वित करना शुरू कर दिया । सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी ट्राट्स्की से स्टालिन का मतभेद अत्यन्त बुनियादी था ।

ट्रास्टकी के अनुसार पूर्ण औद्योगीकरण और जगत-साम्यवाद रूस का मुख्य ध्येय होना चाहिये था : स्टालिन केवल रूस में साम्यवाद और सबसे पहले किसानों के साम्यवादी संगठन का पोषक था। एक-एक करके 1929 तक यह सभी व्यक्ति स्टालिन के विकराल चक्रव्यूह में फँस कर नकशे से हट गये। मोलोटोव के प्रधान मन्त्रित्व में काम्सोमाल [साम्यवादी युवक संघ] के शक्तिशाली सहयोग से इस समय तक स्टालिन रूस का भाग्यविधाता बन गया। “सामुदायिक खेती”, “औद्योगीकरण से शक्ति संचय” “विदेशी आक्रमण से आत्म-रक्षा” का नारा सभी वर्ग के व्यक्तियों को प्रिय लगा [अथवा लगना पड़ा]। मय की उत्तेजक मनोवैज्ञानिक प्रेरणाशक्ति से प्रभावित समाज स्टालिन के हाथों में गीली मिट्टी के समान आ गया जिससे इस महान दृसंस विचारक ने नये रूसी राष्ट्र का मनचाहा निर्माण किया।

## देशी व्यापार

युद्धकालीन साम्यवाद के अनुभव से सोवियत नेताओं को यह ज्ञान हुआ कि देश की कठिन उत्पादन समस्या को जटिल बनाने में प्रमुख कारण व्यापार प्रणाली का भंग होना है। व्यापार के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न अभाव और असंतोष को दूर करने के लिये देशी व्यापार में व्यक्तिगत व्यापारियों को, अपनी पूँजी लगाकर, लाभ के लिये व्यापार करने की छूट दी गयी। इस प्रकार पूँजीवादी गुणों का सोवियत रूस में समावेश हुआ। चारों तरफ इस छूट से साम्यवादी पराजय की धारणा स्थापित हुई। पूँजीवादियों का यह निराधार दिवास्वप्न चन्द वर्षों में ही भंग हो गया। देश बँधी हुई गति से निरंतर समाजवादी पथ पर बढ़ता रहा। व्यापार सम्बन्धी पूँजीवादी कार्यक्रम के पीछे कितना कठोर और संयमित नियन्त्रण था, यह आरम्भ में पार्श्वतः आशावादियों को पता न चला।

इस काल में व्यापार को राज्य एवं निजी क्षेत्र में बाँटा जा सकता है। राजकीय व्यापार संगठन का दो मुख्य रूप था। तोगो [Torg] उसके व्यापारिक संगठन का नाम था जिसे क्षेत्रीय आर्थिक समितियाँ [Regional Councils of National Economy] अपने व्यापार विभाग की तरह चलाती थी। इनका कार्यक्षेत्र स्थानीय उत्पादन तक सीमित था किन्तु आशिक रूप से राष्ट्रीय उद्योगों के उत्पादन को भी यह वितरित करते थे। दूसरा रूप 1922 में सामने आया जिसे सिण्डिकेट [Syndicate] कहते हैं। प्रमुख औद्योगिक संघों [Industrial Trusts] ने आपसी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिये इनका निर्माण किया था। शीघ्र ही यह राजकीय उद्योगों का थोक व्यापार केन्द्र बन गया। माल को फुटकर बाजार तक पहुँचाने के लिये इनके माध्यम थे—व्यक्तिगत व्यापारी, सहकारी समितियाँ और तोगी संगठन। इस प्रकार राजकीय व्यापार



क्षेत्र थोक व्यापार से सम्बन्धित था। फुटकर विक्रय व्यक्तिगत हाथों में बना रहा; 1922-23 में कुल व्यापारिक संचालन का अनुपात था : व्यक्तिगत व्यापार 75.3%, राज्य 14.4% और सहकारी समितियाँ 10.3%।

हो सकता है कि नवीन आर्थिक नीति के काल में व्यक्तिगत व्यापार का अस्तित्व और दृढ़ता के साथ बना रहना, यदि 1922-23 में एक अप्रत्याशित आर्थिक संकट न उत्पन्न हुआ होता। यह आर्थिक-संकट औद्योगिक और कृषि उत्पादन के मूल्यों में भयंकर असंतुलन से पैदा हुआ। युद्धकाल से ही वस्तुओं का मूल्य लगातार बढ़ रहा था। संकट उस समय सामने आया जब मूल्य की वृद्धि ने पक्षपात दिखलाना आरम्भ किया। लगभग 1922 तक औद्योगिक मूल्य में पतन के साथ कृषि क्षेत्र में दाम बहुत बढ़ा। किसानों के पक्ष में मूल्य की इस गति का पूर्ण स्वागत ग्रामीण क्षेत्रों ने किया। उसके बाद ही कृषि उत्पादन का मूल्य गिरने लगा। औद्योगिक सामान इतना महँगा हो गया कि किसानों के लिये उनका उपयोग असम्भव हो गया।

व्यापार का संतुलन ग्रामीण जनता के विपरीत होता रहा। औद्योगिक और कृषि उत्पादन के मूल्यों का यह परिवर्तन यदि ग्राफ पर अंकित किया जाय तो एक खुली हुई कैची का रेखा-चित्र बन जायगा। इसी से इस संकट का नामकरण कैची-संकट [Scissors-Crisis] हुआ। अक्टूबर 1923 तक इस संकट की चरम सीमा पहुँच चुकी थी। थोक मूल्य के निर्देशांक के अनुसार, 1913 को 1,000 मान लेने पर, इस समय कृषि उत्पादन 888 और औद्योगिक उत्पादन 2,717 था। वास्तविकता में परिस्थिति इससे भी खराब रही होगी क्योंकि किसान के लिये औद्योगिक थोक मूल्य निरर्थक होता है। उसे तो गाँवों में प्राप्त फुटकर मूल्य चुकाना पड़ता है। स्वभावतया यह मंडी के थोक भाव से काफी अधिक होता है। इसके विपरीत केन्द्रीय, एकाधिकार प्राप्त, क्रय-संगठन किसानों से बहुत बड़ी मात्रा में थोक के भाव की खरीददारी करते थे।

इस संकट के अनेकों कारण अलग-अलग व्यक्तियों ने दिया है। कैल्विन हूवर<sup>1</sup> तथा मौरिस डोब<sup>2</sup> ने विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। समकालीन आर्थिक साहित्य में इस पर घोर विवाद हुआ। राजनैतिक प्रभाव और आर्थिक धाराओं से प्रथक यदि इनके कारणों को देखा जाय तो उनको सरल रूप में रखा जा सकता है। औद्योगिक मूल्य-वृद्धि अनेकों कारणों का असर थी। स्थापित उत्पादन शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा था, जिससे उत्पादन की प्रति इकाई पर खर्चा अधिक पड़ता था। अनुभवहीन तथा पेचीदी

<sup>1</sup> Calvin B. Hoover, *Economic Life of Soviet Russia* p. 47, 77.

<sup>2</sup> Maurice Dobb, *Soviet Economic Development since 1917*. Chapter Seven.

प्रबंध-व्यवस्था लागत को बढ़ाने में पूरा सहयोग देती थी। एक ओर तो लागत में वृद्धि हुई और दूसरी ओर एकाधिकारप्राप्त बड़े-बड़े सरकारी उद्योगों ने ऊँचा मूल्य निर्धारण करने की नीति अपनाई। 'लाम के निये उत्पादन' का सिद्धान्त स्वीकृत हो चुका था। राजकीय उत्पादकों में ज्यादा लाभ कमाने की हवा-सी लग गई। इस लाभ से वे सभी अपनी कार्यशील पूँजी [Working capital] की कमी दूर करके आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। युद्धकालीन हानि की पूर्ति करने का प्रयत्न भी हुआ। इनके अतिरिक्त फुटकर व्यापारियों ने अपनी ओर से माल को रोककर अधिक-से-अधिक धन कमाने की पूरी कोशिश की।

इसी प्रकार कृषि-क्षेत्र में मूल्य का गिरना कुछ बहुत सौधे-सादे कारणों का प्रभाव था। सोवियत संगठन के साथ कृषि के तरीके में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। परिश्रम और पशु उस समय तक कृषि के आधार थे। यह युद्ध के बुरे प्रभावों से पुन-निर्माण करने में कृषि को उद्योग से अधिक सहूलियत थी। जितनी जल्दी कृषि उत्पादन बढ़ निकला वह उद्योग के लिये असंभव था। इसके साथ इस समय तक यूरोप के अन्न भंडार का स्थान रूस ने पुनः प्राप्त नहीं किया था। देशी बाजारों में अनाज की पूर्ति की मात्रा अधिक थी। अधिक पूर्ति के साथ मूल्य बढ़ाने में किसानों पर कुछ और स्का-वटे भी रही। किसानों से सरकार दर सुगतान अनाज में लेती थी। इसके बेचने का जो मूल्य राज्य निर्धारित करता, उससे अधिक मूल्य किसान खुले बाजार में अपनी बची हुई फसल का नहीं माँग सकता था। व्यक्तिगत किसान की मोलभाव करने की ताकत उस समय नष्ट-प्राय हो जाती थी, जब विशाल संगठित राजकीय संस्थाएँ उनकी एकमात्र खरीददार थीं। आवश्यकताओं का दबाव इतना अधिक था कि किसी भी मूल्य पर जल्दी से-जल्दी फसल को बेचना पड़ता था।

इस संकट के विपाक प्रभाव ने औद्योगिक उत्पादन को निर्जीव बना दिया। सदा से गरीबी व अभाव के अभ्यस्त किसानों के औद्योगिक माल की माँग में अत्यंत लोच था। इस मूल्यवृद्धि से हार कर पौरन ही किसान ने अपनी खपत घटा दी और यह उद्योग से आवश्यकताओं की पूर्ति आरम्भ कर दी। इसका दोहरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक माँग में कमी आ गयी। साथ-ही-साथ किसानों ने अनाज और कच्चा माल बेचना भी बंद कर दिया क्योंकि इतने गिरे हुए मूल्य पर उत्पादन बेचना बेकार था, जबकि उपभोग की निर्मित वस्तुएँ उनके क्षमता से बाहर ही बनी रहती थी। इस परिस्थिति में सम्पूर्ण सोवियत ढाँचे का विनाश निश्चित था। इस कैँची को बंद करना आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से अनिवार्य हो गया। अत्यावश्यक उत्पादन की वृद्धि पर लोक-कल्याण आधारित था और किसान मजदूरों के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध पर समाजवाद की नींव थी। यह संकट इन दोनों को मिटा देने के लिये काफी था। संकट का उत्तर-

दायित्व व्यक्तिगत व्यापारियों की पूँजीवादी प्रवृत्ति पर डाल कर सोवियत नेताओं ने अपनी जान बचाई। देशी व्यापार में व्यक्तिगत व्यापारी के भाग्य का निर्णय साम्यवादी दल के तेरहवें अधिवेशन [1924] में किया गया।

यह निश्चय हुआ कि व्यक्तिगत व्यापार को सीमित करके राज्य और सहकारी व्यापारिक माध्यम अपनाया जाय। औद्योगिक मूल्य में कमी और कृषि-मूल्य को बढ़ाने में राज्य प्रयत्नशील हो। कृषि उत्पादन के व्यापार का केन्द्रीयकरण अनिवार्य है। इसी समय से नई आर्थिक नीति अपने आकर्षक बनावट का परित्याग करके वास्तविक रूप में आ गयी। 1920-23 के सकट के बाद व्यक्तिगत व्यापारी के ऊपर रुकावटें बढ़ने लगी। यह व्यापारी सदा से ही जानते थे कि उनका अस्तित्व स्थायी नहीं है। 1924 से उनको अपने आप क्षेत्र से हट जाने के लिये बाध्य करने का कोई उपाय राज्य ने उठा नहीं रखा। उनके माल का दाम अपने आप ही ज्यादा था क्योंकि कम-से-कम समय में वे अधिक-से-अधिक लाभ उठाने पर तुले हुए थे। फिर राज्य ने उनके विक्रय की लागत हर तरफ से बढ़ाया। कर की ऊँची दर, अधिक किराया और कर्मचारियों को दूसरों से अधिक वेतन देने के नियम से रुकावटें पैदा की गईं।<sup>1</sup> बहुत जल्दी नयी आर्थिक नीति द्वारा पोषित व्यक्तिगत व्यापार केवल बहुत छोटे पैमाने के विनिमय में बाकी बचा जैसे फ़ेरी वाला अपना बहुत छोटा दूकानदार। खेती की अपेक्षा निर्मित वस्तु विनिमय में व्यक्तिगत व्यापार का महत्व बहुत तेजी से घट गया। 1922-23 में कुल फुटकर व्यापार का 75.2% इनके हाथ में था। यह घटकर 1927-1928 में 22.4% रह गया।

कृषि में भी केन्द्रीय राज्य संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अन्न और औद्योगिक फसलों को खरीदने का प्रयत्न हुआ। नीति यह थी कि टैक्स के रूप में दिये जाने वाले अनाज से बची हुई फसल भी राजकीय नियंत्रण में आ जाय। शीघ्र ही किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करके विशाल सरकारी खरीददारों ने 100% कपास, 100% चुकन्दर 98% फ्लेक्स, 98% तम्बाकू, 80% चमड़ा, 92% रोयेदार खाल और 70% ऊन का व्यापार अपने हाथों में कर लिया। अच्छे संचालन और निर्देशन के लिये किसी एक वस्तु में व्यापार करने वाली सरकारी संस्थाओं की संख्या में कमी की गयी। सहूलियत के लिये प्रत्येक मुख्य फसल में व्यापार का एकाधिकार एक ही संस्था को मिला। यह रूप-रेखा सबसे अधिक औद्योगिक फसलों में पायी जाती थी। कठोर मूल्य निर्धारण और अधिक माँग वाले औद्योगिक उत्पादन को बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर लगभग 1928 तक सरकारी तौर पर सकट की समाप्ति घोषित कर दी गयी। फिर भी

<sup>1</sup> Calvin Hoover. Op. Cit. pp. 147-151

कैंची के दोनो फल [Blades] पूरी तरह बढ़ न हुए। व्यापारिक सतुलन किसानों के विपरीत बना रहा। अतः मे स्तालिन ने राशनिंग का सहारा लिया।

## विदेशी व्यापार

यह युद्ध के समय से ही विदेशी व्यापार में राज्य का एकाधिकार था। नवीन आर्थिक नीति के काल में प्रायः सभी आर्थिक क्षेत्र में छूट और सहूलियतें दी गयी थीं किन्तु विदेशी व्यापार के एकाधिकार को छोड़ने के लिये लेनिन और इसका प्रसिद्ध सगठनकर्ता क्रेस्किन एकदम तैयार न थे। सोवियत अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि बिना विदेशी व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण किये अर्थ व्यवस्था की बुनियादी प्रवृत्तियों पर विजय नहीं पाई जा सकती। यह पूर्णतः उचित था। समाजवादी राज्य के एकदम केन्द्रित और आयोजित अर्थप्रणाली से विदेशी व्यापार पूरी तरह हाथ में लिये बिना उन्नति सम्भव नहीं। इस एकाधिकार से अनेकों लाभ रूस को प्राप्त हुए। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के औद्योगिक विकास की रक्षा हुई। ससार के पूँजीवादी, मन्दी और तेजी से आन्तरिक मूल्य-स्तर प्रभावित होने से बच गया। आर्थिक स्थिरता वस्तुतः कठिन होती है परन्तु इस सुरक्षा को पाकर वह और जटिल होने न पाई। अत्यन्त सीमित साधनों का आय व्यय उद्योग और विलासिता की सामग्रियों के आयात में न हुआ। योजना के अनुसार साधनों को केवल विकास के लिये खर्च करना सम्भव हो सका।

सोवियत रूस में विदेशी व्यापार का मुख्य ध्येय आयात-निर्यात से लाभ कमाना नहीं था बल्कि देश की उन्नति में सहायक होना था। इसी से इशारा लेकर इस क्षेत्र की जो रूप-रेखा बनी इसमें देशों माँग और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार-मूल्य का कोई महत्व न था। निर्यात से आयात का भुगतान करना अनिवार्य पाकर उन सभी वस्तुओं की उपलब्धि पर जोर दिया गया जो विदेशों में विक्रि सकती थीं। इतना ही नहीं देशों माँग का कोई ख्याल किये बिना राष्ट्रीय उत्पादन का जितना अंश हो सकता था, निर्यात के लिये सुरक्षित कर दिया जाता। दुनिया के बाजार ने चाहे जो भी भाव रहे, रूस सदा सामान बेचने को तैयार रहता था। हानि उठा कर भी माल बेच कर मशीन खरीदने के लिये देश बाध्य था। इतना त्याग [धन की हानि और देश में वस्तु अभाव] अनाज के निर्यात [export] न होने से करना पड़ा। योरोप का “अन्न भंडार” अब अनाज बेच नहीं पा रहा था। 1913 में अनाज का निर्यात 878.5 मिलियन रूबल से घट कर 1928-29 में कुल 215.7 मिलियन रूबल रह गया।

विदेशी व्यापार का प्रयोग सोवियत सरकार अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी करती थी। माल खरीदने की लालच देकर राजनैतिक मान्यता प्राप्त करने की कोशिश रूस ने कई जगह किया। व्यापारिक मन्दी [1929-31] के कारण पूँजीवादी

देशों में अपना निर्मित-माल न बेच सकने पर बेरोजगारी का सकट प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में हर प्रकार के खरीददार का स्वागत होना स्वाभाविक था। इसी प्रकार पूर्व में, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, मंगोलिया और चीन में पैर जमाने के लिये बड़ी कटौती पर माल बेचकर अंग्रेजों के प्रभुत्व को तोड़ने का प्रयत्न आरम्भ हुआ।

विदेशी व्यापार के संगठन को सरल बनाने का प्रयत्न किया गया। विदेशी व्यापार विभाग [Commissariat of Foreign Trade] के अलग-अलग माध्यम थे। सेंट्रोस्यूज [Centrosyuz] उपभोक्ता सहकारी समितियों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में विदेशी व्यापार करती थी। सेल्स्कोस्यूज [Selskosyuz] कृषि उत्पादन से सम्बन्धित था। इन सहकारी संगठनों के अतिरिक्त विदेशी पूँजी के सहयोग में स्थापित विशेष स्कन्द प्रणाली कम्पनियाँ [Joint stock companies] इस क्षेत्र में लाई गईं। अनुभव और पूँजी की कमी दूर करने के लिये विदेशियों को नियंत्रित किया गया था किन्तु इसमें आशातीत सफलता न मिली।

1925 तक यह अनुभव होने लगा कि देशी और विदेशी व्यापार में समतुलन और सामंजस्य आवश्यक है। इसलिये विदेशी और अतर्देशीय व्यापार विभाग को आपस में मिलाकर एक व्यापार विभाग अथवा नारकमतोर्ग [Commissariat of Trade or Narkomtorg] की स्थापना की गई। जिन देशों से रूस का राजनीतिक सम्बन्ध था वहाँ पर दूतावास का व्यापार प्रतिनिधि मंडल सोवियत संघ के प्रतिनिधि के रूप में व्यापार करता था। जिन देशों के साथ राजनैतिक सम्बन्ध नहीं था वहाँ पर एक कम्पनी इस काम के लिये बनाई जाती थी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्मटोर्ग और इंग्लैंड में आरकौस, नारकमतोर्ग के व्यापारिक प्रतिनिधि थे। निर्यात को उत्साहित करने के लिये कर में भी छूट दी गयी थी। फिर भी अगर देश के बाहर माल बेचने में हानि हो तो इसे नारकमतोर्ग स्वयं सहन करता था।

### मुद्रा बैंकिंग और बजट

नवीन आर्थिक नीति के युग में जितना परिवर्तन और छूट अर्थव्यवस्था के अन्य विभागों में पाया जाता है उसका लेशमात्र भी मुद्रा बैंकिंग और बजट में नहीं मिलता। जैसा कि लेंनिन ने शुरू में ही कहा था कि पूँजीवाद के आगमन से कोई साम्यवाद को कोई हानि नहीं पहुँचेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था के मुख्य केन्द्रों [Commanding Heights] के पूर्ण राजकीय नियंत्रण की सहायता से प्रत्येक अनुचित अर्थ लाभ की प्रवृत्ति को सीमित किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च स्थान मुद्रा, बैंकिंग और बजट को दिया गया था।

मुद्रा के प्रति साम्यवादियों का पुराना विरोध था। इनके विचार से आदर्श साम्यवादी समाज में मुद्रा और उससे उत्पन्न शोषण का कोई स्थान नहीं हो सकता।

एक मुद्रा विहीन समाज की स्थापना का ध्येय लेकर 1917-21 के बीच जितने भी प्रयास किये गये थे उनको और परिष्कृत रूप में नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत लागू किया गया। मुद्रा का सबसे बड़ा गुण—क्रयशक्ति—अव राशन कार्ड और सहकारी समिति की सदस्यता के प्रमाण-पत्र के बिना एक अर्थहीन वस्तु थी। नये सामाजिक संगठन में क्रय-शक्ति छिन जाने के बाद मुद्रा का दो ही काम रह गया—लेखा की इकाई [Unit of Accounts] और मूल्य मापन का साधन [Standard of Value]। विनिमय के माध्यम की क्रिया को अधिक-से-अधिक सीमित कर दिया गया। वास्तविकता में बहुत छोटे फुटकर विनिमय तक ही मुद्रा का प्रयोग बाँध देने की कोशिश हुई। यह काम इतनी अधिक सफलता से किया गया कि 1928 तक पूँजीवादी दृष्टि से वह स्थिति पैदा हुई जबकि मुद्रा रहते हुए भी उसका खर्च करना असम्भव हो गया। परिणामस्वरूप जनता की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हुआ। मुद्रा का अपार आकर्षण और इसके प्राप्ति की असीम लालसा भी कम हो गई क्योंकि सोवियत सरकार ने मुद्रा और आवश्यकतापूर्ति का संबंध विच्छेद कर दिया था। औद्योगिक वित्त [Industrial Finance] में भी मुद्रा ने प्राथमिकता खो दी। पूँजी निर्माण में मुद्रा का स्थान बैंक साख, उसकी मात्रा और गति [Amount and velocity] ने ले लिया। मुद्रा के पदच्युत होने का क्रम 1924 के चलन सुधार [currency reform] के बाद तेजी के साथ आरम्भ हुआ और 1930 के सुधारों से पूरी तरह स्थापित हो गया।

युद्धकालीन साम्यवाद में उद्योग के प्रत्येक कारखाने को स्थायी और चालू पूँजी राजकीय वजत से मिलती थी। इससे बैंक और साख का महत्व प्रायः लुप्त हो चुका था। आर्थिक नीति में पूँजीवादी उत्पादन से बैंकों का पुनरुद्धार अनिवार्य हो गया। यह युद्ध में मुद्रा का मूल्य इतना घटा दिया गया था कि अर्थव्यवस्था के संचालन में भीषण कठिनाई उत्पन्न हुई। इसीलिये नवीन आर्थिक नीति का निर्णय करते ही सबसे पहले गौस बैंक अथवा केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गयी। यह वित्त मंत्रालय [Commissariat of Finance] के अन्तर्गत काम करता था। गौस बैंक की संचालक समिति का सभापति वित्त मंत्रालय ही नियुक्त करता था। 1929 में बैंक को मंत्रालय से एकदम स्वतंत्र कर दिया गया किन्तु राज्य और बैंक की घनिष्ठता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गौस बैंक कभी भी पुराने बैंकिंग सिद्धान्तों का पोषक नहीं रहा। सरकारी नीति और योजना में बैंक इस प्रकार लिप्त था कि उनकी सहायता करने के मार्ग से पुराने बैंकिंग सिद्धांत और प्रथाएँ हटा दी गयीं। उचित-अनुचित का अवरोध हट जाने से बैंक राष्ट्र भी उन्नति का रक्षक, पोषक और पालक सब कुछ बन गया। केन्द्रीय बैंक राज्य की अर्थ और साख व्यवस्था का मूलाधार था। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की दूसरी संस्थाएँ बैंक के सहायक या प्रतिनिधि के रूप में ही काम कर सकती थीं।

गौस बैंक के क्रियाओं में इतनी व्यापकता पाई जाती है कि इसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर आर्थिक ढाँचे का कोई भी अंग नहीं रह सकता। सबसे पहला ध्यान एक स्थिर मुद्रा प्रणाली को ओर दिया गया। सोवियत राज्य द्वारा चलाई हुई पत्र मुद्रा का असाधारण विघटन हो चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी नोटों के पीछे किसी प्रकार के सचित कोप का सहारा न होना था। किन्तु गौस बैंक द्वारा चलाई गयी पत्रमुद्रा—सेरवास [Chevonetz]—100% कोष द्वारा सुरक्षित था। पुराने नोट—सोव्जनाक [Sovznak]—से इसका सन्ध 10 : १ का था। इसको स्थायी बना रखने का पूरा प्रयत्न किया गया। जनवरी 1923 में कुल चलित मुद्रा का ३% सेरवास और 97% सोव्जनाक नोट थे। अक्टूबर 1923 तक पुराने नोट 25% और नये नोट 75% हो गये। इन नये नोटों और गौस बैंक के प्रयत्नों से शीघ्र ही मुद्रा में स्थिरता आनी आरम्भ हुई। सरकार के वित्तीय कार्यक्रम की देख-रेख और सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना-खरीदना इसी के जिम्मे था। बैंक के सगठन और कार्यक्रम में विचित्र आपसदारी पाई जाती है। इसकी शाखाओं का जाल केवल अपने स्वार्थों की सेवा न करके औद्योगिक और कृषि बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता था। किसी स्थान पर एक से अधिक शाखा खोलने का अपव्यय बचाने के लिये गौस बैंक दूसरे बैंकों को अपनी शाखाओं के माध्यम से काम करने की अनुमति देता था। साख नियंत्रण नीति में पूँजीवादी बैंकों के अप्रत्यक्ष नियंत्रणों का रूस में प्रयोग नहीं होता। वहाँ तो केन्द्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से साख की राशनिग का सहारा लेता है। बैंक का योजना विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सगठन है। इस विभाग का काम योजना के आर्थिक अंग पर विशेष सलाह देना है।

गौस बैंक उद्योग और व्यापार से बहुत निकट संबन्ध रखता है। प्रत्येक मुख्य उद्योग के लिये बैंक में पृथक विभाग बना है। इस विभाग के संचालन में बैंक उद्योगों को साख देने के साथ धन के उचित प्रयोग और योजना के अनुसार व्यय का निरीक्षण भी करता है। यह सद्गुणित अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है और उद्योगों के नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली और सरल साधन। प्रत्येक विभाग संबन्धित उद्योग की योजना बनाने में सक्रिय सहयोग देता है। इस आर्थिक सहयोग में लाभ, स्थिरता और तरलता के स्थान पर साख-योग्यता [Credit-worthiness] का माप एकमात्र योजना पूर्ति है। इस अर्द्धित बैंकिंग प्रणाली से हानि की संभावना का डर इसलिये नहीं रहता कि राज्य क्षतिपूर्ति के लिये सदा तत्पर रहता है। इस प्रकार उन्नति के मार्ग पर से पूँजी व साख की कमी का अवरोध गौस बैंक ने एकदम हटा दिया। पूँजीवाद की क्रूर स्वामिनी, पूँजी, साम्यवाद में आज्ञाकारिणी सेविका बन गई।

साम्यवाद में विनिमय के लिये मुद्रा का प्रयोग एक अपवाद माना गया है। इस राजकीय नीति का पालन करते हुए गौस बैंक ने विनिमय में मुद्रा का प्रयोग घटाने

में दृढ़ता पूर्वक नये तरीकों को अपनाया। तर्क यह था कि सभी संपत्ति, पूँजी और उत्पादन राज्य का है। इसलिये राज्य के कार्यवाही के विभिन्न अंग पृथक् इकाइयों की तरह आपसी व्यवहार क्यों करे? पारस्परिक संबंध और विनिमय को सरलतम बनाने में गौस बैङ्क ने सहारा दिया। प्रत्येक उत्पादन की इकाई [कारखाना] बैङ्क के पास अपना खाता रखती थी जिसमें सभी साधनों से प्राप्ति और सभी को देना अंकित किया जाता था। बैङ्क अको के हस्तांतरण से इन दूर-दूर फैले हुये उत्पादन केन्द्रों का आपसी भुगतान बिना मुद्रा-प्रयोग के कर देता।

जहाँ तक बजट का सम्बन्ध है नवीन आर्थिक नीति के आरम्भ में व्यय आय का छुः गुना हो चुका था। बजट का घाटा 1918 में 31,126 मिलियन से बढ़ कर 1921 में 20,332,000 मिलियन रुबल हो गया था। उस घाटे की पूर्ति नोट छापकर की गई। मुद्रास्फीति से पीड़ित देश की सहायता घाटे के बजट को बदले बिना करना असम्भव था। खर्च को कम करने के लिये अनेकों साधन खोजे गये। युद्ध की समाप्ति से इस और अग्रसर होना सम्भव हो सका। सरकारी व्यय के प्रत्येक भाग में बचत, अपव्यय को हटाना और अधिकतम धन के उपयोग के लिये कड़े निरीक्षण की योजनाएँ बनाई गयीं। साथ ही साथ स्थानीय सरकारों की अर्थव्यवस्थाओं को केन्द्रीय सरकार से अलग कर दिया गया। इस प्रकार उन्हें लाचार किया गया कि वे अपने साधनों के अन्दर ही काम करे। आय की वृद्धि के लिए कृषि पर लगे हुए कई करों को मिला दिया गया जिससे वसूली आसान और कम खर्च में हो जाय। 1924 में इस दिशा में खास सुधार हुए। वस्तु में लिये जाने वाले कर मुद्रा में बदल दिये गये और 1917 के पहले के कई प्रचलित कर बन्द कर दिये गये। साम्यवादी दल के ग्यारहवें अधिवेशन [मार्च/अप्रैल 1922] में कर नीति निर्धारित की गयी जिसके अनुसार कर व्यवस्था के दो उद्देश्य निश्चित हुए। प्रथम, साम्यवाद की स्थापना में मदद करना और द्वितीय, अधिक से अधिक धन उपलब्ध करना। कर के अतिरिक्त राज्य ने ऋण का सहारा भी लिया। आरम्भ में [1922] दो ऋण राज्य सरकार ने लिये जिन्हें मुद्रा के स्थान पर वस्तु में [अनाज और चीनी] में वसूला गया। पहला मुद्रा-ऋण भी इसी वर्ष चालू हुआ किन्तु राजकीय आय के चित्र में कर और ऋण का महत्वपूर्ण स्थान न बन पाया। 1922 में कुल आय का 2.7% कर से, 10.6% राजकीय उद्योग तथा संपत्ति से और 86.7% मुद्रा प्रसार से आया।<sup>1</sup> परिस्थिति पर काबू पाने की कोशिशों का परिणाम यह हुआ कि घाटे की पूर्ति में नोट छापने का सहारा कम हो गया। एक वर्ष के अन्दर [अक्टूबर-दिसम्बर 1923] आय का कुल 41% भाग नोट छाप कर प्राप्त किया गया<sup>2</sup>।

1. Cited in Baykov, Op. Cit., p 82

2. Arnold Op Cit, p 192



## कृषि

नवीन आर्थिक नीति के सामान्य उद्देश्य के अनुसार कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि को लक्ष्य बनाया गया। 1920-21 के अकाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनाज और कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाये बिना देश का उद्योगीकरण और प्रगति सम्भव नहीं। बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र और विशाल लाल सेना का भोजन प्राप्त करना राज्य की जिम्मेदारी थी। अनाज के निर्यात के बदले में मशीन मँगाने की आवश्यकता गम्भीर रूप धारण कर रही थी। इन समस्याओं के अतिरिक्त कई और बाते परिस्थिति में उलभन पैदा करती थी। ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक विभाजन ऐसा था जिसमें उत्पादन वृद्धि, विशेषकर बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन [Surplus production for market] का एकमात्र उपाय सोवियत राज्य के बुनियादी सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ता था। गरीब किसान अधिकतर स्वयं उपभोक्ता थे और मध्यम वर्ग के पास बड़े पैमाने की विस्तृत खेती करने का साधन न था। बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकताएँ और अनुभव केवल समृद्ध किसानों के पास मिलता था। लेनिन के विचारों से यह वर्ग पूँजीवाद का गढ़ [Stronghold of Capitalists] था। उद्योग की तरह इनको भी पूँजीवादी छूट देकर अधिक उत्पादन के लिये प्रेरित किया जा सकता था। किन्तु इन पर निकट निरीक्षण और सफल संचालन बड़ी संख्या और बिखरेपन के कारण सम्भव न था। युद्धकालीन साम्यवाद के समय विचारहीन रूप से भूमि का पुनः वितरण [Redistribution] होने से ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादन शक्ति को ज्यादा धक्का पहुँचा था। लोगों ने लालच में अपने साधनों से अधिक भूमि पर कब्जा तो कर लिया लेकिन खेती न कर सके। इन समस्याओं के अतिरिक्त भूस्वामी के पूर्ण संचालन में काम करने के अभ्यस्त रूसी किसान, स्वतंत्र रूप से कुशलतापूर्वक उत्पादन कार्य को चलाने में असमर्थ थे।

इन समस्याओं की जटिलता से प्रेरित होकर नवीन आर्थिक कार्यक्रम में कृषि नीति का सम्पादन हुआ। ईस क्षेत्र की नीति भूमि का राष्ट्रीयकरण [जो पहले हो चुका था] और सामुदायिक खेती थी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। सोवियत नेता यह मानते थे कि वर्गहीन समाज में किसान वर्ग का कोई स्थान नहीं हो सकता। अन्त में किसानों को उसी प्रकार मिट जाना होगा जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्तालिन ने अमीर किसान अथवा कुलक वर्ग को मिटा दिया था। मजदूर—किसान सहयोग [Smytchka] उस समय का नारा अवश्य था पर उसके अस्थायी होने में कभी सन्देह नहीं रहा। इतना ही नहीं, साम्यवादी रूप-रेखा में पुराने विचारों का स्वतंत्र किसान वर्ग विरोधी प्रतिक्रियाओं का केन्द्र माना जाता है। अतः किसानों के निर्विरोध विकास को सोवियत सरकार नवीन आर्थिक नीति में भी सहन न कर सकी। इससे किसानों की उत्पादन शक्ति के पुनरुत्थान में कठिनाई पड़ी। यह भी पूर्वनिश्चित था कि जैसे ही आर्थिक संकट पर

विजय पाई जा सकेगी किसानों पर दिखाई गयी उदारता फिर से प्रतिबन्धों में जकड़ दी जायगी। कृषि नीति का एक स्पष्ट रूप था कि किसी भी प्रकार अस्थायी छूटों की मदद से, किसानों की माँग को तृप्त करके, उनसे उत्पादन कराया जाय। इस काम में प्रत्येक वर्ग के किसानों की व्यक्तिगत कुशलता और उत्साह का सहारा लिया जाय।

इस नीति के पालन में किसानों को अनेकों सुविधाएँ मिलीं। बलपूर्वक उपज को जब्त करने की नीति को त्यागकर सरकार ने हतोत्साह किसानों को पुनर्जीवन दिया। इसकी जगह पर एक कर लगाया गया जिसकी वसूली आरम्भ में तो वस्तु के रूप में होती थी परन्तु नुद्रा स्थिरता आने पर रूबल में होने लगी। व्यक्तिगत सम्पत्ति के अवैधानिक होने से किसानों में परिश्रम और उत्पादन के प्रति जो उदासीनता आ गयी थी, उसके इलाज के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यापार दोनों की अनुमति मिली। टैक्स देने के बाद बची हुई उपज खुले बाजार में बेची जा सकती थी। उससे प्राप्त धन किसी रूप में व्यय किया जा सकता था। खेतों को छोटे-छोटे टुकड़ों में मनचाहे तरीकों से बाँटना रोक दिया गया। गाँवों में गरीब किसान द्वारा बड़े खेतों का आपस में बँटवारा, क्रान्ति के बाद, रूसी कृषि का अभिशाप बन गया। उसके दूर होते ही जोत की भूमि की मात्रा में स्थिरता आ गई। शान्ति के बाद जब किसान ने देखा कि राज्य चाहता है कि वह अपनी प्रिय सम्पत्ति—भूमि—को भी छोड़ दे, अर्थात् सामुदायिक खेतों में अपने व्यक्तिगत स्वामित्व को डुबा दे, तो उसके निराशा की सीमा न रही। इसका उपचार नवीन आर्थिक नीति में किया गया—उन्हे अपनी भूमि पर इच्छानुसार खेती करने की आशा मिली। दबाव के स्थान पर तरह-तरह की सुविधाओं की लालच देकर समाजवादी खेती की ओर आकर्षित करने का निश्चय किया गया। इस कार्यक्रम ने तुरन्त प्रभाव दिखलाया। अनावृष्टि [Drought] और अकाल का प्रभाव दूर होते ही उत्पादन में तेजी के साथ वृद्धि हुई। कृषि का क्षेत्रफल 1922-23 में 66.2 मिलियन हेक्टर से बढ़कर 1926-27 में 93.7 हो गया। 1913 में यह 94.4 मिलियन हेक्टर था। बीज रखने के बाद उत्पादन 1921-22 में 42.3 मिलियन टन से बढ़कर 1926-27 में 78.3 हो गया। यह 1913 में 80.1 मिलियन टन था।<sup>1</sup> उत्पादन वृद्धि के साथ बाजार में आया अनाज कम होता गया। 1913 में कुल फसल का 20.3% बाजार में बिकने आता था। यह मात्रा घटकर 1924-25 में 14.3%, 1925-26 में 13.2%, 1927-28 में 12.1% और 1928-29 में 11.1 हो गई।<sup>2</sup> इसका मुख्य कारण यह था कि गरीब और मध्यम वर्ग के किसान कुल अनाज का 85.3% पैदा करते थे लेकिन फसल

<sup>1</sup> Hubbard, L. E. Economics of Soviet Agriculture.

<sup>2</sup> Soviet Planning Commission data quoted in Baykov. Op. Cit., p. 136.

का केवल 13% बाजार में बेचते थे। सामुदायिक और राजकीय कृषि का उत्पादन कुल 17% था लेकिन वे अपने उपज का 47 2% बाजार में बेचते थे।<sup>1</sup> इस परिस्थिति ने नवीन आर्थिक नीति के अन्त में फिर से सकट पैदा कर दिया। किसानों ने बाजार के एकमात्र खरीदार राजकीय सस्थाओं को निश्चित मूल्य पर अनाज बेचने से इन्कार कर दिया। यहाँ तक कि सरकारी पजों से अनाज की रक्षा करने के लिये जानवरों को अनाज खिलाकर, उनके मांस को बेचना और अन्न की जगह औद्योगिक फसलों को बोना शुरू किया। परिस्थिति अत्यन्त जटिल थी। अनाज का मूल्य बढ़ाते ही औद्योगिक उत्पादन का मूल्य भी बढ़ जाता। कैची सकट के कारण उस समय अपने आप ही औद्योगिक मूल्य कृषि के अनुपात में इतना अधिक था कि उसमें और वृद्धि करने से जनता में विरोध फैल जाता। इसके अतिरिक्त उपभोग की वस्तुओं के व्यापक अभाव की कठिनाई और भी बढ़ जाती अगर किसानों के हाथ में खर्च करने के लिये अधिक धन आने लगता।<sup>2</sup> सरकार को यह करना कदापि स्वीकार न था इसलिये एक ही उपाय बचा जिसके द्वारा सेवा और मजदूरों के लिये पर्याप्त अन्न मिल सकता—बलपूर्वक छिपाये हुए अनाज को प्राप्त करना। सरकारी मूल्य पर अन्न बेचने से इन्कार करने पर सारी उपज जब्त कर ली जाती थी। इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति के अन्त में किसानों की लगभग वही दशा हो गयी जो क्रान्ति के पहले थी। गरीबी, लाचारी और प्रतिवन्ध में जकड़े हुए किसान को अब यह अनुभव हुआ कि बोलशेविक सरकार उसके प्रति किसी भी रूप में पुराने भूमिामियों से अधिक उदार नहीं थी। साम्यवादी दल अडा हुआ था कि किसानों की यह तुच्छ पूँजीवादी प्रवृत्ति [petty bourgoise mentality] के सामने न झुक जाय। इस दिशा में जो कदम सोवियत सरकार ने उठाये, उसने सम्पूर्ण कृषि संगठन को इस तरह पगु बना दिया कि विकराल दुर्भिक्ष का आगमन अनिवार्य हो गया। इससे प्रभावित होकर कृषि-नीति की जो पुनर्विवेचना हुई, वही प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार बनी।

### उद्योग

अगस्त 1921 में सोवियत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में अपनी भूलों को वैधानिक रूप से स्वीकार किया। जल्दीबाजी में किए गए अनावश्यक राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न अव्यवस्थित संगठन व गिरते हुए उत्पादन को दूर करने का उपाय नवीन आर्थिक नीति के रूप में अवतरित हुआ। उद्योग सम्बन्धी नीति के मुख्य सिद्धान्त बनाये गये। प्रथम, वेसिखा अथवा उच्चतम आर्थिक समिति [Supreme Economic Council] के

<sup>1</sup> Louton Economic History of Soviet Russia, Vol. I, p. 102

<sup>2</sup> Hubbard Op. Cit, pp. 105-110

अन्तर्गत केवल प्रमुख बड़े उद्योग ही रहेंगे। द्वितीय, इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादन केन्द्र सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत उत्पादकों को चलाने के लिये दिये जायेंगे। तृतीय, जितने कारखानों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था उन्हें पुराने भूस्वामियों को वापस कर दिया जायगा। चतुर्थ, सम्पन्न और सुसंगठित राजकीय उद्योगों को बड़े-बड़े औद्योगिक सत्र में बाँटा जाय जिससे उन पर नियन्त्रण तथा संचालन और अच्छी तरह हो सके। इन सिद्धान्तों के अनुसार बड़े पैमाने के प्रमुख उद्योग स्थापित हुए।

उत्पादन वृद्धि की इच्छा से प्रेरित होकर नवीन आर्थिक नीति के औद्योगिक अंग को निर्मित किया गया। इसका मुख्य आधार अराष्ट्रीयकरण [Denationalisation] था। अनावश्यक राष्ट्रीयकरण को मूल-सुधार का वह उपाय था। इसका अर्थ यह नहीं कि बोल्शेविक सरकार ने राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्तों को तिलाजलि दे दिया। प्रमुख बड़े उद्योग, बैंकिंग, वायुयान राज्य के हाथ में रहे जिनके द्वारा सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था पर पूर्ण राजकीय संचालन सम्भव था। इस समय तक परिस्थिति बहुत कुछ सुलभ गयी थी और राजकीय संगठन सबल हो चुका था। अतः नवीन केन्द्रीय निर्देशन के साथ औद्योगिक शासन के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त अपनाया गया। इस पुनर्संगठन द्वारा औद्योगिक मामलों में, खास कर दैनिक शासन में, राजकीय संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने का प्रयत्न किया गया। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और इच्छापूर्ण प्रयत्न औद्योगिक कर्मचारियों में उत्पन्न करने का यह प्रभावशाली उपाय था। कठोर और अप्रिय वास्तविकता को नीति का आधार बनाने का क्रम इस समय से आरम्भ होकर बहुत दिनों तक औद्योगिक प्रबन्ध और संगठन की रूपरेखा में निरंतर परिवर्तन करता रहा। पूँजीवादी उत्पादन के ढाँचे के गुणों की रक्षा करते हुए, इसमें ऐसा रूपान्तर किया गया कि वह आश्चर्यजनक सफलता के साथ समाजवादी केन्द्रीय संचालन में अभिन्न रूप से मिल गया। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाय तो रूसी औद्योगिक संगठन किसी प्रकार पूँजीवादी संगठन से अधिक उलझा हुआ नहीं था। नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत विकसित औद्योगिक संगठन एव प्रबन्ध स्थायी रूप में भविष्य के रूसी उत्पादन की नींव बना रहा।

इस नीति में बड़े और प्रमुख उद्योग राज्यस्वामित्व में रहे। असफल और अनुत्पादक निर्माण केन्द्रों को बन्द कर दिया गया। अविकतर छोटे उद्योग सहकारी समितियों और व्यक्तिगत उत्पादकों को सौंपे गए। राष्ट्रीयकरण से बड़ी मात्रा में निकाल कर छोटे पैमाने के उद्योगों को उनके पुराने मालिकों को लौटा दिया गया। पूँजी, कुशलता और अनुभव प्राप्त करने को विदेशियों को कुछ पुराने उद्योग चलाने तथा नये स्थापित करने के लिये आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, राज्य ने व्यक्तिगत पूँजी के सहयोग में मिश्रित उत्पादन व्यवस्था भी चलाई थी। 1924 में लेनिन की मृत्यु के

बाद इस नीति में सशोधन के समय तक 88.5% उत्पादन संस्थाएँ व्यक्तियों के हाथ में, 8.5% राज्य तथा 3.1% सहकारी समितियों के पास थी। इन आँकड़ों से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि उद्योगपतियों के पुराने सुनहले दिन फिर वापस आ गये थे। कुल मजदूरों का केवल 12.4% उनमें लगा था। व्यक्तिगत उद्योग में वही कारखाने दिये गये जो कम से कम दो और अधिक से अधिक 20 मजदूर रखते थे। इसके विपरीत उपरोक्त सरकारी उद्योगों की संख्या 8.5% होते हुए भी उसमें कुल औद्योगिक श्रम का 84.1% काम करता था।<sup>1</sup>

सफल संगठन और संचालन के लिये राजकीय कारखानों को अलग-अलग औद्योगिक समूह अर्थात् सघ में बाँध दिया गया। इनका उद्देश्य सम्बन्धित कारखानों के उत्पादन का संगठन तथा संचालन, व्यापारिक सिद्धान्तों पर, लाभ प्राप्ति के लिये करना था। 1923 में इनकी स्थापना वैधानिक रूप से हुई। व्यक्तिगत उद्योगपति अपने कारखानों का सघ नहीं बना सकते थे। औद्योगिक संगठन के इस रूप के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की संस्थाएँ भी बनीं जिनको सिएडीकेट कहते थे। राजकीय उद्योगों के व्यापारिक कार्यक्रम के लिये इनको बनाया गया था। अधिकतर सिएडीकेट कई ट्रस्ट द्वारा मिलकर ऐच्छिक संस्थाओं की तरह स्थापित किये गये थे। बाजार से सम्बन्धित और आर्थिक रूप से पुष्ट होने के कारण शीघ्र ही इन सिएडीकेटों ने ट्रस्टों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया।

नवीन आर्थिक नीति के काल में राजकीय उद्योग के शासन के पुनर्संगठन का प्रथम प्रयास नवम्बर 1923 में हुआ। इससे प्राप्त अनुभव की सहायता से जुलाई 1927 में दूसरी कोशिश की गई। इनके द्वारा राजकीय संचालन में व्यापकता और आन्तरिक प्रबन्ध में लोच लाने का उद्देश्य पूरा हुआ। शंका, सन्देह, भय तथा अनुभवहीनता के कारण औद्योगिक संचालन में अनेकों संस्थाएँ आ गयी थी जिससे बड़ी कठिनाई उत्पन्न होने लगी। कुछ सुधारों के द्वारा इनमें कमी की गयी और इनका रूप प्रभावशाली तथा सफल बनाया गया। नीति निर्धारण का काम वेसिखा [Supreme Economic Council] के योग्य हाथों में केन्द्रित कर दिया गया। 1927 में वेसिखा के अधिकार और प्रबल बनाने के लिये ट्रस्ट का उद्देश्य भी बदला। “व्यापारिक सिद्धान्तों पर लाभ प्राप्ति” के स्थान में “व्यापारिक सिद्धान्तों पर योजना के लक्ष्यों की पूर्ति” इनका ध्येय बना। सिएडीकेट का प्रभाव-क्षेत्र स्वतन्त्र बन कर सफल निर्देशन में तनाव पैदा कर रहा था। उसके अधिकारों को सीमित करके सिएडीकेटों को वेसिखा के एक विभाग की तरह पुनर्संगठित किया गया। ट्रस्टों को भी सर्वव्यापी संचालन से हटाकर कारखानों के यात्रिक

संगठन [Technical Organisation] की ओर बढ़ाया गया। 1924 तक ट्रस्ट के अन्तर्गत अलग-अलग कारखानों को अगना पृथक् अस्तित्व नहीं प्राप्त था किंतु अब आम आर्थिक लेखा [general financial statements] तो ट्रस्ट ही तैयार करते थे किंतु इनके कारखाने का हिसाब अलग-अलग रखा जाने लगा। इससे व्यक्तिगत उत्पादन की इकाइयों में वचत और कार्य-कुशलता उत्पन्न हुई। 1927 से कारखानों के आंतरिक प्रबंध में भी सुधार हुआ। प्रबंधक [manager] का अधिकार-क्षेत्र और व्यापक बना। उसे सम्पूर्ण कारखाना प्रबंध का एक मात्र उत्तरदायी ठहराया गया। एक व्यक्ति-प्रबंध औद्योगिक क्षेत्र में वरदान सिद्ध हुआ यद्यपि इसको पूरी तरह से लागू करने में काफी समय लगा।

इन प्रयत्नों का संयुक्त प्रभाव था कि औद्योगिक उत्पादन में अपकर्ष की ओर गति रुक गई। 1922 से ही उत्पादन ने उठना शुरू किया। अनेकों कारणों से यह प्रगति आशातीत तेजी के साथ नहीं आ पाई। खेती ने नवीन आर्थिक नीति आरम्भ होने के चार साल बाद ही 1913 का उत्पादन स्तर प्राप्त कर लिया। किन्तु औद्योगिक उत्पादन के मार्ग में प्रमुख रुकावटें थी—खराब हालत में मशीन, पूँजी की कमी, कुशलता और अनुभव का अभाव, कच्चे माल की कठिन प्राप्ति और औद्योगिक श्रम की बिगड़ी हुई मनोवैज्ञानिक स्थिति। फिर भी उत्साहपूर्ण सक्रिय प्रयत्नों का प्रभाव हुए बिना न रहा। 1926-27 में बड़े उद्योगों का उत्पादन लगभग 1913 के बराबर हो चुका था।

### उत्पादन की प्रगति<sup>1</sup>

वर्ष	मूल्य पर आधारित : मिलियन रूबल में		
	भारी उत्पादन	उपभोग उत्पादन	कुल उत्पादन
1913	4,290	5,961	10,251
1921	814	1,111	1,925
1922	1,090	1,422	2,512
1923	1,785	2,044	3,829
1924	1,959	2,510	4,469
1925	3,121	4,315	7,436
1926	4,304	5,973	10,277
1927	5,372	6,679	12,051

इस उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में दो बातें उल्लेखनीय हैं। मात्रा के साथ-

<sup>1</sup> Baykov. Op. Cit., p. 121

साथ उत्पादन की किस्म [Quality] में अवनति होती गई। उत्पादन बढ़ाने पर इतना जोर दिया जाता था कि किस्म के नियन्त्रण पर से ध्यान हट गया। सोवियत उत्पादन में काफी समय तक यह कमजोरी बनी रही। इसके साथ ऊँची लागत का उत्पादन भी नवीन आर्थिक नीति में बराबर पाया जाता था। अनुभवहीन प्रबन्धक, लागत-लेखा प्रणाली [Cost accounting System] का न होना, मजदूरों का अत्यधिक वेतन और उद्योग का पूर्ण एकाधिकार इस परिस्थिति का उत्तरदायी था।

अन्य वर्ग के उत्पादकों में राज्य के बाद, व्यक्तिगत उद्योगपतियों का स्थान आता है। इस काल में व्यक्तिगत उद्योगपतियों को उत्पादन क्षेत्र में बुलाकर कई समस्याओं को हल करने की चेष्टा की गई थी। असंगठित राष्ट्रीयकरण से राज्य को बहुत बड़ी सख्या में कारखानों का प्रबन्ध लेने के लिये बाध्य होना पड़ा था। इस काम के लिये पर्याप्त धन, अनुभव, कुशल कर्मचारी आर सगठन सोवियत सघ के पास उपलब्ध न हो सका। ऐसे समय में औद्योगिक प्रबन्ध निजी उद्योग को सौंपकर, गिरते उत्पादन के पूरे अपयश को सरकार ने अपने सर से ढाल दिया। विदेशी पूँजी और कौशल के स्वागत का उचित वातावरण बनाने के लिये किसी न किसी रूप में पूँजीवाद को आश्रय देना आवश्यक था। राज्य यह कदापि नहीं चाहता था कि निजी उद्योग सफल हो। इस दृष्टि से उन पर ऐसे नियन्त्रण लगाये गये जिनके अंतर्गत सफलता असम्भव हो गई। इसका उद्देश्य था कि देश में साम्यवादी नीति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विरोधी प्रमाणित रूप से यह देख ले कि जिन परिस्थितियों में सोवियत उत्पादन असफल रहा उसमें व्यक्तिगत उत्पादन से भी कोई आशा नहीं की जा सकती, दूसरे शब्दों में, दोष परिस्थितियों का है न कि सोवियत पद्धति के संचालन का। आरम्भ से ही निजी उद्योग अत्यन्त छोटे पैमाने के उद्योगों से बनाया गया था। इसको स्वार्थ-सिद्धि के लिये सहन किया गया, इसके गुणों के लिये नहीं। लेनिन की मृत्यु के बाद [1924] जैसे-जैसे परिस्थिति सुधरती गयी उनका महत्व कम होता गया। इस क्षेत्र के पतन का अन्दाज इस बात से लगता है कि 1928 में इसमें 3,49,000 मजदूर थे। स्टालिन ने 1930 तक यह सख्या कुल 51,000 कर दिया जो शीघ्र ही प्रायः शून्य में बदल गई।<sup>1</sup>

अनुभव और पूँजी प्राप्त करने के लिए विदेशी उद्योगपतियों को विशेष सुविधाएँ देकर देश में बुलाने का प्रयत्न किया गया। विदेशियों के असहयोग और डर के कारण इसमें बहुत कम सफलता मिली। जो उद्योगपति इसके लिये तैयार भी हुए वे या तो बहुत छोटे व्यापारी थे या अवसरवादी धूर्त थे। 1922-27 के बीच जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस से 40 विशेषाधिकार सम्बन्धी समझौते हुए। इसके

<sup>1</sup> Schwartz H · Russia's Soviet Economy, p. 440

अतिरिक्त यान्त्रिक कुशलता की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य के कई देशों के साथ सम-भौता हुआ जिसके द्वारा प्रशिक्षण, फैक्टरी का निर्माण, मशीनों की स्थापना तथा कोयला और पेट्रोल जैसे उद्योगों में सुधार की सलाह ली गई। अधिकतर ऐसे प्रसविदों में सहायता देने वाले देश से आवश्यक मशीनें खरीदना अनिवार्य था। सबसे अधिक सहायता रूस के पुनर्निर्माण में अमरीका और जर्मनी ने प्रदान किया। कौन जानता था कि उद्योगपतियों की लालच भविष्य में इन्हीं राष्ट्रों के लिये अभिशाप बन जायगी।

कम महत्ववान कुछ उद्योगों का मिश्रित कम्पनियों के द्वारा संगठन किया गया। इनमें निजी पूँजी और राज्य परस्पर सहयोगी के रूप में एक साथ मिलकर काम करते थे। मुख्य लक्ष्य पूँजी और विदेशियों से औद्योगिक संगठन की शिक्षा प्राप्त करना था। मिश्रित कम्पनियों के प्रयोग की विदेशी सहायता आकर्षित करने का एक माध्यम कहा जाना चाहिये। सन्तोषजनक रीति से यह प्रयोग न चला तथा इसका क्षेत्र बहुत छोटा ही बना रहा।

### सारांश

गृहयुद्ध के बाद देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई थी। औद्योगिक उत्पादन युद्ध के पहले से 20% और कृषि उत्पादन 54% गिर गया। कोयला, पेट्रोल, लोहा तथा अन्य खनिज पदार्थ का उत्पादन प्रायः रुक चुका था। मजदूरों की संख्या में 60% और वास्तविक वेतन [real wages] में 35% कमी हुई। यातायात इस तरह सैनिक कामों में व्यस्त हो गया कि समाज के विभिन्न प्रदेशों का आर्थिक तथा अन्य सभी सम्पर्क शिथिल पड़ गया। मुद्रा व्यवस्था उठाने से बाजार व व्यापार नष्ट हो गया। 1921 के भयंकर अकाल ने बची हुई कमी को पूरा कर दिया। आर्थिक पुनरुत्थान के अतिरिक्त अस्तित्व की रक्षा का कोई अन्य उपाय न था। नवीन आर्थिक नीति इस दिशा में सफल प्रयास बनी। इस सफलता की कहानी यह आँकड़े बतलाते हैं :



1913 के प्रतिशत में उत्पादन <sup>1</sup>

वर्ष	उद्योग	कृषि	कुल उत्पादन
1913	100.0	100 0	100 0
1916	109 5	99 0	103 4
1919	23 1	76 3	53 9
1920	20 4	68 9	48 5
1920-21	24 7	63 9	47 4
1921-22	30 1	54 4	44.2
1922-23	39 5	73.6	59 2
1923-24	48 0	79 9	66 5
1925-26	89 9	101 3	96 5
1926-27	103 9	106 5	105 4
1927-28	119 6	105 6	115 5

इस प्रगति का यदि विस्तार देखा जाय तो वह और भी आश्चर्यजनक था :  
उत्पादन-वृद्धि <sup>2</sup>

1913 के प्रतिशत में 1927-28	
विजली	259 6%
कोयला	112 5
पेट्रोल	125 8
पीट	446.2
कमबशन इंजन	403.4
कृषि यंत्र	186 6
कच्चा लोहा	78 6
सूती कपड़ा	121.9
ऊनी कपड़ा	102 1
चीनी	103 9
अनाज	89 6
कपास	96 5
फलैक्स	54 6
चुकन्दर	92 7

<sup>1</sup>Grinko G. T. . The Five Year Plan of the Soviet Union, p. 34<sup>2</sup> Ibid. pp. 34-35

नवीन आर्थिक नीति की सफलता का एक मापदण्ड राष्ट्रीय आय होगी। यह 1927-28 में 1913 की 105% हो गई। 1923-1928 के बीच राष्ट्रीय आय की वृद्धि का वार्षिक क्रम 10% था जिसकी बराबरी उस समय में किसी भी देश के लिए करना सम्भव नहीं था।

अन्त में, एक प्रश्न और उठता है कि नवीन आर्थिक नीति को सिद्धान्त की दृष्टि से किस वर्ग में रखा जाय—पूँजीवाद, समाजवाद, अथवा साम्यवाद। इस नीति के प्रत्येक अंग में सैद्धान्तिक विरोधाभास [Doctrinal paradox] इस तरह भरा था कि किसी एक स्पष्ट वर्ग में यह पूरी तरह शामिल नहीं होती। समाजवाद के ढाँचे में पूँजीवादी उत्पादन के प्रभावशाली तरीकों का समावेश इसका मुख्य लक्षण माना जाता है। लेनिन इसे “परिवर्तनकालीन मिश्रित पद्धति” [transitional mixed economy] मानता था। उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक संतुलन के लिए लगभग इसी प्रकार का कार्यक्रम अवश्य क्रान्ति के बाद लेनिन ने अपनाया था।

ऐसी व्यवस्था को समाजवाद कहना कदापि उचित नहीं होगा। लेनिन ने एक नये “वाद” का निर्माण किया—राजकीय पूँजीवाद [state capitalism]। समाजवाद और पूँजीवाद के तत्वों का मिश्रण इस अनुपात में हुआ कि व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा-शक्ति और पूँजी [profit motive and capital] को समाज-कल्याण के लिए एक निश्चित मार्ग पर चलाया जा सके। इसे “निर्देशित पूँजीवाद” [directed capitalism] भी कहा जा सकता है। रूस की वर्तमान अर्थ व्यवस्था में भी समाजवाद के सिद्धान्तों का इतना सशोधित रूप मिलता है, कि उसे समाजवाद कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता। उन्नत पूँजीवाद और वर्तमान रूसी समाजवाद में सबसे बड़ा अन्तर यह नहीं है कि पूँजी का अधिकतम सामाजिक महत्व कम हो गया हो : अन्तर यह है कि पूँजी का स्वामित्व व्यक्तिगत क्षेत्र से राज्य के पास चला गया। इस दृष्टिकोण से आज भी रूस राजकीय पूँजीवाद का समर्थक माना जा सकता है। इसका जो आकार और विस्तार नवीन आर्थिक नीति में बना, कुछ परिवर्तनों के साथ, वह आधुनिक सोवियत अर्थ-प्रणाली का भी आधार है।

यदि गम्भीरता से देखा जाय तो मार्क्स, एङ्गल्स, लेनिन और स्तालिन सभी पूँजीवादी उत्पादन के प्रेरकों, तथा प्रबन्ध [incentives and management] की श्रेष्ठता स्वीकार करते थे। उनका विरोध मुख्य रूप से धनिकवर्ग की तुच्छ प्रवृत्तियों [petty bourgeois mentality] से था जिससे धन का असंतुलित वितरण एवं शोषण पैदा होता है। इसलिए इस दूषित प्रवृत्ति को दबा कर नष्ट करने के लिए राज्य का निर्देशन और संचालन, उत्पादन वृद्धि के लिए पूँजीवादी प्रेरक तथा प्रबन्ध, नवीन आर्थिक नीति का आधार बना।

इन दो बातों के अतिरिक्त राजकीय पूँजीवाद को अपनाने का एक और कारण था। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक विकास की प्राकृतिक शृङ्खला में लेनिन को थोड़ा-सा परिवर्तन करना पड़ा। आरम्भिक व्यवस्था—सामन्तवाद—पूँजीवाद—समाजवाद—साम्यवाद के क्रम में देखा गया कि पूँजीवाद के आरम्भ के रूप [early capitalism]<sup>1</sup> से समाजवाद तक पहुँचने का कोई सीधा मार्ग नहीं है। मामूली तौर पर पूँजीवाद उदय के काफी बाद इतना पुष्ट [matuie] होता है कि समाजवाद के लिए परिस्थिति तैयार हो। यह काम राजकीय पूँजीवाद के द्वारा सबसे अच्छी तरह हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूँजीवाद की दोनों हालतों से देश को गुजरना पड़ेगा—निजी पूँजीवाद [private capitalism] और राजकीय पूँजीवाद [state capitalism]। निजी पूँजीवाद से राजकीय पूँजीवाद उत्पन्न होगा : राजकीय पूँजीवाद से समाजवाद। नवीन आर्थिक नीति ने यह काम पूरा किया।

---

<sup>1</sup> 1921 तक रूसी पूँजीवाद अपने आरम्भ काल में ही माना जाता है।

## सोवियत राज्य की सैद्धान्तिक रूपरेखा

[Doctrinal Outline of Soviet State]

### सोवियत राज्य की सैद्धान्तिक रूपरेखा

रूस एक विशाल विरोधाभास है। रूसी इतिहास विविध प्रभावों का संकलन होने पर सदा अपनी विचित्र मौलिकता और एक-रूपता बनाये रहा। रूसी जनता भावुकता और श्रुता, कोमलता और कठोरता, अग्र भाग्यवादी सहनशक्ति और अनिश्चित अधीरता, बलिष्ठ, साहसी, कर्मठ पुरुषार्थ के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिये उचित-अनुचित का विश्लेषण करने में सदा असमर्थ रही। रूसी बौद्धिक विचारधारा मौलिकता के स्थान पर उत्कृष्ट अनुसरण, सरलता के दारूप में भयंकर जटिलता का सिद्ध प्रमाण है। असंतुष्टि, अभिलाषा और परिवर्तन का चिर प्रयत्न इनके प्रयासों का प्रेरक रहा है।

रूसी सिद्धान्तवाद सदियों से अपने निजी केन्द्र को सुरक्षित बनाये हुए अंग्रेजी, फ्रान्सीसी और जर्मन विचारधाराओं के प्रभाव ग्रहण करता रहा। इनमें से सबसे प्रबल और स्थायी प्रभाव वाली छाप जर्मन-ज्यू वंश के एक विचारक कार्ल हेनरिक मार्क्स की थी। चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स वह अद्भुत विभूतियाँ हो गई हैं जिन्होंने सारे संसार की विचारधारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इनके वाद के विद्वानों का मानों यह पावन कर्तव्य-सा हो गया था कि वे इनका खंडन अथवा मंडन करें। बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने की अभिलाषा लेकर नवयुवक मार्क्स ने दर्शनशास्त्र में डाक्टरेट प्राप्त किया। निराश होने पर पत्रकार के रूप में अपने विचारों के कारण देशनिष्कासन से त्रसित अतः लंदन आकर बस गया। बृटिश म्यूजियम के विशाल पुस्तकालय का पुजारी बन कर मार्क्स ने संसार को नया मार्ग दिखलाया। इनके आर्थिक-पोषक और बौद्धिक सहायक फ्रेडरिक एंगिल्स को कार्ल मार्क्स को संसार के भविष्य-द्रष्टा की तरह सामने लाने का श्रेय देना चाहिये। प्रखर बुद्धि, गहन अध्ययन और अद्वितीय विवेचना-शक्ति से उत्पन्न मार्क्स-साहित्य इतना विशाल है कि उसे मानवीय प्रयत्न समझना कठिन हो जाता है। 1848 में मार्क्स और एंगिल्स ने मिलकर प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणापत्र [Communist Manifesto] तैयार किया। साम्यवाद की इतनी स्पष्ट संज्ञित और उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति उसके बाद फिर कभी न हो सकी।

मार्क्स का महान पर्वतीय ग्रन्थ “पूँजी” [Capital] का प्रथम खंड 1867 में प्रकाशित हुआ। दूसरा और तीसरा खंड मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजिल्स के संपादन में प्रकाशित किया गया।

मार्क्स के अध्ययन का दो भाग किया जा सकता है। प्रथम समकालीन आर्थिक व्यवस्था [पूँजीवाद] का वैज्ञानिक विश्लेषण और इसके आधार पर नये आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण, द्वितीय इतिहास की प्रगति की नई दृष्टिकोण से विवेचना। यूँ तो मार्क्स के पहले अंग्रेज और फ्रांसीसी विचारकों ने पूँजीवाद और सामाजिक शोषण पर काफी काम किया था। इसमें से विशेष उल्लेखनीय राबर्ट ओवेन सेन्ट-साइमन [1760-1825] फारियर [1772-1835] प्राउधन [1809-1865] और लूई ब्लैक [1811-1882] थे। यह माना जाता है कि समाजवाद शब्द का निर्माण भी एक फ्रांसीसी पत्रकार पियरे लेराऊ ने 1832 में किया। इन विचारकों और मार्क्स के बीच कई मुख्य भिन्नताएँ हैं। मार्क्स निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन के क्रान्तिकारी मार्ग को ही अपनाता था जब कि उसके पहले के विद्वान शान्तिपूर्ण तरीकों से ही समाज को बदलने पर जोर देते थे। मार्क्स ने समाज के केवल एक वर्ग को ही आवश्यक माना और उसी के द्वारा तथा उसी के लिये नये सामाजिक निर्माण पर ध्यान दिया। अन्य व्यक्ति सभी सामाजिक वर्गों के संतुलित विकास और सहयोग की शिक्षा देते थे। सबसे बड़ी भिन्नता उस मार्ग में थी जिसके द्वारा मार्क्स निर्णयों पर पहुँचा। उसके पहले के लोग भावनाओं और आदर्शों को लेकर नये समाज की कल्पना करते थे। उनके विचार कोरे तर्कों के लिये तो ठीक थे किन्तु उनमें वास्तविकता की पुष्टि नहीं थी। उसी से इनके विचारों से आदर्शवादी साम्यवाद [Utopian Socialism] की सृष्टि हुई। उनके एकदम विपरीत, मार्क्स ने वैज्ञानिक साम्यवाद [Scientific Socialism] को जन्म दिया जिसमें सामाजिक विकास का तथ्यो पर आधारित अध्ययन किया गया था। इसका उद्देश्य तुरन्त ही विश्वव्यापी रूप में लागू करना था। इसी कारण “दुनिया के मजदूर एक हो” [Workers of the world, Unite] का नारा आज भी अरबों व्यक्तियों को प्रेरणा दे रहा है।

मार्क्सवाद के दो विभाग हैं। अपने सरलतम रूप में इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। मार्क्स इतिहासकार और अर्थशास्त्री दोनों थे। इतिहासकार की तरह इसने संसार के इतिहास को एकमात्र आर्थिक प्रेरणा के दृष्टिकोण से देखा और लगभग अकाट्य रूप से सिद्ध कर दिया कि आर्थिक और सांसारिक [Economic and material] प्रेरणा द्वारा ही व्यक्तियों और राष्ट्रों का जीवन तथा कार्यक्रम संचालित होता है। व्यक्ति और राष्ट्र के प्रत्येक कार्यक्रम की आर्थिक पृष्ठभूमि को मार्क्स ने अकेली मान्यता प्रदान की। राजनैतिक सिद्धांत और धर्म इत्यादि को “सैद्धांतिक

वाह्य रूप" [Ideological superstructures] कहकर मार्क्स ने ढाल दिया। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह निकला कि पूँजीवाद का पतन अवश्यभावी है इसके अन्दर ही विनाश के बीज बनते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, मजदूरों की गरीबी, बढ़ता हुआ मूल्य और गिरती हुई क्रयशक्ति, मंदी और तेजी का व्यापार चक्र इत्यादि बुनियादी कमजोरियों के कारण, समय के साथ, केवल दो वर्गों में समाज बँट जायगा—विशाल एकाधिकारों के स्वामी चन्द पूँजीपति और गरीब, शोषित तथा बेकार मजदूरों का विशाल समुदाय। यही मजदूर अपनी संख्या और बल से एक दिन पूँजीवादी ढाँचे को विध्वंस कर देंगे। कहा जाता है कि पूँजीवाद ने अतुलनीय सफलता से वस्तु उत्पादन किया किन्तु साथ ही साथ ऐसी शक्ति [मजदूर] को बनाया जो एक बार पूरी तरह जागने पर अपने बनाने वालों को ही नष्ट कर देगी।

अर्थशास्त्री मार्क्स ने पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था को शोषण-व्यवस्था सिद्ध कर दिया। उसके अनुसार पूँजी मजदूरों के अधिकारों के अपहरण से इकट्ठा की गयी धन-शक्ति का नाम है। अतिरिक्त श्रम मूल्य [Surplus labour value] के सिद्धांत से मार्क्स ने इस बात को समझाया। इसके अनुसार पूँजीपति मजदूरों से मर्शान और औद्योगिक संगठन द्वारा काम करा कर उत्पादन कराते हैं। यह उत्पादन मजदूरों की अपनी आवश्यकता से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, इसका एक अंश ही मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिये दिया जाता है। बचे हुए अंश पर पूँजीपति अनधिकार रूप से अपना कब्जा कर लेते हैं। एकत्र होकर यही अंश पूँजी कहलाता है। मार्क्स के विवेचना में मजदूरों के उत्पादन का कोई भी भाग [लाभ वा ब्याज] केवल शोषण है। मजदूरों को यह अधिकार है कि वे संगठित होकर इस शोषण का विरोध करें। विरोध कितना ही प्रबल क्यों न हो पूँजीपति अंत में बिना युद्ध के कभी हार नहीं मानेंगे। इसलिये मार्क्स ने युद्ध और हिंसात्मक क्रान्ति को आवश्यक पाया। उसने इस बात में कभी विश्वास नहीं किया कि पूँजीवाद का क्रमिक विकास समाजवाद में हो सकता है [growth of capitalism into socialism]। इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ तक कहा कि इस क्रान्ति की स्थिति तक आने के लिये, मजदूरों में इतनी जागृति पैदा करने के लिये, बहुसंख्यक मजदूर वर्ग का निर्माण करने के लिये, पूँजीवाद और पूँजीवादी शोषण आवश्यक है। मार्क्स ने सामतवाद-पूँजीवाद-साम्राज्यवाद-साम्यवाद की ऐतिहासिक श्रृंखला को देखा और साम्यवाद तक पहुँचने के लिये सामाजिक क्रमिक विकास में पूँजीवाद का स्वागत किया। साथ-ही-साथ यह भी कहा कि मजदूर नेताओं का कर्त्तव्य है कि वे हर प्रकार से समाज को वर्गों में विभाजित होने में सहायता दें क्योंकि वर्ग संघर्ष [Class struggle] बिना साम्यवाद नहीं आ सकता। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। यह वर्ग विभाजन देश के आधार पर ही नहीं वरन् विश्व के

आधार पर होना चाहिये। बिना विश्वव्यापी साम्यवाद की स्थापना हुए किसी एक देश में साम्यवाद का रहना कठिन है। चारो ओर के पूँजीवादी देश उसका गला घोट देंगे। यह साम्यवाद अविकतम उन्नत पूँजीवादो देश में ही सबसे पहले आयेगा क्योंकि उसी जगह वर्ग विभाजन [Class Division] और वर्ग संघर्ष [Class struggle] सबसे ज्यादा होगा। अतः मार्क्स औद्योगिक मजदूरों से ही सफल साम्यवादी क्रान्ति की आशा करता था। उसके विचार में शोषण की कमी, संगठन की कठिनाई और जाग्रति के अभाव के कारण बिखरे हुए किसान अच्छा साम्यवादी मसाला नहीं हो सकते।

मार्क्सवाद के अध्ययन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये, मार्क्स ने समाजवादी संगठन की निश्चित रूप-रेखा तथा परिभाषाएँ नहीं दिया। जो लोग मार्क्स के विचारों को समाजवाद पर अन्तिम शब्द मान लेते हैं उनका दृष्टिकोण संयत नहीं बनता। इसका कारण यह है कि मार्क्स ने एक नये विषय पर अपने नए विचार सामने रखा था; इसलिये जो कुछ उसने कहा उसे परिभाषाओं की सीमा में बाँध लेना अनुचित होगा। विचारों का जो नया मार्ग मार्क्स ने दिखलाया उसका ऐतिहासिक एवं तर्कपूर्ण विकास समय के साथ लगातार होते रहना चाहिये। मार्क्स के विशाल ग्रंथ 'पूँजी' में हमें परिभाषाएँ नहीं मिलती : उसमें वास्तविकता की अत्यन्त गहन विवेचना है। इसी से प्रेरित होकर मार्क्सवाद के स्थापकों ने बार-बार कहा कि वे भविष्य में आने वाले साम्यवादी सामाजिक संगठन की निश्चित रूप-रेखा नहीं दे सकते। उनके अनुसार ऐसे समाज का संगठन और साम्यवादी क्रान्ति का क्रम विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग होगा।

मार्क्स के अनुसार मजदूर वर्ग को पूँजीवाद के विरुद्ध सफल शिक्षा देने का काम उनकी एक स्वतंत्र राजनैतिक पार्टी ही कर सकती है। बाद में लेनिन ने पार्टी के महत्व के सिद्धान्त को एकदम शिखर पर पहुँचा दिया। जनता के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पार्टी को समाज के हर अंग के संचालन का पूर्ण दायित्व सौंपा गया। व्यक्ति तथा विचार पार्टी के आगे प्रभावहीन हो गये। पार्टी द्वारा संगठित राज्य [State] का मुख्य काम 'शोषकों का शोषण' [Expropriation of the Expropriators] निर्धारित किया गया। यह करने का उपाय उत्पादन के साधनों को समाज की सम्पत्ति में बदलना था।

इस प्रकार समाजवाद सामाजिक संगठन का एक सिद्धान्त है जिसमें, मार्क्स के अनुसार, उत्पादन के साधन का सामाजिक स्वामित्व हो [Social ownership of the means of production]; मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण बन्द हो गया हो, और उत्पादन की अव्यवस्था [Anarchy of production] के स्थान पर सम्पूर्ण

समाज का संयोजित संगठन [planned organisation] किया गया हो। इन सबका उद्देश्य उत्पादन शक्ति में तेज वृद्धि तथा मनुष्य का संतुलित विकास होना चाहिये। इस प्रकार मार्क्स का समाजवादी समाज स्वतन्त्र व्यक्तियों का एक संघ है जहाँ सभी लोग सामुदायिक उत्पादन के साधनों से काम करते हैं, और अपनी व्यक्तिगत श्रमशक्ति को एक योजना के अनुसार काम में लाते हैं। स्वतन्त्र व्यक्तियों के इस संघ की श्रम शक्ति का सारा उत्पादन समाज का माना जाता है। इस प्रकार लोगों का काम [Work] और उत्पादन [Produce] के साथ सामाजिक संबंध स्पष्ट हो जाता है। इससे उत्पादन तथा वितरण [Production and Distribution] की समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलती है। मार्क्स समाजवाद [Socialism] को साम्यवाद [Communism] का पहला और सबसे नीचा चरण [Phase] मानना था। इसका मुख्य काम उत्पादन शक्ति को बढ़ाना और साम्यवाद की स्थापना के लिये नींव तैयार करना माना गया है।

मार्क्स के सिद्धांत अथवा मार्क्सवाद की ससारव्यापी पसंद और प्रचलन के कुछ कारणों पर विचार करना असंगत न होगा। इसका सबसे बड़ा आकर्षण शोषित मजदूरों के पुनरुद्धार में लगभग धार्मिक विश्वास था। उस समय पूँजीवाद के विकास का आरम्भ काल [पूँजीवाद का शोषण] चल रहा था। मजदूर उत्पादन की वस्तु माने जाते थे। उनमें मानवता के चिन्ह देखना 'समाज द्रोही' बनना था। वेतन के नाम पर उन्हें जीवित रहने से अधिक धन देना उन्हें बिगाड़ने का प्रयत्न माना जाता था। आत्म-सम्मान और अपने महत्व से पूर्णतया अनभिज्ञ इन मजदूरों को मार्क्सवाद ने भूमि से उठाकर एकदम शिखर पर पहुँचा दिया। उन्हें समाज का एक मात्र आवश्यक वर्ग घोषित करके संपूर्ण उत्पादन का अकेला कर्त्ता बना दिया। उनको बतलाया कि पूँजीपति बिना भी समाज चल सकता है। पूँजीपतियों ने जो अधिकार प्राप्त कर रखे हैं वह वास्तविकता में मजदूरों के होने चाहिये। यह शिक्षा शायद इतनी सफल न होती अगर मार्क्स उचित-अनुचित, नैतिकता और आदर्शवाद का सहारा लेकर उसे सामने रखता। लेकिन मार्क्स ने तो कहा कि पूँजीवाद का पतन, मजदूरों का उत्थान और इसके लिये वर्ग संघर्ष वैज्ञानिक सत्य है, जिसको इतिहास अनिवार्य मानकर सिद्ध करता है। कठोर सत्य और स्पष्ट तथ्यों पर आधारित यह विचारधारा सभी को बहुत उचित और अनुसरण-योग्य मालूम पड़ी। इसी कारण से आज दिन संसार के एक-तिहाई मनुष्य इसी व्यवस्था में रह रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पूँजीवाद का विकास मार्क्स के निर्देशित मार्ग पर नहीं हुआ जिससे उसकी शिक्षाओं में अनेको अपवाद उत्पन्न हो गये। उसकी आशाओं के विपरीत पूँजीवाद ने शोषण की वृद्धि पर स्वयं रुकावट लगाकर वर्ग संघर्ष को क्रान्ति के



स्तर तक नहीं पहुँचने दिया। राजकीय हस्तक्षेप, एकाधिकार पर नियंत्रण, वेतन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि को नियमबद्ध करके पूँजीवाद ने साम्यवाद के मूलाधार को ही तोड़ने का प्रयत्न किया। पूँजीवाद का यह प्रयत्न कहाँ तक सफल और स्थायी होगा, इस पर सदेह करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

**रूस में मार्क्सवाद का आगमन**—1917 की सफल साम्यवादी क्रान्ति अचानक जरूर हुई किन्तु उसका बीज लगभग 100 साल पहले बोया जा चुका था। बोल्शे-विक्वाद के अचानक सत्तारूढ़ होने से सबसे अधिक आश्चर्य स्वयं बोल्शेविक नेताओं को हुआ। राष्ट्र के इस समूल परिवर्तन का सबसे पहला श्रेय नेपोलियन के युद्ध से लौटे हुए सैनिकों को दिया जाना चाहिये जो पश्चिमी यूरोप के संपर्क से प्रजातन्त्रात्मक विचार-धाराएँ अपने साथ लाये। सीमित परिधि में वद रूसी मस्तिष्क को इन्होंने नया जीवन दिया।<sup>1</sup> 1855-1870 के बीच शून्यवादी धाराएँ [Nihilist Tendencies] उत्पन्न हुईं। उन व्यक्तियों का वर्तमान सिद्धांत धर्म और सस्थाएँ को नष्ट करना था क्योंकि यह मानते थे कि पूर्ण विनाश से ही पुनर्जन्म होता है। छोटी-छोटी संस्थाओं और होटलों में गरम ब्रहस के अतिरिक्त यह कर्म-क्षेत्र में नहीं उतरे। धीरे-धीरे इस वर्ग के व्यक्ति शिक्षा द्वारा अपने को उन्नत बनाने पश्चिमी यूरोप के देशों में गये। इन पर उस समय के प्रबल प्रभावशाली दार्शनिक विचारकों जैसे हारजेन, बकुइनीन और मार्क्स-वादी पीटर लावरोव ने गहरी छाप डाली। वापस आने पर नये आदर्शवाद से उत्तेजित इन व्यक्तियों ने किसानों में घुलमिल कर उनके विचारों को सुधारना और उन्हें संगठित करना आरम्भ किया। जार के विचार से यह एक भयंकर काम था। देशव्यापी खोज से इन नवयुवकों को पकड़ कर दवा दिया गया। वैधानिक रूप से शिक्षा द्वारा उन्नति करने की मनाही होने पर इस आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप पकड़ा और आतंकवाद का सहारा लिया। गुप्त रूप से चलता हुआ यह कार्यक्रम मार्च 1881 में जार की हत्या से अंत हुआ। पुलिस के भीषण दमन-चक्र और वैधानिक रुकावटों ने जनता के आंदोलन को मृतप्राय बना दिया। इस समय तक के क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषता यह रही कि उनका कोई आर्थिक या राजनैतिक कार्यक्रम नहीं था। समस्त बुराइयों का प्रतीक उनके दृष्टि में केवल जार था। दूसरे, इस समय तक रूसी विचारकों का ध्यान पूरी तरह किसानों की ओर केन्द्रित था। अतः 1880 तक का क्रांतिकारी आंदोलन वस्तुतः ग्रामीण ही रहा। 1870 के तेज औद्योगीकरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

इसी समय के विद्वानों ने कार्ल मार्क्स का परिचय रूसियों से कराया। फिर भी मजदूरवाद को रूसी समाज और राज्य के लिये खतरनाक समझा जाता था। रूसी

<sup>1</sup> N. Berdyayev . Origin of Russian Communism. London. 1937.p

भाषा में 'पूँजी' का अनुवाद 1872 में हुआ। कितने आश्चर्य की बात है कि इस पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति इसलिये मिल गई कि जार सरकार ने इसे अत्यन्त अरुचिकर एवं पढ़ने में असम्भव पाया। उनके विचार से इस तरह की शुष्क पुस्तक हानिकारक नहीं हो सकती।<sup>1</sup> इसके पहले 1860 में साम्यवादी घोषणा-पत्र [Communist Manifesto] का अनुवाद रूसियों को काफी प्रभावित कर चुका था। सम-कालीन लेखकों के अनुसार 1880-90 के बीच मार्क्स रचित 'पूँजी' रूसी विद्यार्थियों में सबसे अधिक पढ़ी जाती थी।<sup>2</sup> इन्हीं सब का प्रभाव था कि सामाजिक दोषों का उत्तरदायित्व, केवल जार पर न रखकर पूँजी तथा पूँजीपति पर भी रक्खा जाने लगा।

उस समय का प्रमुख सैद्धान्तिक तथा विचारक वी० जी० प्लेखानोव था। इस महान् व्यक्ति ने केवल मार्क्सवाद का ही घोर अध्ययन नहीं किया, परन्तु मार्क्सवाद को रूसी परिस्थितियों में लागू करने का प्रयत्न किया। इनके विचार से साम्यवाद के आगमन के लिये पूँजीवाद का विकास मजदूरों के हित में है।<sup>3</sup> 1895 में प्लेखानोव की प्रेरणा पर लेनिन ने सेन्ट पीटर्सबर्ग में एक संस्था [Society for the Liberation of Labour] स्थापित की। 1898 में विभिन्न वर्ग के मार्क्सवादियों ने मिलकर रूसी सामाजिक प्रजातन्त्रात्मक मजदूर दल [Russian Social Democratic Labour Party] बनाया। यही पार्टी आगे चलकर मार्क्सवादी क्रांतिकारियों की जन्मदाता बनी।<sup>4</sup> दल के अनुशासन और संचालन के प्रश्न को लेकर 1903 में दल का विभाजन हो गया। मेनशेविक अर्थात् अल्पसंख्यक और बोल्शेविक अर्थात् बहुसंख्यक। मेनशेविक नेताओं में प्रमुख प्लेखानोव और ट्राट्स्की थे और बोल्शेविक में लेनिन। इन दोनों भागों में समय के साथ विचारों का अन्तर बढ़ता गया। मेनशेविक नेताओं का विचार था कि क्रांति के बाद रूस में वैधानिक संविधान सभा द्वारा शासन हो जिसमें देश के प्रत्येक राजनैतिक दल का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसके विरुद्ध लेनिन के विचार से राजनैतिक क्रांति के बाद पूँजीवादियों से रक्षा करने के लिये यह आवश्यक है कि देश में क्रांतिकारी सरकार बने जिसका नेतृत्व समाजवादी दल के हाथ में केन्द्रित हो।

1901 में अन्य क्रांतिकारियों ने एक नये दल का निर्माण किया जिसे सामाजिक क्रांतिकारी दल [Social Revolutionary Party] कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि

1 F L Shuman 'Russia Since 1917', p. 1

2 Sir John Maynard 'Russia in Flux', pp. 118-128

3 Berdvyayev 'The Origin of Russian Communism', Trans London 1937, p. 111-112

4. B D Wolfe 'Three Who Made a Revolution', pp 99-117

जार को हटाने और किसानों के विप्लव का समय आ गया। इस काम के लिये खुले-आम हिंसा करने का उनमें कोई विरोध न था।

1905 की क्रांति—1904 के रूसी-जापानी युद्ध की हार, युद्ध का विशाल खर्च, किसानों की विगड़ती हुई परिस्थिति और जार निकोलस द्वितीय के निजी कमजोरी के कारण विस्तृत हड़तालें हुईं और गृहमंत्री की हत्या कर दी गई। सामाजिक साहस और कूटनीति से काम लेने की जगह जार का मन डर से काँप उठा। परिस्थिति के विना समझे सुधार की बातचीत और सुधार की माँग करने वालों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। रविवार जनवरी 9, 1905 को, शून्य से 30 अंश कम तापमान की भीषण सर्दी में, धर्मगुरु गेपान के नेतृत्व में कई हजार मजदूरों की एक भीड़ अत्यन्त शांतिपूर्ण तरीके से जार के शीत-महल [ Winter Palace ] पहुँची। उनके माँग पत्र में जनता की स्थिति में सुधार, अफसरवाद के विरुद्ध शिकायत और शासन में जनता के प्रतिनिधित्व की माँग अत्यन्त श्रद्धा और नम्रता से की गयी थी। जार उनसे मिलने नहीं आया। पुलिस उस समय तक गोली चलाती रही जब तक कि लगभग डेढ़ हजार निहत्थे पुरुष, स्त्री और बच्चों की आहुति देकर भीड़ चली न गई। क्रांति की जो लहर यहाँ पैदा हुई वह सारे देश में फैल गई। अगस्त 1905 में कुछ वैधानिक सुविधाएँ दी गईं और ड्यूमा अर्थात् प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। यह केवल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मात्र था। 1906-1917 के बीच अनेकों बार ड्यूमा का चुनाव हुआ और प्रायः हर बार जार ने उसे भग कर दिया। इतना ही नहीं, ड्यूमा जार के विरोधियों का पता लगाने का साधन बना ली गई। जनता का बढ़ता हुआ आरोप और असन्तोष इतना अधिक हो चुका था कि 27 फरवरी 1917 को सेन्टपीटर्स-बर्ग के मजदूरों की हड़ताल ने सारे देश को क्रांति की आग में भोंक दिया। 1905 तथा 1917 की क्रांति के नेता वास्तव में प्लेखानोव द्वारा संचालित मेन्शविक विचारों के ही अनुयायी रहे। किन्तु एकदम ठीक समय पर सामने आकर, लेनिन की दूरदर्शिता अवसरवादिता, रणकुशलता और बुद्धिबल से बोल्शेविक दल ने, बहुत थोड़ी संख्या होने पर भी, सभी को हटा कर क्रांति का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। दूसरों की भूलों को लेनिन की तीव्र दृष्टि ने देखा और तुरन्त नीति में संशोधन करके लोकप्रियता प्राप्त कर लिया।

### लेनिनवाद अथवा बोल्शेविकवाद

लेनिनवाद मार्क्सवाद के क्रमिक विकास में सबसे नई कड़ी है। चूँकि लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता था इसलिये उसके द्वारा प्रतिपादित विचारधारा को बोल्शेविकवाद भी कहते हैं। रूसी आर्थिक विचारक्रम की परम्परा में यह अत्यन्त स्वाभाविक रूप

से मिल जाती है। क्रान्ति के पहले लगभग १०० वर्ष से लेनिनवाद तक पहुँचने की तैयारी हो रही थी। मार्क्स के सिद्धान्तों को इसी रूप में व्यवहारिकता प्राप्त हुई। मार्क्स शुद्ध सिद्धान्तवादी था; लेनिन भी उतना ही महान् सिद्धान्तवादी होने के साथ-साथ क्रियाशील यथार्थवादी भी था। मार्क्स ने जो कुछ शब्दों में कहा, लेनिन ने उसे कार्यों में बदल दिया। वस्तुतः मार्क्सवाद दर्शन [Philosophy] है, और लेनिनवाद रूस के शासन में प्रयोग किया गया मार्क्सवाद है। बोलशेविक पार्टी के नेताओं को रूसी स्वभाव और मनोविज्ञान का अपार ज्ञान था जिसके साथ रूसी परम्परा से समन्वय रखते हुए लेनिन के नेतृत्व में उन्होंने मार्क्स के सिद्धान्तों को नई आकृति प्रदान किया। लेनिन, मार्क्स और एन्जिल्स के सिद्धांतों पर क्रियात्मक विश्वास [Creative belief] करता था किन्तु उनको अकाव्य अथवा अपरिवर्तनीय नहीं मानता था।

आरम्भ से ही रूसी जनता राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों को छोड़कर केवल सामाजिक दृष्टिकोण पर ही जोर देती थी। सम्पूर्ण इतिहास में रूसी बुद्धिवादी, न्यायपूर्ण और सुन्दर सामाजिक व्यवस्था की खोज में लगे रहे। परिणाम यह हुआ कि उनका आदर्श सामुदायिक सामाजिक जागृति<sup>१</sup> [Collective Social Consciousness] और परिश्रम बन गया। इसकी अभिव्यक्ति क्रान्ति के पहले के मीर और आरेटेल के रूप में हुई। इसी कारण लेनिन के सोवियत सत्र में व्यक्तिगत राजनैतिक स्वतन्त्रता में रुचि न रही और वैयक्तिक आर्थिक स्वतन्त्रता को कोई स्थान नहीं मिला।<sup>२</sup> लेनिन ने अपने कार्यक्रम के प्रति जनता का अदम्य उत्साह प्राप्त करने के लिये, लेनिनवाद को धर्मप्रचारक की एकनिष्ठा और जोश की प्रवृत्ति [Messianic Complex] प्रदान किया। प्रभाव यह था कि प्रत्येक अनुयायी अपने को इतिहास द्वारा नियुक्त साम्यवाद का सेवक और प्रचारक समझता है। इसके सिद्धान्तों को लागू करना उसका पवित्र धार्मिक कर्तव्य बन गया।

लेनिनवाद ने पुराने रूसी समाजवादियों का अपार कृषक प्रेम और शुद्ध मार्क्सवादियों का औद्योगिक श्रम से लगाव दोनों ही नहीं हैं। इसकी जगह पर सोवियत संघ को एकता के सूत्र में बाँधने के लिये हँसिया और हथौड़ा को सम्मिलित रूप से प्रतीक बनाया गया। इस प्रकार लेनिनवाद ने समस्त श्रमिक-वर्ग का अनुसरण प्राप्त किया चाहे वह खेतों में काम करता हो या कारखानों में। रूस कभी भी धीमे क्रमिक विकास के आदर्श में अपनी आस्था नहीं बना सका। लेनिन ने इस प्रवृत्ति से फायदा उठाकर, उस समय के यांत्रिक विकास को देखते हुए अचानक इतिहास की रेखाओं को बदलने

१. सोबोरनास्त [Sabornost] का अनुवाद नहीं हो सकता।

२. N. Berdyayev. Op. Cit pp 180-185

की नीति अग्न्याई। अत्यन्त पिछले हुए देश को, बिना पूँजीवादी शोषण से गुजारे हुए, एकदम समाजवाद पर लादने की सम्भावना स्वीकार किया। सामाजिक परिवर्तन के लिये प्रयत्नकारी और हिंसात्मक परम्परा को बोल्शेविक दल ने भी अपनाया। वर्तमान रूस की गुन पुलित और विरोधियों के रक्तदान की विभीषिका को जनता द्वारा मूक सहमति प्राप्त होने का यही रहस्य है। औद्योगीकरण और सामुदायिक खेती लेनिनवाद की बुनियाद थी। महान् पीटर के समय से यह विचार जड़ पकड़ चुका था कि आर्थिक और यात्रिक शक्ति द्वारा ही रूस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। इस प्राचीन इच्छा को अपनी नीति मान कर देश का पुनर्निर्माण करने में अधिकतर जनता लेनिन के साथ थी।

लेनिन के अनुसार क्रान्ति द्वारा ही समाजवाद की स्थापना सम्भव है। एक दल के निर्देशन में मजदूरों की तानाशाही साम्यवाद तक पहुँचने का एकमात्र सही तरीका है। बोल्शेविकवाद राज्य को दमन का यन्त्र मानता है<sup>1</sup>। पूँजीवादी और समाजवादी राज्य में केवल इतना अन्तर है कि पहले में राज्य का काम मजदूरों को दबाना है और, दूसरे में, पूँजीवादियों और पूँजीवादी प्रवृत्तियों को दबाना है। किन्तु यह अवस्था शुद्ध साम्यवाद की प्राप्ति का मध्य-स्तर होगा। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण और लोगों में बल प्रयोग से काम करने के लिये लाचार करना भी आवश्यक हो सकता है। अनिश्चित काल बाद एक वर्गहीन समाज बन सकेगा। हर प्रकार का धन समाज का होगा। लोग धन की लालच या सजा के डर से काम न करके, आत्म अभिव्यक्ति [Self expression] के लिये उत्पादन करेंगे। समाज में बल प्रयोग की आवश्यकता न रहेगी जिससे राज्य अपने आप विलीन हो जायगा। इस स्थान पर यह कहना आवश्यक है कि जिस प्रकार सोवियत संघ में वर्गहीन समाज की स्थापना का कार्य हो रहा है उससे यही मालूम पड़ता है कि कल्पित वर्गहीन समाज की जगह रूस एकवर्ग के समाज की ओर अग्रसरित है।

### स्तालिनवाद

लेनिन के शिष्य और उत्तराधिकारी स्तालिन का नाम जोसेफ विसारियोनोविच जुगाश्विली [Josef Vissarionovich Dzhugashvili] था। इसका जन्म 1879 में हुआ। इनके पिता एक मोची और माता किसान महिला थी। यह रूस का पहला शासक था जो श्रमिक वर्ग में पैदा होकर ऊपर उठा था। रूस के बाहर की दुनिया से दूर, स्वाध्याय से शिक्षित अद्वैत मानवीय इच्छा शक्ति का प्रतीक स्तालिन था। अपार एकाग्रशक्ति, क्रूरता, चालाकी, अमानवीय धैर्य और स्थिरता के कारण ही उसे रूस का

1. State is a means of suppression.

लौह-पुरुष कहा जाता है। लगभग तीस साल के शासन में स्तालिन ने रूस की शक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया।

स्तालिन का सिद्धान्त बोल्शेविक सिद्धान्त लेनिनवाद का थोड़ा-सा परिवर्तित रूप था। मार्क्स और लेनिन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ग सन्घर्ष को प्रबल राष्ट्रीयता में बदलकर स्तालिन ने प्रेरणात्मक वास्तविकता उत्पन्न किया। पूँजीवादियों से घिरे किसी एक देश में समाज-वाद की स्थापना असम्भव है; जिस देश में साम्यवाद स्थापित हो उसका यह कर्त्तव्य है कि दूसरे देशों में साम्यवादी क्रान्ति कराये; मार्क्स और लेनिन के इन विचारों को एकदम उलटकर स्तालिन ने कहा कि संसार के अन्य देशों के क्रान्तिकारी दलों का यह कर्त्तव्य है कि समाजवादी रूसी सरकार को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाये जिससे उनको प्रेरणा और व्यवहारिक दृष्टान्त प्राप्त हो।

स्तालिन ने पूँजीवादी देशों के आक्रमण का भयकर भय जनता में पैदा किया। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये दो उपाय बतलाये, औद्योगीकरण तथा अस्त्रीकरण। स्तालिन के अनुसार पूर्ण साम्यवाद की स्थापना बहुत दूर है यद्यपि रूसी समाजवाद निरन्तर उस ओर बढ़ रहा है।

लेनिन के साथ ही साथ समाजवाद से उदारता [Liberalism] समाप्त हो गई। लेनिन की सहानुभूति तथा समन्वय की नीति को छोड़कर, स्तालिन ने कठोरता की नीति अपनाई। वर्ग-विहीन [Classless] समाज की जगह, स्तालिनवाद में एक वर्ग [one-class] के समाज को महत्व दिया गया। यह था श्रमिक वर्ग।

**पूँजीवाद तथा समाजवाद—[Capitalism and Socialism]**

समाजवाद के मुख्य विचारको [मार्क्स-एन्जिल्स, लेनिन, स्तालिन तथा अन्य व्यक्ति] के अनुसार पूँजीवाद के प्रायः सभी अंगों पर समाजवाद की श्रेष्ठता दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। इनके कुछ प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं।

[1] मनुष्य के इतिहास में प्रथम बार समाजवाद ने ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें समाज के पूर्ण आर्थिक साधन और श्रम शक्ति का प्रयोग सारे समाज के लिये करना सम्भव हुआ।

[2] चन्द लोगों के व्यक्तिगत लाभ की जगह समाज की आवश्यकता की पूर्ति उत्पादन का उद्देश्य बनाया गया।

[3] साम्यवादी घोषणापत्र के अनुसार पूँजीवाद में मानवीय श्रम पूँजी संग्रह करने का केवल एक साधन होता है लेकिन समाजवाद में संग्रहीत पूँजी मानवीय श्रम के उत्थान तथा आराम के लिये प्रयोग की जाती है।

[4] पूँजीवाद में उत्पादन की अव्यवस्था [Anarchy of production]

के कारण साधन तथा श्रम का अपव्यय होता है। समाजवाद में अर्थ-व्यवस्था का संयोजित विकास [planned development] किया जाता है। इससे सामाजिक श्रम तथा साधनों का अधिकतम लाभ मिल सकता है।

[5] पूँजीवादी विकास में सामयिक संकट [Crisis or depression] के कारण विकास का क्रम एक-सा नहीं चलता। समाजवाद में इस तरह की उथल-पुथल तथा सामाजिक हानि नहीं होती। यह कहा जा सकता है कि जिस तरह बिना सकट, अपव्यय तथा हानि के पूँजीवाद की कल्पना कठिन है उसी प्रकार समाजवाद की कल्पना योजना तथा समाज के प्रत्येक अंग के समुचित विकास के बिना नहीं की जा सकती।

[6] श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि [Higher labour productivity] समाजवाद और पूँजीवाद दोनों के उत्पादन का उद्देश्य है। समाजवाद में इसके लिये समाज की उत्पादन शक्ति को बढ़ाया जाता है और कर्मचारियों के उत्साह को क्रियात्मक बढ़ावा दिया जाता है। पूँजीवाद निरर्थक प्रतिसपर्द्धा [Meaningless Competition] द्वारा यह काम करने की चेष्टा करता है जिसमें अपार अपव्यय तथा सामाजिक लागत [Social Cost] आवश्यकता की एक ही वस्तु के उत्पादन में लगती है।

[7] पूँजीवाद में आर्थिक विकास उद्योग की वस्तुओं के उत्पादन से आरम्भ होता है। उद्योगों के उद्योगों के सहारे बुनियादी भारी उद्योग स्थापित किये जाते हैं। उत्पादन-शक्ति का आधार भारी उद्योग होते हैं। इनके विकास में लापरवाही होने से देश के विकास में बहुत अधिक समय लगता है। इसके विपरीत, समाजवाद में उत्पादन के साधनों का उत्पादन (Production of the means of production) अर्थात् भारी उद्योग को सबसे ऊँचा महत्व दिया जाता है।

[8] दोनों ही सामाजिक व्यवस्थाओं में श्रमिकों के समय की बचत का आदर्श सामने रखा गया है। आवश्यक आर्थिक उत्पादन में जितना कम समय लगेगा, उतना ही अधिक समय लोग मानसिक एवं सामाजिक कामों में लगा सकेंगे। इसके लिये दोनों प्रकार के संगठन अधिक से अधिक यत्कीर्ण तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध का सहारा लेते हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है। पूँजीवाद में समाज के एक वर्ग को अवकाश [Leisure] देने के लिए तमाम श्रमजीवियों [Working masses] का सारा समय काम में लगाना पड़ता है, समाजवाद इस अन्याय को पनपने नहीं देता।

[9] मार्क्स तथा एंजिल्स के अनुसार समाजवादी श्रम संगठन में प्रत्येक व्यक्ति पर काम करने का उत्तरदायित्व रखा गया है। “जो काम नहीं करेगा वह खाना नहीं खायेगा” का साम्यवादी सिद्धान्त सदा से संसार के श्रमजीवियों का सपना बनता आया

है क्योंकि इस व्यवस्था में शोषण का स्थान होता ही नहीं। इसके अतिरिक्त वितरण के संगठन में [Organisation of distribution] इस सिद्धान्त के द्वारा लोगों की माँगों उनके श्रम के अनुसार निर्धारित की जा सकती हैं।

[10] जहाँ तक वेतन का सम्बन्ध है पूँजीवाद की तरह समाजवाद में वेतन का निर्धारण मजदूरों की माँग और पूर्ति [Demand and supply] के अनुसार नहीं होता। समाजवाद में सामाजिक आवश्यकताओं [Social needs] को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय आय का बचा हुआ भाग वेतन के रूप में मजदूरों को दिया जाता है। पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों ने इसकी बड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि अगर समाजवाद मजदूरों को उत्पादन का पूरा भाग उन्हें नहीं देता तो मार्क्स के अनुसार यह शोषण हुआ। यह विचार युक्तिसंगत नहीं मालूम पड़ता। समाजवाद में मजदूरों की सरकार अगर श्रम-उत्पादन [Labour produce] का एक अंश रोक लेती है तो यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों की ही भलाई में व्यय होता है। पूँजीवाद में यह सम्भव नहीं है।

[11] व्यक्तिगत प्रेरक [Personal incentive] को पूँजीवाद और समाजवाद दोनों ही अन्धे तथा अधिक उत्पादन के लिए अनिवार्य मानते हैं। पूँजीवाद में इस काम के लिए केवल आर्थिक प्रलोभन का सहारा लिया जाता है। समाजवाद में आर्थिक प्रलोभन के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक [Psychological and emotional] प्रेरकों को लगभग बराबर महत्व दिया जाता है।

[12] प्रतिस्पर्धा [Competition] पूँजीवाद का मूल मंत्र है। इसके उत्पादन संगठन में विदेश, अपव्यय तथा असन्तुलन का विकराल रूप दिखलाई पड़ता है। समाजवाद में भी प्रतिस्पर्धा के द्वारा उत्पादन में चमत्कारी वृद्धि सम्भव हो सकती। किन्तु समाजवादी प्रतिस्पर्धा में योजना के लक्ष्यों को पूरा करके उसके आगे बढ़ने की स्वास्थ्यप्रद प्रवृत्ति देखी जाती है।

## समाजवाद और साम्यवाद [Socialism and Communism]

पूँजीवाद के अलावा जिस नई सामाजिक संगठन-प्रणाली की कल्पना मार्क्स तथा एंजिल्स ने किया था उसके दो चरण [Phases] हैं—पहला, समाजवाद और दूसरा, साम्यवाद। इस प्रकार नए सामाजिक संगठन की ऐतिहासिक परिपक्वता [Maturity] के यह केवल दो स्तर हैं। इनके सिद्धान्त और रूपरेखा समान हैं। साम्यवाद के उच्चस्तर का पहला विवरण मार्क्स के “गोथा कार्यक्रम की विवेचना” [Critique of Gotha Programme] में मिलता है। उसके अनुसार इस स्तर तक विकास होने पर एक ऐसा समाज तैयार होगा जिसमें कठोर श्रम विभाजन [Divi-



sion of Labour] की दासता से मनुष्य मुक्त हो जायगा; मानसिक तथा शारीरिक श्रम में कोई अन्तर न होगा, काम [work] केवल जीविका का साधन मात्र न रहकर, जीवन की प्रथम आवश्यकता बन जायगा, लोगों के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीय [all sided] विकास होगा; समाज की उत्पादन शक्तियाँ इतनी बढ़ेंगी कि ऐश्वर्य एव सम्पत्ति की बाढ़-सी आ जायगी; उत्कृष्ट मानसिक विकास से हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम तथा आवश्यकता के अनुसार साधन मिल सकेगा, तब कही जाकर ऐसी स्थिति पैदा होगी कि निःस्वार्थ त्याग, स्वशासन तथा कर्तव्यपरायणता के विकास के कारण राज्य की आवश्यकता ही समाप्त हो जायगी [state shall wither away] ।

साम्यवाद की उपरोक्त रूपरेखा को व्यवहारिक रूप देने में कितना समय लगेगा, इस पर साम्यवादी अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है। स्टालिन की मृत्यु के पहले तक तो यही माना जाता था कि साम्यवाद तक पहुँचने में सोवियत रूस को अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। किन्तु उसके मृत्यु के बाद प्रधान मंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने कम्युनिष्ट पार्टी के बीसवें अधिवेशन में घोषित किया कि देश साम्यवाद के स्तर तक पहुँचने के लिए तैयार है। उनकी प्रेरणा पर रूसी अर्थशास्त्रियों ने सोवियत समाज की साम्यवादी रूपरेखा पर विचार प्रकट करना शुरू किया। मार्क्स और लेनिन ने साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था का बहुत धुंधला-सा चित्र दिया है। इसलिए इस नए संगठन के पूरे विस्तार को तैयार करने की जिम्मेदारी आधुनिक अर्थशास्त्रियों पर ही पड़ी। लेनिन के अनुसार साम्यवाद के आरम्भ होने पर राज्य के शासन कार्य कम हो जायेंगे क्योंकि इनकी देख-रेख जनता स्वयं राष्ट्रीय आर्थिक परिषदों [National economic councils] तथा मजदूर संघों [Trade Unions] के रूप में सम्भाल लेगी। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में आधुनिक रूसी साहित्य में निम्नलिखित विशेष परिवर्तनों का इशारा मिलता है। इनके अध्ययन से रूस में आने वाले आर्थिक संगठन का अनुमान लगाया जा सकता है।

[1] वर्तमान व्यवस्था में रूस में दो प्रकार की सम्पत्ति पाई जाती है—राज्य सम्पत्ति तथा सामुदायिक फार्मों की सम्पत्ति। साम्यवाद में इनकी आपसी भिन्नता को मिटाकर केवल एक प्रकार की सम्पत्ति रहेगी—राज्य सम्पत्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्र नष्ट हो जायगा। अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व का [Individual ownership] तथा वर्ग स्वामित्व [Group ownership] को उठा देने का निश्चय किया गया है।

\* [2] सामुदायिक फार्म में दो बड़े परिवर्तन होंगे। अविभाजनीय कोष [Indivisible fund], जिसे सामुदायिक फार्म के सदस्यों ने अपनी बचत से बनाया था, अब राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जायगा। फार्म के सदस्यों को मिली हुई निजी जमीन [Personal Plots] उनसे ले ली जायगी।

[3] इन परिवर्तनों के द्वारा धीरे-धीरे मजदूर और किसान के बीच का अन्तर समाप्त हो जायगा। समाज में केवल एक वर्ग होगा और उत्पादन के साधनों का एक प्रकार का स्वामित्व होगा।

[4] उत्पादन पद्धति के लगभग पूर्ण यंत्रीकरण [Complete Mechanisation] के द्वारा कृषि तथा उद्योग में बुद्धिजीवी और श्रमजीवी [Mental and physical labour] में कोई भेद न रहेगा, प्रत्येक मजदूर को विज्ञान तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना होगा। बिना इसके सर्वव्यापी यंत्रीकरण के कारण किसी भी प्रकार की मजदूरी करना सम्भव न होगा।

[5] न्यूनतम और अधिकतम वेतन को समानता की ओर बढ़ाकर साम्यवाद में समान वेतन [equal wages] की स्थिति प्राप्ति की जायगी। किन्तु इस स्थिति तक पहुँचने में काफी समय लगेगा।

[6] साम्यवाद में वस्तु तथा मुद्रा सम्बन्ध [Commodity and monetary Relationship] उठाया न जा सकेगा जब तक कि सारे ससार में साम्यवाद नहीं हो जाता। इसका कारण यह है कि बिना इस सम्बन्ध के साम्यवादी और पूँजीवादी देशों का आपसी सम्पर्क असम्भव हो जायगा।

[7] साम्यवाद और विज्ञान अमित्र है। साम्यवाद की स्थापना में वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा दृष्टिकोण उत्पन्न करने के मार्ग में से हर एक बाधा हटाना होगा। दूसरे शब्दों में, धर्म और धार्मिक विचार का समूल्य उन्मूलन अनिवार्य है।

[8] साम्यवादी संगठन में केन्द्रीय संचालन एवं स्वामित्व के उचित स्थान को लेकर साम्यवादी अर्थशास्त्रियों में मौलिक मतभेद हुआ है। युगोस्लाविया के अर्थशास्त्रियों के अनुसार साम्यवाद उस समय तक नहीं आ सकता जब तक कि राजकीय-सम्पत्ति समूह-सम्पत्ति [Group property] में नहीं बदल दी जाती। बिना इसके देश की जनता असली साम्यवादी स्वशासन [Communist self government] तक नहीं पहुँचेगी। रूसियों का विचार है कि एकमात्र, सर्वव्यापी राज्य स्वामित्व ही साम्यवादी स्वशासन की स्थिति है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कठोर केन्द्रीय संचालन और स्वामित्व को कम नहीं किया जा सकता, वरन् बढ़ाना पड़ेगा।

[9] जहाँ तक राज्य की आवश्यकता समाप्त होने का सम्बन्ध है, रूसी विचारकों के अनुसार, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्रमशः शासन के प्रत्येक कार्य में जनता का सक्रिय सहयोग बढ़ाना जायगा जिससे समाजवादी प्रजातंत्र [Socialist democracy] का क्षेत्र बराबर बढ़ता रहे। इसके साथ-साथ नागरिकों को साम्यवाद तक उठाने के लिये हर प्रकार से तैयार किया जायगा। किन्तु जब तक पूँजीवादी राष्ट्रों द्वारा

आक्रमण का भय बना है, अर्थात् जब तक विश्वव्यापी साम्यवाद नहीं स्थापित होता, तब तक राज्य का अस्तित्व बना रहेगा।

इस अस्पष्ट तथा अपूर्ण विवेचना से यह नतीजा निकलता है कि रूस के नए नेता रूसी इतिहास में एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। रूस की वर्तमान सप्त-वर्षीय योजना समाजवाद को साम्यवाद में बदलने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयत्न है। यह पूरी तरह न जानते हुए भी, कि जिस साम्यवाद की प्राप्ति के लिए देश जा रहा है वह वास्तविकता में क्या है, रूस प्रायः अज्ञात की ओर अग्रसर हो रहा है। बुनियादी तौर पर साम्यवादी की दो आवश्यकताओं पर प्रयोग किया जा रहा है। पहला, किसी भी मूल्य पर किसी तरह उत्पादन में अधिकतम वृद्धि, दूसरा सर्वव्यापी पूर्ण राज्य-स्वामित्व तथा संचालन की स्थापना।

## अर्थ-व्यवस्था व आयोजन प्रणाली का संगठन

[Economic Organisation and Planning System]

### आयोजन-प्रणाली

समाजवाद को यथार्थ बनाने के प्रयत्न में जिस रूसी आर्थिक संगठन का निर्माण हुआ, वह इतना नया और आश्चर्यजनक था कि आरम्भ में दुनिया ने इसे गम्भीरता से मानना ही अस्वीकार कर दिया। धीरे-धीरे अपने प्रयोगात्मक काल से निकल कर यह संगठन जब सफलता की ओर अग्रसरित हुआ, तब दो विचारधाराएँ उत्पन्न हुईं। प्रथम ने रूस को पृथ्वी पर आदर्श मानकर उसका अधानुसरण किया—दूसरे ने अज्ञान, ईर्ष्या तथा निजी दम्भ से प्रेरित होकर मखौल उड़ाना आरम्भ किया। दोनों ही विचारधाराएँ सतुलन से दूर, सर्वांग तथा पक्षपात से प्रभावित हैं। यह कहना उचित नहीं है कि रूस ने आदर्श की प्राप्ति कर लिया और यह कहना भी अनुचित है कि रूसी अर्थव्यवस्था, स्वयं कुछ नहीं, केवल पूँजीवाद का रूपान्तर है। रूस समाजवादी सिद्धान्तों पर सगठित होने का एक प्रयास है, इसमें कोई सदेह नहीं। नई दिशा में पहला प्रयत्न होने के कारण सिद्धान्त और संगठन की अनेकों जटिल गुत्थियाँ प्रकट होना स्वाभाविक है। ये समस्याएँ व्यवहारिक समाजवाद की दुर्बलता के चिन्ह नहीं हैं। प्रथम प्रयत्न की भूलों को समाजवाद के विनाश की पूर्व-सूचना न समझना चाहिये। रूसी अर्थव्यवस्था ससार के आर्थिक संगठन में नवीनतम एवं निश्चित रूप से स्थायी कड़ो है। इसे हँसकर टाल देना मूर्खता ही नहीं विनाश होगा। इस संगठन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि व विशेषताओं का अध्ययन रुचिकर तथा लाभपूर्ण सिद्ध होना चाहिये।

रूस की वर्तमान अर्थव्यवस्था, आयोजित व्यवस्था [Planned economy] कहलाती है। पूँजीवाद के अन्तर्गत व्यक्तिगत कर्तव्य और कार्यों पर आधारित अर्थ-व्यवस्था को स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका खास कारण यह है कि व्यक्तियों को अपने मनचाहे तरीके से धन कमाने की छूट है। इतना जरूर है कि कानून खुले आम समाज विरोधी व उगारों से धन-लाभ करने की आशा नहीं देता। इन कानूनों में तेज लोगों ने ऐसी कमजोरियों का पता लगा लिया है कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः कुछ भी किया जा सकता है। पूँजीवाद की अन्य बुराइयाँ भी आयोजित अर्थ-

व्यवस्था में दूर की गई है जैसे, साधनों का अपव्यय, राष्ट्रीय धन का असन्तुलित वितरण, प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होने वाली बुराइयाँ और आर्थिक लाभ को अधिकतम महत्व ।

योजना का अर्थ अलग-अलग दशाओं में विभिन्न प्रकार से सामने रखा गया है । मामूली तौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक योजना राष्ट्र के विकास की एक पद्धति है जिसके द्वारा उपलब्ध साधनों के अधिकतम प्रयोग से कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उन्नति की जा सके । योजना में उपभोक्ताओं का शासन [Consumers sovereignty] तथा स्वतन्त्र उत्पादकों के काम का सहारा लिये बिना अर्थ-व्यवस्था चलाती है । मुद्रा, बाजार तथा माँग-पूर्ति द्वारा मूल्य निर्धारण का कोई महत्व नहीं रहता । इनका काम एक केन्द्रीय आर्थिक संचालन समिति करती है जिसके सभी सदस्य राज्य कर्मचारी होते हैं । इन्हें प्रशिक्षित और राजनैतिक दृष्टि से सबसे योग्य अर्थविशेषज्ञ माना जाता है । इनका मुख्य काम देश की समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सन्तुलन [Co-ordination] लाना होता है । इस प्रकार आर्थिक निर्णय, व्यक्तिगत हाथों से हटकर सामूहिक रूप से सारे समाज की भलाई के लिये किया जाता है । जनता के प्रतिनिधि के रूप में यह काम राज्य अपने हाथों में ले लेता है ।

### उत्पादन के साधनों का सामुदायिक स्वामित्व

[Collective Ownership of Means of Production]

मार्क्सवाद पर आधारित होने से निजी सम्पत्ति [Private Property] का उन्मूलन रूसी योजना का गुण बन गया । उत्पादन के प्रत्येक साधन पर पूर्ण राज्य-स्वामित्व स्थापित किया गया । इसका प्रमुख कारण लाभ के लिये होने वाला सामाजिक शोषण रोकना था । सम्पत्ति के समाजीकरण से इन्सान द्वारा इन्सान का अनुचित लाभ उठाना बन्द करने का प्रयत्न हुआ । इसके उपाय किये गये कि भविष्य में लोग सम्पत्ति इकट्ठा न कर सकें । विरासत और उत्तराधिकार के नये नियमों से धन-सम्पत्ति का हस्तान्तरण कम से कम कर दिया गया । उद्योग, व्यापार तथा कृषि में निजी संपत्ति और कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया । नवीन आर्थिक नीति के बाद व्यक्तिगत रूप से व्याज, लाभ तथा किराया पाना असम्भव तथा अवैधानिक बन गया । कम के कम सिद्धान्त में श्रम का अतिरिक्त उत्पादन [surplus value] होना बन्द हो गया क्योंकि अब मजदूर, मजदूरों के राज्य के लिये काम करते हैं । अर्थात् मजदूर अपने-आप के लिये श्रम व उत्पादन करता है । इस हालत में शोषण असंभव हुआ ।

उत्पादन के साधनों का राज्य-स्वामित्व या सामुदायिक स्वामित्व का अर्थ यह नहीं कि सभी उत्पादन के कार्य केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार चलायेगी । कुछ प्रमुख

क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य उद्योगों को राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलाता। वे सहकारी और व्यक्तिगत हाथों में छोड़ दिये जाते हैं। इन पर राज्य का अप्रत्यक्ष निर्देशन [indirect direction] रहता है।

योजनाओं के अन्तर्गत निजी सम्पत्ति [Private Property] के उन्मूलन से यह न समझना चाहिये कि रूस में व्यक्तिगत सम्पत्ति [personal property] एकदम नहीं होती। हर नागरिक व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकारी है किन्तु यह उपभोग के लिये होनी चाहिये, उत्पादन के लिये नहीं। इतना ही नहीं, कृषि-क्षेत्र में तो सामुदायिक किसानों को थोड़ी-सी व्यक्तिगत जमीन रखने का भी अधिकार है जिसकी उपज उनकी निजी आय हुई।

### सामुदायिक निर्णय तथा संचालन

केन्द्रीय संचालन द्वारा सामाजिक लक्ष्यों की स्थापना और उसकी पूर्ति के लिये साधनों के बँटवारे का सामूहिक नाम योजना है। सामाजिक प्रयत्न तथा परिश्रम को विकास की ओर केन्द्रित करने का काम एक केन्द्रीय संचालन संस्था अर्थात् राजकीय योजना आयोग [State Planning Commission] करता है। इसके लिये प्रचार, प्रेरणा और दबाव से काम लिया जाता है। एकछत्र राजनैतिक दल, राज्य शक्ति, मजदूर सघ, ग्रामीण संगठन, औद्योगिक सघ [Trust], सिंडीकेट, बैंक, सहकारी समितियाँ, समाचार-पत्र, शिक्षा संस्थाएँ इत्यादि साधनों के चतुर इस्तेमाल से जनता पर ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव [psychological effect] डाला जाता है कि योजना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। रूस में आयोजन [Planning] की आश्चर्यजनक सफलता का यही कारण है। रूसी योजनाएँ समाज का अपना पवित्र कर्तव्य होती हैं : वे राज्य की इच्छाओं का कोरा ब्योरा नहीं होती। चंद व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित एक कार्यक्रम को प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और गर्व बना देना रूसी योजनाओं का स्वाभाविक गुण है। सोवियत योजना तथा संगठन की शक्ति उसके कार्यप्रणाली में नहीं है। यह तो वस्तुतः अपूर्ण है क्योंकि पूर्णता की गहराइयों तक पहुँचने का इसे कम समय मिला है। इसकी शक्ति का आधार तो इसकी सामाजिक नींव में है। देश के विकास में इस बात को नया महत्व और उचित प्रभाव देकर रूस ने मनुष्य समाज की उन्नति का नवीन युग आरम्भ कर दिया।

सामुदायिक निर्णय का प्रथम प्रभाव उपभोक्ताओं की रुचि [Consumers' Preference] पर पड़ा। स्वतन्त्र अथवा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेको दबाव तथा तनाव उत्पादन के साधनों और शक्तियों को एक साथ अपनी ओर खींचते हैं। इससे लक्ष्य व कार्यक्रम में विनाशकारी विरोधाभास [Paradox] पैदा होता है। पूँजीवाद में

आर्थिक साधनों का बँटवारा उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार असंख्य व्यापारियों के निर्णय द्वारा होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ता, उत्पादक, पूँजीपति [Financiers], व्यापारी तथा अन्य कितने ही वर्गों में स्वार्थ संघर्ष [Clash of interests] होना जरूरी है। इससे बचने का अकेला उपाय रूस ने अपनाया। कठोर केन्द्रीय संचालन और निर्णय द्वारा स्वार्थ-संघर्ष का अन्त किया जा सका। सभी आर्थिक निर्णय तथा लक्ष्य-निर्धारण व्यक्तिगत प्रभावों से हटाकर एक केन्द्रीय संस्था को सौंप दिये गये। इस केन्द्रीयकरण से व्यक्तियों व वर्गों के स्वार्थपूर्ण हितों के बजाय देश और समाज की भलाई के लिये कोशिश की जा सकी। देश के आर्थिक साधनों का सबसे लाभपूर्ण प्रयोग केन्द्रीय संचालन में हो सकता है। यहाँ पर सीमित साधन अनावश्यक वस्तुओं में केवल इसलिये नहीं लगा दिये जाते कि उपभोक्ताओं की रुचि कोका-कोला या नाइलोन् की तरफ बहक गई है। इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं की रुचि उसकी मात्रा [Quantity], गुण [Quality] एवं प्रकार [Variety] को उचित सीमाओं में बाँधना पड़ता है। राशनिंग, उपभोग के साधन की कृत्रिम कमी [Artificial scarcity] तथा प्रमाणीकरण [Standardisation] इसके लिये मुख्य साधन हैं। अतः आयोजन में जनता की आवश्यकता तथा रुचि वैक्तिक रूप से न निर्धारित होकर, सामूहिक रूप से निर्धारित होगी।

योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं [Priorities] के अनुसार आर्थिक साधनों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में बाँटा जाता है। इस काम में ध्यान रखा जाता है कि बँटवारे से साधनों का पूर्ण उपयोग और समाज का अधिकतम कल्याण हो। इसके लिये पहली समस्या उपभोग तथा उत्पादन उद्योगों [Consumers and Producers Industries] का आपसी अनुपात तय करना है। राष्ट्र की शक्ति उत्पादन-क्षमता पर निर्भर करती है जो कि स्वयं मशीनों से पैदा होती है। मशीनों को बनाने वाली मशीनें अथवा उत्पादन के साधनों का उत्पादन, अनिवार्य रूप से प्राथमिकता पाता है। अधिक-से-अधिक साधन इस ओर लगाने के लिये उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरी समस्या उद्योगों के स्थानीयकरण के बारे में आती है। केन्द्रीय संस्था इस निर्णय में बहुत-सी बातें देखती है। ईंधन [Fuel], कच्चा माल, श्रम और बाजार के अतिरिक्त देश में हर प्रदेश के सन्तुलित विकास को काफ़ी महत्व मिलता है।

रूसी योजनाकर्त्ताओं के सामने एक अत्यंत गम्भीर प्रश्न यह उठा कि देश के विकास का आधार कृषि को बनाया जाय या उद्योग को। स्टालिन ने समाजवादी योजनाओं का आधार औद्योगीकरण निश्चित किया। इस निर्णय के लिये अनेकों कारण जिम्मेदार हैं। सैनिक दृष्टिकोण से औद्योगीकरण अनिवार्य था। शत्रुतापूर्ण पूँजीवादी देशों

ने अपनी रक्षा के लिये आधुनिकतम अस्त्रों का निर्माण उद्योग पर निर्भर करता है। उद्योग के विकास से जनता का मजदूरीकरण [proletarianization] करके समाजवाद की जड़ों को मजबूत और गहरी बनाना सम्भव था। नये बोल्शेविक ढाँचे में जनता की आस्था उत्पन्न करने का सबसे आसान उपाय विस्तृत उद्योगों का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करना था। इसके लिये औद्योगिक उन्नति से प्रभावशाली कुछ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, औद्योगीकरण के आदर्श ने साम्यवाद के अनुयायियों के सामने नया कार्यक्षेत्र खोल दिया। इसकी बहुत जरूरत थी। जिस क्रान्तिकारी जोश की आग ने जारशाही का अंत किया था उसकी गर्मी और चमक धीमी पड़ने लगी थी। इसका कारण विश्व-साम्यवादी क्रान्ति के आदर्श का परित्याग और नवीन आर्थिक नीति के समय में पूँजीवाद को छूट था। इसे दुबारा प्रज्वलित करने के लिये औद्योगीकरण के रूप में साम्यवादियों [विशेषकर नवयुवक क्रान्तिकारियों] को नया आदर्श मिला जिसकी प्राप्ति में वे अपनी प्रतिभा एवं उत्साह को लगा सके। औद्योगीकरण के जोश में विशेष रुचि, धार्मिक कर्तव्य तथा नैतिक अनुशासन की कट्टरता लाने के लिये प्रतिस्पर्धा का पुट दिया गया। राष्ट्र के कोने-कोने में पूँजीवादी देशों [खास कर संयुक्त राज्य अमेरिका] के उत्पादन-स्तर से भी आगे बढ़ने की कोशिश करने का नारा बुलंद किया गया। जनता के असंतोष पर विजय पाने के लिये षड्यंत्रकारियों और विदेशी जासूसों की देशव्यापी खोज, खुले मुकदमे और फाँसियों के साथ विदेशी आक्रमण के भय का नाटक रचा जाता था। नीति यह थी कि सिवाय औद्योगीकरण और शक्ति-सचय के जनता को कभी और कुछ सोचने का अवकाश ही न मिले। इस प्रकार औद्योगीकरण दो बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन बन गया। बाहरी तरीके से, सैनिक शक्ति को बढ़ाना; आन्तरिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के समाजवादी सगठन में विस्तार, दृढ़ता और गतिशीलता लाना। पहला उद्देश्य विदेशी पूँजीवादियों से रक्षा करता था : दूसरा देश के अंदर पूँजीवाद के अवशेषों के समूल विनाश के लिये उद्यत था।

कृषि और उद्योग के आपसी महत्व को लेकर राजनैतिक क्षेत्र में इतनी तनातनी पैदा हुई कि बुलारीन, रेकोव और टांस्की ऐसे प्रभावशाली नेताओं को जान से हाथ धोना पड़ा। सफल औद्योगीकरण के लिये कृषि का पुनर्संगठन आवश्यक था। दूसरे शब्दों में कृषि का भी औद्योगीकरण किया गया। इस काम के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया—कृषि का विस्तृत यंत्रीकरण [mechanisation] और कृषि सगठन का सामुदायिक ढाँचा [collective set up]। इनकी मदद किसानों में समाजवादी सिद्धान्तों को फैलाने का प्रयत्न था। सदा से रूस एक कृषिप्रधान देश रहा है किन्तु आधुनिक रूस को केवल उन्नत देश कहना अधिक उचित मालूम पड़ता है। वर्तमान सोवियत योजना [सप्तवर्षीय योजना 1959-1965] कृषि और औद्योगिक उत्पा-



दन को एक में विलय [Integrate] कर देना चाहती है। इसके द्वारा कृषि-उत्पादन का संगठन एकदम औद्योगिक उत्पादन की तरह बनाया जा रहा है जिससे भूमि और कारखानों के उत्पादन में कोई अंतर न रहे।

पूँजीवादी विचारधारा के व्यक्तियों में बहुत बड़ी शंका पैदा होती है कि केन्द्र में बैठे एक संस्था के सात या आठ सदस्य सारी अर्थव्यवस्था का सफल मार्ग निर्धारण तथा संचालन कैसे कर पायेंगे। उद्योग में तो यह कठिनाई से सम्भव हो सकता है। कृषि में प्रकृति की कृपा एवं कोप का प्रभाव अधिक होता है। उत्पादन के लक्ष्य बनाना तथा पूर्वनिश्चित उत्पादन की पूर्ति प्रायः असम्भव दीखती है। अत्यंत सतर्कता और विचार के साथ-साथ विज्ञान तथा अनुभव के आधार पर यह काम किया जाता है जिससे प्राकृतिक बाधाओं का प्रभाव कम-से-कम पड़े।

रूस की अर्थव्यवस्था, कुशलता और कम लागत की दृष्टि से आदर्श नहीं है। किन्तु इसमें वह भयंकर और घृणित अवस्था कभी नहीं उत्पन्न हो सकती कि विहार-नौकाओं [yatch] तथा सुन्दरता-गृहों [beauty parlours] का प्रचुर उत्पादन हो जब कि करोड़ों व्यक्ति भोजन और आश्रय के अभाव में रहे : एक ही समय यह नहीं हो सकता कि शहरों में मजदूर रोटी बिना भूखे मरे, गाँवों में गेहूँ भरा रहने से किसान बर्बाद हो जाय।<sup>1</sup>

### समाजवादी उत्पादन प्रणाली

प्रतिस्पर्धा [Competition]—सोवियत अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के पूँजीवादी स्वरूप का कोई स्थान नहीं है। लाभ की लालच से प्रेरित होकर उत्पादकों की आपसी प्रतिस्पर्धा पूँजीवाद की नींव है। इससे उत्पन्न होने वाली विशेष हानियों में यह मुख्य है : उत्पादन के प्रकार [variety] में अनावश्यक वृद्धि, आर्थिक साधनों का उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग, समाज के हर हिस्से का सन्तुलित विकास न होना, तथा उत्पादन और उपभोग -के बीच आपसी सम्बन्ध में कमी। समाजवादी उत्पादन एक विशाल सहकारी संगठन की तरह काम करता है जिससे अधिकतम सन्तुलन द्वारा राष्ट्रीय साधनों का अनावश्यक प्रयोग तथा अपव्यय मिटाने की चेष्टा की जाती है।

प्रतिस्पर्धा से कुछ लाभ भी है जैसे उत्कृष्ट उत्पादन-प्रबन्ध [production management], पूँजी और मशीन का अधिकतम प्रयोग एवं लागत घटाने का प्रोत्साहन। समाजवाद में इनको अनार्थिक प्रतिस्पर्धा [non-economic competition] से पाने की कोशिश होती है। इसी से समाजवादी प्रतिस्पर्धा [Socialist Competition] का अनोखा सिद्धान्त लागू किया गया। इसमें अर्थव्यवस्था के हर-

<sup>1</sup> John Strachey : How Socialism Works. pp 44-45

एक अंग में काम करने वालों को उत्पादन सेनानी [ production soldiers ] कहते हैं। वह सेनानी पुराने उत्पादन के उच्चतम स्तर [ records ] को तोड़ने के लिये एक दूसरे को ललकारते हैं। सफलता के आकर्षक पारितोषिक इनको आगे बढ़ने के लिये व्यग्र बनाते हैं।<sup>1</sup> इसके द्वारा विना आर्थिक लाभ की आशा के अपूर्व उत्पादन वृद्धि सम्भव हुई। नये बुद्धिवादियों को आदर तथा मान्यता देकर उत्साहित किया गया। रिकार्ड तोड़ने वाले मजदूरों [ Stakhanovites ] का एक सम्मानित सामाजिक वर्ग बनाया गया।<sup>2</sup>

प्रेरणा [Incentive]—सामान्य विश्वास है कि मनुष्य केवल धन-सचय के लिये काम करता है। जिस समाज से निजी सम्पत्ति उठा दी जायगी, वहाँ कार्य तथा उत्पादन के लिये उत्साह, बल और धैर्य कहाँ से आयेगा। यह सिद्ध करके कि निजी स्वार्थ की प्रेरणा ही अकेली उत्तेजक नहीं है सोवियत सच ने ससार को चमत्कृत कर दिया। अनेकों समाजवादी प्रेरक सामने आये जिनका सफल प्रयोग रूस की आर्थिक शक्ति का आधार बन गया। लाभ की आशा सोवियत सच में की जाती है किन्तु यह उत्पादन का मुख्य ध्येय नहीं है। सफल प्रयत्न का मापक लाभ की मात्रा के अतिरिक्त कम समय में अधिक उत्पादन, श्रमिकों की दशा में सुधार और उत्पादन की लागत में कमी बन गया। पूँजीवाद में कुशल उत्पादन के लिये धन से उत्पन्न सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन के सुखों की लालच दी जाती है। समाजवाद ने इन सब के स्थान पर व्यक्तिगत प्रभाव तथा शक्ति [personal influence and power] को लाकर बैठा दिया। इसमें सफलता का पारितोषिक महान् है : असफलता का दंड कठोर। किसी भी योग्य व्यक्ति के सामने, यदि वह साम्यवादी दल का सदस्य है, शक्ति प्राप्त करने की इतनी सुविधा और अवसर है कि आर्थिक लाभ की ओर ध्यान ही न जायगा। तर्क के लिये कहा जा सकता है कि धन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि का साधन मात्र है। धन के अतिरिक्त, प्रभुत्व और शक्ति विशेषाधिकारों द्वारा भी मिल सकते हैं। प्रोफेसर मोल्टन के इस विचार से सहमत होना कठिन मालूम पड़ता है कि व्यक्तिगत उत्साह, प्रेरणा व कार्यकुशलता केवल स्वार्थ और निजी लाभ से ही सबसे अच्छी तरह उत्पन्न होती है। वे समझते हैं कि जाश, पद, सम्मान, अधिकार और दंड का भय [ जो रूस में प्रयोग होता है ] केवल ऋणात्मक दबाव [Negative Compulsions] है।<sup>3</sup> यह अनुचित है। इतना तो मानना ही पड़गा कि आर्थिक निर्जी

1 Williams, A. R. : The Soviets, p. 266

2 Stalin Problems of Leninism, pp. 372-373.

3 Moulton H. G. . Controlling Factors in Economic Development, p. 162.

स्वार्थ के अतिरिक्त अन्य प्रभावशाली प्रेरक भी हो सकते हैं। और रूस ने स्वार्थ को तो नष्ट नहीं किया, केवल स्वार्थ का रूप बदल दिया : आर्थिक स्तर से उठ कर, उससे ऊँचे मनोवैज्ञानिक उत्तेजकों तक पहुँचने का प्रयत्न किया गया।

आरंभ में आर्थिक प्रबंध और राजनैतिक कार्यक्रम एक में मिला दिया गया था। नवीन आर्थिक नीति और उसके बाद इनको पृथक् करने का असफल प्रयत्न हुआ। किन्तु इससे प्रबंधकुशलता में नई प्रेरणा मिली। सफल प्रबंधक पार्टी में प्रभावशाली बन जाता है : पार्टी में प्रभाव शक्ति का परिचायक है। सफल प्रेरणा के लिये आर्थिक वेतन [money wages] के अलावा दूसरी सुविधाएँ अधिक सफल हुईं। मार्क्स का वह सिद्धान्त बदल दिया गया जिसके अनुसार श्रम का भुगतान श्रमिक की आवश्यकता से सम्बन्धित होना चाहिये। आवश्यकता की जगह उत्पादन और लाभ वेतन का मापक बना। लगन से काम करने वाला मेहनती मजदूर दूसरे साथियों से कई गुना अधिक कमा लेता है। वेतन के अतिरिक्त मोटर, निवास-स्थान, यात्रा का खर्च, प्रशिक्षण व शिक्षा के साधन और सुविधा दी जाने लगी। यह सुविधाएँ नये वर्ग के प्रबंधकों और श्रमिकों को कहीं अधिक आकर्षक तथा लाभदायक थी; क्योंकि अधिकतर नये प्रबंधक अत्यन्त गरीब मजदूर श्रेणी से ऊपर उठे थे। इन बातों का प्रभाव इसलिये भी अधिक पड़ता था कि सामाजिक प्रतिष्ठा का अनुमान द्राव्यिक वेतन के स्थान पर इन विशेषाधिकारों द्वारा निश्चित किया जाता था। अन्त में, समाजवादी प्रणाली में कार्यकुशलता और परिश्रम बढ़ाने के लिये बल-प्रयोग का विशेष महत्त्व रहा है। कठोरता के साथ निरन्तर बल-प्रयोग आश्चर्यजनक सफलता का बहुत बड़ा कारण बना।

लाभ [Profit]—लाभ के जिस रूप को, जिस मात्रा में, पूँजीवाद महत्त्व देता है, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था से उठा दिया गया। फिर भी समाजवादी उत्पादन क्षेत्र में लाभ की एक नई शक्ति को काफी ऊँचा महत्त्व दिया जाता है। पूँजीवाद में उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिये होता है, न कि सामाजिक कल्याण के लिये। मार्क्स ने कहा था कि पूँजीवादी उत्पादन उस समय नहीं रुकता जबकि उसकी आवश्यकता सन्तुष्ट हो चुकी हो। यह उस समय रुकता है जब लाभ की प्राप्ति कम होने लगे। बाजार की प्रणाली [Market Mechanism] तथा एकाधिकार के द्वारा लाभ कमाने के बड़े आसान तरीके निकल आये हैं। इतना ही नहीं, अक्सर तो श्रम उत्पादकता की वृद्धि, साधनों के अपेक्ष्य में बचत इत्यादि से लाभ का कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता। समाजवाद में लाभ का अर्थ केवल मौद्रिक लाभ [Money Profit] से नहीं लिया जाता। इसमें उत्पादन के प्रयोग का लाभ [Use-value] भी शामिल रहता है। हर कारखाने को उत्पादन की लागत घटाकर लाभ में विस्तार करने के लिये कहा जाता है। लेकिन अधिक लाभ के लिये दूसरी आवश्यकताओं पर उचित ध्यान न देना एक अपराध है।

योजना के लक्ष्य को पूरा करना, सामान की किन्म गिरने न देना और मजदूरों की दशा तथा वेतन में लगातार सुधार के साथ-साथ लागत कम करके अगर कोई कारखाना लाभ दिखलाता है, तभी इसको प्रशंसनीय माना जायगा।

**पूँजी [Capital]**—आयोजित रूसी अर्थव्यवस्था में पूँजी को वह श्रेष्ठता नहीं दी गई जो पूँजीवाद में दी जाती है। इसका स्थान यंत्र-कौशल [Technical Skill] और प्रबन्ध [Management] ने ले लिया। सिद्धान्त रूप से पूँजी, भूमि व श्रम को सनाजवाद में वस्तु [Commodity] नहीं माना जाता क्योंकि इनका क्रय-विक्रय नहीं होता। कारखाने इनको राज्य से अनुदान की तरह प्राप्त करते हैं। सामान्य पद्धति के अनुसार राजकीय बजट से एक साथ कार्यशील पूँजी [Working Capital] का अनुदान [Grant] दिया जाता है। इसी धन-राशि से कारखाने की स्थापना होती है। यह ऋण कभी वापस नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार औद्योगिक बैंक [Prombank] औद्योगिक निर्माण के लिये सारा प्रबन्ध कर देता है। पूँजी की समस्या इतने आसानी से हल हो जाने से इसके प्रयोग में लापरवाही और अपव्यय रूसी योजना में अब भी पाया जाता है।

स्थायी संपत्ति [fixed assets] की आयु पूरी होने पर उन्हें बेकार कर देने की [Write off] बड़ी अजीब प्रणाली सोवियत संघ में मिलती है। ऐसी मशीनों को कारखाने की पूँजी से एकदम हटा दिया जाता है। इस तरह होनेवाली हानि को न तो कहीं लेखा में दिखाया जाता है और न इससे कारखाने का लाभ प्रभावित होता है। यह एक खास कारण है कि रूस में मशीनों और दूसरी अचल सम्पत्ति को उनकी उपयोगिता समाप्त होने के पहले ही बेकार कर देने में कोई कारखाना नहीं हिचकता।

पूँजीवाद में श्रम-उत्पादकता, लागत और लाभ पर हास [Depreciation] की रकम का सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन रूस में उत्पादन की लागत में हास को बहुत कम महत्व दिया जाता है। 1955 में रूसी उद्योग के उत्पादन के कुल खर्चों में हास का अनुपात लगभग 3% था। केवल पेट्रोल उद्योग में 42.8% और बिजलीघरों में 16.8% हास किया गया।

### मूल्य निर्धारण [Price Formation]

समाजवाद में अर्थ का नियम [Law of Value] तथा मूल्य का उतना ऊँचा महत्व नहीं है जितना कि पूँजीवाद में होता है। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न भागों में उत्पादन के साधन और श्रम-शक्ति के बँटवारे का काम अर्थ के नियम द्वारा न होकर योजनाकर्ताओं द्वारा किया जाता है। फिर भी मूल्य निर्धारण में इसका प्रयोग हटाया न जा सका। उत्पादन के साधनों के राजकीय स्वामित्व ने इसमें रूपान्तर कर दिया।

इस सम्बन्ध में कुछ बातें रूसी योजना और व्यवस्था की विशेषताएँ कही जा सकती हैं।

[1] उत्पादन तथा उपभोग की वस्तुओं के मूल्य में आरम्भ से ही अन्तर पाया जाता है। कभी-कभी तो यह अन्तर काफी होता है। उपभोग की वस्तुओं का मूल्य 1924-25 में 44%, 1926-27 55% और 1955 में उत्पादन की वस्तुओं से 45% अधिक था। इतना अवश्य है कि स्तालिन की मृत्यु के बाद से इस अन्तर में कमी करने की माँग की जा रही है।

[2] रूस में मूल्य को अर्थ के सिद्धांत की अभिव्यक्ति मानते हैं लेकिन उनके विचार से किसी वस्तु के अर्थ [Value] और मूल्य में निश्चित सम्बन्ध होना कोई जरूरी नहीं है। मूल्य निर्धारण में अर्थ से भी महत्वपूर्ण योजना की दूसरी आवश्यकताएँ मानी जाती हैं।

[3] मूल्य पर माँग और पूर्ति का प्रभाव अत्यन्त सीमित रूप से पड़ने दिया जाता है वस्तुओं की माँग और पूर्ति का संतुलन, पूँजीवाद की तरह, जनता की माँग पर नहीं छोड़ दिया जाता। माँग का इतना प्रभाव नहीं होता कि प्रत्यक्ष रूप से वह उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने में सहायता दे। आपसी संतुलन के लिये फुटकर मूल्य [Retail prices] के स्थान पर उत्पादन से इशारा लिया जाता है। यह उत्पादन योजना से संचालित होता है।

[4] उत्पादन की मात्रा माँग से हमेशा कुछ कम रखी जाती है जिससे माँग और पूर्ति का संतुलन कभी बिगड़ने न पाये। बहु उत्पादन [Over-production] और आर्थिक मंदी [Economic Depression] इस प्रकार सदा के लिये दूर कर दिये गये। उपभोग की वस्तुओं की मात्रा और माँग में अधिक से अधिक अन्तर रखा जाता है। राष्ट्रीय साधनों को उपभोग की ओर से हटा कर भारी उद्योगों में लगाने का यह प्रचलित तरीका है।

[5] मूल्य के स्तर में स्थिरता लाना हर देश के लिये आवश्यक है, चाहे वह देश पूँजीवाद पर संगठित हो या समाजवाद पर। इस काम में सोवियत रूस ने विशेष सफलता पाई है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार आदर्श संयोजित अर्थव्यवस्था वह होगी जहाँ पर जनता की क्रय-शक्ति [Purchasing power] तथा बाजार में मिलने वाली वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। इसी संतुलन पर मूल्य-स्तर की स्थिरता निर्भर करती है। रूसी आयोजन इस संतुलन के लिये सदा प्रयत्नशील रहता है। फिर भी यदि इसमें कुछ विकार [Maladjustment] उत्पन्न होते हैं तो कई उपाय काम में लाये जाते हैं—कानून द्वारा मूल्य का स्तर घटाना-बढ़ाना, टैक्स और बलात् ऋण से आय को प्रभावित करना, तथा राशनिंग।

**व्यापार [Trade]**—सोवियत संगठन में व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना या उपभोक्ताओं की रुचि का पता लगाना नहीं होता। माँग से उत्पादन हमेशा कम रहने से विक्रेता अपना सामान बेचने में उत्साह, प्रचार, विज्ञापन का सहारा नहीं लेते। पूँजीवादी देशों की तरह क्रेताओं में “बाजार करने” [“Marketing”] का शौक नहीं हो पाता क्योंकि न तो उन्हें रोज नये माडल व डिजाइन दीखते हैं, न उनके पास इतनी क्रय-शक्ति होती है कि केवल फैशन में रहने के लिये खरीददारी कर सकें। समाजवादी उत्पादन पर उपभोक्ताओं की रुचि का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिये व्यापार का एक खास काम—उपभोक्ताओं की रुचि पता लगाना का—समाप्त हो गया। इन बातों ने व्यापार का महत्व बहुत घटा दिया।

क्रान्ति के बाद ही देशी तथा विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। देश में थोक व्यापार राजकीय संस्थाओं के हाथ में है। विभिन्न उत्पादनों को आयोजित मूल्य पर खरीद कर, सहकारी समितियों तथा कारखाना-स्टोर्स के जरिये, निर्धारित दाम पर उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है। फुटकर भाव अक्सर बदला करते हैं। इसके माध्यम से लोगों की आय और बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का विक्रय-मूल्य समुचित रखने का प्रयत्न होता है। लगभग 1950 से फुटकर व्यापार के लिये बड़े-बड़े शृङ्खला-बद्ध स्टोर्स [Chain Stores] सासुदायिक स्वामित्व में स्थापित हो रहे हैं। इनमें से कुछ का संगठन तो विकसित पश्चिमी दूकानों की तरह है।

आरम्भ में विदेशी व्यापार सोवियत राज्य के स्थापना और विकास में बहुत महत्वपूर्ण था। आजकल विदेशी व्यापार का महत्व आर्थिक की जगह राजनैतिक अधिक है। पूँजीवादी देशों से व्यापार करने की कोई आवश्यकता रूस को अभी नहीं है। आधा योरोप और चान रूसी उत्पादन पर निर्भर करता है। इसलिये अधिकतर विदेशी व्यापार समाजवादी क्षेत्र के अन्दर ही किया जाता है। काफी समय तक अपने उत्पादन की बाजार के लिये देश को चिन्ता न करनी होगी।

### सोवियत योजना प्रणाली में नई धाराएँ

सोवियत रूस की आयोजित अर्थव्यवस्था का बड़ा ही कठोर परीक्षण द्वितीय महायुद्ध ने किया। युद्ध के प्रभाव से योजना प्रणाली और भी परिष्कृत व सुस्त बनानी पड़ी। उसी समय से यह भी अनुभूति हुई कि कुछ आधारभूत परिवर्तन अनिवार्य हो गये हैं। इस दिशा में पहला कदम तो स्तालिन ने ही उठाया था, पर गतिपूर्ण प्रगति नये राजनैतिक संगठन में हुई।

### केन्द्रीयकरण [Centralisation]

इस समय तक रूस उन्नति के उस स्तर तक पहुँच चुका है जहाँ पर केन्द्रीय

संचालन और निर्देशन में कमी की जा सकती है। आरम्भ में इसकी मदद से राष्ट्रोन्नति की बुनियादी आवश्यकताओं का विकास किया गया। किन्तु अब स्थानीय [Local] तथा क्षेत्रीय [Regional] विकास पर अधिक महत्व दिया जा रहा है। केन्द्रीय संस्थाएँ प्रत्येक विषय का सारा विस्तार स्वयं न तैयार करके, अपना अधिक समय मुख्य नीति निर्धारण पर देने की चेष्टा कर रही हैं। सामुदायिक फार्म और प्रजातन्त्र राज्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई, वस्तुओं के वितरण में भी केन्द्रीय संस्थाओं के अधिकार कम किये जा रहे हैं, और योजना-निर्माण का आधार अब क्षेत्रीय विकास होगा। इस काम के लिये नये सगठन में सारा देश आर्थिक क्षेत्र [Economic Regions] में बाँट दिया गया। हर क्षेत्र में एक आर्थिक समिति [Economic Council] बनी जिसके सदस्यों में प्रायः हर वर्ग के व्यक्ति शामिल होते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूरी योजना बनाकर, केन्द्रीय योजना आयोग के पास भेजा जाता है जहाँ पर इन्हें संतुलित और सम्बन्धित करके, राष्ट्रीय योजना का जन्म होता है।

### दीर्घ-कालीन आयोजन [Long-range Planning]

समय के साथ योजना प्रणाली और संगठन में काफी विकास हो चुका है। इसलिये अब यह सम्भव हो सका कि भविष्य में और दूर तक देखने का सफल प्रयत्न किया जाय। साथ ही साथ, वैज्ञानिक तथा यान्त्रिक उन्नति ने उत्पादन सगठन के आकार और जटिलता [Complexities] में इतनी वृद्धि कर दिया कि योजना काल बढ़ाना पड़ा। 1959 से राष्ट्रीय आयोजन लम्बे अरसे के लिये निर्धारित किया जा रहा है। उद्योग के प्रत्येक विभाग, प्रजातन्त्र राज्य, आर्थिक क्षेत्र, कारखाने और निर्माण कार्य [Construction Project] के लिये योजना के लक्ष्य वार्षिक आधार पर बनाये जाते हैं।

### आयोजन का नया संगठन

अभी तक के रूसी आयोजन प्रणाली को विभागीय आयोजन [branch or departmental planning] कहा जा सकता है। इसमें अर्थ व्यवस्था को विभिन्न विभागों में बाँटा जाता है जैसे भारी उद्योग, हलके उद्योग, कृषि, व्यापार, यातायात, और वित्त। इस प्रथा में विकास तो जरूर हुआ किन्तु देश के विकसित और कम विकसित क्षेत्र, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र, उपभोक्ता और उत्पादक क्षेत्र में सामञ्जस्य व संतुलन उत्पन्न हो सका। इस कमी को दूर करने के लिये विभागीय आयोजन [branch planning] को क्षेत्रीय आयोजन [territorial planning] से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, शासन के क्षेत्रों [administrative regions] को भी आर्थिक दृष्टिकोण से पुनर्संगठित किया गया। 1957 में

सोवियत सघ 104 आर्थिक-शासन क्षेत्र [ economic-administrative regions ] में बाँटा गया। साथ ही साथ, सफल आयोजन की दृष्टि से सारे देश को 13 विशाल आर्थिक क्षेत्र [ economic regions ] के अन्दर रखा गया है। हर क्षेत्र में कई प्रजातन्त्र आ जाते हैं। इस तरह राष्ट्रीय तथा स्थानीय लाभ के लिये, देश के प्रत्येक स्थान की उन्नति और उनके साधनों का विकास करने को रूस उद्यत है।

**क्षेत्रीय विशिष्टीकरण तथा प्रमापीकरण** [Territorial Specialization and Standardisation of Products]

क्षेत्रीय आयोजन पद्धति में प्रत्येक क्षेत्र को कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर ही पूरा ध्यान देने को उत्साहित किया जा रहा है। जलवायु और साधनों के अनुसार विशिष्टीकरण को, वृद्ध और उत्पादन वृद्धि का प्रमुख साधन सिद्ध होने की आशा है। मास्को की आर्थिक समिति ने छोटे कारखानों के विविध उत्पादन में एकरूपता लाकर उन्हें आधुनिक, बड़े कारखानों में केन्द्रित कर दिया। इससे 1958 में लगभग 93 मिलियन रूबल की बचत हुई।

### संगठन तथा प्रबन्ध

**योजना संगठन** [Planning Organisation]

सोवियत सघ की स्थापना के बाद आर्थिक क्षेत्र पर राजकीय नियंत्रण तथा संचालन के लिए एक उच्चतम आर्थिक समिति [ Supreme Economic Council ] अथवा वेसेन्का [ Vesenkha ] की स्थापना हुई। राज्य के आर्थिक मामलों का अध्ययन करना और अर्थ व्यवस्था को साम्यवादी उद्देश्यों के लिये तैयार करना इसका ध्येय था। अनुभव, कार्यकुशलता तथा आँकड़ों की कमी से यह समिति बँधी रही फिर भी आर्थिक क्षेत्र पर इसका प्रभाव तथा शासन एकछत्र था।

1921 में नवीन आर्थिक नीति के आरम्भ से संयोजित विकास के लिये एक पृथक संस्था बनी जिसका नाम राजकीय योजना आयोग [ State Planning Commission ] अथवा गौस प्लान [ Gosplan ] था। अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा कुछ राज्य कर्मचारी इसके सदस्य थे। राष्ट्रीयकरण के बढ़ते हुए विस्तार का प्रबन्ध करने में विशेष रूप से योग्य एवं दक्ष संस्था की आवश्यकता गौसप्लान ने पूरा किया।

आरम्भ से इसका अधिकार केवल सलाह देने तक सीमित था। इसके मुख्य कार्य में आर्थिक पुनर्संगठन तथा नीति के विषय पर राज्य के लिये प्रसविदा तैयार करना, विशेष समस्याओं पर सलाह देना और विस्तृत योजना के लिये आँकड़े इकट्ठा



करना होता था। धीरे-धीरे इस सस्था के अधिकार बढ़ते गये। 1941 के विधान ने इसका अधिकार-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित किया—

[1] लम्बी अवधि, वार्षिक, तिमाही, तथा मासिक राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं की तैयारी।

[2] अन्य सस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का सारांश राज्य को देना। इन सस्थाओं में राजकीय विभाग और प्रजातन्त्र राज्य [republics] मुख्य थे।

[3] राज्य द्वारा स्वीकृत योजना की सफल पूर्ति पर नियंत्रण।

[4] समाजवादी अर्थव्यवस्था को विशेष समस्याओं का अध्ययन।

[5] समाजवादी लेखा [socialist accounting] का निर्देशन।

इन कामों को पूरा करने में गौस प्लान को स्थानीय योजना सस्थाओं का पूरा सह-योग मिलता था। योजना आयोग के बाद महत्व के अनुसार राज्यों की योजना समितियाँ [State Planning Committees] और क्षेत्रीय योजना समितियाँ [Regional Planning Committees] आती हैं। इनके अतिरिक्त शहरों में नगर योजना सस्थाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला योजना सस्थाएँ होती हैं। अपनी इन शाखाओं के द्वारा गौस ज्ञान-विशाल देश के कोने-कोने की और प्रत्येक स्थानीय आवश्यकताओं की पूरी खबर रखता था। इस संगठन से एक लाभ यह भी है कि स्थानीय उत्साह, कुशलता और साधन की खोज होती रहती है। अधिकार तथा निर्णय का यह विकेन्द्रीकरण इतना वास्तविक एवं सक्रिय है कि इसी पर योजना अपनी सफलता के लिए निर्भर करती है।

राजकीय योजना आयोग केवल आर्थिक क्षेत्र की सस्था नहीं है। समाज के हर एक अङ्ग का सतुलित विकास करना इसका ध्येय है। एक पूर्व निश्चित रूपरेखा पर हर क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक, आर्थिक और मानवीय साधनों का अधिकतम प्रयोग करने की चेष्टा की जाती है। वर्तमान अध्ययन में इसके आर्थिक रूप को देखना ही युक्तिसंगत होगा। इस दिशा में देश के विकास का आधार औद्योगीकरण होने से उद्योग, श्रम और कृषि ही विशेष महत्वपूर्ण हैं।

सुविधा के लिये योजना आयोग ने उद्योगों को तीन वर्गों में बाँट दिया : सघीय महत्व के उद्योग [union industries], प्रजातन्त्र राज्य के महत्व के उद्योग [republic industries] और स्थानीय महत्व के उद्योग [local industries]। तीसरे वर्ग को फिर से जिला, कस्बा, तथा गाँव के अनुसार विभाजित किया जाता है। इससे लाभ यह है कि साधनों के बँटवारे में प्राथमिकता [priority] की सूची तैयार करना

आसान हो जाता है। विभिन्न उद्योग और उनके हर कारखाने तक पहुँचने की एक और शृंखला है जिसे ट्रस्ट और सिण्डिकेट कहते हैं।<sup>1</sup>

गौस प्लान के अर्थक परिश्रम से आँकड़े इकट्ठा किये गये जिनको आधार मान कर योजना के लक्ष्य बने। 1925-26 में निर्देशक आँकड़े। [Control Figures] प्रकाशित किये जाते हैं जो कि अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा निर्देशाङ्क होता है। रूसी आँकड़ा को सदा से अविश्वास और सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अर्थव्यवस्था के सब आँकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते। वास्तविकता यह है कि सोवियत नेता आँकड़ों को रोक लेने में विश्वास करते हैं। यह मानने का कोई प्रबल कारण नहीं मिलता कि आँकड़ों में हेर-फेर की जाती है या उनको अनुचित तरह से बदल दिया जाता है। इस विषय पर प्रोफेसर हैरी श्वार्ट्ज के विचार सबसे संतुलित प्रतीत होते हैं।<sup>2</sup>

जनवरी 1948 में केन्द्रीय योजना व्यवस्था को फिर से संगठित किया गया। इसका नाम राजकीय योजना समिति रखा गया पुराने गौस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण काम इससे ले लिया गया : उद्योगों के बीच साधनों का बँटवारा करने का कार्य एक नई संस्था को मिला जिसका नाम गौसनैप था [Committee for material—technical supply of the national economy]। इसी समय एक तीसरी संस्था स्थापित की गई जिसे गौसटेक कहते हैं [State Committee for introduction of advance technique into the national economy]। इसका काम आधुनिक यांत्रिक तथा कुशलता प्रणालियों का रूसी अर्थ-व्यवस्था से प्रचलित करना था। यह आशा की जाती थी कि यह समिति आधुनिक कारण [modernization] में आई हुई सुस्ती को दूर कर सकेगी। किन्तु गौसटेक सफलतापूर्वक कार्य न कर सका। विभागीय तनाव इतनी बढ़ी कि 1951 में इसे भंग कर दिया गया। इस प्रकार गौस प्लान का काम उत्पादन और सामाजिक जीवन के दूसरे अंगों की योजना तैयार करने तक सीमित हो गया। जोसेफ स्तालिन की मृत्यु के बाद केन्द्रीय योजना संगठन का रूप दुबारा बदला। गौसनैप को गौसप्लान में मिला दिया गया। आखिरकार फिर से वही स्थिति आ गई जो इन पुनर्संगठन के प्रयत्नों के पहले थी।

गौसप्लान के प्रारम्भिक रूप में, योजना कार्य पर केन्द्रीय सरकार का बड़ा कठोर संचालन था। योजना का प्रयोग इतना नया था कि लेनिन [बाद में स्तालिन] ने इसके हर पहलू पर राजनैतिक देख-रेख आवश्यक समझा। बाद में परिस्थिति स्थिर हो जाने

<sup>1</sup> इनका विस्तार नवीन आर्थिक नीति में देखिये।

<sup>2</sup> Schwartz. H., op cit., p. XVI

पर यह हस्तक्षेप कम होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी केवल मोटे-मोटे सिद्धान्तों को निश्चित कर देती है। इनकी सहायता से गॉसप्लान योजना बनाता है और राजनैतिक उद्देश्य भी अपने पूर्ण प्रभाव में बने रहते हैं।

समय के साथ एक और बहुत बड़ा परिवर्तन योजना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आया। यह अनुभूति जोर पकड़ती गई कि योजना बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण काम योजना को सफलता से लागू करना होता है। शुरू में योजना को कार्यान्वित [implement] करने का दायित्व राज्य के विभिन्न मंत्रालय [Commissariat] पर था। इससे उद्देश्य तथा विचारों में भिन्नता आने लगी। इसलिये केन्द्रीय योजना आयोग को योजना बनाने और उसे लागू करने का काम दोनों ही सौंप दिया गया। आयोजन के इस दूसरे पहलू ने इतना ध्यान आकर्षित किया कि प्रायः हर कम्युनिस्ट पार्टी अधिवेशन में कार्यान्वित योजना वाद-विवाद का मुख्य विषय होता है। रूस उस भयंकर कमजोरी से बच गया जो अच्छी से अच्छी योजना को बेकार कर सकती है और जिसके कारण योजना की सफलता पर ही लोग अविश्वास करते हैं अर्थात् योजना पूर्ति का असफल संचालन।

रूसी योजनाएँ अपरिवर्तनीय नहीं होती। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विशेषज्ञ भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाते हैं और साधनों को दृष्टि में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित करते हैं किन्तु वे भविष्यद्रष्टा नहीं होते। रूस में यह बात काफी पहले से ही मान ली गई थी। इसीलिये वार्षिक, तिमाही और मासिक योजना तथा लक्ष्य बनाया जाता है। फिर भी परिस्थिति तथा प्रगति के अनुसार इनमें हेर-फेर करना न तो असफलता मानी जाती है, न इससे मानहानि का डर रहता है। सामयिक स्थिति और नई समस्याओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना इसी तरीके से सम्भव हो सकता है। योजना का यह संगठन काफी पेचीदा लगता है किन्तु इसकी सफलता-शक्ति का परिचायक स्वयं सोवियत रूस का महान् आर्थिक विकास है।

### औद्योगिक उत्पादन संगठन तथा प्रबन्ध

#### औद्योगिक व्यवस्था की विशेषताएँ :

रूसी आर्थिक संगठन एक कट्टरपंथी धर्म के समान है जहाँ वही सत्य है जो कि धर्म-गुरु कहते हैं। धर्म पुस्तकों में कुछ भी लिखा हो, पर उसकी एकमात्र सही टीका वही है जो कि गुरु को विवेचना है। उचित-अनुचित का निर्धारण, धर्म-अधर्म का अन्तर, पाप-पुण्य की नियमावली, स्वर्ग-नर्क का ठेका सब कुछ केन्द्रित है धर्माधीश की समझ, इच्छा और प्रवृत्तियों पर। व्यक्तिगत बुद्धि-बल का प्रयोग केवल अनुसरण में

किया जा सकता है, निर्देशन में नहीं। स्वतंत्र जिज्ञासा में ही भ्रमनाश होता है। इस-लिये जिज्ञासु एक पथ-भ्रष्ट व्यक्ति है जिसको मिटा देने से ही लोक-कल्याण सम्भव है। 1936 के सोवियत संविधान में उच्चादशों से परिपूर्ण प्रजातंत्र के सिद्धान्त दिये गये हैं। पर जैसा कि एड्वार्ड विशिन्स्की, वैधानिक विशेषज्ञ [Constitutional law expert], ने समझाया कि उन लोगों की भूल है जो यह समझते हैं कि संविधान में व्यक्त प्रजातंत्र के सिद्धान्त किन्हीं भी रूप में मजदूर की तानाशाही को सीमित करते हैं। यही एड्वार्ड विशिन्स्की था जिसने स्तालिन के दाहिना हाथ की तरह रूसी परजीक्यूटर जनरल के पद से देश की शुद्धि [purge] के आवरण में दमन की विभीषिका रचाई थी।

रूस एक विराट सैनिक शिविर है जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक अंग एक ही ईंधन से संचालित हैं—अतुलनीय तेजवान अनुशासन-शक्ति। इसका उद्गम देश का अकेला राजनैतिक दल-कम्युनिस्ट पार्टी है। साम्यवादी दल केवल सरकार का निर्माण ही नहीं करता वरन् सक्रिय निर्देशन ही करता है। सरकार, सेना, न्यायालय और पुलिस पार्टी द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अनुशासन के रक्षक मात्र हैं। राजशक्ति का पूर्ण केन्द्रीयकरण रूसी व्यवस्था की बड़ी भारी विशेषता है। जिसमें कानून प्रबन्ध तथा न्याय [legislative, executive and judicial] का आपसी भेद मिटा दिया गया है। केन्द्र से लेकर प्रत्येक कारखाने और खेत को कठोर अनुशासन शृंखला में बाँधने के लिये संस्थाओं और कर्मचारियों का विशाल समुदाय बना जिसमें वर्गों और स्तरों की जटिल उलझन है। इनमें ही रूस की एक और विशेषता पाई जाती है—कठोर अधिपत्य। हर एक वर्ग तथा स्तर अपने से ऊपर वाले वर्ग तथा स्तर और केन्द्र के पूर्ण अधिपत्य में होता है।

यह धारणा कि रूस पृथ्वी पर स्वर्ग है—वह स्थान जहाँ सभी समान हैं, जहाँ गरीब-अमीर का भेद नहीं है, जहाँ का समाज वर्गहीन है—आधुनिक रूसी प्रगति के विद्यार्थी के लिए केवल विवादास्पद ही नहीं, काल्पनिक है। मार्क्स और एंजिल के वर्गहीन समाज के सिद्धान्त को कुछ थोड़े से प्रारम्भिक प्रयत्नों के बाद बदल दिया गया। वर्गहीन के स्थान पर ऐसे समाज को आदर्श माना गया जहाँ वर्गों में विरोधाभास [antagonistic classes] न हों। किन्तु वर्गों के स्वयं वर्तमान रहने पर आपत्ति समय के साथ कम होती गई। आजकल सोवियत समाज एक पिरामिड की तरह बना है जिसका आधार है किसान वर्ग। आधार होने के कारण यह सबसे नीचा भी है। इसके ऊपर का स्थान मजदूर वर्ग को प्राप्त है। प्रबन्ध वर्ग, कर्मचारी वर्ग, राज्य के उच्चतम पदाधिकारी वर्ग, साम्यवादी-दल के अधिकारी और सबसे चोटी पर एक छोटा-सा चुना हुआ गुट जिसमें या जिसके नेता में सम्पूर्ण राजसत्ता निहित होती है। इस तरह सारा

देश बहुत से वर्गों में बँटा है जिनके आपसी ऊँच-नीच का निर्णय उनकी शक्ति व प्रभुता के अनुसार होता है। क्रान्ति के बाद किये गये आय की समानता [equality of income] के प्रयत्न अब इतिहास की बातें बन गई हैं। उनका बचा हुआ अंश केवल इतना कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति को एक न्यूनतम जीवन-स्तर के योग्य धन-लाभ करने के लिए बाध्य किया जाता है। राज्य यह देखता है कि इसके लिए उनको अवसर प्राप्त हो।

राजकीय नियंत्रण का जाल इतना विस्तृत और गम्भीर है कि जनता का आत्मिक और शारीरिक अस्तित्व पूरी तरह इसमें जकड़ा है। पार्टी और राज्य की आँखें सर्व-द्रष्टा हैं और उनके हाथ की पहुँच सर्वव्यापी है। छोटी-से-छोटी बातों का निर्णय पार्टी करती है। इनके उचित पालन के लिए जो विशाल नियंत्रण-यन्त्र बना है, उसकी पेचीदा बनावट निरर्थक नहीं। उसका उद्देश्य है चोटी पर बैठे चन्द नेताओं द्वारा समाज पर सर्वाङ्ग नियंत्रण और संचालन। इस प्रकार रूस के नागरिक अधिकारों के बारे में यह कहा जा सकता है कि जनता को उन सभी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है जिसमें राजकीय निषेध नहीं है। उपरोक्त पृष्ठ-भूमि में इसका अर्थ स्पष्ट है।

सोवियत अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य अंग हैं—कारखाना, मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन; राजकीय खेत [सोवखोज], सामुदायिक खेत [कोलखोज] और नगर उत्पादक सहकारी समितियाँ [Urban Producers Cooperative]।

सोवियत उत्पादन संगठन की एक ऐसी विशेषता है जो कि पूँजीवादी उत्पादन में नहीं पाई जाती। रूसी मजदूर और किसान के लिए उसका कार्य-क्षेत्र जीविकोपार्जन का साधन मात्र न होकर उसका सम्पूर्ण सामाजिक जीवन है। उत्पादन केन्द्र के भीतर और बाहर के सभी आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं का निर्देशन एक विशेष आयोजित उद्देश्य लेकर राज्य करता है। यह उद्देश्य सैद्धान्तीकरण [indoctrination] है अर्थात् मजदूर और किसानों को बोल्शेविक विचारधारा से अवगत करना तथा बोल्शेविक-कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रेरित करना। हर समय, हर जगह काम में और आराम में उनके चारों ओर बोल्शेविक “सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान” का वातावरण बनाना भी उत्पादन संगठन का खास काम होता है। इस प्रकार उत्पादन केन्द्र चाहे, वे कोई भी हों, अत्यन्त प्रभावशाली समाजवाद के विद्यालय हैं जिनमें समाजवादी विधान को एक जीती-जागती शक्ति में बदल दिया जाता है। इसकी सफलता एक केन्द्रीय योजना की आशापूर्ण पूर्ति से मापी जाती है। पिछले चालीस वर्ष की आश्चर्यजनक प्रगति का यही भेद है। ससार को चकित कर देने वाली उन्नति का मूलाधार वहाँ के मजदूर-किसानों का अदम्य उत्साह, अकथनीय त्याग तथा अथक प्रयत्न है।

सोवियत उत्पादन व्यवस्था दो मुख्य भागों में बाँटी जा सकती है। राजकीय एवं सहकारी व्यवसाय और कोलखोज इनका उदाहरण है। सरकारी उद्यम [enterprises] में सोवियत आर्थिक व्यवस्था का आदर्श पाया जाता है। साम्यवादी दल और राज्य इस बात में प्रयत्नशील हैं कि सारी अर्थ-व्यवस्था को राजकीय उत्पादन क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाय। उनके विचार में इस प्रकार ही पूर्ण समाजवाद की स्थापना हो सकती है। सहकारी क्षेत्र एक अस्थायी व्यवस्था की तरह ही सहन किया जाता है। 19 वीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं के आरम्भ में जो व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्पादन की स्थापना हुई थी उससे एकदम राजकीय संगठन पर जाना जब सम्भव न हो सका तभी, लाचारी से, सहकारी उत्पादन पद्धति को अपनाया गया। आंतरिक स्वतन्त्रता के जो अवशेष कोलखोज में पाये जाते हैं उनको सिर्फ इसलिए रहने दिया गया है कि जनता का विरोध शान्त रहे। इन संस्थाओं के द्वारा किसानों में से तुच्छ पूँजीवादी प्रवृत्तियों [petty bourgeois mentality] को निकाल फेंकने की कोशिश है जिससे किसान एक सच्चा सोवियत उत्पादन मैनिक बन सके। कोलखोज में समाजवादी शिक्षा से प्राचीन व्यक्तिवादी विचारों [individualistic ideas] को समूल नष्ट करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शासन का सदा यह प्रयत्न रहता है कि हर एक व्यक्ति योजना में दिये सामाजिक लक्ष्यों को सामने रखकर काम करे।

1929 में इस ओर सुधार करने की चेष्टा की गई। प्रबन्धकों को कारखाने के प्रबन्ध में अधिक अधिकार और स्वतन्त्रता मिली। साथ-ही-साथ सिद्धान्त रूप में यह भी मान लिया गया कि एक-व्यक्ति-प्रबन्ध ही अपनाया जाय किन्तु राजनीतिज्ञ इतनी आसानी से अपना प्रभुत्व छोड़ने वाले न थे और देश में पुराना ढाँचा ही चलता रहा। दोहरे संचालन के साथ-साथ इस ढाँचे की एक और विशेषता थी—हर एक कारखाना अलग-अलग विभागों में बाँटा था। दोहरे संचालन के साथ इस समय के कारखाना संगठन में कुछ और विशेषताएँ थी जिनके कारण इनको बहु-सूत्री प्रबन्ध व्यवस्था [Functional Management] भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के दो रूप थे—आन्तरिक प्रबन्ध और बाहरी प्रबन्ध। एक कारखाने के आन्तरिक प्रबन्ध को ठीक तरह चलाने के लिए कारखानों को अलग विभागों में बाँट दिया जाता था। इन विभागों के अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में निर्णय करने और आज्ञा देने में पूर्ण स्वतन्त्र थे। संचालक एक तरह से इन अध्यक्षों के बीच सम्पर्क स्थापित करने का साधन मात्र था। संदेह नहीं, इस पद्धति में मुचार रूप से संगठित उत्पादन असम्भव था। विभागों की आपसी स्वार्थी पूरे कारखाने में लाभ को उचित दृष्टिकोण से न देखने देती थी। आरम्भ से ही प्रबन्ध का केन्द्रीयकरण एक व्यक्ति में न किया जा सका। इसका कारण लाचारी कहा जा सकता है। प्रबन्धकों की कमी तथा पुराने अनुभवहीन लोगों पर

अविश्वास से अधिकतर कारखानों में नये अनुभवहीन संचालकों को नियुक्त करना पड़ा जिनमें पूरे कारखाने के सभी विभागों में कार्य को समझने और संचालित करने की क्षमता न थी। इसीलिए संचालन शक्ति ने विकेंद्रीयकरण की आवश्यकता पड़ी। कुछ भी कारण रहा हो इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा।

इस व्यवस्था के अनुसार कारखाने के बाहरी प्रबन्ध में भी कम उलझन न थी। एक कारखाने का नियंत्रण बहुत से विभागों पर निर्भर करता था। केन्द्रीय और प्रान्तीय [Union and Republic] सरकार के विभिन्न मन्त्रालय, आयोग और विभाग हर कारखाने को आज्ञाएँ जारी करते थे। योजना, अर्थ, व्यापार से सम्बन्धित संचालन योजना आयोग, वित्त विभाग और अन्तर्देशीय व्यापार विभाग से क्रमशः प्राप्त होता था। इसी तरह दूसरे क्षेत्रों में भी व्यवस्था थी। इससे होने वाली हानियाँ स्पष्ट हैं। कारखाना संचालन के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण होना कठिन था। साथ ही साथ प्रबन्ध की बुराईयों के श्रोत का भी पता नहीं चलता था। अलग-अलग विभाग अपने अधिकार-क्षेत्र का स्पष्टीकरण न कर पाते थे इसलिए बहुधा एक ही समस्या पर दो या अधिक भिन्न आज्ञाएँ प्रबन्धक को मिलती थीं।

17 वीं कम्युनिस्ट पार्टी अधिवेशन, 1934, में जोसेफ स्तालिन ने प्रबन्ध सुधार की ओर ठोस कदम उठाया। 1929 के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का श्रेय 1934 के अधिवेशन को ही है। एक-व्यक्ति प्रबन्ध को लागू करने के लिए अलग-अलग विभागों में अध्यक्षों के अधिकारों में बड़े पैमाने पर कटौती की गई। स्वतन्त्र निर्णय और आज्ञा देने का अधिकार उनसे बिल्कुल ले लिया गया। अब वे केवल अपने विभाग में आवश्यक परिवर्तनों और दूसरे कामों के लिए संचालक के पास अपनी सलाह भेज सकते थे। जितनी भी आज्ञाएँ थी वे सब संचालक के नाम पर ही निकलती थीं।

1934 में कारखाना पद्धति बदली गई। उस समय तक एक मैनेजर को अपने अलग-अलग कामों के लिए राज्य के अलग-अलग विभागों से संचालित होना पड़ता था जिससे मैनेजर का दायित्व निश्चित करना अत्यन्त कठिन था। 1934 में 17 वे अधिवेशन ने यह तय किया कि उत्पादन का क्षेत्रीय संचालन किया जाय। इसके द्वारा एक क्षेत्र में एक ही वस्तु के उत्पादन में लगे हुए जितने भी कारखाने हों उनको केन्द्रीय औद्योगिक प्रबन्ध समिति [Glavk or Central Board of Industrial Management] के पूर्ण संचालन में दे दिया गया। इससे मैनेजर को योजना आयोग और राज्य के अलग-अलग विभागों से सम्पर्क न रखकर केवल ग्लव्क [Glavk] से आज्ञा लेनी होती थी। इस समिति का उत्तरदायित्व था कि हर एक

मैनेजर उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करे। दूसरी ओर कारखाने की पूँजी की आवश्यकताओं का अनुमान और खर्च की सीमा का विस्तृत लेखा तैयार करे जिसके आधार पर केन्द्रीय योजना में इसका प्रबन्ध हो सके। उत्पादन प्रणाली, मशीन और मजदूरों का चुनाव और दूसरे आन्तरिक प्रबन्ध की बातों को भी यह समिति निश्चय करती थी। मैनेजर का कार्य इन निर्णयों को कार्यान्वित करना था।

कारखाना प्रबन्ध में दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक कारखाना एक स्वतन्त्र आर्थिक इकाई है जिसमें वचत और लागत को कम करना सफल प्रबन्ध की कसौटी मानी जाती है। एक फैक्टरी मैनेजर के लिए उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति से भी अधिक यह आवश्यक है कि वह दिखा सके कि उसने पिछले साल से कम खर्च में अधिक उत्पादन किया। इस प्रकार हर एक कारखाने को सामान, यंत्र और ईंधन; यांत्रिक सुधार [Technological Progress], उत्पादन के किस्म में उन्नति तथा प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन के लिये प्रयत्नशील होने की प्रेरणा और उत्साह प्राप्त होता था।

### सोवियत कारखाना संगठन

यह दो विशेष धाराओं से प्रभावित होकर बना है। प्रथम, प्रभाव अधिक उत्पादन करने का सतत प्रयत्न है। अधिक उत्पादन पर ही सोवियत औद्योगिक व्यवस्था की नींव पड़ी है। कारखाना संगठन की कमजोरियों और शक्तियों का उद्गम बहुत कुछ इसी में पाया जाता है। एक ऐसा संगठन बनाया गया है जिसके द्वारा अधिक उत्पादन के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया जा सके। दूसरे, प्रभाव द्वारा एक फैक्टरी को साम्यवाद की पाठशाला बनाने का प्रयत्न किया गया। साथ ही साथ पूँजीवादी प्रवृत्तियों और सहानुभूतियों को मजदूरों से दूर करने के लिये कारखाना एक सुधार केन्द्र भी है। व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति और सहानुभूति का पता लगाकर मजदूर और उसके परिवारों में से इनका उन्मूलन करना सोवियत कारखाने का एक विशेष अङ्ग है। इस क्षेत्र में जहाँ पर इस पूँजीवादी बीमारी को दूर न किया जा सके वहाँ इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी उत्पादन क्षेत्र से हटा दिया जाता है। उत्पादन और सिद्धान्त-शिक्षा के सफल मिश्रण के लिये यह आवश्यक हो गया कि यांत्रिक विशेषज्ञ [Technician] और राजनीतिज्ञ का ऐसा सहयोग उत्पन्न किया जाय जहाँ उनमें कहीं पर भी विरोधाभास की सम्भावना न हो। यह दोनों वर्ग अपने क्रियात्मक रूप में सर्वथा पृथक् हैं। कारखाना संगठन, इनके आपसी प्रभुत्व के भगड़े की एक लम्बी कहानी है। आरम्भ में स्वाभाविक रूप से राजनीतिज्ञ ने ही प्राथमिकता प्राप्त की। कारण यह था कि वे स्वतंत्रता के विजेता, स्वाधीनता के सैनिक थे। उनके अपने और जनता के विचार में वे सब कुछ कर सकते थे। उन पर किसी प्रकार की रुकावट लगाना अनुचित-सा प्रतीत हुआ। इसका विषाक्त



प्रभाव शीघ्र ही देश के गिरे हुए उत्पादन, वेकारी और भुखमरी में प्रकट हुआ। देश ने यह अनुभव किया कि स्वाधीनता का सैनिक होना कोई ऐसी प्रशिक्षा एव योग्यता नहीं है जिसके द्वारा एक मनुष्य हर काम को करने योग्य बन जाय। स्वतंत्रता संग्राम के लिये अडिग मनोबल, तेज आवाज तथा शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत राष्ट्र निर्माण विशेषज्ञों [वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री और औद्योगिक सङ्गठनकर्ता] द्वारा किया जाता है जो कि बहुत धीमी और कष्टप्रद विद्या-प्रशिक्षा और अनुभव से बनते हैं। योजना के आरंभ से तथा अधिक उत्पादन की आवश्यकता के दबाव में धीरे-धीरे अनिच्छा के साथ राजनीतिज्ञ पीछे हटता गया और विशेषज्ञों को उनकी स्वाभाविक प्राथमिकता प्राप्त हुई।

चास्तविकता में कारखाना ही सोवियत औद्योगिक व्यवस्था का केन्द्र-बिन्दु है। उनका उचित सङ्गठन एवं संचालन पहली आवश्यकता मानी जाती है। सोवियत कारखाना प्रबन्ध के क्रमिक विकास पर कुछ बातों का विशेष असर पड़ा है। मैनेजर और इंजीनियर उत्पादन की प्रथम आवश्यकता हैं। इसलिये उनकी कार्यकुशलता को अधिकतम प्रोत्साहन दिये जाने की कोशिश होती है। प्रबन्धक को उचित शक्ति व प्रतिष्ठा देने के लिये उसे साम्यवादी दल में मिला लिया गया। सफल प्रबन्धक अपने प्रभाव के विस्तार के लिये साम्यवादी दल के ऊँचे अधिकारी बनने का सदा स्वप्न देखा करते हैं। अन्त में प्रबन्धक वर्ग की शक्ति इतनी अधिक न बढ़ जाय कि वे अपना स्वतंत्र मार्ग निर्धारण करने का प्रयत्न करने लगे, इसलिये उन पर साम्यवादी दल से निरीक्षण और नियंत्रण की भी आवश्यकता हुई। इन सब बातों का समन्वय कारखाना-प्रबन्ध-व्यवस्था है।

कारखाना-प्रबन्ध सङ्गठन का विकास-क्रम इन कारणों से बहुत जटिल बन गया। शक्ति देश केन्द्रीय राज्य सत्ता पर आधारित है इसलिये समाज के हर एक वर्ग तथा स्तर के कार्यों की ओर उच्चतम सतर्कता रखनी पड़ती है। औद्योगिक प्रबन्धक वर्ग अत्यन्त शक्तिशाली, वाणियुक्त [Vocal] तथा प्रशस्त प्रभावशाली है। इसलिये साम्यवादी दल के आदर्शों की ओर स्वामिभक्ति [Loyalty] तथा उच्च कार्यकुशलता को जीतने और बनाये रखने के लिये विशेष प्रयत्न किये जाते हैं। इसी कारण कारखाना संगठन ने प्रबन्धक के अतिरिक्त दो और प्रभावों का समावेश किया गया। इस तरह त्रि-सूत्री [Triangular] प्रबन्ध-व्यवस्था बनी। प्रबन्धक के अतिरिक्त कारखाने में समाजवादी दल समिति तथा श्रमिक सङ्घ समिति का निर्माण हुआ। दोनों नई संस्थाएँ कहने को तो एक सहायक के रूप में बनाई गई थी, लेकिन इनके अधिकार इस प्रकार के हैं कि जैसे ही प्रबन्धक में किसी प्रकार की कमी दिखलाई पड़ती है ये संस्थाएँ उसकी भाग्यनिर्ण-

यक बन जाती है। इस विहगम दृष्टि के बाद कारखाना संगठन में इन तीनों अङ्गों का थोड़ा-सा विस्तृत अध्ययन किया जायगा।

### कारखाना प्रबन्धक

1917 की क्रांति के बाद अनुभवी प्रबन्धकों की बहुत कमी हो गई। पुराने प्रबन्धक या तो पूँजीवादी होने के कारण मारे गये या निष्कासित किये गये। थोड़े से जो बचे भी उनकी संख्या इतनी कम थी कि औद्योगिक प्रबन्ध एक महान् समस्या बन गया। आरंभ में इन पुराने प्रबन्धकों पर साम्यवादी सरकार पूर्ण विश्वास भी नहीं करती थी। इसलिये दोहरी प्रबन्ध प्रणाली चली। हर कारखाने में दो संचालक होते थे। एक तो साम्यवादी दल का कोई प्रमुख नेता, प्रायः इनके सहायक के रूप में एक प्रशिक्षित प्रबन्धक। स्पष्ट है कि इसमें आपसी सामंजस्य होना असम्भव था क्योंकि प्रबन्धक अपने को अपमानित समझता था कि वह एक अशिक्षित व्यक्ति के अधीन काम करे।

संचालक को कारखानों का एकमात्र प्रबन्धक माना जाता है। उसका अधिकार-क्षेत्र कारखानों के सभी भागों में व्याप्त है। यांत्रिक औद्योगिक और पूँजी सम्बन्धी कारखाने की योजनाओं को वह बनाता है। कर्मचारियों का चुनाव, सामूहिक रूप से काम का बँट-वारा, उत्पादन प्रगति की देख-रेख, श्रमिक अनुशासन उसके एकमात्र दायित्व के विषय है। योजना लक्ष्य की पूर्ति साधनों का उचित व्यय और श्रम के लाभपूर्ण संगठन की पूरी जिम्मेदारी संचालक पर होती है।

कारखाने का हर एक विभाग उप-विभाग [Sections] में, और उप-विभाग ब्रिगेड में बँटे जाते हैं। उप-विभाग का अध्यक्ष [Incharge] अथवा फोरमैन उत्पादन-शृङ्खला का अन्तिम नायक होता है। इसे उत्पादन कार्य नहीं करना पड़ता। इनका मुख्य काम अनुशासन, ऊपर से आई हुई आज्ञाओं को लागू करना और संयोजित उत्पादन होता रहे इसकी देख-रेख करना है। ब्रिगेड नेता मजदूरों के अप्रदूत होते हैं। मजदूरों के साथ काम करके, उनके अपने आदमी की तरह, सहायता, शिक्षा और प्रोत्साहन देते हैं।

औद्योगिक प्रबन्ध के ढाँचे में उत्पादन वृद्धि की सबसे अधिक जिम्मेदारी इस ब्रिगेड पर पड़ती है। इस प्रकार यह पता लगता है कि सोवियत औद्योगिक संगठन में ऐसी प्रणाली स्थापित हो चुकी है जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति में, अधिकतम उत्पादन करके, योजना-लक्ष्यों से भी आगे बढ़ने का उत्साह पैदा होता है [या बलात् पैदा किया जाता है], और मजदूर का पृथक् व्यक्तित्व पूरी तरह दल या समूह [Team] में विलीन हो जाता है।

### कारखाना साम्यवादी दल संगठन

आरम्भ से ही रूसी साम्यवादी दल अपने को सर्वज्ञानी समझकर सर्वव्यापी बनने की चेष्टा करता रहा है। सदेह और आशका पर आधारित रूसी आर्थिक तथा राज-नैतिक व्यवस्था में ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं था। धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगा कि कारखाना प्रबन्ध और राजनैतिक दल में कारखाने के अन्दर भेद करना आवश्यक है। प्रबन्ध के विशेषज्ञ पार्टी के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते थे। दूसरी ओर पार्टी के लोग स्वामिमक्ति और त्याग में अपने को विशेषज्ञों से श्रेष्ठ मानते थे तथा उनसे अधिक अधिकार चाहते थे। इससे उत्पन्न विरोध और असन्तोष ने देश को बहुत हानि पहुँचाई।

समय के साथ जब क्रान्ति और विजय का नशा उतरने लगा तब कारखाना प्रबन्धकों के अधिकार में वृद्धि हुई। फैक्ट्री के दैनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कम करने की चेष्टा की गई। पार्टी के मुख्य कार्य निश्चित कर दिये गये : सयोजित उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति, उत्पादकता बढ़ाने के लिये आन्दोलन तथा समाजवादी सिद्धान्तों की शिक्षा का नियन्त्रण। दूसरा परिवर्तन 1929 में सामने आया। इसके द्वारा पार्टी तथा कारखाना प्रबन्ध को एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया गया। सचालक, इंजीनियर, फोरमैन, ब्रिगेड नेता तथा 'स्तैखोनेवाइट श्रमिक' को साम्यवादी दल में ही मिला लिया गया। दल में इनकी बढ़ती हुई संख्या और प्रभुत्व के कारण कारखाना सचालकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता में वृद्धि हुई।

प्रत्येक कारखाने में एक साम्यवादी दल समिति होती है जिसका अस्तित्व सचालक से स्वतंत्र होता है। इस समिति की नियुक्ति साम्यवादी दल का केन्द्र करता है तथा इसका उत्तरदायित्व केवल उन्हीं की ओर होता है। योजना के लक्ष्य की पूर्ति और श्रम उत्पादकता बढ़ाने का विशेष प्रयत्न यह समिति करती है। कारखाना प्रबन्ध के अधिकारियों पर निगाह रखना भी इसका काम है।

1939 में 18वीं पार्टी अधिवेशन ने सचालक और समिति के आपसी सम्बन्ध सुधारने पर काफी विचार किया। उस समय तक यह प्रश्न एक विकट समस्या बन चुका था। साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति ने कहा कि किसी भी प्रकार से सचालक और समिति परस्परविरोधी नहीं कहे जा सकते क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। कहने का अर्थ यह था कि समिति के अधिकारों का विरोध वही सचालक करते हैं जिनमें कोई कमी है। 1941 में तो कारखाना दल समिति के कर्तव्यों तथा अधिकारों की एक लम्बी सूची बनाई गई जिसमें कठिनाता से ही कोई कार्य का नाम छूटा हो।

## कारखाना श्रमिक संघ समिति

यह सगठन कारखाने के त्रि-सूत्री सगठन को पूरा करता है। राज्य द्वारा नियुक्त संचालक, साम्यवादी दल समिति के बाद सोवियत कारखाने का तीसरा सगठन श्रमिक संघ समिति [Fabzavkom] है। रूसी श्रमिक संघ के विशाल सगठन में यह प्राथमिक संस्था है। 1949 में हुए सोवियत श्रमिक संघ के दसवें अधिवेशन में इनके कार्यों का एक लेखा प्रस्तुत किया गया था। मजदूरों को योजना-लक्ष्य की पूर्ति अथवा उससे अधिक उत्पादन, श्रमिक अनुशासन को शक्तिशाली बनाना तथा समाजवादी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, सामूहिक समझौता की तैयारी, श्रमिक उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न तथा सुभाव, स्लैखनोवाईट शिक्षण केन्द्रों का सगठन, कर्मचारियों के कल्याण कार्य, सांस्कृतिक तथा खेलकूद के कार्यक्रम का आयोजन एवं उच्च श्रमिक संघ अधिकारियों द्वारा प्राप्त आदेशों का पालन, इनके कार्य बतलाये गये हैं। इस सख्ति सूची से यह स्पष्ट है कि श्रमिक संघ का कार्य-क्षेत्र इतना व्यापक है कि अगर यह अपने सभी अधिकारों को प्रयोग में लाये तो संचालक का अधिकतर काम इनके द्वारा ही हो जायगा। यही नहीं, श्रमिक संघ समिति तथा साम्यवादी दल समिति प्रायः एक-सी लगती हैं। इस अनुरूपता का अर्थ यह हुआ कि अनेकों स्थान पर इन दोनों का अधिकार-क्षेत्र उलभा हुआ है। इससे कुशल प्रबन्ध में अवरोध उत्पन्न होता है।

यह कहना अनुचित न होगा कि श्रमिक संघों के अधिकार तथा कार्य इस प्रकार के बने हैं कि एक आदर्श परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें श्रमिकों की अधिकारपूर्ण, क्रियात्मक एवं प्रभावशाली आवाज प्रबन्ध के हर कोने में सुनाई दे सकती है। इसी से श्रमिक-राज्य [Workers' state] का साम्यवादी लक्ष्य पूरा किया जा सकता है; किन्तु ऐसा हो न सका। समय के साथ श्रमिक संघ का प्रभुत्व भी कम होता जा रहा है। कहने को तो श्रमिक संघ समिति का अध्यक्ष उच्च संघ अधिकारियों द्वारा ही नियुक्त होता है तथा वह पूर्ण स्वतंत्र कार्यकर्ता है, परन्तु कारखाना सगठन में उसका स्थान संचालक, दल सचिव तथा विभाग-अध्यक्ष के बाद ही आने लगा है। श्रमिक समिति अध्यक्ष की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा आघात इस बात से लगता है कि केवल वही व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो सकता है जो कि कारखाना-संचालक को मान्य हो।

सोवियत औद्योगिक सगठन का केन्द्रीय लक्ष्य है अधिक उत्पादन। सभी संस्थाएँ, सगठन और नियम इसी की पूर्ति के लिये बनाये गये हैं। श्रमिक संघ समिति के भी अस्तित्व का आधार यही है। इसका एक विशेष साधन सामूहिक समझौता [Collective Agreement] है। यह प्रबन्ध और श्रमिकों के बीच एक वादा [Pledge] है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम को पूरा करने का

उत्तरदायित्व दोनों पक्ष इसलिये लेते हैं कि उत्पादन-शक्ति तथा उत्पादन में वृद्धि हो सके। किन्तु सामूहिक समझौता, श्रमिकों के अधिकार और कर्तव्य की स्पष्ट विवेचना करने के स्थान पर, कारखाना संगठन में श्रमिकों को स्वतंत्रता का केवल एक ढोंग बन कर रह गया। पाश्चात्य देशों की तरह प्रबन्ध और श्रमिक सघ अधिकारी आमने-सामने बैठकर यह समझौता नहीं करते जिसमें कि मजदूरी, काम का समय, उत्पादन, मकान, सुविधाएँ इत्यादि तय होती है। समझौते की रूप-रेखा का इशारा तीन बातों से लिया जाता है—[1] देश में उस समय चलती हुई योजना के सिद्धान्त, [2] श्रमिक अधिनियम तथा [3] 'आदर्श सामूहिक समझौता' [Model Collective Agreement] जिसे उच्च अधिकारी मजदूरों के 'सहूलियत और मदद' के लिये भेजते हैं। इस मदद को स्वीकार न करना अनुशासनहीनता का प्रमाण माना जा सकता है। इसका अच्छा प्रभाव इस बात से और भी कम हो जाता है कि इन समझौतों में कोई वैधानिक शक्ति नहीं होती तथा मजदूरों की नियुक्ति इसके क्षेत्र से बाहर है। नियुक्ति के समय, मजदूरों को प्रबन्धकों के साथ अलग एक व्यक्तिगत समझौता करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से सामुदायिक समझौते को मजदूरों की शक्ति का प्रतीक नहीं माना जा सकता।

श्रमिक सघ के प्रतिनिधि कई आयोग और समितियों में भाग लेते हैं।<sup>1</sup> पूर्ण

<sup>1</sup> [a] Council of Social Insurance . सामाजिक बीमा का सक्रिय संगठन व संचालन।

[b] Wage Commission . यह वेतन का निर्धारण नहीं करता। निर्धारित वेतन को कारखाने में लागू करने पर संचालक को सलाह देता है।

[c] Commission for Labour Protection काम, समय, सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के उचित पालन की देख-रेख के लिये निरीक्षकों [inspectors] की नियुक्ति।

[d] Commission for Cultural and Educational Activity : प्रशिक्षण और कार्य कुशलता में वृद्धि के लिये शिक्षा का प्रबन्ध।

[e] Housing Commission : निवास स्थान का प्रबन्धक।

[f] Commission for Workers, Suppliers . कारखाने के फार्म व बगीचों की देख-रेख। कैंटीन व सहकारी दुकानों का प्रबन्ध।

[g] Commission for Workers Inventions and Rationalization : कर्मचारियों द्वारा की गई खोज व आविष्कार को प्रोत्साहन। विवेकीकरण का प्रयत्न।

अधिकार के साथ यह समितियाँ केवल सामाजिक बीमा, चिकित्सा सुविधा और पेन्शन के प्रबन्ध में काम करती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इन कल्याण कार्यों ने श्रमिक संघ के दूसरे कामों का स्थान ले लिया। उद्योगों का प्रजातन्त्रात्मक संचालन [democratic control] और मजदूरों का सौदा करने का अधिकार [Right to bargain] से श्रमिक संघ का सम्बन्ध टूट चुका है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रायः सभी विषय उच्च राजकीय स्तर पर तय किये जाते हैं। श्रमिक संघ समिति इन निर्णयों पर मजदूरों की स्वाकृति का मुहर लगा देती है। वाद में सरकारी तौर पर इन्हीं को श्रमिक संघ के निर्णय की तरह जनता के सामने रखा जाता है।

सिद्धान्त से रूसी सरकार एक मजदूर सरकार है। मजदूरों की सरकार ही जब उनके लिये काम, वेतन, कार्य-काल तथा कल्याण-सेवाओं की रूप-रेखा तथा विस्तार निश्चित करती है, तब मजदूरों को किसी प्रकार भी असंतोष या मतभेद नहीं अनुभव करना चाहिये। 1949 में श्रमिक संघ के नियम [Statute of the Trade Union] ने मान लिया कि प्रत्येक मजदूर बाध्य है कि वह राज्य एवं श्रमिक अनुशासन का कठोर पालन करे। इस प्रकार रूसी औद्योगिक संगठन में मतभेद और हड़ताल का कोई स्थान ही नहीं है। फिर भी औद्योगिक झगड़ों को तय करने के लिये एक विशेष संस्था है [Appraisal and Conflict Commission or Norms and Conflicts Commission] जिनको R. K. K. कहा जाता है। इसमें प्रबन्ध तथा श्रमिक संघ समिति के सदस्य बराबर संख्या में बैठते हैं। अधिकतर संचालक ही इसका सभापतित्व करता है। इसके निर्णय अगर दोनों पक्षों को मान्य न हुए तो उन्हें ग्लाव्क [Glavk] और उनके बाद अदालत में भी भेजा जा सकता है। यह आयोग कानून द्वारा संचालित [Controlled] विषयों को निर्णय के लिये स्वीकार नहीं करता। इनमें मुख्यतः काम का बँटवारा, अतिरिक्त कार्य और छुट्टी इत्यादि छोटे-छोटे मामले ही आते हैं। संचालक के हाथों में अधिकार-शक्ति के केन्द्रित होने के स्थिति ही साथ इस संस्था का महत्व भी घटता जा रहा है।

### अपूर्ण निर्माण कार्य

औद्योगिक उत्पादन संगठन तथा योजना प्रणाली में एक गम्भीर असंतुलन मिलता है। योजना का आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि प्रतिवर्ष पूँजी विनियोग [Capital Investment] की मात्रा राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग बन जाती है। सातवीं योजना में पूँजी विनियोग इतना अधिक है कि उसकी मात्रा आज तक की कुल सोवियत पूँजी विनियोग से कुछ ही कम है। ऐसी दशा में पूँजी के व्यय और उपयोगिता में जरा भी कमी होने से राष्ट्र को बहुत हानि हो सकती है। मालूम पड़ता

है कि राजशक्ति के बल पर इकट्ठा की हुई पूँजी उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो पाती जितना होना चाहिये। इसी कारण प्रतिवर्ष अपूर्ण निर्माण कार्यों [Unfinished construction] की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1958 के आरम्भ तक 1,76,100 मिलियन रूबल तक अपूर्ण कार्यों में लगी पूँजी पहुँच चुकी थी। तुलनात्मक दृष्टि से यह 1958 की कुल पूँजी विनियोग का लगभग 85% हुआ। अनेको उदाहरण इस प्रकार के हैं कि 15-18 वर्ष पहले शुरू किये हुए काम अभी तक पूरे नहीं हुए। स्तालिनस्क-अवाकान रेल मार्ग 1940 में शुरू हुआ था। जनवरी 1958 तक कुल 78% पूरा हुआ। फरगना में पेट्रोल साफ करने का कारखाना पिछले नौ सालों में योजना का कुल 27% पूरा कर सका।

पूँजी का यह विशाल अपव्यय और अनावश्यक देरी योजना में कमजोरी तथा उत्पादन संगठन में सुस्ती का प्रमाण है। इसके कारणों का सक्षिप्त अध्ययन विशेष शिक्षाप्रद होगा :

1. योजना में धन और साधन एक साथ इतने अधिक काम शुरू करने पर लगाये जाते हैं कि पूरी शक्ति से कोई भी काम नहीं हो पाता।

2. बहुत बड़ी संख्या में अपूर्ण कार्य होने पर भी प्रतिवर्ष नये निर्माण कार्यों को आरम्भ करने की अनुमति मिलती रहती है।

3. कार्यों को योजना-काल में पूरा न होने का एक कारण है : निर्माण कार्य तथा निर्माण सामग्री में सन्तुलन न होना। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संगठन की दुर्बलता से कुछ योजना-कार्यों [projects] को आवश्यकता से अधिक मशीनें तथा अन्य वस्तुएँ पहुँच जाती हैं। दूसरी ओर अनेको कार्य इन्हीं मशीनों की कमी से पूरे नहीं हो पाते। अनेको बार यह भी देखा गया है कि आवश्यक निर्माण के साधन समय से नहीं प्राप्त होते।

4. पूँजी विनियोग को पूरे वर्ष तक व्यय के लिये एक-सा नहीं बाँटा जाता। अक्सर यह होता है कि शुरू के महीनों की लापरवाही बाद के चन्द महीनों में पूरी की जाती है। वर्ष की अन्तिम तिमाही में 70% से ज्यादा पूँजी खर्च करने की सामान्य प्रवृत्ति मालूम पड़ती है।

अपूर्ण निर्माण कार्य में पूँजी का असफल प्रयोग होता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन शक्ति का निर्माण पूँजी के दुरुपयोग का तरीका है। ख्याति तथा क्षेत्रिक प्रतिद्वन्द्विता [Regional Rivalry] के साथ-साथ यह योजना-संचालन की कमी दिखलाता है।

## कृषि उत्पादन संगठन तथा प्रबन्ध

कृषक और राज्य—ससार में सभी जगह किसान धरती का पुत्र होता है। हजारों साल से अपनी जमीन का प्रेम उसके खून में भरता आया है। लेनिन ने बोल्शेविक क्रान्ति के लिए जब उनसे सहयोग माँगा, तो किसानों ने समझा कि स्वर्ग पृथ्वी पर आने वाला है। किसानों की कल्पना ने उड़ान भरी और विश्वास जमाने लगा कि लेनिन कुलक, भू-स्वामी व सानन्तों से जमीन ले कर उनको दे देगा। ईश्वर का पुत्र राष्ट्रपिता जार [Son of God Little Father the Czar] हटा दिया गया। सामत और भू-स्वामी नार डाले गये या भाग गये। किन्तु कल्पना साकार न हुई। पूर्ण भू-स्वामित्व की जगह उनकी अपनी जमीन, बोड़े, गाय तथा अन्य औजार सामाजिक सम्पत्ति घोषित कर दिये गये। किसानों को एक नया स्वामी मिला जो कि कठोरता में किसी भी तरह पुराने से कम न था। इसका नाम था सोवियत राज्य। स्वतन्त्रता का पहला परिचय था अनाज को जन्त करना, भूमि का सामुदायिक स्वामित्व, बढ़ते हुए उत्तर-दायित्व, तथा कपड़े, जूते और दूसरी आवश्यक वस्तुओं में आश्चर्यजनक मूल्य की वृद्धि।

सोवियत कृषि नीति के दो आधार थे। प्रथम, किसानों को बड़े सहकारी तथा सामुदायिक संगठन में बाँधना। अनुशासन तथा अनाज वमूली में सुविधा के साथ उनको समाजवाद के सिद्धान्तों से अवगत कराया जा सकेगा। किसान का भूमि-प्रेम उसके सच्चे समाजवादी बनने में सबसे बड़ी रुकावट थी। इसी से किसान पर राज्य का सदा से कड़ा हाथ रहा। सामुदायिक संगठन और समाजवादी प्रवृत्ति उत्पन्न करने में सोवियत नीति को सफलता नहीं मिली। इसका प्रमाण द्वितीय महायुद्ध में दिखलाई पड़ा। नाजी जर्मनी को मध्य और दक्षिणी कृषि प्रदेशों पर अधिकार करते ही, किसान कोलखोज [सामुदायिक फार्म] छोड़ कर व्यक्तिगत खेती पर चले आये जबकि इस समय तक उन्हें लगभग 25 वर्ष नये संगठन में रहने हो चुके थे। कृषि-नीति का द्वितीय आधार था किसानों के अधिकतम प्रयत्न तथा त्याग से औद्योगिकरण को सहारा देना। अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों ने उसे सोवियत राज्य का किसानों के प्रति धोखा, शोषण या शत्रुता माना है। इस विषय पर एक और दृष्टिकोण रखा जा सकता है। इसमें कोई सदेह नहीं कि जब भी पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देश के विकास का प्रयत्न किया जायगा, राज्य पर उद्योगों के प्रति पक्षपात का दोष सदा लगाया जा सकता है। विकास की योजना में उद्योगों को उच्चतम प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कृषि-विकास पर कुछ ध्यान नहीं दिया जायगा। उद्योगों के पक्षपात की विचारधारा कुछ मनोवैज्ञानिक भूलों का परिणाम भी कही जा सकती है। उद्योग की उन्नति उतनी प्रत्यक्ष और तीव्र होती है कि उसके आगे दूर गाँवों में होने वाली प्रगति तुलनात्मक दृष्टि से [relatively] सदा ही कम मालूम पड़ेगी। उसी प्रकार मजदूरों का सामा-



जिक स्तर भी किसानों से ऊँचा रहेगा। मजदूर वर्ग समाज में उठता हुआ नया वर्ग होता है जिसके नये दृष्टिकोण [Sense of Values], श्रम-भुगतान की नई पद्धति तथा अनेकों राजकीय प्रेरणाएँ व प्रोत्साहन उसे किसानों से इतना भिन्न बना देता है कि तुलनात्मक रूप में उसकी दशा-सुधार और जीवन स्तर ऊँचा उठ जाता है। एक स्थान पर इकट्ठा होकर सगठित होने का मौका मिलने से मजदूर वर्ग राजनीति और राज्य में भी अपना स्थान बना लेता है। अन्त में यह कहना अनुचित न होगा कि रूसी कृषि-नीति पर परिस्थितियों का प्रभाव अधिक था। इसे समकालीन जटिल समस्याओं को हल करने का प्रयास कहना चाहिये : राज्य का किसानों के प्रति विद्वेष [hostility] का प्रतीक नहीं।

### कृषि संगठन :

क्रान्ति के बाद खेती के पुनर्संगठन की आवश्यकता पड़ी। यह अनुभव किया गया कि किसानों को बड़े समूहों [groups] में विभाजित करना अनिवार्य है। सह-कारिता के तीन प्रधान रूप इस सम्बन्ध में अपनाये गये। प्रथम, तोज [Toz] अथवा संयुक्त खेती के लिये आपसी संगठन आता है। इसमें किसान भूमि पर काम करने के लिये आपस में मिल जाते थे। हर एक सदस्य का अपने भूमि पर स्वामित्व अलग होता था। इसके साथ पशु तथा औजार भी अपना होता था। बाद में अपनी जमीन पर हुई फसल बाँट ली जाती थी। द्वितीय, आरटेल [Artel] था जिसमें हर एक सदस्य के पास अपना घर और जमीन का छोटा-सा भाग निजी सम्पत्ति के रूप में रहता है। अधिकतर उत्पादन के साधनों का स्वामी कोलखोज या आरटेल होता था। सामूहिक रूप से खेतों पर काम किया जाता है। बाद में सामुदायिक उत्पादन की आय सदस्यों में बाँट ली जाती है। इस प्रकार प्रत्येक किसान की दोहरी आय होती है, सामुदायिक क्षेत्र से तथा निजी भूमि व पशु से। इसका अर्थ यह हुआ कि आरटेल सिद्धान्त पर आधारित सामुदायिक संगठन में समाजवादी एवं व्यक्तिगत प्रेरणाओं का समावेश रहता है। तृतीय, कम्यून [Commune] कहलाता है। इस प्रणाली में सदस्य सामुदायिक रूप से केवल काम ही नहीं करते परन्तु वे सामुदायिक रूप से रहते भी हैं। उत्पादन के साधन और तमाम सम्पत्ति कम्यून की होती है। सदस्य सामुदायिक मकानों में रहते हैं, सामुदायिक रूप से एक साथ उनका भोजन बनता है और उनके बच्चों का पालन-पोषण समुदाय करता है। इसे सामुदायिक विकास का उच्चतम रूप माना गया है। इसमें व्यक्तिगत प्रवृत्ति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। स्तालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के 17 वे अधिवेशन में कम्यून को ही भविष्य का रूसी कृषि संगठन घोषित किया था। यह तीनों वर्गीकरण स्पष्ट नहीं हैं। इनके बीच-बीच में अनेकों प्रकार के सामुदायिक संगठन हैं जिनमें उपरोक्त तीनों वर्गों के

गुण अलग-अलग परिमाण में व्यवहार किये जाते हैं।<sup>१</sup> इन तीनों में से रूसी कृषि संगठन के लिये आरटेल के सिद्धांतों पर आधारित सामुदायिक फार्म चुना गया। 1933 में कुल कोलखोज का 96.3% आरटेल, 19% तोज और 18% कम्यून थे।<sup>२</sup> आज-कल कम्यून और तोज प्रायः लुप्त हो चुके हैं और आरटेल को ही कोलखोज पुकारा जाता है।

आधुनिक रूसी कृषि संगठन के तीन प्रधान अंग हैं : सामुदायिक फार्म या कोलखोज, राजकीय फार्म या सोवखोज तथा मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन [या संक्षेप में 'मट्रस']।

### कोलखोज [Kolkhoz]

**विशेषताएँ**—कोलखोज की रूप-रेखा 1935 के "कृषि आरटेल के आदर्श नियम" में सामने रखी गई। इसके अनुसार आदर्श कोलखोज में निम्नलिखित बातें होनी चाहिये :

**उद्देश्य**—श्रम तथा उत्पादन के साधनों का सामान्य प्रयोग करके किसान शोषण, गरीबी, अज्ञानता, व्यक्तिगत कृषि पर विजय पायेगा। इससे श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी और किसान के जीवन-स्तर में सुधार होगा। प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि आरटेल को शक्तिशाली बनाये, पूरे ईमानदारी और मेहनत से काम करे, सामुदायिक आय को काम के अनुसार बाँटा जाय, सार्वजनिक सम्पत्ति की देख भाल करे, राजकीय योजनाओं की पूर्ति में पूर्ण सहयोग दे तथा इन सब कामों से सच्चा बोलशेविक बने।

**भूमि**—सारी भूमि सोवियत राज्य की है। आरटेल का इस पर स्थायी अधिकार होगा। भूमि बेची या खरीदी नहीं जा सकती। सदस्यों की भूमि को आपस में मिला कर एक विशाल खेत में बदल दिया जायगा। मकान के नजदीक हर सदस्य को निजी भूमि मिलेगी जो लगभग आधे एकड़ से 2.5 एकड़ तक हो सकती है। इसकी मात्रा सदस्य की राज्य सेवा पर निर्भर करती है।

**उत्पादन के साधन**—सारे उत्पादन के साधन जिससे कोलखोज पर काम होता है, सामुदायिक स्वामित्व में रहेगा। सदस्य के परिवार का निवास-स्थान, पशु-पक्षी तथा औज़ार, जिसका वह निजी प्रयोग करता है, व्यक्तिगत स्वामित्व में रहेगा।

**सदस्यता**—नये सदस्यों के लिये सार्वजनिक सभा से स्वीकृति लेना आवश्यक है। 16 वर्ष के युवक-युवतियों को सदस्य बनाया जा सकता है। किसी सदस्य का निष्काशन

1 Calvin Hoover The Economic Life of Soviet Russia, p. 92

2 Naum Jasny The Socialized Agriculture of the U. S S R.,

भी आम सभा ही कर सकती है। यदि कोई सदस्य अपनी इच्छा से आरटेल छोड़ना चाहे तो उसको नगद पूँजी वापस कर दी जायगी और सामुदायिक भूमि के बाहर उसे भूमि भी दी जायगी।

**आर्थिक साधन—**भूमि तथा पशु उत्पादन का प्रयोग इस प्रकार होगा :

[1] राज्य से प्राप्त सुविधाओं का सुगतान करना उत्पादन का प्रथम कार्य है। इसमें मशीन व ट्रैक्टर स्टेशन की सहायता, राज्य से मिले बीज की वापसी और राज्य को अनाज देने के समझौते का पालन आता है।

[11] अगले वर्ष के बीज तथा चारे के लिये एक कोप बनना जो अनुमानित आवश्यकताओं का 10 से 15% होना चाहिये।

[111] बूढ़, पशु, सैनिकों के परिवार तथा बच्चों के पालन-गर्हो [nursuries] के लिये भी सचय करना, इसकी मात्रा कुल उत्पादन के 2% से अधिक नहीं हो सकती।

[1V] उत्पादन का एक अंश राज्य या बाजार को बेचने के लिये अलग रखा जाय।

[V] कार्य-दिवस [work days] के अनुसार वचा हुआ उत्पादन सदस्यों में बाँट दिया जायगा।

इसी तरह पूरे सामूहिक फार्म की 'वार्षिक' आय के बटवारे के लिये भी नियम बनाये गये—

[1] राजकीय टैक्स और बीमा

[11] उत्पादन की वर्तमान आवश्यकताओं का खर्च जैसे मशीन, मरम्मत, जड़ल साफ करना इत्यादि।

[111] प्रबन्ध तथा व्यवसायिक खर्च

[1V] सांस्कृतिक तथा प्रशिक्षण कार्यों के लिये व्यय

[V] अविभाजनीय कोष [indivisible fund] में जमा, बाहरी कारीगरो व मजदूरों का वेतन, कृषि बैंक से प्राप्त दीर्घ-कालीन ऋण का सुगतान।

[VI] वचा हुआ धन सदस्यों में कार्य-दिवस के अनुसार बाँट दिया जायगा।

कोलखोज की आर्थिक शक्ति अविभाजनीय कोष [indivisible fund] पर निर्भर करती है। सदस्यों के अंशदान [contribution] से इसका निर्माण होता

है। किसी भी अवस्था में इसे बढ़ा नहीं जा सकता। आय का कम से कम १०% और अधिक से अधिक २०% इस कोष में रखा जा सकता है।

**संगठन**—फार्म का सभी काम सदस्यों के व्यक्तिगत श्रम से होगा। विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त वैतनिक श्रम नहीं रखा जा सकता। फार्म के सदस्य उत्पादन त्रिगेड [production brigade] में वॉट दिये जायेंगे। इनके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। कुछ त्रिगेड में १०० से भी अधिक व्यक्ति होते हैं। त्रिगेड को लगभग ७ से १४ व्यक्तियों के दल में बाँटा जाता है। इन्हें ज्वीनो या कड़ी [Zveno or link] कहते हैं। खेतों पर नियुक्त त्रिगेड कम से कम एक फसल-क्रम [crop-rotation] के लिये रहेंगे जिससे काम को जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली जा सके। औसतन इनकी नियुक्ति तीन सालों के लिये होती है। प्रत्येक त्रिगेड को सभी आवश्यक औजार, पशु तथा अन्य वस्तुएँ दी जायेंगी। त्रिगेड फार्म के पशुओं की देख-रेख और वृद्धि का काम करेंगे। त्रिगेड का नेता [त्रिगेडियर] काम का बँटवारा, अनुशासन तथा भुगतान संभालेगा।

त्रिगेड तथा ज्वीनो के आपसी महत्व में समय-समय पर बहुत परिवर्तन हुआ। कोलखोज संगठन का आधार होने से इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के पहले तक कार्यकुशलता, अधिक उत्पादन और उत्तरदायित्व की दृष्टि से बड़े-बड़े त्रिगेड अच्छे नहीं समझे जाते थे। इनको छोटे कार्य समूह [working groups] अथवा ज्वीनो में बाँटने की पद्धति लागू करने पर बहुत जोर दिया जाता था। युद्ध के बाद भी यही क्रम चलता रहा। अचानक फरवरी १९५० में यह नीति बदल दी गई। ऐसा विचार किया जाता है कि ज्वीनो का प्रचलन बढ़ता देख कर सोवियत नेताओं को व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के पुनर्जागरण का डर हुआ।<sup>१</sup> आजकल त्रिगेड द्वारा काम कराने की ही ठीक समझा जाता है।

**भुगतान**—कृषि का कार्य कर्म-भुक्ति अथवा वेतन [piece-wage] प्रणाली पर होगा। कोलखोज शासन की ओर से कार्य के प्रमाण [standards for work] तथा वेतन निश्चित किया जायगा। इस औसत से यदि कोई त्रिगेड अधिक उत्पादन कर ले तो सामान्य सदस्यों को उपार्जित कार्य दिवस [number of work-days earned] का १०%, उदात्तिक [udalnik] अथवा विशेष योग्य, परिश्रमी व कर्मठ सदस्य को १५%, और त्रिगेडियर को २०% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। आय का आधार सदस्य के द्वारा उपार्जित कार्य-दिवस की संख्या होगी। कार्य-दिवस [work-day] एक काल्पनिक माप है। अलग-अलग कामों के लिये त्रिगेडियर कार्य दिवस निश्चित

करता है। कठिन कार्य करने वालों को अधिक कार्य-दिवस मिलता है, आसान काम करने वालों को कम।

आरम्भ से ही किसान समुदाय को अधिकार, कार्य तथा वेतन के अनुसार वर्गों में बाँटने का प्रयत्न किया गया। इसके द्वारा आपसी प्रतिस्पर्धा, अधिकतम प्रयत्न तथा मनोवैज्ञानिक रूप से श्रेष्ठता के अनुभव का लाभ उठाना सम्भव था। 1933 में ही कृषि-कार्य को सात वर्गों में विभाजित किया गया। कार्यकुशलता की आवश्यकता और परिश्रम की मात्रा इस वर्गीकरण का आधार बनाये गये। प्रतिदिन का वेतन इस बात पर निर्भर करता था कि उस दिन किस वर्ग का काम किया गया। पहले वर्ग के कार्य के लिये आधा कार्य-दिवस जोड़ा जाता था। प्रत्येक ऊँचे वर्ग के लिये चौथाई कार्य-दिवस अधिक मिलता था। साल के अन्त में किसान द्वारा अर्जित कार्य-दिवस के योग [Total] के अनुसार पारिश्रमिक की मात्रा नापी जाती थी। 1948 में नया वर्गीकरण किया गया जिसमें नौ श्रेणियाँ थीं। प्रथम तथा अन्तिम श्रेणी के पारिश्रमिक की दर में पॉचगुना पारिश्रमिक का अन्तर था। इसके अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य से अधिक काम करने वालों को और भी कार्य-दिवस का लाभ दिया गया। लक्ष्य तक न पहुँचने वालों का कार्य-दिवस काट लिया जाता था। उद्देश्य यह था कि सुस्ती और लापरवाही करने वालों को सजा देने के साथ अच्छे कार्य-कर्ताओं को पुरस्कृत किया जाय।

### कोलखोज प्रबन्ध

‘आरटेल के आदर्श नियम’ के अनुसार कोलखोज का प्रबन्ध एकदम प्रजातन्त्रात्मक तरीके से होना चाहिये। प्रायः हर एक पदाधिकारी का चुनाव होता है। 16 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों की एक ग्राम सभा होती है। इसके द्वारा एक सभापति, प्रबन्ध समिति, अक्रेडिटिंग समिति [Auditing Commission], वार्षिक आय-व्यय का अनुमान, वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण, कृषि बैंक से ऋण, राज्य तथा मशीन-ट्रेक्टर स्टेशन [मट्रस] के साथ समझौता इत्यादि सभी काम पर विचार तथा निर्णय किया जाता है। प्रबन्ध समिति के सभापति पर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहता है। अगर ग्राम सभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो सभापति को स्तीफा देना होगा। प्रबन्ध का यह चित्र प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्त तथा स्वशासन [Self-government] का आदर्श रूप प्रतीत होता है। वास्तविकता में कोलखोज प्रबन्ध पर दो इतने शक्तिशाली प्रभाव हैं कि यह स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय अर्थहीन बन गया है।

**राज्य का प्रभाव**—सर्वव्यापी आयोजन पद्धति में राज्य का प्रबल प्रभाव कोलखोज पर पड़ना स्वाभाविक है। फैक्टरी तथा कोलखोज प्रबन्ध में राजकीय संचालन

[या हस्तक्षेप] लगभग एक ही तरह का मिलता है। अन्तर केवल यह है कि कारखाना में प्रत्यक्ष संचालन होता है : कोलखोज में ग्राम सभा के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की 'सलाह' पर विचार करके उनको सदा स्वीकार किया जाता है। रूसी लेखकों के अनुसार राज्य कारखानों का प्रबन्ध करता है किन्तु कोलखोज का केवल पथ-प्रदर्शन [guide] करता है। इस काम में गाँव की सोवियत, जिला सोवियत, मशीन ट्रेक्टर स्टेशन और कोलखोज समिति [The Council of Kolkhoz Affairs] की सहायता ली जाती है। मद्रस केवल भारी कृषि यन्त्रों को किराये पर देकर कोलखोज की सहायता नहीं करता, संगठन तथा अन्य समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह [expert advice] भी देता है। इसके द्वारा कोलखोज को कुछ भी मानने के लिये राजा किया जा सकता है क्योंकि बिना यान्त्रिक सहायता के उत्पादन सम्भव नहीं होता। 1946 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के आधीन कोलखोज समिति का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य कोलखोज संगठन, प्रबन्ध तथा कार्यक्रम में सन्तुलन उत्पन्न करना है। कोलखोज में होनेवाले साधनों का अपव्यय, दुरुपयोग तथा अन्य बुराइयों को दूर करने के लिये समिति कार्यशील रहती है। विशेष निरीक्षकों [Inspectors] के द्वारा यह काम किया जाता है। राज्य के हितों के रक्षक की तरह इन निरीक्षकों का अधिकार-क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। अतः कोलखोज प्रजातंत्र एक संचालित प्रजातंत्र [Controlled democracy] है जो वास्तविक शक्ति का प्रतीक न होकर, शासन प्रबन्ध की कला में शिक्षा देने का माध्यम है।

**कम्युनिष्ट पार्टी का प्रभाव**—कारखाना सङ्गठन की तरह कृषि-क्षेत्र में भी साम्यवादी दल की शाखाएँ प्रायः हर क्षेत्र में फैली हैं। गाँव, जिला के अतिरिक्त प्रत्येक कोलखोज में दल का सङ्गठन पाया जाता है। इतने दिन हो जाने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवादी का एक हिस्सा साम्यवादी दल का सदस्य नहीं बना है। इसलिये कोलखोज के साम्यवादी नेता बोलशेविक सिद्धान्त के प्रचारक के रूप में काम करते हैं। कोलखोज की ग्राम सभा या प्रबन्ध समिति के कार्यों की आलोचना करना और उनको सलाह देना इनका अधिकार है। समाजवाद के विस्तार के लिये आवश्यक समझ कर कोई भी काम करा लेना, इनके लिये कठिन नहीं।<sup>1</sup>

इन प्रभावों को सुदृढ़ तथा आसान बनाने के लिये 1950 से एक नई योजना चलाई गई। इसके अनुसार कोलखोजों की संख्या में कमी करना निश्चित हुआ। इसका प्रत्यक्ष कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ प्राप्त करना था। अधिकारियों द्वारा यह भी

<sup>1</sup> राज्य तथा पार्टी के प्रभाव का सब से शक्तिशाली माध्यम मद्रस है। इसका अध्ययन उपयुक्त स्थान पर होगा।

बतलाया गया कि बड़े सामुदायिक फार्मों की मदद से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को समाजवादी ढाँचे में मिला लेना आसान होगा और कृषि-कार्य में श्रम उत्पादकता [labour productivity] बढ़ सकेगी। इतना ही नहीं, अनावश्यक श्रम, कर्मचारी तथा प्रबन्धकों से कमी कर देने से कोलखोज अधिक लाभपूर्ण बन सकेंगे। ऐसा अनुमान है कि आफिस कर्मचारी तथा अफसरों की संख्या में नई नीति के द्वारा ३०% कमी की गई है। बड़े पैमाने पर कृषि सङ्गठन होने से विशाल कृषि नगर [Agricultural cities] का निर्माण निश्चित है। इस तरीके से गाँव और शहर के बीच का अन्तर कम किया जा सकता है। कोलखोज की संख्या में कमी करने की प्रगति अत्यन्त तीव्र रही। १९५० में २,५२,००० कोलखोज को एक साल के अन्दर १,२३,००० में बदल दिया गया। अक्टूबर १९५८ में कुल ७८,००० सामुदायिक फार्म थे।

यह कहा जा सकता है कि सोवियत नेता सदा से ही कोलखोज को एक अस्थायी संगठन मानते थे। स्टालिन ने अपने प्रसिद्ध “रूस में समाजवाद की समस्याएँ” [Economic Problems of Socialism in USSR]<sup>1</sup> में यह आशा की थी कि सामुदायिक फार्म को धीरे-धीरे राष्ट्रीय सम्पत्ति में बदल दिया जायगा जिससे फार्म का उत्पादन राज्य को सीधे मिल जाय तथा उसके बदले में राज्य उन्हें निर्मित वस्तुएँ दे। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पूर्ण राष्ट्रीयकरण ही सोवियत संघ का अन्तिम ध्येय है।

### सोवखोज [Sovkhoz]

विकास—राजकीय कृषि फार्मों को, गुणों तथा विशेषताओं के अनुसार अन्न उत्पादन के राजकीय कारखाने [State factories of agricultural produce] कहा जा सकता है। इन खेतों का प्रबन्ध औद्योगिक कारखानों की तरह होता है। क्रान्ति के बाद कृषि सङ्गठन का यह रूप साम्यवादियों को बहुत आकर्षक लगा। १९१७ से १९३२ तक राज्य की ओर से सोवखोज संगठन तथा विस्तार में पूरी सहायता दी गई। सार्वजनिक स्वामित्व तथा अन्य साम्यवादी सिद्धान्तों से सोवखोज का इतना साहस था कि इसके विकास में सैद्धान्तिक जोश का बहुत हाथ रहा। आदर्श फार्मों के रूप में भी यह महत्वपूर्ण थे। इनके द्वारा आधुनिक कृषि प्रणाली तथा सामुदायिक संगठन के लाभ प्रदर्शित किये जाते थे। क्रान्ति के बाद किसानों का खुला असहयोग और अन्न की भीषण कमी ने भी सोवखोज के प्रचलन में बहुत मदद किया। प्रत्यक्ष रूप से, बिना किसानों की सहायता लिये, अन्न प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन राजकीय फार्म मालूम पड़े।

<sup>1</sup> Translated in “Current Digest of Soviet Press”,

राजकीय फार्मों की प्रगति अत्यन्त तीव्र रही। 1918 से आरम्भ होकर 1928 में इनकी संख्या 1,400, औसत वार्षिक मजदूर 3,16.800, और जोती हुई जमीन का क्षेत्रफल 17,00,000 हेक्टर हो गया इसके बाद विकास का क्रम और बढ़ा। 1932 में यही ऑफ़े इस प्रकार थे—संख्या 1,337, मजदूरों की संख्या 18,91,500 और जोती हुई जमीन का क्षेत्रफल 1,34,00,000 हेक्टर हो गया। इस समय से राजकीय फार्मों का अपव्यय, कुप्रबंध तथा अनार्थिक संचालन को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इनके आकार और कार्य प्रणाली को पुष्ट तथा लाभपूर्ण बनाने के लिये नये फार्मों की स्थापना रोक दी गई। इस कान में विशेष सफलता न मिलने का कारण सोवखोज का विशाल आकार और खराब भूमि थी। औसत राजकीय फार्म केन्द्रीय रूप में 3,000 हेक्टर का और ओमस्क क्षेत्र में 22,000 हेक्टर का पाया जाता है। आरम्भ के सोवखोज पुराने सामन्तों के विस्तृत खेतों पर स्थापित किये गये थे। किन्तु बाद में नई भूमि को कृषि में लाने के लिये इस संगठन का व्यवहार किया गया। पिछले चार सालों में इन फार्मों के आकार तथा उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। 150,00,000 हेक्टर नई भूमि इनके द्वारा खेती योग्य बनाई गई। बहुत बड़े बंजर भूमि के टुकड़ों पर सोवखोज स्थापित कर दिये जाते थे। स्वाभाविक है कि प्रबंध की कठिनाइयों के साथ-साथ बंजर भूमि का विकास महंगा पड़ता है। इतना सब होने पर भी सोवखोज का महत्व कम नहीं होने पाया। राजकीय फार्म पर पूँजी विनियोग इस प्रकार रहा : 1946-50 में 42 मिलियर्ड रूबल; 1951-55 में 157; और 1956-57 में 149। 1956 में 9,000 से भी अधिक राजकीय फार्म थे। उनके अधिकार में लगभग 121 मिलियन हेक्टर भूमि है जिसमें से 25 मिलियन हेक्टर पर खेती होती है। इनका यंत्रीकरण भी बहुत अधिक है। 1956 में 2,57,000 ट्रैक्टर, 63,000 हारवेस्टर-कम्बाइन और 70,000 लारी इनके पास थीं। इनके महत्व का अनुमान इन ऑफ़िज़ों से लगता है : 1956 में 17% खेती योग्य भूमि इनके पास थी, राज्य की आवश्यकताओं में से 27%, अनाज, 15%, मांस और 18% दूध इनसे प्राप्त होता था।

**सोवखोज और कोलखोज में अन्तर :**

कृषि क्षेत्र में सहयोगी होने पर भी सोवखोज तथा कोलखोज में समानता पाना अत्यन्त कठिन है। राजकीय फार्म में सहकारिता का कोई चिन्ह नहीं मिलता। किसी प्रकार का भी सोवखोज हो, इसके संगठन तथा प्रबंध में किसानों का सहयोग नहीं लिया जाता। एक कारखाने की तरह इसके प्रबंधक राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और उनका उत्तरदायित्व भी राज्य की ओर रहता है। किसी एक प्रकार के उत्पादन या कृषि कार्य में ही सोवखोज पूरा ध्यान देते हैं। यह विशिष्टीकरण कोलखोज में नहीं पाया जाता है। आजकल यह चेष्टा की जा रही है कि एक तरह के उत्पादन के साथ-साथ अन्य



सम्भावित दिशाओं में भी इनको बढ़ाया जाय। कोलखोज एक एच्छिक समुदाय [Voluntary association] है जिसे किसान आपस में मिलकर बनाते हैं। राजकीय फार्म केवल राज्य बना सकता है। सोवखोज का प्रबन्ध ट्रस्ट और ग्लाव्क [glavk] तथा सोवखोज मंत्रालय या अन्य मन्त्रालय करते हैं। इस प्रकार इनका प्रबन्ध निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा न होकर राज्य द्वारा नियुक्त संस्थाएँ तथा व्यक्ति करते हैं। सोवखोज में निजी भूमि, निवास-स्थान तथा अन्य मकानों के लिये भूमि मिलती है। उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि इससे होने वाली आय [कोलखोज की तरह] सदस्यों की आर्थिक स्थिति का आधार नहीं होती। 1947 से पहले कर्मचारियों को 0.37 एकड़ तथा प्रबन्धकों को 0.50 एकड़ भूमि मिलती थी, इनको बढ़ाकर अब 1.25 एकड़ कर दिया गया है। इसकी तुलना में कोलखोज के सदस्यों को 2.5 एकड़ तक निजी भूमि मिलती है जिसमें निवास स्थान इत्यादि की भूमि शामिल नहीं की जाती। मजदूरों का संगठन कोलखोज से मिलता-जुलता है। मजदूरों को ब्रिगेड तथा इक्विनों में बाँटकर काम कराया जाता है। वेतन के भुगतान में विशेष अन्तर दिखलाई पड़ता है। राजकीय फार्म सीधे तौर पर काम के अनुसार [straight piece wages] रूबल में वेतन देते हैं। यह तरीका एकदम कारखानों की तरह है। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये अपने वेतन का 10 से 30% तक बोनस दिया जा सकता है। श्रम के क्षेत्र में एक बुनियादी भिन्नता मिलती है। सोवखोज में काम करने वालों को मजदूर [worker] का पद तथा अधिकार मिलते हैं जो कि एकदम कारखाना मजदूर की तरह होते हैं। कोलखोज के सदस्य केवल किसान [Peasant] हैं। इनको मजदूरों से कम विकसित तथा महत्वपूर्ण समझा जाता है। अर्थ-व्यवस्था में भी इनको मजदूरों के समान स्थान नहीं मिलता।

### संगठन तथा प्रबन्ध

सोवखोज का संगठन तथा प्रबन्ध औद्योगिक ढाँचे पर किया गया है। एक क्षेत्र में, एक ही प्रकार का उत्पादन करने वाले सोवखोज एक ट्रस्ट में बाँधे जाते हैं। अधिकतर यह ट्रस्ट सोवखोज मंत्रालय के केन्द्रीय बोर्ड [Central Board of the Ministry of Sovkhoz] के आधीन कार्य करते हैं। इन केन्द्रीय बोर्ड को ग्लाव्क [glavk] कहा जाता है। कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादन करने वाले सोवखोज अन्य मंत्रालयों से भी सम्बन्धित रहते हैं।

कारखाने की तरह एक-व्यक्ति-प्रबन्ध [one-man-management] सोवखोज में अपनाया गया है। इसका संचालक [director] विशेष अधिकार प्राप्त राज्य कर्मचारी होता है। फार्म की पूरी जिम्मेदारी इसको उठानी पड़ती है। संचालक

को अधिक स्वतंत्रता देने के लिये, उसके ऊपर से स्थानीय सोवियत शासन का अधिकार हटा दिया गया।

आर्थिक प्रबन्ध, हिसाब-किताब और लागत लेखा [cost accounting] के लिये प्रशिक्षित एकाउन्टेन्ट तथा आडीटर को सोवखोज का मुख्य अफसर माना जाता है। सोवखोज संगठन में कम्युनिस्ट पार्टी तथा मजदूर संघ का अपना अलग अस्तित्व होता है। इनके काम करने का ढङ्ग और अधिकार प्रायः उसी प्रकार के हैं जैसा औद्योगिक क्षेत्र में मिलता है।

सोवखोज संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन 1954 में किये गये। सिद्धान्त रूप में यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक राजकीय फार्म लाभदायक उद्यम [enterprise] होना चाहिये। इसके लिए यह कदम उठाए गये : [1] सोवखोज मुद्रा-प्रणाली में अपना हिसाब रखे जिससे लागत नियंत्रण [cost control] संभव हो सके। [2] अपने ही साधनों से हर फार्म अपने सभी खर्चें पूरा करे। इस दृष्टि से 1954, अप्रैल से राजकीय अनुदान [state subsidy] बढ़ कर दिया गया। [3] फार्म के उत्पादन की मूल्य-निर्धारण प्रणाली बदल दी गई। नई प्रणाली में सभी फार्म पृथक् क्षेत्रों [zones] में बाँटे गये। हर क्षेत्र में मूल्य-निर्धारण अलग-अलग होता था। उत्पादन की लागत पर ध्यान रखते हुए मूल्य का स्तर इतना रखा जाता था कि हर फार्म को कुछ लाभ हो सके। चूँकि सोवखोज को अपनी आय से ही सम्पूर्ण खर्च पूरा करके आवश्यक कोष भी बनाना पड़ता था, इसलिये यह तरीका बड़ा सफल रहा। सोवियत फार्म को लाभपूर्ण बनाने के साथ कृषि आयोजन प्रणाली में भी परिवर्तन किया गया। इसके द्वारा फार्मों को अपना साधन देखते हुए कई बातों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया जैसे, जोताई का क्षेत्रफल, कृषि उत्पादकता, पशुओं की संख्या, पशु-उत्पादन इत्यादि। इन सब परिवर्तनों से राजकीय फार्म के प्रबन्धको पर अच्छा प्रबन्ध-संगठन का पूरा उत्तरदायित्व आ गया और इसके लिये काफी प्रोत्साहन भी मिला।

### मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन [मट्रस]

कृषि विकास के लिए, आधुनिक यांत्रिक सहायता केन्द्रीय रूप से दी जाती है। मट्रस राजकीय संस्थाएँ हैं जिनका मुख्य काम सामुदायिक फार्मों को सहायता करना है। इसकी अन्य सहायताओं में सिंचाई, सड़क निर्माण, कुएँ-तालाब बनाना, चरागाह की उन्नति तथा नई भूमि खेती योग्य बनाना उल्लेखनीय है। प्रायः हर प्रकार की बड़ी मशीनें राज्य की ओर से इन केन्द्रों को दी जाती हैं। लगभग 20 लाख कर्मचारी, इञ्जीनियर, तथा कृषि-विशेषज्ञ मट्रस में काम करते हैं। इनकी सहायता तथा सलाह निःशुल्क

[free] नहीं होती। कोलखोज और मद्रस के आपसी प्रसविदा [contract] के द्वारा मशीनों की आवश्यकता, समय, कार्यकाल तथा किराया तय होता है। यह किराया उत्पादन के एक अंश में दिया जाता है इसकी औसत मात्रा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के 15 से 20% तक होती है। कुछ सेवाओं का भुगतान नगद भी होता है।

पहला मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन 1928 में स्थापित किया गया। 1956 में लगभग 9,000 स्टेशन सारे देश में फैले थे। इनकी प्रगति अत्यन्त तीव्र रही। 1930 में मद्रस के पास कुल 25,000 ट्रैक्टर और सात हारवेस्टर-कम्बाइन [harvester-combine] थे। 1955 में 11,09,000 ट्रैक्टर तथा 2,80,000 हारवेस्टर-कम्बाइन तथा विविध प्रकार की अन्य मशीनें काम में लगी थीं।

मद्रस का उद्देश्य बहुमुखी है। सामुदायिक उत्पादन विकास में यह प्रबल शक्ति बन गई। कोलखोज प्रबन्ध तथा संचालन में भी इनका महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। राज्य के वित्त [fiscal] व्यवस्था का यह विशेष अङ्ग है।

यह संगठन रूस के कृषि संचालन का एक विभाग है फिर भी एक कारखाने की तरह इसका प्रबन्ध आर्थिक सिद्धान्तों पर किया जाता है। लेकिन लागत-प्रणाली [cost accounting] इसमें लागू नहीं होती। पूँजी केन्द्रीय बैंक से मिलती है परन्तु कारखाने की तरह निर्णय तथा काम की स्वतंत्रता नहीं होती।

मद्रस का प्रबन्ध-सङ्गठन सोवखोज से मिलता है। कृषि मन्त्रालय को मद्रस केन्द्रीय बोर्ड [glavk] 1947 में स्थापित की गई। इसके द्वारा सभी स्टेशनों के बीच संतुलन, कोलखोज से सम्बन्ध तथा राजकीय नीति निर्धारण किया जाता है। एक स्टेशन 5 या 6 कोलखोज का काम देखता है। मद्रस और सदस्य कोलखोज के प्रतिनिधियों की एक समिति घनिष्ठ आपसी सम्बन्ध स्थापित करने के लिये काम करती हैं। प्रत्येक मद्रस में एक संचालक के साथ तीन सह-संचालक और एक एकाउन्टेन्ट रहता है। सह-संचालकों में राजनैतिक कार्यकर्ता [political worker], कृषि-वैज्ञानिक [agronomist] और इंजीनियर-मिक्सी [engineer-mechanic] नियुक्त होते हैं। इनको उच्च वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारी माना गया है। अन्य कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिया जाता है। काम के ब्रेटवारे की सुविधा के लिये अनेकों ट्रैक्टर-ब्रिगेड बनाये जाते हैं। एक ब्रिगेड में तीन या चार ट्रैक्टर तथा अन्य आवश्यक यंत्र होते हैं। प्रत्येक ट्रैक्टर संचालक [operator] ब्रिगेड की सबसे छोटी इकाई होती है। मिले हुए काम को ब्रिगेड इनमें बाँट देता है जिससे मशीनों का अधिकतम प्रयोग हो सके।

### कृषि आयोजन में नई धाराएँ

जोसेफ स्तालिन की मृत्यु के बाद से देश में परिवर्तनों का नया युग आरम्भ

हुआ। कृषि क्षेत्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। दिसम्बर 1958 में खुश्चेव ने पिछले पाँच सालों के कृषि विकास पर एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें कई धाराओं पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्तमान योजना में कई परिवर्तन तो स्थान भी पा गये। यह आशा की जाती है कि योजना के सन्तान होने तक [1965] कृषि संगठन और प्रबन्ध का ढाँचा एकदम बदल जायगा। इन परिवर्तनों के लिए सारा श्रेय खुश्चेव को नहीं मिलना चाहिये। मृत्यु के कुछ ही पहले न्नालिन ने कृषि-क्षेत्र को नई चेतना देने के लिए तीन उपाय बताये थे—[1] कोलखोज की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध, [2] राजकीय संचालन में वृद्धि, तथा [3] कृषि में लगभग उन्हें सिद्धान्तों को लागू करना जो उद्योग में सफल सिद्ध हो चुके थे।<sup>1</sup>

**कोलखोज तथा मद्रस :** यह अनुभव किया गया कि देश के कृषि-विकास में वह स्तर आ चुका है जब कि मद्रस और कोलखोज को मिला देना चाहिये। खेती पर इन संस्थाओं का दोहरा संचालन [dual control] स्थापित हो गया है। मद्रस की कुछ अपनी कर्मचारियों भी इस निर्णय का कारण थी। अनावश्यक मात्रा में मशीनों का संग्रह केवल प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया जाने लगा। मशीनों के लिए पूरा काम नहीं मिलता था। कोलखोज के विलयन [merger] की नीति से साधन इतने बढ़ गये थे कि सामुदायिक फार्म अपनी निजी मशीनें रखना पसन्द करने लगे। यह भी विश्वास किया जाता है कि कोलखोज के साधनों को राष्ट्रीय काम में लगाने का यह आसान तरीका होगा। मशीनों का भुगतान पा कर राज्य की आर्थिक सहायता होगी।

**सामुदायिक तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति :** साम्यवाद के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के सभी साधन राष्ट्रीय सम्पत्ति बना दिये जायें। सामुदायिक फार्म की सम्पत्ति एक समूह [group] की सम्पत्ति है जिसे सच्चा समाजवादी रूप नहीं माना जा सकता। इसलिए कोलखोज को पूर्ण राजकीय स्वामित्व में बदलना होगा। यह उसी समय हो सकता है जब सामुदायिक फार्म को राजकीय फार्म में बदल दिया जाय। मद्रस की संस्था को तोड़कर मशीनों को कोलखोज को वेचना उस दिशा में पहला कदम है।

समय के साथ कोलखोजों के अविभाजनीय कोष [indivisible fund] ने विशाल आकार ग्रहण कर लिया है। 1952 में कुल सामुदायिक फार्मों के पास इस कोष में 4.7 बिलियन रूबल था। इस समय लगभग 100 बिलियन रूबल है। इस धन-राशि को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने के लिए आन्दोलन चलाया गया है। सातवीं योजना ने कोलखोज और राष्ट्रीय सम्पत्ति को सहयोगी मान कर साथ रखा है।

<sup>1</sup> "Economic Problems of Socialism in Russia, Op. Cit."

1959-1965 में कृषि पर लगभग 500 बिलियन रूबल खर्च होगा जिसका 70% कोलखोज की सम्पत्ति से लिया जायगा।

इसके अतिरिक्त, अविभाजनीय कोष को सार्वजनिक रूप में लगाने का एक और तरीका अपनाया जा रहा है। अन्तर-कोलखोज [inter-kolkhoz], औद्योगिक तथा अन्य निर्माण में इसका उपयोग होगा। एक क्षेत्र के कई सामुदायिक फार्म आपसी आवश्यकता के काम पूरे करेंगे और इसका खर्च अविभाजनीय कोष से आयेगा। इनके मुख्य काम हैं—बिजलीघर निर्माण, सड़क, सिंचाई, कृषि उत्पादन को रखने के लिए कोल्ड-स्टोरेज [Cold Storage], कृषि के कुछ उद्योग [चीनी मिल, एल्कोहल, कैनरी, दूध तथा मांस के उद्योग] अन्न संग्रह स्थान [elevators], स्कूल, अस्पताल इत्यादि। यह केवल योजना ही नहीं है। 1958 के अन्त तक इन पर 102 बिलियन रूबल खर्च हो चुका है।<sup>1</sup>

**निजी भूमि तथा पशु**—व्यक्तिगत सम्पत्ति का यह अवशेष भी शीघ्र ही मिट जायगा। दिसम्बर 1958 में खुश्चेव ने इनको अनावश्यक तथा “प्राचीन-काल की वस्तु” कहा और सोवखोज में इस प्रथा को उठा देने की सलाह दी। इस काम के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। फिर भी, इसमें संदेह नहीं कि कोलखोज की निजी-भूमि के 20 मिलियन टुकड़े ज्यादा समय तक व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं बचेंगे। इन पर पलने वाले करोड़ों पशु भी राज्य द्वारा खरीदने की योजना है। इस प्रकार किसानों की आय के दोनों मुख्य साधन उनसे छिन जायेंगे।

**आर्थिक साधन तथा वेतन प्रणाली**—1953 से कोलखोज के आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए अनाज खरीदने का सरकारी मूल्य बढ़ा दिया गया। अधिक उत्पादन के साथ यह मूल्य वृद्धि तथा अन्य सुविधाओं ने सामुदायिक फार्म की मौद्रिक आय को काफी बढ़ा दिया : 1953-49'6 बिलियन रूबल, 1955-75 और 1956-94'6। किसानों के आर्थिक प्रोत्साहन [material incentive] की नई विधियों की खोज हो रही है। मार्च 6, 1956 में एक आज्ञा द्वारा वेतन तथा दूसरे पारिश्रमिक निर्धारित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता कोलखोज को दी गई। वेतन प्रणाली के कई नये रूपों पर विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है। कोशिश यह है कि किसानों को निश्चित वेतन मिले [regular guaranteed payment]। अलग-अलग कोलखोज इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयत्नशील हैं। इसका एक प्रचलित तरीका है जिसमें महीने के आरम्भ में निश्चित धन किसानों को दे दिया जाता है [Monthly Payment in Advance System]। इसका आधार पिछले महीने में उपार्जित कार्य-दिवस [work-days] होते हैं। 1956 में देश के 40% कोलखोज इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे।

<sup>1</sup> Bulletin . Institute for the Study of the U.S.S.R May, 1959, p. 41

## श्रमिक संघ संगठन तथा प्रबन्ध

रूस में श्रमिक संघ के वही अर्थ नहीं माने जाते जैसा कि पश्चिमी देशों में समझा जाता है। मजदूरों के संगठित प्रतिनिधि के रूप में उनके अधिकार तथा सुविधाओं के लिये प्रयत्नशील रहना, रूस में कोई महत्व नहीं रखता। सरकार मजदूरों से बनी है। कारखाना सरकार के हैं इसलिये मजदूर अपने आप ही बनाये नियमों के अनुसार अपने लिये ही काम करता है। सिद्धान्त में, इस ढाँचे के अन्दर शोषण हो ही नहीं सकता। समाज कल्याण को देखते हुए राज्य जितना वेतन और सुविधाएँ दे सकता है, अपने आप दे देगा। इससे अधिक 'माँगना' समाज के हितों के विरुद्ध होगा। जो भी राज्य देना तय करे उसे 'स्वीकार' करना ही मजदूरों का कर्तव्य है।

क्रान्ति के बाद राज्य तथा श्रमिक संघ के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर बहुत मतभेद था। एक वर्ग यह मानता था कि श्रमिक संघ को स्वतंत्र काम करने देना चाहिये। 1922 के श्रमिक संघ कांग्रेस ने इसी विचार को उचित माना और इसी के आधार पर श्रमिक नियम [Labour Code] बनाया गया। किन्तु स्टालिन के सचालन में दूसरे वर्ग ने श्रमिक संघ तथा राज्य के घनिष्ठ सम्बन्ध को ही ठीक माना। राजशक्ति पाने के बाद, प्रथम योजना के आरम्भ [1928-1929] से ही पुरानी नीति को एकदम उलट दिया गया और इस वर्ग के नेता, टॉम्स्की [Tomsky] को पदच्युत कर दिया गया। उस समय से रूसी श्रमिक संघ राज्य के एक अंग की तरह काम करते हैं।

इस राजकीय प्रभाव से श्रमिक संघ के कुछ बुनियादी गुण उत्पन्न हुए। राज्य ने इनको अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार प्रयोग किया। असर यह हुआ कि श्रमिक संघ कानून और व्यवहारिक कार्य-प्रणाली [Law and practice] में अन्तर लगातार बढ़ना गया। धीरे-धीरे आजकल यह स्थिति आ गई कि श्रमिक संघ के कानून को पढ़ना ही बेकार हो गया है। राजनैतिक कारणों में इनको बदलो नहीं गया। इनमें लिखी उदार बातें तथा अधिकारों की सूची देखकर दोखे में न पड़ना चाहिये। असलियत में आजकल श्रमिक संघ के दो विशेष कार्य हैं। मजदूरों को कठोर अनुशासन में रखना [Labour discipline] और मजदूरों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध। प्रायः अन्य सभी काम में राज्य से प्राप्त 'सलाह' को स्वीकार किया जाता है।

श्रमिक संघ का विकास : पुराने रूसी शासन में इसका जन्म हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में होने वाली हड़तालों के कारण ही श्रमिक संघ बनाये गये थे। पहला श्रमिक संघ कीव [Kiev] में 1903 में बना। लेकिन वास्तविक आरम्भ 1905 के आन्दोलन से माना जाता है। 1905 के अन्त तक 199 श्रमिक संघ बन चुके थे।

इनकी संख्या 1906 में 453 और 1907 में 652 हो गई। इस समय इनके 2,45,000 सदस्य थे। 1906 में प्रथम अखिल-रूसी श्रमिक संघ सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के प्रभाव से श्रमिक संघ को वैधानिकता तो मिल गई किन्तु राष्ट्रीय संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। अक्टूबर क्रान्ति के बाद कम्युनिस्ट सरकार ने श्रमिक संघ का संचालन ले लिया। अनेक शासन सुधार तथा शुद्धि [purgas] से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई कि केवल साम्यवादी ही ऊँचे पदों पर नियुक्त हो सके। इसका प्रबल राजनैतिक विरोध हुआ। 1955 तक स्तालिन इसे दबाने में सफल हुआ और राज्य तथा श्रमिक संघ का स्थायी गठबन्धन हो गया। इतना होने पर भी श्रमिक संघ संगठन तथा कार्य-प्रणाली में स्थिरता न आने पाई। समय-समय पर होने वाले परिवर्तन कभी सतुलन नहीं आने देते। 1930 में 23 श्रमिक संघ थे और इनकी संख्या बराबर बढ़ रही थी : 1931-45, 1934-54, 1939-68, 1948 के बाद इनमें फिर संकुचन आरम्भ हुआ। 1948-53, 1954-43, 1957-47। नये पुनर्संगठन में इनकी संख्या केवल 23 रह जायगी।

श्रमिक संघ की सदस्यता ऐच्छिक [Optional] है लेकिन मजदूरों को इसका सदस्य बनना ही पड़ता है। 1957 में 5,00,00,000 श्रमिकों में से 4,71,00,000 संघ के सदस्य थे। बचे हुए श्रमिक या तो नये थे या अस्थायी।

**श्रम संघ का संगठन**—सोवियत श्रमिक संघ संगठन का आधार एक उद्योग होता है। उस उद्योग में काम करने वाले सभी व्यक्ति [मजदूर, कर्मचारी, अफसर तथा संचालक] एक संघ के सदस्य होंगे। प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीयकरण [Democratic Centralism] से इनका संचालन होता है। फ़ैक्ट्री समिति से लेकर केन्द्रीय समिति तक प्रत्येक पदाधिकारी का चुनाव किया जाता है। सदस्य अपनी मासिक आय का 1% शुल्क के रूप में देते हैं। सदस्यता ऐच्छिक है फिर भी श्रमिक संघ के सदस्य बनने पर कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। काम मिलने में प्राथमिकता इसमें मुख्य है। सामुदायिक समझौते [Collective Agreement] के अनुसार संघ के सदस्यों को पहला अवसर देने के लिये वाक्य किया जाता है। अगर ऐसी हालत आ जाय कि कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना पड़े, तो संघ के सदस्य सबसे बाद में निकाले जायेंगे। सामाजिक बीमा की सुविधाओं में भी इनको ऊँची दर पर लाभ मिलता है।

श्रमिक संघ के आधार पर तीन संगठन होते हैं। उद्योगों में फ़ैक्टरी समिति, आफिस तथा अन्य संस्थाओं में स्थानीय समिति, और फ़ैक्ट्री की दुकानों के कर्मचारियों के लिये [यदि उनकी संख्या 100 से अधिक है] दुकान समिति। इनमें से प्रत्येक, एक नेता [Group Steward], एक सामाजिक बीमा एजेंट तथा एक मजदूर इन्स्पेक्टर का चुनाव करती हैं। अखिल सोवियत श्रमिक संघ कांग्रेस देश भर के संघों की उच्चतम

संस्था है। कार्य-भार सँभालने के लिये यह कांग्रेस एक अखिल सोवियत श्रमिक संघ की केन्द्रीय समिति [All Union Central Committee of Trade Unions or AUCCCTU] चुनती है। वास्तविकता में कांग्रेस कभी-कभी हाँ बुलाई जाती है। 1912 और 1949 के बीच एक बार भी कांग्रेस नहीं बुलाई गई जबकि विधान के अनुसार चार वर्षों में कांग्रेस का इकट्ठा होना जरूरी है। श्रमिक संघ की केन्द्रीय समिति का निर्णय सभी सदस्यों पर अनिवार्य होता है। दैनिक कार्य-के लिये यह समिति एक प्रेसिडेंट, एक सिक्रेटरी तथा एक चेयरमैन चुनती है। केन्द्रीय समिति विभिन्न विभागों द्वारा कार्य-संचालन करती है जैसे संगठन विभाग, सामाजिक बीमा, वेतन, श्रमिक सुरक्षा, मकान, सांस्कृतिक तथा शिक्षा, वित्त, विधान, कसरत तथा खेल, और लेखा के विभाग, सेना-टोरियम तथा विश्राम यह विभाग, तथा कार्य-कारिणी-शासन विभाग।

**श्रमिक संघ के कार्य—**1949 में श्रमिक संघ विधान कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया। 1954 में कुछ परिवर्तन के साथ इनको फिर से स्वीकार किया गया। दिसम्बर 1957 में इनको सरकारी तौर पर मान्यता दी गई। इसके अनुसार श्रमिक संघ के मुख्य कार्य हैं : [1] मजदूर तथा अन्य कर्मचारियों में समाजवादी प्रतिस्पर्धा का सिद्धान्त फैलाना; [2] श्रम-उत्पादकता को अधिकतम प्रोत्साहन देना; [3] योजना के लक्ष्यों की पूर्ति और लक्ष्य से अधिक उत्पादन; [4] उत्पादन के गुण [quality] में उन्नति; [5] उत्पादन के लागत में कमी, [6] आर्थिक साधनों का अधिकतम प्रयोग; [7] वेतन निर्धारण में सहयोग; [8] कारखाने के साथ सामुदायिक समझौता करना, [9] सामाजिक बीमा तथा जन कल्याण के कार्य का प्रबन्ध, [10] सदस्यों की शिक्षा, प्रशिक्षण [Training] तथा समाजवादी सिद्धान्तों की जानकारी बढ़ाना, [11] स्त्रियों को औद्योगिक और सामाजिक जीवन में आकर्षित करना, तथा [12] मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में उनको समस्याओं का अध्ययन करना और सुझाव देना।

इन कामों में सामुदायिक समझौता [Collective Agreement] रूसी श्रमिक संघ की विशेषता है। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के प्रतिनिधि की तरह, श्रमिक संघ कारखाने के साथ यह समझौता करता है। इसके द्वारा कारखाना प्रबंध और मजदूर दोनों ही कुछ कर्तव्य-पालन की प्रतिज्ञा करते हैं जिससे [1] योजना के लक्ष्य पूरे हो सकें, [2] मजदूरों के काम के वातावरण में सुधार हो, और [3] मजदूरों का जीवन-स्तर ऊँचा उठे।



## अध्याय ११

# रूसी योजनाएँ

[Russian Plans]

### रूसी योजनाएँ

• • • जोसेफ स्तालिन के संचालन में कृषि-प्रधान, पिछड़ा हुआ, दुर्बल रूस औद्योगिक, विकसित तथा शक्तिशाली बनने के लिये उद्यत हुआ। प्रगति के नये मार्ग की खोज हुई, जो इतना प्रशस्त और व्यापक था कि संसार चकित हो उठा। इस मार्ग का नाम था 'राष्ट्रीय योजना' और लक्ष्य था देश के सभी अङ्गों का संयोजित तथा समुचित विकास। कौन जानता था कि प्रगति की ओर अग्रसर होने की यह प्रणाली एक दिन संसार के सभी अविकसित देशों का आदर्श बन जायगी। इतना ही नहीं नाजी जर्मनी को तोड़कर पाशविकता से सारे संसार को बचाने का श्रेय योजनाओं को ही है। यदि 1940 तक रूस की दो योजनाएँ पिछले 60 वर्ष के पिछलेपन को दूर न करती तो आज इतिहास नए तरह से लिखा गया होता। इस प्रणाली की सफलता एवं आवश्यकता में अब सदेह करना अज्ञानता का परिचायक होगा। समय के साथ योजना प्रणाली में इतनी प्रगति हो चुकी है कि सकटकाल में तो इसी के एक रूपान्तर का सहारा प्रायः सभी पूँजीवादी देशों ने लिया। सैद्धान्तिक तनातनी और 18वीं शताब्दी की अर्थहीन आदर्शवादिता से प्रेरित होकर अभी भी विश्व के विचारक रूसी ढङ्ग की योजना को उसका उचित स्थान नहीं देते। रूस, और अभी हाल में चीन, की सफलता को देखते हुए यह विचारधारा अनुचित प्रतीत होती है।

### गोयल्रो योजना [Goelro Plan]

रूस में व्यवहारिक योजना का मूलपात लेनिन के द्वारा किया गया था। उसके विचार से रूस में समाजवाद स्थापित करने का एकमात्र उपाय देश की आर्थिक व्यवस्था को विद्युतकरण के आधार पर पुनर्संगठित करना था। बिजली पर मशीनों का उत्पादन निर्भर करता है जिनके बिना समाजवादी औद्योगीकरण और सैनिक शक्ति नहीं बन सकती। लेनिन का प्रसिद्ध फार्मूला था कि साम्यवाद सोवियत शक्ति तथा सम्पूर्ण देश के विद्युतकरण का योग है [Soviets plus Electricity equals Commu-

nism]। इसी कारण से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम लेनिन ने अपने सामने देश के विद्युतकरण की योजना [Electrification-Plan] के रूप में आरम्भ किया। राज्य के स्थायी अङ्ग की तरह एक योजना सगठन का सूत्रपात इस काम के लिये किया गया। इस आयोजन संस्था को राजकीय विद्युतकरण आयोग [State Commission for Electrification] अथवा गोयल्न्रो [Goelro] कहने हैं। गोयल्न्रो मार्च 1920 में स्थापित हुआ और दिसम्बर 1920 में इसकी योजना को स्वीकृति मिली। फरवरी 1921 में इसे गासप्लान से मिला दिया गया। इसके अनुसार 10 से 15 वर्षों के बीच सारे देश में विद्युतशक्ति पहुँचा दी जायगी। इसका उद्देश्य था कि 30 नये बिजलीघर बना कर विद्युत उत्पादन की क्षमता 175 मिलियन किलोवाट बढ़ा दी जाय और पुराने बिजलीघरों की नये नक्शे के अनुसार मरम्मत हो। इसका प्रभाव, यह अनुमान किया गया था कि योजना काल में औद्योगिक उत्पादन 1913 का लगभग दूना हो जायगा। क्रान्ति के पहले रूस के उद्योग बिजली का अधिक प्रयोग नहीं करते थे। 1913 में रूसी बिजलीघरों की उत्पादन शक्ति कुल 11.1 मिलियन किलोवाट थी और वार्षिक उत्पादन 1.9 बिलियन किलोवाट-घण्टे [kwh]। धन, सगठन, अनुभव तथा विरोध की कठिनाइयों को झेलते हुए इस योजना ने 1930 तक करीब-करीब अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लिया। इस समय तक औद्योगिक उत्पादन 1913 का लगभग दुगुना हो गया था। 1931 के मध्य तक नये बिजलीघर बन गये और 1932 में बिजली का उत्पादन भी योजना से अधिक होने लगा। 1935 में इस 15 वर्षीय योजना की पूर्ण सफलता घोषित की गई। उस समय तक औद्योगिक उत्पादन 1913 का 5.7 गुना और बिजली का उत्पादन 14.5 गुना अधिक होने लगा।

आगे आने वाली योजनाओं में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति के साथ विद्युत शक्ति पर पूरा ध्यान रहा। प्रथम योजना में 2.97 मिलियन किलोवाट की नई उत्पादन शक्ति स्थापित हुई; दूसरी योजना में 3.6; चौथी में 8.5 और पाँचवीं में 17.6 मिलियन किलोवाट की नई उत्पादन शक्ति स्थापित की गई। छठी योजना में लगभग 40 मिलियन किलोवाट विद्युत-शक्ति की स्थापना होगी। 1957 के आरम्भ में रूसी बिजलीघर की उत्पादन शक्ति 43 मिलियन किलोवाट अथवा 1913 का 39 गुना बढ़कर हो गई। इस प्रगति में लगभग 300 बड़े बिजलीघर स्थापित हुए जिनमें 10 जल-विद्युत केन्द्र थे। इस प्रकार रूस तेजी के साथ संयुक्त राज्य अमरीका को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 1913 में संयुक्त राज्य अमरीका रूस से 11.8 गुना अधिक बिजली पैदा करता था। यह संख्या घटकर 1932 में 7.4 और 1957 में कुल 3.4 गुना रह गई। 1959-65 की सतवर्षीय योजना में यह आशा की जाती है कि बिजली का उत्पादन लगभग 57.5 बिलियन-किलोवाट-घण्टे हो जायगा।

विजली का उत्पादन और महत्व<sup>1</sup>

वर्ष	उद्योग में विद्युत शक्ति का उपयोग		औसत वार्षिक श्रम संख्या [उद्योग में]		प्रति औद्योगिक श्रमिक द्वारा विजली का उपयोग		औद्योगिक श्रम की उत्पादन शक्ति [Labour Productivity]
	बिलियन kwh	%	हजार	%	kwh	%	%
1928	3.3	100	3,124	100	1,056	100	100
1932	8.7	264	6,007	192	1,448	137	141
1937	24.4	740	7,924	254	3,079	292	258
1940	32.1	973	8,290	265	3,872	367	343
1950	60.6	1,836	11,208	362	5,319	507	470
1955	113.3	3,433	14,281	457	7,399	751	679
1956	126.0	3,818	15,180	486	8,300	786	726

**प्रथम पंचवर्षीय योजना [1928-1932]**—६ वर्ष की विस्तृत खोज घोर विवाद और अथक परिश्रम के बाद इसका जन्म हुआ। यह एक प्रयोग था जिसमें प्रथम प्रयास के उत्साहपूर्ण विश्वास और अनुभवहीनता की त्रुटियाँ थीं, इसलिये असन्तुलन के साथ क्षमता से अधिक काम करने की आशा इसके प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। इनको योजनाकर्ताओं ने देखा और आगे आने वाले प्रयत्नों में इनका संशोधन किया।

प्रथम योजना का आराम उद्देश्य एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना था जिसमें उत्पादन शक्तियों का अधिकतम विकास हो और संयोजित रूप से मजदूरों की दशा में सुधार हो।<sup>2</sup> नवीन आर्थिक नीति का पुनर्संगठन और समाज का औद्योगिकरण के

<sup>1</sup> "Problems of Economics", October 1958, p. 16,

<sup>2</sup> V. V. Obolensky-Ossinsky : World Social Economic Planning p. 330

आधार पर पुनर्निर्माण का मार्ग अग्रसर किया गया। आरम्भ में तो उद्योगों को केवल सकेत द्वारा निर्देशित किया गया, जोकि शीघ्र ही कठोर आज्ञाओं में बदल गए। पृज्जीवाद के समूल विनाश के प्रयत्न का चिन्ह इसके हर अंग में दृष्टिगोचर होता है विशेषकर कृषि-क्षेत्र में जहाँ कि इसकी जड़ें खोदने दृढ़ता के साथ ज़रूरती थी। सिद्धान्त रूप से यह अटल विश्वास बन चुका था कि पृज्जीवाद और समाजवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। यह आवश्यक है कि इनमें से एक का ही सहारा लिया जाय। यह कहा जा सकता है कि इसपर और भविष्य की योजनाओं पर राजनीति की छाप गहरी थी। राजनैतिक तथा नैतिक उद्देश्य के आगे आर्थिक योजना के दूसरे सभी पहलुओं का समर्पण हुआ।<sup>1</sup> जन-कल्याण के लिये समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना प्राथमिक उद्देश्य न रही। इस प्रकार बुनियादी तौर पर प्रथम योजना गृह-युद्ध की नैतिक प्रणाली का विस्तार था या यों कहा जाय कि यह दूसरी क्रान्ति थी जिसे स्तालिन ने सफलतापूर्वक पूरा किया। पहली क्रान्ति में लेनिन ने राजसत्ता प्राप्त कर नए रूस का निर्माण किया। दूसरे में स्तालिन ने देश के औद्योगिक और नैतिक क्षेत्रों को मूलरूप से बदलकर नई समाजवादी राज्यसत्ता को स्थायी बनाया। लेनिन ने जारशाही का अन्त किया और विदेशी शत्रुओं से देश की रक्षा की, स्तालिन ने देश के अन्दर के उन सभी केन्द्रों को उखाड़ फेंका, जिसमें नए विचारधारा के शत्रुओं का नृजन और पोषण हो सकता था। दो आधारभूत विचार योजनाकार्ताओं के मन में जमे : प्रथम किसी भी मूल्य पर शीघ्रतम औद्योगीकरण अतिआवश्यक है, द्वितीय सोवियत कृषि का समूल पुनर्संगठन से कम कोई भी प्रयत्न इस औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक अन्नकोष नहीं बना सकता।

यह सब परिवर्तन जनता पर ऊपर से लादा गया। 1917 की क्रान्ति समाज के निम्नतर स्तरों को उत्तेजित करके उत्पन्न की गई थी, स्तालिन ने दूसरी क्रान्ति उच्चतम स्तर से आरम्भ किया और सारे देश को उसमें सम्मिलित होने के लिये बाध्य किया। कठुता, रक्तपात और असम्भव को सम्भव बनाने वाली सफलता इसका परिणाम था।

कृषि क्षेत्र में प्रथम योजना ने बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाये। यह पूर्णतया निश्चित हो गया कि कृषि का स्थान केवल उद्योगों के बाद ही नहीं आता, वरन् कृषि का उद्देश्य हर प्रकार से उद्योगों को सहारा देना है। विख्यात रूसी प्रोफेसर कौन्ट्रेतीव ने कहा कि औद्योगीकरण की गति इतनी अधिक है कि आर्थिक साधनों की खोज में किसानों पर अत्यधिक दबाव डालना होगा।<sup>2</sup> जून 1928 में स्तालिन ने घोषित किया,

1. Oscar Lange in Lippincot (Ed), On Economic Theory of Socialism, p. 43

2. Manya Gordon, Workers before and after Lenin, p. 377.

‘हमारे पास उपनिवेश, साथ, अथवा ऋण नहीं है। वे [पूँजीवादी देश] हमें देगे नहीं। परिणामस्वरूप कृषक पर टैक्स लगाने को आधार बनाना होगा’<sup>1</sup> और यही हुआ भी। सरकार ने राष्ट्रीय साधनों का मुख्य अंग विदेशों से मशीन और कौशल प्राप्त करने के लिये अलग कर दिया। 1927-28 में राष्ट्रीय बजट को उद्योग से 288 मिलियन रूबल प्राप्त हुए और 783 मिलियन रूबल इन पर खर्च किए गए। 1932 में 943 मिलियन रूबल मिला और 15,357 मिलियन रूबल उद्योग पर खर्च हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि सदा की भाँति सोवियत संघ में भी किसान अपने पसीने से दूसरों को ही सहारा देता रहा। क्रांति के पहले जार तथा उच्च वर्ग की समृद्धि का किसान साधन था; क्रांति के बाद औद्योगिक प्रगति का आधार। लेनिन का विख्यात सिद्धान्त ‘किसान मजदूर सहयोग’ [smytchka] उसकी मृत्यु के बाद खुले पक्षपात में बदल जायगा, इसकी आशा किसी को न थी। प्रथम योजना [वाद की अन्य योजनाओं की भी] यह विशेषता रही है कि लक्ष्य का निर्धारण अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों तथा राजनैतिक नेताओं के द्वारा होने पर भी, उसे लागू करते समय फिर से संशोधन [बिना योजना आयोग के पूछे] किया जाता था। इसीलिये यह धारणा काफी प्रबल है कि समाजवादी सरकार ने आर्थिक योजनाओं को भी अपने राजनैतिक खेल का एक अंग बना लिया है। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये उत्पादन के लक्ष्य की जो रूपरेखा तैयार होती थी, उसका व्यवहारिक महत्व केवल सैद्धान्तिक था। सैनिक दृष्टि से भारी उद्योग की वृद्धि करने का सिद्धान्त इन लक्ष्यों में परिवर्तन का आधार बनाया जाता था। प्रथम योजना में मशीन व बिजली के सामान का उत्पादन अपने लक्ष्य का 157% हुआ जबकि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन केवल 73.5% था। इसी प्रकार सामुदायिक खेतों में 25% कृषक परिवारों को सम्मिलित करने की योजना 1932-33 तक बढ़ कर 60% हो गई।

लक्ष्यों की पूर्ति केवल निर्देशित ही नहीं थी वरन् असन्तुलित भी थी। 1932-33 में मशीन व बिजली के सामान की उपरोक्त वृद्धि के साथ स्पात का उत्पादन 44 लाख टन कम हुआ और अनाज का 106 मिलियन टन के स्थान पर केवल 70 मिलियन टन था। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि रूसी योजनाएँ जन-कल्याण की समाजवादी अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप से स्थापित करने में भी राजनैतिक प्रभाव से अपने को न बचा सकी।

**कृषि**

कृषि-क्षेत्र में प्रथम योजना अत्यन्त सक्रिय रूप से पुनर्संरुद्धन के काम में लगी।

इसमें पहला उद्देश्य पूँजीवादी प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना था। इस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्वामित्व, स्वतन्त्रता तथा प्राचीन प्रथाओं में पाई जाती थी। बिना इसको बदले हुए स्थायी व सुरक्षित समाजवादी राज्य की स्थापना वस्तुतः असम्भव थी। छोटे-छोटे खेतों में बँटी हुई कृषि और बहुत ही विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण किसानों तक पहुँचने का एक ही सफल साधन था—उनको बड़ी इकाइयों में बाँट दिया जाय जिससे राजनैतिक शिक्षा सङ्गठित रूप से देना सम्भव हो। इसी उद्देश्य-प्राप्ति के लिये परिवर्तन की आवश्यकता की मनोवैज्ञानिक स्थिति और वर्ग-सघर्ष को भी सहारा दिया गया। खेतों की बड़ी इकाइयों से 'समाजवादीकरण' के अतिरिक्त उत्पादन पर राज्य को पूर्ण संचालन तथा नियंत्रण मिल पाता था। इस प्रकार प्रथम योजना के कृषि सम्बन्धी दो मुख्य कार्यक्रम बने—सामुदायिक खेती का विकास तथा समृद्धिशाली किसान अथवा कुलक वर्ग का समूल विनाश।

सामुदायिक कृषि के साथ उत्पादन के यंत्रीकरण से राज्य को अनेकों लाभ प्राप्त हुए। किसानों का विरोध, कम खेत जोतना और अनाज को सरकार के हाथ न बेचना सामुदायिक कृषि प्रथा में सम्भव नहीं था। मशीन, ऋण, बीज, खाद इत्यादि सुविधाएँ तथा उनके भुगतान में राज्य के प्रति किसानों का दायित्व इतना अधिक हो जाता था कि बाध्य होकर किसान निश्चित मूल्य पर उत्पादन का बहुत बड़ा भाग सरकार को दे देता था। इस तरह रूसी अर्थव्यवस्था की अत्यन्त प्राचीन समस्या—राज्य द्वारा अन्न की प्राप्ति—सदा के लिये हल हो गई; क्योंकि इस व्यवस्था में राज्य के पंजा से वच निकलने का कोई उपाय न था। मार्च 1930 तक सामुदायिक खेती की वृद्धि किसानों के खुले विरोध पर भी बराबर होती रही। यहाँ तक कि अधिकारियों द्वारा पूरे जिले को सामुदायिक कृषि का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था और सभी किसान अपने आप कोलखोज [Kolkhoz or Collective Farms] के सदस्य मान लिये जाते थे। इसका जरा भी विरोध किसान को समाजवाद का शत्रु और देशद्रोही बनाने के लिये काफी था। प्रथम योजना ने स्पष्ट रूप से आगाह किया था कि इस काम में अनुचित दबाव या जल्दी हानिकारक होगी। क्रमिक सामुदायिक खेती का उद्देश्य योजना ने सामने रखा था। इसके विपरीत, इस बात में मतभेद है कि इतना दबाव स्तलिन की चाल थी अथवा कर्मचारियों का अनुचित उत्साह। शायद नये जोश में आकर किसानों पर हर प्रकार का सम्भव दबाव डाला गया जिससे कि वे डर कर कोलखोज का सदस्य होना स्वीकार करें। खुले बाजार में अनाज बेचने का अधिकार छिन गया। किसान केवल सरकारी समितियों को ही निश्चित मूल्य पर अपनी उपज बेच सकते थे। शताब्दियों बाद 1917 की क्रान्ति में अपनी आशाओं को फलित होने देखकर रूसी कृषक ने नया जीवन प्राप्त किया था। उन सबको अचानक खो देने पर किसानों की शोषण सहन करने की

अपार शक्ति अपनी सीमा तक पहुँच गई। सुसुप्त विरोध प्रत्यक्ष हो उठा। जगह-जगह पर सरकारी अफसरों की हत्याएँ, कोलखोज में आग लगाना और पशु-वध तेजी से बढ़ने लगा।

नवीन आर्थिक नीति के अन्तिम वर्षों में यह दिखलाई पड़ने लगा था कि कृषि-क्षेत्र कुलक वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभुत्व सोवियत किसानों से मेल नहीं खा सकता। इनको हटाने की नीति फरवरी 1930 में सरकारी तौर पर घोषित की गई किन्तु 1929 में ही इनको सामाजिक शत्रु कह कर हटाने का प्रयत्न चल चुका था। यह किसान वर्ग सपन्न, शिक्षित और कुशल कृषि उत्पादक होने के साथ व्यक्तिगत उत्पादन प्रणाली का खुला पोषक था। अपने अधिकार व स्वामित्व को छोड़कर इन्हे सामुदायिक खेतों में सम्मिलित करने के लिये किसी भी तरह आकर्षित नहीं किया जा सकता था। इसी से यह निश्चित किया गया कि इस छोटे से वर्ग की बलि देकर दूसरे सभी किसानों को सामुदायिक खेतों में सङ्गठित होने के लिये लाचार किया जाय। यह काम काफी आसान था क्योंकि गरीब, आलसी किसानों की ईर्ष्या तथा क्रोध का लक्ष्य मेहनती, धनी किसानों को आसानी से बनाया जा सकता है। स्टालिन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पूँजीवादी प्रभावों को क्रमिक प्रतिबन्ध द्वारा हटाने की पुरानी नीति के स्थान पर कुलक वर्ग के पूर्ण उन्मूलन [elimination] की नई नीति अपनाना आवश्यक था। इसके विपरीत प्रथम योजना ने व्यक्तिगत किसान विशेषकर समृद्धिशाली किसानों की पूरी सहायता लेने के लिये प्रेरित किया था। 1917 के बाद से दबी हुई जनता की पाशविक प्रवृत्तियों कुलक वर्ग पर एक साथ टूट पड़ी। जिस प्रकार का जघन्य अत्याचार इस समय सामने आया वह रूसी इतिहास पर स्थायी कलक है। क्रूरता, दमन और प्रतिशोध की जो आग भड़की वह इतनी भयंकर थी कि सारा ससार यह समझने लगा कि स्टालिन ने आखिरकार अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठा लिया। सोवियत शक्ति का आधार लाल सेना थी जिसके अधिकतर अफसर कुलक वर्ग के थे। अपने परिवार की दुर्दशा देखकर सेना में भी असन्तोष फैलने लगा।

मार्च 1930 तक परिस्थिति इतनी बिगड़ी कि स्टालिन को अपनी एकतंत्रात्मक, असीमित राज्य-शक्ति तथा विलक्षण बुद्धिबल व चातुर्य को प्रयोग में लाने के लिए वाय्य होना पड़ा। 2 मार्च 1930 को स्टालिन ने एक ऐतिहासिक लेख लिखा जिसका शीर्षक 'सफलता का उन्माद' [Dizzy with Success] था। इसमें उसने स्वयं अनावश्यक जोश से उत्पन्न भ्रूतों को दिखलाया और सलाह दी कि यंत्र तथा बल प्रयोग के स्थान पर ऐच्छिक रूप से कोलखोज का विस्तार किया जाय। कुलक वर्ग के उन्मूलन में व्यक्तिगत प्रतिशोध तथा ईर्ष्या के प्रयोग से जो मध्यवर्गीय किसान भी कुलक मान लिये गये थे उसकी स्टालिन ने बुराई की। शिक्षा और प्रबन्धकुशलता न होने से कोलखोज

की तीव्र वृद्धि ने उत्पादन को बहुत हानि पहुँचाई थी। स्टालिन ने सलाह दी कि जहाँ कोलखोज के आवश्यक साधन न हों वहाँ पुरानी पद्धति ही रहने दी जाय। इस नई विचारधारा ने तहलका मचा दिया। यह समझा जाने लगा कि जिस प्रकार लेनिन ने अपनी जल्दवाजी की भूलों को नवीन आर्थिक नीति [New Economic Policy] से सुधारा, उसी प्रकार स्टालिन भी अब नवीनतम आर्थिक नीति [Newest Economic Policy] अपनायेगा। किन्तु स्टालिन ने आश्चर्यजनक तत्परता से परिस्थिति को सम्भाला। इस शासक की शक्ति इतनी सर्वव्यापी थी, और किसान इतनी असहाय अवस्था में थे कि थोड़ी-सी छूट पाकर उनका असन्तोष शान्त हो गया। सामुदायिक कृषि की अभूतपूर्व तीव्र-गति ने ससार को चमत्कृत कर दिया। प्रथम योजना के साधारण आशाओं के विपरीत जनवरी से मार्च 1930 के बीच कोलखोज में 21.6% कृषक परिवारों से बढ़कर 55% कृषक परिवार आ गये। 'सफलता का उन्माद' के धक्के के बाद बड़े पैमाने पर किसानों ने सामुदायिक सङ्गठन की सदस्यता छोड़कर पुराने ढाँचे पर आना शुरू किया। मई 1930 में कुल 24.1% परिवार कोलखोज में बचे। यह सब क्षणिक छूट ही थी। कुलक उन्मूलन और सामुदायिक कृषि के सिद्धान्त की प्राथमिकता कभी कम न हुई। 1930 में अच्छी फसल हो जाने से नये दङ्ग की खेती पर योजना-कर्ताओं और जनता का विश्वास जमने लगा। साथ ही साथ इस दिशा में प्रगति पूर्ववत् चलती रही। परिणामस्वरूप 1931 में फिर से 52.7% और 1932 में 61.5% कृषक परिवार कोलखोज की सदस्यता में लाये गये और उनकी संख्या बराबर बढ़ती रही।

इस नीति का कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों को जब अपने स्वामित्व का विश्वास न रहा तो उन्होंने खेतों को बोना बन्द कर दिया और अपने पशुओं को सरकारी सम्पत्ति बनने के पहले मार डाला। यह पशु-वध इतना व्यापक था कि इसमें होने वाली हानि को देश अगले 10 वर्षों में पूरा न कर सका। किसानों की अरुचि तथा अविश्वास से कृषि उत्पादन में अचानक इतनी कमी आई कि 1931-32 में भयंकर अकाल पड़ा; सरकारी तौर पर इस अकाल को केवल अन्न की कमी करके ढाल दिया गया है। किन्तु विभिन्न स्रोतों के अनुमान के अनुसार 30 से 90 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।<sup>1</sup>

जारशाही को उखाड़ने के लिये अक्टूबर क्रान्ति में किसानों से 'शान्ति तथा भूमि' का वायदा किया गया था किन्तु उन्हें इनमें से कुछ भी न मिला। विश्व-युद्ध, क्रान्ति, गृह-युद्ध और अन्त में वर्ग-युद्ध ने उन्हें कभी भी चैन से न बैठने दिया। जब तक भूमि उसके पास थी वह सन्तुष्ट था। 'स्टालिन क्रान्ति' ने खोई हुई शान्ति के साथ

<sup>1</sup> S and B Webb Soviet Communism pp. 358-94 and 561-72, W. H Chamberlin Russia's Iron Age, pp 66-92, J. E. Davies : Mission to Moscow, p. 390



किसानों की भूमि भी ले ली। कृषि-क्षेत्र में इस योजना से भविष्य-निर्माण तो हुआ किन्तु किसानों का वर्तमान बिल्कुल बिगड़ गया।

### ✓ पूँजी-निर्माण

किसी प्रकार की भी योजना हो वंचित और पूँजी-निर्माण के सफल सङ्गठन बिना उसका उचित विस्तार असम्भव है। पूँजीवाद के प्रत्येक प्रभाव को हटा देने पर भी पूँजी का महत्व समाजवादी रूस में कम न हो सका। एक गरीब कृषि-प्रधान देश के लिये औद्योगिक विकास की आवश्यक पूँजी इकट्ठा कर लेना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि पूँजी-निर्माण की मात्रा-उत्पादन के साधनों में होने वाले वार्षिक ह्रास [Depreciation] से अधिक होना चाहिये। इसी तरह, आवादी के लगातार बढ़ने पर भी राष्ट्रीय पूँजी का विस्तार किया जा सकेगा। अगर इतना न हुआ तो उन्नति और विकास की जगह अर्थव्यवस्था स्थिर हो जायगी। पूँजीवाद में यह काम व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें इतना धन पैदा करना सभव बनाया जाता है कि वे अपने आप वंचित तथा विनियोग करें। समाजवाद में आय-व्यय और विनियोग का काम राज्य अपने ऊपर ले लेता है। आर्थिक सङ्गठन इस प्रकार किया जाता है कि इस क्षेत्र में पूर्व-निश्चित पूँजी-निर्माण अनिवार्य रूप से हो जाय। इसी सफलता के आधार पर उत्पादन तथा औद्योगीकरण का पूरा ढाँचा बनता है।

प्रथम योजना काल में पूँजी विनियोग [capital investment] का निम्नलिखित रूप रहा—

रूस में पूँजी विनियोग <sup>1</sup>

	विलियन रूबल में	
	1923-24 से 1927-28	1928-29 से 1932-33
कुल विनियोग	26 5	64 6
उद्योग	4 4	16 4
विद्युत्करण [केवल केन्द्रीय विद्युत् गृह]	8	3 1
यातायातकरण [पूँजीगत मरम्मत सहित]	2 7	10 0
कृषि	15 0	23 2

इसके अनुसार कुल पूँजी विनियोग  $2\frac{1}{2}$  गुना बढ़ेगा; राजकीय उद्योग, विद्युत-करण और यातायात में लगभग 4 गुना उन्नति होगी। निर्माण का आरम्भकाल सबसे कठिन होता है क्योंकि इस समय पुरानी 'रुकावटों को हटाकर नये उत्पादन संगठन की नींव डालनी पड़ती है। प्रथम योजना ने यह काम तो किया ही, साथ-ही-साथ इस नींव पर एक प्रभावशाली उत्पादन संगठन खड़ा कर दिया। इसे सम्भव बनाने के लिए वचत और पूँजी-निर्माण का जो विशाल प्रयास रूस ने किया वह नानवी प्रयत्न नहीं, दैवी चमत्कार नालून पड़ता है। आधुनिक उद्योगों का नया संगठन चन्द वर्षों पहले नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत हुआ। फिर भी प्रथम योजना के लिए आवश्यक साधन संचय करने में राष्ट्रीय आय का 30-5% भाग पूँजी निर्माण के लिए बचा लिया गया। यह इतनी बड़ी मात्रा है जिसकी बराबरी उस समय के श्रेष्ठतम औद्योगिक देश संयुक्त राज्य अमरीका तथा जर्मनी भी नहीं कर सकते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि 1928 के बाद राष्ट्रीय आय में जितनी उन्नति हुई वह लगभग पूरी तरह राष्ट्रीय पूँजी बना ली गई। इतना बड़ा सग्रह [accumulation] केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था में सम्भव है।

1925-26 के मूल्य पर निर्धारित राष्ट्रीय पूँजी के बँटवारे के आँकड़े यह बतलायेंगे कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों का आपसी सन्तुलन योजना किस प्रकार बदल रही थी।

उद्योग के अनुसार प्रारम्भिक पूँजी का वितरण : [प्रतिशत में]<sup>1</sup>

	अनुपात 1932-33 का 1927-28 से
कुल प्रारम्भिक पूँजी	182.1
उद्योग	300.0
केन्द्रीय शक्ति संस्था	530.0
रेल यातायात	167.4
कृषि	135.5

इसके साथ-साथ विविध सामाजिक अंगों में राष्ट्रीय पूँजी का बँटवारा भी अपना रूप बदल रहा था।

<sup>1</sup> Glinko, Op. Cit. p. 60

सामाजिक क्षेत्र के अनुसार प्रारम्भिक पूँजी का वितरण <sup>1</sup>

	प्रतिशत	
	1927-28	1932-33
कुल प्रारम्भिक पूँजी	100 I	100 I
राजकीय साहस द्वारा	51 0	63.6
सहकारी " "	1 7	5 3
व्यक्तिगत " "	47 3	31.1

इसके अनुसार राजकीय उद्योग-क्षेत्र की वृद्धि लगभग उसी अनुपात में हुई जिसमें व्यक्तिगत उद्योग कम किये गये। यह परिवर्तन आनेवाली सामाजिक रूपरेखा का पूर्व-संकेत था जिसमें नवीन आर्थिक नीति के व्यक्तिगत क्षेत्र को कोई स्थान नहीं दिया जायगा।

इस प्रकार अगर पूँजी विनियोग का क्रम देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उत्पादन के साधनों का उत्पादन इसका मुख्य ध्येय था। कुल औद्योगिक पूँजी विनियोग का लगभग 75% भारी उद्योगों में लगाया गया। औद्योगीकरण की इस सफल नीति के कारण देश की पूँजी में उद्योगों का हिस्सा 1928 में 14% से बढ़कर 1932-33 में 23% हो गया। रूस में विदेशों का असहयोग और पूँजीवादी देशों का डर विदेशी पूँजी को कोई भी महत्वपूर्ण स्थान पाने से रोके रहा। अधिकतर पूँजी-निर्माण राजकीय उद्योगों का लाभ तथा नागरिकों की वचत से पूरा किया गया। बड़े उद्योगों में लगाई जाने वाली 16,140 मिलियन रूबल की पूँजी का 90% उद्योगों की अपनी वचत से प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि यह केवल राजकीय एकाधिकार और केन्द्रीय संचालन के अन्तर्गत हो सकता है।

### उद्योग

आर्थिक स्वतन्त्रता और सैनिक शक्ति के लिए उत्पादन की वृद्धि रूसी योजना का विशेष प्रयत्न था। प्रथम योजना ने प्रतिवर्ष 20% उत्पादन वृद्धि का अनुमान किया था। हर क्षेत्र की तरह यहाँ भी लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ अर्थात् 24.4% प्रतिवर्ष। योजना के प्रथम वर्षों में उत्पादन की यह वृद्धि सम्भव बनाना देखकर सारा

<sup>1</sup> Ibid, p. 61.

संसार चकित हो गया क्योंकि इतिहास में कहा भी उन्नति को यह गति नहीं बन पाई थी। जारशाही के सबसे शान्तपूर्ण और प्रगतिशील काल में भी 10% प्रतिवर्ष से अधिक उत्पादन वृद्धि कमो नहीं हुई। यह अवश्य है कि उत्पादन के आँकड़े अधिकतर केवल राजकीय बड़े उद्योगों से सम्बन्धित होते हैं। इसलिए इनको सामान्य रूसी उत्पादन का नाटक मान लेना उचित नहीं। फिर भी उत्पादन वृद्धि की यह गति संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी तथा इंग्लैंड से इतनी अधिक है कि इसका कारण जानना एक रुचिकर विषय होगा।

1 नया विकास होने से यांत्रिक कुशलता का स्तर रूस में बहुत अधिक था। विज्ञान की सबसे नई देन रूसी उद्योग ने अपनायी।

2 1913 के बाद से उत्पादन इतना अधिक गिर गया था कि थोड़ी-सी वृद्धि होने पर प्रतिशत वृद्धि एकदम ऊँची उठ जाती थी।

3. उत्पादन के साधनों को संयोजित रूप से कम प्रकार की वस्तु निर्माण पर खर्च किया गया। योरप के औसत शहर में जितने प्रकार की वस्तुएँ मिलती हैं उसकी 5% भी रूस में नहीं बनाई जाती। इससे साधनों की बचत और उत्पादन में वृद्धि स्वाभाविक है।

4 मॉग का स्तर सदा उद्योगों के पक्ष में बना रहा। 1922-23 के संकटकाल [Scissors Crisis] को छोड़कर उद्योग कभी भी जनता की मॉग से अधिक उत्पादन न कर सके। प्रथम योजना काल [1928-33] सारे संसार के लिए औद्योगिक मंदी का समय था जिसका कोई भी चिह्न रूसी उद्योग में नहीं मिलता। एक-सी मॉग होने का कारण यह है कि क्रेताओं की इच्छा और क्षमता की समस्या रूस में पैदा नहीं होती। उतना ही उत्पादन होता है जितना योजना कहती है : योजना उतना ही कहती है जितनी क्रय शक्ति उपभोक्ताओं के हाथ में दी जाती है। प्रबल केन्द्रीय निर्देशन के द्वारा यह सम्भव होता है।

5 मुद्रा और साख पर पूर्ण नियन्त्रण होने से राज्य इच्छानुसार वस्तुओं के उत्पादन को निश्चित सीमा में बाँधे रखता है।

उत्पादन-वृद्धि के साथ एक और बात विशेष उल्लेखनीय है। उद्योग-क्षेत्र में लागत को घटाने पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि बिना लागत के कम किये हुए उच्चतम कोटि का पूँजी-निर्माण सम्भव नहीं था। प्रथम योजना ने पाँच वर्षों में 35% लागत घटाने का अनुमान किया; जबकि थोक दाम कुल 24% घटाने का विचार था। इस दिशा में विशेष ध्यान देने के कारण ही उद्योगों पर राजकीय नियन्त्रण तथा आंतरिक प्रबन्ध में सुधार हो सके। इस पर इतना अधिक जोर दिया गया कि उत्पादन की किस्म

बना। इसके द्वारा उन्हें हर समय पवित्र कर्तव्य की तरह उत्पादन वृद्धि का दायित्व समझने में बड़ी मदद मिली। बाहरी प्रोत्साहन और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा ने मिलकर रूसी मजदूर में अद्भुत कार्यशीलता उत्पन्न की, जिससे राष्ट्रोन्नति में वे पूरी तरह राज्य के सहयोगी बन सके।

### व्यापार :

वस्तु विनिमय तथा उपभोग का एकदम नया रूप सामने आया। प्रथम योजना ने पूँजी-निर्माण और भारी उद्योग की वृद्धि के लिये उपभोग पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। यह नियन्त्रण एक विशेष प्रकार का था। इसके अन्तर्गत राज्य ने संयोजित रूप से बिकने योग्य वस्तुओं का वेंचवारा तथा जनता के उपभोग का संचालन अपने हाथों में ले लिया। नागरिक उपभोग की सीमाएँ एक नये तरह से स्थापित की गईं, जिसका सिद्धान्त था कि जो काम नहीं करेगा उसको भोजन करने का अधिकार नहीं है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग की सामग्री उसके काम के महत्व तथा मात्रा के आधार पर निश्चित की जाती थी। उद्देश्य था कि लोग अधिकतम प्रयास करने के लिये उत्तेजित हों। उपभोग की सामग्री का मूल्य निर्धारण इस तरह से होता था कि जनता की माँग उन्हीं वस्तुओं के प्रयोग की ओर छोड़ दी जाय जिसको देश आसानी से बना सकता हो। अन्त में, इसके पीछे यह प्रयत्न भी था कि मूल्य-निर्धारण सीमित उपभोग की सामग्री के सहारे इस प्रकार हो कि जनता के हाथों से अधिक-से-अधिक आय राज्य के पास आ जाय। वचन का यह रूप रूस के विशाल पूँजी-निर्माण का अवलम्ब था।

1933 से कोलखोज के सदस्यों को तथा व्यक्तिगत किसानों को निजी उत्पादन खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता दी गई। कहने को तो इसका उद्देश्य था कि लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति की इच्छा, बिना किसी नुकसान के, आशिक्र रूप से पूरी हो जाय। किन्तु इसके साथ ग्रामीण जनता को राशनिंग के अन्तर्गत अनाज तथा अन्य खाद्य वस्तुएँ नहीं दी जाती थी। प्रभाव यह पड़ा कि अपनी व्यक्तिगत भूमि पर उत्पन्न वस्तुएँ व्यापार का अंग बनकर उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लग गईं। इस प्रकार व्यापार नाममात्र का ही चलता रहा। इस समय से रूसी व्यापार को 'व्यापार' की संज्ञा न देकर 'राजकीय वितरण' कहना ही ठीक मालूम पड़ता है।

### संचित समीक्षा

अंत में संसार की पहली योजना की संचित समीक्षा आवश्यक है। नवीन आर्थिक नीति में आर्थिक संगठन का संतुलन सुधारने का प्रयत्न किया गया था। उद्योग के राजकीय नियंत्रण तथा कारखाने के आन्तरिक प्रबंध में सरलता लाने के सभी प्रयास

केवल आंशिक रूप में सफल हो कर रह गये। प्रथम योजना में इन कमजोरियों पर ऊपर से नज़राने ने काफी ध्यान दिया किन्तु सामान्य कर्मचारी व मजदूर इसका महत्व काफी दाद में समझे। इतना ही नहीं। दृष्टिकोण सन्तुष्ट रूप में विकसित न होने से योजना के उच्चतम स्तर पर भी मनुष्य की कमी थी। सबसे महत्वपूर्ण और भारत के लिये रुचिकर उदाहरण था उद्योगों का स्थानीयकरण। कारखानों की स्थापना उपभोक्ता और कच्चा माल की प्राप्ति के अनुसार न होकर प्रदेशों की राजनैतिक तनातनी और अयनी-अयनी प्रतिष्ठावृद्धि के लिये हुआ।

दूसरी कमी इस क्षेत्र में अधूरे कानों की थी। योजना में जितने भी काम शुरू किये गये, उनमें से अधिकतर योजनाकाल में समाप्त हो सके। बड़े उद्योगों के लिये निर्धारित २४,७८९ मिलियन रूबल में से १९,७२८ मिलियन रूबल का काम हो पाया। बाकी अधूरा पड़ा रहा। इससे लक्ष्यपूर्ति का मुख्य भार पुराने कारखानों पर पड़ा जिनको अपनी क्षमता में बाहर काम करना जरूरी हो गया। उनके मशीनों का भयंकर ह्रास [Depreciation] सारे देश की हानि थी। इस कमी के मुख्य कारणों में सुस्ती, संगठन और आकार प्रियता [Gigantomania] मुख्य हैं। आकार-प्रियता संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह रूस की भी बीमारी बन गई थी। उनका हर एक काम भी सत्तार में सबसे बड़ा और सबसे महान कहलाने का प्रयत्न होता था। इसमें धन, समय और ज़िन्दगी आवश्यकता से अधिक लगता था। ज़रा-सी भूल सारी योजना को डगमगाने के लिये काफी थी। इससे भी बड़ा नुकसान इन विराट् केन्द्रों के निर्माण में यह था कि इनके आरम्भ और पूर्ति की अवधि बहुत लम्बी होती थी। समाज को इनके उत्पादन का व्यय अनेकों वर्ष तक उठाने पर कुछ लाभ प्राप्त होता था।

सूत्रा-सुधार और राजकीय नियंत्रण में अधिकतम कठोरता से भी मूल्य की वृद्धि न रोकी जा सकी। मजदूर किसान को अधिक काम की प्रेरणा देने के लिये उनकी आय तो बढ़ा दी गई किन्तु उपभोग की वस्तुएँ न बढ़ सकीं। भारी उद्योगों पर अत्यधिक जोर देने का यह कुप्रभाव पूरी योजनाकाल में साथ लगा रहा।

यातायात के साधनों का महत्व शायद पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के सत्रहवें अधिवेशन [१९३२] में अविकसित यातायात को प्रथम योजना की सबसे बड़ी कमजोरी घोषित किया गया। दूसरी योजना में इसे दूर करने के अच्छे प्रयत्न हुए। मजदूरों की कम उत्पादन शक्ति और वस्तुओं की ऊँची लागत का हल प्रथम योजना में न मिला। वेतन प्रणाली की त्रुटियाँ और अनुभवहीन इंजीनियर तथा कारीगरों की कमी इसका मुख्य कारण था। कुछ भी हो प्रथम योजना ने एक कृषक देश को कृषक-औद्योगिक देश बना दिया। इसके अंत में राष्ट्रीय आय का ५७.५% उद्योग, यातायात तथा निर्माण से, और २२.९% कृषि से मिला।

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना [1933-1937]

इस योजना की पृष्ठभूमि, रूसी पद्धति के अनुसार, रक्त रंजित रही है। आर्थिक क्षेत्र में प्रथम योजना की सफलता से उत्साहित होकर स्तालिन ने ट्रॉट्स्की के बाद अपने दूसरे प्रतिद्वन्द्वियों को क्षेत्र से हटाना आरम्भ किया। यह काम स्तालिन और इसके कुछ भक्त अनुयायियों ने बड़े पक्के तौर पर कठोरता से किया। 1934 में कीरोव की हत्या का बहाना लेकर अगले 4 सालों तक और दमन का चक्र, साम्यवादी दल से आरम्भ रक्त होकर, सारे देश में फैल गया। ख़ुबराइन तथा फिशर के अनुसार इस राष्ट्रीय शुद्धि [National Purge] में गिरे लोगों की सूची पर नये रूस के प्रायः सभी कर्णधारों का नाम मिल जायगा।<sup>1</sup> इसलिए 117 व्यक्तियों को फाँसी, पुराने बोलशेविक नेताओं में ६७ व्यक्तियों को कैद, पुलिस तथा सेना के 12 सबसे ऊँचे अधिकारियों की हत्या और लगभग 1 लाख राजनैतिक विरोधियों का देश-निष्काशन किया गया। अपना नेतृत्व सुदृढ़ करने के लिए और अपने से अधिक प्रतिभाशाली अथवा लोकप्रिय सभी नेताओं की सम्भावित प्रतिस्पर्धा को हटाने के लिए यह शुद्धि की गई। 1917 में साम्यवादी दल के केन्द्रीय समिति में 24 सदस्य थे। इनमें से 7 स्वाभाविक मृत्यु से मर चुके थे, 6 को प्राण-दण्ड दिया गया, 1 जेल में था और 6 अकारण ही गायब हो गये। ट्रॉट्स्की की देश-निष्कासन के बाद हत्या कर दी गई, और मैडम कोलोन्ताई स्वीडन में राजदूत थी। इस समय तक उस समिति का अकेला स्तालिन ही बचा था। इसका आर्थिक प्रभाव यह हुआ कि स्तालिन द्वारा निर्धारित नीति और संचालन निर्विवाद रूप से सर्वमान्यता प्राप्त कर सका। प्रभावशाली नेताओं के हट जाने से मनचाहे रूप में स्तालिन ने देश के नये ढाँचे का निर्माण किया। शुद्धि की विभीषिका से जनता इतनी डर गई कि आशापालन और अनुशासन अपनी चरम सीमा को छूने लगा। नवयुवक साम्यवादियों को मनोवैज्ञानिक रूप से रूस के लौह पुरुष ने राष्ट्रीय विकास का महा प्रभावशाली यंत्र बना दिया। उनकी शिक्षा, विचारधारा तथा परिश्रम का केवल एक ही उद्देश्य उनको बताया गया : रूस को शक्तिशाली बनाने में सहयोग देना। इस प्रवृत्ति से कर्तव्यों के प्रति जाग्रति और आत्मविश्वास की उत्पत्ति इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि रूसियों के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना असम्भव नहीं रह गया। द्वितीय-योजना और उसके बाद के प्रयास में यह पृष्ठभूमि सबसे महत्वपूर्ण बनी रही।

जर्मनी में 1931 के बाद बढ़ता हुआ हिटलर का प्रभाव इस बात की पूर्व-सूचना थी कि वार्सेली की संधि द्वारा स्थापित शांति अधिक दिन नहीं चलेगी। डौ योजना [Dawe's Plan] के अन्तर्गत जर्मनी अधिक दिन तक हर्जाना नहीं देगा और निकट

<sup>1</sup> Boris Souvarine Stalin. p. 598, and Louis Fisher : Men and Politics, pp 433-439

भविष्य में युद्ध से ससार न बच सकेगा। इन्ने स्तालिन की तीव्र बुद्धि ने देख लिया था। इसलिए द्वितीय योजना में युद्ध के उत्पादन और नैतिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया गया। इसकी सफलता द्वितीय विश्वयुद्ध [1939-46] में ससार के लिए वरदान बनी। एलेक्जेंडर प्रथम की तरह दूसरी बार रूसी शासक ससार की स्वतन्त्रता का आधार सिद्ध हुआ। नेपोलियन और हिटलर दोनों का मूर्त्य रूस में ही अस्त हुआ।

### उद्योग

उद्योग में द्वितीय योजना विशेष कार्यशील थी। नैतिक शक्ति के लिए औद्योगीकरण रूसी योजनाओं का केन्द्रीय सिद्धान्त रहा है, किन्तु इस योजना में औसत उत्पादन का कार्य-क्रम कुछ बढ़ा दिया गया था। जितनी वृद्धि प्रथम योजना में करने की कोशिश की गई, इसमें उनका आकार कम था। इसका अर्थ यह नहीं कि इस योजना में राष्ट्रोन्नति की इच्छा कम थी। काफी बड़ी मात्रा में साधन प्रथम योजना के अधूरे निर्माण-कार्यों को पूरा करने में लगाया गया। निर्माण-कार्य पर व्यय होने वाली धन-राशि का मुख्य भाग पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने में और प्रथम योजना के अधूरे काम को पूरा करने में लगा। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अनावश्यक दुहरा खर्चा और पेचीदा उत्पादन बच गया। प्रथम दो वर्षों में यह काम पूरा करने के बाद नये कारखानों की स्थापना आरम्भ की गई।

इस समय तक आते-आते योजनाकर्ताओं ने यह अनुभव किया कि स्तालिन की नयी नीतियों से देश के प्रत्येक अङ्ग पर राज्य का इतना पूर्ण अधिशासन हो गया है कि योजना प्रणाली में कुछ नये प्रयोग बिना हिचक किये जा सकते हैं। इस अनुभूति का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि लक्ष्य निर्धारण में पूँजी का महत्व घटा दिया गया। अभी तक आर्थिक साधन की उपलब्धि पर उत्पादन वृद्धि तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ निर्भर करती थी। किन्तु इस योजना में अर्थव्यवस्था से इच्छानुसार त्याग पा लेने पर इतना विश्वास हो गया था कि आर्थिक साधन अपनी प्राथमिकता खो बैठे। पूँजी को स्वामी से सेवक में परिणित करने में जो सफलता मिली, उसने पूँजीवाद की नींव [आर्थिक संचालन केवल पूँजी करती है] एक दम हिला दिया।

वस्तु उत्पादन का प्रमापीकरण [Standardisation] इस योजना में आकर उद्योग संगठन की एक विशेषता कही जा सकती है। यह निश्चित किया गया कि इसके द्वारा अधिकतर साधन तथा श्रम की वृत्त की जायगी। इस उद्देश्य से कुल चार प्रकार का ट्रैक्टर बनाया गया जब कि उस समय संयुक्त राज्य अमरीका में 80 प्रकार का ट्रैक्टर बनता था। 1924 में 2,600 प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता था। इसे काट कर 187 कर दिया गया। कुछ कारखानों में तो यह संख्या 500 से 42 तक पहुँची।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> M. Aronovitch Planned Economy, pp. 122-123



1937 तक औसत 4 प्रकार का मूल और 2 प्रकार का कपड़ा हर मिल बनायेगी।<sup>1</sup> व्यापक रूप से इसी तरीके को उत्पादन के साधन तथा उपयोग की वस्तुओं में प्रयोग किया गया।

दूसरी योजना का आधार देश की यात्रिक कुशलता की बड़े से बड़े पैमाने पर स्थापना और वृद्धि था। इसी की मदद से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया जा सकता था जिसके अंदर बड़े पैमाने पर मशीनों से उत्पादन हो और यह मशीनें आधुनिकतम यंत्र विज्ञान का नतीजा हो। जितने भी प्रशिक्षित व्यक्ति प्रथम योजना ने बनाये, उनकी शिक्षा तथा विचारों की सहायता ले कर, अर्थ-व्यवस्था को अमरीका और जर्मनी के स्तर पर लाने में, सोवियत सङ्घ ने काफी सफलता प्राप्त की। यात्रिक कुशलता के यह सफल प्रयास देश को तेजी के साथ उन्नति की ओर ले चले। इस योजना में 3,69,900 विशेषज्ञ शिक्षित किये गये। जबकि प्रथम योजना में यह संख्या 1,17,000 थी। 1928 में 1,000 मजदूरों पर 36 इंजीनियर थे। 1936 में औसत रूप से यह संख्या 82 हो गई। इसके साथ काम करने वाले मजदूरों को अपनी कुशलता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण के काम ने बहुत तेजी पकड़ी। 1933-1937 के बीच श्रमजीवी प्रशिक्षण विद्यालय [Worker's Training Schools] ने 14,00,000 कारीगरों को कुशल कारीगर बना दिया। इस प्रकार इंजीनियरों की संख्या 77 गुना बढ़ी, वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की 71 गुना और कृषि विशेषज्ञों की 5 गुना। कृषि क्षेत्र में भी इनको काफी महत्व दिया गया। लगभग 39,00,000 कुशल कारीगर तैयार हुए जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर कार्य संचालक, पशु विशेषज्ञ, मिट्टी वैज्ञानिक [soil scientists] सामुदायिक प्रबंधक तथा एकाउन्टेन्ट।

श्रमिक कुशलता और प्रति व्यक्ति उत्पादन की कृषि में दो मुख्य बातें हुईं। पहला तो स्तालिन का वह प्रसिद्ध नारा था जिसने औद्योगिक प्रबन्ध को एकदम बदल दिया। 'सब निर्णायकर्मचारी करें—[Personnel Decide Everything]। इसके अन्तर्गत औद्योगिक प्रबन्ध में राजनैतिक प्रभाव और सरकारी हस्तक्षेप कम करने का प्रयत्न किया गया। उद्देश्य यह था कि यदि कारखाना कर्मचारी ही मुख्य निर्णायक करेंगे तो उनमें कारखाना के प्रति अपनापन पैदा होगा। असफलता की पूरी जिम्मेदारी उन्हें स्वयं उठानी पड़ेगी। दूसरी विशेषता स्ताखनोव आन्दोलन [Stakhanov Movement] था। इसका आरम्भ 1935 में हुआ। यह आन्दोलन यात्रिक कुशलता और कार्य-प्रणाली के सुधार से प्रति व्यक्ति उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि करने में सफल हुआ। मजदूरों के बीच ही इसका आविष्कार हुआ और शायद इसी कारण इसका प्रचलन मजदूरों में इतनी तीव्रता से बढ़ा। कोयले की खान में काम करने वाले

<sup>1</sup> The Second Five Year Plan, p. 358

एक नवयुवक मजदूर, एलेक्सी स्लाखानोव, ने अपने काम में अपने ही ग्वांजे हुए नये तरीकों का प्रयोग किया। उसके उत्पादन ने सबको चकित कर दिया। नयी प्रणाली के अनुसार स्लाखानोव ने एक शिफ्ट में औसत 7 टन कोयला ग्वाने के स्थान पर 102 टन कोयला खोदा।

एक महीने के अन्दर इस नई प्रणाली को सुधार कर उसने अपना उत्पादन एक शिफ्ट में 227 टन कर दिया। राज्य के तत्वाधान में उसका अनुकरण देश के प्रत्येक उत्पादन-क्षेत्र में होने लगा। यह चमत्कारी उत्पादन वृद्धि तभी ने रूसी मजदूरों का एक अङ्ग बन गई। द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में ही स्लाखानोव आन्दोलन ने उत्पादन में 30.2% की वृद्धि हुई। इस आन्दोलन में मजदूर संचालन के विज्ञान में अनेकों नये अव्याय जुड़े। यह मान लिया गया कि अधिक उत्पादन के लिये मजदूर को सुशिक्षित, कुशल, अच्छे यंत्रों से सुसज्जित और सन्तुष्ट होना आवश्यक है। इतने पर भी यह देखा गया कि बिना किसी प्रकार के ठोस आर्थिक लाभ [material advantage] के उत्पादन बढ़ाना कठिन होता है। केवल समाजवादी प्रतिस्पर्धा [socialist competition] तथा सामाजिक प्रेरणा [social incentives] के द्वारा यह सम्भव नहीं। इसलिये इनके साथ-साथ आर्थिक पारितोषिक की व्यवस्था की गई है। दूसरी मुख्य प्रगति व्यक्तिगत प्रयास को अपना उचित महत्व देकर की गई। समाजवाद में व्यक्ति की जगह समाज और समूह को इतना ऊँचा स्थान दिया गया कि व्यक्ति को कोई जगह ही न मिल सकी। इस योजना में यह मानना पड़ा कि सामूहिक जाग्रति और संयुक्त प्रयत्न आवश्यक है किन्तु व्यक्तिगत प्रयत्न को हटाया नहीं जा सकता। अतः व्यक्तिगत प्रयत्न को सामाजिक उद्देश्यों के लिए उत्तेजित करने की नीति अपनाई गई। समान वेतन के पुराने सिद्धान्त को एकदम उठा दिया गया।

औद्योगिक क्षेत्र के विभागों में साधनों के बँटवारे की नीति में भी परिवर्तन हुआ। भारी उद्योगों का महत्व तो वैसा ही बना रहा परन्तु पहली बार उपभोग के उत्पादन को कुछ अधिक स्थान दिया गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपभोग की सामग्री का प्रकार [variety] बहुत कम कर दिया गया था परन्तु अपेक्षाकृत उनकी उत्पादन मात्रा बढ़ा दी गयी। ऐसा अनुमान है कि यह छूट आर्थिक कारणों से नहीं की गई। राजनैतिक शुद्धि [political purge] के कारण देश में गहरा असंतोष था। इसको शान्त करने के लिये ही यह छूट दी गई।

इस समय तक उत्पादन में गिरे हुए गुण [quality] की समस्या का हल करना अनिवार्य हो गया। बढ़ते हुए औद्योगीकरण में निम्न कोटि का उत्पादन बहुत रूकावट पैदा कर रहा था। मशीनों का घिस जाना या पुर्जों का अच्छी तरह न

आना रोजाना की बातें बन गई थीं। जब और सभी उपाय असफल सिद्ध हुए तो कानून का सहारा लिया गया। 1940 में वस्तुओं के गुण [quality] सुधारने के प्रयत्न में कमी करना, या रुकावट डालना या पूरी कोशिश न करना फौजदारी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया।<sup>1</sup>

इस योजना की सफल पूर्ति अर्थशास्त्रियों में विवाद का विषय है। धातु तथा असल उद्योगों में तो लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ किन्तु हलके उद्योग [खास कर कपड़ा] काफी पीछे रहा। पहले योजना की तरह, इसमें भी उद्देश्यों की संचालित पूर्ति [directed fulfilment of targets] की गई, यह विश्वास सर्वथा निर्मूल नहीं है।

### कृषि

इस योजना में कृषि-क्षेत्र के नये सोवियत सगठन को और गुष्ट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गये। इनका उद्देश्य यह था कि कृषक वर्ग अपना उत्तर-दायित्व समझे और मन लगाकर उत्पादन में सहयोग दे। तीव्र गति से होने वाले सामुदायिक कृषि की प्रगति ने किसानों का सन्तुलन बिगाड़ दिया था। उसकी पुनर्स्थापना राज्य की सफल उन्नति के लिए अनिवार्य बन गयी। “सफलता का उन्माद” [Dizzy with Success] में जो ताड़ना जनता को दी गयी उसका बहुत बड़ा असर न हो सका। इस समय तक आते-आते यह आवश्यक हो गया कि कुछ ऐसे व्यवहारिक सुधार किये जायें जो किसानों को लाभपूर्ण मालूम पड़ें। 1935 में उत्पादन में इतना सुधार हो चुका था कि समाज की अनेकों कमजोरियों की जड़—राशनिंग—को उठा दिया गया। इस सकटकालीन व्यवस्था के समाप्त होने से कृषक वर्ग में नयी आशाएँ उत्पन्न हुईं।

सहानुभूति, कृषि सगठन में एकरूपता तथा समान नियन्त्रण लाने के लिए फरवरी 1935 में कृषि आर्टेल के आदर्श नियम [Model Rules of the Agricultural Artel] बनाये गये। इन नियमों को स्तालिन की महानता का एक प्रतीक माना जाता है। इसके अन्तर्गत कृषि पद्धति, भूमि, उत्पादन का षट्पद्वारा, प्रवन्ध, सदस्यता, कोष तथा श्रमिक अनुशासन इत्यादि सभी अंगों के लिए नियम बनाये गये जिसके आधार पर देश की सामुदायिक खेती को संगठित किया जा सके।<sup>2</sup> इन नियमों ने किसानों में आलस्य और गैरजिम्मेदारी, मन लगाकर काम न करना, इत्यादि वृत्तियों को दूर करने में बहुत मदद किया। सभी तरफ से यह प्रयत्न हो रहा था कि किसानों को

<sup>1</sup> Yugow A. Russia's Economic Front for War and Peace, p. 23

<sup>2</sup> Turin, S. P. : The U. S. S. R., pp. 175-189

अपना स्वतन्त्र तथा पृथक् रूप से काम करने का तरीका छोड़ने के लिए बाध्य किया जाय जिससे कि उन्हें एक औद्योगिक मजदूर की तरह कठोर अनुशासन में बाँधा जा सके। मजदूरों और किसानों को एक स्तर पर लाकर तथा एक ही प्रकार के संगठन में रखकर उनको आपसी सहयोग, असन्तुष्टि व प्रतिद्वन्द्विता से बचाया जा सकता था। इतना ही नहीं उनको एक ही प्रकार के प्रोत्साहन से उत्तेजित करके अधिकतम उत्पादन सम्भाव्य था। उदाहरण के लिए सामुदायिक फार्म में वेतन निर्धारित करते समय कुशलता को नहत्व देना, काम के अनुसार भुगतान [Piece wage] और मजदूरों की तरह जितने दिन काम किया है उतना वेतन प्राप्त होगा। इसका किसान पर बहुत अच्छा असर पड़ा। उनके सभी विशेषाधिकार उत्तरदायित्व पर आधारित हो गये।

अनाज वमूली [Procurement] प्रणाली के मुद्धार बड़े प्रभावशाली थे। पहले इसमें कोई निश्चित नियमावली न होने से किसान के उत्साह पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। इस समय केवल इनकी मात्रा ही नहीं निर्धारित की गयी बल्कि इसको प्रति एकड़ उत्पादन का एक पूर्व निश्चित अंश बना दिया गया। इससे किसानों को अधिक उत्पादन करने में कोई रुकावट न रही। उनको तथा राज्य को यह पहले से मालूम रहता था कि कितना अनाज लिया या दिया जायगा।

कुलक वर्ग के उन्मूलन का कार्य अविराम चलता रहा। व्यक्तिगत किसानों के ऊपर आर्थिक दबाव तथा पक्षपात के बोझ में वृद्धि होती रही। इसका सबसे प्रचलित रूप राज्य-करो में पक्षपात था। व्यक्तिगत किसान सामुदायिक खेतों के किसान से 5 से 10 प्रतिशत अधिक कर देते थे। अनेको सुविधाएँ इनको नहीं मिलती थीं। खुले बाजार में अनाज बेच सकने की स्वतन्त्रता से किसानों को बहुत सन्तुष्टि मिली। राज्य को भुगतान करने के बाद जितना अनाज बचे उसे बाजार भाव पर बेचा जा सकता था। इसके साथ शीघ्र ही इस श्रेणी के विक्रय किसानों की आय का महत्वपूर्ण अंग बन गये। इस व्यवस्था से राशनिंग और अन्न वितरण की समस्या सदा के लिए हल हो गयी। अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने के पहले अपनी उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति किसान इसी में से कर लेते थे।

1935 से कृषि-क्षेत्र में व्यक्तिगत सम्पत्ति को दुबारा स्थापित किया गया। अपने नियन्त्रित रूप में व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुविधा एक हानिरहित किन्तु प्रबल प्रोत्साहन सिद्ध हुई। 1933 में स्टालिन के विख्यात नारे का जन्म हुआ—“समस्त सामुदायिक किसानों को समृद्ध बनाओ” [Make all collective farmers prosperous] स्टालिन का तर्क यह था कि पहले किसान दूसरों की मेहनत से, बेईमानी से तथा पड़ोसियों के शोषण से समृद्ध बनने का प्रयत्न करते थे जिससे कि वे पूँजीवादी अथवा कुलक बन सके। किन्तु नई सोवियत प्रणाली में सामुदायिक किसान यह सब न करके केवल ईमान-

दारी और नेहनत के साथ अपना काम करता है। अतः सामुदायिक किसानों को समृद्ध-शाली किसान बनने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। स्टालिन के विचार से पुरानी और नयी कृषि व्यवस्था में केवल इतना अन्तर था कि पहले किसान भूस्वामी से शोषित होकर, उसके जमीन पर, खेती करता था किन्तु अब अपने लिए हितकर सामुदायिक फार्म की भूमि पर काम करता है। इसलिए इसको सम्पन्न बनने का और सुविधाएँ प्राप्त करने का निश्चित अधिकार है। इस नयी विचारधारा के अन्तर्गत पशु को व्यक्तिगत सम्पत्ति की तरह रखने का अधिकार मिला। एक छोटा-सा खेत भी व्यक्तिगत रूप में दिया गया जिस पर किसान अपनी आवश्यकताओं की वस्तु उत्पन्न कर सके, जैसे, मधुमक्खी, चिड़ियाँ, पशुपालन, फल इत्यादि। इसी समय से किसानों को अपना खोया हुआ व्यक्तित्व कुछ अंशों में दुबारा मिल गया।

कृषि क्षेत्र में सैद्धान्तिक प्रचार का विस्तार किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य कोलखोज किसान थे जिनके विचारों को अत्यन्त वैज्ञानिक रूप से सोवियत सिद्धान्तों के आधार पर ढालने की चेष्टा हुई। कुप्रबन्ध, सुस्ती, असहयोग और बेईमानी को दूर करने में राज्य ने अपना प्रभाव प्रत्येक कोलखोज तक फैला लिया। इसके कई उपाय अपनाये गये। मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन की मदद बिना कोलखोज का सफल होना असम्भव था। इस यांत्रिक मदद का परिमाण और मूल्य के साथ कुछ शर्तें लगायी गयीं जिससे इन्हे पाने के लिए हर दिशा में सफल और उन्नतिशील बनना आवश्यक हो गया। उधार आर्थिक सहायता देकर सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप से सन्तोपजनक कोलखोज को पुरस्कृत किया जाता था। इन सब का प्रभाव अत्यन्त स्वास्थ्यकर सिद्ध हुआ। सोवियत व्यवस्था में पहली बार किसान ने शान्ति और सन्तोष अनुभव किया। उत्पादन का इससे प्रभावित होना अनिवार्य था। इन्हीं कारणों से 1935 में राशनिंग समाप्त की जा सकी।

**तृतीय पंचवर्षीय योजना : [1938-1942]**

1928 में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो कार्य आरम्भ हुआ उसे तृतीय योजना बहुत बड़े आकार पर बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। इसका दृष्टिकोण अत्यन्त साहसपूर्ण तथा व्यापक था। राष्ट्र का संयोजित विकास में अनुभव और साधन निरन्तर बढ़ रहा था। इसी से स्टालिन के कठोर अंकुश से संचालित राष्ट्र अपनी सम्पूर्ण शक्ति से गतिशील बना। नींव की तैयारी प्रथम दो योजनाओं ने कर दिया था। अतः मोलोटोव ने तृतीय योजना के उद्देश्य की घोषणा की : यह योजना समाजवाद को साम्यवाद में बदल देगी।<sup>1</sup> इसका एक और उद्देश्य था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं समाज कल्याण

<sup>1</sup> Molotov Third Five Year Plan, [1939] p. 5

का स्तर उठाना। यातायात पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि इस समय तक यह क्षेत्र विकास के मार्ग से सबसे बड़ी स्कावट बन रहा था। इस स्कावट को कम करने के लिए औद्योगिक स्थानीयकरण [Localization] का विशेष ध्यान रखना पड़ा। उद्योगों को कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट, और जहाँ तक सम्भव हो, उपयोग के क्षेत्रों के समीप स्थापित करना आवश्यक बना। इससे यातायात पर दबाव काफी कम हो गया। संसार की बिगड़ती हुई राजनैतिक स्थिति ने भी इस योजना को प्रभावित किया। इसी कारण सुरक्षा तथा सशस्त्र उद्योग [Armament Industry] विकास का केंद्र बन गये। इस क्षेत्र में उच्चतम गुण का स्तर [qualitative level] प्राप्त करने की कोशिश की गई। 1939 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ने के साथ सुरक्षा पर राजकीय व्यय कुल साधनों के  $\frac{1}{3}$  में बढ़ा कर 1940 में  $\frac{2}{3}$  कर दिया गया।

1939 के मूल्य पर आकारित अनुमान के अनुसार इस योजना पर 192 मिलियर्ड [एक मिलियर्ड = हजार मिलियन] रूबल का व्यय पूँजी के क्षेत्र में रक्खा गया। इसमें से 1119 मिलियर्ड रूबल उद्योग पर खर्च होने वाला था। यह धन द्वितीय योजना का लगभग दूना था। इसमें 37 मिलियर्ड रूबल यातायात का भी सम्मिलित है।<sup>1</sup> औद्योगिक उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि का प्रयत्न हुआ।

उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि<sup>2</sup>

1942 [1937 के प्रतिशत में]

पूँजी के सामान	207
उपयोग के सामान	172
रसायन उद्योग	237
मशीन निर्माण	229
विद्युत् शक्ति	206
अल्पमिनियम	346
टिन के योजन	206

लेकिन औद्योगिक उत्पादन की प्रतिवर्ष वृद्धि में कमी हुई। यह 12.4% प्रतिवर्ष रक्खी गई। भारी उद्योगों की प्राथमिकता पूर्वतः बनी रही। श्रमिक उत्पादन बढ़ाना द्वितीय योजना ने बहुत जरूरी समझा। “समाजवादी प्रतिस्पर्धा [Socialist Com-

<sup>1</sup> Ibid, p 28

<sup>2</sup> Baykov Op Cit, p 289

petition] उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में फैला। इसके अतिरिक्त राज्य की ओर से अत्यन्त आकर्षित आर्थिक पारितोषिक देने की नीति अपनाई गई। उस आर्थिक प्रोत्साहन का विधान इस प्रकार बना था कि जिस किसी कारखाने में आशा से अधिक उत्पादन हो वहाँ से सम्बन्धित राजनैतिक नेता, प्रबन्धक तथा मजदूर सभी को उदार अर्थ-लाभ होता था। नेताओं की प्रेरणा, प्रबन्धकों का कौशल एवं मजदूरों का परिश्रम वैज्ञानिकों से सहायता पकर श्रम-उत्पादकता [Labour Productivity] को ऊपर उठाने में सफल हुआ। इसमें लगभग 65% की वृद्धि तृतीय योजना ने किया। औद्योगिक उत्पादन में 88.5 मिलियर्ड रूबल की वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि का 70% अथवा 62 मिलियर्ड रूबल श्रम उत्पादन बढ़ने से प्राप्त हुआ। इसके विपरीत उत्पादन के मूल्य में कमी 5 वर्षों में केवल 10% ही की जा सकी। अतः यह देखा गया कि इस योजना-काल में श्रमिकों को हर प्रकार की उत्तेजना, सुविधा और उत्साह दे कर उत्पादकता बढ़ाने का ऐसा आन्दोलन चला जिससे कोई भी प्रभावित हुए बिना न रह पाया।

अच्छे किस्म के उत्पादन करने का प्रयत्न बराबर होता रहा किन्तु इससे आशा तीव्र सफलता न मिल सकी। गौसप्लान के समापति एन० वोझनेसेन्स्की [N Voznesensky] के अनुसार सुरक्षा उद्योगों को छोड़कर दूसरे सभी क्षेत्रों में अच्छे गुणयुक्त माल नहीं बन पा रहे थे।<sup>1</sup> इसमें सुधार करने के लिए जब सीधे उपाय सफल न हुए तो वैधानिक दबाव का सहारा लिया गया। 1940 के कानून द्वारा खराब किस्म के माल बनाने की जिम्मेदारी सिद्ध हो जाने पर 5 से 8 वर्षों तक का कठोर कारावास दिया जा सकता था।

द्वितीय योजना के अन्तिम चरण में और तृतीय योजना के आरम्भ से ही कारखानों के आर्थिक आत्म-निर्भरता पर बहुत जोर दिया गया। मौद्रिक मूल्यांकन, व्यवस्थित लेखा, और लाभपूर्ण उत्पादन की मदद से यह उद्देश्य बनाया गया कि प्रत्येक कारखाना आर्थिक आवश्यकताओं को बिना-राजकीय सहायता के पूरा कर ले। इससे राज्य पर दबाव और कारखाना प्रबन्ध में लापरवाही दोनों पर नियंत्रण हो गया। उत्पादन लागत और [राज्य-निर्धारित] मूल्य के अन्तर से होनेवाली हानि को राज्य भर करता था। यही कारण था कि किसी भी कारखाने को प्रबन्ध में बचत करना और लागत में कमी करने का कोई प्रभावशाली तर्क सम्भव में न आता था। लागत कम हो रही थी, व्यापारिक प्रणाली पर उत्पादन के प्रत्येक अंग का लेखा रखना पुनः आरम्भ किया गया जिससे लागत और मूल्य बराबर किया जा सके; श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि ने भी बहुत

<sup>1</sup> N Voznesensky Economic Results of USSR and the Plan of National Economic Development for 1941, pp 11-12

महायुता किया। कारखानों को आर्थिक स्वतन्त्रता देकर राज्य का भार कम करने के लिए संचित लाभ [reserved profit] की मात्रा असाधारण रूप से बढ़ाई गई। कुछ ही नमय में औद्योगिक पूँजी का यह प्रमुख भाग बन गया। इसके साथ साथ केन्द्रीय संचालन में एक उद्योग के कारखानों में आपसी विनियोग [inter-investment] की प्रथा को खूब प्रोत्साहन दिया गया। दृढ़ और सम्पन्न कारखाने उसी उद्योग के कम-जोर कारखानों को आर्थिक सहायता देकर संभालते रहते थे। पूँजीवादी संगठन की यह भयङ्कर कुप्रथा ने एकाधिकार और उपभोक्ताओं के शोषण को जन्म दिया। किन्तु रूस ने इस विकार को औपधि बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को आन्तरिक बल और दृढ़ता प्रदान किया।

राजकीय नियन्त्रण जब सर्वव्यापी रूप में स्थापित किया गया तो उसके शासन के लिये अफसरशाही [Bureaucracy] का ऐसा जटिल आडम्बर बना कि औद्योगिक सङ्गठन में तत्कालिक निर्णय [Quick decision] और उत्तरदायित्व [Responsibility] अत्यन्त कठिन हो गया। तृतीय योजनाकाल में सङ्गठन सुधार पर विशेष ध्यान देकर दोहरे काम और पेचीदी प्रणाली को बहुत कुछ कम किया गया किन्तु अलग-अलग विभागों में सन्तुलन तथा सम्पर्क [Balance and Co-ordination] की समस्या हल न हो सकी। 1939 में विश्व युद्ध छिड़ गया। कुछ ही समय बाद रूस भी सम्मिलित होने के लिये बाध्य हुआ। प्रभाव यह पड़ा कि यह योजना अपूर्ण ही छोड़ दी गयी। 1941 से रूस लड़ाई में उनका और देश सम्पूर्ण शक्ति से हिटलर का प्रभुत्व तोड़ने में जुट गया। युद्ध का विनाश, जनहानि और अव्यवस्था ने रूसी प्रगति में बाधा उत्पन्न किया, प्रगति भी कम कर दिया किन्तु उन्नति के लिये अत्यन्त शक्तिशाली प्रेरणाओं को जन्म देकर भविष्य के विकास का आकार बहुत ही बड़ा दिया।

इस प्रकार तृतीय योजना लगभग 3½ साल तक चली। किन्तु इतने समय में सांख्यिक उद्योग ने अचूक प्रगति दिखाई। औद्योगिक उत्पादन की प्रतिवर्ष वृद्धि 13% थी। भारी उद्योगों में विशेष उन्नति हुई। योजना की दूरदर्शिता के फलस्वरूप देश के पूर्वी भाग का इन तीन वर्षों में विशेष औद्योगीकरण हुआ। यूराल, वोल्गा क्षेत्र, साइबेरिया, मध्य एशिया और कजाखस्तान का औद्योगिक उत्पादन 3 साल में लगभग 50% बढ़ा। खेती के क्षेत्र में अन्न उत्पादन 1940 से 119 मिलियन टन पहुँचा था। दक्षिणी-पूर्वी प्रदेशों में विज्ञान की सहायता से अपूर्व अन्न उत्पादन की शक्ति पैदा की गई। सानुदायिक खेती कृषि पर अपना लगभग पूर्णरूपेण प्रभाव जमा चुकी थी। पूँजी-निर्माण कार्य [Capital Construction Programme] में 130 मिलियन रूबल का काम हुआ। इसका एक-तिहाई खर्च देश के पूर्वी भाग को विकसित करने में किया गया। इसके अन्तर्गत लगभग 3,000 राजकीय मिल-कारखाने, त्रिजली-



घर तथा दूसरे उद्योगों ने उत्पादन आरम्भ किया। पूर्वोक्त क्षेत्रों के विकास का महत्व सकट आने के पहले समझ लेने से रुस ने ससार का इतिहास ही बदल दिया। युद्ध आरम्भ होने के बाद आश्चर्यजनक शीघ्रता से उद्योगों को युद्धकालीन उत्पादन में लगाया गया। हिटलर के आक्रमण के बाद केवल एक वर्ष में लगभग एक हजार तीन सौ बड़े कारखाने [मोटर, हवाई जहाज, रेलवे इंजन आदि] बढ़ती हुई जर्मन सेनाओं के सामने में उखाड़कर एक हजार मील पूर्व में पुनर्स्थापित कर दिए गए। ससार के साहसपूर्ण कर्मठ पुरुषों का ऐसा दूसरा उदाहरण कभी सामने नहीं आया।

द्वितीय विश्व युद्ध ने रूसी अर्थव्यवस्था पर भयंकर दबाव डाला। विशाल और सुसज्जित जर्मन सेनाएँ वगडर की तरह रुस पर छा गईं। अठम्य साहस तथा अपूर्व सहनशक्ति से देश ने इनका सामना किया। आधुनिक स्तर पर पूर्ण विकसित न होने से मशीनों की कमी मैनिफेक्चर तथा नागरिकों के बलिदान से पूर्ण की गई। इसका निश्चित आँकड़ा तो प्राप्त नहीं है फिर भी विभिन्न अनुमानों के अनुसार सब मित्रराष्ट्रों से अधिक रूसी ही युद्ध में काम आये। लगभग 125 से 150 लाख व्यक्ति तक मारे गए।

औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र देश के हाथों से निकल गए। युद्ध के प्रथम दो वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 25% से अधिक और कृषि उत्पादन में लगभग 40% की कमी हुई।

जनता और साधन की इतनी विशाल हानि उठा कर भी देश की प्रगति का प्रयास निरन्तर चलता रहा। युद्ध की समाप्ति होने भी न पाई थी कि स्तालिन ने चौथी पंचवर्षीय योजना को घोषणा की। इससे स्पष्ट है कि युद्ध के घोर सकटकाल में आत्म-विश्वास एवं आगावादिता ने रूसियों का साथ नहीं छोड़ा।

#### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—[1946-1950]

इस योजना का केवल सक्षिप्त प्रकरण ही प्रकाशित किया गया। इसके तीन उद्देश्य थे : (1) युद्धकालीन विध्वंस का पुनर्निर्माण, (2) 1939-40 का उत्पादन-स्तर कृषि तथा उद्योग में फिर से प्राप्त करना और (3) जहाँ तक सम्भव हो इसके आगे बढ़ना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में देश की संपूर्ण शक्ति जुट पड़ी। भारी उद्योग, रेल यातायात, को प्राथमिकता दी गई। लगभग 40 हजार मील लम्बी रेलवे लाइन नष्ट कर दी गई थी जिससे कमजोर यातायात व्यवस्था प्रायः बेकार हो गई। योजना ने इस कमी को पूरा करने का निश्चय किया। 6,000 भाप इंजिन, 550 बिजली इंजिन और 850 डीजल इंजिन के साथ 4½ लाख मालगाडी के और 6 लाख यात्री डिब्बे बनाने का प्रयत्न हुआ। रेल के पूँजी निर्माण पर 40 मिलियर्ड रूबल खर्चा गया। अन्तर्देशीय जल-यातायात में 1950 तक 38% उन्नति का विचार था जिसके लिए नदियों की सफाई

बन्दरगाह और जहाज बनाने के 5 कारखाने स्थापित हुए। इसी प्रकार व्यापारी समुद्री बेटा में भी दोगुने से अधिक विस्तार हुआ।

उद्योग के क्षेत्र में 1950 तक आशा की जाती थी कि 1940 से उत्पादन 48% बढ़ जायगा। 1945 के मूल्य में अनुमानित आँकड़ों के अनुसार 1940-50 के बीच उद्योगों में पूँजी निर्माण कार्य लगभग 157 मिलियर्ड रूबल निश्चित किया गया। लोहा और स्पात उद्योग पर ही पुनर्निर्माण की सारी योजनाएँ निर्भर करती थी। उस योजना ने 1940 से 35% अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न किया। 45 न्यात भट्टियाँ [Blast Furnaces], 165 खुली भट्टियाँ [open hearth furnaces] 15 कनवर्टर और 90 विजली की भट्टियाँ बनाई गईं। इन सब का उत्पादन 16 मिलियन टन से अधिक न्यात था। कोयले में 51% वृद्धि आवश्यक समझी गई। दक्षिण-पूर्व में नई कोयले की खानों का पता चला। टन सब का प्रभाव यह था कि 1946-50 के बीच 183 मिलियन टन काँचला पैदा करने वाली खानें उत्पादन में लगीं। पेट्रोल का महत्व युद्ध ने इतना अधिक बढ़ा दिया कि किसी भी मूल्य पर इसके अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित हुआ। विद्युत उत्पादन में भी 1940 से 70% अधिक उत्पादन निश्चित किया गया। मशीन निर्माण उद्योग के प्रत्येक अङ्ग में दूने से अधिक उत्पादन का लक्ष्य था। इसमें प्रायः हर प्रकार के यंत्र सम्मिलित थे। रसायन-उद्योग, युद्ध के पहले से 50% अधिक ऊँचा रखा गया। कपड़ा तथा अन्य हल्के उद्योगों पर, ऊपर की श्रेणी से बचे हुए साधन खर्च करने की व्यवस्था थी। इसी कारण जनता के न्याग की मात्रा में उस योजना के अन्तर्गत कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

कृषि के क्षेत्र में युद्ध की हानि बहुत अधिक थी। लगभग 10 लाख सामुदायिक फार्म, 15 लाख ट्रैक्टर तथा 50 हजार हारवेस्टर कम्बाइन मशीनें नष्ट हो गईं। 8 लाख वर्ग मील भूमि जर्मनी के कब्जे में चले जाने से रूसी कृषि द्रुत गई। इतने बड़े नुकसान को फिर से पूरा करके 27% वृद्धि की योजना बनाई गई। औद्योगिक फसले एवं पशु-धन को बढ़ाने में सङ्कार पूरी तरह क्रियाशील बनी। युद्धकाल में भोजन की कमी, दुश्मन का डर और जर्मन सिपाहियों की लापरवाही से रूस में दूसरी बार पशुओं की संख्या बहुत अधिक घट गई। इसमें कुछ तो भोजन के काम आए किन्तु अधिकतर किसानों ने शत्रु से बचाने के लिए स्वयं नष्ट कर दिया अथवा बीमारी और भूख से मर गए। कृषि-क्षेत्र के विभिन्न अङ्गों को पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 20 मिलियर्ड रूबल खर्च हुआ। इसमें आधे से अधिक मशीनें और ट्रैक्टर केन्द्र पर खर्च किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युद्ध के अपार विनाश से 1950 तक देश ऊपर उठ चुका था। इस योजना ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति सदा की तरह अपने समय से पहले किया। इतने बड़े

निर्माण कार्य की पूर्ति के लिए विज्ञान और यान्त्रिक कुशलता के विकास पर पूरा जोर देना पड़ा। इस योजना की पूर्ति के आँकड़े इस प्रकार हैं।<sup>1</sup>

	1940	1950	
		योजना लक्ष्य	वास्तविक पूर्ति
1 1926-27 के मूल्य पर राष्ट्रीय आय	100	138	164
2. मजदूर तथा कर्मचारी	100	—	126
3. औद्योगिक उत्पादन	100	148	173
4. रेल-यातायात	100	128	146
5 विद्युत-उत्पादन	100	170	189

#### पंचम पंचवर्षीय योजना : 1950-1955

ऐसा प्रतीत होता है कि रूसी अर्थशास्त्री प्रयत्न कर रहे थे कि देश में विकास की गति इतनी अधिक रखी जाय कि 10 या 15 सालों में कुल उतनी उन्नति हो जाय जितनी विश्व युद्ध न होने पर होती। दीर्घकालीन योजना में इस प्रकार की रूचि रूस की विशेषता रही है। वहाँ के अर्थशास्त्री देश का विकास योजनाओं की सहायता से नापते हैं। पाँचवी योजना भी कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने नक्शे का एक क्रम रही। नारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना और अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक अङ्ग को इसी दृष्टिकोण से विकसित करना इस योजना का ध्येय था। यान्त्रिक प्रगति [Technical Progress] और श्रम-उत्पादकता में वृद्धि उस समय तक अर्थहीन बनी रहेगी जब तक कि उत्पादन करने वाले साधनों का उत्पादन उपभोग की वस्तुओं से अधिक न हो। यही योजनाओं की विचारधारा का मुख्य क्रम था।

पंचम योजना औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष 12% अथवा 5 वर्षों में 72% वृद्धि करने का अनुमान करती थी। 1951-55 में 85% वृद्धि हुई। पूँजी के साधन [Capital Goods] का वार्षिक विकास 13% अथवा 5 वर्षों में 80% रखा गया

<sup>1</sup> Strumilin Planning in the Soviet Union, p 52

था, परन्तु विशेष प्रयत्नों द्वारा यह 91% हुआ। इसके विपरीत उपभोग सामग्री का उत्पादन अनुमानित 11% अथवा 5 वर्षों में 65% की जगह वास्तविकता में 76% रहा। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि युद्ध के बाद में उत्पादन तथा उपभोग की सामग्री में विकास की मात्रा समानता की ओर बढ़ रही थी। युद्ध के पहले सुरक्षा पर अत्यधिक महत्व होने से यह सम्भव न हो सका था। अतः यह कहना उचित न होगा कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी कमी तथा त्याग [austerity and sacrifice] रूसी योजना का मुख्य अङ्ग बना रहा। इस समय उपभोग के औद्योगिक सामान पहले में लगभग दूने की मात्रा में बनाये जा रहे थे। पार्टी अधिवेशन में खुशचेव ने बतलाया कि इस समय तक भारी उद्योग आशातीत रूप से इतनी उन्नति कर चुके हैं कि आसानी के साथ जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव है। इस उन्नति का उचित तरीके से समझने के लिये तुलनात्मक अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा। विकास की यह गति पूँजीवादी देशों के विकास से लगभग 50% अधिक थी। 1950-55 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास की गति से यह दूनी थी।

#### औद्योगिक उत्पादन [1929 का प्रतिशत]<sup>1</sup>

देश	1927	1937	1946	1950	1955
सोवियत रूस	100	429	466	1,082	2,049
संयुक्त राज्य अमेरिका	100	103	153	190	234
ब्रिटेन	100	124	118	153	181
फ्रांस	100	82	63	92	125
पूँजीवादी देश	100	104	107	148	192

इस प्रकार सोवियत रूस की प्रगति पूँजीवादी देशों से लगभग 11 गुना अधिक है।

औद्योगिक प्रगति का सबसे अच्छा माप-दण्ड अर्थ-व्यवस्था में पूँजी का विनियोग होता है। पंचम योजना में इसकी मात्रा 686.7 मिलियर्ड रूबल थी। यह विनियोग प्रथम योजना के 10 गुने से भी अधिक था। इस विशाल योजना को लगभग 4 वर्ष 4 महीने में ही पूरा कर लिया गया। इसकी सफलता का अनुमान इन आँकड़ों से लगता है।

<sup>1</sup> Report to the 20th Congress of Communist Party, 1956 p -

1955 में पूर्ति<sup>1</sup>

	1950	योजना	वास्तविक पूर्ति
1. राष्ट्रीय आय	100	160	168
2. रोजगार	100	115	120
3. औद्योगिक उत्पादन	100	117	185
4. भारी उद्योग	100	180	191
5. अन्य उद्योग	100	165	176
6. विद्युत-शक्ति	100	180	187
7. श्रम उत्पादकता—			
उद्योग	100	150	144
निर्माण में	100	155	145
कृषि में	100	140	147

सबसे अधिक विकास इर्झानियरिझ उद्योग में हुआ। 120% की वृद्धि प्राप्त करना सचमुच आश्चर्य की बात थी। तेल का उत्पादन 80%, कच्चा लोहा 74%, और कोयला 50% बढ़ा। इस योजना के प्रथम भाग में कृषि-क्षेत्र में फिर से असंतुलन दिखाई पड़ने लगा। स्टालिन की मृत्यु के बाद कृषि का विकास और उपयोग के उद्योगों का महत्व राज्य-शक्ति के भंगड़े में सबसे बड़ा बहाना बनाया गया। इसमें सदेह नहीं कि कृषि उत्पादन 1953 तक नाममात्र की ही प्रगति कर पाया था। किन्तु इसके बाद कृषि-क्षेत्र पर पूरा ध्यान केन्द्रित होने से 100% से अधिक वृद्धि हुई। 1954-55 में कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 लाख 50 हजार नवयुवकों को बजर भूमि को खेती योग्य बनाने के कार्य पर लगाया। 2 लाख ट्रैक्टर की मदद से 33 मिलियन हेक्टर भूमि 2 सालों में खेती योग्य बन गई। 1955 में अन्न उत्पादन 1950 से 129% बढ़ा। औद्योगिक फसलों में भी अच्छी वृद्धि हुई। पशु-पालन में सुधार से गायों की संख्या 20%, भेड़ 32% और सूअर 83% बढ़े।

पंचम योजना में योजना पद्धति को और पुष्ट बनाने के प्रयत्न किये गये। आर्थिक निर्णय के विकेन्द्रीकरण के लिये ठोस कदम उठाए गये। केन्द्र के स्थान पर प्रजातंत्रों को [Union Republics] को आर्थिक निर्माण का भार मिला। इसके द्वारा अलग-अलग संस्थाओं का कार्य-क्षेत्र बढ़ाया गया जिससे अधिक केन्द्रीयकरण की कमजोरियाँ दूर हो सकें। शासन और औद्योगिक प्रबन्ध को सरल बनाने का काम चलता

<sup>1</sup> Stumiln Op Cit, p. 54

रहा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद योरोप के अनेकों देशों का रूसी प्रभाव-क्षेत्र में आना बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। साधनों में वृद्धि के साथ अधिकार क्षेत्र और बाजार बढ़ जाने से रूस की योजनाओं का दृष्टिकोण और भी व्यापक बनने में सफल हुआ। पंचम योजना तथा उसके बाद के प्रयत्न इसी कारण अपना आकार बरसभर बढ़ाते रहे।

### छठवीं पंचवर्षीय योजना [1956-60]

कम्युनिस्ट पार्टी का एक ऐतिहासिक अधिवेशन फरवरी 1956 में हुआ। इस अधिवेशन में नये रूसी शासन ने अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निश्चय किया। जोसेफ स्तालिन की मृत्यु के बाद इस अधिवेशन ने आर्थिक ढाँचे को पुनर्संगठित करके नई दिशा की ओर मोड़ना चाहा था। अनेक सैद्धान्तिक परिवर्तनों के साथ-साथ छठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप भी स्वीकार किया गया। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह योजना स्तालिन की परिपटी पर तैयार की गई थी और नये नेताओं ने अपने नये जोश में इसके उद्देश्यों पर शुरू में ध्यान नहीं दिया। इसीलिये आरम्भ होने के साथ ही साथ इस योजना के अव्यावहारिक लक्ष्यों को बदलने की जरूरत पड़ी। इसका प्रथम संशोधन 1957 में हुआ और 1958 में इसे स्थगित कर दिया गया।

इस योजना की विशेष बातों पर संक्षेप में ध्यान देना उचित होगा। उद्योग-धन्यों में स्वयंचालित यंत्रों [Automation] का प्रयोग बढ़ाकर यह कोशिश की गई कि आधुनिक विज्ञान का पूरा लाभ उठाया जाय। कृषि संगठन तथा उत्पादन को बहुत ऊँचा स्थान मिला। अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये हर प्रकार की चेष्टा की गई थी। अन्य क्षेत्रों में, उद्योग को सदा की तरह महत्व दिया गया। यह आशा थी कि औद्योगिक उत्पादन में 13% उन्नति होगी। निकिता ख्रुश्चेव ने रूसी इतिहास में पहली बार उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह समय आ गया है कि रूस के पास बहुत शक्तिशाली भारी उद्योग स्थापित हो चुके हैं। इसलिये यह सम्भव है कि उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जाय। 1955-60 के लिये उत्पादन की वस्तुओं में 70% और उपभोग की वस्तुओं में 60% वृद्धि करना तय हुआ। पहले कर्मों भी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था।

यह योजना कितनी अव्यावहारिक थी इसका अनुमान निर्धारित लक्ष्य [Targets] तथा उनकी पूर्ति से नता चलता है।

औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि [प्रतिशत में]<sup>1</sup>

	छठवी योजना वार्षिक लक्ष्य	1957-1958 में पूर्ति	सातवी योजना के वार्षिक लक्ष्य
कोयला	8.6	2.8	2.8 से 3.2
पेट्रोल	13.6	9.4	10.7 से 11.4
गैस	31.0	19.6	25.4 से
विजली	13.5	9.7	11.5 से 12.2
कच्चा लोहा	10.0	5.3	7.4 से 8.5
स्वात	8.5	5.3	6.6 से 7.3
सीमेंट	19.5	8.6	12.1 से 13.3
चीनी	14.0	5.1	8.7 से 9.9
ऊनी कपड़ा	7.7	5.2	7.6
चमड़े के जूते	8.7	4.9	5.5

इतना ही नहीं, इस तालिका से यह भी स्पष्ट है कि योजनाकर्ताओं ने छठवी योजना की असफलता से शिक्षा ग्रहण किया। सातवी योजना के लक्ष्य सब जगह कम तथा व्यवहारिक मालूम पड़ते हैं। यह विचारधारा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायगी।

सोवियत अर्थ व्यवस्था की वार्षिक उन्नति की दर<sup>2</sup>

[ प्रतिशत में ]

	छठवी योजना	सातवी योजना
1. राष्ट्रीय आय	10.0	7.1-7.4
2. औद्योगिक उत्पादन	10.5	8.8
3. उत्पादन के साधनों का उत्पादन	11.2	9.2-9.4
4. उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	10.7	7.2-7.4
5. कृषि उत्पादन	11.0	8.0
6. श्रम उत्पादकता :		
A. उद्योग	8.4	5.5-6.0
B. निर्माण	8.7	6.9-7.0
C. कोलखोज	14.9	10.4
7. फुटकर व्यापार	8.4	6.7-7.1
8. रेल यातायात	7.3	4.9-5.5

<sup>1</sup> Bulletin, May 1959, p 24 [Institute for the Study of the USSR Munich]

<sup>2</sup> Ibid page 25

कृषि के क्षेत्र में छठवाँ योजना ने उन्नति करने का विशेष प्रयास किया था। कुल अन्न का उत्पादन बढ़ाकर 180 मिलियन टन [11,000 मिलियन पृड] करने का विचार था। कृषि के दूसरे क्षेत्र में उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार थे।<sup>1</sup>

	1960
	[1950 का प्रतिशत]
कपास	156
फ्लेक्स	135
चुकन्दर	151
आलू	185
अन्य तरकारियाँ	218
मांस	200
दूध	195
अण्डा	254
ऊन	182

अन्त में केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि छठवीं योजना की असफलता एक वरदान सिद्ध हुई। रूसी योजनाओं में से अव्यवहारिकता की मात्रा कम होने लगी। भविष्य के लिए वातावरण आशापूर्ण बनाने में यह बहुत सहायक होगा।

#### सप्त वर्षीय सातवीं योजना [1959-65]

इस योजना के अध्ययन से पहली चीज यह स्पष्ट होती है कि इसमें जनता का रहन-सहन का स्तर उठाना इसका मुख्य ध्येय था। कम्युनिस्ट पार्टी के 21वें अधिवेशन में इस योजना का स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन इतना अधिक बढ़ाया जाय कि रूसी नागरिक सुविधा-जनक जीवन विताने में समर्थ हो। योजना का समय 5 वर्षों से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया। योजना प्रणाली स्थिर होने से और योजनाकर्ताओं के अनुभव में वृद्धि के कारण भविष्य में और दूर तक देख सकना सम्भव हुआ। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी उनके हाथ में आये जिसके द्वारा भविष्य के परिवर्तनों का नियंत्रण अधिक गहराई तक बढ़ा। जो काम इसमें उठाये गये वे इतने बड़े और पेचीदे हैं कि उनकी सफल पूर्ति

<sup>1</sup> National Economy of U. S. S. R. Statistical Returns, p 92



के लिये ५ वर्ष का समय कम था। अभिलाषापूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वही मार्ग अपनाया गया जो अपना सार्थकता सिद्ध कर चुके थे। उत्पादन के साधनों का उत्पादन ही वह मार्ग है। यह योजना रूस की पुरानी इच्छा पूरा करने में सफल होगी अर्थात् अनेकों आवश्यक क्षेत्र में सयुक्त राज्य अमरीका के उत्पादन से देश आगे बढ़ जायगा। इसके लिये 1,600 से अधिक कारखाने स्थापित होंगे जिनमें हल्के उद्योग और भोजन उद्योग [Food Industries] का विशेष महत्व रहेगा। उपभोग के उद्योगों की वृद्धि के लिये मशीनों का उत्पादन और भी बढ़ाना पड़ेगा। कच्चे माल की प्राप्ति के लिये कृषि का महत्व अर्थव्यवस्था में और ऊँचा उठाने का विचार है। 100 मिलियन हेक्टर में अधिक भूमि खेती के अन्दर होने में कृषि यंत्रों की आवश्यकता बराबर बढ़ती जायगी। योजना ने इस क्षेत्र को उचित महत्व दिया है। रसायन उद्योग आधुनिक प्रगति के प्रतीक बनते जा रहे हैं। इसमें न पिछड़ने के लिये 270 बड़े रसायन कारखाने खोले जायेंगे। कहने के लिये तो यह योजना हर प्रकार से उपभोग को सामग्री का उत्पादन इतना बढ़ायेगी कि जनता की सब माँग पूरी हो सके, लेकिन हर स्थान पर यह कहा गया है कि यह उर्सा समय हो सकेगा जबकि भारी उद्योग और भी विकसित किये जायें। इसलिये वास्तविकता में यह योजना भी जनता की माँगों को पूरा कर सकेगी, इसमें संदेह होता है। कुछ प्रगति तो इस दिशा में हुई है। बढ़ती हुई शक्ति से प्रेरित होकर उपभोक्ताओं को छूट भी मिली, किन्तु यह कहाँ तक पर्याप्त होगा या फिर किसी बहाने राष्ट्रोन्नति के पक्ष में कुछ दिन और त्याग तथा धीरज के साथ प्रतीक्षा करने की सलाह दी जायगी, यह नहीं कहा जा सकता। इतना जरूर है कि रूसी योजनाओं की एक पुरानी कमी शायद 1959-65 के बीच पूरी हो सके। मकानों की कमी, बढ़ती हुई आबादी और औद्योगीकरण के कारण जटिल समस्या बन गई है। पिछले दो सालों में लगभग 30 लाख फ्लैट्स [flats] बनाये गये। नयी योजना अपने काल में 150 लाख मकान [houses] बनाने का प्रयत्न करेगी। किन्तु इस क्षेत्र में फिर से यह याद दिलाया गया कि मकानों का निर्माण मशीनों पर निर्भर करता है। इस सुविधा की आशा उस समय तक न करना चाहिये जब तक मकान बनानेवाली मशीनों का उत्पादन आवश्यक मात्रा में न बढ़ जाय। अतः प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी सुन्दर आशाएँ दिलाई गईं जिनकी पूर्ति एकमात्र भारी उद्योगों की उन्नति पर निर्भर करती है। सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण की दूसरी सेवाओं पर व्यय और भी बढ़ेगा। इन पर 1942 में 42 मिलियर्ड रूबल, 1958 में 215 मिलियर्ड रूबल खर्च हुए। यह मात्रा 1965 में लगभग 360 मिलियार्ड रूबल होगी।<sup>1</sup>

1. एक मिलियर्ड = 1,000 मिलियन

सप्तम योजना ने अपने सात साल के कार्यकाल के लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं : प्रथम, 1959-65 के बीच अर्थव्यवस्था की प्रत्येक शाखाओं में नया विकास जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी जायगी। इस विकास ने आर्थिक और यांत्रिक प्रगति सबल बनकर साम्यवाद की स्थापना में सहायक होगी। शहरो और गाँवों की जनता की वास्तविक आय में वृद्धि, निम्न तथा मध्यम वर्ग के मजदूरों तथा कर्मचारियों के वेतन में उन्नति, उपभोग के उत्पादन तथा मकान निर्माण पर अधिक जोर दिया गया। नई पीढ़ी को जन्म से ही आदर्श साम्यवादी बनाने के लिये उनको मैट्रानिक् शिक्षा के प्रसार को विशेष स्थान मिला है। द्वितीय, शान्तिपूर्ण आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बहुत ऊँचा स्थान मिला है। इसके द्वारा सोवियत संघ का प्रमुख अर्थिक उद्देश्य पूर्ण होगा अर्थात् कम से कम समय में प्रति व्यक्ति उत्पादन में पूर्वावर्ती देशों का बराबरी करके आगे निकल जाना। इसके लिये उत्पादन की मुख्य शाखाओं को तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को अधिकतम गतिशील बनाना निश्चय हुआ है। राजकीय भावनों पर जो प्रभुत्व रूसी सरकार को प्राप्त है उसके कारण इतना ऊँचा उठ जाना कोई असम्भव नहीं। उत्पादन प्रणाली में बहुत-सी बातों पर ध्यान देने के लिये प्रेरित किया गया है जैसे उत्पादन के गुणों में सुधार, विकास की गति में वृद्धि, हर प्रकार के धातु उद्योग तथा आधुनिक रसायन उद्योग, विशेषकर कृत्रिम धागे तथा वस्तुआ [Synthetic fibres, plastics and other materials] का निर्माण, कोयले के स्थान पर तेल और गैस का प्रयोग, बड़े पैमाने पर थर्मल बिजली उत्पादन, प्रत्येक निर्माण के कार्य का अधिकतम यंत्रीकरण जिससे श्रम उत्पादकता में वृद्धि हो, रेलों का विद्युतकरण और डीजल इंजन का प्रयोग, बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिये कृषि की प्रत्येक शाखा में विकास और मजदूरों के लिये मकान की कमी दूर करना। तृतीय, सात सालों में देश के प्रचुर प्राकृतिक साधनों की खोज तथा विकास। लाभपूर्ण उत्पादन शक्ति का बँटवारा करने का प्रयत्न किता जायगा जिससे प्रत्येक क्षेत्र विकसित हो और उद्योग, कच्चा माल, ईंधन, बाजार के अधिकतम निकट पहुँचाये जायें। यहाँ पर पूर्वी रूस के विकास को विशेष स्थान दिया गया है। यह अनुमान है कि पूर्वी क्षेत्रों में रूस का 3 कोयला, 70% जंगल और 90% जलविद्युत के साधन हैं। इनके अतिरिक्त प्रायः हर प्रकार के रसायन एवं खनिज पदार्थ यहाँ उपलब्ध हैं। इन सुरक्षित प्रदेशों में हर प्रकार के उद्योग विकसित किये जा रहे हैं। यूराल, साइबेरिया, सुदूर-पूर्व एशिया, कजाखस्तान [Kazakhstan] तथा मध्य एशिया में सप्तम योजना कुल पूँजी विनियोग का 40% से अधिक खर्च करेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि 1965 में कुल उत्पादन में पूर्वी क्षेत्रों का भाग बहुत बढ़ जायगा : कच्चा लोहा 43%, स्पात 47%, कोयला 50%, तेल 30% और विद्युतशक्ति 46%। पूर्वी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी प्राकृतिक

साधनों का विकास किया जायगा। अनाज, औद्योगिक फसलों तथा पशु उत्पादन के विकास में हर प्रकार का सहारा देकर अधिक उपज प्राप्त करने का विचार है। चतुर्थ, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग में यान्त्रिक कुशलता का विकास [technological progress] अधिक से अधिक किया जायगा। इससे इन्जीनियरिंग उद्योग को सबसे ऊँचा स्थान मिलेगा। इसी की मदद से अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण प्रयोग करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। पंचम, उत्पादन के बढ़ाने में अर्थव्यवस्था का समाजवादी संगठन, नई प्रणाली तथा यंत्रीकरण का प्रयोग और बराबर बढ़ता हुआ अनुभव तथा कुशलता का सहारा श्रम-उत्पादकता को प्राप्त होगा। इस प्रकार उत्पादन वृद्धि के लिये संगठन सुधार एक आधुनिक प्रणाली अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इसपर जोर देकर योजना-कर्ताओं ने उत्पादन व्यवस्था को असीम स्थिरता प्रदान की है।

### पूँजी निर्माण तथा विनियोग

पूँजी विनियोग का जो आकार इस योजना में प्रस्तुत किया गया है वह एक प्रकार का रूसी चमत्कार है। 195६-65 के बीच राज्य द्वारा लगाई रूसी पूँजी 1940 से 1970 मिलियर्ड रूबल होगी। तब अद्भुत विनियोग 1917-58 के बीच जितनी पूँजी देश में लगाई गई है, लगभग उसी के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि चालीस वर्षों में रूस की आश्चर्यजनक प्रगति के लिए जितना खर्च किया गया था लगभग उतना ही केवल सात वर्षों में किया जायगा। इस पूँजी के व्यय के लिए मोटे-मोटे सिद्धान्त सामने रखे गए। यह निश्चय किया गया है कि जहाँ पर नये प्राकृतिक साधनों का पता लगा है वही पर नये कारखाने स्थापित किये जायें। इस वर्ग में तेल, गैस, बिजली, खनिज पदार्थ इत्यादि आते हैं। निर्माण उद्योगों में [Manufacturing industries] नये कारखानों पर पूँजी न लगा करके वर्तमान कारखानों का आधुनिक-करण व पुनर्संगठन अधिक लाभप्रद होगा। इस नीति के पीछे इतनी पक्की यथार्थ-वादिता दिखलाई पड़ती है जो प्रत्येक देश के लिए प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय है। प्रथम योजना में स्थापित अधिकतर कारखाने इस समय तक पुनर्निर्माण मॉग रहे हैं। अगर इन पर ध्यान न दिया जाता तो पूँजी, श्रमशक्ति तथा उत्पादन के गुण [quality] पर बहुत बुरा असर पड़ना अनिवार्य था।

1959-65 के बीच कुल पूँजी विनियोग में 80% की वृद्धि होगी। उद्योग के क्षेत्र में पिछले 7 सालों का दूना धन लगाया जायगा। लगभग 100 मिलियर्ड रूबल लोहे तथा स्पात उद्योग में लगेंगे जो 1952-58 से 140% अधिक है। इसी प्रकार कच्चा लोहा उद्योग में 180% की वृद्धि की जायगी। रसायन उद्योग पर भी 100-105 मिलियर्ड रूबल खर्च होगा। इसका आधा भाग प्लास्टिक, कृत्रिम धागे, कृत्रिम रबड़

तथा स्प्रिट बनाने के लिए रखा गया है। तेल तथा गैस उद्योग को विशेष प्रकार से विकसित करने के लिए चुना गया। 170-173 मिलियर्ड रूबल खर्च करके पिछले सात सालों की अपेक्षा 130-140% वृद्धि होने का अनुमान है। कोयले का महत्व कम कर दिया गया किन्तु विद्युत उत्पादन पर 125-129 मिलियर्ड रूबल खर्च होगा जिसने 70% वृद्धि की आशा है। हल्के तथा भोजन उद्योग [light and food industry] में पिछले सात सालों की दूनी वृद्धि की जायगी। मकान निर्माण के लिए 375-380 मिलियर्ड रूबल अलग किया गया है। इतनी पूँजी लगाने पर मकान की कमी सन्तुष्ट कम हो जाना चाहिये।

कृषि के क्षेत्र में राज्य ने 150 मिलियर्ड रूबल लगाने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक फार्मों के भूमि तथा पशु उत्पादन से उत्पन्न पूँजी कृषि-विकास में लगेगी। यह अनुमान किया जाता है कि 1959-65 में साम्प्रदायिक फार्म 250 मिलियर्ड रूबल उत्पादन तथा अन्य सुविधाओं के विकास पर खर्च करेंगे और 95 मिलियर्ड रूबल कृषि यन्त्र खरीदने में लगवा जायगा। इस प्रकार कृषि में कुल मिलाकर 500 मिलियर्ड रूबल की पूँजी लगेगी। यह 1952-58 का लगभग दूना है। रेल यातायात में पिछले सात वर्षों से 85-94% अधिक विस्तार होगा जिसके लिए 110-115 मिलियर्ड रूबल सुरक्षित रखा गया है। रेलों के विद्युतकरण पर व्यय में 170% की वृद्धि होगी।

निर्माण के समय तथा पूँजी में अधिकतम वृद्धि करने के लिए सप्तम योजना ने बड़ी महत्वपूर्ण कोशिश की है। विकास में सामंजस्य [Co-ordination] लाना पूँजी विनियोग का विशेष कार्य होगा। अभी तक चली आ रही कमजोरियों को दूर करके यह प्रयत्न किया जायगा कि क्षेत्रों में कारखानों का बँटवारा, विभिन्न कारखानों के उत्पादन में विशिष्टीकरण [Specialization] और एक क्षेत्र के सभी उद्योगों में सहयोग तथा सामंजस्य उत्पन्न हो। एक स्थान के हर कारखानों को एक स्वतन्त्र इकाई की तरह निर्माण करने से पूँजी का व्यय और उत्पादन की लागत अकारण बढ़ जाती थी। नये कारखानों के निर्माण में सुन्दरता तथा प्रतिष्ठा के स्थान पर वृद्धि, सुविधा और अच्छे उत्पादन का दृष्टिकोण सामने रखा जायगा। उद्योगों में आत्म-निर्भरता उत्पन्न हो इसलिए कारखाना निर्माण का प्रारूप [draft] व प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने का व्यय राजकीय बजट से हटाकर उस कारखाने के बजट में सम्मिलित कर दिया गया है। इस परिवर्तन से उद्योगों का लागत लेखा आधार [Cost accounting basis] और भी दृढ़ होगा।

**कृषि**

छूटी योजना 1960 तक चलने वाली थी किन्तु 1958 में उसको स्थगित कर

दिया गया। छठी योजना के अन्तिम दो वर्ष (1959-60) सातवीं योजना के प्रथम दो वर्ष बन गये। कम्युनिस्ट पार्टी के 21 वे अधिवेशन ने फरवरी 1959 में नई योजना के लक्ष्य स्वीकार किये। यह आशा की गई कि सात वर्षों में कृषि-उत्पादन इतना बढ़ा लिया जायगा कि जनता के भोजन की सभी आवश्यकताएँ पूरी हो जायँगी। इसके अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल और कृषि उत्पादन की राजकीय माँग 1965 तक पूरी कर ली जायगी। कृषि-क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में उठाने का विचार है। समाजवादी उद्योगों ने कृषि को आधुनिक यन्त्रा से सुसज्जित करके, कृत्रिम खाद तथा अन्य रसायन प्राप्त करने में बहुत सहयोग दिया। सामूहिक फार्म अथवा कोलखोज में कुशल श्रम की वृद्धि हुई। बहुत बड़ी मात्रा में नई भूमि कृषि में लाई गई और वज्र भूमि को कृषियोग्य बनाया गया।

इतना हो चुकने पर 7 वीं योजना इस गत का प्रयत्न करेगी कि खेती की उन्नति और समाजवादी उत्पादन को और घनिष्ठ रूप से पास लाया जाय। इसका अर्थ यह होगा कि राजकीय क्षेत्र [state farms] और कोलखोज राष्ट्र की समाजवादी सम्पत्ति होने के नाते एकरूपता की ओर अग्रसर होंगे। यह काम कई तरह से किया जायगा। सामूहिक फार्म पद्धति की उन्नति, उसकी सम्पत्ति [Stocks] में वृद्धि, अविभाजनीय कोष [Indivisible funds] का विकास व उचित सामाजिक प्रयोग, सामूहिक फार्मों में पारस्परिक सहयोग द्वारा अद्योगिक उत्पादन करना तथा विजलीघर, नहरे, कृषि-उत्पादन का संग्रह [Storing and processing], स्कूल एवं अस्पताल बनवाना इसका मुख्य कार्य होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि नई नीति के अनुसार भविष्य में कोलखोज और सोवखोज को मिलाने का निश्चय किया गया है। राष्ट्रीय सम्पत्ति के इन दोनों रूपों को एक में मिलाने के लिए तर्क यह है कि जब सामूहिक फार्म का उत्पादन बढ़ेगा, और यह फार्म बड़े पैमाने पर कुशल श्रम तथा आधुनिक यांत्रिक सुविधाओं के साथ विकसित होंगे, तो सामूहिक फार्म के किसानों की अधिकतर आवश्यकताएँ सार्वजनिक आर्थिक साधनों [Public economic resources] से पूरी होंगी। अतः सामूहिक फार्मों की निजी सम्पत्ति [Indivisible fund and its investments] अपना पृथक् अस्तित्व छोड़कर राष्ट्रीय सम्पत्ति में विलीन हो जायगी।

राजकीय फार्म का स्थान समाजवादी कृषि में और ऊपर उठा दिया गया है। यह अपने आदर्श प्रबन्ध, कम लागत पर उत्पादन और श्रम तथा साधनों में बचत का प्रतीक बनकर सामने आयेगा। इनके प्रबन्ध संगठन में श्रम का प्रत्यक्ष सहयोग और भी बढ़ा दिया जायगा। राजकीय खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिये उनकी मशीनों तथा वस्तुओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। प्रत्येक क्षेत्र में जलवायु तथा भूमि को देखते हुए उत्पादन में विशिष्टीकरण [Specialisation] किया जायगा

जिससे राजकीय खेत अधिक लाभप्रद बन सके। उत्पादन की लागत घटाने के लिये पूरा प्रयत्न होगा। आशा है कि 1957 के आधार पर 1965 में अन्न उत्पादन की लागत में 30% कमी, मांस में 19%, दूध में 23%, ऊन में 10% और कपास में 20% होगी।

इन सब परिवर्तनों में रूसी कृषि में जो नई उत्तेजना होने की आशा है उसके आधार पर उत्पादन का बहुत ऊँचा लक्ष्य सामने रखा गया है। इनकी पूर्ति में पूर्वी प्रदेशों की नई भूमि तथा कृषि-विकास का विशेष स्थान होगा। अन्न के उत्पादन में यह आशा की जाती है कि 160-180 मिलियन टन उत्पादन होगा। प्रतिवर्ग एकड़ उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। 1954-57 के बीच प्रति हेक्टर औसत उत्पादन 620 किलोग्राम रहा। इस योजना में इसको लगभग 1,000 किलोग्राम तक पहुँचाने की चेष्टा होगी। जहाँ तक नई भूमि खेतों में लाने का सम्बन्ध है 1954-55 के बीच लगभग 33 मिलियन हेक्टर नई भूमि पर खेतों की जा चुकी। यह अद्भुत प्रगति 1956 में आकर लगभग 3 मिलियन हेक्टर हो गई। इन तीन वर्षों में यह अनुमान किया जाता है कि 90% नई भूमि पर खेती की जा चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति में [ दिसम्बर 1958 ] बताया गया कि 1954-58 के बीच राज्य ने नई भूमि के विकास पर 307 मिलियर्ड रूबल खर्च किया और लगभग 489 मिलियर्ड रूबल की आय नई भूमि से हुई। इस प्रकार यह क्षेत्र सातवीं योजना के पहले ही काफी विकास कर चुका है। नई भूमि पर इतना तीव्र उत्पादन किया जा चुका है कि, वर्तमान योजना में, उर्वरा शक्ति बनाये रखने के लिये इस भूमि का आराम देना ही होगा। रसायनिक खाद का प्रयोग 1965 तक 31 मिलियन टन हो जायगा, 1958 में इसकी मात्रा केवल 106 मिलियन टन थी।

कृषि के पशुपालन विभाग में बहुत उन्नति करने का आयोजन है। दूध, मांस, अण्डा और ऊन के उत्पादन पर विशेष ध्यान रखा गया है। 1952-58 के बीच मांस का औसत उत्पादन प्रति वर्ष 5 लाख टन था। 1955 तक इसे 11 लाख टन, दूध 31 लाख टन से 59-66 लाख टन, ऊन 18,000 से 35,000 टन कर दिया जायगा। इसके लिये 1959-65 में, 1952-58 के आधार पर, पशुओं की संख्या में इस प्रकार वृद्धि होगी—पशु [Cattle] 20%, गाय 90%, भेड़ लगभग 50%। चारे के उत्पादन में केवल विकास ही नहीं किया जायगा किन्तु उसमें पौष्टिकतत्व भी बढ़ेगा। आलू और मक्का इसका आधार होंगे।

विकास की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिये कृषि के प्रत्येक विभाग में यन्त्र एवं बिजली का प्रयोग किया जायगा। सात वर्षों में 10 लाख ट्रैक्टर

और 4 लाख हारवेस्टर-कम्बाइन और बहुत बड़ी मात्रा में अन्य कृषि यंत्र बनाने की योजना है। इस अवधि में सभी सामूहिक खेतों में बिजली पहुँचा दी जायगी जिससे विद्युत शक्ति का प्रयोग 300% बढ़ेगा। इसके लिये सामूहिक खेतों का अविभाजनीय कोष [Indivisible fund] सक्रिय रूप से सहायक बनेगा। यह प्रयत्न किया गया है कि सामूहिक फार्म आपस में मिलाकर इस धनराशि की मदद से सामूहिक बिजली-घर अपने-अपने ज़ेब्रा में बनायेंगे। पिछले 40 साल से संचित सामूहिक फार्म के कर्मचारियों की यह वचत अब राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में राजा के हाथों सौंप दी जायगी।

कृषि में श्रम उत्पादन [Labour productivity] बढ़ाने का प्रश्न बड़े प्रभावशाली रूप में सामने आया है क्योंकि 7 वीं योजना कृषि को एक बड़े पैमाने के उद्योग में बदल देगी। किसान और मजदूर सहयोग [Smyčnka] का जो नारा लेनिन ने लगाया था वह वर्तमान परिस्थिति में अर्थहीन घोषित कर दिया गया है। सहयोग का अर्थ होता है पृथक् अस्तित्व। रूस के नये कर्णधारों ने सहयोग के स्थान पर विलयन [Integration] को अधिक उचित माना है इसीलिये सातवी योजना किसान को बदल कर औद्योगिक मजदूर का रूप दे देगी। इस रूप में उत्पादकता की समस्या प्रथम आवश्यकता है। यह सम्भावना है कि 7 वर्षों में सामूहिक फार्म में श्रमिकों की उत्पादकता दूनी कर दी जायगी और राजकीय खेतों में 60-65% वृद्धि होगी।

योजना ने कृषि में महान् परिवर्तन करने की रूप-रेखा तैयार की है। 1929-57 के बीच वे सभी आवश्यकताएँ उत्पन्न कर ली गई हैं जिससे वर्तमान योजना की पूर्ति हो सके। कृषकों के बीच समाजवादी प्रतिस्पर्धा [Socialist emulation] और अनुभव के आधार पर नये कृषि सगठन का विशाल निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे व्यक्ति तथा व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व खो देगी। राज्य इन सब को अपने में छिपाकर देश को समाजवाद से साम्यवाद की ओर बढ़ायेगा।

### उद्योग

सातवी योजना ने औद्योगिक विकास की प्रणाली में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया। भारी उद्योगों का सर्वश्रेष्ठ स्थान पूर्ववत् बना रहा। सुरक्षा तथा उत्पादन के साधन इसकी प्रेरणा थे। भारी उद्योगों में रसायन उद्योग ने विशेष स्थान पाया। नये वैज्ञानिक युग में रसायनिक उद्योग ही वह साधन है जिसके द्वारा प्रकृति की कमियों को पूरा किया जा सकता है। कृत्रिम रबर और प्लास्टिक के विविध रूपों से आधुनिक सैनिक शक्ति तथा औद्योगिक उत्पादन दोनों को सहायता दी जाती है।

कुल औद्योगिक उत्पादन [1958 की तुलना में] 1965 तक लगभग 80% बढ़ेगा जिसमें उत्पादन के साधनों का उत्पादन 85-88% और उपभोग की सामग्री का उत्पादन 62-65% होगा। प्रति वर्ष उत्पादन की गति 8.6% रखी गई है। इस वृद्धि में प्रथम वर्ग के उद्योग 9.3% प्रतिवर्ष की गति से बढ़ेंगे और द्वितीय वर्ग के 7.3%। औसत वार्षिक औद्योगिक उत्पादन का मूल्य अगले सात सालों तक करीब 135 मिलियर्ड रूबल होगा जब कि पिछले सात सालों में यह 90 मिलियर्ड रूबल था।

लोहा तथा स्पात उद्योग औद्योगिक विकास के आधार माने गये हैं। 1958 की अपेक्षा 1965 में कच्चा लोहा उत्पादन में 64-77%, रोल्ड धातु [Rolled metal] में 53-62%, वृद्धि होगी।

वार्षिक उत्पादन वृद्धि <sup>1</sup>

	1952-58	1959-65
कच्चा लोहा	25,00,000 टन	36-44,00,000 टन
स्पात	34,00,000 ,	44-51,00,000 ..
रोल्ड धातु	27,00,000 ,	32-39,00,000 ..

इनके अनिरीक्त रसायन उद्योग में तीनगुना उत्पादन वृद्धि हूँगी। कृत्रिम रेशदार पदार्थ [Synthetic fibres] में 300% उन्नति से प्रकृति की कमियों को पूरा करने का प्रयत्न है। कृत्रिम गोंदयुक्त पदार्थ [resins] की 600% प्रगति से प्राकृतिक रबर की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। योजना के समय में लगभग 140 नये रसायन कारखाने स्थापित किये जायेंगे तथा 230 पुराने कारखानों का पुनरुद्धार होगा। ईंधन के विभाग में गैस और तेल से कोयला की वचत करने का विचार है। गैस का उत्पादन तीनगुना और तेल का दुगना हो जायगा। जल-विद्युत [hydro-electricity] तथा कोयला-विद्युत [Thermal electricity] को 110 से 120 प्रतिशत बढ़ाकर देशव्यापी विद्युतकरण करने की आशा है। बिजली का नया साधन—अणु शक्ति का समुचित विकास करने की योजना बनी है। आधुनिक इञ्जीनियरिंग उद्योग के विस्तार से उत्पादन शक्ति का यान्त्रिक उत्थान होगा। अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक अंग में यंत्रों के प्रयोग से महत्वाकांक्षी उत्पादन-लक्ष्य साकार बनाये जायेंगे।

भारी उद्योग तथा कृषि की प्रगति ने उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा सकना संभव बना दिया है। जीवन-स्तर को उठाने के लिए इस वर्ग के उत्पादन भी

<sup>1</sup>Target Figures for the Economic Development of USSR from 1958 to 1965, p 51



नीछे नहीं छोड़ दिए गए। स्तालिन की मृत्यु के बाद, इस क्षेत्र में काफी उदारता दिखलाई गई है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इस समय तक देश की उत्पादन शक्ति इतनी विकसित हो चुकी है कि निम्न सैनिक आवश्यकताओं तथा भारी उद्योगों में कटौती किए हुए, जनता के उपभोग के उत्पादन के लिए साधन अलग किये जा सकते हैं। इसीलिए 1959-65 के बीच हल्के उद्योगों में 50% वृद्धि होगी जिसके लिए 156 नए बड़े पैमाने के कारखाने स्थापित होंगे और 1959 के पहले आरम्भ किये गए 114 कारखानों को पूरा किया जायगा। रूसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ मूली-ऊनी कपड़े तथा जूते का उत्पादन इसका आधार है। 1958 से 1965 तक मूली कपड़े में 138%, ऊनी कपड़े में 165%, सिल्क में 176% और जूतों में 145% की वृद्धि होगी। रूस के समान ठड़े देश में इनसे अधिक आवश्यक वस्तु केवल आग और भोजन को माना जा सकता है।

औद्योगिक संगठन इस महान कार्य को सफलता से पूरा कर सके इसलिए विशिष्टीकरण [Specialisation] और आपसी सम्पर्क एवं सन्तुलन [Coordination] के साथ यन्त्रीकरण [Mechanisation] की पूर्ण रूप से सहायता ली जायगी। इनके द्वारा उत्पादन प्रणाली में फिजूलखर्चा [waste], लागत [cost of production] और खराब किस्म का उत्पादन [bad quality] में कमी होगी तथा श्रम-उत्पादकता बढ़ेगी। देश के प्रत्येक क्षेत्र अपने-अपने साधन, परिस्थिति, जलवायु व आवश्यकता को देखते हुए निर्माण कार्य में सलग्न होंगे। इस प्रकार अधिक साधन व यातायात की वृद्धि तथा लाभपूर्ण प्रयोग हो सकेगा। 1959-65 में मजदूर कम समय काम करेगा फिर भी श्रम-उत्पादकता प्रति मजदूर लगभग 45 से 50 प्रतिशत बढ़ जायगी। साथ ही साथ उत्पादन की लागत में 11.5% कमी होने का अनुमान है।

### यातायात

विकास के इच्छुक देशों में यातायात सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाता है। इसकी उन्नति इतनी महँगी और धीमी होती है कि जटिल समस्या बनने में कोई देर नहीं लगती। सोवियत रूस में भी यही हाल रहा। सार्वी योजना ने इसके विकास के लिये जो चित्र बनाया है उसके अनुसार यह समस्या सदा के लिये समाप्त हो जायगी। योजना का विशेष ध्यान रेल और वायु यातायात पर होगा। माल ढोने की क्षमता में रेल यातायात 39 से 43 प्रतिशत विकास करेगा। इस काम में विजली और डीजल शक्ति का अधिकतर प्रयोग होगा। 1958 में 74% मालगाड़ियों कोयला-इंजन प्रयोग में लाती थी किन्तु 1965 में 85 से 87% मालगाड़ियाँ विजली और डीजल इंजन

से चलेगी। नवविकसित पूर्वी औद्योगिक प्रदेशों [कजाख़स्तान, यूराल, वोल्गा तथा साइबेरिया] में ट्रान्स-साइबेरियन रेलवे के अतिरिक्त दक्षिणी साइबेरिया और मध्य साइबेरिया तक विशाल रेल लाइने बनाई जायेंगी। रेल यातायात के आधुनिककरण में माल ढोने की लागत में 22% कमी होगी।

समुद्र, नदी एवं मोटर यातायात की उन्नति के प्रयत्न जारी रहेंगे किन्तु वायु-यातायात सवारी का मुख्य साधन बन जायगा। यह आशा है कि वायुयानों की सवारी की संख्या में 500% की वृद्धि होगी। यातायात के क्षेत्र में एक नई दिशा पर अत्यधिक जोर दिया गया है। तेल के वाहन के रूप में पाइप लाइन का जाल बिछाया जायगा जिससे तेल वाहन में किसी प्रकार के यातायात की ज़रूरत ही न पड़े। पाइप द्वारा तेल ले जाने में 450% की बढ़ती करने की योजना है।

### जन-कल्याण

लेनिन का कहना था कि आर्थिक प्रेरणा व सृद्धि के दिये बिना करोड़ों व्यक्तियों को साम्यवाद में लाना सम्भव नहीं है। रूसी योजनाएँ इस लक्ष्यप्राप्ति का साधन रही हैं। 7 वी योजना 1959-65 के बीच राष्ट्रीय आय में 62 से 65% की वृद्धि करेगी। इससे राष्ट्र की उपभोग क्षमता [Consumption capacity] में 60 से 63% की उन्नति होगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान योजना जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये उपभोग-विस्तार का विशेष प्रयत्न है। अर्थ-व्यवस्था के विविध अंगों के निरन्तर बढ़ने से मजदूर व कर्मचारियों [Factory and office workers] की संख्या में 120 लाख व्यक्तियों अथवा 22% की वृद्धि होगी। 1965 तक इनकी कुल संख्या 665 लाख हो जायगी। मूल्य में कमी तथा वेतन, पेंशन व सहायता में प्रगति होने से मजदूर-कर्मचारियों की वास्तविक आय [real income] 40% बढ़ जायगी। ध्यान देने की बात यह है कि यह योजना कृषि क्षेत्र में भी जीवन-स्तर उठाने में लगी है। उद्योगों को छोड़कर, सामूहिक फार्मों के किसानों की वास्तविक आय भी 40% ही बढ़ेगी। यह अधिक कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण श्रम-उत्पादकता में उत्थान से पूरा होगा।

वेतन प्रणाली में कई सुधार किये जायेंगे। निम्न तथा मध्यमवर्ग के मजदूर कर्मचारियों के वेतन को ऊपर उठाकर उच्चवर्ग के साथ असमानता को कम कर दिया जायगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये दो चरण [Stages] बनस्य गा हैं। प्रथम चरण [1959-62] में लागू होगा। इसके द्वारा न्यूनतम वेतन [minimum wages] 270-350 से बढ़ाकर 400-450 रूबल प्रति माह होगा। दूसरे चरण [1962-65] में दुबारा इसे उठाकर 500-600 रूबल प्रतिमाह तक पहुँचा दिया

जायगा। औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान [hygiene] तथा कारखानों में मशीनों से रक्षा में प्रगति, मजदूर-कर्मचारियों को विशेष सुविधाएँ, नर्सरी तथा किण्डरगार्टन स्कूल, निःशुल्क शिक्षा, इलाज, सामाजिक बीमा, बड़े परिवार की माताओं को अनुदान [giants], पेन्शन, वृद्धों के लिए विश्राम-भवन, इत्यादि पर राजकीय व्यय 215 मिलियर्ड रूबल [1958] की जगह 360 मिलियर्ड रूबल [1965] में किया जायगा। वीसवी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन की आज्ञा के अनुसार कार्य काल में कमी करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। जिसका आदर्श पाँच दिन प्रति सप्ताह में 6 से 7 घंटे का कार्यकाल माना गया है। प्रति सप्ताह दो दिन का लगातार अवकाश रूसी मजदूर कर्मचारियों के लिए वरदान बन जायगा। अवकाश व मनोरंजन की उनके जीवन में अत्यधिक कमी थी। 1958 से स्यात और कायला उद्योग में 7 घंटे प्रति दिन कार्यकाल लागू कर दिया गया। पहिली अक्टूबर 1959 से यह सुविधा अन्य सभी कारखानों तथा आफिसों में कार्यान्वित होगी। खानों में काम करने वालों का कार्य-काल 6 घंटा प्रतिदिन कर दिया जायगा।<sup>1</sup>

सोवियत संघ के इस विकास से विश्व औद्योगिक उत्पादन में समाजवादी उत्पादन का भाग बहुत बढ़ जायगा। 1938 में इस वर्ग के देशों की जनसंख्या तथा उत्पादन संसार का लगभग एक-तिहाई था। सातवी योजना इसे बढ़ाकर 1965 में आधा तक पहुँच देगी। समाजवाद और पूँजीवाद की दौड़ में रूस की गति बराबर तीव्र होती जा रही है। रूस के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क का विस्तार फैल रहा है। 1946 में रूसी व्यापार 46 देशों से था। इस समय 70 देशों से व्यापारिक सम्बन्ध है। सातवी योजना इसे और भी प्रोत्साहन देगी। समाजवादी देशों के साथ व्यापार में 50% वृद्धि की जायगी। अविकसित तथा अर्द्ध-विकसित देशों के साथ भी सोवियत संघ का सम्बन्ध निरन्तर उन्नति पर है। 1953-57 के बीच इस व्यापार में पाँच गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है।

सातवी योजना सोवियत रूस के प्रथम लक्ष्य की ओर अत्यन्त सुदृढ़ कदम है : संयुक्त राज्य अमरीका से आगे निकलना इस योजना की सफल पूर्ति से ही सम्भव हो पायेगा। इन सात वर्षों तक देश यदि राजनैतिक भूचाल से अपनी रक्षा कर सके तो लेनिन का स्वप्न सम्भवतः साकार हो जायगा।

<sup>1</sup> The "Leader" Allahabad, dated September 21, 1959, p. 2

## अर्द्ध-विकसित देशों के लिये रूसी आर्थिक विकास का संदेश

( Message of Russian Economic Development  
for Under-Developed Countries ]

### अर्द्ध विकसित देशों के लिये रूसी आर्थिक विकास का संदेश

प्रोफेसर मारिस डॉव ने ठीक ही कहा—इसमें सदेह है कि पहले कभी भी सत्तार के इतने विशाल भू-खंड पर, इस प्रकार के गहन परिवर्तन, इतने अल्प समय में हुए हों जितना कि सोवियत रूस में हुआ। इस कथन का पूर्ण महत्व इस समय समझने आता है जब 1913-1916 के रूस पर दृष्टिपात किया जाय। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय का रूस और आज के अर्द्ध विकसित देश लगभग एक ही स्तर पर है : छोटे टुकड़ों वाली अनार्थिक भू-क्षेत्र, तेज से बढ़ती जन-संख्या, अशिक्षा, दरिद्रता व उदासीनता, उद्योग के उत्पादन पर आधारित सामान्य औद्योगिक विकास, विदेशियों पर आश्रित अर्थ-व्यवस्था; संचारित्रता एवं कर्तव्य-परायणता से गिरी हुई जनता तथा शासन; राज्य और जनता के बीच बढ़ती हुई दूरी विलासिता और भुखमरी का दर्दनाक संयोग की समानता आसानी से देखी जा सकती है। यही कारण है कि विकास की खोज में उन्मत्त यह देश आज रूसी आर्थिक विकास का संदेश इतना आकर्षक तथा अनुकरणीय पाते हैं।

निःसंदेह, रूस की राजनैतिक पृष्ठ-भूमि भली नहीं जा सकती। चमत्कारी उन्नति पर एक कालिमा है जिसे सदा दृष्टि में रखना उचित होगा। प्रकृति ने मानव को कुछ आधारभूत अधिकार दिये हैं। व्यक्तिगत विचार तथा निर्णय की स्वतंत्रता इनमें सर्वप्रधान है। इसी प्रकार मनुष्य व्यक्तिगत-भावनाविहीन यत्र नहीं है जिसे धन या धन से उत्पन्न सुविधाओं द्वारा एक निर्देशित मार्ग पर सदा चलाते रहा जाय। सोवियत रूस की आश्चर्यजनक प्रगति का मूल्य जनता ने अपने प्राकृतिक अधिकार तथा व्यक्तित्व को खोकर चुकाया। इसलिये रूस का अन्ध-अनुसरण करने के पहले आत्मा को पेट के लिये ब्रेच देना होगा।

इसका यह अर्थ नहीं कि सोवियत उदाहरण को उचित स्थान न दिया जाय। रूस एक ऐसा यथार्थ है जिसने विश्व-इतिहास में नया अध्याय जोड़ा, जिसने विकास का नया मार्ग दिखलाया। यह बात दूसरी है कि कोई इस नये मार्ग से सहमत न हो। फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि लक्ष्य-प्राप्ति का यह भी एक साधन है। इसके द्वारा कई असंभव संभव बन गया। लोगों के मन में यह बात घर कर गई थी कि पूँजीवाद में पाई जाने वाली बुराइयों दूर नहीं की जा सकती : चंद व्यक्तियों के व्यक्तिगत लाभ के लिये शोषण; कुछ लोगों को अमीर बनाने के लिये औरों को गरीब बन रहना होगा; आय की असमानता आवश्यक है कि बचत, पूँजी निर्माण तथा उत्पादन हो सके जिससे अल्प जनता को रांटी मिलती रहे, औद्योगिक विकास की दौड़ में जो देश पिछड़ गये हैं, वह सदा पिछड़े ही रहेंगे, जब तक कि अपनी स्वतंत्रता को बुनियादी मशीनों के लिये बेचना उनको स्वीकार न हो।

रूस ने सिद्ध कर दिया कि [१] कोई भी देश विकास में इसलिये नहीं पिछड़ा कि वह गरीब था या वहाँ बचत और पूँजी निर्माण कम होता था : देश के पिछड़ने का कारण आर्थिक संगठन [economic organisation] की कमजोरी और लापरवाही होती है। [२] कृषि प्रधान देशों में औद्योगीकरण से खेती का उत्पादन अल्प के अभाव के कारण कम नहीं होता क्योंकि इन देशों के ग्रामीण क्षेत्र पर आवश्यकता से बहुत अधिक आबादी रहती है। [३] विदेशी पूँजी की अत्यधिक सहायता लिये बिना भी विकास हो सकता है। [४] राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का केन्द्रीय निर्देशन तथा संचालन, कम से कम समय में आर्थिक प्रगति संभव बना देगा। [५] व्याज तथा लाभ [interest and profit] बिना भी विशाल पूँजी तथा विनियोग किया जा सकता है। [६] मूल्य निर्धारण पर लागत [cost], माँग तथा पूर्ति का प्रभाव हटाया जा सकता है। [७] औद्योगिक मर्दा [trade depression] आवश्यक नहीं है।

अतः यह देखना उचित होगा कि रूसी आयोजन में ऐसी क्या विशेषताएँ हैं जिन्होंने इतना कुछ संभव बनाया। इनका कहाँ तक लाभ उठाया जा सकता है, यह तो विभिन्न देशों के राजनैतिक संगठन तथा सैद्धान्तिक विश्वास पर निर्भर करेगा। कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका सरलता से उपयोग किना जा सकता है।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी अधिकतर अच्छे शान्तिकालीन राज्य-कर्मचारी तथा अनुशासनपूर्ण नागरिक नहीं बन पाते। स्वतंत्रता संग्राम का त्याग, कष्ट, उत्तेजना, भय और जोखिम लक्ष्य प्राप्ति के बाद दो मनोवृत्तियों पैदा कर सकता है। प्रथम, इन व्यक्तियों को शान्ति-चैन का वातावरण एकदम नीरस तथा निष्प्राण लगता है। परिस्थितियों से प्रेरित तत्कालिक जोश और भावावेश में वह निकलने की पुरानी आदत के कारण सोच-समझकर कदम उठाना इनके लिये बहुत कठिन और अरुचिकर हो

जाता है। इस मनोवैज्ञानिक असन्तोष से उदासीनता [indifference] या विरोध का जन्म होता है। नवीन आर्थिक नीति के समय यह असन्तोष खुले विरोध में बदल रहा था। स्तालिन ने इसे परखा और जोश को सृद्धिशाली किसानों के विरुद्ध, कृषि का सामुदायीकरण [collectivisation] तथा आर्थिक योजनाओं में क्रियात्मक रूप से लगा लिया। द्वितीय, स्वतंत्रता संग्राम में किये गये त्याग और सेवाओं से दृष्टिकोण विकृत भी हो जाता है। अहंकार और निजी महत्व की भावना इनको उद्धारकर्ता में शोषक में बदल देती है। ठीक यही क्रम क्रान्ति के बाद—लगभग एक वर्ष तक चलता रहा। कठोर राष्ट्रीयकरण से इस पर काबू पाने का प्रयत्न हुआ। विचारों में विकार के कारण ऐसे व्यक्तियों के लिये स्वतंत्रता निजी कष्ट का पुरस्कार बन जाती है। समाज में अनुचित लाभ उठाना अपना स्वामित्व अधिकार प्रतीत होने लगता है।

आरम्भिक पूँजीवाद [early capitalism] के स्तर में देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए रूस ने एक नया उपाय खोजा। पूँजीवादी विकास ध्रुव की गति तेज करने में राजकीय पूँजीवाद [state capitalism] का सहारा लिया जा सकता है। इस द्वारा देश की शीघ्रतम एवं सतुलित प्रगति संभव हो सकेगी।

प्रश्न यह उठता है कि राजकीय पूँजीवाद में ठीक गई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ क्या स्थाई रूप से बनी रह सकती हैं? रूस के ऐतिहासिक अनुभव में एक उत्तर पाया जाता है। राजकीय पूँजीवाद के विकास में एक समय वह स्थिति आ जायेगी जब राजकीय संचालन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में विरोध उत्पन्न होगा। राज्य शक्ति के आगे व्यक्तिगत अधिकार दबते जायेंगे। इन अधिकारों का पुराना रूप नष्ट हो जायेगा। राजकीय संचालन की व्यापकता फैलेगी और संस्थाओं के साथ व्यक्ति भी पूरी तरह इसी में विलीन हो जायेंगे। निष्कर्ष यह निकला कि राजकीय पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था स्वयं एक ध्येय नहीं बन सकती। समाज के क्रमिक विकास में यह केवल एक कड़ी है। अतः में समाजवाद का आकार अपनाना होगा।

आयोजन के क्षेत्र में रूस को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। व्यक्तिगत पूँजी और निर्णय के अतिरिक्त भी आर्थिक विकास हो सकता है, इसका पहला उदाहरण सोवियत संघ है। केन्द्रीय संचालन, स्वामित्व तथा निर्देशन से अद्भुत प्रगति अत्यन्त कम समय में संभव बन गई। इस सम्बन्ध में रूसी कार्य प्रणाली ध्यान देने योग्य है।

सोवियत योजनाओं की सफलता का रहस्य उसके सामाजिक नींव में छिपा है। रूसी योजनाएँ राज्य की इच्छा या आज्ञा के स्थान पर समाज का ध्येय और जनता का प्रथम कर्तव्य बनकर कार्यान्वित होती हैं। प्रत्येक नागरिक को विश्वास है कि योजना को बनाने में वह सांझीदार है तथा योजना उसकी अपनी चीज

है। इससे ऐसी कर्तव्यनिष्ठा और परिश्रम का वातावरण बनता है कि कोई भी योजना सफल हुए बिना नहीं रह सकती।

योजना को समाज का उत्तरदायित्व बनाने में दो साधन काम में लाया जाता है : प्रचार व प्रयोग। अत्यंत चतुर तथा मनोवैज्ञानिक प्रचार का देशव्यापी जाल जनता की विचारधारा और विवेचना शक्ति को किसी भी ओर मोड़ देने में समर्थ है। जीवन का कोई भी समय या पहलू ऐसा नहीं बचता जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार न चल रहा हो। सोवियत संघ के आरम्भिक काल में तो यह कहना भी कठिन था कि शिक्षा द्वारा प्रचार किया जाता है अथवा प्रचार को ही शिक्षा मान लिया गया है। इतने पर भी जनता का जो भाग प्रभावित होने से इन्कार करता है उसके लिये प्रयोग किया जाता है। गुप्तचर और पुलिस इतने प्रबल रूप से क्रियाशील रहते हैं कि यह सोचना भूल माना जायगा कि दिवालियों को कान नहीं होते। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संगठन का आधार “प्रचार-शक्ति-सदेह” कहा जाय तो शायद कोई भूल न होगी।

सफल आयोजन में सिद्धान्त तथा अँकड़ों से परिपूर्ण योजना बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण उसे कार्यान्वित करने के लिये संगठन है। इस संगठन के रूपरेखा की तैयारी और विस्तार अत्यंत जटिल कार्य होता है। 1922 में स्थापित रूसी योजना आयोग लगभग छः सालों तक इस काम में लगा रहा फिर भी हर योजना के समय शासन-संगठन को सुधारना पड़ता था। उचित संगठन का अभाव अच्छी से अच्छी योजना को निष्क्रिय बना देगा। विकास में नये उद्यत देश योजना के प्रारूप बनाने में इतना उलझ जाते हैं कि संगठन का ध्यान नहीं मिल पाता। रूस की प्रथम योजना का विशाल अपव्यय और अनावश्यक त्याग का कारण संगठन की कमजोरी भी थी।

आर्थिक योजना के दो विभाग होते हैं। वित्तीय योजना [financial plan] तथा भौतिक या उत्पादन योजना [physical or production plan]। एक पिल्लड़ा हुआ गरीब देश जब आयोजन आरम्भ करता है तो पूँजी की कमी उसके मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट होती है। आर्थिक साधन उपलब्ध करने का प्रयत्न इतना कठिन और महत्वपूर्ण होता है कि योजनाकर्त्ता, राज्य तथा जनता इसी पहलू पर विचार करने में लीन हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि किसी भी प्रकार योजना पर खर्च की जाने वाली धन-राशि इकट्ठा करना और खर्च कर देना ही आयोजन बन जाता है। इस खर्च का प्रभाव क्या पड़ा यह तो वाद की बात बन जाती है। लेनिन की गायल्लो योजना तथा स्तालिन की प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह कमी बहुत स्पष्ट पाई जाती है। द्वितीय योजना से ही आर्थिक पक्ष पर इतना शोर न मचाकर, उत्पादन तथा लक्ष्य प्राप्ति पर जनता का ध्यान केन्द्रित करने का प्रयत्न किया गया। धन का व्यय उस समय तक निरर्थक है जब तक कि उससे आशातीत, प्रत्यक्ष प्रभाव न उत्पन्न हो।

विकास के मार्ग पर आने वाले नये राही को एक विशेष प्रलोभन की ओर में भी आगाह करना आवश्यक है। यह है विशालता [gigantism]। एक तरह से इस प्रवृत्ति को संयुक्त राज्य अमरीका की देन कही जा सकती है। उनके पास जो कुछ भी है, या हो सकता है, वह जरूर ही "ससार में सबसे बड़ा, सुन्दर, अच्छा या महंगा" होना चाहिये। उन्नति के आरम्भिक काल में रूस ने इस लालच में पड़कर अपार श्रम तथा श्रम का अपव्यय किया। बाद में इस आदत पर रुकावट तो लग गई किन्तु इसका उन्मूलन न हो सका। अनावश्यक आकार-वृद्धि का ध्येय उपयोगिता [utility] नहीं होती। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठा [prestige] होती है। कोई भी अर्द्ध-विकसित देश केवल प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिये आयोजन करने की विलासिता नहीं कर सकता। अगर करना है, तो उपयोगिता आयोजन [utilitarian planning] के अधिकतर लाभ खो देगा।

श्रम के संवेध में भी कुछ विचारणीय धाराएँ सामने आती हैं। प्रथम, श्रमिक अशिक्षित तथा सर्कीर विचारों वाला व्यक्ति होता है। यह दशा अर्द्ध विकसित देशों में और भी व्यापकता से पाई जाती है। इन्हें आर्थिक प्रेरकों [economic incentive] द्वारा सबसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। द्वितीय, केवल वेतन बढ़ा देने में मजदूर अधिक काम नहीं करता। वेतन की वृद्धि उसके अधिक उत्पादन पर निर्भर करनी चाहिये। उत्पादकता और वेतन के घनिष्ठ संबंध में सतुष्ट मजदूर और सफल योजना का निर्माण होता है। तृतीय, जब तक शिक्षा तथा प्रचार द्वारा मजदूरों में नागरिक कर्तव्य और राष्ट्र भ्रम की भावना नहीं उन्नत की जाती, आर्थिक प्रेरक भी उनसे पूरा काम लेने में सफल न होंगे। इसलिये परिवर्तनकाल में, बलपूर्वक अनुशासन व्यवस्था का स्थापना करना ही होगा। नहीं तो आये दिन मनभेद, असमय मोंग, लापरवाही तथा मुस्ती उत्पादन में बाधक बन जायगी। चतुर्थ, नई उत्पादन क्षमता [production capacity] स्थापित करके उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करना हर अर्द्ध विकसित देश के लिये महँगी तथा कठिन होती है। इससे कहीं अधिक प्रभावशाली, उद्योग श्रम-उत्पादकता [labour productivity] में वृद्धि करके उत्पादन को ऊँचा उठाना है। मशीन तथा श्रम का अधिकतम प्रयोग होने से लागत और पूँजी की आवश्यकता दोनों में कमी होती है। रूस की प्रथम दो योजनाओं में इस ओर ध्यान जा चुका था परन्तु तीसरी योजना में ही इसका विशेष लाभ उठाया गया। आयोजित उत्पादन वृद्धि का 70% श्रम-उत्पादकता बढ़ाकर प्राप्त किया गया। यह हर देश के लिए अनुकरणीय है।



## परिशिष्ट १

### सोवियत रूस का यातायात संगठन

[Transport Organisation of Soviet Russia]

रूस में सफल यातायात विशेष स्थान रखता है। विशाल देश होने से विभिन्न प्रदेशों में सम्पर्क तथा राष्ट्रीय श्रम विभाजन उन्नत यातायात से ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक और राजनैतिक कारणों से जनसंख्या एवं प्राकृतिक साधन सारे देश में बिखरे हैं। दक्षिण में अनाज उत्पन्न होता है लेकिन लकड़ी उत्तर में ही मिलती है। दोंनेत्स घाटी और बाक में अधिकतर कोयला और पेट्रोल केन्द्रित है। मास्को के आसपास के बड़े उद्योग मुख्य उपभोक्ता हैं। यह दूरी लगभग 2,000 किलोमीटर है। इसी प्रकार यूराल पर्वत का लोहा प्रयोग करने के लिये 2000 किलोमीटर से भी अधिक दूर कजनेत्स घाटी से कोयला लाना पड़ता है। विस्तृत प्रदेश पर हल्की आबादी फैली है। यातायात को इन तक पहुँचाने के लिये ऊँचे विकास की जरूरत पड़ती है।

#### रेल-यातायात

विशाल समतल मैदान यातायात की उन्नति को प्रभावित करते हैं। सबक से अधिक लाभपूर्ण रेल-यातायात सिद्ध हुआ। समुद्र-तट बहुत कम होने से तटीय-जल-यातायात उन्नत न हो सका। वायु यातायात एकदम आधुनिक साधन है। भविष्य में इसी को यात्री तथा हल्के सामान ले जाने का साधन बनाना होगा।

दुनिया के क्षेत्रफल के 1/6 भाग पर फैले इन देश में आधुनिक यातायात का सूत्रपात 1809 में एलेक्जेंडर प्रथम ने किया। फ्रांसीसी इंजीनियरों की सहायता से पहली रेल लाइन 1836 में बनी। प्रगति अत्यन्त कम थी। इस ओर क्रीमिया के युद्ध के कारण ध्यान आकर्षित हुआ। एक विशेष संस्था बनाई गई [General Company of Russian Railways] जिसको रेल यातायात की उन्नति का काम सौंपा गया। इस संस्था के प्रयत्नों से काफी अच्छी प्रगति हुई।

रेल यातायात <sup>1</sup>

वर्ष	यूरोपीय रूस [किलोमीटर]
1840	26
1850	601
1860	1589
1870	11,243
1880	23,857
1890	30,957
1900	48,107
1910	59,559
1914	62,200

सोवियत संघ की स्थापना के बाद यातायात को राष्ट्रीय योजनाओं में उचित स्थान न मिल सका। क्रान्ति के बाद जो यातायात संगठन नई सरकार को मिला उसे प्रथम विश्वयुद्ध के तीन वर्षों ने काफी कमजोर बना दिया था। [यह-युद्ध 1917-21] के समय लगभग 4,000 रेलवे पुल, 5,000 रेलवे ब्रिड्ज और 100 जलाशय [water reservoir] नष्ट कर दिये गये। इसके साथ-साथ सैनिक कार्य के लिये रेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। नवीन आर्थिक नीति में इस दशा को सुधारने की चेष्टा की गई। <sup>2</sup>

	1913	1921-26	1929	1935	1937
					रूस संयुक्त राज्य अमेरिका
रेल की लम्बाई [हजार किलोमीटर]	55.1	74.1	77	82.8	85 402
वस्तु वाहन [मिलियन टन]	132.4	83.5	188	388.5	517 1928
यात्री वाहन [मिलियन]	84.8	154.4	365	919	1143 497

1 V Obiaztsov Soviet Transport, p 3

2 Ibid, p 10

इन आँकड़ों से पता चलता है कि नवीन आर्थिक नीति ने रेल निर्माण में बहुत उन्नति किया किन्तु उसके बाद निर्माण कार्य में शिथिलता आ गई। नई लाइन बनाने की जगह पुराने निर्माण को अधिक से अधिक प्रयोग में लाकर आवश्यकताएँ पूर्ण की गईं।

रूस का रेल निर्माण राज्य के सरकारी में व्यक्तिगत उद्यम [private enterprise] द्वारा आरम्भ किया गया लेकिन शीघ्र ही राजकीय हस्तक्षेप निर्देशन से प्रबन्ध तथा संचालन तक पहुँच गया। राजकीय रेल संचालन तक प्रबन्ध 1889 में 23.5% से बढ़कर 1913 में 67.5% हो गया।<sup>1</sup> रूसी रेलों का निर्माण व्यापार तथा उत्पादन के लिए नहीं किया गया। नैतिक सुविधा मुख्य उद्देश्य था। इसका असर यह हुआ कि देश के आर्थिक विकास में इनसे पूरी सहायता न मिल सकी।

द्वितीय विश्व-युद्ध में हिटलर सोचता था कि ब्रिटेन की तटस्थता [neutrality] और रूसी रेलों की कमजोरी के कारण सोवियत संघ की विजय बड़ी आसान होगी<sup>2</sup> लेकिन कमजोर यातायात व्यवस्था को इतने अच्छे संगठन से प्रयोग में लाया गया कि ससार चमत्कृत हो उठा। हिटलर द्वारा विनाश के बाद भी लगभग सभी भारी उद्योगों को जर्मन सेना के सामने से हटाकर यूरोपल पहाड़ के पीछे पहुँचा देना, रेलों की ऐतिहासिक सफलता थी। युद्ध ने पुरानी मशीनों को इतना बेकार कर दिया कि आधुनिकतम रीति से पुनर्संगठन सम्भव बना। चतुर्थ योजना ने 40 मिलियर्ड रूबल से भी अधिक खर्च करके इस क्षेत्र की कमी दूर करने में सहायता दिया। 7,000 किलोमीटर नई मुख्य लाइन, और 12,500 किलोमीटर शाखा लाइन बनाई गईं। इस योजना का ध्येय पुराने लाइनों की मरम्मत और युद्ध से हुई हानि को पूरा करना था।

इतना कहना होगा कि रूसी योजनाओं में यातायात को उचित महत्व नहीं दिया गया। विशाल योजनाओं में बृहद् पूँजी विनियोग का बहुत कम अंश यातायात को मिला। 1918-28 में 23.8%, तृतीय योजना में 20.4%, चतुर्थ योजना में 14.2%, पंचम योजना में 10.1%, सप्तम में 5.5%। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विनियोग की मात्रा बराबर बढ़ती रही परन्तु गिरते हुए प्रतिशत ने इसको बराबर कर दिया। पिछले 40 सालों में रेलवे लाइन में कुल 76% वृद्धि हुई। यही कारण है कि रेलों की चल सम्पत्ति में तीव्रता से ह्रास [depreciation] होता है। प्रत्येक योजना में इस कमी को पूरा करने में ही इतनी पूँजी लग जाती है कि प्रगति नहीं हो पाती। सातवीं योजना में भी अधिकतर यातायात में होने वाला पूँजी विनियोग इसी दिशा में लगेगा।

1. M. S Millet Economic Development of Russia, 1905-14 pp 183-184

2 E Henri Hitler over Russia, p 136.

वर्तमान योजना 110-115 मिलियर्ड रूबल यातायात में, विशेषतः रेल पर, लगायेगी। पूर्वी रूस में आर्थिक विकास होने से रेल यातायात का महत्व और भी बढ़ गया है। ट्रान्ससाइबेरियन के अतिरिक्त दूसरी विशाल रेल लाइन [दक्षिणी-साइबेरियन रेलवे] बनाने का निश्चय किया गया है।

### नदी यातायात

रूस में सगठित समाज तथा राज्य का उदय नदियों और झीलों के किनारे ही हुआ। मास्कोवी [Muscovy] राज्य वोल्गा और ओका नदी के बीच स्थापित हुआ था। आगे चलकर यह रूसी सभ्यता का केन्द्र बना। महान् पीटर ने संगठित रूप से जल यातायात को बढ़ाने में सहयोग दिया। नहरें बनाने का सिलसिला भी उसी की प्रेरणा का प्रभाव था। 1815 में पहला भाप का इञ्जन नदी यातायात में प्रयोग किया गया। डीजल इञ्जन के आविष्कार से स्टीमर का प्रयोग पूरी तरह होना शुरू हुआ। 1917 तक वोल्गा नदी पर 500 से 600 तक बड़ी-बड़ी नावें हर समय चला करती थीं। गृह-युद्ध में एडमिरल कोलचक ने वोल्गा के जहाजी बेड़े को जला दिया। 1919 में जहाजों तथा नावों की संख्या 1913 की लगभग 1/3 बची और वस्तु वाहन [freight carriage] कुल 16% रह गया। नवीन आर्थिक नीति के समय में अधिकतर कमी पूरी कर ली गई। इतना ही नहीं सामान और यात्री ले जाने में नदी यातायात 1913 के आगे निकल गया।

रेल के बाद रूस में नदी यातायात का महत्व दिया गया है। प्रकृति ने नदियों का ऐसा जाल रूस में बिछाया कि नदी यातायात की उन्नति स्वाभाविक बन गई। साल-भर बहने वाली, प्रचुर जलयुक्त नदियों की लम्बाई 4,00,000 किलोमीटर से अधिक है। इसका 1,32,000 किलोमीटर यातायात के लिए प्रयोग होता है। नदी यातायात की दूरी लगभग रेल यातायात के बराबर है। नई योजनाओं में साइबेरिया की अन्य नदियों को नहरों से जोड़कर यातायात के योग्य बनाने का प्रयत्न हो रहा है। नहरों की श्रृङ्खला में सबसे नई कड़ी वोल्गा-डॉन नहर है जो 1952 में खुली। बीसवीं शताब्दी में निर्माण-कला के इस अद्भुत नमूने ने कैस्पियन सागर और काले सागर को मिला दिया। उत्तर के बर्फीले प्रदेशों ने नदी यातायात का पूरा विकास नहीं होने दिया। वोल्गा नदी यातायात की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। रूस की सबसे बड़ी नदी होने के साथ-साथ यह अत्यन्त घनी आबादी के प्रदेशों से बहती है। उत्तर से लकड़ी और दक्षिण से पेट्रोल यातायात की मुख्य वस्तुएँ हैं। अनाज, मछली और नमक के व्यापार में इस जलमार्ग का विशेष स्थान है। पाँचवीं और छठवीं योजना में नदियों द्वारा वस्तु वाहन [freight] की मात्रा लगभग 50% बढ़ी। नदियों की गहराई, जहाजों के ठहरने का

स्थान, बन्दरगाहों की उन्नति, जहाज बनाने और मरम्मत करने के कारखानों के विकास में देश प्रयत्नशील है। सातवी योजना में आशा की जाती है कि रेलों द्वारा वस्तु-वाहन 60% बढ़ेगा। इसी योजना में वोल्गा नदी को बाल्टिक सागर से मिला देने का काम भी पूरा हो जायगा। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक का जलमार्ग आर्थिक विकास और सैनिक सुविधा में बहुत मदद देगा।

### समुद्र यातायात

आर्कटिक और प्रशान्त महासागर के बीच बसे रूस के पास 20,000 किलोमीटर में भी अधिक लम्बा समुद्रतट है। बहुत विस्तृत क्षेत्रफल और आबादी के तटों से दूर होने के कारण इसका उपयोग नहीं होता। जलवायु ने भी कठिनाइयों को बहुत बढ़ा दिया। आर्कटिक महासागर लगभग पूरा जम जाता है। गर्म जलधारा [गल्फ स्ट्रीम] के कारण थोड़ा-सा भाग यातायात योग्य रहता है। समुद्री यातायात की दृष्टि में काला सागर सबसे महत्वपूर्ण है। 50% से अधिक निर्यात व्यापार [पेट्रोल, अनाज, कोयला] बर्मा, सुखुमी, ताउस्से, रोस्तोव, सेवास्तोपोल, ओदेसा इत्यादि कालासागर के बन्दरगाहों से होता है। बाल्टिक सागर और प्रशान्त महासागर से निर्यात की मुख्य वस्तु लकड़ी है। कैलीनीनग्राद, रीगा, तैलीन, और लेनिनग्राद—बाल्टिक सागर; मरम्स्क—आर्कटिक महासागर, आखज़ीलस्क—श्वेत सागर; ब्लाडीवोस्टक, ओखा—प्रशान्त महासागर, तथा वाक्, अस्ट्राल्वा—कैस्पियन सागर के मुख्य बन्दरगाह हैं।

प्रथम युद्ध तथा गृह युद्ध के बाद रूस के पास पुराने जहाजों के बड़े का कुल 30% ही बचा था। इसमें भी मरम्मत की कमी होने से काम योग्य जहाज और बड़ी नावे बहुत कम थीं। 1922 तक कुछ प्रगति उनको सुधारने में हुई। प्रथम योजना में जहाजरानी को 1913 से 20% तक बढ़ाने की योजना थी। बन्दरगाहों का पुनर्निर्माण, जहाजी मरम्मत के कारखाने और मालगोदाम पर 200 मिलियन रूबल खर्च हुआ। जहाज निर्माण पर भी 350 मिलियन रूबल खर्च किया गया। इन विशेष प्रयत्नों द्वारा 1933 तक 23.4% वृद्धि हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तक 1913 से छः गुना विकास हो चुका था। चतुर्थ योजना में बन्दरगाहों के आयुनिककरण के साथ तीन बड़े जहाज-मरम्मत के कारखाने तैयार हुए। काले सागर और बाल्टिक सागर पर दो जहाज बनाने के कारखाने स्थापित हुए। इन प्रयत्नों में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उधार दिये गये लगभग 50 बड़े जहाज और सैकड़ों छोटे स्टीमर को भी शामिल कर लिया गया। सातवी योजना [1959-1965] में जहाजों का कुल वजन लगभग दूना कर दिया जायगा, बन्दरगाहों की कार्यक्षमता में 60-70 प्रतिशत वृद्धि होगी, और सामान उतारने-चढ़ाने का 75% काम यंत्रों द्वारा किया जायगा।

## वायु-यातायात

1923 में सोवियत संघ ने एक नागरिक वायु-परिवहन समिति [Civil Aviation Committee] की स्थापना किया। इसके निर्देशन में वायु-परिवहन का संगठन हुआ। प्रथम योजना से ही इस क्षेत्र में प्रगति हो सकी। 1933 तक हवाई जहाज का निर्माण रूस में आरम्भ हो गया। द्वितीय महायुद्ध तक रूसी वायुयान केवल परिवहन में ही नहीं, कृषि में भी सहायता दे रहे थे। सैनिक क्षेत्र को छोड़ देने पर, केवल नागरिक क्षेत्र की प्रगति भी विकास का विस्तार बतलाती है। 1923 में कुल 420 किलोमीटर [262 मील] तक ही हवाई-मार्ग था और 221 यात्री हवाई जहाज पर चढ़े। 1940 में 1,43,000 किलोमीटर [81,375 मील] के हवाई मार्ग का 3,99,000 यात्री तथा 60,000 टन वस्तु-वाहन द्वारा प्रयोग हुआ। मलेरिया तथा कृषि के कीड़ों के विरुद्ध वायुयान का प्रयोग विस्तृत रूप से होता है।

द्वितीय महायुद्ध में वायु यातायात ने सहायनीय कार्य किया किन्तु इसे गहरी क्षति उठानी पड़ी। इसी समय से वायु यातायात को रूस में सर्वोच्च स्थान देने का निश्चय हुआ। हल्का सामान और यात्री परिवहन तो इसी के द्वारा होगा। रेल भारी सामान ले जाने का साधन बन जायगी। इस दिशा में प्रगति अत्यन्त सन्तोषजनक है। युद्ध के बाद के पहले साल में ही लगभग 200 वायु-मार्ग खोले गये। इनके द्वारा सभी बड़े शहर आपस में सम्बन्धित हो गये। 1949 से मॉस्को-व्लाडीवोस्टोक के बीच प्रतिदिन हवाई जहाज चलने लगा। 1950 में नागरिक परिवहन 1940 का आठ गुना हो गया। सातवीं योजना में जेट हवाई जहाजों का प्रचुर प्रयोग करके यात्री परिवहन में 500% वृद्धि की जायगी। आधुनिक भारी यानों के योग्य 90 एयरोड्रोम [हवाई स्टेशन] बनाकर वायु यातायात में संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुँचने की चेष्टा की जायगी।

## मोटर यातायात तथा सड़कें

मोटर यातायात बहुत बाद में बढ़ना आरम्भ हुआ। सोवियत शासन के पहले इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। 1914 में रूस के पास कुल 9,000 गाड़ियाँ थी जिनमें अधिकतर ट्रकें थीं। यह संख्या 1950 में 10,00,000 कार, ट्रक तथा बसों तक पहुँच गई। द्वितीय युद्ध में संयुक्त राज्य ने रूस को 3,00,000 विविध प्रकार की ट्रकों से सहायता किया। युद्ध के बाद की योजना में आधुनिक प्रकार की मोटरों और मरम्मत केन्द्र स्थापित किये गये। सिद्धान्त रूप से यह स्थिर किया गया कि अन्तर-जिला [Inter-district] यातायात में भारी सामान मोटर से भेजा जाय। कम दूरी के लिये रेल का प्रयोग बराबर बटाया जायगा। इस निर्णय से मोटर यातायात में बहुत सहायता

मिली। सातवीं योजना में मोटर द्वारा माल भेजने में 90% वृद्धि की जायगी और यात्रियों की संख्या को तीन गुना बढ़ाया जायगा। छोटे-छोटे गैरेज और डिपो को मिला कर आर्थिक समितियों [Economic Councils] के निर्देशन में पुनर्संगठित किया जायगा। बसों की संख्या में 340% उन्नति होगी।

सड़कों का विकास तथा निर्माण पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। आधुनिक पक्की सड़कों का उन्नति-काल द्वितीय युद्ध के बाद से ही माना जाता है। सारे देश में सड़क निर्माण और मरम्मत स्टेशन [Road Repair and Construction Stations] का जाल बिछाया गया। इस क्षेत्र में कितना काम करना है यह इस बात से पता चलता है कि 1938 में कुल 87.5 हजार किलोमीटर पक्की सड़कें सारे देश में थीं। 1950 तक मोटर योग्य सड़कों की लम्बाई में लगभग 12 हजार किलोमीटर और जोड़ा जा सका। सातवीं योजना में राष्ट्रीय सड़कें कंक्रीट की बनेंगी; क्षेत्रीय महत्व की सड़कें पक्की की जायगी, और नव-विकसित प्रदेशों में मोटर योग्य सड़कें बनेंगी। यह अनुमान है कि 1959-65 में पिछले सात वर्षों [1952-1958] से 180% अधिक मोटर योग्य सड़कें बनेंगी।

## परिशिष्ट २

### रूस में सामाजिक सुरक्षा

[Social Security System in Russia]

सोवियत संघ का संविधान [1936] संसार का अकेला संविधान है जिसमें सामाजिक सुरक्षा को नागरिकों का आधारभूत अधिकार माना गया है। धारा 120 के अनुसार नागरिकों को वृद्धावस्था, बीमारी तथा कार्य-शक्ति के हानि की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार है। इसमें सन्देह नहीं कि सैद्धान्तिक घोषणा तथा वास्तविक प्रतिपादन में बहुत बड़ी दूरी हो सकती है। समय के साथ रूस ने इस दूरी को कम करने का लगातार प्रयत्न जारी रखा है। आरम्भ से ही इस दिशा में लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ था। लेनिन ने कहा था कि एक वर्गात् देश की प्रथम आवश्यकता है कि मजदूर की रक्षा की जाय। यदि वह बच जाय, तो सभी कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकों को समाज की ओर से बहुमुखी सेवाएँ मिलती हैं। स्पष्ट प्रयत्न इस गत का प्रतीत होता है कि महान्-निर्णय महायत्ता का राजकीय सहारा जीवन की लगभग हर विषम एवं विपरीत परिस्थिति में उपलब्ध रहे। रूस की विशिष्ट राजनैतिक तथा सामाजिक भूमिका के कारण सामाजिक सुरक्षा ने जो रूप धारण किया है वह अपने तरह का निराला है। सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के तीन मुख्य भाग किये गये हैं : स्वास्थ्य सेवाएँ; सामाजिक पोषण; सामाजिक बीमा।

#### स्वास्थ्य सेवाएँ

सोवियत जन-स्वास्थ्य सेवाएँ सम्पूर्ण देश के लिये एक बृहत् योजना के अंतर्गत की जाती हैं। चिकित्सा विज्ञान [Medical Science] के सभी पहलू इसी में सम्मिलित होते हैं। जन-स्वास्थ्य मन्त्रालय [Ministry of Public Health of the U S S R] के संचालन में हर एक राज्य, क्षेत्र, जिला और शहरों में जन-स्वास्थ्य विभाग हैं। कुछ मन्त्रालयों की अपनी निजी स्वास्थ्य सेवाएँ चलती हैं जैसे सुरक्षा, रेलवे तथा अन्तर्देशीय मन्त्रालय। इन सेवाओं का पूर्ण व्यय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के दजत से होता है। इसकी वृद्धि से इन सेवाओं के प्रसार का अनुमान लगाया जा सकता है :



रूस का जन स्वास्थ्य बजट <sup>1</sup>

वर्ष	मिलियन रूबल
1928	661
1938	9,433
1955	30,300
1956	35,500
1957	37,900

हर प्रकार की सेवाएँ निःशुल्क दी जाती हैं। सरकारी दुकानों से निश्चित मूल्य पर दवाइयाँ मिलती हैं। अस्पतालों में दवाएँ मुफ्त दी जाती हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के दो अङ्ग हैं—रोग-रोधक [Prophylactic] तथा चिकित्सा [Treatment] सेवाएँ। यह शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में काफी विस्तृत रूप में सङ्गठित की गई हैं। अस्पतालों की सुविधा शहर, क्षेत्र [Region] तथा जिला में उपलब्ध है। ग्राम अस्पतालों में अनेकों विभाग होते हैं। सीमित रूप से लगभग हर प्रकार की चिकित्सा इनमें की जाती है। विशेषज्ञ अस्पतालों में किसी एक प्रकार के रोग की उच्चतम चिकित्सा का प्रबन्ध रहता है जैसे सक्रामक रोग, मानसिक रोग, मातृत्व, बच्चों के रोग का अस्पताल। 1947 के पुनर्सङ्गठन के पहले भर्ती न होने वाले रोगियों [Out-door Patients] के लिये अलग अस्पताल थे किन्तु उस समय से दोनों प्रकार के रोगी [Out-door and in-door Patients] को एक स्थान पर ही देखा जाता है।

प्रत्येक शहर को चिकित्सा-क्षेत्रों [Medical Areas] में विभाजित करके उनकी देख-रेख में लगभग 4,000 व्यक्ति रखे जाते हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में प्रायः हर प्रकार के विशेषज्ञ नियुक्त होते हैं। औद्योगिक उद्यमों में चिकित्सा सेवाओं के समुचित प्रबन्ध पर जोर दिया जाता है। हर कारखाने में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का सञ्चालन एक डाक्टर या उसका सहकारी करता है। मामूली तौर पर 1,500 मजदूरों के लिये एक चिकित्सा केन्द्र, खान, रसायन और पेट्रोल उद्योग में 500 मजदूरों के लिये एक चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था है। औद्योगिक बीमारी की रोक-थाम करने में इन्होंने अत्यन्त सहायनीय कार्य किया। जनता के स्वास्थ्य की निरन्तर देख-रेख के लिये एक विशेष प्रवृत्ति [Dispensarisation] अपनाई गई। हर व्यक्ति को एक बहुमुखी चिकित्साख

<sup>1</sup> U S S R Reference Book, p 163.

[ Polyclinic ] से सम्बन्धित रहना पड़ता है। यहाँ उनकी सामयिक जाँच होनी रहती है।

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएँ पहुँचाने में काफी प्रगति हुई। 1913 में कुल 4,500 ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र थे। 1955 तक 65,900 केन्द्र काम कर रहे थे। प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय अस्पताल होता है। इसके संचालन में पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यान्वित होती हैं। इनके अतिरिक्त सामुदायिक फार्म, मर्शान-ट्रेक्टर स्टेशन, राजकीय फार्म इत्यादि पर चिकित्सा केन्द्र स्थापित हैं। 1955 में लगभग 12,000 ग्रामीण अस्पताल और 10,000 सामुदायिक फार्म के मातृत्व गृह [ Maternity homes ] थे। सफाई द्वारा स्वास्थ्य रक्षा, संक्रामक रोगों की रोक-थाम, माँ-बच्चों की देख-रेख, स्वास्थ्य सुधारने के लिये सेनीटोरियम व स्वास्थ्य केन्द्र तथा चिकित्सकों की शिक्षा का प्रबन्ध स्वास्थ्य सेवा में ही सम्मिलित किया जाता है।

### सामाजिक पोषण [Social Maintenance]

सामाजिक पोषण पेंशन की तरह मिलता है। प्रबन्ध की दृष्टि से पेंशन दो विभागों में रक्खी गई है जो व्यक्ति प्रासंगिक सेवा [ Contract of Service ] में काम करते हैं उन्हें पेंशन सामाजिक बीमा द्वारा दी जाती है; जो व्यक्ति किसी प्रसंगिक के अंतर्गत काम नहीं करते, उनके लिये राज्य की ओर से निर्वाह के साधन दिये जाते हैं। सामाजिक पोषण में द्राविक सहायता [ Monetary assistance ] के साथ-साथ अन्य सेवाएँ भी मिलती हैं। इनमें वृद्ध व्यक्तियों के विश्राम-गृह, पंगु तथा अन्य लाचार व्यक्तियों के लिये निर्वाह और प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य हैं। राज्य व्यय का पूर्ण भार स्वयं वहन करता है। सामाजिक पोषण पानेवालों पर किसी प्रकार का राज्य-कर नहीं लगता। यह सहायताएँ कई वर्गों के व्यक्तियों को प्राप्त हैं : [1] वैतनिक कान करने वाले, [2] नेनिक, [3] उच्च या विरोपज्ञ मंस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी, [4] अन्य नागरिक जो राज्य अथवा सार्वजनिक कर्तव्य के पालन में पंगु हो गये हो, और [5] इन सभी व्यक्तियों के परिवार का निर्वाह भी किया जायगा यदि उपरोक्त नागरिक अपने परिवारों के पोषक [ Bread winner ] थे। इस प्रकार सामाजिक पोषण सेवाओं के कई रूप बन गये। वृद्धावस्था पेंशन [ Old age pension ], असमर्थता पेंशन [ Disability pension ], तथा इनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन [ Loss-of-bread-winner pension ]

वृद्धावस्था की पेंशन का आरम्भ सोवियत संघ में 1927 से हुआ। उस समय यह केवल चन्द उद्योगों में लागू की गई। 1929 में इसका क्षेत्र बढ़ाकर सारे मजदूरों [ Wage-earners ] तक पहुँचाया गया। द्वितीय योजनाओं की सफलता के साथ

इनमें पुनः विस्तार दिखलाई पड़ा। 1937 तक सभी वैतनिक कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। आजकल कुछ अस्थायी तथा मौसमी [Seasonal] मजदूरों को छोड़कर अन्य सभी प्रासम्बद्धिक काम करनेवालों को जीवन भर के लिये वृद्धावस्था पेन्शन दी जाती है। जुलाई 1956 में पेन्शन अधिनियम में परिवर्तन किये गये जिस कारण इसके खर्च में करीब  $\frac{1}{3}$  की वृद्धि हुई। जनवरी 1957 के लगभग 1,60,00,000 व्यक्ति पेन्शन पर रहे थे। सोवियत पेन्शन प्रणाली की एक विशेषता यह है कि इसकी प्राप्ति एक निश्चित अवधि तक काम करनेवालों को ही होती है। पुरुष कर्मचारियों को 60 वर्ष और स्त्रियों को 55 वर्ष की उम्र में पेन्शन मिलती है यदि उस समय तक इन्होंने कम से कम 25 साल और 20 साल का कार्य-काल क्रमशः पूरा कर लिया हो। कुछ विशेष कठिन और खतरनाक क्षेत्रों में काम करनेवाले व्यक्तियों को पेन्शन जल्दी मिलती है—पुरुषों को 10 वर्ष और स्त्रियों को 45 वर्ष की उम्र में, यदि उस समय तक इन्होंने कम से कम 20 साल और 15 साल का कार्य-काल पूरा किया हो। जिन स्त्रियों के पाँच या उससे अधिक बच्चे हों [और वे आठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों] तो उन्हें 50 वर्ष की आयु में पेन्शन मिलेगी, यदि उस समय तक उनका कार्य-काल कम से कम 15 साल हो।

निम्न वेतन पानेवाले कर्मचारियों की पेन्शन उनके मासिक वेतन के बराबर होती है। अन्य व्यक्तियों के लिये इसकी मात्रा उनके मासिक वेतन का 100 से 50% तक हो सकता है। किसी भी दशा में यह 300 रूबल प्रतिमाह से कम और 1200 रूबल प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। जिन व्यक्तियों का कार्य-काल 15 वर्ष से अधिक हो चुका है और उनके परिवार में पंगु-आश्रित [Non-able-bodied dependents] हों तो उन्हें पेन्शन के अलावा और सहायता दी जाती है। सातवीं योजना के अनुसार 1963 तक कम से कम पेन्शन की मात्रा शहरों में 300 रूबल से बढ़ाकर 400 रूबल कर दी जायगी। 1966 में यह संख्या 450 से 500 रूबल प्रतिमाह तक पहुँचाने का विचार है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को वर्तमान 255 रूबल के स्थान पर 340 रूबल प्रतिमाह देने का प्रयत्न हो रहा। जिन वृद्ध व्यक्तियों की देख-रेख करनेवाला कोई नहीं होता, उनके लिये विशेष निवास-स्थान का प्रबन्ध रहता है।

असमर्थता पेन्शन [Disability pension] उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी कार्यक्षमता काम करते समय चोट लगने से या किसी औद्योगिक बीमारी से नष्ट हो गई हो। यह सहायता अन्य बीमारियों की अवस्था में भी मिलती है यदि मजदूर ने कम से कम कार्य-काल की अवधि पूरी कर ली है। इस वर्ग के पेन्शन की मात्रा कम से कम 210 से अधिक से अधिक 1,200 रूबल प्रतिमाह होती है। जिन व्यक्तियों की कार्य-

क्षमता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है उन्हें कुछ न कुछ काम करने के लिये उत्साहित किया जाता है। इस प्रकार होनेवाली आय पेन्शन के अतिरिक्त होती है।

इनके परिवारों को मिलने वाली पेन्शन [ Loss-of-bread-winner pension ] केवल उन सदस्यों को दी जाती है जो स्वयं कार्य नहीं कर सकते। इन पेन्शन की मात्रा परिवार के आश्रित सदस्यों पर निर्भर करती है। कम से कम 160 से 300 रूबल और अधिक से अधिक 480 से 1,200 रूबल प्रतिमाह तक दिया जाता है। कानून के अनुसार सेना के किसी भी पद पर काम करने वाले व्यक्ति और उनके परिवारों को इस पेन्शन का लाभ मिलेगा।

### सामाजिक बीमा [Social Insurance]

सामाजिक बीमा का विस्तार सोवियत सरकार की स्थापना के बाद आरम्भ हुआ। मजदूरों की असतुष्टि तथा मॉर्गों को शान्त करने के लिये जार सरकार ने 1912 में सामाजिक बीमा प्रणाली का सूत्रपात किया था। बीमारी तथा चोट लगने की परिस्थिति में मजदूरों को सहायता देने का प्रयत्न किया गया। सोवियत सामाजिक बीमा को तीन हिस्सों में रखा जा सकता है—[1] प्रसविदा के अनुसार काम करने वालों के लिये अनिवार्य राजकीय बीमा, [2] बिना प्रसविदा के काम करने वाले व्यक्तियों के लिये ऐच्छिक आपसी सहायता समितियाँ, तथा [3] इन दोनों वर्गों में न आने वालों के लिये राज्य से प्राप्त सहायता।

### अनिवार्य सामाजिक बीमा

क्रान्ति के बाद तुरन्त इस दिशा में नये कानून बने। नवम्बर-दिसम्बर 1917 में नये सिद्धान्तों का सन्नावेश हुआ। इसका क्षेत्र सभी मजदूर तथा कर्मचारियों तक बढ़ा दिया गया। उन हर परिस्थितियों में रक्षा करने का प्रयत्न किया गया जिनसे विभिन्न कारणों से नागरिक की कार्य शक्ति [Capacity to work] नष्ट हो जाती है। इनमें बेकारी [unemployment] का विशेष स्थान था। काम करते समय पंगु होने पर वेतन के बराबर सहायता का विधान बना। बीमा का प्रवन्ध बीमादाता [Insured persons] को सौंपा गया जिससे मालिकों द्वारा गड़बड़ी करने का पुराना डर समाप्त हो जाय। मजदूर सरकार ने अपनी सहायभूति तथा सदभावना सिद्ध करने के लिये सामाजिक बीमा का पूरा भार प्रत्यक्ष रूप से कारखानों पर रखा। व्यक्तिकतः से कारखानों की समस्त पूँजी राज्य देता था। इस तरह बीमा का भार भी राज्य के ऊपर ही पड़ता था। क्रान्ति के बाद की अशान्ति, अव्यवस्था व अराजकता में यह प्रयास केवल कानून बन कर रह गये। इनको लागू न किया जा सका। कुछ स्थानों पर किया गया प्रयोग; असमर्थन के कारण बहुत सफल न रहा।

युद्धकालीन साम्यवाद की समाप्ति पर बीमा की ओर फिर ध्यान दिया गया नवोन आर्थिक नीति के आरम्भ में एक कानून बना। इसका उद्देश्य 1917 के राजा जाओ को सुचारु रूप से कार्यान्वित करना था। यही कानून 1922 के प्रसिद्ध 'श्रम नियम' [ Labour Code ] में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अनुसार वैतनिक वृत्ति [ paid employment ] के समस्त कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा मिली—जैसे, गजकीय मजदूर व कर्मचारी, व्यक्तिगत क्षेत्र में काम करने वाले तथा धरेलू नौकर। वेकारी, बुढ़ापा, पगु होना, शारीरिक आघात, बीमारी, कर्त्ता [ bread winner ] की मृत्यु, और स्त्रियों के लिये मातृत्व काल की अवधि में रक्षा प्राप्त की जायगी। इस सम्बन्ध में कार्य की श्रेणी तथा नौकरी की अवधि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह प्रतिबन्ध बाद में सामने आये। बीमा रक्षा दो रूपों में मिलती है—आर्थिक तथा अनार्थिक। निःशुल्क चिकित्सा, विशेष प्रकार के स्वास्थ्य सुधार केन्द्रों में रहने की सुविधा, बच्चों की देखभाल की सस्थाएँ तथा अन्य प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएँ अनार्थिक सहायता के मुख्य तरीके हैं।

1922 के 'श्रम नियम' के अनुसार सामाजिक बीमा का प्रबन्ध श्रमिक सघ [ Trade Unions ] के हाथों में देने के लिये कहा गया। किन्तु श्रमिक सघों का अधिकार, कार्य क्षेत्र, व राज्य से सम्बन्ध भीषण राजनैतिक तनातनी का कारण बना था जिससे इस दिशा की प्रगति अस्पष्ट बनी रही। 1930 तक स्तालिन का प्रभुत्व स्थापित होने पर श्रमिक सघ और राज्य का लगभग पूर्ण विलयन कर दिया गया। यह सघ मजदूरों के स्वतन्त्र नेतृत्व के स्थान पर राजकीय अनुशासन लागू करने की सस्थाएँ बन गए। 1933 में, श्रमिक सघ श्रमिक मंत्रालय का स्थान वैधानिक रूप में पा चुके थे। इसी समय से इनके अस्तित्व का एकमात्र कारण सामाजिक बीमा का प्रबन्ध बना।<sup>1</sup> सामाजिक बीमा सम्बन्धित सभी बातों का ग्राम संचालन, बीमा बजट तैयार करना और बीमा धन की मात्रा तथा दर निश्चित करना श्रमिक सघ का कार्य है। इसके लिये अखिल-संघीय केन्द्रीय श्रमिक सङ्घ समिति [ All-Union Central Council of Trade Unions or AUCCTU ] अपने बीमा विभाग द्वारा देश में इन सेवाओं का संचालन तथा निर्देशन करती है। 1937 से हर कारखानों में सामाजिक बीमा प्रबन्ध के लिये एक निर्वाचित बीमा समिति बनी। उस समय तक यह काम पूरी तरह कारखाना श्रमिक सङ्घ समिति निजी रूप से करती थी। इस सुधार का उद्देश्य बीमादारों [ insured persons ] द्वारा स्वयं ही बीमा सुरक्षा को चलाना था।

<sup>1</sup> Issac Deutscher Soviet Trade Unions, p 116

and Dobb in "Organised Labour in Four Continents"

Ed. H. A. Marquand, pp 311-312

सोवियत रूस के सामाजिक बीमा संगठन में कुछ बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम] बीमा द्वारा मिलने वाली सहायता की दर व मात्रा केवल परिस्थिति अथवा घटना पर निर्भर नहीं करती। इसको प्राप्त करने के लिये एक निश्चित अवधि तक काम करना जरूरी है। 1938 तक कम से कम 3 साल तक की नौकरी करना आवश्यक था। इसके बाद से अवधि को बढ़ा कर 6 साल कर दिया गया। द्वितीय] ऊँचे दर पर सहायता प्राप्त करने के लिये एक ही कारखाने में लगातार किये गये काम की अधिक मान्यता दी जाती है। तृतीय] दूरे दूर पर बीमा लाभ केवल श्रमिक सङ्घ के सदस्यों को दिया जायगा। गैर-सदस्यों को उनके वेतन का कुल 50% ही सहायता की तरह मिल सकता है।<sup>1</sup> चतुर्थ] सामाजिक सेवाओं को लाभ की लालच उत्पादकता बढ़ाने में विशेष प्रोत्साहन की तरह इस्तेमाल की जाती है। स्लाखेनोवाइट मजदूरों को बीमा के अन्तर्गत अधिक सहूलियतें प्राप्त हैं। पंचम] मजदूर तथा कर्मचारी बीमा के लिये कोई चन्दा नहीं देते। इसका भार कारखाना उठाता है। कुल वेतन [gross wage] का एक प्रतिशत के रूप में यह लिया जाता है। जोखिम के अनुसार विभिन्न कारखानों 4 से 10 प्रतिशत तक देते हैं। औसत लगभग 6½% पड़ता है।<sup>2</sup> अन्य प्रकार के मजदूरों [व्यक्तिगत उत्पादकों, तथा घरों में काम करने वाले] के लिये उनके मालिक अपने अंश का बीमा-चन्दा सरकारी हिसाब में जमा करा देते हैं। षष्ठम] राज्य द्वारा आयोजित बीमा में वे व्यक्ति नहीं आते जो प्रसविदा के अन्दर काम नहीं करते जैसे सामुदायिक किसान, निजो उत्पादक तथा स्वतन्त्र काम करने वाले मजदूर जैसे बढ़ई, मोची, लुहार इत्यादि। इन वर्ग के लोगों को ऐच्छिक आपसी सहायता समिति [mutual aid societies] तथा सहकारी रूप से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। सप्तम] बेकारों बीमा [unemployment insurance] 1930 में उठा दिया गया। प्रथम योजना द्वारा उत्पन्न नये कामों को देखते हुए, सरकारी तौर पर रूस से बेकारों की समस्या की समाप्ति घोषित की गई। सोवियत सङ्घ के अतिरिक्त कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतने जटिल प्रश्न का इतना सहज हल निकला हो। अष्टम] प्रत्येक वैतनिक कर्मचारी बीमा का सदस्य होता है। मजदूर से लेकर इंजीनियर व डाइरेक्टर चाहे उनकी आय कितनी भी हो, एक प्रकार के बीमा नियमों से संचालित किये जाते हैं।

### ऐच्छिक सामाजिक बीमा

अनिवार्य बीमा के अतिरिक्त बिना प्रसविदा के काम करने वाले व्यक्तियों [people not under contract of service] के लिये सामाजिक बीमा का

<sup>1</sup> H W Lardley Social Economic Movements p 409

<sup>2</sup> Maurice Dobb, Op Cit p 400

लाभ अपने नौजवा प्रयत्नों से ही प्राप्त हो सकता है। इस वर्ग में सामुदायिक किसान, व्यक्तिगत फार्म के स्वामी और उनके परिवार तथा अनियमित रूप से काम करने वाले व्यक्ति, जैसे, बटई, लुहार, मिन्त्री इत्यादि आते हैं। इन लोगों की इच्छा हो तो आपसी सहायता समितियाँ संगठित करके सामाजिक बीमा की सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा करना निश्चित किया गया तो इन समितियों का निर्देशन समाज कल्याण मंत्रालय करना स्वीकार कर लेता है। इनके साधनों के सूत्र इस प्रकार हैं : [1] सदस्यों द्वारा दिया गया अशदान अथवा चन्दा; [2] सामुदायिक फार्म मतदान द्वारा इन्हें दी जाने वाली सहायता निश्चित करता है। इसकी मात्रा सामान्यतः वार्षिक फसल का दो से चार प्रतिशत तक होती है और यह द्रव्य तथा वस्तु दोनों में दिया जाता है; [3] राज्य से भी इन समितियों के सहायतार्थ अनुदान मिलता है। इन साधनों से आपसी सहायता समितियाँ अपने सदस्यों को लगभग वह सभी सेवाएँ देती हैं जो अनिवार्य राजकीय सामाजिक बीमा के अन्तर्गत प्राप्त होती हैं।

### अन्य सामाजिक बीमा

जो व्यक्ति उल्लेखित दोनों प्रकार के सामाजिक बीमा में नहीं आ पाते उनके लिये राष्ट्रीय सहायता समाज कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में संगठित किया जाता है। इसके द्वारा इन व्यक्तियों को निःशुल्क बुढ़ावस्था पेन्शन मिलती है। यदि किसी कारण से वह व्यक्ति पगुँहा जाता है और जीविकोपार्जन के लिये कोई काम नहीं कर पाता, तो इन्हें विशेष सन्थाओं [invalid homes] में रहने का प्रयत्न होता है। इसके लिये प्रार्थी को मंत्रालय में अर्जी देनी पड़ती है। मामूली तौर पर इस सहायता का क्षेत्र समिति है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति इसके अन्तर्गत आते हैं।

### सोवियत सामाजिक सुरक्षा की विवेचना

इस विषय पर मतभेद है कि सोवियत सामाजिक सुरक्षा का कितना अंश वास्तविक है और कितना केवल प्रचार का साधन है। सोवियत अर्थव्यवस्था के विद्यार्थियों ने एक-दूसरे के विपरीत निष्कर्ष निकालकर परिस्थिति की उचित विवेचना अत्यन्त कठिन बना दिया है। राजनैतिक दृष्टिकोण और सैद्धान्तिक पक्षपात सोवियत अर्थव्यवस्था के अध्ययन में इतना अधिक पाया जाता है कि निष्पक्ष रूप से सत्यता का अनुमान नहीं हो पाता। श्री और श्रीमती सिडनी वेब के अनुसार रुस में असीमित तथा सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा मजदूर वर्ग को मिली है। जनता में सोवियत नागरिकता के प्रति गर्व तथा राज्य के साथ सफेदारी की भावना उत्पन्न करने का यह मुख्य साधन है।<sup>1</sup> इसके

<sup>1</sup> Soviet Communism, p 863

विपरीत डी वासीली यह मानते हैं कि सर्वशक्तिशाली राज्य अपने निर्मम शोषण के बदले में सामाजिक सुरक्षा खैरात की तरह देता है।<sup>1</sup> इसी प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं।

सोवियत सुरक्षा की आलोचना में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें मिलेंगी :—

[1] रूस में सामाजिक सुरक्षा का अर्थ एक नये ढंग से लगाया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मिलने वाली सभी राजकीय सेवाएँ इसमें शामिल कर ली गई हैं। बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, मृत्यु, मातृत्व, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से मिलने वाली हर एक राजकीय सुविधा इसमें सम्मिलित है जैसे शिक्षा, बच्चों का देखभाल, छात्रवृत्ति, यह निर्माण, सार्वजनिक बागीचे, सैलकूद के स्थान [Stadia] इत्यादि। इस बात का विरोध इसलिये किया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भेद करने से साधनों का वँटवारा और सुविधाओं का निर्विवाद लेखा तैयार करना सम्भव हो सकता है। अन्यथा यह पता नहीं लगता कि व्यय को किस क्रम से अलग-अलग मदों पर बाँटा गया।

[2] यह विश्वास काफी विस्तृत है कि उद्योग से कुल वेतन का जितना प्रतिशत सामाजिक बीमा के लिये जाता है उसका कुछ अंश ही इस काम पर खर्च होता है। सामाजिक बीमा को राज्य ने प्रचार और अप्रत्यक्ष कर का साधन बना लिया है।

[3] नियमों के अनुसार कई परिस्थितियों में मजदूरों को अपने मासिक वेतन के बराबर सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसमें सन्देह है कि वास्तविकता में ऐसा होता है। प्रचलित धारणा है कि सहायताएँ तथा सुविधाएँ नियम तथा परिस्थिति के अनुसार नहीं मिलती। इनकी मात्रा पर मजदूरों के सामाजिक महत्व [Social worth] का गहरा प्रभाव होता है। सामाजिक महत्व अधिक उत्पादन, श्रमिक सघ की सदस्यता, साम्यवादी संघ की सदस्यता, राजनैतिक कार्य तथा राज्य की विशेष सेवाओं से आँका जाता है।

[4] सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में सहायता देने के अतिरिक्त, श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि, अच्छा साम्यवादी बनाने का प्रयत्न और राजकीय अनुशासन नियमों का कठोर पालन भी है। इस प्रकार इसे सामान्य अर्थ में केवल सामाजिक सुरक्षा नहीं कहा जा सकता।

[5] समान वेतन के सिद्धान्त का सोवियत संघ ने काफी पहले ही परित्याग कर दिया था। असमान वेतन के साथ सामाजिक बीमा की सुरक्षा भी असमान मात्रा में दी जाती है। सभी नागरिकों को एक-सी सुरक्षा पाने का एक-सा अधिकार होना चाहिये।



[६] समाज द्वारा मिलने वाली सुविधाओं की प्राप्ति पर व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा व प्रभाव का अनावश्यक असर देखा जाता है। इस वर्ग के थोड़े से लोगों के लिये उच्च कोटि की सुविधा पाना सुलभ है। सामान्य मजदूर को या तो यह सब मिल नहीं पाता, या बहुत मामूली तरह की सेवाएँ मिलती हैं।<sup>1</sup> इसमें सदेह नहीं कि युद्ध के पहले से आजकल हालते काफी सुधर गई हैं। फिर भी इस प्रकार की विचारधारा बनी हुई है।

[७] 1931 में सुरक्षा सुविधाओं की मात्रा का निर्णय आधार कार्य-काल की अवधि को बनाया गया। एक ही स्थान पर लगातार काम करने वालों को विशेष मान्यता मिली। इसका कारण मजदूरों के प्रवास की आदत को रोकना था। किन्तु वास्तविकता में इस प्रतिबंध से [काफी समय तक के लिये] मजदूरों का बहुत बड़ा भाग बीमारी, दुर्घटना इत्यादि में मदद से वंचित हो गया।<sup>2</sup> इतना ही नहीं, इस प्रतिबंध ने अपने पसंद के अनुसार धंधा खोजने की स्वतंत्रता को अत्यंत सीमित बना दिया।

उपरोक्त चित्र में सतुलन लाने के लिए इसके दूसरे पहलू पर भी दृष्टिपात करना होगा। किसी भी अच्छी सामाजिक सुरक्षा पद्धति में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। प्रथम, शरीर तथा काम के कारण उत्पन्न सभी विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करना इसका उद्देश्य होना चाहिए। सोवियत संघ ने समय के साथ लगभग सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न कर लिया है—जन्म, शिक्षा, रोग, दुर्घटना, बुढ़ापा, मृत्यु तथा अन्य सक्रिय स्थितियों तक राजकीय सुरक्षा का विस्तार हो चुका है। यह व्यापकता [Comprehensiveness] अत्यन्त सराहनीय है। द्वितीय, सामाजिक सुरक्षा की समरूप योजना [unified scheme] की आवश्यकता तथा लाभ सर्व-विदित है। अखिल सघीय केन्द्रीय श्रमिक संघ समिति [A. U. C. C. T. U.] के साथ सोवियत संघ के समाज-कल्याण मंत्रालय [Ministry of Social Welfare] का परोक्ष सम्बन्ध स्थापित करके उत्कृष्ट समरूपता उत्पन्न की गई है। तृतीय, विस्तार [Coverage] की दृष्टि से भी लगभग संपूर्ण जन-संख्या किसी न किसी रूप में सुरक्षा के अन्दर आ जाती है। चतुर्थ, इन व्यापक सेवाओं के बदले में प्रत्यक्ष तरीके से जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। अधिकतर मालिक वर्ग [employers] तथा सामुदायिक फार्म इसका भार उठाते हैं। कर्मचारी वर्ग पर इसका बहुत सुन्दर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। पंचम, यदि सामाजिक सुरक्षा की ओर राज्य की जागरूकता देखी जाय तो सोवियत सरकार के कर्तव्यनिष्ठा का अनुमान लगता है। राजकीय वज्रट तथा उद्यम कोष [enterprise funds] से दी जाने वाली सुविधाएँ तथा नगद भुगतान की वृद्धि अत्यन्त आकर्षक है।

<sup>1</sup> Andrew Smith I was a Soviet Worker 1936, pp 214-226

<sup>2</sup> Yuzov Op Cit pp. 166-167

सुरक्षा सुविधाएँ तथा भुगतान<sup>1</sup>

वर्ष	००० मिलियन रुबल में
1940	2
1950	122
1955	154
1956	169
1957	192 <sup>2</sup>

चिकित्सा सेवाओं में स्थिति अस्पताल के विकास से आँकी जा सकती है। इन आँकड़ों में फौजी अस्पताल शामिल नहीं है :

अस्पताल में विस्तर-संख्या<sup>3</sup>

वर्ष	१००० में
1913	207
1928	247
1940	791
1950	1,011
1955	1,289
1956	1,360

<sup>1</sup> USSR Reference Book, p. 153

<sup>2</sup> अनुमानित

<sup>3</sup> Ibid p 165

विभिन्न सेवाओं में वृद्धि का क्रम इस प्रकार है <sup>1</sup>

सेवाएँ	मिलियन रूबल में	
	1956	1957
शिक्षा	73,100	78,900
स्वास्थ्य सेवा	35,500	37,900
राजकीय सामाजिक बीमा	18,600	20,900
सामाजिक पोषण	31,400	45,400

अन्त में, प्रचार तथा सामाजिक सुरक्षा कोष के अन्य प्रयोग को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि सोवियत सुरक्षा संगठन तीव्र प्रगति कर रहा है। संगठन, प्रबन्ध तथा प्रयोग की कमजोरियाँ समय के साथ कम होती जायेंगी। जिस महत्व तथा उत्साह से सोवियत राज्य ने सामाजिक सुरक्षा को अपनाया है वह केवल प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय है।

